

राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था
(१५७४ से १८१८ ई०)



धरती प्रकाशन

अमरावती, बी.के. रोड

राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था

(१५७४ से १८१८ ई०)

डॉ० जी. एस. एल. देवडा

बीकानेर संभाग के सदस्य मे

प्रकाशक सरती प्रकाशन मगासहर, भोकरनेर ३३४००१/मुद्रक विभाग घाट प्रिंटर्स,
शाहदरा दिल्ली ३२/मावर्ण सन्/संस्करण प्रथम, १९८१

RAJASTHAN KI PRASHASNIK VYAVASTHA (History)
By Dr G S L. Devra

पुज्यनीय पिता श्री
स्व० श्री सीतारामजी देवडा
की पावन स्मृति मे...

आमुख

अपनी सांस्कृतिक एकता के पीछे राजस्थान प्रदेश भौगोलिक व वातावरणीय दृष्टि से दो भागों में विभक्त है। एक भाग हरा भरा उबरी अरावली पहाड़ियाँ की विभिन्न जगहों से युक्त है जिसे अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने अध्ययन का दृष्टि बनाकर राजस्थान का इतिहास लिखा है। द्वितीय भाग रेतीले टीलों से भरा हुआ है, जिस पर प्रकृति की अनुदारता के साथ साथ इतिहासकारों का भी ध्यान कम गया है। परिणामस्वरूप राजस्थान का इतिहास लेखन व अध्ययन की दृष्टि में अपन-आप में पूर्ण व समुचित नहीं रहा है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान के रेतीले सभाग व १५७४ व १८१८ ई० तक के काल के कुछ पक्षों का अध्ययन करके एक प्रारम्भिक व सीमित प्रयास किया गया है।

राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेतीला क्षेत्र अपनी विविध प्राकृतिक परिस्थितियों व कारणों के कारण राजस्थान में वल्लि सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक भिन्न स्थान रखता है। विश्व के रेगिस्तानों में इसको मरु में उड़ा बड़ा गढ़ा भरा रेगिस्तान कहा जाता गया है। यहाँ का इतिहास निरंतर प्राकृतिक विपदाओं तथा मनुष्य कृत समस्याओं से जूझने का इतिहास है। उल्लेखनीय बात यह कि अत्यधिक गर्म प्रदेश, वर्षा की कमी तथा सिंचाई व साधना व प्रभाव में भी यहाँ के मानव ने मरुपरत होकर अपने श्रेष्ठ गुणों का परिचय दिया है। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति की धरोहर को रेतीले टीलों के बीच सुरक्षित रखा बल्कि स्थानीय विशेषताओं व मायताओं से उस परिष्कृत करके श्रमशक्ति व गति प्रदान की। मुगल काल में वेदों के नियंत्रण व हस्तक्षेप के बाद भी उनके उचित प्रभावों को स्वीकार करके व स्थानीय परम्पराओं के बीच उन्हें रखकर जो विकास की गति इस क्षेत्र को प्रदान की वह इतिहास का स्मरणीय अध्ययन है। विश्व के रेगिस्तानी भागों में ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार विकास की निरंतर प्रक्रिया चलती रही है।

मध्ययुग में इस रेतीले सभाग में स्थापित कबीरावादी व ज्ञासीय परम्पराओं के बीच राठौड़ जाति मात्र एक आक्रमणकारी के आवेग में यहाँ के अल्प साधनों को निचोड़ने के लिये नहीं आई थी बल्कि सर्वत्र के लिये यहाँ वसने की

दृढ़ धारणा के साथ सत्ता स्थापित करने हेतु आई थी। निम्नतर विजयों के परिणामों को सुदृढ़ व स्थायी बतान के लिए गठित व प्रभावशाली प्रशासकीय मस्याओं को स्थापित करने व अथवा प्रयास किए थे। इन प्रयासों में आन्तरिक विरोधों व समर्थन ने तथा बाह्य दबावों व मरदानों ने जो योगदान दिया था, वह इतिहास की प्रक्रिया में गीमाचिह्न है। प्रशासकीय वर्ग के तीन शक्तिशाली तत्त्व- राजा, सामन्त व मुत्तमही ने अपने विवास, लाभ व हानि के समक्ष प्रशासन की विभिन्न मस्याओं के निर्माण में जो योगदान दिया तथा उनकी अवगति के द्वारा खोलकर जहाँ सामान्य व्यक्ति के कष्टों में वृद्धि की तथा बाह्य दबावों के सम्मुख अपनी शताब्दियों में सभासी मान्यताओं के मूल्य को समझा तथा फिर स्वयम् ही उनसे विनाश में कोई कसर नहीं छोड़ी—यह सब प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य विषय हैं। वर सरचना, उसके स्वरूप तथा समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले उसके दबावों का मूल्यांकन करके कुछ निश्चित निर्णयों पर आन का यत्न किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राज्य की मूल समस्याओं में आन्तरिक थीं। राज्य के उत्थान व पतन के पीछे निर्णय युद्ध के मैदानों में न होकर विभिन्न मस्याओं के गठन, कोशल तथा चरमराने व निष्प्राण होने से हुए थे। राज्य के घड़न का अध्ययन करने उसके सम्पूर्ण ताड़ी मस्याओं को पकड़ने का प्रयास किया गया है ताकि वित्तीय असंतुलन के राजनैतिक व मैनिक दुष्परिणाम समझाये जा सकें।

१५७८ व १६१८ ई० के बीच का काल राजस्थान इतिहास में साधारणतया तथा विशेषकर रेतीले सभाग में नवस्थापित बीकानेर राज्य के लिये बहुत महत्वपूर्ण था। १५७४ ई० में बीकानेर राज्य के मुगल सत्ता के साथ सन्धि होने के पश्चात् इस समाज के आन्तरिक ढांचे पर दूरगामी प्रभाव पड़े। डीली-हाली बबीला व कुलीय राजनीतिक व्यवस्था अब तेजी से सशक्त नृपतन्त्र की ओर अग्रसर होने लगी। क्षेत्रीय सीमाओं का गठन हुआ। सम्पूर्ण सत्रहवीं शताब्दी राजसत्ता के विस्तार के प्रयासों व प्रभावों की गाथा है। अठारहवीं शताब्दी में मुगलों के पराभव से पड़ने वाले परिणामों बाह्य आक्रमणों की चिन्ता तथा राज्य व कुलीय सामन्तवाद के बीच व्याप्त निरन्तर संघर्ष की धुनियों ने सम्पूर्ण व्यवस्था का शकलधारे रखा तथा जिसका समाधान ढूँढ़ने के लिये भारत में उठती हुई ब्रिटिश सत्ता से संरक्षण प्राप्त करने के कदम उठाये गये। आधुनिक काल में भारतीय संघ में बिलीनीकरण से पूर्व अधिकांश राजस्थान के राज्यों को इसी काल में परीक्षण के दौर से गुजरना पड़ा तथा स्थायित्व पाने के लिये नये सिरे से प्रयास करने पड़े।

प्रस्तुत पुस्तक में शोध प्रबन्ध 'बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था' पर आधारित है। इस तैयार करते समय उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों से मेरा साक्षात्कार

हुआ था, तथा मैं अनुभव किया था कि इस क्षेत्र के इतिहास का सही निरूपण करने के लिये, यहाँ की विपुल अभिलेखीय सामग्री अध्ययन का आधार है। यह सामग्री प्रशासन व जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डालती है। राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश अभिलेखीय सामग्री बहियों के नाम से विख्यात है। राज्य द्वारा सामू किये जाने वाले आदेशों से लेकर, प्रशासन द्वारा उन्हें प्रियान्वित करने तथा प्रजा द्वारा उनके पालन किये जाने, विभिन्न बरों, वेतन, अधिकारों, नियुक्तियों, मूचनाएँ आदि सभी का आधिकारिक विवरण प्राप्त हो जाता है। यह सत्य है कि इस सामग्री की कुछ सीमाएँ हैं। प्रथम, इसमें सरकारी पक्ष ही उभरकर सामने आता है। द्वितीय, ये बहियाँ अधिकतर सत्रहवीं-शती के उत्तरार्द्ध से प्रारम्भ होती हैं।

१६वीं व १७वीं शताब्दी के अधिकांश भाग के अध्ययन के लिये साहित्यिक सामग्री अपनी समस्त सीमाओं के बाढ़ भी, मुख्य आधार है। वैस बीकानेर क्षेत्र में ऐतिहासिक सामग्री अन्य क्षेत्रों की तुलना में १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही प्राप्त होने लगती है। अकबरवासीन कुछ रचनाएँ तो बहुत प्रामाणिक हैं। अध्ययन में सहयोग के लिये फारसी साहित्य व फरमानों का पूर्ण लाभ उठाया गया है। १८वीं शताब्दी व तत्पश्चात् रचित ख्यात साहित्य महत्त्वपूर्ण सामग्री के रूप में मिल जाता है। इस क्षेत्र की प्रसिद्ध ख्यात दयालदास की ख्यात है, पर अधिक प्रामाणिक विवरण इसमें पूर्ण लिखित ख्यात 'बीकानेर के राठौड़ा की ख्यात महाराजा सुजाणसिंह जी सू महाराजा गजसिंह जी ताई' में है। प्रस्तुत काल की स्थितियों व समस्याओं का निष्पक्ष ज्ञान प्राप्त करने तथा उनके और समीप जाने में बीकानेर शहर के दो निजी संग्रह—मोहता व भैरवा संग्रह बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इस सामग्री तथा विशेषकर भैरवा सामग्री के बिना तो १८वीं शताब्दी में अन्त में आई प्रशासनिक जटिल समस्याओं तथा संकट की पूरी तरह समझ पाना ही पठिन था।

प्रस्तुत पुस्तक में जहाँ तक सम्भव हुआ है, स्थानीय भाषा के शब्दों का व्याख्या के साथ प्रयोग किया गया है। परन्तु इन शब्दों का प्रयोग कई स्थानों पर होने पर ध्यान देने वाले हर स्थल पर व्याख्या नहीं की गई है। यही स्थिति प्रत्येक शासक के काल वर्णन को लेकर है। मूल सामग्री में प्राप्त सूचनओं को और अधिक स्पष्ट करने के लिये स्थल-स्थल पर मारिजिया दी गई हैं—विशेषकर पट्टावता के दरवारी गठन में तथा वित्तीय आकड़ों में। इसी दृष्टि में कुछ स्थानों पर रेखाचित्र व मानचित्र का भी सहारा लिया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में पाठकों को कुछ शब्द उल्लेख पैदा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, सामान्यतः प्रत्येक उच्च अधिकारी के लिये 'हुवलदार' शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः एक स्थल पर अनेक 'हुवलदारों' का वर्णन आ जाना उल्लेख पैदा कर सकता है।

दृढ़ धारणा के साथ सत्ता स्थापित करने हेतु आई थी। निरन्तर विजयो के परिणामों को मुदृढ़ व स्थायी बनाने के लिए गठित व प्रभावशाली प्रशासकीय मस्याओं को स्थापित करने व अथक प्रयास किये थे। इन प्रयासों में आन्तरिक विरोधों व समर्पण ने तथा बाह्य दबावों व सरक्षण ने जो योगदान दिया था, वह इतिहास की प्रशिया में सीमाचिह्न है। प्रशासकीय वर्ग के तीन शक्तिशाली तत्व- राजा, सामन्त व मुत्सद्दी ने अपने विकास, लाभ व हानि के समक्ष प्रशासन की विभिन्न मस्याओं के निर्माण में जो योगदान दिया तथा उनकी अवसति के द्वार खोलकर जहाँ सामान्य व्यक्ति के कष्टों में वृद्धि की तथा बाह्य दबावों के सम्मुख अपनी शताब्दियों से सभाली मान्यताओं के मूल्य को समझा तथा फिर स्वयम् ही उनके विनाश में कोई कसर नहीं छोड़ी—यह सब प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य विषय हैं। पर सरचना, उसके स्वरूप तथा समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले उसके दबावों का मूल्यांकन करके कुछ निश्चित निर्णयों पर आने का यत्न किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राज्य की मूल समस्याएँ आन्तरिक थीं। राज्य के उत्थान व पतन के पीछे निर्णय युद्ध के मैदानों में न होकर विभिन्न मस्याओं के गठन, कौशल तथा चरमराने व निष्प्राण होने से हुए थे। राज्य के वजट का अध्ययन करके उसके सम्पूर्ण नाडी मस्थान को पकड़ने का प्रयास किया गया है ताकि वित्तीय असतुलन के राजनैतिक व सैनिक दुष्परिणाम समझाये जा सकें।

१५७४ म १८१८ ई० के बीच का काल राजस्थान इतिहास में साधारणतया तथा विशेषकर रेतीले सभाग में नवस्थापित बीकानेर राज्य के लिये बहुत महत्वपूर्ण था। १५७४ ई० में बीकानेर राज्य के मुगल सत्ता के साथ सन्धि होने के पश्चात् इस सभाग के आन्तरिक ढांचे पर दूरगामी प्रभाव पड़े। डीली-ढाली कबीला व कुलीय राजनीतिक व्यवस्था अब तेजी से सशक्त नृपतन्त्र की ओर अग्रसर होने लगी। क्षेत्रीय सीमाओं का गठन हुआ। सम्पूर्ण सत्रहवीं शताब्दी राजसत्ता के विस्तार के प्रयासों व प्रभावों की गथा है। अठारहवीं शताब्दी में मुगलों के पराभव में पड़ने वाले परिणामों बाह्य आक्रमणों की चिन्ता तथा राज्य व कुलीय सामन्तवाद के बीच व्याप्त निरन्तर संघर्ष की चुनौतियों ने सम्पूर्ण व्यवस्था को क्षयज्ञोरे रखा तथा जिसका समाधान ढूँढ़ने के लिये भारत में उठती हुई ब्रिटिश सत्ता में सरक्षण प्राप्त करने के कदम उठाये गये। आधुनिक काल में भारतीय मध्य में विलीनीकरण में पूर्व अधिवाश राजस्थान के राज्यों को इसी काल में परीक्षण के दौर से गुजरना पड़ा तथा स्थायित्व पाने के लिये नये सिरे से प्रयास करने पड़े।

प्रस्तुत पुस्तक मेरे शोध प्रबन्ध 'बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था' पर आधारित है। इस तैयार करते समय उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्यों से मेरा साक्षात्कार

यही स्थिति 'गुवाता' को लेकर है। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

मेरे इस प्रयास को मूर्तरूप देने में जिन-जिन लोगों ने सहयोग मिला है, उन सबके नामों का उल्लेख करना सम्भवतः मेरे सामर्थ्य में नहीं है। सर्वप्रथम, मैं उन तीन आत्माओं—स्व० श्री नाथूराम गडगावत (भूतपूर्व, निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार), स्व० श्री घासीराम जी परिहार (भूतपूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर) एवं स्व० श्री जयपालसिंह जी भैंया (भैंया सग्रह के स्वामी) की वन्दना करता हूँ, जिन्होंने न केवल हम दोनों सम्बन्धी विपुल सामग्री में मेरा परिचय करवाया बल्कि विषय को समझने तथा कदम-कदम पर आगे बढ़ाती प्रत्येक अवस्था को दूर किया। मुझे इस बात का हार्दिक दुःख है कि प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में पूर्व ही वे इस असार मसार में विदा हो चुके हैं। श्री० सतीशचन्द्र (अध्यक्ष, विद्वद्विद्यालय अनुदान आयोग) ने मुझे इस बात की प्रेरणा दी कि अन्य क्षेत्रों के इतिहास का अध्ययन करने की अपेक्षा मैं अपनी मातृभूमि के विगत इतिहास का अध्ययन करूँ। उनकी इस प्रेरणा के लिए मैं नतमस्तक हूँ।

पुस्तक को साकार बनाने में रायसिंह ट्रस्ट, जूनागढ़, बीकानेर ने जो चार हजार रुपये की राशि मुद्रण खर्च हेतु दी, उसके लिये मैं डा० करणीसिंह व ट्रस्ट के सदस्यों के प्रति हृदय में अपना आभार व्यक्त करता हूँ। डा० करणीसिंह जो स्वयम् इस क्षेत्र के एक गम्भीर शोधकर्ता हैं, इस बात के लिये सदैव उत्सुक रहे कि मेरा शोध-प्रबन्ध पुस्तक के रूप में प्रकाश में आये। डा० नारायणसिंह घण्टेल ने भी इस कार्य में सदैव मेरा उत्साह बढ़ाया। मेरे मित्र डा० मेघराज शर्मा ने मुद्रण सम्बन्धी अनेक व्यवस्थाएँ जुटाकर अवश्यनीय सहायता दी। मैं इन सब महानुभावों के प्रति एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर व अनुग संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जो मुझे सहयोग व सुविधाएँ दीं उनको धन्यवाद देना मैं अपना परम धर्म समझता हूँ। श्री ओमप्रकाश, धरती प्रकाशन, गंगाशहर, के उत्साह व सहयोग के बिना तो इसका मुद्रण, साज-सज्जा व शीघ्र प्रकाशन सम्भव ही नहीं होता।

अन्त में, मैं डा० दिलीपसिंह, श्री वृजलाल विश्नोई, श्री शिवरतन भूतडा, श्री एस० के० मनोह, डा० शिवनारायण जोशी व डा० शशी अरोड़ा का भी आभारी हूँ, जिनकी सत्प्रेरणाओं से यह अनुष्ठान पूरा हो सका।

जनवरी, १९८१

बीकानेर

जी० एस० एल० देवडा

अनुक्रम

आमुख

१. विषय प्रवेश	१
२ राजपद	१३
३. सामन्त वर्ग एवं पट्टा प्रणाली	४६
४. केन्द्रीय प्रशासन व मुत्सद्दी वर्ग	६६
५. स्थानीय प्रशासन	१२७
६ विस्तीय प्रशासन	१५८
१. आय	१५८
२ व्यय	१५८
३. विस्तीय प्रबन्ध	१८७
७ भू-राजस्व प्रशासन	२००
८. उपसंहार	२११
परिशिष्ट	२३६
सदर्भ-ग्रन्थ	२४३
अनुक्रमणी	२५२
	२७१

संक्षेपण

१. रा० रा० अ० बी०
१ अ० स० पु० बी०

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
अनूप सञ्चित पुस्तकालय, बीकानेर

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पवित	अशुद्ध	शुद्ध
६४	अन्तिम	साईदासोत व साईदास	साईदासोत व साईदास
१०२	१८	मढी रा हुवनदार	मढी रा हुवलदार
१५२	मुख्य पवित	जमीवार	जमादार
१६३	न० ६	कीयता दमासा	कीयाता द ला
१६४	न० २६	हुवक	हुव
१६४	न० ३०	मूगा	भूगा
१६५	१	भास	माल
२०८	२३	राजसिंह	गजसिंह

प्रथम अध्याय विषय-प्रवेश

सन् १९४६ ई० में राजपूताना की रियासतों के राजस्थान राज्य में विलीनीकरण से पूर्व बीकानेर राज्य भारतीय मरुप्रदेश में अक्षांश २७.१२° से ३०.१२° उत्तर तथा देशान्तर ६२.१२° से ७५.४१° पूर्व के बीच फैला हुआ था। राठीठ सरदारों के आक्रमण से पूर्व यह क्षेत्र जांगल देश के नाम से जाना जाता था।^१ इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल २३,३१७ वर्गमील था। राजपूताना के राज्यों में क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इसका स्थान दूसरा था।^२ विलीनीकरण से पूर्व राज्य की सीमाएँ उत्तर में पंजाब के फिरोजपुर जिले, उत्तर-पूर्व में हिसार जिले तथा उत्तर-पश्चिम में भावलपुर राज्य की सीमाओं में मिलती थी। राज्य के दक्षिण में जोधपुर, दक्षिण-पूर्व में जयपुर और दक्षिण-पश्चिम में जैमलमेर की रियासतें

१ महाभारत में इस क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार मिलता है

‘तत्रैवै कुरुपाचाना गात्वा माद्रेय आदृतः’

इसका तात्पर्य यह है कि कुरु देश से मिला हुआ पाचान देश, गात्वा और माद्र देश से मिला हुआ जांगल देश जाति।

महाभारत, भीष्मपर्व, अध्याय ६, श्लोक ३६

जांगल देश के महान मे बताये गये हैं कि जिस देश में जल और घास कम होनी हो, वायु व घास की प्रचलना हो और जल आदि बहुत होना हो, उसको जांगल देश जानना चाहिए।
(स्वत्पोदवतुको यस्तु प्रवातः प्रचुरा तपः। सञ्जेवा जांगलो देशो बहु घापादि संयुतः ॥)

शब्दकोषदुष्ट, काण्ड २, पृ० ५२६

—अपभ्रंश-कर्मचन्द्र बजोरहीतंक ब्रह्मम्, पृ०, २५

(अनुशासक—जी० एच० मोदा)—अस्य जैन प्रचालय १०००। इति० बीकानेर—की इन्फोर्मेशन गवर्नर आठ इण्डिया, भाग ८, पृ० २०२

—डा० बरनोमिष्ठ, बी रिलेवन्स आठ बी हाउस आठ बीकानेर वि० बी मेंटल पार्ले (१९६३-१९४६ ई०), पृ० १४४, नई दिल्ली, १९७४

२ इन्फोर्मेशन गवर्नर आठ इण्डिया, भाग ८, पृ० २०२, अर्सेकिन गवर्नर आठ बीकानेर, पृ० १०६, राजपूताना में जोधपुर राज्य का संतुलन सबसे अधिक ३३,०६६ वर्गमील था।

स्थित थी।

आकार में अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में (मारवाड़ को छोड़कर) बीकानेर राज्य क्षेत्रीय दृष्टि से विस्तार अवश्य था तथापि जनसंख्या में पिछड़ा हुआ था। २३,३१७ वर्गमील के क्षेत्र में लगभग १७०० गांव थे। राज्य की शुष्क जलवायु, पानी तथा प्राकृतिक साधनों के अभाव जनसंख्या की वृद्धि में बाधक थे। मुख्यतः राज्य में पानी की कमी से भूमि में अधिकांश भाग पर वृषि नहीं होती थी। अतः इस रेतीले और कम आबादी वाले राज्य में दूध और सुसंगठित प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना एक चुपकर कार्य था। वर्षा की कमी के कारण बार-बार पड़ने वाले अकाल, निवासियों और प्रशासकों—दोनों के लिए, एक सदैव बनी रहने वाली समस्या थी।

१ इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया, भाग ८, पृ० २०२

२. १६९१ ई० में जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर राज्य का स्थान राजपूताने में पाँचवा था जो १६९१ ई० में बड़नर चतुर्थ हो गया। उस समय राज्य की कुल जनसंख्या ६,३६ २१८ थी।

—रिपोर्ट ऑफ दी सेन्स ऑफ दी बीकानेर स्टेट, बीकानेर १६३१, रा० रा० अ० पुस्तकालय, बीकानेर।

सत्रहवीं शताब्दी में अतः में राज्य की जनसंख्या लगभग दार्द सात अनुमानित थी। यह गणना राज्य में धुआं भाछ (गृहकर), जो प्रत्येक घर से बचन की जाती थी, के आधार पर तय की गई है। इनमें प्रत्येक घर में साढ़े चार व्यक्तिों को गिना गया है। १८वीं शताब्दी के अंत में राज्य का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण जनसंख्या में कुछ और वृद्धि हुई होगी। पाउलेट गजेटियर में १६वीं शताब्दी के प्रथम भाग में प्रत्येक घर में पाँच व्यक्तियों का जोड़ बिठाकर तीन लाख की जनसंख्या अनुमानित की है। जेम्स टाड ने १८वीं शताब्दी के अंत में प्रति घर पाँच व्यक्तियों की गणना के आधार पर ही लगभग पाँच लाख जनसंख्या द्वारा की जनसंख्या बताई है। यह अनुमान उस काल की विषय से सम्बंधित अभिलेखीय सामग्री के आधार पर सही प्रतीत नहीं होता है—धुआं रीकड वही, स० १७५०/१९६३ ई०, न० ८६, बीकानेर बहिषात, रा० रा० अ० बी०, क० जेम्स टाड एनस एण्ड एंटीक्विटीज आफ राजस्थान, भाग २, पृ० ११६५, जालसोर्ट, १६२० ई०, पाउलेट गजेटियर आफ दी बीकानेर स्टेट, पृ० ८६, बीकानेर १६३५

३ समकालीन अभिलेखीय सामग्री से यह निष्कर्ष निकलता है कि १८वीं शताब्दी के अंतिम दशक से पूर्व राज्य में गांवों की संख्या लगभग १७०० थी। गांवों की संख्या में वृद्धि १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जारी रखी गयी मठाराजा मन्त्रिण तथा सूरतमिह के राज्यकाल में क्षेत्रीय विस्तार के कारण सम्भव हुई थी—पट्टा वही, स० १७२५/१६६८ ई०, न० ३३/४, रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर बही खासरा रे गांव रो, स० १७२५/१६६८ ई०, बीकानेर बहिषात, रा० रा० अ० बी०, वही न० २, स० १८७८/१८२१ ई०—मेय्या सग्रह, बीकानेर।

४ प्रकृति ने हम क्षेत्र पर किसी भी तरह से अपनी कृपा नहीं दिखाई है। यह क्षेत्र भारत के विस्तार चार मरुस्थल में स्थित है। अधिकांश भाग बज्र तथा सूखा है। स्थान

१२वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में, राजपूताने में चौहानों की सत्ता के पराभव के साथ, विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में कई छोटी-छोटी स्वशासित इकाइया उभरने लगी, जो आगे चलकर भोमीचारा तथा प्रासिया कहलाई। इन प्रदेशों के दिल्ली के इतने निकट स्थित होने पर भी दिल्ली के सुल्तान चौहान-शक्ति के पतन का लाभ नहीं उठा सके। उनकी अधिकांश गतिविधिया भटनेर के क्षेत्र तक ही सीमित रही। परिणामस्वरूप केन्द्रीय सत्ता के हस्तक्षेप से मुबन इस क्षेत्र की अनेक जातियाँ अवसर का लाभ उठाकर इसके अलग-अलग भागों पर अपना अधिकार जमाने में जुट गयी।

मध्यप्रदेश के इस भूखण्ड पर अधिकार करने वालों में जाट जाति मुख्य थी। प्रदेश के संपूर्ण मध्यवर्ती तथा पूर्वी भाग इनका अधिकृत क्षेत्र था। जाट जाति के प्रमुखतः सात भोमीचारे थे तथा उनके अतिरिक्त अनेक छोटे-बड़े प्रासिये थे। मुख्य शाखाओं में सोहसर के मोदारा, सूर के मिहाग, घाणसिया के सोहुआ, सीधमुख के कसवा, रायसलाणा के वैणीवाल, भाडग के सारण और लुही के पूनीमा थे। इनके

छोड़ने वाले देतीते टीबे जगह-जगह पर दृष्टिगत होते हैं। यहाँ नदी नहीं है, केवल वर्षा के मौसम में राज्य के उत्तरी भाग में सूची घगर नदी में पानी बहता है। यहाँ बिजई के साधनों का अभाव है। वर्षा का औसत लगभग २० से० औ० है। वर्षा की अनिश्चितता भी बहुत है और साधारणतया यह काफी दूर-दूर तथा अस्थिर होती है। औसत पानी की गहराई १५० फुट से भी अधिक मानी जाती है। यहाँ कुछ स्थानों की छोड़कर वर्ष में एव ही फसल बोई जाती है—शब्दरस्पत्रूम, काण्ड २, पृ० ५२६; जौहर-तबनिर तुल बानेवात (रित्रवी से उद्धृत)—मुगलबालोन भारत, हुमायूँ, भाग १, पृ० ११५-१७, विनियम फ़ैजिल-येमीयर्स आफ़ बि० जार्ज थामस (१८०३ ई०), पृ० १३१-७७; टाइल, भाग २, पृ० ११४६-३२; वाउलेट ग्रेविटियर, पृ० ८२-८४; फ़ैपन सैटलमेण्ट रिपीट, पृ० ६-७ बीकानेर, १८६३

१. समूचा बीकानेर संभाग अजमेर के चौहानों के अधीन था। पुष्पीराज चौहान तृतीय की गहाबुदीन गीरी के हाथों पराजय के पश्चात् यहाँ केवल स्थानीय चौहान शासकों की सत्ता रह गयी थी।—दशरथ शर्मा, राजस्थान यू० दी एंजेज, भाग १, पृ० ३००-१, बीकानेर, १६६६
२. इस क्षेत्र पर मुगलों से पूर्व रिकी भी दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण का उत्तेज प्राप्त नहीं हुआ है। केवल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के निकट अवश्य बीकानेर संभाग के पूर्व क्षेत्र में स्थित फोगा गाँव से मिले हैं।—महमारी, वर्ष १६, अक्ष ३, राजस्थान यू० दी एंजेज (पूर्व), पृ० ६८५-८६
३. जकरनामा, भाग २, रित्रवी, तुगलबालोन भारत, भाग २, पृ० २४४-४६, अलीगढ़, १६५७
४. बर्भचण्ड (पूर्व), पृ० २६; दयालदास सिङ्गानच-दयालदास दी क्राश (प्रकाशित), भाग २, पृ० ७-१०, सयादक-दशरथ शर्मा सादूस, ओरिएण्टल सोरोज, अ० सं०, पृ० ११४८

अतिरिक्त भादू, भूबर, जासड, कसहेर, नैण इत्यादि अन्य छोटी घाटाए भी थी।^१

जाट क्षेत्र के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम भाग पर जोहिया जाति का नियन्त्रण था। ये प्राचीन योद्धा जाति के वंशज थे और इनमें अधिकांश ने दूरतम स्वीकार कर लिया था। ये मनीसों के रूप में कई साम्राज्यों में बटे हुए थे। भट्टी व राठ मुसलमान इन्हीं के गाँवों के आगपास बसे हुए थे।^२ राज्य का संपूर्ण पश्चिमोत्तर प्रदेश, जो जैसलमेर राज्य की सीमा से भटिण्डा तक फैला हुआ था, भाटी राजपूतों के नियन्त्रण में था। उत्तर-पश्चिम भाग में बसने वाले भाटी मुगलमान हो गये थे तथा भट्टी कहलाने लगे थे। इनका मुख्य केन्द्र भटनेर था। दक्षिण में बसने वाले भाटी राजपूत ही बने रहे। शक्ति व सद्यता की दृष्टि से इनकी स्थिति भट्टियों से अधिक व्यापक थी। इनका मुख्य ठिकाना धूमल था।^३ दक्षिण भाग में सागरना (परमार) राजपूत बसे हुए थे तथा जागलू इनका मुख्य केन्द्र था।^४ दक्षिण-पूर्वी भाग में चौहानों की शाखा मोहिल शासन करती थी। इनका क्षेत्र छापरा-झोणपुर के नाम से प्रसिद्ध था। यह मोहिलवाडी भी कहलाता था। चौहानों के अन्य प्रमुख केन्द्र रीणी, द्वेदेवा इत्यादि थे।^५

इन जातियों के शासक राणा, राव, मुस्तिया तथा चौधरी कहलाते थे। चौहानों के शासक राणा, भाटियों के राव तथा जाटों व जोहियों में चौधरी या मुस्तिया की पदवी थी।^६ चौहानों और भाटियों का राज्य शासन के परिवार का सामूहिक उत्तरदायित्व समझा जाता था। इनके माय परिवार के सदस्यों के बीच बँटे हुए थे। इनकी सेना मूलतः परिवार के सदस्यों की टुकड़ियों पर ही गठित की जाती

१ जाट राज्यों के सम्बन्ध में एच. बहादुर त्रिपाठी, 'सात पट्टी, तत्कालीन संस्था' अर्घाऊ, उनके सात बंधों और तत्कालीन छोटे राज्य थे—दयालदास की कथाएँ (प्र०), भाग २, पृ० ७१०, टाड (पूर्व), पृ० ११२४-२८

२ दयालदास की कथाएँ (प्र०), २ पृ० ८, १६, टाड, पृ० ११३०-३१, राजस्थान यू.पी. एजेंस, भाग १, पृ० ३१-३४

३ कर्मचंद (पूर्व), पृ० ६८-६९, दयालदास की कथाएँ (प्र०) १, पृ० ४-५, टाड, भाग २, पृ० ११६५-६६

४ रासीसर तिलालेख—अमावस अंठ, वि० सं० १२८८/१२३१ ई०, रासीसर नाम बीकानेर शहर के दक्षिण पूर्व में मोखा सदक पर स्थित है, नैणसी की कथाएँ (सं० बंदीप्रसाद साकरिया), भाग १, पृ० १६५-६६, दयालदास की कथाएँ (प्र०) २, पृ० २-३

५ क्यामण्डा रासी (सं० डा० दत्तारथ शर्मा, अमरबंद नहिटा), पृ० ७६, राजस्थान पुरातनत्व द्वायमाता जायपुर नैणसी की कथाएँ भाग ३ (सं० बंदीप्रसाद साकरिया), पृ० १५३, १५८-१६०, १६७, दयालदास की कथाएँ (प्र०) २, पृ० १२, १३, डा० दत्तारथ शर्मा—बर्लीन चौहान हाइनेस्टीज, पृ० २२ मिलनी १६५०

६ नैणसी की कथाएँ, भाग ३, पृ० १५८, दयालदास की कथाएँ (प्र०) २, पृ० २, १, ७, ८

थी। इन जातीय राज्यों में प्रशासकीय एकता का अभाव था। इनके भोसिये व प्रासिये स्वतंत्र रूप से अपने-अपने क्षेत्र वा आन्तरिक प्रशासन चलाते थे।^१ जाटों की प्रशासकीय व्यवस्था भी इससे भिन्न नहीं थी। जाटों की प्रत्येक शाखा के पास अनेक गांव थे तथा उनका मुखिया प्रासिया व चौधरी कहलाता था। एक शाखा के सभी प्रासिये मिलकर अपने चौधरी का निर्वाचन करते थे। यह चौधरी उनरी एकता का प्रतीक था। जाट जाति के प्रासियों के पास अपने क्षेत्र में प्रशासन के असौमित्र अधिकार थे। जोहिया भी अनेक कबीलों में बटे हुए थे। उन कबीलों के मुखिया मिलकर अपने जाति-नेता का चुनाव करते थे।^२

इन प्रकार राठीड़ों के आक्रमण से पूर्व जागत देश में राजनैतिक विखलता व प्रशासनिक अव्यवस्था विद्यमान थी। इस क्षेत्र में निवास करने वाली समस्त जातियां तीन तरह के सघर्षों में उलझी हुई थीं (१) एक जाति की विभिन्न शाखाओं में जातिप्रमुखता तथा नेता पद के लिए सघर्ष, (२) इस क्षेत्र में राजनैतिक तथा सैनिक सर्वोच्चता को पाने के लिए विभिन्न जातियों में पारस्परिक सघर्ष तथा (३) इस क्षेत्र पर होने वाले बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध सघर्ष।

जागत देश पर राठीड़ जाति के असावा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश के बलूचियों की भी ललचाई दृष्टि थी। यहाँ की जातियां भी इन दोनों जातियों या कबीलों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के प्रति शक्ति थी। भाटी तथा जोहियों ने इस क्षेत्र पर मुलतान तथा सिंध से होने वाले आक्रमणों को पूरी तरह रोक रखा था।^३ उन्होंने भगोड़े राव जोधा के इस क्षेत्र में निर्वासित जीवन को स्थायी राज्य की स्थापना में भी परिवर्तित नहीं होने दिया था।^४ क्षेत्र के पूर्वी भाग में बसे मोहिल चौहान भी मारवाड़ के राठीड़ों के विस्तार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे।^५ परन्तु ये सभी प्रयास आपसी जातिगत सघर्ष तथा कलह के कारण धीरे-धीरे प्रभावहीन हो गये थे।

१. गणमर्धा रासी (पृष्ठ ५०-१०, कर्मचन्द्र (पृष्ठ), पृ० २३, बीरानेर रै राठीड़ों की क्यात सीहेंजी सु, पृ० ३४-३६, न० १६२/१४, अ० स० पु० बी०, दयालदास की क्यात (पृ०), पृ० २, ३

२. दयालदास की क्यात (पृ०) २, पृ० ७ १०, १३-१४, देवराज, जाट इतिहास, पृ० ६१२-२०

३. नैगसी की क्यात, भाग ३, पृ० १३, ३६, टाड, भाग २, पृ० १२२२

४. नैगसी की क्यात, भाग ३, पृ० ५ रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग १, पृ० ८४, जोधपुर, १६३८ ई०

५. छद राव जैतसी की बीटू सुर्वी की केयो, छद न ८, अ० स० पु० बी०, नैगसी की क्यात भाग ३, पृ० १६०, रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग १, पृ० ६७-६६

भाटी-साखला, भाटी-जोहिया, भाटी-जाट, जोहिया-जाट तथा चौहान-जाट के पारस्परिक वैमनस्य ने इस क्षेत्र की राजनैतिक अस्थिरता को ही बढ़ावा नहीं दिया अपितु, पड़ोसी शक्तियों के लिए आक्रमण की अनुबल परिस्थितियाँ भी उत्पन्न की।^१ भाटियों की संयुक्त शक्ति के सम्मुख मुलतान व सिन्ध के आक्रमण तो सफल नहीं हुए;^२ परन्तु साखलों की सहायता से मारवाड़ के राठौड़ों को इस मह भूमि पर अपने पैर जमाने का अवसर अवश्य मिल गया।

जोधपुर का शासक राय जोधा अपने बढ़ते हुए परिवार में पारस्परिक पल्लु की संभावना को रोकने के लिए नई भूमि की खोज में चिन्तित था।^३ ऐसी दशा में जागलू के नापा साखला द्वारा राठौड़ों को जागल देस में आक्रमण का निमन्त्रण उनकी सत्ता के विस्तार के लिए मन भागी मुराद को पूरा करने वाला कार्य बन गया।^४ इससे पूर्व राठौड़ों के जागल देस पर आक्रमण स्थायी रूप से सफल नहीं हुए थे। नापा साखला भी अपने गावों के ऊपर बलूचियों व भाटियों के निरन्तर होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध अपने अस्तित्व को राठौड़ शक्ति के सरक्षण में सुरक्षित रखने की योजनाएँ बना रहा था। अब राय जोधा ने स्थानीय शक्ति के सहयोग से प्रोत्साहित होकर अविन शुक्ला १० वि० स० १५२२ (३० सितम्बर,

१ नैणमी की कथात, भाग ३, पृ० १५६ १२, नापा सांखला की बात, पृ० १०१-१२, पट्टकर बाता, न० २०६।२-अ० सं० पु० की०

दयालदाम की कथात (प्र०) २, पृ० ३-१२, टाड, भाग १, पृ० ११२५ ३०

२ नैणमी की कथात भाग ३, पृ० ३३-३७

३ राय जोधा का अपनी हाड़ी रानी जममादे पर अधिक स्नेह था। उसके पुत्र नीला की मृत्यु हो जाने पर, उससे दूगरे छोटे पुत्र सागल को गद्दी देने के लिए, सागली रानी नोरगदे के पुत्र बीका को निजी अर्थ क्षेत्र में बनाकर वह जोधपुर राज्य की उत्तराधिकार की समस्याओं से बचाना चाहता था। 'कर्मचन्द्र बसौलीतंकर' काव्य में लिखा है "तब रात्रा (राय जोधा) ने पत्नी (जममादे) के कपट से मोहित होकर अपने बेटे विक्रम को जागल देस में निवास देने की इच्छा से अपने पास बुलाकर कहा, हे पुत्र! बाप के राज्य को बेटा भोगे इसमें कोई खचरज की बात नहीं, परन्तु जो नया राज्य प्राप्त करे वही बेटो में मुख्य गिना जाता है। पृथ्वी पर कठिणता से धन में आने वाला जागल नामक एक देस है साहमी हैतु इसलिए मैंने तुम इस कार्य के लिए नियुक्त किया है।" "कर्मचन्द्र, (जी०एच० ओसा), पृ० २५

'नापा साखला की कथात' में घटना का विवरण इस प्रकार है कि रानी नोरगदे ने अपने पुत्र की जीविता के लिए जागीर हेतु अपने भाई नापा सांखला को राय जोधा के पास निवेदन हेतु भेजा। नापा साखला जब रायजी के रूप से भागवत नहीं हुए तब उन्होंने अपने भाजो को जागीर हेतु जागल देस पर आक्रमण की योजना बनाई थी।—नापा सांखला की बात, पृ० १०१ ११

४ नैणमी की कथात, भाग ३, पृ० १६, नापा साखला की बात, पृ० १०१ १२, दयालदाम की कथात (प्र०) २ पृ० १२

१४६५ ई०) के दिन अपने पुत्र राव बीका को अपने योग्य भाइयों के सरक्षण में नापा सांखला के साथ जागल देश की ओर रवाना किया।^१ प्रारम्भ में राव बीका ने सांखलो के क्षेत्र में टिककर राठौड़ों की स्थिति को दृढ़ किया। लेकिन भाटियों के विरोध के कारण उनकी सफलता सदिग्ध थी। कालान्तर में भाटियों पर मुलतान के आक्रमण ने राठौड़ों को यह अवसर दिया कि वे सकट में भाटियों की सहायता करके उनकी तटस्थता व सहानुभूति प्राप्त कर लें। राव बीका के भाटियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने के उपरान्त इस क्षेत्र में उसकी स्थिति दृढ़ हो गई।^२ बीका ने १४८८ ई० में राठीघाटी नाम के स्थान पर अपने नव स्थापित राज्य की राजधानी की नींव डाली।^३ अब वह निश्चिन्त होकर अपनी क्षेत्रीय विस्तार की आकांक्षा को पूरा कर सकता था।

इनके उपरान्त राव बीका ने मरु प्रदेश के मध्यवर्ती तथा पूर्वी क्षेत्र की ओर दृष्टि डाली, जहाँ जाटों की आपसी फूट राठौड़ों को अपनी सत्ता-विस्तार के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रही थी। गोदारा जाटों ने तथा फिर शर्नै-शर्नै: एक-

१ दयालदास व्यास (प्र०) २, पृ० ३-४

२. वही, पृ० ४-७

३. राजधानी बनाने के स्थान के प्रश्न को लेकर राठौड़ों व भाटियों के मध्य फिर सघर्ष छिड़ा था। भाटों किसी भी सीमा पर अपनी सीमा के समीप राठौड़ों की राजधानी बनने देना नहीं चाहते थे। राव बीका को उनके विरोध के कारण ही बोरपदेगर स्थान का चुनाव छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने राठीघाटी स्थल का चयन किया जो उस समय मुलतान-फलोधी तथा मुलतान-नागीर के मार्ग पर स्थित था। दयालदास री व्यास (प्र०) २, पृ० ५
राजधानी के गढ़ की स्थापना के सम्बन्ध में इस लेख में एक प्रबलित रोड़ा है :

पन्दरे से बंतावदे, मुद बैसाथ गुयेर।

बाबर बीक भरपोया, बीके बीकानेर ॥

मार्च १२, अर्बैल, १४८८ ई० की बीकानेर शहर की नींव डाली गई थी। जी० एच० ओझा, बीकानेर राज्य का इतिहास भाग १, पृ० ६६। जगदीशसिंह गहलोत इने १३ अर्बैल मानते हैं (जगदीशसिंह गहलोत कृष्ण बीकानेर राज्य का इतिहास, अप्रकाशित)। कुछ लेखकों का विचार है कि जहाँ बीकानेर नगर बसाया गया वहाँ पहले से आबादी थी। संभवतः इसी बस्ती को विस्तार करके राव बीका ने बीकानेर बसाया हो। तैमितीरी १४८५ ई० में नगर की नींव रखना मानते हैं। अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर में सप्तपद्यायी वस्तु प्रकाशनी मूर्ति की एक प्रति है, जिसके भुजिका लेख से भी यह बात प्रमाणित होती है कि बीकानेर नगर १४८८ ई० से पूर्व बसा गया था।

“छन्द राव बीकसी रो” (तैमितीरी), भूमिका पृ० ३, बिबनोदिका इण्डिका, ए० एम० बी० सीरीज नं० १४३०, बनकला, गोविन्द अग्रवाल, बुक सप्लायर का इतिहास, पृ० १४८, पृ० १४७४

एक करके सभी जाट जातियों ने राठीडों की शक्ति व कूटनीति के आगे समर्पण कर दिया।^१ राव बीका ने जोहियों को पराजित करके तथा उन्हें अधीनस्थ बनाकर जाट क्षेत्रों को सुरक्षा भी प्रदान की।^२ फिर, उसने अपनी शक्ति-वृद्धि का लाभ उठाकर भाटियों को भी अपने नियन्त्रण में ले लिया तथा उत्तर व उत्तर-पूर्व के चौहानों का भी दमन किया।^३

मोहिलवादी के क्षेत्र को, जिसे राव जोधा ने मोहिल चौहानों से छीनकर अपने छोटे पुत्र बीदा को प्रदान किया था,^४ मोहिलों व हिसार के फौजदार सारगखा व सयुक्त आक्रमण से सुरक्षित करके उसने वहाँ अपनी विजय पताका फहराई।^५ चाचा रावत काफल की मृत्यु का बदला लेने के लिए सारगखा को युद्ध में पराजित करके मार डाला गया।^६ इससे राज्य के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को दिल्ली के मुल्तानों के आक्रमण से सुरक्षा व स्थिरता प्राप्त हुई।^७ बीका की समस्त विजयों का परिणाम यह निकला कि उसने नव स्थापित राज्य की सीमाएँ, दक्षिण में जैसलमेर, मारवाड़ व नागौर राज्य की सीमाओं तथा पश्चिम में मुलतान व सिन्ध के क्षेत्र की सीमाओं तथा पूर्व में आमेर व शेखावाटी के क्षेत्र की सीमाओं को छूने लगी।

राव बीका की इन विजयों का आधार राठीडों का सयुक्त प्रयास था जो नव स्थापित राज्य जोधपुर से आये राठीडों के सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में था, जिसमें राव बीका की स्थिति उनके मुखिया अथवा टिकायत के रूप में थी।^८ राठीडों की सफलताएँ चमत्कारिक थी, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में प्रथम बार राजनैतिक तथा प्रशासनिक एकता स्थापित हुई। पर यह एकता, राज्य में सतही तौर पर ही दृष्टिगत होती है, क्योंकि विभिन्न राठीड कुल मुखिया अपने कुलपति का सम्मान अवश्य करते थे, परन्तु उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं थे।^९ अधीनस्थ

१ दयालदास की कथा (प्र०) २, पृ० ४५

२ वही, पृ० १०

३ वही, पृ० ११-१६

४ राठीडा की बहावली ने पीढ़ियाँ नें फुटकर जाता, न० २३३/६ अ० स० पु० बी०, नैणसी की कथा, भाग ३, पृ० १६६

५ राठीडा की बहावली ने पीढ़ियाँ नें फुटकर जाता, न० २३३/६, दयालदास की कथा (प्र०) २, पृ० ११-१७

६ वही, पृ० १८-१९

७ वही, पृ० १८-१९

८ राठीडा की बहावली तथा पीढ़िया, पृ० २१-२३, न० २३२/३ अ० स० पु० बी०, राठीडा की बहावली ने पीढ़िया नें फुटकर जाता, २३३/६, बीकानेर के राठीडा की कथा सीहवी सू, न० १६२/१४ अ० स० पु० बी०

९ वही, बीदावत बन्धाणमल ने शाहू राव लूणकरव व जैतसी की आज्ञा के विरुद्ध कार्य-वाही की थी तथा नागौर ने हाजीखान पटान से बीकानेर के विरुद्ध सोठ-पाठ की थी।

स्थानीय जातियों की निष्ठा भी विवादास्पद थी।^१ इस प्रकार राठीड राज्य की स्थापना एक कमजोर समय के रूप में हुई, जो किसी भी विशेष विपत्ति के समय अनगिनत समस्याओं को उत्पन्न कर सकता था।

रूपारो के अनुसार, राव बीका ने अपनी साहसिक विजयों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लगभग ३००० गावों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।^२ यह सख्या आगामी वर्षों में मिले आवंटों के आधार पर अतिशयोक्तिपूर्ण नजर आती है। मुगल साम्राज्य में बीकानेर घटन जागीर का जो क्षेत्र निर्धारित हुआ था, उसमें कम से कम १२०० तथा अधिक से अधिक १५०० गावों की संख्या थी।^३ अठारहवीं शताब्दी में राज्य की सीमाओं में विस्तार होने पर भी, जिसकी सीमाएँ निःसंदेह राव बीका के अधिकृत क्षेत्र से अधिक थी, यह संख्या बढ़कर १७०० के लगभग पहुँच गयी थी।^४ क्षेत्रफल की दृष्टि में भी राव बीका के काल में गावों की संख्या उचित नहीं जान पड़ती है।^५

राव बीका के उत्तराधिकारियों ने अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। अपने शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में राव लूणकरण (१५०५-१५२६ ई०) व जैतसी (१५२६-१५४२ ई०), विद्रोही कुल-मुखियों (सामन्त) व अधीनस्थ शक्तियों को नियंत्रित करने में ही उलझे रहे।^६ परन्तु, अवसर पाते ही राव लूणकरण ने उत्तरी सीमा की ओर चापलबाजा की जीत कर भटनेर तक अपनी सीमा बढ़ा ली।^७ उत्तर की ओर अधिक उपजाऊ भूमि पर अधिकार करने

१ राव लूणकरण व राव जैतसी की अपने भवनों के विरुद्ध पराजय व मृत्यु के लिए एक कारण जीर्णोद्धार आदिशों का युद्धक्षेत्र से चला जाना था। दयालदास री दशात (प्र०) २, पृ० ३६-३६

२ दयालदास री दशात (प्र०) २, पृ० ११-१२, टॉड, भाग २, पृ० ११४६, पाउलेट गर्जेटियर, आफ बीकानेर, पृ० ४। राज्य में एक कहावत प्रचलित थी—'बीकानेर रा धनी सत्ताइतेरा, (२७०० गावों का भूमापिक)

३ पट्टा बही वि० सं० १७२२/१९६८ ई० (पूर्व), वही खालसा री गाँवा री, वि० सं० १७२५/१९६८ ई० (पूर्व)

४ दयालदास सिंहायक आर्याध्यान कल्याण, पृ० बीकानेर री ठिवाणा री पोडियों में पट्टा री विगत नं० १८०/२ (ब) अ० सं० यु० की०, पाउलेट ने भी गाँवों की संख्या १८१४ दी है। पाउलेट गर्जेटियर, पृ० ८६

५ रूपांतों में राव बीका के काल में केवल जाट-अनपदों की संख्या दो हजार से ऊपर बताई जाती है, जब कि सम्पूर्ण जाट जाति के गाँव बार हजार वर्गमील के क्षेत्र में बसे हुए थे, जिसे देखकर इतनी अधिक गाँवों की संख्या सम्भव जान पड़ती है। विशेष अध्ययन के लिए देखिए—चुरू मण्डल का इतिहास, पृ० १०८-१०

६ दयालदास रूपात (प्र०) २, पृ० २७-२८, ३८-३९

७ वही, पृ० २८

एक करके सभी जाट जातियों ने राठीडों की शक्ति व कूटनीति के आगे समर्पण कर दिया।^१ राव बीका ने जोड़ियों को राजित करके तथा उन्हें अधीनस्थ बनाकर जाट क्षेत्रों को सुरक्षा भी प्रदान की।^२ फिर, उगने अपनी शक्ति-शुद्धि का लाभ उठाकर भाटियों को भी अपने नियन्त्रण में ले लिया तथा उत्तर व उत्तर-पूर्व के चौहानों का भी दमन किया।^३

मोहिलवाडी के क्षेत्र को, जिसे राय जोधा ने मोहिल चौहानों से छीनकर अपने छोटे पुत्र बीदा को प्रदान किया था,^४ मोहिलों व हिसार के फौजदार सारंगखा व सयुक्त आक्रमण से सुरक्षित करके उसने वहाँ अपनी विजय पताका फहराई।^५ चाचा रावत काधल की मृत्यु का बदला लेने के लिए सारंगखा को युद्ध में पराजित करके मार डाला गया।^६ इससे राज्य के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण से सुरक्षा व स्थिरता प्राप्त हुई।^७ बीका की समस्त विजयों का परिणाम यह निकला कि उसके नव स्थापित राज्य की सीमाएँ, दक्षिण में जैसलमेर, मारवाड़ व नागौर राज्य की सीमाओं तथा पश्चिम में मुलतान व सिन्ध के क्षेत्र की सीमाओं तथा पूर्व में आमेर व शेखावाड़ी के क्षेत्र की सीमाओं को छूने लगी।

राव बीका की इन विजयों का आधार राठीडों का सयुक्त प्रयास था जो नव स्थापित राज्य जोधपुर से आये राठीडों के सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में था, जिसमें राव बीका की स्थिति उनके मुखिया अथवा टिकायत के रूप में थी।^८ राठीडों की सफलताएँ चमत्कारिक थीं, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में प्रथम बार राजनैतिक तथा प्रशासनिक एकता स्थापित हुई। पर यह एकता, राज्य में सतही तौर पर ही दृष्टिगत होती है, क्योंकि विभिन्न राठीड कुल मुखिया अपने कुलपति का सम्मान अवश्य करते थे, परन्तु उनकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं थे।^९ अधीनस्थ

१. दयालदास की द्यात (प्र०) २, पृ० ४-५

२. वही, पृ० ७-९०

३. वही, पृ० ११-१६

४. राठीडा की बहावली नै पोटियाँ नै फुटवर बाता, न० २३३/६ ख० स० पु० बी०, नैगली की द्यात भाग ३, पृ० १६६

५. राठीडा की बहावली नै पोटियाँ नै फुटवर बाता, न० २३३/६, दयालदास की द्यात (प्र०) २, पृ० १५-१७

६. वही, पृ० १८-१९

७. वही, पृ० १८-१९

८. राठीडा की बहावली तथा पोटियाँ, पृ० २१-२३, न० २३२/५ ख० स० पु० बी०, राठीडा की बहावली नै पोटियाँ नै फुटवर बाता, २३३/६, बीकानेर रै राठीडा की द्यात सीद्देओ मू, न० १६२/१४ ख० स० पु० बी०

९. वही, बीदावन कल्याणमस में शासन राव लूणकरण व बीतली की आज्ञा के विरुद्ध कार्य-बाही की थी तथा नागौर के हजोखान पटान से बीकानेर के विरुद्ध साठ-वाठ की थी।

स्थानीय जातियों की निष्ठा भी विवादास्पद थी।^१ इस प्रकार राठीह राज्य की स्थापना एक बमजोर सघ के रूप में हुई, जो किसी भी विशेष विपत्ति के समय अनपेक्षित समस्याओं को उत्पन्न कर सकता था।

ख्यातो के अनुसार, राव बीका ने अपनी साहसिक विजयों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लगभग ३००० गावों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।^२ यह सख्या आगामी वर्षों में मिले आंकड़ों के आधार पर अतिशयोक्तिपूर्ण नजर आती है। मुगल साम्राज्य में बीकानेर वतन आगीर का जो क्षेत्र निर्धारित हुआ था, उसमें कम से कम १२०० तथा अधिक से अधिक १५०० गावों की संख्या थी।^३ अठारहवीं सताब्दी में राज्य की सीमाओं में विस्तार होने पर भी, जिसकी सीमाएँ निःसंदेह राव बीका के अधिकृत क्षेत्र से अधिक थीं, यह संख्या बढ़कर १७०० के लगभग पहुँच गयी थी।^४ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राव बीका के काल में गावों की संख्या उचित नहीं जान पड़ती है।^५

राव बीका के उत्तराधिकारियों ने अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। अपने शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में राव भूणकरण (१५०५-१५२६ ई०) व जैतसी (१५२६-१५४२ ई०), विद्रोही कुल-मुखियों (सामन्त) व अधीनस्थ शक्तियों को निमग्नित करने में ही उलझे रहे।^६ परन्तु, अवसर पाते ही राव भूणकरण ने उत्तरी सीमा की ओर धावसबाड़ा की जीत कर भटनेर तक अपनी सीमा बढ़ा दी।^७ उत्तर की ओर अधिक उपजाऊ भूमि पर अधिकार करने

१ राव भूणकरण व राव जैतसी की मगने सख्यों के विद्वत् परामर्श व मृत्यु के लिए एक कारण जोड़ियाँ व भाटियाँ का युद्धोत्सव से बना जाना था। दयालदास री दयात (प्र०) २, पृ० १६-१८

२ दयालदास री दयात (प्र०) २, पृ० ११-१२, टॉड, भाग २, पृ० ११४६, पाउलेट मनेटियर, आर बीकानेर, पृ० ४। राज्य में एक बड़ावत प्रचलित थी—'बीकानेर रा घणी सत्ताइसेरा, (१७०० गावों का भूमांलिक)

३ पट्टा बही वि० सं० १७२५/१९९८ ई० (पूर्व), बही खालसा री गाँवा री, वि० सं० १७२५/१९९८ ई० (पूर्व)

४ दयालदास सिंहायब आर्याध्यान कल्याण, पृ० बीकानेर री दिवाणा री घोड़ियों ने पट्टा री विगत नं० १८०/२ (ब) अ० सं० पु० घो०, पाउलेट ने भी गावों की संख्या १८१४ दी है। पाउलेट मनेटियर, पृ० ८९

५ ख्यातों में राव बीका के जाल में कैपल जाट-जनपदों की संख्या की हजार से ऊपर बनावर्दी जाती है, जब कि सम्पूर्ण जाट जाति के गाँव ज़रूर हजार वगंभीत के क्षेत्र में बसे हुए थे, जिसे देखकर इतनी अधिक गावों की संख्या अमंभव जान पड़ती है। विशेष अध्ययन के लिए देखिए—चुरु मण्डल का इतिहास, पृ० १०८-१०

६ दयालदास दयान (प्र०) २, पृ० २७-२८, ३८-३९

७ बही, पृ० २८

की लालसा ने उसे नारनोल के फौजदारके साथ संधर्ष में मृत्यु का वरण कराया।^१ राव जैतसी भी इस दिशा में उत्साहित था, परन्तु मुगल व मारवाड़ के आक्रमणों के कारण वह विशद प्रगति नहीं कर सका। मिर्जा कामरान ने उससे भटनेर छीन लिया^२ तथा राव मालदेव की सेनाओं ने उसे मारकर राजधानी पर अधिकार कर लिया।^३ राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल (१५४२-१५७१ ई०) के प्रारम्भिक वर्ष राजगद्दी को प्राप्त करने में ही लग गये।^४ काबलोत ठाकुरसी ने भारत से मुगलों के पलायन का लाभ उठाकर भटनेर पर पुन अधिकार कर लिया^५ तथा शर्न-शर्न राव जैतसी के बाल का सम्पूर्ण क्षेत्र पुन उनके पुत्र के अधिकार में आ गया। केवल पश्चिमी क्षेत्र के माटियों व जोहियों के उत्पादों को नियमित नहीं किया जा सका था।^६

सन् १५७० ई० में राव कल्याणमल द्वारा मुगलों से संधि करने के पश्चात् ही राज्य को शक्ति व स्थिरता प्राप्त हुई।^७ मुगल सरकार के आश्वासन पर राव कल्याणमल व उसके उत्तराधिकारी राजा रायसिंह ने विद्रोही सामन्तों को कुचलने में कोई कसर नहीं उठा रखी।^८ परन्तु राज्य के चारों ओर मुगल सत्ता के प्रसार के कारण राठौड़ों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित भटनेर, पूनीया जाटों का क्षेत्र व हिसार के कुछ भाग स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य के अंग बन गए।^९ बीकानेर राज्य भी यहाँ के शासकों को मुगल सम्राट् द्वारा दिए गए भनसब के विरुद्ध वतन के रूप में वतन जागीर के नाम से गठित किया, जिसमें परगना बीकमपुर, बरसलपुर, बीकानेर, प्रगल, द्रोणपुर, भाड़ग व सीधमुख के परगने सम्मिलित थे।^{१०} परगना भटनेर, पूनिया व हिसार इन्हें सदैव मुगल जागीर के रूप में प्राप्त होते रहे थे।^{११} परगना

१ वही, पृ० ३४-३५

२ यद्यपि राव जैतसी ने मुगलों को खदेड़कर राजधानी को बचा लिया था पर भटनेर राठौड़ों के हाथ से निवृत गया था।—छद राव जैतसी री (पू०), छ दन० १७५-८५, दयालदास री ख्यात (प्र०) २ पृ० १४ ५६

३ वही, पृ० ५०

४ वही पृ० ६४ ७०

५ वही, पृ० ८२ ८४

६ टॉड, भाग २ पृ० ११३० ३१

७ दलपत विलास, पृ० १४ १५ (स०) रावत सारस्वत मादूल, राजस्थानी रितब इन्स्टी-ट्यूट, बीकानेर, १९६०, दयालदास री ख्यात, (प्र०) २, पृ० ६५

८ टॉड, भाग २, पृ० ११३० ३३

९ आदले अकबरी भाग २, पृ० २६३ (अनु० जेरेट), कलकत्ता, १८९१ ई०

१० राजा मूरजसिंह री जागीर री विवर पृ० ८८-९०, महाराजा मनुपसिंह जी री मृतत्व ने तत्व री विवर, पृ० ८८ ९०, फुटकर बाता, न० २०६/२, अ० स० पृ० ५० बी०

११ वही, पृ० ८६ ९०

फत्तोधी व सरकार नागौर के बई परगने भी राजा रायसिंह (१५७४-१६१२ ई०) के पास थे, परन्तु राजा सूरसिंह के समय (१६१३-१६३१) में फत्तोधी व वर्णसिंह के समय (१६३१-१६६६ ई०) नागौर इनसे छीनकर मारवाड़ के राठोडों सुपुर्द कर दिए गए थे।^१ महाराजा अनूपसिंह के समय (१६६६-१६९८ ई०) ओहियो व भट्टियों के उत्पात से हिसार व भटनेर के क्षेत्र भी इनके हाथ से निकल गए।^२ उस काल में मुगल सत्ता भी सम्राट औरंगजेब के लम्बे दक्षिण प्रवास तथा उत्तरी भारत में हो रहे अनेक विद्रोहों के कारण प्रभावहीन हो रही थी। महाराजा मुजानसिंह के समय (१७००-१७३५ ई०) में उत्तर मुगल कालीन सम्राटों से सम्बन्ध टूट गया था,^३ परन्तु राज्य में हो रहे आंतरिक, पड़ोसी, विद्रोहों तथा मारवाड़ के आक्रमणों के कारण वह तथा उसका उत्तराधिकारी महाराजा जौरावर सिंह (१७३५-१७४६ ई०) सीमा-विस्तार का दायित्व नहीं निभा पाये।^४ सन् १७३६ ई० में भटनेर पर कुछ समय के लिए अधिकार स्थापित हो गया था।^५ महाराजा गजसिंह (१७४६-१७८७ ई०) ने पूनीया परगना स्थायी रूप से राज्य में मिला लिया था।^६ इससे पूर्व यह परगना महाराजा अनूपसिंह के छोटे पुत्र महाराज आनन्दसिंह की जागीर में था।^७ कुछ समय के लिए हिसार पर भी बीकानेर की सत्ता स्थापित हो गई थी तथा राठोडी मेनार्स मिरसा तक पहुँच गई थी।^८ उत्तर दिशा में अधिकतर क्षेत्रों पर इसलिए स्थायी अधिकार नहीं रह सका, क्योंकि बीकानेर की सेना मारवाड़ के शासक महाराजा विजयसिंह के सहयोग्य मराठों के विरुद्ध लड़ रही थी।^९

महाराजा सूरसिंह के काल (१७८७-१८२८ ई०) में बीकानेर की विस्तार-वादी नीति की एक नयी स्फूर्ति मिली। राज्य का विस्तार इस काल में चारों ओर

१ वही, ८६-८७

२ दयालदास की व्याप्त (अ०) २, पृ० २१९

३ बीकानेर की व्याप्त महाराजा मुजानसिंहजी सु महाराजा गजसिंहजी ठाई ने दुबरी फुटकर बाँटा, पृ० २, अ० १८६/११, दयालदास विद्याधर-बीरानेर १ राठोडी की व्याप्त (अग्रजानि), भाग २, पृ० २६२, अ० १८८/१ अ० —अ० स० पृ० बी०

४ बीकानेर की व्याप्त महाराजा मुजानसिंहजी सु महाराजा गजसिंहजी ठाई (पूर्व), पृ० ५-७, मोहता भीमसिंह द्वारा मारवाड़ के महाराजा अजयसिंह द्वारा बीकानेर घेरे का वर्णन—मोहता रिवाइज, माइक्रो फिल्म, रोल न० ८, रा० रा० अ० बी०

५ दयालदास की व्याप्त (अ०) २, पृ० २६७

६ वही, पृ० २८४

७ परवाना वही, वि० अ० १७४६/१६६२ ई० अ० १, रायपुरिया रिवाइज, बीकानेर, रा० रा० अ० बी०, दयालदास की व्याप्त (अ०) २, पृ० २६३

८ दयालदास की व्याप्त (अ०) २, पृ० २८५

९ वही, पृ० २८८

हुआ। महाराजा ने जाहियों व भट्टियों की शक्ति को कुछतक मूलतमत्र व पतह-गढ़ का निर्माण किया।^१ सन् १८०५ ई० में अटनेर स्वायत्ती रूप से राज्य में मिलाने पर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया।^२ राज्य की पश्चिमी दिशा में महाराजा की गतिविधियाँ और चमत्कारिक थी। सन् १८०१ ई० में अनूपगढ़ की दिशा में मुलतान की ओर दाऊद पुत्रों व भीरगढ़, जामगढ़, मारोठ व मौजगढ़ छीन लिया गया।^३ सन् १८०२ ई० में निचने मिन्ध प्रांत की ओर सेनाएँ भेजी गईं व खानगढ़ पर अधिकार कर लिया गया।^४ सन् १८०७ ई० में मारवाड़ के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर पारससिंह का पक्ष लेकर फौजी अधिकृत कर दिया गया^५, परन्तु ये विजय स्थायी रूप से महाराजा के पास नहीं रही। इस सक्रिय नीति का यह परिणाम अवश्य हुआ कि उत्तरी व उत्तरी-पश्चिमी सीमा को स्थिरता प्राप्त हो गयी। सन् १८१८ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ संधि करते समय राज्य की यही सीमाएँ थी तथा इसी क्षेत्र में आगे चलकर आपुनिक बीकानेर राज्य का रूप धारण किया।

१. दयालदास की व्यास (अ०) २, पृ० ३१३

२. वही, पृ० ३१४-१५

३. वही, पृ० ३१५

४. वही, पृ० ३१६-१७

५. वही, पृ० ३१८-२०, टॉड, २, पृ० ११४२-४३

द्वितीय अध्याय

राजपद

राजपद का स्वरूप

१३ अप्रैल, १४८८ ई० को राज बीबा द्वारा बीबानेर राज्य की स्थापना के उपरांत यहाँ का सम्पूर्ण प्रशासकीय ढाँचा नृपतत्र के आधार पर रखा किया गया था। राज्य की सर्वोच्च शक्ति राजा के पद में केन्द्रित थी। राजपद राज बीबा के राठीड़ परिवार का विशेषाधिकार था, जो बीका राठीड़ घाप के नाम से विख्यात था।^१ राजपद आनुवंशिक था और साधारणतया अधिवारी बीबा खाप की मुख्य शक्ति में से ही नियुक्त होते थे। यहाँ के शासक स्वयं को प्रभुतागमन्य समझते थे। उन्हें अपने घरा गोरेब का गर्व था और राजपूतों में सूर्यवंशी का दावा करने में अपनी श्रेष्ठता प्रस्थापित करते थे।^२ उनके समक्ष प्राचीन भारत के हिन्दू नृपतत्र आदर्श थे। राज्य की प्रजा में उनकी इतनी प्रतिष्ठा व मान था कि वे ईश्वर व प्रतिनिधि के रूप में पूजे जाते थे।^३ राजपदों में यहाँ के शासकों को 'श्री जी हजूर' और 'माई-बाप' के नाम से सम्बोधित किया जाता था।^४ वे अपने राज्य की कुलदेवी बरणीजी तथा कुलदेवता श्री लक्ष्मीनारायणजी की कृपा का पल मानते थे और उन्हींके प्रतिनिधि के रूप में 'दीवान' व नाम से शासन करते थे। राजमनदी पत्रों में सबसे ऊपर 'भीजी बीबान बखानात' लिखा होता था।^५

१ छन्द राज बीउसी से छन्द न० १०१ १२, नर्मबन्द, पृ० १, मुखगीन प्रशस्ति कुतान्त्र, बीबानेर, पविन न० ६८

२ बीबानेर के राठीड़ों की क्वात, २२६/२ "अथ सूर्यवंश प्रभुन राठीड़न बखानतन महाराज"

३ शाहदों की बहा, वि० न० १८३७/१८०० ई०, न० ११, पृ० १०१ राजपुरिया रिवाजें, रा० रा० म० बी०

४ 'दी हाउस ऑफ बीबानेर', पृ० १, बीबानेर, १९३३

५ 'बी दीवान बखानात मगरि गरी पगी रे बीरे देवी' इत्यादि बीबा बीबान बीबानेया रईस राजपूत समुदाय आचार्य तथा बा सोप बीबी बीबान हूँ लेरी खेड़ खरप रा बुवादा १ (पृ० २) रा देन सार हो मी पाया हूँ मु बुवादी री भीगजी बखान बुवादी सरब मदाय बुवादी (पृ० २), रा बुवाय देजा। गी० ३४, बीबान सप्तह—सप्तह मातुका मुद १२ वि० म० १८१०। २२ अक्षर, १८०३ ई०, बीबानेर।

राजस्थान के इस उत्तर-पश्चिमी मरु प्रदेश में स्वतंत्र राजसत्ता का इतिहास, राठौड़ों के आगमन के उपरान्त ही प्रारम्भ होता है। इससे ठीक पूर्व, यह क्षेत्र कई स्वतन्त्र व अर्ध स्वतन्त्र राजनैतिक इकाइयों में बंटा हुआ था। राव बीका ने एक-एक करके इन सबको जीतकर, न केवल एक नये राज्य की नींव डाली, अपितु राजपद को प्रतिष्ठित भी किया। अनेक भौमियों के स्थान पर इस क्षेत्र में एक शासक के नेतृत्व में नई राजनैतिक एकता स्थापित की गयी।^१

अपनी प्रारम्भिक अवस्था में, राजपद का स्वरूप, अनिश्चित व अस्थिर था। राव बीका ने अपने जीते हुए क्षेत्र की सीमाओं को गठित करने के लिए, राजपूत कुल-परम्पराओं को ही अपनाया था।^२ उसके समक्ष राव जोधा द्वारा मारवाड़ राज्य में अपने भाइयों व रिश्तेदारों के बीच हुए क्षेत्रीय बंटवारे का उदाहरण प्रस्तुत था।^३ फिर, परिस्थितियाँ भी ऐसी नहीं थी कि वह व्यवस्था में कुछ परिवर्तन ला सकता। राव बीका अपने जीवनकाल में जागल प्रदेश तथा आसपास की विभिन्न शाखाओं से लड़ता ही रहा।^४ इन युद्धों व भाइयों के साथ सम्बन्धों में उसे सदैव इस स्थिति में रखा कि वह कोई ऐसा कार्य न करे, जिससे राठौड़ों की एकात्मता भंग होती हो। वह हम तथ्य से भली-भाँति परिचित था कि सबके सहयोग से ही सत्ता सुदृढ़ की जा सकती है। अतः उसने राठौड़ कुलीय भाई बन्धु भावनाओं का सम्मान किया तथा अपने रिश्तेदारों द्वारा दी गई मेवाओं को मान्यता प्रदान की।^५ फलस्वरूप नवस्थापित राज्य, राठौड़ों की खास में, असग-असग इकाई के रूप में बंट गया। राव बीका इस अवस्था से सतुष्ट था तथा स्वयम् को राठौड़ों का नेता ही समझता रहा।^६

१ कर्मचन्द्र, पृ० ३१

२ बीकानेर के क्षत्रीयों की याद में बीकरी कुटकर बाँटी, पृ० १२-१३, न० २२५/१, अ० स० पु० बी०, बीकानेर की ख्यात सीहँसी मु०, पृ० ८४-८५

३ हकीकत बड़ी जोधपुर, पृ० ७६-७८, न० १२, हकीकत खाता बड़ी, पृ० ६०, न० २, रा० रा० अ० बी०, राव रणमल के २४ पुत्रों तथा राव जोधा के १४ पुत्रों के बीच क्षेत्रीय बंटवारा किया गया था—देवासी की ख्यात भाग १, पृ० १६३, विजित क्षेत्र को अपने परिवार के सदस्यों के बीच बाँट देना राजपूत युग की एक सामान्य प्रथा थी, जो सत्तनन काल से पूर्व भी विद्यमान थी। डा० बी० पी० मनुष्यदार शास्त्रियों इकानोनिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, प्रथम अध्याय, कलकत्ता, १९६०

४ दयालदास ख्यात (प्र०) २, पृ० ३-२८

५ उसने अपने सभी नातेदारों की आगों में दी व जिन्होंने राज्य की स्थापना के साथ जागीरें बना ली थीं, उनको मान्यता प्रदान की। आर्याव्यान कल्पद्रुम, पृ०-३८-४३, दयालदास की ख्यात (प्र०) २, पृ० २०-२३

६ राव बीका ने कभी भी कुल मुखियों के संघ में हस्तक्षेप नहीं किया था, आर्याव्यान कल्पद्रुम, पृ०, ४०-४४

राव बीका के उत्तराधिकारी इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हुए। राव सूणकरण ने कुलीय भाई बन्धु पर आधारित व्यवस्था को शासक की शक्तियों के लिए हानिकारक पाया। वह नवस्थापित राज्य की एवता तथा समृद्धि के लिए सशक्त राज-तन्त्र के सिद्धांत में विश्वास रखता था, परंतु इस दिशा में विभिन्न कुल मुखियों के प्रबल विरोध के कारण कोई प्रगति सम्भव नहीं थी। उल्टे उसकी इच्छा के कारण अनेक कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुईं। राव सूणकरण व उसके पुत्र राव जैतसी ने कुलीय सामन्तवादी ढांचे को कमजोर बनाकर राजा की सत्ता के विस्तार की योजना बनाई थी, परन्तु उसकी कीमत उन्हें प्राण गवाकर चुकानी पड़ी। दोनों ही शासक राज्य के बाह्य शत्रुओं से लड़ते समय अपने प्रमुख सामन्तों के असहयोग के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे।^१ राव जैतसी की मृत्यु के साथ ही बीकानेर पर जोधपुर के राव मालदेव की सेनाओं का अधिकार स्थापित हो गया। इन परिस्थितियों में राव जैतसी के उत्तराधिकारी राव कल्याणमल ने यही श्रेयस्कर समझा कि कुलीय परम्पराओं से समझौता करके खोये हुए राज्य को पुनः प्राप्त करके जागल प्रदेश में बीका राजवंश को बचावें। उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में दिल्ली के अफगान सुल्तान शेरशाह से भी सहायता मिली, जो राव मालदेव का दात्र था।^२ टाकुरों के सहयोग में राव कल्याणमल ने पुनः प्राप्त राज्य को स्थिरता प्रदान की।^३ यहाँ, अफगान शक्ति के सहयोग ने क्षेत्रीय राजनीति में यह तत्त्व और उभार दिया कि साम्राज्यवादी सत्ता के संरक्षण में स्थानीय सामन्तवादी शक्तियाँ सुरक्षा पा सकती हैं। इसी तथ्य ने आगे चलकर बीकानेर के राठीडों को मुगलों से सन्धि करने के लिए प्रेरित किया।

राजपद का स्वरूप सन् १५७० ई० के उपरांत एक नये परिवेश में विकसित हुआ। मुगल सम्राट अकबर की सन् १५७० ई० में नागौर यात्रा के समय राव कल्याणमल ने, उससे वहाँ जाकर बैठ की तथा मुगल अधीनता स्वीकार कर ली।^४ तत्पश्चात् धीरे-धीरे दोनों राज परिवारों के सम्बन्ध दृढ़ होते चले गये एवं बीकानेर शासक मुगल सम्राट के विद्वत्सनीय अमीर व मुगल साम्राज्य के स्थायी स्तम्भ बन गये।^५ इन सम्बन्धों से मुगल सम्राटों की स्वेच्छाचारिता का प्रभाव बीकानेर

१ शिवायक दयानदास, देश दर्शन पृ० २, ११, न० १८६/८ अ० त० पृ० बीकानेर

२ दयानदास से खान (प्रकाशित) भाग २, पृ० २८, १४, ३२

३ दयानदास से खान (प्र०), भाग २, पृ० ६४, ६७, ८३, ८४, कानूनपो, शेरशाह धीरे-धीरे समय, पृ० ४२२, खालिफा १६९६

४ दयानदास से खान (प्र०), भाग २, पृ० ८० ८६

५ दनपत बिनास, पृ० १२, अबुल फजल—आई ने अकबरी (अनु० ब्लोक्मेन) प्रथम भाग पृ० ३२६ १८७३ ई०

६ दनपत बिनास, पृष्ठ २३, ३४, डा० करनीसिंह, दी रिजिजन आफ दी हाउस आफ बीकानेर, बिद् दी सेंट्रल पाब्लिश, पृ० ११२, दिल्ली, १९७४

राज्य के राजनैतिक समूहों पर पड़ना स्वाभाविक था। मुगल दरबार के निकट वातावरण ने यहां के शासकों को प्रेरणा दी की वे भी अपनी बतन जागीर के क्षेत्र में एकाधिकारिक ढंग से सत्ता का प्रयोग करें। यद्यपि राजपद में स्वेच्छाचारिता भारत में मुगलों की देन नहीं है^१ और न ही बीकानेर के शासक इस तथ्य से अपरिचित थे, "तथापि राठौड़ों की कुल परम्पराओं ने राज्य के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं किया था। कुल-मुखिया राज्य की शक्तियों में अधिक भागीदार होने से सत्ता के विवैक्यीकरण की मांग करते रहे।^२ अब मुगल सत्ता के प्रभाव ने राजपूतों के राजनैतिक व प्रशासनिक समूहों में नई दिशाएं खोल दीं। मुगलों के साथ सन्धि के फलस्वरूप यहां के शासकों को बाह्य आक्रमण का भय नहीं रहा। इतना ही नहीं, किसी गम्भीर आन्तरिक विद्रोह की कुचलन के लिए, मुगल सैनिक शक्ति की सुविधा उनके लिए पर्याप्त थी।^३ परिणामस्वरूप मुगल संरक्षण में, उनकी व्यवस्था से प्रभावित यहां के शासकों ने प्राचीन हिन्दू नरेशों को अपना आदर्श मानकर राज्य में सदातः राजतन्त्र की स्थापना की। वे प्राचीन हिन्दू नरेशों की तरह यज्ञ, अनुष्ठान, तुलादान, राज्याभिषेक महोत्सव व अन्य पुनीत कार्य सम्पन्न करके, स्वयम् को धर्मरक्षक घोषित करके और भी ब्राह्मण प्रतिपालक जैसी पदवियां धारण करके आदर्श हिन्दू शासक का यश प्राप्त करना चाहते थे।^४ राजा रायसिंह ने, प्रथम बार, अपने दुर्ग के निर्माण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् मूरज पोल (द्वार) पर प्रशस्ति लगाकर यह बताया कि राठौड़ों का सीधा सम्बन्ध हिन्दू देवता राजा रामचन्द्रजी के कुल से है।^५ इस प्रकार राजा रायसिंह ने मुगल-काल में राठौड़ों की गौरवमयी व सम्मानजनक दैवीय स्थिति प्रदान करने का प्रयास किया।

मुगलों के प्रभाव से राजपद की एक अ्य दिशा व शक्ति भी प्रदान हुई। राजा रायसिंह ने अपने पिता राव कल्याणभट्ट की भांति स्वयं को कुल-प्रधान की

१ डा० आर० पी० जिशाठी, सप्त आत्येय्य आक मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन पृ० १५५, इलाहाबाद १९१४, डा० आशीर्वादीशम चौधरी, अफ्जर महान, भाग २ (हिंदी) पृ० १, १० १८ आगरा, १९७२

२ मूरजपोल प्रशस्ति (पूर्व), पत्रिका न० ६६-६७

३ राठौड़ों की कलात्मक व शिल्पीय कौशल की कृति पर भाग, पृ० ६१ न० २३१/६, अ० स० पु० बी०

४ कर्मचन्द्र, पृ० ३८ ३९, दयालदास की कला (प्र०) २, पृ० ६१, १२८ ३०, १६५, डा० कर्मचन्द्र (पूर्व), पृ० ४१।

५ महादेव, रायसिंह गुणावलि पृ० ४, न० ४८३, रायसिंह प्रशस्ति, गीत गोविन्द टीका, पृ० १२-१४, क० न० २६/२९, हाजिगढ़ का कर्मचन्द्र, पृ० ६, न० २६५१, बीकानेर के राठौड़ों की कला महापद्म गुणावलि पृ० महापद्म कर्मचन्द्र की टीका, पृ० ३०६, ८ २०, न० १८६। ११ न० ८० पृ० ४०

स्थिति तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु सम्राट अकबर की भांति राजमुकुट को एक पृथक् व विस्तृत आधार देने के प्रयास किये। 'उसने कठोरता से राज्य के कुल-मुखियों व कब्रियों के मुखियों का दमन किया और शक्तिशाली नृपतन्त्र के अधीन, इस क्षेत्र में राजनैतिक एकता को स्थापित किया।' जैसे-जैसे कुलीय व्यवस्था का प्रभाव घटता गया, वैसे-वैसे राजा स्वतः शक्तिशाली बनता गया। इस अर्थ में रायसिंह राज्य का प्रथम वास्तविक राजा था। प्रजा के मस्तिष्क पर वह ही पहली बार यह प्रभाव डालने में सफल हुआ कि केवल बीका की सन्तान ही उन पर शासन करने की वास्तविक अधिकारी है।^१

उसने व उसके उत्तराधिकारियों ने पुरानी दरबारी व्यवस्था में परिवर्तन करके, उसे मुगल सौचे में ढाला। आगे चलकर इस व्यवस्था ने एक निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। दरबार में सामन्तों की बैठकें निश्चित नियमों पर निर्धारित की गईं। शासक की चाहिनी और पक्ति, उन सामन्तों के लिए सुरक्षित रखी गयी जो रावत कांथल व राव बीदा के वंशज थे। बायीं ओर की बैठक पक्ति राव बीका के वंशजों के लिए निश्चित की गई।^२ राजा के निजी सेवकों (जिन्हें हजुरी कहा गया था) में खुवास,^३ पामवान,^४ बहारण^५ आदि पदों का निर्माण किया गया। शासक की तलवार व ढाल रखने का कार्य पगिहार राजपूतों को सौंपा गया। खवर, मोरखान, पक्षा, और आस निवान रखने से सम्बन्धित कार्यों का उत्तरदायित्व भाटी व सोनगरा राजपूतों की विभिन्न खापों को सौंपा गया। राजा के अन्य निजी कार्य भी, इसी प्रकार राजपूतों की विभिन्न जातियों की खापों में वितरित किये गये। महाराजा अनूपसिंह (१६६६-१६६८ ई०) ने शासक के पीछे हाथी की सवारी के समय बैठने का कार्य खुवास उदैराम अहीर को सौंपा।^६ इन सारे

१. डा० आर० पी०, लिपाडी सम आस्वेइस आफ दी मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १२६, १४१

२. दलपत बिलाम, पृ० ४४, ४६, ६२ ६४, दयालदास की कथा (प्रकाशित), भाग २, पृ० १२६, डा०-२, पृ० ११३३

३. कर्णावतस (पूर्व), पृ० ६-८

४. दरबार में सामन्तों की बैठक की पूर्ण व्यवस्था महाराजा मुरतसिंह के काल में स्थापित हुई, परन्तु राजा रावबिह के समय से ही यह प्रणाली प्रारम्भ हो गई थी।—बोकारनेर गांव के पट्टा की शिगत राजा कर्णामय जो रे सवै से बीहु ११वीं मीहफल से लेखो न० २२६/२, अ० सं० पु० बी०, भैया सपड़-बही दरबार से भैया नचपल रे सपेरी, १८५७/१००० ई०, उदयपुर की टपान में घुटकर बसित—बीवावन तथा बीदावत रे गांवों रे गांवों की बिलन, न० १८२/४, अ० सं० पु० बी०

५. विषवमतीय मेवक

६. सम्मानित उपपत्नी, सदा पास रहने वाला सेवक, मरजीदान

७. जनानी ह्योड़ी की मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

८. देगदर्पण (पूर्व), पृ० १४७-४९

नियमों से राजपद के गौरव और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।

१८वीं सदी में मुगलों के पतन के साथ राजपद की स्वेच्छाचारिता के सिद्धांत को भी धक्का लगा। अब यहाँ के शासक किसी भी सबूत की वेला में केन्द्रीय शक्ति का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनकी शक्ति का छोट फिर कुलीय मुनिया बन गये। जिन्होंने परिस्थितियों से लाभ उठाकर पुन राजपद को कुलीय तन्त्र पर आधारित करने का प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप शासक की सत्ता के विरुद्ध स्थान-स्थान पर विद्रोह होने लगे।^१ सन् १८१८ ई० में राज्य की ईस्ट इण्डिया क० से संधि से पूर्व तब इस प्रश्न पर निरन्तर राज्य में आन्तरिक संघर्ष चलते रहे कि राजपद सर्वाधिकारी या परमपूर्ण हो अथवा कुलीय भाई-बन्धु परम्परा पर आधारित हो। सन् १८१८ ई० की संधि ने पुन राजतन्त्र को केन्द्रीय सुरक्षा प्रदान की और यह निरकुशता की ओर अग्रसर होने लगा।^२ इस प्रकार भ्रातृत्व सिद्धांत पर आधारित राजपद बाह्य संबंधीमित्रता को स्वीकार करने पर ही सर्वशक्तिमान हुआ। अन्यथा राजव्यवस्था राजा और सामन्तों के बीच भार्गवदारी पर ही चलती रही।

उपाधियाँ एवं सम्मान

बीकानेर के प्रथम चार शासकों की पदवी 'राव' थी।^३ अपने शासक कल्याणमल ने अपनी राजनैतिक विवशताओं के कारण मुगलों से सन्धि कर ली थी तथा उसकी पदवी 'राव' ही मनी रही।^४ उसका पुत्र रायसिंह, जो राज्य का छठा

१. मोहता भीमसिंह का जोधपुर महाराजा अयसिंह द्वारा बीकानेर चले का वचन, पृ० १७ २२, भाईको रोल, न० ८, रा० रा० अ० बा०

२. दयालदास की दयाल (अप्रकाशित), भाग २, पृ० १६६, १८१, २२२, ३१८, २२

३. बीकानेर राज्य और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बीच ६ सन्धि, सन् १८१८ ई० की संधि हुई थी, उसकी सातवीं धारा इसी समस्या के हल से सम्बंधित थी। 'महाराजा की याचना पर अंग्रेज सरकार महाराजा से विद्रोह करने एवं उनकी सत्ता को न मानने वाले ठाकुर तथा राज्य के अन्य पुरुषों को उनके अधीन करेगी। ऐसी दशा में सारा सैन्य एवं महाराजा को देना होगा। परंतु, उस दशा में जबकि उनके पास स्वर्ण चुनने के साधन उपस्थित न होंगे, उन्हें अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेज सरकार को सुपुर्द कर देना होगा, जो उस धन को पूर्ण हो जान पर उन्हें वापस मिल जायेगा।'—एचिसन ट्रीटीज इनवेन्टर्स एण्ड सनदज, भाग ३, पृ० २८८ ६०, दयालदास की दयाल (अप्र०) २, पृष्ठ ३३७ ३८

४. राज्य के प्रथम चार शासक राव बीका, नरा, लूचकरण, जैतमी थे। राव जैतमी से छन्द, छन्द न० ११, ६३-६४, दयालदास की दयाल (प्रकाशित) १, पृष्ठ २४, २६-२७, ३७

५. दयालदास की दयाल (प्रकाशित) २, पृष्ठ ६४, कमजदमे कल्याणमल की पदवी राजा की गई है। पृष्ठ २७

शासक था, मुगल सम्राट् अकबर द्वारा 'राजा' की पदवी से सम्मानित हुआ।^१ उनके पश्चात् मुगल सम्राट् सदैव बीकानेर शासकों के वशानुगत अधिकारी व उनकी उपाधियों को मान्यता देते रहे। सम्राट् जहाँगीर द्वारा राजा रायसिंह के पुत्र सूरसिंह को भेजे गये विभिन्न फरमानों में से अनेक में उसे 'राजा' की पदवी से सम्मानित किया गया था।^२ सम्राज्ञी नूरजहाँ ने भी सूरसिंह को 'राजा' बहकर संबोधित किया था।^३ राज्य का दमवा दासक राजा अनूपसिंह सम्राट् औरंगजेब द्वारा 'महाराजा' की उपाधि में अलंकृत हुआ।^४ यहाँ के शासकों को राजकीय उपाधियों में उस समय एब और महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई, जय कि सम्राट् शाह आलम द्वितीय ने राज्य के चौदहवें दासक गजसिंह को 'राजराजेश्वर महाराजाधिराज' की पदवी में विभूषित किया।^५

मुगल सम्राट् द्वारा बीकानेर के शासकों को समय-समय पर भेजे गये फरमानों के अध्ययन से विदित होता है कि वे यहाँ के शासकों के लिए अनेक सम्मानित व आदरमूलक शब्दों की शैली अथवा सम्बोधनों का प्रयोग किया करते थे। उन्हें 'अमीरों का अमीर',^६ 'साम्राज्य के आधार स्तम्भ',^७ 'साम्राज्य के विश्वास

१ दयालदास की ध्यात (प्रकाशित), भाग २, पृष्ठ ६७ अलखधारी राजा रायसिंह, पृष्ठ ४०, बीकानेर, १६३४

राजा रायसिंह को यह पदवी ध्यात के अनुसार सन् १५७७ ई० मुगलों के अठक अभियान के पश्चात् सम्राट् द्वारा दी गयी। अलखधारी के अनुसार सन् १५७२ ई० के गुजरात अभियान के पश्चात् दी गयी थी।

२ सम्राट् जहाँगीर द्वारा राजा सूरसिंह को भेजा गया फरमान दिनांक २६ इम्फरारमुज इलाही १५ / फरवरी १६२३ ई०, न० ४७, रा० रा० अ० बी०

३ नूरजहाँ का निशान दि० १० अजर इलाही १२ / दिसम्बर १६१७, न० १६, रा० रा० अ० बी०

४ मुगल फरमानों में यह पदवी प्राप्य नहीं होती है, परन्तु वशत में इसका विशद विवरण मिलता है। दयालदास के अनुसार अनूपसिंह को यह पदवी सम्राट् आलमगीर के मराठों के विरुद्ध विजय के फलस्वरूप प्राप्य हुई थी। पाउलेट ने इसे अनूपसिंह की औरंगजेब के मोलकुण्डा अभियान की सेवाओं का परिणाम माना है।

—दयालदास की ध्यात (प्रकाशित), भाग २, पृष्ठ २०५, पाउलेट गवर्नियर आफ् बीकानेर, पृष्ठ ३६

५ सम्राट् शाहआलम द्वितीय का महाराजा गजसिंह को फरमान, दि० २४ अमादि उषशानी, ४ जुलाई, १७६२, न० ८०, रा० रा० अ० बी०

६ सम्राट् जहाँगीर का फरमान, न० ६७, रा० रा० अ० बी० (दिनांक लिखा हुआ नहीं है।)

७ शाहआद सनीम का राजा रायसिंह की निशान, दिनांक २६ अजर, ४२ / नवम्बर, १५९७, न० ५, रा० रा० अ० बी०

पात्र" 'समस्त शाही सम्मानों के योग्य' आदि पदवियों से सम्बोधित किया जाता था। शाहजादा खुर्रम ने अपने निशान में राजा सूरसिंह को 'उच्च कूल' राजाओं में सर्वश्रेष्ठ लिखा था। सम्राट् जहाँगीर ने इसी राजा को अपने एक फरमान में 'राम राम' भेजी थी।^१ सम्राट् शाहजहाँ ने भी राजा सूरसिंह को 'अपने बराबर वालों में श्रेष्ठ' कहकर सम्मानित किया था।^२ इन सम्मानजनक शब्दावलियों के साथ साथ यहाँ के शासकों को सैनिक सम्मान भी प्राप्त हुए थे। शाहजादा सलीम व सम्राट् औरंगजेब ने राजा रायसिंह व महाराजा अनूपसिंह को उच्च सैनिक स्तर की श्रेणी का सम्मान 'तोग' प्रदान किया था।^३ महाराजा अनूपसिंह और महाराजा गजसिंह को मुगल सम्राट् द्वारा राजसी सम्मान के निशान 'माही ओ मरातिब' प्राप्त हुए थे।^४

प्रत्येक फरमान व निशान में इनके लिए राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अधिकतर म 'राव' अथवा 'राय' शब्द का ही पदवी के रूप में प्रयोग मिलता है।^५ गजसिंह ही एकमात्र शासक थे, जिनके लिए प्रत्येक फरमान में

- १ सम्राट् शाह ज़ालम द्वितीय का फरमान (पूर्व)
- २ शाहजादे सलीम का निशान (पूर्व)
- ३ शाहजादे खुर्रम का सूरसिंह (शूरसिंह) को निशान दिनांक १५ जिल्जहिश्न (१०२६) ए १५ / दिसम्बर १६१७ ई० न० ३५
- ४ सम्राट् जहाँगीर का सूरसिंह को फरमान न० ६७
- ५ सम्राट् शाहजहाँ का राव सूरसिंह को फरमान दि० ११, धरवराद ३ / मई १६२० ई०, न० ७५
- ६ तोग प्राय ऊँचे ओहदे वाले मनसबदारों को सम्मानित करने के लिए उन्हें प्रदान किया जाता था। लंबी के आकार के छडों में धाक के बालों से बनी हुई तीन पूछों से यह बना होता था, जो कि एक लम्बे छन्डे के सिरे से बूझा रहता था।
—शाहजादे सलीम का निशान (पूर्व) महाराजा अनूपसिंह जो रे मुनसब नै तलब दी निगत, पृष्ठ ८८ ६० कृत्वर वाता न० २०६ / २, ख० स० पु० बी०
- ७ माही ओ-मरातिब का अर्थ था गेंदों तथा मछली के आकार के चिह्नों से सम्मानित करता था। पाउलेट गजटियर पृ० १२३ बी हाउस ऑफ बीकानेर (पूर्व) पृ० २१ ओसा बीकानेर १ पृ० २८८ ८६। यद्यपि इस सम्मान को प्राप्त करने का विवरण हमें हम सम काशीन ग्रन्थों में नहीं प्राप्त होता है पर तु ये चिह्न फौट सप्रहासय बीकानेर में अभी भी देख जा सकते हैं।
- ८ प्राप्त फरमानों में रायसिंह का नाम क १६ फरमान व निशान में 'राय' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। सूरसिंह के २६ फरमान व निशान में ४३ में 'राव व १३ में राजा' पदवी का प्रयोग किया गया है। राव शब्द के २ व अनूपसिंह के ४ फरमान व निशान में भी केवल 'राव' शब्द का प्रयोग किया गया है। बीकानेर शासकों के मिले फरमान व निशान की सूची—रा० रा० ख० ओ०

‘राजा’ या ‘महाराजाधिराज’ की पदवी का प्रयोग किया गया है।^१ पर उस काल तक मुगलों का वैभव समाप्त हो चुका था और देश में वे राजनैतिक सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकते थे। स्वयं महाराजा गजसिंह ने उनके आदेशों की परवाह नहीं की थी।^२ उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने, अपने राज्य-अभिलेखों में प्रभुतामय शासकों की तरह गौरवमयी तरीकों से श्री राज, महाराजा, राजेश्वराधिराज, महाराजा शिरोमणि, महाराजा, श्री श्री १०८ श्री ... आदि अनेक उपाधियों को एकसाथ धारण किया था।^३

इसके अलावा यहाँ के शासकों ने अपने निजी पत्रों में सर्वत्र ‘महाराजा-धिगज’ लिखकर ही स्वयम् को सम्बोधित किया था।^४ विभिन्न शिलालेखों तथा प्रगतिपत्रों में भी इन शासकों के नाम से पूर्व महाराजाधिराज से कम उपाधि नहीं प्राप्त होती है।^५ स्थानीय साहित्य में वे प्राचीन हिन्दू नरेशों की भाँति महिषति, महाराजाधिराज, राजराजेश्वर और राजेन्द्र पदवी में सम्मानित किये गए हैं।^६

इतनी विशाल उपाधियाँ व शब्दावलिसे विभूषित बीकानेर शासक जब राज्य के स्वतन्त्र अधिपति थे, तब केवल राज ही कहलाते थे। प्राचीन हिन्दू नरेशों की तरह, उन्होंने इतनी विशाल अर्थों वाली उपाधियाँ उस समय धारण की जब वे मुगल साम्राज्य के एक मनसबदार थे। समकालीन फारसी तबारीखों में व मुगल शासकों के फरमानों में इसके लिए जर्बोदार शब्द का प्रयोग किया गया है।^७ इनकी राजनैतिक व सामाजिक स्थिति को देखते हुए यह सम्बोधन निराशाजनक कहा जा सकता है।

१ फरमान नं० ८७ व ११, रा० रा० अ० बी०

२ बपालदास री क्यात (अप्रकाशित), भाग २, पृष्ठ २८८

३ बानदी की बही, वि० सं० १८२७/१७७० ई०, नं० ३, पृष्ठ १-२

४ महाराजा गजसिंह का जोधपुर नरेश विजयसिंह को लिखा पत्र, आश्विन बरी ८, वि० सं० १८०१/३० वितम्बर, १७१२ ई०, लरीठा सपह, बीकानेर, रा० रा० अ० बी०, बी हाजग आफ बीकानेर, पृ० १४४

५ मुरज बील प्रगति, पत्रि नं० ६८, अमृतसिंह की छत्री बिलालेख, वि० सं० १७११/१९१८ ई०, बीकानेर

६ दसवत बिलाल, पृष्ठ १२, जयभोग (पूर्व), पृ० ६६, राधासिंह गुणामिधु (पूर्व), पृ० १-२, कर्णवत्तस (पूर्व), पृष्ठ १

७ मन्नाट जहांगीर का राज मुरसिंह को फरमान नं० ६१, सम्राट् अहमदशाह का राजा गजसिंह को फरमान, दि० २ अहमदन ७/२ अगस्त, १७१३, नं० ८८, आदि प्रहबरी, प्रथम भाग (पूर्व), पृष्ठ ३१७, डा० इरफान हबीब, जोधनेथ ‘दी जर्बोदार इन दी आईन, एडिशन टिप्पणी कावेय प्रोतिहिम, १९१८, पृष्ठ ३२२, एम० गुरन हसन, बादम घान एन्टोरियन रिसेग्न इन मुगल इतिहास, पृष्ठ ३१, दिल्ली १९७३

उत्तराधिकार समस्या

आनुवंशिक नृपतन्त्र मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की एक मुख्य विशेषता थी। जैसा पहले लिखा जा चुका है, भूतपूर्व बीकानेर राज्य क्षेत्र में इसकी स्थापना १५वीं शताब्दी के अन्त तक बिखरे अनेक छोटे छोटे जातीय जनपदों की गणतन्त्रीय व्यवस्था को मारवाड़ के राठौड़ों के अनवरत आक्रमण द्वारा उखाड़ फेंकने व तदनन्तर राठौड़ राजतन्त्र सिद्धान्त के स्थापित होने के साथ हुई थी। राठौड़ आक्रमणकारियों ने निर्वाचित नृपतन्त्र सिद्धांत के प्रति कोई मोह नहीं था। यह अवश्य था कि उपयुक्त उत्तराधिकारी की खोज में कुलीय वन्धुओं व मन्त्रियों के बीच विचार-विमर्श या मन्त्रणा होती रहती थी, लेकिन उनके विकल्प भाव केवल राज परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहते थे।^१ जब तक कुलीय व्यवस्था का जोर रहा, तब तक जाति के विभिन्न कुल-मुख्तियों के विचार ही उत्तराधिकारी के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे।^२

साधारणतया उत्तराधिकार के प्रश्न में ज्येष्ठाधिकार के नियम को ही मान्यता प्राप्त थी, परन्तु व्यवहार में इस सिद्धांत की अवहेलना के उदाहरण भी मिलते हैं।^३ ज्येष्ठ पुत्र के अभाव में सासक का छोटा भाई राजगद्दी के अधिकारी

—मुगल फरमानों व समवासीन फारसी द्वा-रों में कई बार बीकानेर शासकों को 'मुरटिया राजा' कहकर सम्बोधित किया गया है। सम्भवतः इन राज की वनस्पति-सम्बन्धित विशेषताओं के कारण, इसका प्रयोग किया गया है। रेगिस्तानी क्षेत्र की मुख्य घास 'मुरट' होती है तथा कई बार यहाँ की भूमि को 'मुरटी' भी कहा जाता है। इसी संदर्भ में यहाँ के शासकों को मुरटिया राजा कहा गया है।

• —शाहजादा गुर्रम का राज सूरजसिंह ने निजान, दिनांक २२ खुरदाद इलाही / १२, मई, १९१७ ई०, जालमनोरनामा, पृष्ठ ३७१

—श्री० जी० एन० शर्मा ने राजपूत राजाओं की जमींदार बहूने वर आपत्ति उठाई है। उनके अनुसार 'ऐसा कहना अवैधानिक है। उन्होंने अपना विचार राजपूत राजाओं की स्थिति, उनके स्वशासित राज्य मुगलों द्वारा उन्हें दिये गये सम्मान के आधार पर प्रस्तुत किया है।—राजस्थान स्टडीज, पृष्ठ २०७ ११, भाग ४, १९७०। सम्भवतः इस शब्द का प्रयोग मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में उनके भू-स्वत्व अधिकारों की लेकर किया गया हो।

१. कुलीय व्यवस्था में कुल के वरानुवर्तन अधिकारों को सम्मान देने की प्रथा थी।—बी०पी० मन्मथदास (पूर्व), पृ. १७

२. दयालदास री कथात (पृ०) २, पृष्ठ ३४ (अप्र०), पृ० २७६-७७

३. उपर्युक्त

४. देखिये, बीकानेर शासकों का वंशवृक्ष, परिशिष्ट १

को प्राप्त कर सकता था।^१ अल्पवयस्क शासक होने की दशा में दिवंगत राजा का अनुज अथवा राजमाता राज प्रतिनिधि के रूप में शासनभार सभाल सकते थे।^२ कई बार उत्तराधिकार की समस्या शासक के जीवनकाल में ही उत्पन्न होकर उलझनें खड़ी कर देती थी। राजकुमारों की महत्वाकांक्षाएँ इस समस्या को अपरिपक्व अवस्था में ही जटिल बना देती थी, जिससे प्रशासन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था।^३

मुगलों ने सधि के पश्चात्, मुगल सम्राट् के पास यह परमाधिकार आ गया कि वह राज्य के प्रत्येक नये शासक को गद्दी पर बैठते समय मान्यता प्रदान करे।^४ मुगल सम्राटों ने अपनी इन निर्बाचन शक्तियों का प्रयोग इसनी स्वेच्छा से किया कि उन्होंने कई बार दिवंगत राजा के वनिष्ठ पुत्रा को उत्तराधिकारी के रूप में चुना।^५ यहाँ तक कि उन्होंने कई राजाओं को उनके जीवनकाल में ही राजगद्दी से उतार दिया था। बीकानेर राज्य इतिहास में इस प्रकार के तीन उदाहरण हैं, जिनके समस्तुल्य उदाहरण इस काल में कहीं अन्य किसी राज्य में प्राप्त नहीं होते।

- १ बीकानेर की गटौडां की ध्यात (पूर्व), पृष्ठ १४, महाराजा स्वर्णसिंह की मृत्यु के पश्चात् पुत्र न होने की दशा में उसका छोटा भाई सुवानसिंह सन १७०० ई० में गद्दी पर बैठा था।
- २ महाराजा स्वर्णसिंह के बाल्यकाल में उनके दक्षिण प्रवासकाल में राजमाता सीसीदौगी राजप्रतिनिधि के रूप में शासनकार्यों की देखती थी। सूरसिंह ने अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराजा राजसिंह की अस्वस्थता तथा घोर प्रतापसिंह के बाल्यकाल में राजप्रतिनिधि के रूप में राज्यप्रशासन का मवाजन किया था।—दयालदास की ध्यात (अग्र०) २, पृष्ठ २५७-५८, टाइ २, पृष्ठ ११३६-४१
- ३ राजकुमार दत्तपत व राजसिंह का अपने पिता राजा राधसिंह व महाराजा धर्मसिंह के विरुद्ध विद्रोह से राज्य में अस्थिरता व अमरुता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। (दयालदास की ध्यात) २ पृष्ठ १३०, (अग्र०) २, पृष्ठ ३०-३१
- ४ शान्ति का अर्थ यहाँ सम्राट् द्वारा नये शासक के अधिकारों को स्वीकृत करना था। इस अवसर पर दरबार में एक छोटा सा उत्सव होता था। सम्राट् अपने हाथ से नये शासक के सलान पर टीका लगाता था तथा दिए गए मनसब के अनुसार उनकी वतन जागीर व अन्य जागीरी क्षेत्रों को प्रदान करता था। शाहजहाँ के काल में सम्राट् द्वारा टीका लगाने की प्रथा समाप्त हो गयी। उसके स्थान पर बजोर यह कार्य सम्पन्न करने लगा था, औरांगजेब ने इस प्रथा को पुनर्स्थापित ही मिटा दिया।
—शत्रु ने मरवरी, भाग १, पृष्ठ २२८ तुरुके जहांगीरी, अनु० खोजें, स० एच बेवरिज, पृष्ठ २१७ १८, सन्दन १६०६ ई०, बासीरे आनमबीरी, पृष्ठ १७६
- ५ सम्राट् जहांगीर ने राजा राधसिंह के उत्तराधिकारी दत्तपतसिंह को हटाकर, उनके वनिष्ठ भ्राता सूरसिंह को गद्दी प्रदान कर दी थी।—तुरुके जहांगीरी (पूर्व), पृष्ठ २१७ १८
—दयालदास की ध्यात (अग्र०), भाग २, पृष्ठ १४४

केवल सम्राट् शाहजहाँ को छोड़कर प्रत्येक महान मुगल सम्राट् ने अपनी इन असीमित शक्तियों का प्रयोग किया था। सम्राट् अकबर ने कूबर दलपत के मुद्द व पदग्रन्थ द्वारा बीकानेर राज्य का सर्वेसर्वाजन जाने पर अपना समर्थन प्रदान किया। 'सम्राट् जहांगीर ने सूरसिंह का पक्ष लेकर राजा दलपतसिंह के विरुद्ध मुगल सेना भेजी थी व उसको गद्दी पर बिठाया था।' औरगजेब ने राजा कर्णसिंह को मुगल विरोधी गतिविधियों के आरोप में गद्दी से हटाकर उसके पुत्र अनूपसिंह को राज्यप्रशासन का दायित्व सौंपा था।^१

उत्तराधिकार के प्रश्न पर मुगलों के हस्तक्षेप से निर्णय अवश्य शीघ्रातिशीघ्र होने लगे, परन्तु इससे राज्य में पड़्यन्नकारी गतिविधियाँ बढ़ने लगी। मुगल सम्राट की स्वेच्छानारिता से राज परिवार की महत्वाकांक्षाओं को हवा मिलने लगी, जिससे प्रचलित ज्येष्ठाधिकार का नियम कमजोर पड़ने लगा।^२ अब सदा की आशाओं व आकर्षण का केन्द्र मुगल सम्राट बन गया। यद्यपि मुगलों ने भी जहाँ तहाँ परम्पराओं का सम्मान करने के फल लिये थे परन्तु अधिकतर उन्होंने अपनी इच्छाओं को ही धोया। उनकी नियोजन की असीमित शक्तियों ने राज्य के सम्मुख नयी उलझनें पड़ी कर दी। राजा रायसिंह अपने विरुद्ध ही रहे पड़यन्त्रों का शिकार बना जिसके फलस्वरूप सम्राट् अकबर के साथ उसके सम्बन्ध एक अवस्था में बहुत बिगड़ गये थे।^३ दलपतसिंह व सूरसिंह की प्रतिद्वन्द्विता ने राज्य

१ आर्देन जफरी भाग १ पृष्ठ ११८ दयालदास की श्यात (प्र०) २, पृष्ठ १२६ ३०
दशदपण पृष्ठ १४ कागज में यह घटना जब घनी हमकी गद्दी सूचना प्राप्त नहीं है।
क्याती में जो वहीन दिया गया है वह सम्राट् अकबर के नाम से जहांगीर के काल का दे
दिया गया है जो लगभग सन १६००-१० ई० के पड़ता है। कुछ कथाओं में इस घटना
को छिपाकर भी लिखा गया है। मिक कूबर दलपत के विरोध व उसके द्वारा रायसिंह
को हराने का विवरण दिया गया है। दशदपण में स्पष्टतः अकबर द्वारा रायसिंह को
हटाकर दलपत को मनमय व जागीर देना लिखा है। संभवत यह घटना सन् १५६६
व १६०० ई० के लगभग घटी थी, जब दलपत ने राज्य में आकर विद्रोह किया था।
उस समय सम्राट अकबर रायसिंह से रूठ था।

२ तुजुके जहांगीरी (पृष्ठ) पृष्ठ २३८ ४६

३ सम्राट औरगजेब का अनूपसिंह को फरमान दिनांक १६ रबी उल अस्मात् १०/११
अतवरी, १६६७ ई० व ६१

४ महाराजा अनूपसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रों के बीच गद्दी प्राप्त करने के लिए
उनके समर्थकों द्वारा पड़्यन्न प्रारम्भ हो गए थे। सभी दलों ने सम्राट से अपने अपने पक्ष
के प्रति निवेदन किया था।—बीकानेर की कथा महाराजा गुजार्जसिंहजी सू गजसिंह जी
तार्ई पृष्ठ ५

५ अकबरनामा, अनु० एच० बेवरल भाग ३, पृष्ठ १०३८ दयालदास की श्यात (प्र०) २,
पृष्ठ १२६ ३०

भेदभाव को जन्म दिया व प्रशामकीय अस्थिरता के वातावरण को जनपाया ।^१ बनमालीदास काष्ठ ने तो राज्य ने अस्तित्व तक को खतरे में डाल दिया था ।^२ सन् १६६८ ई० में महाराजा अनूपसिंह की मृत्यु के पश्चात् नाजर ललित के पड़-पड़ों ने राज्य के शत्रुओं को लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया ।^३ लेकिन यह हस्तक्षेप सम्राट् के निजी साम्राज्य के स्वार्थों के हित में था । इस तरह की असीमित शक्तियों के प्रयोग से वह न केवल केन्द्रीय सरकार की स्थानीय शक्तियों पर नियंत्रणकारी शक्तियों को दृढ़ करता था, अपितु राजा को उसके प्रति व्यक्तिगत आभार की भावना से भी जकड़ देता था ।

१८वीं शताब्दी में मुगल के पतन और उनकी सर्वोच्च सत्ता के लोप होने के साथ मान्यता के इस सिद्धांत का प्रभाव भी समाप्त हो गया । बीकानेर के शासकों ने अधीनता का जुमा हटा दिया । उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णायक शक्ति पुनः उनके हाथ में आ गई । परन्तु शासकों की अयोग्यता, राज्य में ही रहे आंतरिक विद्रोहों व बाह्य आक्रमणों ने उसे इस अधिकार का भली भाँति प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया । इस काल में, सामन्तों की शक्ति बढ़ने तथा राज वसंचारी वर्ग के समष्टित होने से ठाकुरों व मुत्ताहिदों की इच्छा भी उत्तराधिकार के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी ।^४

राज्य में उत्तराधिकार की समस्या ने उस समय सबसे अधिक बखेड़े किये जब सन् १७४५ ई० में नि सतान महाराजा जोरावरसिंह की मृत्यु हो गई । उनके पीछे राज्य व गढ़ का प्रबन्ध मुत्तमही दीवान मोहता बख्तावरसिंह ने तथा शक्ति-शाली मुन्सरका के मुसाहिव ठाकुर कुशनसिंह ने अपने हाथों में ले लिया ।^५ अब

- १ भूरसिंह ने दमपनसिंह के समर्थकों को बुरी तरह दण्डित किया था । —दयालदास री क्वात (१०) २, पृष्ठ १५२-५३
- २ सम्राट् औरंगजेब ने राजा कण के बड़े पुत्र अनूपसिंह व बनमालीदास के बीच राज्य-विभाजन की योजना बनाई थी, जो अनूपसिंह की अनुरोध से सफल नहीं हो सकी । दयाल-दास री क्वात (१०) २, पृष्ठ २१७-२०
- ३ मारवाड़ के राजा अजीतसिंह ने राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर आक्रामक नीति अपनाई थी । जोड़ियों व मट्टियों के विद्रोह बढ़ गये थे । —बीकानेर री क्वात, महाराजा मुजानसिंहजी सू महाराजा अनूपसिंह ताई, पृष्ठ ५-७
- ४ बीकानेर री क्वात, महाराजा मुजानसिंह जी महाराजा अनूपसिंहजी ताई, पृ० ५७, ३८, ७०
- ५ बीकानेर री क्वात, महाराजा मुजानसिंह जी सू वज्रसिंहजी ताई, पृष्ठ ३८, ४०, महाराजा अनूपसिंह, पृष्ठ ६५, ६६, मोहता लिखतें, भागकी चिन्त, रोल व १८, २०, २० वी०

वे ही उत्तराधिकारी के लिए वास्तविक ध्यानवर्ता थे। हालाँकि राज्य के मामलों की देख-रेख हेतु एक समिति भी गठित की गयी थी, जिसमें रायों के प्रभावशाली सरदार, मुत्तदी व हजुरी सम्मिलित थे।^१ लेकिन अंतिम निर्णय इन्हीं 'दो सहयोगियों' के हाथ में था।

इन 'दो सहयोगियों' के सम्मुख गद्दी के दो दावेदार थे, मृत महाराजा जोरावर-सिंह के चचेरे भाई कुंअर अमरसिंह और कुंअर गजसिंह।^२ राज्य की प्रवर्धक समिति कुंअर गजसिंह के दावे के समर्थन में थी। उसके सदस्यों की दृष्टि में गजसिंह एक आदर्श नरेश, वसंध्यपालक सम्राट् व बुद्धिमान राजा हो सकता था।^३ उसकी सैनिक योग्यताएँ भी जोधपुर नरेश महाराजा अमरसिंह द्वारा बीकानेर के घेरे के समय भली भाँति परखी जा चुकी थी।^४ परन्तु इससे भी अधिक 'दो सहयोगियों' को भ्रुकान घाली बात यह थी कि कुंअर गजसिंह ने उन्हे यह वचन दिया था कि वह गद्दी पर बैठने के पश्चात् उनसे राजकोष का पिछला हिसाब नहीं मागेगा।^५ फिर, कुंअर गजसिंह का बड़ा भाई कुंअर अमरसिंह अभिमानी प्रकृति तथा अनियंत्रित स्वभाव का था, जिसने दीवान व मुसाहिब को उसके प्रति शकालु बना दिया।^६ राज्य में एक शक्तिशाली शासक तथा एक शक्तिशाली सामन्त या दीवान का एकसाथ कार्य करना बठिन था। घट १७ जून, सन् १७४५ ई० की मध्य रात्रि में 'दो सहयोगियों' ने कुंअर गजसिंह को घुपके से गढ़ में प्रवेश करवाकर उसका राज्याभिषेक करा दिया।^७

परवर्ती काल में राज्य में अनेक राजनीतिक सरदों की आमन्त्रित करने वाली यही घटना थी, जिसने राज्य में न केवल अराजकता को जन्म दिया, बल्कि बाहरी आक्रमणों को भी आमन्त्रित किया। कुंअर अमरसिंह ने भारवाड की सैनिक शक्ति के बल पर गद्दी पर अपना दावा प्रस्तुत किया, फिर असफल होने पर राज्य के

- १ दयालदास री ख्यात (अप्र०) २, २७६
- २ उपयुक्त
- ३ मोहता ख्यात (पूर्व), पृष्ठ ६६, मोहता रिकार्ड्स, दयालदास री ख्यात (अप्र०) २, पृष्ठ २७६
- ४ मोहता भीमसिंह द्वारा जोधपुर महाराजा अमरसिंह के बीकानेर घेरे का वर्णन, पृ० १७ १६
- ५ मोहता ख्यात, पृ० ६७, दयालदास री ख्यात (अप्र०) २, पृ० २७६
- ६ बीकानेर री ख्यात महाराजा गुजार्णसिंघजी व गजसिंघजी तार्ई, पृ० ३८-३९, दयालदास री ख्यात (अप्र०) २, पृ० २७६
- ७ उपर्युक्त
- ८ दयालदास री ख्यात (अप्र०) २, पृष्ठ २७७ ६०
- ९ वही, पृष्ठ ३१२ ४३

उत्तरी क्षेत्र में वह जीवनपर्यन्त आतंक फैलाये रहा।^१ जब महाराजा सूरतसिंह राजगढ़ी पर बैठे तो उन्हें भी इन्हीं विपत्तियों से जूझना पड़ा। उनके विरुद्ध मारवाड़ के शासक ने उनके भाइयों को समर्थन दिया। महाराजा सूरतसिंह ने इस सबूत को टालने के लिए महाराजा विजयसिंह के साथ समझौता कर लिया,^२ क्योंकि वे इस तथ्य से परिचित थे कि मारवाड़ के शासक बीकानेर की हर कमजोरी का लाभ उठाने को तत्पर रहते हैं। जोधपुर राज्य की ह्वातों में यह दावा प्रस्तुत किया गया है कि अपनी मान्यता के लिए महाराजा सूरतसिंह ने जोधपुर महाराजा विजयसिंह द्वारा भेजा गया टीका स्वीकार किया था।^३ इस दावे पर बीकानेरी स्रोत मौन हैं। सम्भवतः राज्य की आंतरिक कठिनाइयों व बाह्य आक्रमणों से अरक्षित स्थिति को देखकर महाराजा सूरतसिंह ने कुछ समय के लिए परिस्थितियों में समझौता कर लिया हो। इस संदर्भ में यह बात उल्लेखनीय है कि बीकानेर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जोधपुर राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की दखलान्दाजी का कोई उदाहरण नहीं प्राप्त होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उत्तराधिकार के प्रश्न की प्रभावित करने वाले कई तत्त्व परिचित राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार क्रमशः उभरते गये। १५७०-१७०७ ई० तक मुगल सम्राट की सार्वभौमिकता निर्णायक तत्त्व रही। १८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगल शक्ति के पराभव के साथ राज्य के व्यावहारिक रूप में स्वतंत्र हो जाने से इसमें आंतरिक शक्तियों की दखलान्दाजी भी बढ़ने लगी। राजा की इच्छा के साथ-साथ सामन्त व मुस्तद्दी वर्ग की राय भी विचारणीय बन गई। राज्य की कमजोरी का लाभ उठाते हुए मारवाड़ की घचित ने भी अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अपने पदा के ध्यवित के धुनाव में दृष्टि दिवाई। इससे समस्या मुलमने के स्थान पर और जटिल हो गई।

राजा का क्षेत्राधिकार एवं उसकी शक्तियों का विकास

(अ) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

राज्य-संस्थापक राज बीकानेरी अपनी समस्त प्रजा का शासक नहीं बल्कि जा सत्ता। वह अधिक से अधिक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करने वाले अपने समीप कुलपतियों का मुखिया था। उमके ध्वज के नीचे तीन तरह की क्षेत्रीय

१ दशतदाम की ह्वात (घ३०) २, पृ० २७७-८४

२ तापुंजु पृ० ३१२-१३

३ मारवाड़ की ह्वात, भाग २, पृ० २२६, अ० ४०५० बी०। भैया निजी संग्रह, बीकानेर के एक पत्र द्वारा ज्ञात होता है कि महाराजा सूरतसिंह ने बीकानेर राज्य की ह्वात पर अपनी मान्यता हेतु जयपुर गये थे और टीका मयवाया था। जयपुर में युनायतसिंह का भैया करणीदान, की पत्र, पौष बदी ३, १८२१/११ विसाखर, १७६४ ई०।

इकाइयां थी। प्रथम क्षेत्रीय इकाई राजभूमि थी, जहाँ पर राजा प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था। यही क्षेत्र आगे चलकर सातवा भूमि के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ भी सामन्त ने रहने वाली विभिन्न स्थानीय जातियों के साथ समझौता किया था, जिन्होंने अनुसार राजा के बर्मेचारी निर्धारित कर को वसूल करने गाँवों में जाते थे। राज्य इन्हें आक्रमण व अव्यवस्था के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन देता था। इसके अलावा, उनका प्रचलित स्थानीय व्यवस्था में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था।^१ द्वितीय क्षेत्र विभिन्न ठाकुरों द्वारा शासित होता था। वे अपने क्षेत्र में राजा के प्रतिरूप थे तथा व्यावहारिक उद्देश्यों में पूर्णतया स्वतंत्र थे। वे अपने खुल प्रधान को आवश्यकता पड़ने पर अथवा सबक के समय जो सैनिक सहायता देते थे वह सेवा के रूप में नहीं अपितु नैतिक व सामाजिक दायित्व के रूप में देते थे।^२ तीसरी तरह का क्षेत्र वह था जिसपर उन विभिन्न वंश, गोत्र की जातियों व बचीलों का आधिपत्य था, जिन्होंने केवल राठौड़ी की उच्च सैनिक शक्ति के आगे झुककर, नाममात्र की अधीनता स्वीकार करके सालाना पेशकशी (भेंट) देना स्वीकार किया था। ये भी अपने आंतरिक प्रशासन में पूर्णतया स्वतंत्र थे तथा राजा द्वारा बुलाया आने पर सैनिक सहायता प्रदान करते थे।^३

राव बीका के उत्तराधिकारी सामन्त के नीमित क्षेत्राधिकारों में सतुष्ट नहीं थे। उन्होंने न केवल राज्य की स्वतंत्रप्रिय जातियों व बचीलों के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया अपितु ठाकुराई क्षेत्रों पर भी अधिकार करने की भरसक कोशिश की थी। इससे स्पष्ट होकर राज्य के ठाकुर, राज्य के सन्तुओं से मिल गये व राज्य को बहुत हानि पहुँचायी। राव खूणवरण व राव जैतसी को अपने प्राण देकर इस नीति की नीमत चुकानी पड़ी। राव कल्याणमल ने तो सीमित अधिकारों को बचाने में ही अपना कल्याण समझा।

(ब) शक्ति का विकास (१५७०-१७०७)

राव कल्याणमल ने भारत में मुगलों के द्वारा अफगान शक्ति के दमन के पश्चात् और राजपूताने में मुगलों की सक्रिय हस्तक्षेप की नीति को देखकर सन् १५७० ई० में उनसे समझौता कर लिया।^४ मारवाड़ की आन्नापक गतिविधियों व राज्य के सरदारों के विद्रोही रुख के सामने राज्य को एक शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता के आश्रय की (नितात) आवश्यकता थी। परवर्ती शासक राजा रावसिंह के समय,

१ बीकानेर के धनीया से याद, पृ० १०-४२, टाइ २, पृ० ११२४

२ उपर्युक्त, पृ० ७-१२ बीकानेर के राठौड़ा से क्वाल गीहेंको से, पृ० १०१४, राठौड़ा से बहावनी ने पीड़ियाँ ने फुटकर आता, पृ० ६०-६१

३ इयालदास से क्वाल (५०) २, पृ० ७-१२ टाइ २, पृ० ११२६-२८

४ दलपत बिलास, पृ० १२

राज्य के मुगलों के साथ सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए। उसने सन् १५८६ ई० में अपनी पुत्री का विवाह शाहजादे सलीम के साथ किया।^१ विभिन्न मुगल अभियानों में भाग लेकर व अनेक स्थानों पर प्रशासकीय सेवाएँ अर्पित करके उसने मुगल सम्राट् का विश्वास जीत लिया।^२ उसके उत्तराधिकारियों में केवल राजा दलपतसिंह व राजा यशसिंह के अल्पकाल को छोड़कर सभी बीकानेर के राजाओं के सम्बन्ध मुगलों से मंत्रीपूर्ण ही रहे।^३

इस काल में न केवल राज्य में शासक की सत्ता का प्रसार हुआ अपितु सर्वत्र उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अब उन्हें किसी बाहरी हमले व आन्तरिक विद्रोहों का भय नहीं रहा था। राजा रायसिंह ने स्थानीय जातियों के राजनैतिक अधिकारों का दमन करके उन्हें साधारण नागरिक की स्थिति में ला दिया था, परिणामस्वरूप कालान्तर में चालसा भूमि विकसित हुई^४ और राज्य प्रशासन हर क्षेत्र में लागू किया गया। इसी प्रकार कुलीय भाईचारे के सिद्धान्त को भी प्रभावहीन बना दिया गया। राज्य के सामन्त शासक के साम्प्रदायिक नहीं रहे बल्कि राज्य के प्रति निश्चित दायित्वों के अन्तर्गत बन्धन उसकी सेवा करने वाले बन गये। उनपर पट्टा प्रणाली लागू की गई जिसके अनुसार वे अपनी जागीर का पट्टा शासक को दी गई सेवाओं के बदले वेतन के रूप में प्राप्त करने लगे।^५ अब कुल मुलिया राज चाकर बन गए। कुलीय राज्य के स्थान पर एक सम्पूर्ण सत्ता-सम्पन्न निश्चित क्षेत्रीय राजनैतिक इकाई ने जन्म लिया। राज्य के क्षेत्र को

१. आईने-अकबरी, भाग १, पृ० ३४७ भाग ३, पृ० ६४६, डा० ए० एल० थीबास्तव, अकबर महान, भाग १, पृ० १४६

२. आईने अकबरी, भाग १, पृ० ३५७ ५८, दलपत विलास, पृ० २१-२७

३. सम्राट् औरंगजेब का अनुमतिह की फरमान (पूर्व), न० ६१ तुलुके जहांगीरी (पूर्व), २५८ ५६ दयानंदराय री द्यात (प्र०) २, पृ० १४५ ४६, १६४-६५

राजा दलपतसिंह स्वभाव से स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने शाही आदेशों की अवहेलना की तथा मुगल शासक के दबाव के आगे हथियार उठा लिये थे। वे युद्ध में बन्दी बनाए गए तथा जयमेर के मबीय चारे गये। राय बख्त को भी मुगल विरोधी आन्दोलन के कारण उन्हें गिराफ्तार में हटाया गया। उनके पुत्र अनुमतिह की मुबराज की पदवी देकर बीकानेर बनन का शासनभार सौंपा गया। इन बाधकानों ने अन्ततुष्ट होकर राय बख्त ने औरंगाबाद व मुल्तानपुर के क्षेत्र में बड़ा उत्थान मचाया था।

४. दलपत विलास, पृ० ६२, मोहता रयात, पृ० १७ टाइल २, पृ० ११२६-३१

५. सम्भवतः राजा रायसिंह के शासन के अन्तिम वर्षों में पट्टा व्यवस्था लागू कर दी गई थी।—पट्टाबन्दी, वि० ख० १६८२/१६२३ ई०, न० १, वि० ख० १७२५/१६६८ ई०, न० ५, वि० ख० १७५३ / १६६६ ई०, न० ७, रामपुरिया रिवाजत बीकानेर

६. उपसृष्ट

घोरा (प्रशासनिक इकाइयों)¹ में बाटबर छालसा व पट्टे के गाँवों को एक ही विधान के अन्तर्गत रख दिया गया। ठाबुरी की शक्ति को और कमजोर करने के लिए उनकी जागीर को उनके परिवार के सदस्यों में विभाजित कर दिया गया और एक खाप के पट्टे के गाँवों के पास दूसरी खाप के सदस्यों को पट्टे में गाँव दिए गए।² एक खाप के सदस्यों को जहाँ तक सम्भव हुआ, एक क्षेत्र में समूह के रूप में एकीकृत नहीं होने दिया गया।³ सरदारों के न्यायिक अधिकार छीन लिये गए। उन्हें शासन की मैनिक सेवा प्रदान करने के साथ-साथ अब निर्धारित कर भी चुकाने पड़ने लगे।⁴

उत्तर व उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न जातियाँ भी अपनी स्वतन्त्रता के सुख को अधिक नहीं भोग सकी। राजा रायसिंह ने जोहियों का दमन किया।⁵ भाटी राजपूत निष्ठाभाव से राज्य की सेवा करने लगे। राजा दलपतसिंह ने भी इनके विरुद्ध बठोर नीति अपनाई।⁶ राजा वर्ण ने भाटियों के शक्तिशाली ठिठाने पूंगरा को राय दोस्त्रा के वश में विभक्त करके उनकी एकात्मता को भंग कर दिया।⁷ तत्पश्चात्, महाराजा अनूपसिंह को विद्रोही भाटियों व जोहियों की संयुक्त शक्ति का सामना करना पड़ा, और सफलतापूर्वक उनका दमन करने के पश्चात्, उन्हें नियन्त्रित करने के लिए उसने पश्चिमी सीमा पर अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया।⁸

मुगल साम्राज्य में स्थान

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बीकानेर के दासकों को मुगल मित्रता से प्राप्त उपस्थियों की कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन मुगलों से सन्धि व निरंतर उनकी सेवा में रहने के कारण जहाँ एक ओर आन्तरिक तोड़ फोड़ व बाह्य आक्रमणों की

१. बीरा राज्य की राजस्व प्रशासनिक इकाई का नाम था।—बीरा जवरामर र लेखे री बही, वि० सं० १७४८ / १९६१ ई०, न० २७ बीरा गुमाईसर र लेखे री बही वि० सं० १७४६ / १६६२ ई०, न० २६, बीकानेर अधिवान, रा० रा० ख० बी०
२. परवाना वही, वि० सं० १७४६ / १६६२ ई०, आयाज्याय कस्तद्वय, पृ० १८७-१६४, देशदर्पण, पृष्ठ ८७ ६२
३. देखिए पट्टेदारी शत का मानचित्र
४. परवाना बही, वि० सं० १७४६ / १९६२ ई०, पृष्ठ २२-२६, पट्टा बही, वि० सं० १७४६ / १९६६ ई०, न० ७
५. दलपत विलास, पृष्ठ ४३-४६, टाड २, पृष्ठ ११३३
६. दयालदास री क्वात (प्रकाशित) २, पृष्ठ १४२,
७. उपर्युक्त, पृष्ठ १९६
८. उपर्युक्त, पृष्ठ २१२ १३

दृष्टि से उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई वहा विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र कार्यवाही करने का अपना अधिकार वे खो बैठे। वे अब प्रभुतासम्पन्न शासक नहीं रहे, बल्कि मुगल दरबार के एक अमीर बन गए, जो अपनी सुविधाओं, शक्ति, पदोन्नति, सम्मान आदि के लिए मुगल सम्राट की ओर ताकने की विवश थे।^१ राज्य के वैदेशिक, बाह्य रक्षा व मुद्रा-मन्वन्धी अधिकार पूर्णतया मुगलों की केन्द्रीय सत्ता के नियन्त्रण में चले गए।^२ उन्होंने उत्तराधिकार के प्रश्न पर मुगलों की निर्वाचन शक्ति को स्वीकार कर लिया।^३ उन्हें घोष हो गया कि मुगल सम्राट के प्रति पूर्ण राजभक्ति ही उनके राजा के पद पर बने रहने की स्थायी कड़ी है। समय-समय पर उनका सम्राट के दरबार में उपस्थित होना आवश्यक हो गया। अपनी अनुपस्थिति में उन्हें अपने पुत्र या निवृत्त नानेदार को भेजना पड़ता था,^४ जिस सम्राट से मिलने पर भेंट देनी पड़ती थी और जिसके लिए राज्य में पैदावसी वसूल की जाती थी।^५ औरंगजेब कान में जजिया कर भी उनसे उगाहा गया था।^६ उनकी बतन जागीर भी सम्राट द्वारा दिये गये मनसब के बतन का भाग थी।^७ मुगल सम्राट कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए शाही नियमों को इनके राज्य में बिमान्वित करते थे और विद्रोहियों तथा अपराधियों को पकड़ने के आदेश जारी कर सकते थे।^८ इन आदेशों का पालन राज्य में स्वाभाविक रूप से किया जाता था। इन कमियों व हानि के बावजूद भी यहाँ के शासकों को मुगल अधीनता से कई लाभ प्राप्त हुए थे। मुगलों की राजकीय सेवाएँ उनकी शक्ति का स्रोत थी। नये

१. डा० जनहरजनी—बी मुगल नोबिलिटी अफ्टर औरंगजेब, पृ० ११, एशिया १९६९
२. ब्यानदास की ध्यात (पृ०) २, पृ० ६५, डा० आर० बी० त्रिपाठी—मुगल साम्राज्य का उत्थान व पतन (हिंदी), पृष्ठ १०८, इलाहाबाद १९६८, डा० जी० एन० शर्मा, राजस्थान का इतिहास (पूर्व), पृष्ठ ४०३, डा० ए० आर० शान, पोजिशन आफ़ वीकूम इन मुगल एम्पायर इयूरोप की रेन आफ़ अकबर, (अप्र०) शोध-प्रबन्ध, जूनीफ़, पृ० ११३-१४
३. एन० के जहागीर (पूर्व), २१७-१८, सम्राट औरंगजेब का अनुसंधान की करवान (पूर्व), न० २१
४. दलपत बिनाम, पृ० १५-७३, ८२, डा० ए० आर० शान (पूर्व), पृ० ११३-१४
५. कामदारों व कर्मियों के रोजगारी से बही, वि० स० १०५३ / १९६९ ई०, न० २०६, बीकानेर महिषान
६. उपर्युक्त
७. राजा मुरजमिह जी २ जहागीर की बिनाम, पृष्ठ ६०-६१, महाराजा अनुसंधान के मुनसब न सतव की बिनाम, पृष्ठ ८८-९०, फुटकर मार्ग, २०६ / २, अ० स० पु० बी०
८. सम्राट अकबर का राज राजमिह की करवान, दि० ७ उदिविहित, १७-१२ रजवउल मुराजब ९६०, ए० एन०/२३ अर्बन, १५६२ ई०, न० २, सम्राट जहागीर का राज मुरजमिह की करवान, दिनांक २ बहपन/८ जनवरी, १९१३ ई० न० २३, रा० रा० अ० बी०

उत्तरदायित्वों के कारण उनकी सैनिक शक्ति में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप ही वे अपनी सत्ता को दृढ़ता से स्थापित कर सके थे।^१ मुगल राठौड़ सन्धि के फलस्वरूप राठौड़ शासक अपने राज्य के आन्तरिक प्रशासन में पूर्ण स्वतन्त्र थे।^२ राज्य के न्यायिक व नागरिक प्रशासन में उनकी शक्तियाँ अचूनीतीपूर्ण बनी रही।^३ मुगल सम्राट् से वैवाहिक सम्बन्ध व प्राप्त उच्च मनसब के कारण उनकी स्थिति मुगल दरबार में अन्य मुगल अमीरा की तुलना में ही नहीं, बल्कि उनके राज्य में भी ईर्ष्यालु व दृढ़ हो गयी।^४ उनके मामलों में साधारणतया मुगल सूबेदार दखल नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनका मुगल सम्राट् से सीधा सम्बन्ध था। सम्राट् अकबर राजपूत राज्यों को अधीनस्थ नहीं करने प्रतिष्ठित साम्राज्ञीदार मानकर उनके समर्थन व सहयोग को मुगल शासन को संघटित करने में प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था।^५ बीकानेर राज्य प्रत्येक शाही आदेश एवं कानूनों का क्षत्र भी नहीं था। बीकानेर शासकों की राजस्व प्रशासन में भी पूर्ण स्वायत्तता थी।^६

दूसरे, बीकानेर के राजाओं की मुगल दरबार में सर्वोच्च सम्मानजनक स्थिति रही। किसी राजा का मनसब कभी भी डेढ़ हज़ारी से कम नहीं रहा। अधिकतम मनसब राजा रायसिंह का पाँचहज़ारी था।^७ वैसे भी मुगल दरबार में राजपूतों की विभिन्न जातियों में सबसे अधिक मनसब और सत्ता राठौड़ों के पास ही थी। सम्राट् अकबर के काल में मनसब प्राप्ति में कछवाहा अग्रणी रहे, परन्तु सम्राट् जहांगीर के शासन के दसवें वर्ष से राजपूत मनसबदारों में राठौड़ों की प्रमुखता स्थापित हो गयी। सन् १५६५ ई० में कछवाहा के पास कुल मनसब १२, ५५० का था, वहीं राठौड़ों के पास कुल मनसब ५५०० ही था। जहांगीर की मृत्यु के समय कछवाहा का कुल मनसब ६,५०० था, वही राठौड़ों का मनसब १०,३०० था।^८

- १ डा० नूरुल हसन की पोजिशन आफ दी जमींदार इन दी मुगल एम्पायर, शोधलेख इण्डियन इकोनॉमिक एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, भाग न० ४
- २ कर्मचंद्र (पूर्व), पृष्ठ ६५ ७३ डा० जी० एन० शर्मा, राजस्थान स्टडीज़, पृ० २११
- ३ मोहता खाल, पृ० ३३ ३४
- ४ दलपत बिलास पृ० २३
- ५ डा० जी० एन० शर्मा, राजस्थान स्टडीज़, पृ० २०३ ११, डा० आर० पी० त्रिपाठी (पूर्व), पृ० १०८
- ६ सम्राट् परवर द्वारा साम्राज्य में करोड़ी व्यवस्था लागू करने पर जब बरोही बीकानेर आये तो उन्हें वाफ़ा भज दिया गया। दलपत बिलास पृ० ३२ ३३, विशेष अध्ययन के लिए देखिए पुस्तक का शू-राजस्व व्यवस्था अध्याय।
- ७, दी हाउस आफ बाकानेर, पृ० १२ १६ देखिए मारफी न० १
- ८ आईने अकबरी (ग्लोबल), भाग १, तुर्क जहाँगीरी (बैबरीज व रोजर्स) भाग १-२,

सम्राट अकबर के बाल म मुगल दरबार के राठौड मनसबदारो मे, बीकानेर के मनसबदारों की सर्वोच्चता थी। मन १५६५ ई० मे कुल राठौड मनसब ५,५०० में बीकानेर के राठौडों का ८५०० भाग था। सम्राट जहांगीर के शासन बाल के प्रथम वर्ष म राठौडों के कुल ७००० मनसब मे इनके पास ५,५०० मनसब था। राजा रायसिंह की सन् १६१२ ई० मृत्यु के पश्चात् मुगल-दरबार म बीकानेरी राठौडों की स्थिति, अन्य राठौडों की तुलना मे कमजोर पड़ गयी। राठौडों के कुल ६००० मनसब मे इनके पास २००० मनसब ही था। सम्राट जहांगीर की मृत्यु के वर्ष राठौडों के कुल मनसब १०,३०० मे बीकानेरी राठौडों के पास केवल ३००० हजार ही था, अर्थात् कुल राठौड मनसब का केवल २६ १ प्रतिशत था।^१ बीकानेर के मनसब मे इस गिरावट का कारण राजा रायसिंह के पश्चात् राव दसपत के स्वामिमानी आचरण तथा मुगल शासकों द्वारा बीकानेर की तुलना मे, मारवाड के राठौडों को प्रोत्साहन देना था। सम्राट जहांगीर के बाल मे मुगलों की राजपूताना नीति में भी परिवर्तन आया, क्योंकि उनके मारवाड के साथ सम्बन्ध सुधर चुके थे तथा शक्ति-संतुलन नीति के आधार पर अब मारवाड के विरुद्ध बीकानेर के राठौडों की सहायता की आवश्यकता नहीं रही थी। दूसरे, राजा सूरसिंह में अपने पिता की प्रतिभा का अभाव था। राव वर्ण दो हजार मनसबदार था, परन्तु वह भी स्थिति मे सुधार नहीं कर पाया। औरंगजेब के साथ उसके सम्बन्ध पूर्णतया बिगड़ गए थे। महाराजा अनूपसिंह के समय मारवाड के राठौड मुगल सत्ता के विरुद्ध थे, फिर भी बीकानेरी राठौडों की समर्थन नहीं मिला, क्योंकि औरंगजेब राजपूतों की पदोन्नति पर विपरीत नीति पर चल रहा था।^१

बीकानेर के शासकों को प्राप्त मनसब के लिए, जो जागीरें प्रदान की गईं, वे उनके पैतृक प्रदेश से नहीं अधिक विस्तृत व प्राकृतिक साधनों से युक्त थीं। इनसे प्राप्त होने वाली आय साधारणतया उनके पैतृक राज्य की आय से अधिक ही रही। राजा सूरसिंह का मन् १६१८ ई० म १५०० जात व १२०० सवार

इकबालनामा एजहांगीरी (द्विविधोपिका इण्डिका) खासिदा मुउम्वर उस मुवाव (द्विविधोपिका इण्डिका) मामिर-उल उमरा शाहनवाज खान (धनु० बजरनदान), दयालदास ख्यात (प्रकाशित) और भीर विलोद में राठौडी व बच्छवाहा मनसबदारों के दिये गये विवरण के आधार पर उपयुक्त अध्ययन किया गया है और अध्ययन के लिए देखिए कृ० रफाकत अली खान—दी कच्छवाहा बख्तर अकबर एण्ड जहांगीर, पृ० २२१ ३०, दिल्ली, १९७६

१ उपर्युक्त

२ मन्स फजल मामूरी—तारीख औरंगजेब, पृ० १५६—दी मुगल नॉबिलिटी बख्तर औरंगजेब, डा० अतहर अली से उद्धृत, पृ० २५

सारणी नं० १

बोकारे के राजाओं का मनसब

राजा का नाम	सन्	मनसब	संदर्भ ^१
१. कल्याणमल		२०००।	आईने० १ पृष्ठ ३५७
		२०००।	फरमान न० ४६ १०,
२. रायसिंह	१५६५	४०००।	आईने० १ पृष्ठ ३५७,
	१६०६	५०००।५०००	अबवरनामा - ३ पृष्ठ
			८३६, मासिर-१, पृष्ठ
			३६०
३. दलपतसिंह	१६१२	१५००।५००	जहागीरनामा २८७
	१६१२	२०००।१०००	२६६, मासिर-१, ४५६
			सूरजसिंह की जागीर
४. सूरसिंह	१६१३	१५००।१०००	फरमान न० ४३, ६४,
	१६१३	१५००।१२००	जहागीरनामा ३२०,
	१६१८	१५००।१२००	पादशाहनामा-६, मासिर
	१६२६	३०००।२०००	१-४५६; सूरजसिंह की
	१६२६	४०००।२५००	जागीर
	१६३१	४०००।३०००	
५. कर्णसिंह	१६३१	२०००।१५००	फरमान न० ६१,
	१६६६	३५००।२०००	मासिर-२ - २८७
६. अनूपसिंह	१६६७	२०००।१५००	फरमान न० ६१,
	१६६८	२०००।१८००	अनूपसिंह रं मनसब की
	१६७४	२०००।२०००	विगत, मा० आलम-
	१६७५	२५००।३०००	गोरी-१२४, मासिर २,
		२०० सवार पहले	२८६-६१
		शर्त के थे।	
	१६८८	३५००।३५००	
		(५०० जात व	
		सवार शर्तों)	
	१६९३	३५००।३५००	
		बिना शर्तों	
	१६९५	३५००।४०००	
		(१५०० दो अस्प-	
		सिंह अस्प)	
७. स्वरूपसिंह	१७००	१५००।८००	मासिर-२; ६१
अल्प व्यवस्था			

का मनसब था, जिसके बदले तीन करोड़, छब्बीस लाख, बत्तीस हजार, आठ सौ दाम की जागीर प्रदान की गयी। इसमें बीकानेर दर-ओ-बस्त की कुल आय केवल एक करोड़ उन्तालीस लाख दाम थी और बीकानेर परगने की आय एक करोड़ दाम थी।^१ सन् १६६७ ई० में, जब सम्राट औरंगजेब ने अनूपसिंह को बीकानेर का टीका दिया, उस वकन उसे २००० जात व १५०० सवार का मनसब भी प्रदान किया गया था जिसके बदले उसका वेतन एक करोड़ सत्तावन लाख दाम निर्धारित हुआ था। उसमें उसे एक करोड़ उन्तालीस लाख पचास हजार दाम बीकानेर दर-ओ-बस्त से प्राप्त होते थे। सत्तह लाख पचास हजार का पूनिया परगना, सरबार हिस्सा, मूवा दिन्ती का असल से जागीर में दिया गया,^२ लेकिन ज्यो-ज्यो उसके मनसब में वृद्धि होती चली गयी उसे बीकानेर जागीर के और आस-पास के क्षेत्र मिलने लगे। सन् १६६७ ई० में, जब उसका मनसब बढ़कर ३५०० जात व ४००० सवार (पन्द्रह सौ सवार दोहू असा सिंह असा) हो गया तो बदले में उसे तीन करोड़ सत्तासी लाख दाम का वेतन, जागीर के रूप में प्राप्त हुआ। उसे दक्षिण में निपुकिन के स्थान पर भी जागीरें प्रदान की गईं। इस प्रकार मनसब-वृद्धि के साथ उसकी आय के श्रोत भी विस्तृत हो गए। जो नि मन्देह वतन जागीर की आय से अधिक थे। आगे चलकर आद्रणी का किला तो बीकानेर के शामवी, सरदारों व सैनिकों का दूसरा घर बन गया।^३

मुगल सम्राट ने बीकानेर के मामलों को उनके मनसब के आधार पर निर्धारित वेतन के बदले, जो सनकवाह जागीरें प्रदान की थीं, वे अपने स्वल्प में भिन्न-भिन्न थीं। उन्होंने बीकानेर के शासकों को जागीर देते समय उनके वतन जागीर के आनुवर्षिक दावे के अतिरिक्त वतन जागीर के बाहर के क्षेत्रों में पैतृक अधिकारों, उनकी सत्ता की ऐतिहासिक घृष्टभूमि तथा प्रशासनिक व अन्य

१ राजा मुरारिसिंहजी हैं जागीर की विवरण, पृ० ६०-६१, फुटकर बाता न० २०६/२ (पूर्व) —राजा रामसिंह के काल में बीकानेर परगने की जमा वसूल लाख घांटी गई थी। महाराजा मुरारिसिंह के समय से यह एक करोड़ निर्धारित हुई थी। अफसर के समय के परगनों के समस्त घांटी से यह परिवर्तन बाद के समय में आ गया था। बीकानेर परगनों की यह जमा औरंगजेब के काल तक स्थिर रही थी।

—अफसर का राजा रामसिंह को परमान दि० ५ अर्दे जिह्जिह, ४१, चनेल १५६६ ई०, न० ४, सम्राट औरंगजेब का अनूपसिंह को परमान न० ६१ (पूर्व), परगना सरबार विगत—सिरकार, बीकानेर सूबा अफसर न० २२७१ न० पु० स० बी०

२ महाराजा अनूपसिंहजी हैं मनसब के तख्त की विवरण, पृ० ८८-९०, फुटकर बाता (पूर्व) औरंगजेब के काल तक आते-आते मनसब के बदले मिलने वाले वेतन में 'माह वेतन मान' के कारण कमी आ गई थी।

३ महाराजा अनूपसिंहजी हैं मनसब के तख्त की विवरण, पृष्ठ ८८-९०, फुटकर बाता (पूर्व), डा० अठहर अली (पूर्व), पृ० २५६, देखिये, बागीर शारली

राजनैतिक व कूटनीतिक विचारों को अपने सम्मुख रखा था। परिणामस्वरूप मुगल दरबार के अमीरों के बीच बीकानेर शासकों की विशेष सम्मानजनक स्थिति बन गयी थी। मुगल सम्राट ने इनकी क्षेत्रीय परम्पराओं का सम्मान करते हुए, जागीर-वितरण के समय जो सुविधाएँ प्रदान की गयी थी, उनसे राजपूताने में बीकानेर के शासक प्रथम श्रेणी की शक्ति के रूप में उभरकर सामने आये।

बीकानेर-शासकों द्वारा मुगलों से प्राप्त जागीरों की, उनके स्वरूप को देखते हुए तीन श्रेणियाँ बनायी जा सकती हैं—

जागीरों की श्रेणियाँ

१. वतन जागीर या पैतृक राज्य।
२. सीमावर्ती क्षेत्रों की जागीर (ऐतिहासिक व पैतृक दावों का क्षेत्र)।
३. साधारण जागीर-क्षेत्र।

वतन जागीर

वतन जागीर मूलतः तनख्वाह जागीर थी। इसकी अनुमानित आय मनसब के निर्धारित वेतन का एक भाग होती थी। वतन जागीर की आय को आधार बनाकर ही मनसब के वेतन की बाकी रकम को पूरा करने के लिए दूसरी जागीरें प्रदान की जाती थी। परन्तु, वतन जागीर व साधारण तनख्वाह जागीर में आधारभूत अन्तर यह था कि वतन जागीर अन्य तनख्वाह जागीरों के समान स्थानान्तरित नहीं होती थी। वतन जागीर में मुगल सम्राट द्वारा राब बीका के बंशजों का इस क्षेत्र पर दावा माना गया था, जबकि अन्य जागीरों में आनुवंशिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई थी। साधारण तनख्वाह जागीरें जहाँ पूर्ण-तया शाही नियमों से बंधी हुई थी, वहाँ वतन जागीर का प्रशासन राज्य की परम्पराओं से भी चलता था। वतन जागीर के 'जमींदार' स्वायत्तशासी होते थे।^१

बीकानेर वतन जागीर का निर्माण सूबा अजमेर के सरकार बीकानेर के परगना बीकमपुर वरसलपुर बीकानेर और पोकल (पूगल) सरकार नागीर के परगना द्रोणपुर तथा सूबा दिल्ली के सरकार हिसार के परगने सीधमुज, भाडग, धेणीवाल के क्षेत्र में मिलकर हुआ था। यही क्षेत्र बीकानेर दर ओ-वस्त कहा गया।^२

१ राजा मुरजमिषजी के जागीरों की विवरण पृ० ६०-६१ फटकर बाता (पूव) डा० अतहर-मली, (पूव) पृ० ७८ ७९ डा० जी० एन० शर्मा—राजस्थान स्टडीज पृष्ठ २१०

२ आईने प्रकवरी भाग २ पृ० २७७ ७८ (पूव) महाराजा धनूपमिषजी के मनसब के तख्त की विवरण, पृष्ठ ८ ६०, फटकर बाता (पूव) यह सही नहीं है कि सम्पूर्ण बीकानेर सरकार का क्षेत्र बीकानेर राज्य था। डा० करणीसिंह (पूव) पृष्ठ ६१

इस प्रकार मुगलों ने राठौड़ों से सन्धि करने के बाद, बीकानेर राज्य के अधिकांश भाग पर उनके पंतूक अधिकारों को स्वीकार कर लिया था। राज्य के प्रत्येक नये शासक ने मुगल सम्राट से टीका लेने के पश्चात् अपनी अविभाजित वतन जागीर पर पंतूक अधिकारों का प्रयोग किया था। मुगल सम्राटों ने राठौड़ राजवंश से उनकी वतन जागीर के एक बार निर्धारित होने के पश्चात्, किसी भाग को न तो छीना और न ही सीमित किया।^१ यहां यह उल्लेखनीय है कि दोनों राजवंशों के बीच मनमुटाव व असन्तोष का प्रभाव भी वतन जागीर की सीमाओं पर नहीं पड़ा। बीकानेर के शासक, जैसे पहले लिखा जा चुका है, कभी भी डेढ़-हजारी मनसबदार से कम नहीं रहे, जिसके बदले प्राप्त वेतन में बीकानेर वतन की एक करोड़ दाम की आय, सदैव कम ही थी।^२ मुगल प्रशासन द्वारा पूरा वेतन चुकाने के लिए अन्य जागीरें देनी पड़ी।^३ अतः प्रशामनिक कारणों से भी बीकानेर वतन की सीमाएं कभी खण्डित नहीं हुईं।

मुगल साम्राज्य में वतन जागीर का अस्तित्व इस बात का द्योतक है कि निरंकुश मुगल सम्राट, स्थानीय स्वायत्तता पर, प्रभावशाली केन्द्रीय नियन्त्रण की नीति पर चल रहे थे, जो दूसरी ओर बीकानेर का राजवंश प्रशासन में अपने परम्परागत अधिकारों के प्रति सचेत था। मुगल साम्राज्य में चल रही इस प्रकार दो परस्पर विरोधी शक्तियों के परिणामस्वरूप वतन जागीर के स्वरूप को लेकर मुगलों व राठौड़ों के बीच की उस झगड़ें आती रहती थी पर इनका प्रभाव वतन-जागीर की स्थिति पर कभी बुरा नहीं पड़ा था।

सीमावर्ती जागीर

मुगल सम्राट मनसब के बदले प्राप्त वेतन को व्यवस्थित करने के लिए, वतन जागीर के साथ-साथ साधारण तनख्वाह जागीरें भी प्रदान करते थे। उन्होंने ऐसा करते समय, बीकानेर राजवंश की भावनाओं का सम्मान करते हुए,

१ देखिए, जागीर सारणी

—बीकानेर वतन का समस्त क्षेत्र प्रत्येक शासक को प्राप्त हुआ था। उसके किसी भी भाग पर मुगलों का अव्यक्त शासन नहीं रहा था तथा न ही वह किसी अन्य जागीरदार की जागीर का भाग बना था।

२ सम्राट औरंगजेब ने जब महाराजा धनूपसिंह को २००० जात, १२०० सवार का मनसब प्रदान किया था, तो उसका कुल वेतन एक करोड़ सनावन साठ निर्धारित हुआ था जिसमें एक करोड़ उन्तासीस साठ का बीकानेर-दरौ-वस्त था। बाकी के लिए अन्य जागीरें प्रदान की गयी थीं।

—सम्राट औरंगजेब का धनूपसिंह को परमान न० २१ (पूर्व), महाराजा धनूपसिंहजी रं मनसब नै तनेव री विगत, पृष्ठ ८२ ८८

३. वही

जागीर सारणी

मुगल सम्राट से बीकानेर शासकों को प्राप्त जागीर क्षेत्र व उसका वर्गीकरण^१

शासक का नाम	वर्तन जागीर	सीमावर्ती क्षेत्र की जागीर	साधारण जागीर
१	२	३	४
१ कल्याणमल	बीकानेर राज्य	सिरसा	जोधपुर (३ बप तक) मिरोही (कुछ समय के लिए) नागीर मारोट
२ रायसिंह	परगना बीकानेर बीकमपुर पूगल बरसमपुर दद्रवा (बीकानेर सरकार सूबा अजमेर) डोणपुर (सरकार नागीर सूबा अज मेर) सीधमुख भाङग (सरकार हिसार सूबा दिल्ली बीकानेर दरा प्रस्त	परगना भटनेर पूनिया हिसार, तासोम वेणीवाल सिवराण, सिरसा (सरकार हिसार सूबा दिल्ली)	परगना फलोधी जोध- पुर (सरकार जोधपुर सूबा अजमेर) मारोट (स मुलतान सूबा ला हौर) दीपानपुर लाबी (स० जालंधर सूबा लाहौर) बहलौद दरी वाला बरवा अगरवा अतागढ (स० हिसार सूबा दिल्ली) कसूर करहार (स० पट्टा), भटिण्डा सहरोह (स० सरहिन्द सू० दिल्ली)
३ दलपतसिंह		परगना भटनेर पूनिया सिरसा वेणीवाल सिव राण तोसोम (सरकार हिसार सूबा दिल्ली)	परगना फलोधी (सर कार जोधपुर सू० अज मेर) अगरवा (सरकार हिसार सूबा दिल्ली)

१ दलपत विलास प० २३ बीकानेर फरमान न० १० १३ १८ २१ महाराजा सूरज
सिंघजी की जागीर महाराजा अनूपसिंघजी के मुनसब की तलब परगना के जमा जोड
की वही थि० स० १७२७/१६७० ई० वि० १७४७/१६६० ई० दयालदास ध्यात (प्र०)
२ प० ११२ १७, १४६ १५० २६

१	२	३	४
४ सूरसिंह	"	परगना भटनेर, वेणीवाल, सिवराण, तोसोम, सिरसा, हिसार (कुछ भाग) (स० हिसार सूबा दिल्ली)	परगना अगरवा (स० हिसार, सूबा दिल्ली), फलोधी (सरकार जोधपुर सूबा अजमेर), मारोट (सरकार मुलतान, सूबा लाहौर), भटिण्डा (सरकार सरहिन्द सूबा दिल्ली), पनावाडी (सूबा अहमद नगर) नागौर (स० नागौर, सूबा अजमेर)
५ कर्णसिंह	"	परगना भटनेर, पुनिया, वेणीवाल, सिवराण, तोसोम, सिरसा (सरकार हिसार सूबा दिल्ली)	परगना अगरवा (सरकार हिसार, सूबा दिल्ली), नागौर [लेबर अमरसिंह राठौड जोधपुर] को दे दिया गया (सूबा अजमेर) दोलताबाद की किलेदारी
६ अनूपसिंह	"	परगना भटनेर, पुनिया, वेणीवाल, सिरसा, तोसोम, सिवराण (स० हिसार सूबा दिल्ली)	परगना बालसपुर, फतीया-बाद, भगवन्तगढ बूदो-डेरा, अमरसरमन, जोग-रवा, चरखी दादरी (स० हिसार सूबा दिल्ली) झुझणू (स० नारनोल, सूबा आगरा), फलोधी (स० जोधपुर, सूबा अजमेर)
७ स्वरूपसिंह	"	परगना पुनिया (स० हिसार, सूबा दिल्ली) छोटे भाई आनन्दसिंह को । वेणीवाल (स० हिसार, सूबा दिल्ली)	

उन्हें वे जागीरी क्षेत्र प्रदान किये जहाँ वे किसी न किसी रूप में अपने पतन अधिपतों का दावा करते थे। वे क्षेत्र कभी भी बीकानेर दर ओ-बस्त की सीमा में स्वीकार नहीं किए गए थे। उनके ऐतिहासिक दावों को स्वीकार करने से मुगल साम्राज्य में उनका महत्व साधारण मनसबदारों की पंक्ति में अलग-गया हो गया था। इस तरह उनको प्राप्त हुए जागीरी क्षेत्र राज्य के उत्तरी व उत्तर-पूर्वी सीमा से जुड़े सरकार हिमालय के परगने पूनिया, मटनेर व शिवराज इत्यादि में स्थित थे। वे क्षेत्र राय बीका व रावत कायल और उनके उत्तराधिकारियों में जीते थे। लेकिन सन् १५२६ ई० से १५७० ई० के बीच राजनैतिक सङ्घटन के समय में राज्य के हाथ से निकल गये थे।^१ मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद वे इलाके सरदार हिसार के परगने बना दिये गए^२ व इन्हें बीकानेर वसत जागीर में सम्मिलित नहीं माना गया था, परन्तु जागीर के रूप में वे इलाके साधारण-तया बीकानेर-शासकों के पास ही रहे। वे सीमावर्ती जागीरें उनके पास मृत्यु-पर्यन्त रहती थीं।^३ राजा के मरने के पश्चात् नये शासन की उसकी मनसब-वृद्धि के साथ प्राथमिकता के तौर पर उन्हें फिर प्राप्त हो जाती थी।^४ शासक के पास इस क्षेत्र के न आने पर मुगल सम्राट द्वारा राजपरिवार के किसी अन्य सदस्य को जागीर के रूप में इसे प्रदान कर दिया जाता था।^५ इस प्रकार बीका राजवंश को लेकर प्राथमिकता देने से, इन जागीरों का अन्य मुगल जागीरों से स्वरूप भिन्न हो गया था। बीकानेर-शासकों ने इन जागीरों के क्षेत्र में अपने स्वतंत्र अधिपत्य हम गीमा तक बढ़ा दिये थे कि राज्य के पट्टायतो को उन्हाते इन क्षेत्र में वसतानुगत पट्टे भी प्रदान कर दिये थे।^६

बीकानेर के शासकों को, इन क्षेत्रों की जागीर में देने में मुगल प्रशासन को भी लाभ था। बीकानेर के शासक अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्थानीय लोगों से सम्पर्क व उनकी समस्याओं से परिचित होने के कारण एक कुशल प्रशासन देने की क्षमता रखते थे, जबकि कोई बाहरी मनसबदार अपरिचित होने के कारण अनेक कठिनाइयों में उत्पन्न, शक्ति व धन दोनों को नष्ट

१ दयालदास व्यास (प्र०) २ पृष्ठ १८, ६४ ७०, ८३ ८४

२ भाईने अवबरी भाग २ पृष्ठ २६३ २४

३ राजा सूरजसिंह की जागीर की विवरण, पृष्ठ ६० ६१ (पृष्ठ) महाराजा अनूपसिंह की मनसब नै तालब की विवरण, पृष्ठ ८८ ९० (पृष्ठ), देखिए जागीर सारणी

४ वही

५ सम्राट मकबूर ने मटनेर का किला रायसिंह के चचेरे भाई बाघजी को दिया था। औरंगजेब ने महाराजा मुजानसिंह को बीकानेर की जागीर देत समय, उसके छोटे भाई आनन्दसिंह को पूनिया परगना दिया था—परवाना वही, वि० सं० १७४६/१६९२ ई० पृ० २२ दयालदास व्यास (प्र०) २, पृ० ८७

६ पट्टा वही, वि० सं० १६९२/१६३५ ई० न० २, वि० सं० १७५३/१६९६ ई०, न० ७

कर सकता था ।

१८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ये क्षेत्र, व्यावहारिक रूप में, बीकानेर राज्य के स्थाई भाग बन गये । यद्यपि आमेर (जयपुर) राज्य की भाँति बीकानेर राज्य का पूर्ण विकास मुगल जागीरों के हटपने से नहीं हुआ था, किन्तु उससे इसके आकार में वृद्धि अवश्य हुई थी ।^१

साधारण जागीर

बीकानेर-शासकों के मनसब में वृद्धि होने पर अथवा उनकी नियुक्ति के स्थान पर उन्हें साधारण सनच्चाह जागीरें प्रदान की जाती थी, जहाँ वे अन्य जागीरदारों की भाँति कार्य करते थे व तीन चार वर्ष के पश्चात् उनका स्थानांतर हो जाया करता था । इन जागीरों को देने व नई जागीर को लेते समय उनके वेतन के दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । अगर किसी जागीर में इनका सेवाकाल अधिक हो जाता था, तो यह सम्राट की इच्छा या उस क्षेत्र की सैनिक स्थिति व उसके महत्व से ही सम्भव होता था । बीकानेर-शासकों की उस क्षेत्र के लिए मुगल सम्राट से कोई विशेष मांग नहीं होती थी ।^१

इन प्रकार मुगलों से प्राप्त अन्य जागीरों से न केवल राज्य की आय में ही वृद्धि हुई, अपितु मुगल सम्राट द्वारा इनके प्रति अपनाये गए रुख से उनका सम्मान में गौरव भी बढ़ा । वतन जागीर व स्थायी जागीरों के कारण ये मुगल-दरबार के साधारण अमीर नहीं रहे, बल्कि एक विशिष्ट स्थिति में आ गये । बदले में यहाँ के शासकों से भी मुगल साम्राज्य को सेवाएँ प्रदान करके अपनी निष्ठा दिखाई ।

मुगल शक्ति के पतन-काल में राज्य में राजा की स्थिति व उसकी शक्तियों को बहुत हानि पहुँची थी । एक दृढ़ केन्द्रीय सत्ता के संरक्षण के अभाव में, राज्य की उपद्रवी शक्तिमा फिर सिर उठाने लगीं और मुगल-शक्ति का अक्षुण्ण भिट जाने से, राज्य बाह्य आक्रमण के आकर्षण का केन्द्र बन गया । अकेले मारवाड़ ने एक बार के छ आक्रमण किये ।^२ छत्रों से निपटने के लिए राजा

१ दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृष्ठ २१२, २३, ३६, ४६, ८७, ३१८-२०, डा० करणीसिंह का यह मत है कि मुगल सम्राटों से प्राप्त जागीरों से बीकानेर का क्षेत्रीय विस्तार नहीं हुआ था ।—डा० करणीसिंह पृष्ठ ११४-१२, आमेर की अवस्था लिए—डा० एम० पी० गुप्ता—सेण्ट रेवेन्यू सिस्टम इन ईस्टर्न राजपूताना (अप्रकाशित शोध प्रबंध) अध्याय १

२. महाराजा मनुसिंह रं मनसब में तबबरी नियुक्त, पृष्ठ ८८-९० (पूर्व) डा० मनहर अनी पृष्ठ ७८, देखिये, आगीर सारणी

३ दो हाउस ऑफ बीकानेर, पृ० ६८-७०

को विवश होकर राज्य के शक्तिशाली सरदार के साथ समझौता करना पड़ा।^१ राज्य में पुनः सामन्तवादी शक्तियाँ जोर पकड़ने लगीं। शासकों की अयोग्यता ने सामन्तों को अपनी शक्ति दृढ़ करने का एक और अवसर प्रदान किया।^२ उन्होंने विद्रोह करके पट्टा-चाकरी सिद्धांत की छुली अवहेलना प्रारम्भ कर दी। सामन्त कुलीय-भाई चारे के सिद्धांत पर पुनः शासक के साथ सम्बन्ध निर्धारित करने लगे।^३ मन्त्रियों व राजकर्मचारियों ने भी अवसर देखकर शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया।^४ इससे शासक की लोकप्रियता को हानि पहुँची। उत्तराधिकार की जटिल समस्या व राजकुमारों के विद्रोही आचरण ने भी उसकी प्रतिष्ठा गिराने में बरकर नहीं छोड़ी।^५ इस प्रकार शासक की स्थिति में अस्थिरता तथा दुर्बलता के लक्षण प्रकट होने लगे।

महाराजा गजसिंह (सन् १७४८-८७ ई०) एक योग्य शासक थे। उन्होंने अपने दीर्घशासनकाल में, शासक की शक्तियों को पुनः गठित करने के भरसक प्रयत्न किये तथा राज्य में प्रशासकीय दृढ़ता लाने की चेष्टा की, परन्तु वे सभी प्रयास उनके जीवन की अन्तिम मास के साथ समाप्त हो गए।^६ वस्तुतः महाराजा गजसिंह एवं सम्बन्धित समय तक स्थिति को केवल नियन्त्रित ही कर सके थे। शासन व राज्य के विरुद्ध पनपने वाली विनाशकारी शक्तियों को नष्ट करने में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। परिणामस्वरूप उनके उत्तराधिकारियों को फिर उन्ही समस्याओं से जूझना पड़ा।

महाराजा सूरतसिंह द्वारा राज्य पर बलात् अधिकार करने से विरोधियों को एक और अवसर मिल गया। महाराजा के घुणित कार्य के विरोध ने सामूहिक असन्तोष को जन्म दिया। राज्य के सामन्तों ने शासक की सत्ता को चुनौतियाँ देनी शुरू कर दी।^७ दूसरी ओर सूरतसिंह ने भी अपनी स्थिति को दृढ़ करने में शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया। उसने विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया।^८ लेकिन इससे मनोवांछित परिणाम नहीं निकले। निरक्षुण्ण नृप-

१ मोहता भीमसिंह द्वारा जोधपुर महाराजा अजयसिंह के घेरे का वर्णन, पृ० १६-२५, दयालदास श्यात (अप्र०) २, पृष्ठ २५८, ६५, ७६, ३१५, २२

२ बीकानेर की श्यात महाराजा मुजानसिंहजी व महाराजा गजसिंहजी ताई, पृष्ठ ५, ३८, मोहता भीमसिंह द्वारा जोधपुर महाराजा अजयसिंह के घेरे का वर्णन, पृष्ठ ११, ४३, मोहता श्यात, पृष्ठ ६१, ६५

३ दयालदास श्यात (अप्र०) २, पृष्ठ २६५, ३१५-२२

४ मोहता श्यात पृष्ठ ६१, ६५, मोहता भीमसिंह द्वारा जोधपुर महाराजा अजयसिंह के घेरे का वर्णन, पृष्ठ ११, १५, १७

५ दयालदास श्यात (अप्र०) २, पृष्ठ २६३, ३०६ १०

६ बीकानेर की श्यात महाराजा मुजानसिंह व महाराजा गजसिंहजी ताई, पृ० ७० ७७

७ टांड-२, पृष्ठ ११४०-४१

८ दयालदास श्यात (अप्र०) २, पृष्ठ ३१५-२२

तन्त्र व कुलीय-भाई-चारे के सिद्धांत ने दोनों शक्तियों के बीच कोई समझौता नहीं होने दिया। अविश्वास, पड़्यन्त्र व ईर्ष्या के वातावरण में कोई भी समझौता सम्भव नहीं था। अतः राज्य में अव्यवस्था व अराजकता की स्थिति ने जन्म ले लिया। सामन्तो ने अपने ठिकानों को स्वतन्त्र घोषित करना प्रारम्भ कर दिया।^१ महाराजा मुरतसिंह के अडिग विद्वांस व घोर परिश्रम के बाद भी असफलताएँ बढ़ने लगी।^२ विद्रोहियों ने बाहरी आक्रमणों को भी प्रोत्साहित किया।^३ अन्त में, निराश होकर महाराजा ने बीका-राजवंश को सुरक्षित रखने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी की सर्वोच्च सत्ता में शरण लेने का निश्चय किया।

राजा के सामान्य कार्य

हिन्दू शास्त्रों में राजधर्म की कर्तव्यों में सर्वोच्च व पवित्रतम माना है। बीकानेर के राजा भी पौराणिक आदर्श हिन्दू नरेश का पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे।^४ हिन्दू धर्मशास्त्रों और नीतिशास्त्रों में ही उन्होंने अपने आचरण का औचित्य ढूँढा तथा सम्पूर्ण प्रशासन को उन्हीं की मान्यताओं के अनुसार गठित करने का प्रयास किया।^५ पहले लिखा जा चुका है कि वे अपने राज्य को कुलदेवता "लक्ष्मीनारायण जी" और कुलदेवी "वरणो जी" की कृपा का फल मानते थे। इन मान्यताओं के साथ, वे अन्य धार्मिक मतों व विश्वासों के प्रति पूर्ण सहिष्णुता बरतते थे। जाति व समुदाय के धार्मिक मामलों में उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उनका ध्येय सभी धार्मिक मस्झानों के लिए खुला था। वे मुक्त रूप से, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, दान-गुण्य करते थे। मंदिरों के साथ-साथ दरगाहों को भी नियमित रूप से आर्थिक सहायता भेजी जाती थी।^६ हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था का उन्होंने पूर्ण आदर किया तथा अन्य

१. चूक व भादरा के ठाकुरों ने स्वतन्त्र आचरण करना प्रारम्भ कर दिया था।

—इयानदास (अध०) २, पृष्ठ ३१८-२२, चूक मण्डल का इतिहास, पृष्ठ २४४

२. वही।

३. अमीर खाँ निजामों ने ठाकुरों के निमंत्रण पर, राज्य पर आक्रमण किया था, परन्तु उसकी गतिविधियाँ चूक व बीकानेर सीमा-क्षेत्र से अग्रिम नहीं बढ़ी थीं।

—ओमर, प्रथम भाग, पृ० ३६९

४. बर्नावलस, पृष्ठ ६-८

५. महादेव—रायसिंह गुजामिन्दू, पृष्ठ ४, न० ४२८३, अ० स० पु० बी०, गीत गोविन्द टोरा, पृष्ठ १२-१४ पूर्व, बर्नावलस, पृष्ठ १४

६. नियमान्त ई मेस रो बही वि० सं० १७००/१६४३ ई० न० १८८—बीकानेर बहिषात, समयन घोषा रो बही, वि० स० १७२०/१७४६, १६७०/१६६२ ई०, न० ७९

सामाजिक मान्यताओं में अटूट विश्वास अभिव्यक्त किया ।^१

उनके राजदरबार में ब्राह्मणों व चारणों को उचित सम्मान दिया जाता था । राजा के लिए, 'श्री ब्राह्मण-प्रतिपालक' उपाधिया लगायी जाती थी । प्रत्येक राजा ने ब्राह्मणों व चारणों को अनुदान के रूप में गांव व भूमि प्रदान किये थे ।^२ राजा रायसिंह ने तो इन्हीं कार्यों से बहुत यश कमाया था ।^३ महाराजा सूरतसिंह की भूमि व अन्य बहुमूल्य भेंट देने की प्रवृत्ति से ब्राह्मण बहुत लाभान्वित हुए ।^४ महाराजा सूरतसिंह सदा ब्राह्मणों से घिरा रहता था । उसका यह विश्वास था कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उसके पाप धुल जायेंगे ।^५

राजा समस्त राज्य-प्रशासन की मुख्य धुरी तथा समस्त पैनिक राजनैतिक, न्यायिक व प्रशासनिक शक्तियों का केन्द्रबिन्दु था । निःसन्देह मन्त्रियों की एक समिति उसकी सहायता व परामर्श के लिए बनी हुई थी परन्तु अन्तिम निर्णय उस पर ही निर्भर था । प्रजा या उसके प्रतिनिधि, राज्य की मुद्रा अथवा शान्तिकालीन नीतियों के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं थे ।^६

कार्यकारिणी सम्बन्धी समस्त विषयों में राजा की सर्वोच्च सत्ता थी । वह स्वयं अपने मन्त्रियों, दूतों व राज्य के अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता था और उनके सहयोग से राज्य के प्रशासन को संचालित करता था । वह व्यक्तिगत रूप से, मुस्तद्दियों, चिरायतों, हाकिमों व हक्सदारों के कार्यों का निरीक्षण करता तथा उन्हें उचित निर्देश देता था । आर्थिक विषयों पर चिन्तन करके, जनता के प्रार्थना पत्रों को लेकर, सम्बन्धित अधिकारियों को सलाह देकर, वह राज्य की आय व्यय को सन्तुलित रखने का प्रयास करता था । गुप्तचर विभाग से उसका सीधा सम्पर्क था । अपराधियों को दण्डित करके वह राजाशा का सम्मान बनाये रखता था ।^७

१ वही (पृष्ठ ४३ के प्रतिम सदरर्ष अनुसार)

२ परवाना बही वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, पृ० २६

३ दयालदास ख्यात (अप्रकाशित) २, पृ० १२६

४ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० २१०, रामपुरिया रिकार्ड्स, रा० रा० अ० बी०

५ टॉड २, पृ० ११४३ ४४

६ कर्णावतस, पृ० १७ १७, दयालदास ख्यात (अप्रकाशित) भाग २, पृ० २६५ २७६

७ महाराजा मनुपसिंह से आनंद राम बाबुर के नाम परवानों, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, न० १६७/१६ अ० सं० पु० बी०, कामदारों व बकीलों के रोजगार की बही, वि० सं० १७४३/१६६६ ई० न० २०६ थी राबले लेख बही, वि० सं० १७७५/१७१८ ई०, न० २१२ काफ़ी की बही वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृ० २६-२७ सनदी-पत्र, वि० सं० १८३६/१७८२ ई०, न० ६, सनदी-पत्र, वि० सं० १८६३, १८०४ ई० न० १४, सनदी-पत्र, हुवाला पत्र ।

मध्यकालीन भारत के अन्य सामन्तों की भाँति, मुल्क-शाह ने अपनी सेनाओं का मजबूत रख करना, यज्ञों के आयोजन करना महत्त्वपूर्ण व गौरवशाली कर्तव्य समझते थे। स्वयंसेवक भी महत्त्वपूर्ण सैनिक अभियानों में राजा के व्यक्तिगत रूप में भाग लेता था। प्रत्येक राजा स्वयंसेवकों के पदवात् मुगल-सेना के अन्तर्गत अथवा राजा के पारम्परिक युद्धों या विद्रोहियों का दमन करने के लिए महत्वा हो रहा था। इनमें से कुछ ने भी अपने प्राण भी शत्रु से खोते हुए ही स्वयंसेवक थे।^१ वह सभी सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति का स्वयं करता था और उन्हेगनीय सामरिक नेतृत्वों के लिए अपना बलिदान व त्याग के लिए पदचुम्बि व पददे देकर पुरस्कार व अनुमति करता था। यह अपने सहयोगियों से आज्ञात्मक व प्रतिरक्षात्मक नीतियों पर विचार-विमर्श करता था; परन्तु अन्तिम निर्णय गदैव उसकी दृष्टि या सम्मान पर ही निर्भर था।^२

राजा राज्य का मुल्क व्यापारीक भी था। दीवानी व पौजदारी मामलों के अन्तिम निर्णय उसी के हाथ में थे। सभी प्रकार के विवादों की सुनवाई उसी समक्ष ही हो गवनी थी, जिनमें प्रचलित हिन्दू नियमों के आधार पर ही वह निर्णय देता था। निर्णय में पूर्व वह विषयों में सम्बन्धित जानकारी रखने-वाले पण्डितों, मन्त्रियों, महाशय कि स्थानीय पक्षों से भी सलाह लेता था। कई बार वह अपने न्यायिक अधिकार जति-यन्त्रों अथवा प्राचीन पक्षों के सुपुर्द भी कर देता था। पक्षों के निर्णय भी समान रूप में बाध्यकारी थे। यहाँ उत्तरेय-नीय है कि समस्त निर्णय राज्य के कुल-देवता के नाम पर ही किये जाते थे।^३

राजा के क्षेत्राधिकार में जनानी ह्योदी व मुखराज का स्थान

राज्य-प्रशासन अथवा नीति-निर्माण में जनानी ह्योदी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं; लेकिन कुछ दानियों ने बागल व नीति-निर्माण को अवश्य प्रभावित किया था। राजा रायसिंह की पत्नी मृगा का अपने पति व पुत्र, राजा गुरसिंह के शासनकाल में बड़ा मान था।^४ मन्नाजी मूरजहा

१. वसन्तदास व्यास (प्रकाशित) भाग-२, पृ० २८, ४८, ६४ (अप्रकाशित), भाग २, पृ० २७६, दो हज्जि घाँस बीकानेर, पृ० ४४-४६

२. मोहना भीमसिंह द्वारा जोधपुर महाराजा जयसिंह के बीकानेर घेरे का वर्णन, पृ० १६-२२

३. कर्णावत, पृ० ६, १८, ६६; बागदो की कहियाँ, वि० सं० १८११/१७५४ ई०, न० १, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, वि० सं० १८२४/१७६७ ई०, न० १०, रीठ के कायद

४. मोहना-कथन, पृ० १३, मोहना भीमसिंह द्वारा जोधपुर महाराज जयसिंह के घेरे का वर्णन, पृ० २०, बीकानेर की कथान महा राजा भूषणसिंहजी व महाराजा गजसिंहजी तर्क, पृ० १७

विवश किया था।^१ अतः जनसंख्या की कमी, तत्पश्चात् कर-वसूली की समस्या ने शासक को प्रजा के प्रति अत्याचारी होने से सदैव रोका। वित्तीय आवश्यकताएँ उसे प्रजा के साथ मिलकर चलने को विवश करती थी।^२

इस प्रकार शासक परिस्थितियों से समझौता करके अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकता था।

१ प्रत्येक अकाल व सूखे के वर्ष यहाँ के लोग पड़ोसी क्षेत्रों में चले जाते थे। कागदों की वही, वि० सं० १८३१ माघ सुदी ३, २३ जगवरी, १७७३ ई०, न० ६, वि० सं० १८६६/१८०६ ई० न० १३, पृ० १२२-२६, वि० सं० १८७२/१८१३ ई०, न० २१, पृ० ३० ४१

२ कागदों की वही—ज्येष्ठ सुदी ३, वि० सं० १८३१/३१ मई, १७६४ ई०, न० ६; जी० एस० एल० देवड़ा—बीकानेर-निवासी और देशान्तर यमन प्रवृत्ति, राज० हिस्ट्री काग्रेस, १९७६

तृतीय अध्याय

सामन्त-वर्ग एवं पट्टा-प्रणाली

सामन्त-प्रथा का उद्भव व विकास

बीकानेर राज्य में सामन्त-व्यवस्था का उद्भव राजपूतों की कुलीन परम्परा में हुआ। राज्य केवल शासक की ही सम्पत्ति नहीं था, अपितु मार-बाड से आये हुए राठौड़ों की सामूहिक धरोहर थी। मालसा व ठगुराई क्षेत्र दोनों साथ विकसित हुए थे। राज्य के सामन्त शासक के सहयोगी के रूप में राज्य के निर्माण-कार्य में भागीदार थे। राठौड़ सेनापतियों की दृष्टि में राजा राठौड़-कुल का प्रधान था। वे स्वयं को राव बीका के अधीनस्थ नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में मानते थे।^१ राव बीका के अधीनस्थ सामन्तों में, स्थानीय शासक जाति के मुखिया—भाटी, साख्खा, बाघोड, चौहान इत्यादि आते थे।^२ यह सामन्त-व्यवस्था बीका के वंशजों में राव बल्ल्याणमल तब चमकी रही। राव लूणकरण व उसके पुत्र राव जैतमी ने इस स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने राठौड़ों की कुलीन परम्परा को अधीनस्थ सामन्त-बादी ढांचे में ढालने के प्रयत्न किये, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी।^३

राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग ८० प्रतिशत से अधिक भाग विभिन्न कुल-मुखिया व अधीनस्थ सामन्तों के अधिकार में था।^४ राज्य की अधिक उप-जाऊ भूमि पर भी इन्हीं का स्वामित्व था। इन उपर्युक्त दो तथ्यों ने आने-वाले वर्षों में, शासक-सामन्त सम्बन्धों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। शासक की महत्वाकांक्षाओं तथा राज्य के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों के कारण जब शासकी

१. बीकानेर र घनीया री गाह में बीजी फुटकर बाता, पृ० १०-१२; नैनघरी री ध्यात, भाग २, (पूर्व) पृ० ३८, दयालदास ध्यात, (प्र०) २, पृ० ७-८

२. दयालदास ध्यात, (प्रकाशित) भाग २, पृ० ७-८

३. राठौड़ा री बसावली नै पोटिया नै फुटकर बाता (पूर्व) पृ० १६-१९; दयालदास ध्यात, (प्रकाशित), भाग २, पृ० ३५-३६

४. महाराजा भनूपसिंह के काल में आकर भी बड़ा सामन्तों के गांवों की संख्या ११८८ थी, बड़ा घामसा गांवों की संख्या केवल २६१ थी।

—पट्टा बही, वि० सं० १७२५/१६६८ ई०, न० ४, ५ रामपुरिया रिवाज, बीकानेर, बही घामसा री गावा री वि० सं० १७२५/१६६८ ई०, न० ६२, बीकानेर बहिषाव

को ग्रामगा भूमि को विस्तृत करने व उपजाऊ क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए विवश होना पड़ा तो उनसे बीच एवं स्यायी तनाव जन्म लेने लगा। शासक व सामन्तों के बीच सम्बन्धों का क्या रूप हो, यह भी दोनों शक्तियों के मध्य तनाव का कारण था। यदि सामन्त राज्य में राठौड़-कुलीय व्यवस्था को बनाये रखने के पक्ष में थे तो शासक अपनी शक्तियों व प्रणिष्टा को बढ़ाने के इच्छुन थे। वे शासकीय नवृत्त के अधीन सामन्त-व्यवस्था को गठित करना चाहते थे।

प्रारम्भ में, राठौड़-कुल के विभिन्न मुखिया, जो अपनी-अपनी छाप के 'पाटबी' थे, अपने अधिकृत क्षेत्र में एक स्वतन्त्र शासन की तरह ही आचरण करते थे। वे केवल अपने कुलपति को राज्य व कुल का प्रथम व्यक्ति मानकर आवश्यकता पड़ने पर उसे नैनिष महयोग देकर अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण हुआ समझते थे। वे राव, रावत जैसे महत्वपूर्ण पदधियां धारण करते थे। साधारणतया वे 'ठाकुर' कहलाते थे व उनका क्षेत्र 'ठकुराई-क्षेत्र' कहलाता था। अपनी छाप के वे 'पाटबी' होते थे तथा वे अपने छाप के सदस्यों को जीवन निर्वाह के लिए 'ठकुराई क्षेत्र' में गांव प्रदान कर सकते थे। वे अपने अधिकृत क्षेत्र का बटवारा भी कर सकते थे एवं उनमें मनचाहा प्रशासनिक परिवर्तन भी ला सकते थे। उनके उप-सामन्त, जो 'छुट-भाइयो' के नाम से

१. महाराजा जोरावरसिंह, गजसिंह व गुरतसिंह की नीति इस घोर विरोध थी। दयालदास श्यात, (प्र०) २ पृ० २२६-२३०, २३१-२५, २६३-६४
२. बीकानेरी व बीकानेरी ने महाराजा गुरतसिंह को इसी प्रश्न पर चुनौती दी थी—दयाल-दास श्यात (प्र०), भाग २ पृ० ३६३-६७
३. मुखिया, जो साधारणतया छाप की प्रथम पक्ति से सम्बन्धित होते थे। छाप का अर्थ यहाँ एक जाति के परिवार से ही जो बाद में उपजाति का स्वरूप धारण कर लेता है।
४. बीकानेर रं धणीया री बाद में बीकानेर फुटकर जाती पृ० ७-१०, बीकानेर रं राठौड़ा री श्यात सोहेजी सँ—पृ० १२३ २५, न० १६२/१४, दयालदास श्यात (प्र०) २ पृ० ७-१०, ३५-३८, ४२-४३
५. राठौड़ा री बसावली ने पोटिया ने फुटकर जाती न २३३/६ (पूर्व)
६. राज्य के सामन्तों की प्रारम्भ में 'ठाकुर' कहा जाता था। दत्तपत विलास व बाद की श्यातों ने इसी पदवी का प्रयोग किया गया है। महाराजा वर्णसिंह के समय की पट्टा बही व बाद की पट्टा बही व परवाना बहियों में सामन्तों को पट्टाबज कहा गया है।
—दत्तपत विलास पृ० १६ २७, बीकानेर रं पट्टा रं गावा री बिलास राजा करणसिंह जी रं सर्वे री, वि० सं० १७१४/१६५७ ई०, पट्टा बही, वि० सं० १७२५/१६६८ ई० न० ४५, परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई०, रामपुरिया रिकार्ड्स बीकानेर रा० ग० अ० बी, दयालदास श्यात, (प्र०) २ पृ० ३८
७. राठौड़ा री बसावली ने पोटिया ने फुटकर जाती पृ० ५८ ६३ न० २३३ ६ धार्या श्यात कल्याण, पृ० १८७-८८

सामन्त-वर्ग एवं पट्टा-प्रणाली

जाने जाते थे, अपनी 'छाप' के 'पाटवी' के प्रति निष्ठावान होते थे। 'ठिकाने-दार' की जमीयत भी इन्हीं 'छुट भाइयो' की टुकड़ियों से बनती थी। 'छाप-पाटवी' का राजा के साथ सघर्ष होने की अवस्था में उप-सामन्त अपने 'पाटवी' को समर्थन देते थे। ये छुटभाई भी अपनी उप-इकाइयों का प्रशासन स्वतन्त्रतापूर्वक चलाते थे।^१ एक छाप के अगर दो-तीन स्वतन्त्र ठिकाने भी स्थापित हो जाते अथवा छाप के 'पाटवी' का उन पर कोई नियन्त्रण भी न रहता, तो भी वे अपनी छाप के 'पाटवी' को ही सम्मान देते थे। 'पाटवी' का ठिकाना ही छाप का मुख्य 'ठिकाना' माना जाता था।^२ इस प्रकार उस समय राज्य एक शिथिल सघ-व्यवस्था के रूप में था, जो अनेक स्वतन्त्र आन्तरिक प्रशासन इकाइयों में बंटा हुआ था।

राजत बघल, राज बीदा महला रूपा, नाया राज्य के प्रथम ठिकानेदार थे। ये अपनी-अपनी छाप के जन्मदाता भी थे।^३ राज बीका के उत्तराधि-कारियों ने भी अपने भाइयों व परिवार के अन्य सदस्यों के लिए स्वतन्त्र 'ठिकाने' बाँचे थे। उनके 'ठिकाने' भी अपने स्वरूप में पुराने 'ठिकानों' की भाँति ही थे।^४ उनकी भी अपनी अलग छापें चल पड़ी थी। इस प्रकार प्रारम्भ से ही राज्य का सामन्त-वर्ग (दरबार) मुख्य रूप से तीन वर्गों में बंटा हुआ था—प्रथम, राज बीका के वंशज, द्वितीय, बीका के भाई व चाचा के वंशज, तथा तृतीय, स्थानीय जातियों के ठिकानेदार व मुखिया थे।

गर्न-गर्न राज्य प्रशासन में केन्द्रीकरण की शक्तियाँ दृढ़ होने लगी। राजा रायसिंह ने अपने सामन्तों को महयोगी समझने के स्थान पर अधीनस्थ माना। पट्टा-प्रणाली प्रारम्भ करके सामन्तों के अधीनस्थ क्षेत्र का राज्य-सेवा में निश्चित दायित्वों के साथ सम्बन्ध जोड़कर, सम्पूर्ण सामन्ती व्यवस्था को एक

-
- १ विपदरी की सेना
 - २ राठौर की वशावली में पीढ़ियाँ नें फुटकर बता, पृ० ५६-६३, न० २३३/६, प्रायोज्यान
 - ३ कल्पद्रुम, पृ० १८७ ८८
 - ४ बीकानेर के पट्टे के गाँवों की विगत, वि० सं० १७१४/१६५७ ई०, देशदर्पण, पृ० ६४ से ६७
 - ५ राठौर की वशावली में पीढ़ियाँ नें फुटकर बता, पृ० ५६-६३, न० २३३/६
 - ६ बीकानेर के पट्टे के गाँवों की विगत, वि० सं० १७१४/१६५७ ई०, देशदर्पण पृ० ६४ से ६७
 - ७ बीकानेर के राठौर राजाओं की नें बीका मौकाँ की पीढ़ियाँ, २२६/२, सं० सं० पु० बी०,
 - ८ दयालदास ध्यात, (प्र०) ३, पृ० ३६
 - ९ राठौर की पट्टावली धासपस सू बीकानेर के मूरजसिंहजी ताई, दयालदास ध्यात (प्र०) ३, पृ० ३५-३७, ६७-६९, ८४ ८५

नया स्वरूप प्रदान कर दिया।^१ अब शासक प्रजा व सामन्त दोनों का अधि-पति बन गया। अपनी-अपनी नीतियों का विरोध करनेवाले सभी बड़े सामन्तों की शक्ति का उसने कठोरता से दमन किया तथा उन्हें निर्धारित शर्तों पर राज्य की सेवा करने के लिए बाध्य किया।^२ प्रत्येक सामन्त को शासक की कृपा पर आश्रित किया गया। दरबार में बैठने के लिए उन्हें एक निश्चित स्थान प्रदान किया गया एवं उन्हें अलग-अलग श्रेणियों के सम्मानजनक ढाके ढालकर उनकी दरबारी स्थिति स्पष्ट की गई।^३ राजा रणसिंह के उत्तराधिकारी भी सदैव इन्हीं नीतियों का सक्रिय पालन करते रहे, जिनसे सामन्त अपना स्वतंत्र बंधन छोड़ बैठे और राज्य के चाकर बन गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन परिवर्तनों के पश्चात् भी बीकानेर-दरबार अन्य राजपूत राज्यों के दरबारों की भाँति अपनी कुल परम्पराओं पर ही गठित रहा। मुगल दरबार की भाँति पद व दायित्व से जुड़कर सामन्त की स्थिति राजपूत-दरबार में बैठने की नहीं बनी। राजपूत-दरबार में पद के आधार पर श्रेणियाँ नहीं बनी थी। विभिन्न राजपूत खासों की जो स्थिति राजपूत-समाज व राज्य में थी तथा जिन्होंने अशूल्य सेवाएँ सिंहासन को प्रदान करके स्वयं के कुल को गौरवान्वित किया था, उन्हीं का प्रतिरूप ही दरबार में था। सामन्त अपने-अपने कुल की स्थिति-अनुसार श्रेणियाँ बनाकर दरबार में बैठते थे। अन्य जातियों के प्रवेश के बाद भी मूलतः दरबार इन्हीं की जाति का रहा। केवल शासक की शक्तियाँ घट जाने से उसकी स्थिति में अन्तर आया था। मूल ढाँचे में परिवर्तन न होने के कारण ही सामन्त १८वीं शताब्दी में शासक की शक्तियों को चुनौती दे सके।

राज्य के मुख्य सामन्तों में, जायल व बीदा के वंशज थे, जो अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिये शासक की नई स्थिति को गम्भीर चुनौती दे सकते थे। राजा रामसिंह व उसके उत्तराधिकारियों ने उन्हें व अन्य प्रभावशाली सामन्तों को नियंत्रित करने के लिए भिन्न-भिन्न नीति अपनायी। बीदावतों की शक्ति को तोड़ने के लिए उनकी क्षेत्रीय इकाइयों को उनके छुट-भाड़्यों में बाँट दिया और उनमें कई स्वतंत्र 'ठिकानों' को स्थापित किया।^४ हालाँकि 'पाटवी टाकुर' को सम्मान बना रहा, लेकिन छुटभाई अपनी स्थिति व सम्मान के लिए राजा

१ पट्टा बही, वि० सं० १६८२/१६२५ ई० न० ३३/१—रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर, बीकानेर रं पट्टा रं गावा रं विगत

२ दलपत बिलाम पृ० ७०-७१, दयानंदाम स्थात (प्र०) २ पृ० ३८-४१

३ बीकानेर रं गावा रं पट्टा रं विगत (पूर्व), वही दरबार रं ग्रंथ नथमन रं सम रं (पूर्व) १८५७/१८०० ई०

४ देखिये, बीदावत पट्टों की सूची—भार्यान्वय कल्पद्रुम

नया स्वर
 पति बन ग
 की शक्ति
 राज्य की
 कृपा पर ।
 स्थान प्रद
 ढालकर २
 धिवारी १
 अपना स्व
 नीय है वि
 के दरबार
 वार पी ।
 बैठने की
 थी । वि
 तथा जि
 वा वत ।
 कुल की ।
 के प्रवेश
 की शक्ति
 परिवर्तन
 को धुनी
 रा
 को बना
 राजा रा
 को निय
 को तोड़
 और उ
 का सम्

-
- १ पट्टा
 वीर
 २ दलप
 ३ बोका

की कृपा पर आश्रित हो गये।^१ कायलोतों के तीन-चार शक्तिशाली 'ठिकाणे' स्थापित हो चुके थे और उनका राज्य में काफी प्रभाव था। उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया। कायलोतों के 'ठिकाणों' के पास बीका के बंजरों को 'ठिकाणों' दिये गए, और इस प्रकार कायलोतो के छेत्र में शक्ति-संतुलन स्थापित किया गया।^२ इससे अनावा शासकों ने जहां तक सम्भव हुआ, छुट-भाइयों को स्वतंत्र ठिकाणों देकर, पुराने 'ठिकाणों' की एक-रूपता को समाप्त करने का प्रयत्न किया। जहां प्रारम्भ में बीका और कायलोतो के १-१ ठिकाणे थे, वे बढ़कर ३३ हुए^३ और फिर शासकों की मुगल-अधीनता के पश्चात् १२ व १३ की सख्या में स्वतंत्र 'ठिकाणों' के रूप में बढ़ गए।^४ शासकों ने बीका-ठिकाणों को भी अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया। वे छुट-भाइयों को जागीर देकर बीका ठिकाणों की सख्या बढ़ाते रहे। सन् १८१८ ई० तक बीका राठीडों की विभिन्न गावों के २६ ठिकाणें स्थापित हो चुके थे।^५ प्रायः प्रत्येक शामक ने राज्य में नये 'ठिकाणें' बाँचे थे, लेकिन इस दिशा में राजा रायसिंह, सूरसिंह, महाराजा गर्जसिंह तथा सूरतसिंह अधिक सक्रिय रहे। अन्तिम दो शामकों ने तो १६-१८ नये ठिकाणें बाँचे थे।^६ इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि नये 'ठिकाणों' की स्थापना से 'ठकु-राई' क्षेत्र के गांवों की सख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि १८वीं शताब्दी में राज्य की सीमाओं का विस्तार भी हुआ था। सन् १५२५ ई० में जहां पुराने सामन्तो (आसामीदार बाकर)^७ के कुल पट्टे के गावों की सख्या ११५४ थी वह १८१८ ई० तक केवल १२२६ तक पहुँच गई जबकि राज्य के कुल पट्टे के गावों की सख्या १२४२ से १६०८ तक पहुँच गई थी। इन वर्षों में राज्य के कुल पट्टे के गावा की सख्या में ४० ८०% की तुलना में पुराने सामन्तों के गावा में ६२३% ही वृद्धि हुई थी। सन् १६५७ ई० में इनके ६९६ गावों की तुलना में यह अवश्य वृद्धि मानी जा सकती है, परन्तु शासक की सामंता के प्रति चौकस रहने की नीति को देखते हुए, यह घट-बढ़ कोई

- १ परमाना नहीं वि० स० १७४६/१६६२ ई० पृ० ४४४८ न० १, रामपुरिया रिकार्ड्स
- २ पट्टेदारों का मानचित्र
- ३ राठीडा रो बंशवली में पीढ़ियों में फुटकर बातें पृ० ६०
- ४ पट्टा वही वि० स० १६८२/१६२५ ई० न० १, बीकानेर के पट्टे के गावा की विगत, पट्टा वही वि० स० १७२५/१६९८ ई०, न० ५, पट्टा वही, वि० स० १७५३/१६६६ ई० न० ७, देगदर्शन पृ० ८४ १४६, आर्वाध्यान क पदुम, पृ० १८७ २०६, देखिये सूची भाग न० १
- ५ वही
- ६ वही, ब्रिष्ठा वर तात्पर्य स्थापित करने से है।
- ७ ऐसे पट्टायत जिनके पट्टे बलानुगत व स्थायी थे।

पट्टा गांवों की संख्या*

वर्ष	आसामीदार चाकर पट्टो की संख्या	आसामीयो की संख्या	प्रति पट्टायत औसत गांव (लगभग)	अन्य पट्टा गांवों की संख्या	पट्टे के गांवों की कुल संख्या
१६२५ ई०	११५४	—	—	८८	१२४२
१६५७ ई०	६६६	३१६	३	१६०	११५६
१६६८ ई०	१०३०	४०३	६	१०४	११७४
१८१८ ई०	१२२६	४३०	२८५	३८२	१६०८

विशेष महत्व की नहीं थी। आखिर, १६५७ ई० में इनके गांवों की संख्या, १६२५ ई० की ११५४ से घटकर ६६६ तक पहुँची थी। फिर, राज्य के कुल पट्टे के गांवों में निरन्तर स्थिति गिरने से पुराने सामन्तों की स्थिति को भारी धक्का पहुँचा था। १६२५ ई० में सामन्तों के पट्टा की स्थिति, राज्य के कुल पट्टे के गांवों में ६२.६१% थी, वह ऊमण बिरते हुए १८१८ ई० में ७६.२४% रह गई। इनके प्रति 'पट्टायत' औसत गांव की संख्या १६५७ ई० में ३ गांव से घटकर १८१८ ई० में २८५ हो गई। इस प्रकार वस्तुतः पट्टा-क्षेत्र के गांवों की संख्या बढ़ने से पुराने व स्थायी सामन्तों को लाभ नहीं पहुँचा था, बल्कि उनकी स्थिति में गिरावट आई थी। नये विजित क्षेत्रों का लाभ भी इस कारण प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि शासकों की नीति इन क्षेत्रों को

१ राज्य में पट्टायतो व उनके गांवों की स्थिति व संख्या के बारे में जानकारी देने हेतु, पट्टा बहियो में सामग्री प्रचुर मात्रा में है। ये बहिया राजा सूरसिंह (सम्राट जहागीर) के काल से प्रारम्भ होकर १६वीं सताब्दी तक चलती रही हैं। परन्तु, इनमें से बहुत-सी बहियों की सूचना पूर्ण नहीं है। इस कारण मैंने पट्टेदारों की स्थिति व उनके गांवों की संख्या के अध्ययन के लिये चार बहियाँ को, जो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं, को आधार बनाया है। प्रथम बही, राजा सूरसिंह के काल में, सन् १६२५ ई० की है—पट्टा बही वि० सं० १६८२/१६२५, न० १, रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर। द्वितीय, बही राजा कर्णसिंह के काल में, सन् १६५७ ई० की है, —बीकानेर रं पट्टा रं गावा रं विगत राजा कर्णसिंहजी रं सर्व रं, वि० सं० १७१४ १६५७ ई०, न० २२६/२, धनूप सस्वत पुस्तकालय, बीकानेर। तृतीय बही फिर रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर की पट्टा बही, वि० सं० १७२५/१६६८ ई०, न० ५ की, महाराजा धनूपसिंहजी के काल की कुनी है। चतुर्थ बही भँय्या-सबह (निजो सबह), बीकानेर की है जो महाराजा सूरसिंह के काल में वि० सं० १८७५/१८१८ ई० का विवरण देती है।

"इस अध्याय में पट्टायतो की जो सूचियाँ बनाई गई हैं उनसे उपर्युक्त नामांकित बहियों परान् सन् १६२५, १६५७, १६६८ व १८१८ ई० की बहियों से धाकड़े लिये गये हैं। धागे के पट्टों में इन बयों का उल्लेख इन्हीं बहियों के सदर्थ में किया जायेगा। भ्रम से पाद-टिप्पणी नहीं दी गई है।

खालसा में रखने की थी।^१

इस काल में राज्य के पुराने सामन्तों के पट्टों के स्थान पर नये अस्थायी 'चाकरी' पट्टों 'परसगी', 'चींछड', 'कामदार', 'हजुरी', 'राजलोक' तथा 'सामण' के गावों की सख्या बढ रही थी। सन् १६२५ ई० में जहा उनकी सख्या मात्र ८८ थी, वह १६५७ ई० में बढ़कर १६० हो गई तथा थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ वह १८१८ ई० में वह ३८२ गावों की सख्या तक पहुच गई। १६२५ ई० में जहा इन पट्टों के गावों की स्थिति राज्य के कुल पट्टों के गावों में ६०८% थी, वह १८१८ ई० में २३७५% हो गई। १६२५ ई० के आधार पर १८१८ ई० तक ३३४०६% की वृद्धि हुई जो कि अपने आपमें महत्वपूर्ण थी, तथा जासकों के राज्य के सामन्त-वर्ग के प्रति अपने परिवर्तित दृष्टिकोण को हर कोण से स्पष्ट करती है। शामकों का इनकी वृद्धि के प्रति इतना उत्साह था कि खालसा गावों की कीमत पर इन्हे प्रयत्न किया गया था।^२

इस प्रकार एक ओर सामन्तों की शक्ति नियंत्रित करने की नीति अपनाई गई तो दूसरी ओर शामकों के द्वारा खानसा-भूमि को विस्तृत करने के प्रयत्न किये गये। पहले खानसा-भूमि राजधानी के आस-पास के क्षेत्र तक ही सीमित थी, पर धीरे-धीरे दूरस्थ क्षेत्रों को भी खालसा में परिणत किया जाने लगा।^३ शासकों ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की 'सूई'^४ जमीन को खालसा में मिलावे में विशेष हथि दिखाई, ताकि राज्य की आय के माध्यन बढ़ाये जा सकें। वह काश्गरीतो का प्रभाव-क्षेत्र था। वहा शामकों ने बीका राठौड़ी के भी 'ठिकाने' बाधे। परिणामस्वरूप एक ओर शामक व काश्गरीतो के बीच तथा दूसरी ओर काश्गरीतो व बीका राठौड़ी के 'ठिकानेदारों' के बीच मतभेद शुरू हो गया।^५

१ दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृ० ३२२-२५, ३७०

२ ऐसे राजपूत पट्टामन, जिनमें शादी-व्याह के सम्बन्ध तय किये जाने थे।

३. निजी सैनिक

४ राजपरिवार के सदस्यों के पट्टे

५ पुष्पार्थ भूमि (अनुदानित)

६ खानसा गावों की सख्या, १६६८ ई० में २५० थी, जो १८०० ई० में इस नीति के कारण घटकर १५० के लगभग रह गई—वही खानसा री गावा री, वि० स० १७२५/१६६८ ई०, न० २६; खानसा री गावा री बही, वि० स० १८१७/१८०६ ई०, बरता न० १ बीकानेर रिकार्ड, रा० रा० ध० बी०

७ पट्टा बही—१६२५, १६२७, १६६८, १८१८ ई० (पूर्व)

८ सप्त भूमि

९. भाद्रा के काश्गरीतो व भूकरका के बीकावता के बीच सर्वत्र वैमनस्य बना रहा। वही के शासकों की भाद्रा के प्रति नीति भी इसी स्वार्थ से प्रेरित थी।

—बीकानेर री व्यास महाराज मुखाणसिपजी व महाराज राजसिपजी साँई, पृ० ५-६; दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृ० २६३, ३३३-३५

सामन्तों की शक्तियों पर और अकुश लगाने तथा शासक की शक्ति बढ़ाने के लिये 'ठकुराई'-क्षेत्र में शासक द्वारा वसूल किये गये करों की संख्या भी बढ़ने लगी। पहले वे केवल 'पेशवाशी' व 'खेद खरब' दिया करते थे।^१ अब उन्हें नियमित रूप से कई नये करों का भार सहन करना पड़ा। धुमाँ भाछ^२, 'हवूर', रुखवाली भाछ^३ व 'घोड़ा रेख'^४ आदि कई कर उन्हें प्रतिवर्ष चुकाने पड़े।^५ उनसे 'जगात'^६ आदि के अधिकार भी छीन लिये गये^७ तथा उनके भूमि व न्यायिक अधिकार भी सीमित कर दिये गये।^८ महात्तक कि प्रत्येक नया ठाकुर शासक से पट्टा प्राप्त करने के बाद ही अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाता था।

सामन्त-वर्ग की रचना

प्रारम्भ में राज्य का सामन्त-वर्ग मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित था। प्रथम, वे बुलीय सामन्त तथा उनके वंशज, जो राव बीका के साथ मारवाड़ से आये थे। द्वितीय, वे सामन्त, जो राव बीका के वंशज थे तथा तृतीय, स्थानीय शासक जाति के मुखिया, जो अधीनस्थ सामन्त बन गये थे। इनके अलावा परदेशी सामन्त भी थे, जिन्हें शासक द्वारा समय-समय पर राज्य-सेवा में सम्मिलित किया गया था। इन सामन्तों में सबसे अधिक संख्या स्वाम्याधिकारी पर राठौड़ों की थी, जो अपनी अनेक शाखाओं (खापों) में विभक्त थे। परदेशी सामन्तों में राजपूतों की अन्य जातियाँ व उनकी खापें थीं। राजपूतों के अलावा अन्य सैनिक जातियों को सामन्त-वर्ग में सम्मिलित करने में बहुत कम उत्साह दिखाया गया था।^९

१ दत्तपत विलास, पृ० १४-१५

२ गृहकर

३ रक्षाकर

४ सैनिक दायित्व कर

५ बीरा जमरासर बीराहद गुसाईमर रं सेख री बही वि० सं० १७६६/१७४२ ई०, न० ३१, धुमा रोकड बही वि० सं० १७५०/१६६३ ई० न० ८८ बोकानेर बहिषात, हवूर बही, वि० सं० १८१२/१७५५ ई० बला न० १

६ सीमा व जुगी कर

७ परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई० पृ० ४१-४४। शासक ने अपनी विशेष कृपा से कुछ सामन्तों को इसकी वसूली के अधिकार प्रदान किये थे।

८ कागदों की बही वि० सं० १८७३/१८१६ ई० न० २२, पृ० ४५

९ राज्य के पुराने सामन्तों में ओहिया व भट्टी जाति के नेता सम्मिलित थे। बाद में अस्थायी पट्टे अवश्य गैर राजपूतों को दिये गये थे। इनमें मुस्लिम, खत्री व मिक्खों की संख्या सबसे अधिक थी। —परवाना बही वि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृ० ३२१, दयालदान ख्यात (प्र०) २, पृ० ७६

राज्य के राठोड सामन्त अपनी निम्न स्थापों में विभक्त थे :

बीकावत—राज्य के संस्थापक राव बीका के वंशज बीकावत राठोड कहलाते थे। साधारणतया पाटवी भाषा से राज्यघड़ी का उत्तराधिकारी चुना जाता था व अन्य वंशजों के निर्वाह व सम्मान के लिये 'ठिकाने' बाँट दिये जाते थे। राज्य के सामन्तों में सबसे अधिक सख्या इन्हीं की थी। बीका वंश के होने के कारण दरबार में इनका विशेष सम्मान भी था। राज्य के चार 'मिरासत ठाकुरों' में दो बीका राठोड ही थे।^१ ये महाजन और भूकरवा के ठाकुर थे। अपने भाई-सम्बन्धी होने के कारण प्रत्येक शासक ने बीका राठोडों को पट्टा देने में पूर्ण उदारता दिखाई थी। महाराजा रायसिंह, गुरसिंह व गुरतसिंह ने इन्हें सबसे अधिक पट्टे दिये थे। महाराजा गुरसिंह ने तो अपने शासन-काल में दिये ७ पट्टों में ६ पट्टे बीका राठोडों को ही प्रदान किये थे।^२ साधारणतया ये नामक के प्रति अत्यन्त स्वामिभक्त होते थे, परन्तु महाराजा गुरतसिंह के समय में अवश्य कुछ प्रमुख 'ठिकानेदारों' के सम्बन्ध शासक के साथ बिगड़ गये थे, जिसने फलस्वरूप कुछ समय के लिये उनके 'ठिकाने' जप्त कर लिये गये थे। उनमें अजीतपुरा, सांघू व सीधमुल के ठिकाने मुख्य थे।^३

बीकावत पट्टों के गांवों की स्थिति^४

वर्ष	कुल बीका पट्टों के गाँव	वृद्धि (प्रतिशत में)	राज्य के कुल पट्टा गाँवों में स्थिति (प्रतिशत में)	शासमीशर बाबर पट्टा गाँवों में स्थिति (प्रतिशत में)	पट्टायतो की सख्या	प्रति बीका पट्टायत के पास औसत गाँव
१६२५	३२६	१००	२६.३२	२८.३३	५४	६.०५
१६५७	३०४	९२.९६	२६.२९	३१.४६	६१	४.९९
१६६८	३८४	११७.४३	३२.६०	३५.८८	९१	४.२१
१८१८	४६०	१४०.६७	२८.६०	३७.१२	१३६	३.३८

१ मिरासत का वर्ष प्रथम मा मुम्ब। राज्य के चार प्रमुख ठिकानेदार—महाजन (रतन भोज बीका), भूकरवा (गृगोम बीका), बीदासर (बीदावत) तथा रायनसर (काध सोत) के थे—भार्याश्रयन कलाद्रुम, पृ० १८७

२ भार्याश्रयन कलाद्रुम, पृ० १८७-८८, देशदर्पण, पृ० ९९-१०१, शासक द्वारा प्रदत्त पट्टे की सूची—पार्ट न० १

३ दयानंदाम स्थात (अग्र०) २, पृ० ३२२

४ पूर्व उद्धृत

सामन्तो की शक्तियों पर और अधिक लगाने तथा शासक की शक्ति बढ़ाने के लिये 'ठकुराई'-क्षेत्र में शासक द्वारा वसूल किये गये करों की सख्या भी बढ़ने लगी। पहले वे केवल 'पेशवशी' व 'खेड खरच' दिया करते थे।^१ अब उन्हें नियमित रूप से कई नये करों का भार सहन करना पड़ा। घुम्रा भाछ^२, 'हवूव', रूखवाली भाछ^३ व 'घोडा रेघ'^४ आदि कई कर उन्हें प्रतिवर्ष चुकाने पड़े।^५ उनमें 'जगात'^६ आदि के अधिकार भी छीन लिये गये^७ तथा उनके भूमि व न्यायिक अधिकार भी सीमित कर दिये गये।^८ यहां तक कि प्रत्येक नया ठाकुर शासक से पट्टा प्राप्त करने के बाद ही अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाता था।

सामन्त-वर्ग की रचना

प्रारम्भ में राज्य का सामन्त-वर्ग मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित था। प्रथम, वे तुलीय सामन्त तथा उनके वंशज, जो राव बीका के साथ मारवाड़ से आये थे। द्वितीय, वे सामन्त, जो राव बीका के वंशज थे तथा तृतीय, स्थानीय शासक जाति के मुखिया, जो अधीनस्थ सामन्त बन गये थे। इनके अलावा परदेशी सामन्त भी थे, जिन्हें शासक द्वारा समय-समय पर राज्य-सेवा में सम्मिलित किया गया था। इन सामन्तों में सबसे अधिक सख्या स्वाभाविक तौर पर राठौड़ों की थी, जो अपनी अनेक शाखाओं (खाणों) में विभक्त थे। परदेशी सामन्तों में राजपूतों की अन्य जातियां व उनकी खाएँ थीं। राजपूतों के अलावा अन्य सैनिक जातियों को सामन्त-वर्ग में सम्मिलित करने में बहुत कम उत्साह दिखाया गया था।^९

१ दलपत बिज्ञास, पृ० १४-१५

२ गूहकर

३ रस्ताकर

४ सैनिक दायित्व कर

५ बीरा जमरासर, बीदाहद, मुनाईनर ई लेख री बही, वि० स० १७६६/१७४२ ई०, न० ३१, घुम्रा रोकड बही, वि० स० १७५०/१६६३ ई०, न० ८८, बीकानेर बहियात, हवूव बही, वि० स० १८१२/१७५५ ई०, बस्ता न० १

६ सीमा व घुम्रा कर

७ परवाना बही, वि० स० १७४६/१६६२ ई०, पृ० ४१-४४। शासक ने अपनी विशेष कृपा से कुछ सामन्तों को इसकी धमूनी के अधिकार प्रदान किये थे।

८ कागदों की बही, वि० स० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृ० ४५

९ राज्य के पुराने सामन्तों में जोड़िया व शट्टी जाति के नेता सम्मिलित थे। बाद में अस्थाई पट्टे अवश्य गैर राजपूतों को दिये गये थे। इनमें मुन्तिस, खली व दिक्खों की सख्या सबसे अधिक थी। — परवाना बही, वि० स० १७४६/१६८२ ई०, पृ० ३२१, दयालदास ख्यात (प्र०) २, पृ० ७-६

राज्य के राठौड सामन्त अपनी निम्न पापो में विभक्त थे :

बीकावत—राज्य के सस्थापक राव बीका के वंशज बीकावत राठौड कहलाते थे। साधारणतया पाटवी शाखा से राज्यघड़ी का उत्तराधिकारी चुना जाता था व अन्य वंशजों के निर्वाह व सम्मान के लिये 'ठिकाने' बाँध दिये जाते थे। राज्य के सामन्तों में सबसे अधिक सख्या इन्हीं की थी। बीका वंश के होने के कारण दरबार में इनका विशेष सम्मान भी था। राज्य के चार 'सिरायत ठाकुरों' में दो बीका राठौड ही थे।^१ ये महाजन और भूकरका के ठाकुर थे। अपने भाई-सम्बन्धी होने के कारण प्रत्येक शासक ने बीका राठौडों को पट्टा देने में पूर्ण उदारता दिखाई थी। महाराजा रावसिंह, सूरसिंह व सूरतसिंह ने इन्हें सबसे अधिक पट्टे दिये थे। महाराजा सूरसिंह ने तो अपने शासन-काल में दिये ७ पट्टों में ६ पट्टे बीका राठौडों को ही प्रदान किये थे।^२ साधारणतया ये शासक के प्रति अत्यन्त स्वामिभक्त होते थे; परन्तु महाराजा सूरसिंह के समय में अवश्य कुछ प्रमुख 'ठिकानेश्वरों' के सम्बन्ध शासक के साथ बिगड़ गये थे, जिससे फलस्वरूप कुछ समय के लिये उनके 'ठिकाने' जप्त कर लिये गये थे। उनमें अजीतपुरा, साखू व सीधमुख के ठिकाने मुख्य थे।^३

बीकावत पट्टों के गांवों की स्थिति^४

वर्ष	कुल बीका पट्टों के गांव	वृद्धि (प्रतिशत में)	राज्य के कुल पट्टा गांवों में स्थिति (प्रतिशत में)	आसामीनार चाकर पट्टा गांवों में स्थिति (प्रतिशत में)	पट्टायतों की सख्या	प्रति बीका पट्टायत के पास औसत गांव
१६२५	३२६	१००	२६.३२	२८.३३	५४	६.०५
१६५७	३०४	९२.९६	२६.२६	३१.४६	६१	४.९६
१६६८	३८४	११७.४३	३२.६०	३५.८८	६१	४.२१
१८१८	४६०	१४०.६७	२८.६०	३७.१२	१३६	३.३८

१. सिरायत का अर्थ भूमि या मुख्य। राज्य में चार प्रमुख ठिकानेश्वर—महाजन (राज सोत बीका), भूकरका (शृंगोत बीका), बीदावर (बीदावन) तथा रावनवर (शाय सोत) के थे—धार्वाध्यान कल्याण, पृ० १८७

२. धार्वाध्यान कल्याण, पृ० १८७-८८; देखदर्शन, पृ० ६६-१०१, शासक द्वारा प्राप्त पट्टों की सूची—पार्ट न० १

३. दयालदास स्मृत (अप्र०) २, पृ० ३२२

४. पूर्व उद्धृत

पूर्वांकित सारणी से विदित होता है कि बीका ठाकुरों की स्थिति सामान्त-
वर्ग में सबसे उत्तम थी। इनके बीका राजवंश से सम्बन्धित रहने के कारण
तथा इनके द्वारा सिंहासन को दी गई पूर्ण निष्ठा के फलस्वरूप राज्य में इन्हे
पट्टे के गावों की वृद्धि का पूरा लाभ मिला। १६२५ ई० से १८१८ ई० तक
इनके पट्टे के गावों में १३३ गावों अर्थात् ४०.६७ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो
कि राज्य में कुल पट्टे के गावों की वृद्धि—४०.८०% के लगभग समकक्ष है।^१
जबकि, इस काल में 'आसामीदार चारुर', जिनमें ये स्वयं एक अंग थे के
पट्टे के गावों की वृद्धि मात्र ६.२३% हुई थी।^२ राज्य के कुल पट्टे के गावों
के अन्दर इनकी स्थिति सुघरकर २६.३२ में २८.६० हो गई। यहाँ यह
उल्लेखनीय है कि १६२५ ई० से १६५७ ई० में जबकि इनके गावों की संख्या
पटकर ३२७ से ३०४ हो गई थी, राज्य के कुल पट्टों में इनकी स्थिति में परि-
वर्तन मात्र ०.३% का आया था, जबकि इस काल में पट्टों की संख्या बहुत
घटी थी। 'आसामीदार चारुर' पट्टों में जो निरन्तर वृद्धि होती चली गई थी,
जो कि १८१८ ई० में १६२५ ई० की तुलना में लगभग ६% थी। प्रति
'पट्टायत' औमत गाव में भी इनकी स्थिति सतोपजनक थी, जबकि इनके
'पट्टायतो' की संख्या ५४ से बढ़कर १३६ हो गई थी। राज्य में प्रति 'पट्टायत'
औमत गाव की तुलना में ये बराबर या अधिक रहे।^३ १६२५ ई० में प्रति
'पट्टायत' औमत गाव ६.०५ की तुलना में १८१८ ई० में प्रति गाव ३.३८ का
हो जाना, इस बात का अवश्य सूचक है कि ठिकाणों का निरन्तर विभाजन
होता जा रहा था।

बीका राठौड़ निम्नांकित कई शाखाओं में विभाजित थे

रतनसोत

बीका रतन सोत, बीकावन ठाकुरों में प्रमुख थे। ये राव लूणकरण के
ज्येष्ठ पुत्र रतनसो के वंशज थे।^४ इनका मुख्य 'ठिकाणा' महाजन था। इनकी
संख्या बीका राठौड़ों में सबसे अधिक थी। सन् १६६८ ई० में, कुल बीका पट्टे
के गावों में, इनकी संख्या बीका ३२.३१ प्रतिशत थी जो सन् १६८२ ई० में
३६.३६ प्रतिशत हो गई। सन् १८१८ ई० में अवश्य इनकी संख्या ३५ प्रतिशत
थी। इस प्रकार इनकी स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ, जो कि कल बीकावन
पट्टों में २.२८ प्रतिशत वृद्धि के समान ही ३ प्रतिशत वृद्धि थी। राज्य में गाव

१. देखिए सारणी—पट्टा गावों की संख्या

२. वही

३. वही

४. दयालदास श्याम (प्र०) २, पृ० ३६

की सख्या भी सबसे अधिक इनकी थी। प्रति 'पट्टायत' इनके पास ४१ गांव थे। अकेले महाजन पट्टे में १३५ गांव थे। महाजन राज्य का सिरायत^१ ठिकाणा था।

शृंगोत बीवा

रतन सोन के बाद शृंगोत बीवा का नम्बर आता है। ये राव जैतसी के पुत्र, शृंगाजी के वंशज थे।^१ इनके मुख्य ठिकाणे भूवरवा, सीधमुख व अजीतपुरा थे। भूवरवा राज्य का सिरायत ठिकाणा था। इन्होंने राज्य सेवा में बहुत यश कमाया था। भूवरवा में ठाकुर पृथ्वीराज व कुशलसिंह ने, महाराजा स्वयंभूतसिंह के समय व महाराजा जोरावरसिंह की मृत्यु के बाद, राज्य प्रशासन का संचालन किया था।^२ सन् १६६८ ई० में, कुल बीवा पट्टा में इनकी सख्या १७ ६६ प्रतिशत थी, जो सन् १८१८ ई० में ३६ ७६ प्रतिशत हो गयी, अर्थात् रतन सोन से भी ४ ७६ प्रतिशत आगे बढ़ गई। सन् १९६८ ई० में इनके पास प्रति पट्टायत = ५ प्रतिशत गांव थे जहाँ कुल बीवा पट्टे के पास औसत ३ ३८ गांव थे। १९६८ ई० के आधार पर १८१८ ई० तक इनके गांवों में वृद्धि १४३ ४७ प्रतिशत हुई जो कि कुल बीवा पट्टा में वृद्धि से लगभग १०१% अधिक है।

भीमराजोत बीवा

ये राव जैतसी के पुत्र, भीमराज के वंशज थे।^३ राव बल्लभानमल ने भीमराज को गई भूमि का बाहुद^४ की पदवी देकर सम्मानित किया था, क्योंकि भारवाड के आक्रमण के विरुद्ध भीमराज घोरणाह सूर को सहायता के लिए चढ़ा लाया था।^५ इनका ठिकाणा राजपुरा में था। बीका पट्टे में ये सन् १९६८ ई० में १५ प्रतिशत थे सन् १९८२ ई० में ये ५ ५७ प्रतिशत व सन् १८१८ ई० में इनकी स्थिति ४ ४७ प्रतिशत थी। सन् १९६८ ई० में प्रति पट्टायत इनके पास ७ ५ गांव थे।

पृथ्वीराजोत बीवा

ये राजा रावसिंह के भाई कवि पृथ्वीराज के वंशज थे। इनका ठिकाणा

१ राज्य का प्रमुख ठिकाणा

२ शृंगजी सम्राट भकवर द्वारा कश्यपिर आक्रमण के समय मुगल सेना में लड़ते हुए घारे गए थे—भकवरनामा भाग ३ पृ० ७६६—८ (पूर्व०)

३ बीकानेर री राठौड़ा से ध्यात में सुजाणसिंहजी से महाराजा बरसिंहजी साई (पूर्व) पृ० ३ ३८ ३६ दयालदास कणत (धप्र०) २ पृ० २५ २७५ ७६

४ बीका पट्टायतो की सारणी—पार्ट १

५ दयालदास ध्यात (३०), भाग २ पृ० ७७

ददेवा या ।^१ इनकी स्थिति बीका पट्टे में सन् १८६८ ई० में २५० प्रतिशत थी, जो सन् १६८२ ई० में घटकर एक प्रतिशत हो गयी और सन् १८१८ ई० में यह १.६६ प्रतिशत थी । प्रति 'पट्टायत' इनके पास दो गाव थे, जो कि प्रति बीका पट्टा औसत से १.३८ ससवा कम थी ।

बाघावत

ये, राव जैतसी के पौत्र, ठानुरसी के पुत्र, धारमिह के वंशज थे ।^१ इनके पास जागीर में भटनेर, नौहर व सीधमुण्ड रहे थे । राजा रायसिंह ने इनका मेघाणा 'ठिकाणा' बांधा था । कुल बीका पट्टे में इनकी स्थिति ६५१ प्रतिशत थी, जो सन् १८१८ ई० में घटकर १.१६ प्रतिशत रह गयी थी, जबकि बीका पट्टो में वृद्धि हो रही थी । प्रति 'पट्टायत' इनके पास सन् १६६८ ई० में २७६ गाव थे, जो सन् १८१८ ई० में घटकर एक गाव रह गये थे । इस प्रकार बाघावतों की स्थिति में निरन्तर गिरावट आई थी तथा इनका महत्व घट गया था ।

अमरावत

ये, राव कल्याणमल के पुत्र अमरसिंह के वंशज थे । इनका 'ठिकाणा' राजा रायसिंह ने बांधा था ।^१ ये हरदेसर के पट्टायत थे । सन् १६६८ ई० में कुल बीका पट्टो में इनकी स्थिति ८.७३ प्रतिशत थी, जो सन् १६८२ ई० में ५.८६ प्रतिशत होने के बाद सन् १८१८ ई० में घटकर २.३८ प्रतिशत रह गयी । इस प्रकार इनकी स्थिति बीका छाप की २.२८ प्रतिशत वृद्धि की तुलना में ६.३४ प्रतिशत गिरावट की थी । प्रति 'पट्टायत' इनके पास ३ गाव थे ।

नारणोत

ये, राव लूणकरण के पौत्र, वैरसी के पुत्र, नारण के वंशज थे ।^१ इनके मुख्य

१ इन्हीं के बारे में यह प्रस्तावित है कि उन्होंने महाराजा प्रताप को सम्राट अकबर की छोटी-मता स्वीकार करने की इच्छा रोकने के लिए पत्र लिखा था ।— घोषा, भाग १, पृ० १५७-५८

२ बाघजी ने भटनेर का किला जीता था व राजा गरमसिंहजी ने उनमें भटनेर लेकर, नौहर में ठिकाणा बांधा था । ग्रन्थ में इनका ठिकाणा मेघाणा रहा । —दयालदास ख्यात, भाग २ (प्रकाशित) पृ० ८६

३ राठौड़ अमरसिंह, जो अमरा के नाम से विख्यात थे, ने सम्राट अकबर व महाराजा रायसिंह के विरुद्ध मिर्दोही कायंबाहिया की थी—दनपत विलास पृ० ५०, दयालदास ख्यात (प्र०) २, पृ० ६०

४ दयालदास ख्यात (प्र०) २, पृ० ३६

'ठिकाणे' मगरासर, मेणसर, तिहाणदेसर व वातर थे । कुल बीका पट्टो मे ये ४.६६ प्रतिशत थे, जो बढ़कर सन् १६८२ ई० मे ७.६१ प्रतिशत हो गये व बाद मे सन् १८१८ ई० मे घटकर ०.६५ प्रतिशत ही रह गये । इनकी सख्या मे भी ६.६६ प्रतिशत की गिरावट आई । प्रति 'पट्टायत' इनके पास २.७७ गाव थे ।

घडमीयोत

ये, राव बीका के पुत्र घडमी के वंशज थे व राव लूणकरण ने अपने भाई का 'ठिकाणा' घडसीगर मे याचा था ।^१ इनका दूसरा मुख्य ठिकाणा गारवदेसर था । सन् १६८२ ई० मे बीका पट्टो मे इनकी स्थिति १३.७८ प्रतिशत थी, जो सन् १६६६ ई० मे बढ़कर १६ प्रतिशत हो गयी, लेकिन १-१८ ई० मे घटकर ५.२३ प्रतिशत रह गयी । प्रति 'पट्टायत' इनके पास १२.५ गाव सन् १६८२ ई० मे थे, जो सन् १६६६ ई० मे बढ़कर १८ गाव पर आ गये, लेकिन सन् १८१८ ई० मे घटकर ११ गाव रह गये । इस प्रकार समय-परिवर्तन ने इनकी स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं डाला । बीका खाप मे रतनसोतो व शृंगोतो के पश्चात् इन्ही की प्रभावशाली स्थिति थी ।

विशानसिघोत बीका

ये, राजा रायसिंह के पुत्र विशानसिंह के वंशज थे व राजा सूरसिंह ने साखू मे इनका 'ठिकाणा' याचा था । इनका दूसरा मुख्य 'ठिकाणा' नीबा था ।^२ सन् १८१८ ई० मे इनकी स्थिति कुल बीका पट्टो मे १०.७८ प्रतिशत थी और प्रति पट्टेदार २२ गाव थे, जो कि रतनसोतो के बाद सबसे अधिक थे ।

इसके अलावा समय-समय पर कई खापों का अस्तित्व मिट गया था, जैसे — राजावत, रामावत, माघोदासोत, भगवानदामोत, नीबावत इत्यादि ।

काधलोत^३

रावत काधनजी, राव बीका के चाचा थे और इन्ही के सक्रिय सहयोग से राव बीका ने राज्य स्थापित करने का निश्चय किया था ।^४ जब बीका का राज्य दृढ़ता से स्थापित हो गया, तब रावत काधल ने गाव सङ्घा, राजासर व

१ दयालदाम ख्यात (प्र०) २ पृ० २६

२ दयालदाम ख्यात (प्र०) २, पृ० १४०

३ काधलोतो की विभिन्न शाखाओं के पट्टेदारों के वंश के लिए देखिये—काधलोत खाप के पट्टेदारा की सारणी—पार्ट न० १

४ नावा माधनरा री बातों, २२६/२५, प्र० न० पू० बी०, दयालदाम ख्यात (प्र०) २, पृ०

सेरडा में आना ठिकाणा' बाधा ।^१ उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके तीन पुत्रों के बीच सारे ठिकाणे बंट गये ।^२ उनके वंशज बाघसोत राठौड कहलाये तथा उनकी गणना राज्य के प्रमुख सामन्तों में की जाने लगी । उदाहरणतः राघतसर का ठिकाणेदार राज्य का 'सिरायत' सामन्त था । प्रारम्भ में इनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, लेकिन धीरे-धीरे वोका राठौडों की संख्या के बढ़ने से इनकी स्थिति द्वितीय स्तर की हो गयी । सन् १८१८ ई० तक इनके मुख्य ठिकाणों की संख्या ११ थी ।

कांघलोत पट्टों के गांवों की स्थिति

वर्ष	कुल कांघलोत पट्टों के गांव	वृद्धि (प्रतिशत में)	राज्य के कुल पट्टा गांवों में स्थिति (प्रतिशत में)	आसामीदार चाकर पट्टा गांवों में स्थिति (प्रतिशत में)	पट्टायतो की स्थिति	प्रति कांघलोत पट्टायत के पास औसत गांव
१६२५	२१७	१००%	१७.४७	१८८०	२५	८६८
१६५७	१४६	६७.२८	१२.६२	१५११	३३	४४२
१६६८	१७०	७८.३४	१४.४८	१५८८	५६	३०३
१८१८	३०८	१४७.६३	१६.१५	२५.१२	७३	४२१

उपरोक्त सारणी में विदित होता है कि राज्य के सामन्त-वर्ग में कांघलोतों की स्थिति सम्मानजनक थी । इसका नम्बर बीजावल पट्टायतो के पश्चात् आता था । सन् १६२५ ई० से १८१८ ई० तक इनके पट्टे के गांवों में ४७.६३ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि राज्य के कुल पट्टों के गांवों में ४०.८० प्रतिशत वृद्धि हुई थी । यह वृद्धि इनके लिये इस कारण भी उत्साहजनक थी, क्योंकि इस काल में 'आसामीदार चाकर' पट्टा गांवों में मात्र ६.२३ प्रतिशत वृद्धि हुई थी व यहा तक बीजा-राजवंश से सम्बन्धित बीजावल 'पट्टायत' भी

१ नैजमी ख्यात, २, पृ० २०५, दयालदास ख्यात (प्र०) २, पृ० १५

२ राजाधर, सोहवा व जावाबाद के तीन ठिकाणे स्थापित हुए थे ।—दयालदास ख्यात (प्र०)

४० ६७ प्रतिशत वृद्धि का लाभ उठा पाये थे, अर्थात् इनके गावों में राज्य के सर्वप्रमुख सामन्त वर्ग बीकावतों के गावों से भी ७०.२७ प्रतिशत की वृद्धि अधिक हुई थी। १६२५ ई० से १८१८ ई० के बीच थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ, राज्य के कुल पट्टा गावों में भी इनकी स्थिति १ ६८ प्रतिशत सुधरी थी। राज्य के कुल पट्टों में बीकावतों के पश्चात् इनकी स्थिति सर्वोत्तम थी। 'आसामीदार चाकर' पट्टों में इनकी स्थिति १८ ८० प्रतिशत से बढ़कर १५ १२ हो गई, जो कि अपने-आपमें ६.३२ प्रतिशत वृद्धि थी। यहाँ, इस काल में बीकावत पट्टों में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।^१

राज्य के पट्टा-क्षेत्र में, काघलोतो की स्थिति को १६२५ ई० से १६५७ ई० के बीच भारी धक्का लगा था। इस काल में बीकानेर के शासक राजा रावसिंह की नीति अर्थात् पुराने सामन्तों को नियन्त्रित तथा बीकावतों को प्रोत्साहित करने की नीति पर कठोरता से चल रहे थे। वैसे, इस काल में साधारणतया पट्टे के गावों में भी कमी हुई थी, पर काघलोत बहुत अधिक प्रभावित हुए। इन वर्षों में, जहाँ कुल पट्टों के गावों में ६ ६३ प्रतिशत की, 'आसामीदार चाकर' पट्टा गावों में १६ ३० प्रतिशत की तथा बीकावत पट्टा-गावों में ७ ०८ प्रतिशत की घटोतरी आई वहाँ काघलोत पट्टों के गावों में ३२ ७२ प्रतिशत की भारी कमी आई। राज्य के कुल पट्टों के गावों में इनकी स्थिति ४ ८५ प्रतिशत तथा 'आसामीदार चाकर' पट्टों के गावों में ३ ६६ प्रतिशत घट गई, जबकि इनके निकट प्रतिद्वन्द्वी बीकावतों के कुल पट्टों में मात्र ० ०३ प्रतिशत की कमी आई तथा 'आसामीदार चाकर' पट्टों में तो उनकी ३ १३ प्रतिशत की वृद्धि हो गई। काघलोतों को प्रति पट्टायत औसत गाव में भी बहुत नुकसान हुआ। उनके पास ८ ६८ गाव से घटकर ४ ४२ गाव रह गये।^२

१६५७ ई० के बाद का काल इनकी प्रगति का काल है। महाराजा अनूप-सिंह के काल में इन्होंने उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की तथा १७वीं शताब्दी में खूब व भादरा, रावतसर ठिकाना का बहुत विश्वास हुआ। परवर्ती पुनिया के राज्य में स्थायी रूप से मिल जाने पर उस क्षेत्र के गावों में इनके स्थायित्व के अधिकार भी बढ़ गये। १६५७ ई० में १८१८ ई० तक इनके गावों में ८०.६५ वृद्धि हुई जो कि राज्य में 'आसामीदार चाकरों' में सबसे अधिकतम वृद्धि थी। 'आसामीदार चाकर' पट्टों में इनका स्थान १५ ११ प्रतिशत से बढ़कर २५ १२ प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि बीकावत पट्टायतों से लगभग ५ प्रतिशत अधिक थी। इस काल में, राज्य के कुल पट्टों में भी इनके गावों की वृद्धि ६ ८३

- १ राज्य के कुल पट्टों आसामीदार चाकर पट्टों तथा बीकावत पट्टों के गाव तुलनात्मक अध्ययन के निम्ने देखिये—पट्टा गाँवा तथा बीकावत पट्टा गाँवों की सारणी
- २ देखिये, पट्टा व बीकावत पट्टा गाँवों की सारणी

प्रतिशत भी जो बि बीवायत पट्टो से लगभग ८ प्रतिशत अधिक थी। इस प्रकार १६५७ से १८१८ ई० के बीच इन्हें बीवायतों में अधिक लाभ मिला, परन्तु उनकी सख्या महाराजा अनूपसिंह के काबू तब दबती हो गई थी बि बाधलोत ज़ाती प्रभुगता की भग नहीं कर गये।^१

प्रति 'पट्टायत' ओसन गांव में भी, बाधलोतो के १६५७ ई० के पश्चात् विशेष अन्तर नहीं आया। केवल ० २१ का अन्तर था, जबकि बीवायतों में, इस काल में यह अन्तर १ ६० था था। महाराजा जोरावरसिंह, गजसिंह व सूरतसिंह ने इन्हें सबसे अधिक गांव दिये थे तथा धूम व भादरा 'ठिकाना' गांवों की सख्या ८४-८४ तक पहुंच गई थी। महाराजा सूरतसिंह के काल में जब भादरा व धूम के 'ठिकानेदारों' ने मत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया तो उनके क्षेत्र को सदैव के त्रिये सातसा में मिला लिया गया।^२

बाधलोत भी राज्य में अपनी विभिन्न शाखाओं में बंटे हुए थे, और उनके 'ठिकाने' एक-दूसरे से स्वतन्त्र थे।

रायतोंत

ये, बाधल के बड़े रावन राजसिंह के वंशज थे। इनका मुख्य ठिकाना रावतसर था, जो बीवानेर की चार 'सिरायतों' में से एक 'ठिकाना' था। सन् १६६८ में बाधलोत पट्टो में, इनके पट्टों की स्थिति २५.८ प्रतिशत थी, जो राज्य में रतनसोत बीवायतों के बाद सर्वोत्तम थी। लेकिन आर्याध्यान के अनुसार इनकी स्थिति १८१८ ई० में ५१ ११ प्रतिशत रह गई।^३ प्रत्येक पट्टायत के पाग सन १६६८ ई० में १२ गांव थे। इनकी स्थिति सन् १६६८ ई० में बाधलोतों की छाप में सबसे अधिक अच्छी थी, लेकिन धीरे-धीरे अन्य शाखाएं इनसे आगे निकल गयीं। इनकी केवल महाराजा गजसिंह और सूरतसिंह ने ही और पट्टे दिये थे।

साईदासोत

ये, बाधल के लडके, बडकमल के पौत्र, साईदास के वंशज थे। इनके

१ वही, दयालदास व्यास (प्र०) २, पृ० १८-२०

२ दयालदास व्यास (प्र०) २, पृ० ३२२-२३

३ पट्टा बहियो में जहा-जहाँ छाप की शाखाओं का वर्णन कम आया है, वहां तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से दयालदास द्वारा रचित 'आर्याध्यान कल्पद्रुम' का महारा लिया गया है, जिसकी रचना १६वीं सदी के मध्य में हुई थी। —आर्याध्यान कल्पद्रुम, पृष्ठ १६१ ६३

‘ठिकाणे’ में बहुत परिवर्तन हुआ ।^१ अन्त में महाराजा जोरावरसिंह ने भादरा में इनका ठिकाणा बाधा, जोकि राज्य के प्रमुख ‘ठिकाणे’ में गिना जाने लगा । १८वीं शताब्दी में काघलोतो के गावों की संख्या बढ़ने का एक मुख्य कारण, साईदासोतों के गावों में वृद्धि होना था । बाद में भादरा के ठाकुर लालसिंह के बीकानेर शासकी के साथ सम्बन्ध निरन्तर सधर्पपूर्ण रहे थे ।^२ इस कारण भादरा ठिकाणा कई बार खालसा में मिलाया गया ।^३ अन्त में महाराजा सूरत सिंह के समय यह अन्तिम रूप से जम्त कर लिया गया ।^४ भादरा पूर्वी क्षेत्र के बीरे नौहर का, सूई झूझ का उपग्रह क्षेत्र था । आर्याख्यान ने, साई-दासोतो की स्थिति काघलोतो के पट्टे में २६.८६ प्रतिशत मतसाई है जो कि काघलोतो में वणीरोतों के बाद सबसे अधिक थी ।

गोपालदासोत

ये भी, रावत राजसिंह के वंशज थे और रावतसर की शाखा से निजले थे । इनका ‘ठिकाणा’ जंतपुर था, और ये अपने पूर्वज गोपालदास के कारण गोपाल-दामोत कहलाते थे ।^१ सन् १६६८ ई० में इनकी स्थिति काघलोत पट्टी में सबसे कम १२.२६ प्रतिशत थी, लेकिन आर्याख्यान के अनुसार, ११.१३ प्रतिशत थी, जो रावलोतो से २ प्रतिशत अधिक थी । प्रति पट्टायत इनके पास सन् १६६८ ई० में ३ गांव थे ।

वणीरोत

ये, रावत काघल के ज्येष्ठ पुत्र बाधा के पुत्र, वणीर जी के वंशज थे ।

१. पहले इनके पास सोहवा गांव था । धरकमन ने पुत्र छेतमी ने भटनेर विजय की थी, फिर इनके पास पूनिया परगने में देईरागपुरो व करणपुरो रहे । महाराजा मनूपसिंह के पुत्र; महाराजा धानसिंह ने लालसिंह को भादरा की जागीर दी थी जिसे बीकानेर के शासक जोरावरसिंह ने बाद में भाग्यता प्रभाव कर दी थी । छन्द राव जंतसी रो, पृ० १८-४१; परवाना बही, बि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृ० ११२-१४
२. ठाकुर लालसिंह ने महाराजा जोरावरसिंह को बहुत तग दिया था । लालसिंह की मृत्यु के ही मारवाड़ नरेश धनपसिंह ने बीकानेर पर धाकपन किये थे । अन्त में जयपुर की सहायता से लालसिंह को बन्दी बनाकर वाहरवाड़ किले में कैद रखा गया था । परवाना बही बि० सं० १७४६, पृ० १११-१४, मोहनां भीष्मसिंह द्वारा जयपुर महाराजा धनपसिंह ने बीकानेर केरे का वर्षान, पृ० १८-२०, मोहनां रिकार्ड्स, ख० रा० घ० बी०; दयानदास ख्यात (धप्र०) २, पृ० ३२२, देगदर्शन पृ० १२०-२२
३. उपर्युक्त—महाराजा जोरावरसिंह तथा गजसिंह ने इसे जम्त किया था ।
४. दयानदास ख्यात (धप्र०) २, पृ० ३२२
५. देगदर्शन, पृ० १२०

इनका मुख्य ठिकाण चूरु था, जिसे वणीरजी के पुत्र मालदेव ने बसाया था।^१ इनके अन्य मुख्य ठिकाण घाघू, देपालसर, लोसाणा, दूदवा, सात्यू व झारिया थे। प्रारम्भ में इनकी सख्या व इनका प्रभाव कम था, लेकिन धीरे-धीरे चूरु के ठाकुर मालदेव, भीमसिंह, संग्रामसिंह, हरीसिंह के प्रभाव से इनके पट्टे के गावों की सख्या, काबिलोता में सबसे अधिक हो गयी।^२ अकेले चूरु के पट्टे में ८४ गाव थे, जो काबिलोता की सख्या बढ़ाने में बड़े सहायक सिद्ध हुए।^३ सन् १६६८ ई० में काबिलोता के पट्टे में इनकी स्थिति ४४ ७० प्रतिशत थी, जो सन् १६८५ ई० में बढ़कर ४७ प्रतिशत तक पहुँच गयी, लेकिन सन् १६९६ ई० में घटकर वह ४४ २४ प्रतिशत ही रह गयी। एव खाप में यह राज्य की सर्वाधिक ऊँची स्थिति थी, क्योंकि रतनसोत बीका भी, अपनी खाप में अधिक से अधिक ३६ प्रतिशत स्थिति रखते थे। सन् १६६८ ई० में प्रति पट्टागत इनके पास ३ गाव थे।

बीदावत

राव बीका के भाई रावबीदा के वंशज बीदावत ठाकुर कहलाते थे। राव बीदा छापर, झोणपुर का स्वामी था। राव बीदा ने अपने क्षेत्र को अपने तीन पुत्रों

बीदावत पट्टे के गावों की स्थिति

वर्ष ई० सन	कुल बीदावत पट्टे के गाव	वृद्धि (प्रतिशत में)	राज्य के कुल पट्टा गावों में स्थिति (प्रतिशत में)	मासामीदार चाकर पट्टा गावों में स्थिति (प्रतिशत में)	पट्टायतो की सख्या	प्रति पट्टायत औसत गाव
१६२५	१३८	१००%	११ ११	११ ६५	२६	५ ३०
१६५७	१७६	१२६ ०१	१५ ४८	१८ ५३	३३	५ ४२
१६६८	१७४	१२६ ०८	१४ ८२	१६ २६	४२	४ १४
१८१८	२२८	१६५ २१	१४ १७	१८ ५६	८५	२ ६८

१ भार्याभोजन कल्पद्रुम पृ० २०२

२ बाकानर के पट्टा की विवरण पृ० २६ परवाना बही वि० सं० १७४६/१६८२ ई० पृ० २४७ ४६

३ भार्याभोजन पृ० १६१ ८३

में बांट दिया था, जो आगे चलकर और भी कई भागों में विभक्त हो गया।^१ शासकों ने भी विभाजन की नीति पर चलते हुए कई छुट भाईयों के स्वतंत्र ठिकाने स्थापित किये। इन प्रकार बीदावतों की कई शाखाओं का जन्म लिया। राज्य में इनकी स्थिति घटती बढ़ती रही, लेकिन अन्त में सन् १८१८ ई० में जाकर वह बड़ोत्तरी पर ही जा पहुँची। प्रारम्भ में इनके जो तीन ठिकाने थे, वे बढ़कर १२ हो गये। इसमें अलावा कई छुट भाईयों के ठिकाने भी इनके साथ थे। महाराजा गजसिंह ने इन्हें सबसे अधिक, तीन पट्टे प्रदान किये थे।

राज्य की तीन प्रमुख खापों बीकावत, बीदावत व काघलोत में बीदावतों की स्थिति अन्य दोनों की तुलना में कमजोर थी। वैसे इनकी स्थिति में थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ, निरन्तर सुधार हुआ था, परन्तु प्रारम्भ से ही ये बीकावत व काघलोत के बाद ही श्रेणी में आते थे। सन् १६२५ से १६५७ ई० के बीच इनकी स्थिति में वृद्धि उल्लेखनीय है, क्योंकि इस काल में जहाँ राज्य की अन्य खापों की स्थिति में गिरावट आई थी, वहाँ इनमें सुधार हुआ था। बीकावत व काघलोत पट्टों में गिरावट क्रमशः ७०४ प्रतिशत व ३२६२ प्रतिशत हुई थी, वहाँ बीदावतों में ६६१ प्रतिशत की वृद्धि आई थी। तथापि ये सामन्त-वर्ग में प्रमुख स्थिति में नहीं आ सके। १६५७ ई० में राज्य में कुल पट्टों की संख्या की स्थिति में जहाँ बीकावत २०२६ प्रतिशत तथा काघलोत १२६२ प्रतिशत थे वहाँ बीदावत १५४८ प्रतिशत थे। वैसे इनकी स्थिति काघलोतों के लगभग समीप पहुँच गई थी। १६२५ ई० में जहाँ काघलोतों की राज्य के कुल पट्टों में स्थिति १७४७ थी तथा इनकी तुलना में बीदावतों की ११११ प्रतिशत स्थिति थी वो १६५७ ई० में क्रमशः १२६२ प्रतिशत तथा १५४८ प्रतिशत हो गई। इस काल में 'आसामीदार चाकर पट्टा' में भी इनकी वृद्धि आशाजनक थी जो ११६५ प्रतिशत से बढ़कर १८५३ प्रतिशत हो गई। तत्पश्चात् इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यद्यपि इनके पट्टे के गावों की संख्या १६५७ ई० से १८१८ ई० तक बढ़कर १७६ से २२८ पहुँच गई थी, अर्थात् ३५.६० प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु राज्य में पट्टों के गावों की वृद्धि को देखते हुए यह निराशाजनक थी। फिर, राज्य के कुल पट्टे के गावों में इनकी स्थिति इस काल में १३१ प्रतिशत घट गई थी। केवल 'आसामीदार चाकर पट्टा' में नाममात्र की ००६ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्रति 'पट्टायत' औसत गांव की संख्या भी १६२५ ई० की ५३० प्रतिशत से १८१८ ई० में घटकर २६८ प्रतिशत रह गई, जो शासकों द्वारा बीदावत पट्टों के निरन्तर हो रहे विभाजन की प्रक्रिया की ओर संकेत करती है।

१ राठौरों की वंशावली ने पीढ़ियों में घटकर चाना पृ० ५८, २२८/६, बीदावतों की संख्या, पृ० २९

बीदावतो की विभिन्न खापें निम्नावि—

केसोदासोत—

ये, राव बीदा के पौत्र, सागा के पुत्र, गोपालदाम के वंशज थे। गोपालदास ने अपनी जागीर को अपने तीन पुत्रों में बांट दिया था। छोटे पुत्र बेशवदास को ५ टकी बनाकर बीदासर का पट्टा दिया था। उसी के वंशज केसोदासोत कहलाये। बीदावतो में बीदासर इनका 'ठिकाना' बना व इनकी शाखा अपनी छाप में प्रमुख गाथा कहलायी।^१ बीदासर का 'ठिकाना' राज्य के चार सिरायता में से एक था। सन् १६६८ ई० में कुल बीदा पट्टों में इनकी स्थिति सबसे अधिक ४२ ५ प्रतिशत थी, जो कि एक छाप के अन्दर किसी परिवार में सर्वोच्च थी। सन् १६८५ ई० में इनकी स्थिति बीदा पट्टों में ४० ४८ प्रतिशत थी। १८ वीं शताब्दी में इनकी स्थिति गिरने लगी। आर्याध्यान के अनुसार वे सोदासोत केवल १७ ८२ ही थे।^२ महाराजा जर्णसिंह से लेकर महाराजा सूरतसिंह तक, जो बीदावतो को १० नय पट्टे दिये गये, उनमें केसोदासोत को केवल एक ही पट्टा प्राप्त हुआ जो चारला का ठिकाना था। महाराजा जर्णसिंह व सूरतसिंह ने छुट भाईयो की शाखाओं को अधिक प्रोत्साहित किया था। प्रति पट्टेदार इनके पास ४ ५ गाव थे।

खगारोत

ये, बीदा के पुत्र ससारचन्द्र के वंशज खगारसिंह की सत्तान थे। इनके मुख्य 'ठिकाने' लोहा, खुडी व बनवाडी थे। महाराजा जर्णसिंह ने इनके दो ठिकाने, बाधे थे। सन् १६६८ ई० में कुल बीदा पट्टों में, इनकी स्थिति २७ ०१ प्रतिशत थी, जो सन् १६८२ ई० में घटकर २४ ८७ प्रतिशत हो गयी। आर्याध्यान के अनुसार १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इनकी स्थिति ३५ ७४ प्रतिशत बढ़ गयी थी,^३ जो कि बीदा पट्टों में सबसे अधिक थी। महाराजा जर्णसिंह व सूरतसिंह के संरक्षण प्रदान करने से यह स्थिति सम्भव हुई थी। प्रति पट्टेदार ४ ७ गाव थे।

मदनावत

ये, बीदा के पुत्र ससारचन्द्र के दूसरे पुत्र, पाता के पुत्र मदनसिंह के वंशज थे। पहले इनके पास छापरा गाव था, फिर अनूपसिंह ने साठवीं दिया व अन्त में अनूपसिंह द्वारा ही सोभासर का पट्टा प्रदान किया गया। सन् १६६८ ई० में कुल बीदा पट्टों में इनकी स्थिति १७ ८१ प्रतिशत थी जो सन् १६८२ ई०

१ वही

२ आर्याध्यान कल्पद्रुम पृ० ११०

३ आर्याध्यान कल्पद्रुम पृ० ११०

में घटकर १७.६७ हो गयी थी। आर्याख्यान के अनुसार इनकी स्थिति ६६३ प्रतिशत थी, जोकि बीदा पट्टों में सबसे कम थापा की थी। प्रति पट्टेदार इनके पास ५.१६ गांव थे। यह अनुसूत अवश्य बीदा पट्टों में सबसे अधिक था।

मनोहरदासोत

ये गोराल दास के पुत्र, जसवंतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र मनोहरदास के वंशज थे, जिनको राजा रायसिंह ने साँझवा की आगीर प्रदान की थी। इनके दूसरे 'ठिकाणा' पट्टिहारा व कक्कू थे।^१ सन् १६६८ ई० में इनकी स्थिति कुल बीदा पट्टों में ३.४४ प्रतिशत थी जो जो सन् १६८२ ई० में घटकर २.९२ प्रतिशत रह गयी। लेकिन आर्याख्यान के अनुसार १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह बढ़कर २६.६३ हो गयी, जो कि छगारोतो के बाद सबसे अधिक सङ्ख्या थी। प्रति पट्टेदार १.५ गांव थे।

पृथ्वीराजोत

ये, गोपालदाम के पुत्र जसवंतसिंह के दूसरे पुत्र, पृथ्वीराज के वंशज थे। इनके पास पहले भाडेला व अडघीसर गांव के पट्टे थे, बाद में महाराजा सुजान सिंह ने हरासर में इनका 'ठिकाणा' बाधा।^१ इनका दूसरा, ठिकाणा सारोठिया गांव था। सन् १६६८ ई० में इनकी स्थिति कुल बीदा पट्टों में १०.३४ प्रतिशत थी, जो सन् १६८२ ई० में बढ़कर १२.६७ प्रतिशत हो गयी। प्रति पट्टेदार इनके पास ३ गांव थे।

राय बीका के साथ मारवाड से आये, अन्य राठोडों में उनके चाचा मंडला, रूपी व नामोजी मुख्य सामन्त थे। बीदा व बाघनजी की तुलना में इनकी छापी का महत्त्व कम रहा था।^२

मण्डलावत

ये, राय बीका के चाचा 'मण्डनाजी' के वंशज थे जिन्होंने राय बीका के साथ ही मारवाड से आकर, अपना 'ठिकाणा' स्थापित किया था।^३ इनका मुख्य 'ठिकाणा' साँझवा गांव था। राज्य के इतिहास में इनकी स्थिति सम्मानजनक अवश्य रही, परन्तु उन्होंने कोई विशेष सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। सन् १६२५

१ आर्याख्यान बल्पद्रुम, पृ० १००, देशदर्पण पृ० ११५

२. वही

३. देशदर्पण, पृ० ११५

४. दयालदास ख्यात (शकाजिन) २, पृ० २

५. उपर्युक्त

ई० में कुल आसामीदार चाकरी पट्टो में इनकी स्थिति १३६ प्रतिशत थी, सन् १६६८ ई० में यह १४६ प्रतिशत हो गई। फिर सन् १८१८ ई० में घटकर १२२ रह गयी। कुल पट्टो में इनकी स्थिति सन् १६२५ ई० में १५४ प्रतिशत थी, जो घटकर १६६८ ई० में १११ प्रतिशत रह गयी। सन् १८२१ ई० में यह पुनः घटकर १०८ प्रतिशत तक आ पहुची। प्रति पट्टेदार इनके पास, सन् १६२५ ई० में, ५ गाव थे, जो सन् १६६८ ई० में घटकर १६ गाव तक पहुच गये। सन् १८१८ ई० में भी यही स्थिति बनी रही।^१

रूपावत

यह राव बीका के साथ 'मारवाड से आये', दूसरे चाचा रूपाजी के वंशज थे।^२ इनका मुख्य 'ठिकाणा' भादला था। इनकी स्थिति भी विशेष अच्छी नहीं थी। पट्टो क अनुपात में वह घटती-बढती रही थी। आसामीदार चाकरी पट्टो में सन् १६२५ ई० में इनकी स्थिति १३६ प्रतिशत थी जो सन् १६६८ ई० में बढ कर २२४ प्रतिशत हो गयी लेकिन सन् १८१८ ई० में मात्र ०७३ प्रतिशत रह गयी। कुल पट्टो में इनकी स्थिति सन् १६२५ में १५४ प्रतिशत थी, जो सन् १६६८ ई० में थोड़ी बढकर १७८ प्रतिशत हो गयी, लेकिन सन् १८१८ ई० में घटकर मात्र ०६१ प्रतिशत रह गयी। सन् १६२५ ई० में अवश्य प्रति पट्टेदार इनके पास ३ गाव थे, जो सन् १६६८ ई० में घटकर १८४ औंसत रह गये और सन् १८१८ ई० में तो मात्र १ गाव ही रह गया।

नाथोत

यह भी राव बीका के चाचा नाथूजी के वंशज थे और इनका ठिकाणा चानी था।^३ यह राज्य के महत्त्वहीन 'ठिकाणों' में से एक था। सन् १६२५ ई० में कुल आसामीदार चाकरी पट्टो में इनकी स्थिति ००६ प्रतिशत थी, जो सन् १६६८ में बढकर ११२ प्रतिशत हो गयी। कुल पट्टो में सन् १६२५ ई० में इनकी स्थिति ००८ प्रतिशत थी, जो सन् १६६८ ई० में बढकर १०२ प्रतिशत हो गयी। सन् १६२५ ई० में प्रति पट्टेदार इनके पास १ गाव था जो सन् १६६५ ई० में जाकर ४ की संख्या तक पहुच गया।

देशी-परदेशी

राठौडों की विभिन्न खापों के अलावा अन्य महत्त्वपूर्ण ठिकाणों, विभिन्न

१ मण्डलावतों के इतिहास के अध्ययन से लिये देखिये—डा० खगतिह द्वारा रचित मण्डल वतों का इतिहास

२ दयालदास व्यास (प्र०) २ पृ० २-५

३ दयालदान व्यास (प्र०) २ पृ० २

राजपूतों की जाति के पट्टेदारों के थे, इन्हें देशी-परदेशी ठाकुर कहा जाता था। देशी ठाकुर पट्टेदारों में व राठौड़ राजपूत भी सम्मिलित थे, जो कि राज्य की स्थापना के बाद आकर यहाँ आ बसे थे। साधला, बाघोड, भट्टी, जोहिवा आदि राठौड़ों के आक्रमण से पूर्व महा के शासक थे, इस कारण वे भी 'देशी ठाकुर पट्टायत' कहलाते थे। भाटी ठाकुर अपनी अधिक सख्या व प्रभाव के कारण अलग से भी एक गुट का निर्माण करते थे। इनके अलावा राज्य सेवा में सलग्न सामन्त 'परदेशी ठाकुर' व पट्टेदार बड़े जाते थे। देशी-परदेशियों में राठौड़ों को छोड़कर बाकी सभी ठाकुरों को 'परसगी' भी कहा जाता था। क्योंकि शामन व अन्य राठौड़ राजा के सदस्यों के वैवाहिक सम्बन्ध इनके परिवारों में सम्पन्न होते थे। इनमें से बहुत स धराने तो बीकानेर नरेशों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के कारण ही स्थापित हुए थे। सामन्तवर्ग में शक्ति-संतुलन बनात हुए शासकों ने गैर राठौड़ों को पट्टा प्रदान करने में विशेष रुचि भी दिखाई थी। परदेशी ठाकुरों ने भी राज्य सेवा में पूर्ण उत्साह दिखाया था तथा समय-समय पर अपनी उल्लेखनीय सेवाएँ प्रदान की थीं। सन् १८१८ ई० तक भाटी 'ठिकानों' के अलावा देशी-परदेशी सामन्ती के ६ 'ठिकाने' स्थापित हो चुके थे।

देशी-परदेशी पट्टायतों के गांवों की स्थिति*

वर्ष ई० सन्	कुल पट्टा के गांव	वर्द्धि (प्रतिशत में)	राज्य के कुल पट्टा गांवों में स्थिति (प्रतिशत में)	आसानीदार चार पट्टा गांवों में स्थिति (प्रतिशत में)	पट्टायता की सख्या	प्रति पट्टायत औसत गांव
१६२५	१२२	१००.	६२६	१०५७	१२	१०१६
१६५७	६६	५४.०६	५७०	६८३	१५	४४८
१६६८	२७	२२.१३	२२६	२५२	२६	१०३
१८१८	१०१	८२.७८	६२८	८२३	५८	१७४

देशी-परदेशी ठाकुर राज्य के पुराने राठौड़ 'ठिकानेदारों' की महत्वपूर्ण स्थिति में कभी नहीं आ सके। बीकानेर राज्य राठौड़ राज्य ही बना रहा।

२ पट्टा बहा वि० स० १७२५/१६६८ ई०, न० ४

३ परवाना बही वि० स० १८००/१७४३ ई० न० २२/२

१ आर्षान्धान कल्पद्रुम, पृ० २०३-०४

२. यह मगना भाटी राजपूत पट्टायता को छोड़ कर की गई है। भाटी राज्य के पुराने सामन्त थे तथा उनका धर्म वे महत्त्वपूर्ण गुट था

बीकावत, बीदावत व बाधलोत पट्टायतो की तुलना में इनकी स्थिति सदैव निराशाजनक रही। १६२५ ई० में राज्य के कुल पट्टो में जहाँ बीकावत, बीदावत व बाधलोत पट्टा गाव क्रमशः ३२७, १३८ व २१७ थे वहाँ देशी परदेशी पट्टा गाव १२२ थे। वैसे, १६२५ ई० में इनकी स्थिति अपने प्रभाव में हर दृष्टि से उत्तम थी। इस वर्ष आसामीदार चाकर पट्टा गावों में इनकी स्थिति १०.५७% थी जो बीदावतो के ११.११% के समीप थी। तत्पश्चात् इनकी स्थिति ऐसी कभी नहीं रही। बीकानेर शासकों के मनमथ में घटोतरी तथा मुगल जागीरों की कमी से राठौड़ सामन्तों को सतुष्ट करने के लिये वतन क्षेत्र में पट्टे अधिक देने के फलस्वरूप इनकी स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। १६६८ ई० में इनके पास मात्र २७ गाव रह गये जो अपने आपमें ७७.८७% की घटोतरी थी। राज्य के कुल पट्टो व 'आसामीदार चाकर पट्टो' में इनकी स्थिति क्रमशः २.२६% तथा २.५२% रह गई। यह इनकी स्थिति का न्यूनतम बिन्दु था। १८वीं शताब्दी में शासकों की अमीमित सत्ता के विरुद्ध जब राठौड़ सामन्तों ने विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया तब शासकों की विवशतावश कृपा से इनकी स्थिति में फिर सुधार होना प्रारम्भ हुआ। १८१८ ई० में इनके गावों की संख्या १०१ हो गई तथा आसामीदार चाकर पट्टो में इनकी स्थिति ८.२३ की सम्मानजनक हो गई। यद्यपि ये १६२५ ई० की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके। १६-५ ई० में प्रति 'पट्टायत' औसत गाव की संख्या में इनकी स्थिति राज्य भर में सर्वोत्तम थी। बाद में १८१८ ई० तक घटकर १०.१६ से १.७४ हो गई। देशी परदेशी 'पट्टायत' अलग-अलग उप-जाति तथा खासों में बँटे रहने के कारण राज्य के सामान्य वर्ग में कभी भी अपना प्रभावशाली गुट नहीं बना सके। अतः इनकी स्थिति सदैव कमजोर बनी रही तथा ये अपनी स्थिति व सम्मान के लिये राजा की कृपा पर ही आश्रित रह।

देशी परदेशी पट्टायतो में निम्न उप-जाति व खास मुख्य थी —

साँखला—ये नापा साँखला के वंशज थे तथा जागलू गाव के ठिकानेदार थे। नापा साँखला ने निमल्लण पर हो राठौड़ों ने यहाँ आकर राज्य स्थापित किया था। महाराजा मुजानसिंह (१७३३ ई०) के समय साँखलो द्वारा नागीर के बखसिह के साथ, पदमन्त करके उसको गढ़ सुपुर्द करने के कारण राज्य में इनकी स्थिति बिगड़ गयी थी।^१ हालाँकि धीरे-धीरे इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर ली थी, लेकिन राज्य के उच्च पट्टायतो की श्रेणी में नहीं आ सके थे। एन् १६२५ ई० में देशी-परदेशी पट्टा में इनकी स्थिति २४.५६ प्रतिशत थी जो एन् १६६८ ई० तक बढ़कर ८८.८८ प्रतिशत हो गयी। इसके बाद

इनकी स्थिति गिरी और सन् १७४८ ई० में यह केवल २ प्रतिशत रह गयी। सन् १८१८ ई० में तो इनके नाम पर कोई पट्टा ही नहीं था। साबलो जैसा पतन राज्य में किसी दूसरे पुरानी खाप का नहीं हुआ था।

निरवाण—इनकी कोई स्थायी 'ठिकाणा' नहीं था। इनकी स्थिति कुल देशी-परदेशी पट्टों में ०.५ प्रतिशत थी। प्रति पट्टायत इनके पास एक गांव था। ये अधिकतर 'चाकर' पट्टायत ही बने रहे।

उदावत—देशी-परदेशी ठाकुरा में इनकी स्थिति सम्मानजनक थी। सन् १६२५ ई० इनकी स्थिति देशी परदेशी पट्टा में १० प्रतिशत थी जो सन् १६६८ ई० में घटकर ८.३४ प्रतिशत रह गयी। महाराजा कर्णसिंह के चिट्ठोही काल में इनके साथ दक्षिण में रहने के कारण इनकी स्थिति राज्य में कमजोर पड़ गई थी। बाद में महाराजा अनूपसिंह ने पुनः राज्य-सेवा में रख लिया था, परन्तु इनको विशेष सम्मान प्रदान नहीं कर सके। उदावत ही महाराजा अनूपसिंह के काल से चीधड़ कहलाये।^१ लेकिन महाराजा अनूपसिंह के बाद पुनः इनकी स्थिति में उन्नति हुई और सन् १८१८ ई० में यह ८० प्रतिशत हो गयी, लेकिन प्रति पट्टायत इनके पास ०.६४ औसत गांव थे जो कि राज्य में सबसे कम सख्या थी।

राठौड—राव जोधा के वंशज, जो बाद में आकर 'ठिकाणेदार' बने थे, वे देशी-परदेशी राठौड कहलाते थे। इनमें जोधावत, करमसोत व मेडतिया प्रमुख थे।^२ सन् १८१८ ई० में इनके पास कुल देशी-परदेशी ठाकुरों में ६ प्रतिशत गांव थे। प्रति पट्टायत इनके पास औसत १.३३ गांव थे। इनके मुख्य ठिकाणे भेसली पावो, मोखो, रायसर आदि थे।^३

सोनगरा—राठौडों के अलावा अन्य राजपूत सामन्ता में, सोनगरो की स्थिति सर्वद्व उत्तम रही। इनके पास पहले बाय का 'ठिकाणा' था। महाराजा अनूपसिंह के समय इनकी गणना राज्य के श्रेष्ठ सामन्ता में की जाती थी। वनमालीदास को मारने के पड़यन्त्र में, लक्ष्मीदास सोनगरे का मुख्य हाथ था।^४ सन् १६२५ ई० में जहाँ सोनगरो की स्थिति देशी-परदेशी पट्टा में २०.४६ प्रतिशत थी, वह सन् १६६६ ई० तक ८० प्रतिशत हो गई। प्रति पट्टेदार इनके पास ४ गांव रहे, लेकिन १८वीं शताब्दी में इनका महत्त्व घटता चला गया। यद्वा तक कि सन् १८१८ ई० में इनके पास एक गांव भी नहीं रहा।

१ बही परवाना दि० सं० १८००/१७४३ ई०, दस्तखत, पृ० १५२-२३

२, भार्याध्यान ब्रह्मद्वज, पृष्ठ २०३-४

३ उपर्युक्त

४ बीकानेर की व्याव महाराजा मुबारकसिंहजी से महाराजा गजसिंहजी साँद, पृष्ठ ७, मोहतामीसिंह द्वारा जोधपुर महाराजा अश्ववत्सिंह से बीकानेर बरे का वसुंन पृ० १५, दयाल दाम व्यास (अप्रकाशित) पृष्ठ २, पृष्ठ २१७

चौहान—सोनगरो की भांति १७वीं शताब्दी में इनकी शक्ति का भी उत्थान हुआ, लेकिन १८वीं शताब्दी में इनका पतन हो गया। वैसे भी इनका कोई स्थायी 'ठिकाणा' नहीं था। सन् १६२५ ई० में जहाँ ये देशी-परदेशी पट्टो में ७३७ प्रतिशत की स्थिति रखते थे, वहाँ सन् १६६८ ई० में ५१.८८ प्रतिशत बढ़ गये। सन् १८१८ ई० में इनके पास एक भी पट्टा नहीं था। प्रतिपट्टेदार इनके पास १.५ गांव रहे। देशी परदेशी पट्टायतो की स्थिति किसी एक शासक की कृपा पर बढ़ जाती थी तो दूसरे के समय घट जाती या समाप्त हो जाती थी।

कच्छावा—महाराजा गर्जसिंह व सूरजसिंह के समय इनकी राज्य में ४ पट्टे मिले हुए थे। इनके मुख्य ठिकाणों, गजरूपदेसर, आमनमर, पुनलसर इत्यादि थे। सन् १६२५ ई० में देशी-परदेशी ठाकुरों में इनकी स्थिति १६४ प्रतिशत थी, जो सन् १६६८ ई० में ३७.०३ प्रतिशत थी व सन् १८१८ ई० में २६.७६ प्रतिशत घट गई।

संवर—महाराजा कर्णसिंह के समय इन्हें विशेष प्रोत्साहन मिला था। लखासर इनका स्थायी 'ठिकाणा' था। उनके काल में इनकी स्थिति परदेशी ठाकुरों में २५.३६ प्रतिशत हो गयी थी व गांव भी प्रति पट्टेदार १.३३ हो गया था, जबकि उससे पूर्व देशी-परदेशी ठाकुरों में उनकी स्थिति ४.०६ प्रतिशत थी व बाद में १.६३ थी। इनके पास प्रति पट्टेदार गांव पहले ०.६ था और बाद में ०.७ रहा।

सिसोदिया—इनका भी कोई स्थायी 'ठिकाणा' नहीं था। जोधासर व गजरूपदेसर महाराजा सूरजसिंह के समय इनको पट्टे में मिले हुए थे। सन् १६२५ ई० में ये देशी-विदेशी पट्टों में ७३७ प्रतिशत की स्थिति रखते थे और महाराजा अनूपसिंह के अन्तिम वर्षों में ये ६०.६६ प्रतिशत की स्थिति तक पहुँच गये थे। प्रति पट्टेदार उनके पास उस समय ८ गांव थे। सन् १८१८ ई० में इनकी स्थिति १.६८ प्रतिशत थी व प्रति पट्टेदार २ गांव थे।

इनके अलावा पवार, गोमलिये, रिणधीरोत, देवडा, सोडी, खीची, जंतमा-लोत, जंतुग आदि अन्य परदेशी ठाकुर थे, जिनकी स्थिति रिणधीरोतो को छोड़ कर कुल देशी-परदेशी पट्टों में १.५ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पायी। रिणधीरोत खाप के पास अवश्य २१ पट्टे रहे थे। सन् १६२५ ई० में इनकी स्थिति देशी-परदेशी पट्टों में ५२ प्रतिशत तक थी। लेकिन यह खाप १८वीं शताब्दी में अपना अस्तित्व खो बैठी।^१

१ धार्याध्यान बल्पद्रुम, पृष्ठ २०४-५

२. देशदर्पण, पृष्ठ १४५

३. देशदर्पण, पृष्ठ १४५-४६

४. परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृ० ३००-२०

भाटी—राव बीबा के जागत देश पर आक्रमण करने से पूर्व, यहां के पश्चिमी क्षेत्र पर भाटी राजपूतों का अधिकार था, जिनकी राजधानी पूगल थी।^१ पूगल के भाटी राज्य के पहले सामन्त बने थे। भाटी राजपूतों ने अपनी शक्ति को संचित करने के अनेक यत्न किये थे, लेकिन राठौड़ों की संयुक्त शक्ति के समक्ष वे 'सदैव' असफल रहे। धीरे-धीरे इन्होंने अपना साहस छोड़ दिया व आशा-वश के उनकी शक्ति को विभाजित व क्षिप्त बना दिया।^२ महाराजा अनूपसिंह के समय, अनूपगढ़ के निर्माण के बाद, इनकी विरोधी शक्ति एकदम टूट गयी।^३ महाराजा सूरतसिंह ने इन्हें ५ पट्टे प्रदान किये जो कि उनके द्वारा किसी खाप के दिये गये पट्टा में सबसे अधिक थे। इनके पट्टों की कुल संख्या १५ के बरीब थी, जिनमें मुख्य रूप से पूगल, बरसलपुर, सत्तासर, खीदासर, मंजु, हाडला, परेवडी, हटियालो, खारवारा, राणेर, बेला, साहू बीठनोक जैमलसर इत्यादि थे।^४ इनकी सन् १६२५ ई० में कुल आसामीदार चाकरी पट्टों में स्थिति ११.३६% थी जो १६६८ ई० में बढ़कर १२.७१% हो गई। राज्य के कुल पट्टों में इनकी स्थिति १६२५ ई० में १०.६३% थी जो १६६८ ई० में थोड़ी बढ़कर ११.५८% पट्टुची, लेकिन १८१८ ई० में घटकर ७.६८% रह गई। इसी प्रकार 'आसामीदार चाकरी पट्टों' में इनकी घटोतरी २.७% हुई, जबकि कुल पट्टों में यह गिरावट २.६५% थी। इस गिरावट का एक मुख्य कारण यह था कि इस अवधि में कुल पट्टों में राठौड़ पट्टा की संख्या बढ़ रही थी। इनके पास प्रति 'पट्टायत' १६२५ ई० में २४२ गांव थे जो कि १६६८ ई० में घटकर १६२ रह गये। १८१८ ई० में यह संख्या १४४ गांव ही थी। इस प्रकार भाटियों के प्रति 'पट्टायत' औसत गांव किसी भी प्रमुख राठौड़ खाप के औसत गांव की तुलना में कम ही रहे। भाटिया में केवल पूगलिया खाप ही ऐसी थी, जिनके पास प्रति 'पट्टायत' ३१६ गांव थे। इस प्रकार बीकानेर राज्य के सामन्त-वर्ग में राठौड़ का ही बाहुल्य व प्रधानता थी। राज्य में प्रमुख प्रशासन के ही थे।

पट्टा-प्रणाली

राज्य में पट्टा-प्रणाली जिस समय लागू हुई, इसको निर्धारित करना कठिन

१. दयासहाय व्यास, (पृ०) २, पृष्ठ ५-६
२. वही, पृष्ठ ८
३. वही, पृष्ठ १६६
४. वही, पृष्ठ २१२-१३
५. मार्शल्लान कल्पद्रुम, पृष्ठ २०४-६

है। १८वीं शताब्दी की शुरुआत में इस प्रकार के विवरण अवश्य आते हैं कि राजा रावसिंह ने अपने ठाकुरों को पट्टे प्रदान किये थे।^१ राज्य की प्रथम प्राप्ति पट्टा वही राजा मूरसिंह के बाल की है, जिससे विदित होता है कि राज्य में पट्टा प्रणाली का प्रचलन १६२५ ई० से पूर्व हो चुका था।^२

पट्टा प्रणाली राज्य की सामन्त-व्यवस्था में एक विशेष परिवर्तन की ओर संकेत करती है। इससे राठौड़-राजपूता की कुलीय मान्यताएँ, जो कि राजा की साम्राज्यवादी की भावना पर गठित करती थी, समाप्त हो गई तथा उसके स्थान पर शासक द्वारा प्रदत्त पट्टे में उल्लिखित 'चाकरी' से निर्धारित दायित्वों पर जागीरी क्षेत्रों का उपभोग करने वाले सामन्त-वर्ग का निर्माण हुआ।^३ सामन्तों को अपनी वशानुगत क्षेत्रीय इकाइयों पर अधिकार बनाये रखने के लिये शासक की ओर से पट्टा प्राप्त करना आवश्यक हो गया, जिसमें उल्लिखित निर्धारित 'चाकरी'—सैनिक अथवा असैनिक का निर्वाह करना भी उतना ही आवश्यक हो गया।^४ पट्टे में उसे प्रदान किये गये गांवों की संख्या, कई बार उसकी आय तथा विभिन्न वसूली हेतु करों की संख्या व दर भी स्पष्ट लिखी होती थी। पट्टे में यह निर्देश उल्लिखित होता था कि पट्टायत भू-राजस्व को निर्धारित दरा पर वसूल करेगा, गांव में आवादी बढ़ायेगा तथा अन्य सहायक करों को वसूल करके राज्य का निर्धारित करा को चुकायेगा।^५ प्रत्येक नये पट्टायत को पट्टा प्राप्ति के अवसर पर शासक को एक निर्धारित रकम 'पेशकसी' के रूप में चुकानी पड़ती थी।^६ प्रत्येक पट्टे के लिये यह राशि अलग-अलग थी।^७ 'पेशकसी'

१ पट्टा वही वि० सं० १६८२/१६१५ ई०, न० १

२ परवाना वही वि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृ० २३-२६, पट्टा वही वि० सं० १६५२/१६८५ ई०, पृ० ६८

३ वही

४ श्री जी मेहरवानगी वर राठौड़ जातवसिष्ठ केमरीसिंह सीध नीपोत जीवणदास प्रदाप-सपोत रो पीठ रो व्याप काधल बपीरोठ नै पटो ईनामत कीयो दीण रो विपत

गी० ४—लीभणा बसुवा गो० १ मेघसर

गी० ५ खरर गांव ५ चाकरी भसवार ५ खरर भसवार ५ सु मुहीम माईकर सीग रै हाजरी पट्टे माटे भर लीजमी हमल हसाबी लेसी रैयत आवादीन राखसो जयो बाधरी किणी मु करन पार्व नही भसष बडूक वरछी राखसो सोव सध धनीयो पटो सावक दसगूर बाहुल राखीयो समत १८२८ मिली सावण बंद ५ मुकाम पाव तखत थी बोकानेर, कीट दाखल दसो मुहती राव बरतावर सध

— भैया सध परवाना पट्टा, सावण बंद ५, वि० सं० १८२८/३१ जुलाई १७७१ ई०

५ परवाना वही वि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृष्ठ २२-२४

६ महाजन पट्टे में यह रकम बीस हजार के समान बसुवा की जाती थी, लेकिन महाराजा अनूपसिंह ने उत्तराधिकारी चुनाव के समय ८०,००० रु० पेशकसी के रूप में वसूल किये थे। ठिकाना सीधमुख से यह १६,००० रु० में वसूल की गई थी। पट्टा वही वि० सं० १७४३/१६८५ ई०, पृष्ठ ७

की राशि निर्धारित करत समय कौन से तत्त्व उत्तरदायी होत थे, इस पर सम कालीन स्रोत मौन है। ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि पट्ट के क्षत्र क आकार व आय क साधनों से इस राशि का निर्धारण अवश्य प्रभावित होता होगा। सामन्त क परिवार व किसी सदस्य द्वारा पट्टा प्राप्ति की लालसा भी राशि को बढ़ा दती थी।^१ वास्तव म पट्टायत द्वारा शासक का यह भेंट शासक की स्वच्छाचारिता की प्रतीक थी। १६वां शताब्दी के प्रारम्भ म अवश्य यह राशि पट्ट की कुल आय का १/३ भाग निर्धारित हो गई थी।^२ राज्य व प्रमुख पट्टायता की जगात^३ वसूली क अधिकार भी मिल हुए थे।^४ क्षत्र व सम्पूर्ण फौजदारी अधिकार उन्हीं क पास थे। अपन क्षत्र म वे शांति व व्यवस्था व लिये उत्तरदायी थे। प्रत्येक पट्टायत को पेशकसी व अन्नावा अपन पट्ट के क्षत्र म बस निवानियों से राजा के कमचारियों द्वारा घुमा भाछ^५ रुखवासी भाछ^६ नोता,^७ हकूम,^८ धान की चौथाई^९ व इत्यादि कर वसूल करवाने म सहायता देनी पड़ती थी।^{१०}

पट्ट म चाकरी^{११} व लिय निर्धारित सैनिका की जाबता का असवार^{१२} कहा जाता था। पट्ट म उत्सखानुसार उनकी नियुक्ति लसकर^{१३} 'मुहिम'^{१४} या देस^{१५} म की जाती थी।^{१६} साधारणतया म असवार^{१७} घुड़सवार सैनिक ही हुआ करत थे, पर ऊटसवार तथा प्यादा की चाकरी भी इसम सम्मिलित कर ली जाती थी। पट्ट के क्षत्र की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति पर यह निर्भर

१ वही

२ वैराग्यन, पृष्ठ २४

३ भूमीकर

४ पट्टा वही वि० सं० १७१३/१६८५ ई०, पृ० ७

५ वही

६ महार

७ सुरला कर

८ विवाह उत्सव पर अमलन कर

९ विविध

१० जमा किए अनाज पर चौथाई (१/४) कर

११ बीरा जमरासर दे भेज रो वही सं० १३४८/१६८१ ई० न० २७ बीरा जमरासर वंशा ह्व गुमांभर र सख रो वही सं० १३६८/१७४२ ई० न० ३१—बाबावर बहियात कागदा की वही सं० १८२४/१७८७ ई०, न० १० पृ० २०४

१२ निष्पीरत सजिद

१३ मुज

१४ पररम

१५ मजन देस

१६ पट्टा वही सं० १६८२/१६२२ ई०, न० १ सं० १३०४/१६४७ ई०, न० ३ सं० १७४२/१६८२ ई०, न० ६

सारणी—पट्टा और चाकरी

५८

राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था

वर्ष ई० सन्	खाप बीकावत राठोड			खाप काधलोत राठोड			खाप बीदावत राठोड			देशी-परदेशी ठाकुर		
	कुल गाय	कुल सह्या अमवार	अमवार सह्या का गाव सह्या के साथ प्रतिशत	कुल गाव	कुल सह्या अमवार	अमवार सह्या का गाव सह्या के साथ प्रतिशत	कुल गाव	कुल सह्या अमवार	अमवार सह्या का गाव सह्या के साथ प्रतिशत	कुल गाव	कुल सह्या अमवार	अमवार सह्या का गाव सह्या के साथ प्रतिशत
१९२५	३२७	११०	३३.६३%	२१७	११३	५१.०१%	१३८	११२	८१.१५%	१२२	१३६	११३.१३%
१९३७	३०४	७३२	७६.३१%	१४६	११७	८०.१३%	१७६	१६१	८६.४०%	७७	७०	९०.६०%
१९६८	३८४	८७६	७२.७४%	१७०	१२४	९०.५८%	१७४	१६४	९४.२५%	२७	२५	९२.५७%
१९९८	४६०	४८२	१०४.७८%	३८	३९	१०३.२४%	२२८	२७२	११९.२६%	१०१	१५६	१५४.४५%

रहता था कि बौन-मे सैनिक चाकरी के लिये चुने जायें।^१

'जाबता असवार' की सहाय्य किम आधार पर निर्धारित की गयी थी, इसका विवरण नहीं प्राप्त होता है। राज्य की पट्टा बढ़ियाँ में गावों की सहाय्य के पीछे 'जाबता असवारों' की सहाय्य तिग दी गई है। पट्टे और चाकरी के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिये पड़ोसी राज्य मारवाड़ की भाँति यहाँ रख प्रथा का प्रचलन नहीं था।^२ १८वीं शताब्दी के अन्त में अवध पट्टों की कुल आय के सदर्भ में रेश शब्द का प्रयोग किया गया है, पर वह भी कुछ गावों के लिये। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह प्रयोग भी बन्द हो गया है।^३ जहाँ विवरण मिला है, वहाँ प्रति १००० रेश पर १ 'जाबता असवार' निर्धारित हुआ है।^४ बीकानेर राज्य में रेगिस्तानी खातावरण में फलस्वरूप अनाज व जनसंख्या की कमी की समस्या से आधिन अस्थिरता छाई हुई थी। सम्भवतः इस कारण गावों की 'जमा' अथवा 'रेख' अनुमानित करके ही 'जाबता असवारों' को निर्धारित कर दिया जाता था। समकालीन सामग्री में केवल 'जाबता असवारों' के ही उल्लेख से यह भी जान पड़ता है कि इनके आगे गावों की अनुमानित आय का मानक अपने दायरे में काफी विस्तृत रहा होगा।

गावों या क्षेत्रों की निर्धारित आय पर 'जाबता असवारों' का निर्धारण केवल 'चाकरी पट्टों'—देशी-परदेशी, हजारी, कामदारी व अस्थायी पट्टों में ही हुआ करता था। बीका राजवंश के सम्बन्धियों व नातेदारों के वशानुगत पट्टों में चाकरी के लिये 'जाबता असवारों' का निर्धारण 'जमा' के अलावा अन्य कारणों से भी प्रभावित होता था। जिनमें मुख्य थे, पट्टागत वा राज-परिवार के साथ रक्त वा सम्बन्ध, पट्टे का स्वरूप तथा पट्टे के निर्माण का समय व उसकी परिस्थितियाँ। साथ में दो गई सारणी से यह विदित होना है कि इन कारणों के फलस्वरूप माधारण व वशानुगत पट्टों के पीछे दायित्वों में काफी अन्तर था। राज्य में साधारणतया कम-से-कम एक गाव के पीछे एक 'जाबता असवार' का उल्लेख अवश्य मिलता है तथा वशानुगत पट्टे राज्य के सभी भागों में बिखरे हुए थे। इसी आधार पर पट्टा और चाकरी सारणी के माध्यम से पट्टा और 'जाबता

१ भाटिया के साथ से अजिब ऊँट व प्यादा जाते थे, भाटिया के पट्टे, पट्टा बही स० १६८२/१६२५ ई०, न० १

२ जी० डी० शर्मा—राजपूत पोलिटो, पृ० ८४-८७, दिल्ली, १९७७

३ पट्टा परवाना भाटुवा मुद्र ३, न० १८६०/२२ अगस्त, १७७३ ई०—भेय्या सपह, बीकानेर। मिर्जापुर दयालदास ने अपने किमी भी ग्रन्थ में बीकानेर के सदर्भ में रेश शब्द का प्रयोग नहीं किया है जबकि अपने गावों व सैनिक दायित्वों का करो का पूरा विवरण दिया है। यही हम धमिलेखीय सामग्री का है।

४ भेय्या सपह—पट्टा-परवाना, भाटुवा मुद्र ३ स० १८३०/२२, अगस्त १७७३ ई०

असवारों' की सख्या के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न किया गया है। बीजा खाप के पट्टायतो का राजा के साथ भीष्म रक्त का सम्बन्ध था तथा उनका पट्टो का स्वरूप यथानुगत था, जिनके पास १६२५ ई० में कुल ३२७ गावों के बदले ११० 'जाबता असवारों' की ही चाकरी देनी पड़ती थी अर्थात् उनका अपने पट्टो के बदले दायित्व केवल ३३ ६३% था। काघलोत खाप के पट्टायत राजा के पारिवारिक सम्बन्धी थे तथा उनके 'पाटवी' पट्टे का निर्माण राज्य की स्थापना के साथ हुआ था, इस कारण १६२५ ई० में इनके कुल पट्टो के पीछे चाकरी का निर्धारण ५२.०७ प्रतिशत था। काघलोतो की घाति बीदाघत पट्टायत भी राजा के पारिवारिक सम्बन्धी भाई थे लेकिन इनके पूर्वजों ने बाद में बीजा वंश के राजा की अधीनता स्वीकार की थी। इनके पास १६२५ ई० में कुल १३८ गाव थे तथा बदले में ११२ 'जाबता असवार' के अर्थात् दायित्व ८१ १५% था। काघलोतो के साथ इनके मुख्य ठियानों का स्वरूप भी यथानुगत था। इनके बदले देशी-परदेशी राजपूता ४ पट्टे, जो पूर्णतया राजा की कृपा के ऊपर निर्भर थे व अधिकांश प्रवृत्ति में अस्थायी थे के १६२५ ई० में कुल १२२ गावों के बदले १३६ 'जाबता असवार' निर्धारित थे अर्थात् दायित्व ११३ १३ प्रतिशत था जो एक गाव एक 'जाबता असवार' के सम्बन्ध में अधिक है। इस प्रकार 'आमामीदार चापर पट्टायतो' को अपने दायित्वों में निम्न स्थिति रखने के कारण काफी छूट थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ शासकों का इस पट्टायतो के दायित्वों के बारे में दृढ़ होता चला गया। सम्भवतः सैन्य आवश्यकताओं ने भी दबाव डाला हो। बीजा खाप के पट्टायतो का दायित्व १६२५ ई० में कुल गावों की सख्या के अनुपात में ३३ ६३ प्रतिशत था वह १६५७ ई० में ७६ ३१ प्रतिशत १६६८ में ७२ ७५ प्रतिशत तथा १८१८ ई० में बढ़कर १०४ ७८ प्रतिशत हो गया अर्थात् अन्य पट्टायतो की तरह लगभग एक गाव एक जाबता असवार के अनुपात में आ गया। यही स्थिति काघलोत तथा बीदाघत पट्टायतो की है। देशी-परदेशी पट्टायतो का अनुपात भी इसी तुलना में अधिक बढ़ गया। १८१८ ई० में वह १५४ ४५ प्रतिशत अर्थात् उनके दो गावों पर तीन 'जाबता असवारों' का औसत आ गया। यहाँ यह उल्लेखनीय बात है कि बीजा व काघलोत पट्टायतो के पास अधिकांश पट्टे राज्य के उपजाऊ क्षेत्र में थे।

महाराजा सूरतसिंह ने १७६४ ई० में पट्टायतो से जाबता असवारों की चाकरी के स्थान पर 'घोडा रेग' नाम का कर वसूल करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसकी दर प्रति 'असवार' १०० रु० थी। उन्होंने पट्टे के क्षेत्र में निवास करने वाली प्रजा से भी प्रति गुवाडी २ रु० की दर से सुरक्षा के नाम का 'रुखवाली

१ हबूब नही स० १८३१/१७७४ ई०, कागदों की नही स० १८७३/१८१६ ई० न० २२ पृ० १०१

भाछ' कर वसूल किया।^१ १८०० ई० में 'पोडा रेख' की दर प्रति असवार २०० रु० तथा 'रखवाली भाछ' की दर प्रति गुवाडी १० रु० हो गई।^२ इसी समय 'रेख' शब्द का भी प्रयोग किया जाने लगा लेकिन यह 'रेख' गांव की 'जमा' की भाति न होकर सवारों की सख्या की प्रतीक थी।^३ अन्त में 'पोडा रेख' व 'रखवाली भाछ' को मिलाने पर उसका नाम 'दरवार री रखम' रखा गया जो पट्टे की निर्धारित आय का एक तिहाई भाग होती थी।^४ चूंकि पट्टे चाकरी के बदले दिये जाते थे, अतः पट्टे के गांवों की सख्या भी पट्टायत्त के दायित्वों के अनुपात में घटती-बढ़ती रहती थी। केवल 'वैतसब' गांव अपवाद थे।^५

राज्य में पट्टा प्रणाली के प्रचलन का यह तात्पर्य बदापि नहीं है कि प्राचीन कुलीय ढांचे का अन्त हो गया तथा उसका स्थान एक नई व्यवस्था ने ले लिया। राज्य का सामन्त वर्ग अभी पुराने ठाकुरों की धरोहर था तथा उनकी कुलीय मान्यताएं अभी भी उनके अधिकारों व जीविषा का स्रोत थी। राजा अपने 'सम्बन्धियों' की विशिष्ट स्थिति को जड़ से उखाड़ देने की बात नहीं सोचता था बल्कि सम्मान देता था। राजा का दरबार केवल नामन्तो से सम्बन्धित था जहां राजा व विभिन्न राजपूत गतिधियों की छापो के मुखिया व उप-मुखिया मुगल दरबार की 'मनसब' व्यवस्था के आधार पर श्रेणीगत होकर न बटकर अपनी-अपनी छांप के सम्मान व सम्बन्ध के आधार पर बैठते थे। यह सम्मान उनके राजा के माथ रखन के सम्बन्ध, अपनी शक्ति व राज्य की दी गई उल्लेखनीय सेवाओं से निमित्त होता था। राजपूत दरबार सभी भी चाकरी या कार्यालय की स्थिति पर श्रेणियों में नहीं विभाजित हुआ, यद्यपि ये किसी को सम्मान प्रदान करने में एक कारण अवश्य बन सकते थे, बल्कि सर्व ही राज्य की शासकीय जाति, उगकी उपजाति तथा सेवा में आई अन्य सजातीय छापो के आधार पर ही विभाजित हुआ।^६ कुछ अपवाद अवश्य दूढ़े जा सकते हैं, पर इससे दरबार के मूल स्वरूप में अन्तर नहीं आता है।

शासकों ने पट्टा प्रणाली के माध्यम से अधिक से-अधिक अपने सामन्तों के

१ बागदा की बही सं० १८५१/१७६४ ई०, न० ८ पृ० १११

२ बागदा की बही सं० १८५७/१८०० ई० न० ११, पृ० २६८०, सं० १८७१/१८१४ ई०, न० २०, पृ० ६०, ३२२

३ भूम्या सप्त पट्टा परवाना भादुवा सुद ५ वि० सं० १८३०, २२ मगस्त, १७७३ ई०। रेख के दूसरे धर्म के लिए देखिये—जी० डी थर्मा (पूर्व) पृ० ८४, ८६

४ देगदर्पण पृ० ८७ ६४, ६७

५ परवाना वगी वि० सं० १७४६/१६८२ ई० पृ० २२ २६

६ भूम्या नयमल रं सर्व दरबार री बही, भूम्या सप्तह। यह बही महाराजा सूरतसिंह के राज की है

दायित्वों को निर्धारित कर दिया तथा उनके जाभीरों दौल पर निरीक्षण व नियन्त्रण की नीति अपनाकर राज्य में राजा की स्थिति को निरंकुश बना दिया। इस प्रणाली द्वारा उनकी शक्तियों को विभाजित करने उन्हें राजा की कृपा पर अधिक आश्रित कर दिया। राज्य एक द्वाद्वी में रूप में उभरा तथा उसके कम-स्वरूप उसकी अग्रगण्यता को सुरक्षा मिली। राज्य की आय में मोन बट गये तथा अशांति को फैलाने में अतगर घट गये। सम्भवतः राजा हमेशा अधिक चाहता भी नहीं था। ये 'भातेदार' सामन्त ही उसकी सेवा में रहते थे तथा मुगल सम्राट के साथ सम्बन्ध बिगड़ जाने तथा राज्य की विभिन्न जातियों में विद्रोह करने पर वे ही विश्वसनीय 'सहायक' थे। इनको मिठा दान में उसके स्वयम् की राज-नैतिक व सांस्कृतिक आधार समाप्त होना था। अधिक-से-अधिक वह उन्हें ठीक रखने के लिये नियन्त्रण व शक्ति सन्तुष्टन की नीति पर चल सकता था। पर, इस मूल ढाँचे में परिवर्तन न करने का एक दुष्परिणाम यह निकला कि १८वीं शताब्दी में मुगल सरकार के समाप्त हो जाने पर सामन्तों को अपनी खोयी हुई शक्ति व प्रतिरूप को प्राप्त करने का आधार मिस गया। फलस्वरूप राज्य में विद्रोह बढ़ गये।

पट्टायत दो तरह के थे। प्रथम, 'आसामीदार चाकर पट्टायत' तथा द्वितीय 'चाकर पट्टायत'। 'आसामीदार' चाकर वे पट्टायत थे, जिनके 'ठिकानों' बीका के राज्य में साथ स्थापित हो चुके थे तथा परवर्ती काल में बीका छाप के सदस्यों के लिये 'ठिकानों' बाँट गये थे। उन 'ठिकानों' पर चूँकि इनके वशानुगत एक क्षेत्रीय अधिकारों की मान्यता दी जाती थी इसलिए ये लोग आसामीदार कहलाते थे। अपने उन अधिकारों को बनाये रखने के लिये इन्हें राज्य को चाकरी देनी पड़ती थी, इसलिए ये 'आसामीदार चाकर पट्टायत' कहलाते थे। इसके विपरीत साधारण चाकर पट्टायत वे लोग थे, जिन्हें शासक के द्वारा केवल चाकरी के बदले पट्टे प्रदान किये थे। इनके पट्टे चाकरी के साथ ही बने रह सकते थे। इन पट्टायतों का अपने क्षेत्र में कोई वशानुगत दावा नहीं होता था। केवल शासक की स्वीकृति से ही ये पट्टे भी वशानुगत हो सकते थे। अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए ये शासक की कृपा पर पूर्ण आश्रित थे। इनका अपना किसी तरह का कोई भी दावा नहीं होता था।

आसामीदार चाकर पट्टायत

बीका, बीदा, काघल, मठला, रूपा के वंशज वस्तुशः 'आसामीदार चाकर पट्टायत' कहलाते थे। शासक के साथ रक्त के विशेष सम्बन्धों के कारण राज्य

में राठोड़ कुलीय भाई-बारे का महफूज 'यम' उनके पूर्वजों के द्वारा अपनी जागीर का निर्माण करने के 'परायना' में ७^{वें} अंग्रेजों के पट्टे के क्षेत्र पर विधिवत सामान-जनक शोदीय दावा रखने में। पं.देशी ठानुरों में भाटी व गाँव भी इसी श्रेणी में आते थे। राज्य की स्थापना के पूर्व उनके पट्टों विद्यमान होते थे राठोड़ों ने इनके अधिकारों को यह मंजूरता दी थी। उनके ठानुरों के क्षेत्र में नामा उनके वशानुगत अधिकारों को स्वीकार करता था परन्तु, प्रत्येक नये पट्टागत को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पतनगी पुरानी पट्टों की तथा नये पट्टे के रूप में स्वीकृति लेनी पड़ती थी। पट्टा प्रदा के प्रवर्तन के बाद में दाँते शोदी में भी धीरे-धीरे शासक का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था तथा केन्द्रीय शासन द्वारा बनाए हुए प्रशासनिक व राजस्वी निदमों को मानने के लिए बाध्य होता पट्टा था। इनके विरुद्ध इनकी प्रजा शासक तक विवादित पट्टा गहनी थी। नामा पट्टे के गाँवों में बुद्धि या बटोनी कर मकाना या घर ऐसा करने समय 'ठिकानों' के मुख्य पक्षी को बना रहने दिया जाता था। बाकी गाँवों में शासक मनवाहा परिवर्तन कर देता था। माधारणतया, नामा उनके मौनिक दायित्वों के आधार पर यह बुद्धि या बटोनी किया करता था। वह इनके 'जमान' बसूरी के अधिकार भी छीन सकता था।

शासक द्वारा साम्यता प्राप्त होने पर ही ठानुर को 'ठिकाने' के अधिकार प्राप्त होते थे। साम्यता प्रदान करने के इन अधिकार का प्रयोग शासक स्वेच्छा-पूर्वक किया करता था। छोटे-मोटे ठिकानों में तो उसका हस्तक्षेप होता ही रहता था, राज्य के 'मिरासत' व अन्य मुख्य ठिकानों भी उनके स्वेच्छाकारी आचरण से युक्त नहीं थे। विशेषकर उत्तराधिकार के मामलों में शासक का हस्तक्षेप कुछ बढ़ जाता था। महाराजा अनूपसिंह ने राज्य के सबसे प्रमुख ठिकाने महाजन में सन् १६८५ ई० से लेकर सन् १६९१ ई० तक एक के बाद एक चार

१. गाँवों के सेन-देन की बही, वि० सं० १७५६/१६९६ ई०, न० १२२, गाँवों के रकम बसूरी की बही, वि० सं० १७५६/१६९६ ई०, न० १२३, बीकानेर बहियान

२. कागदों की बही, कागों की २, वि० सं० १८२७/६ अक्टूबर, १७७० ई०, न० १, वि० सं० १८७३/१८९६ ई०, न० २२, पृ० ४-५

३. बुकरका, राज्य का सिपायत ठिकाना था। उसमें आधक में गाँवों को लेकर मनवाहे परिवर्तन किये थे। ठानुर करमसेन मनोहरकासीठ व वास सन् १६५७ ई० में २० गांव था, जो उसके पुत्र खडगमन के समय में (सन् १६६८ ई०) में रह गये थे। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फिर स अक्टूबर २६ की संख्या पर पहुंच गये थे, पट्टा बही, वि० सं० १६९२/१६९३ ई० न० २, बीकानेर के पट्टा गाँवों की विवर, वि० सं० १७९४/१६५७ ई०, पट्टा बही वि० सं० १७२५/१६६८ ई०, न० ४, आदाशियान बसूरी, पृ० १८७

ठाकुरों को नियुक्त किया था।^१ इस प्रकार का हस्तक्षेप महाराजा अनूपसिंह ने रावतसर के ठिकानों में,^२ महाराजा गजसिंह ने बूळ के ठिकानों में,^३ महाराजा सूरतसिंह ने भीष्ममुख के ठिकानों में किया था।^४ बिगी खांप की एक शाखा को हटाकर दूसरी शाखा को पट्टे भी दिये जाते थे।^५ एक खांप में पट्टायत के गांवों में

१. महाराज के ठाकुर जगतसिंह उदैमानोन की सन् १६८२ ई० में मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र अजसिंह को पट्टा प्रदान किया गया। तीन वर्ष बाद उसे हटाकर उसके छोटे भाई मानसिंह को ८०,००० पैसवगी के बदले पट्टा प्रदान कर दिया गया। एक वर्ष पश्चात् सन् १६८९ ई० में अजसिंह ने ८०,००० व० पैसवगी देकर पुनः पट्टा प्राप्त कर लिया। परन्तु दो वर्ष बाद ही उसने एक अन्य भाई हिम्मतसिंह ने ८०,००० व० पैसवगी के बिना जगत के महाराज पट्टे को महाराजा से प्राप्त कर लिया।

मु० सोहन लाल रचित, तत्कालीन राज धी बीरानेर बीर बीरभुनी श्रीरामभुन—
साजीमी, राजबीर, ठाकुरों के पञ्च दशकालीन और बीरानेर तथा बीरानेर राज्य का इतिहास भाग २, पृ० १४२ में महाराज के ठाकुरों के बल प्रम में उदैमान के पश्चात् पाँचों ठाकुरों का नाम नहीं दिया गया है। जबकि परवाना बरी के पट्टा बरिषों में इनका पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। सम्भवतः अपने पगले के सम्मान को बचाने के लिए उपर्युक्त चरित्रों में सम्मिश्रित भगरी का वर्णन न दिया गया हो। परवाना बही, वि० स० १७४६/१६८२ ई० पृ० २२, २४, पट्टा बरी वि० स० १७५३/१६८९ ई०, पृ० ७, पृ० ५, ७

२. महाराजा अनूपसिंह ने ठाकुर जगरसिंह अजसिंहों से पट्टा छीनकर लखवीर राज को सौंप दिया था, परवाना बरी १७४६/१६८२ ई०, पृ० ३१

३. महाराजा गजसिंह ने बूळ ठाकुर छीरसिंह के पुत्रों को वही न देकर उसके भाई हरीसिंह को गरी प्रदान कर दी थी, परवाना बरी, वि० स० १७४६/१६८२ ई०, पृ० ४४, ४७
सोमिन्द अग्रवाल (मूर्ख) पृ० २१२

४. महाराजा सूरतसिंह ने भीष्ममुख के ठाकुर माहरसिंह को सातव बिरौधी होने के दण्ड-फलस्वरूप मरवा दिया था कि उसने छोटे भाई अमरसिंह को पट्टा प्रदान कर दिया था
—दयालदास श्यात (अग्रवाल) भाग २, पृ० ३२२

५. राज्य में सामान्यतः यह प्रथा थी कि एक खांप के ठिकानों के गांव को छोड़कर अन्य गांवों में हस्तान्तरण कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में 'जातामीदार पाकर पट्टायतो' के श्लोक में विशेष बात यह थी कि उन गांवों को उगी खांप के दूसरे पट्टायतों को दिया जाता था। अन्य खांप के पट्टायतों को उन गांवों को देने में पहली खांप के अधिकारों के सम्मिलन। हस्त समझा जाता था। बीरानेर के नामों ने पट्टा प्रणाली द्वारा हर दृष्टि से, सामान्य के क्षेत्रीय दावों को धुनीनी देकर उनकी स्थिति को शासन की हृषा पर निर्भर बनाने के प्रयत्न किये थे। महाराजा अनूपसिंह न बीरानेर की हरावत शाख का हटाकर सोभावर का पट्टा दूसरी शाखा मरनावत को दे दिया था। महाराजा मुजानसिंह ने हरावत शाख का पट्टा बीरानेरों की तैजसिंहों शाखा से छीनकर पट्टायत को मरवावर दूसरी शाखा पुष्पोराजोत को सौंप दिया था। बीरानेरों के पट्टे, पट्टा बही वि० स० १७२५/१६६८ ई०, पृ० ४, वि० स० १७५३/१६८६ ई०, पृ० ७, परवाना बही, वि० स० १७४६/१६८२ ई०

उसके छुट-भाइयों के लिए नये ठिकाने बाधना तथा उमड़े पट्टे के कुछ गांवों को अलग करके दूसरी स्थाप के ठिकाने बाधने की प्रथा का भी सामान्यतः प्रचलन था।^१ कुछ मामलों में ठिकाना गांव भी छीनकर दूसरों को दे दिया गया पर, ऐसा बहुत कम हुआ है। शासक के द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के रूप में, इस प्रकार प्रायः ठाकुरों के वशानुगत अधिकारों को चुनौती दी जाती थी।^२ पट्टागत के विद्रोही हो जाने पर इससे पट्टे के कुछ गांव या कभी-कभी सम्पूर्ण पट्टा ही 'पालसा' कर लिया जाता था। महाराजा सूरतसिंह ने तो राज्य के दो प्रमुख 'ठिकानों'—चूरु व भादरा को मदैब के लिए 'पालसा' में मिला लिया था।^३ साधारणतया सामन्त के क्षमा मांगने पर अथवा उसके पुत्र का पुनः उसका 'ठिकाना' दे दिया जाता था। इस प्रकार शासक के हस्तक्षेप से पट्टा व्यवस्था के माध्यम से 'आसामादार चाकर पट्टायतो' के क्षेत्रीय गांवों को बहुत सीमित कर दिया गया था। कुछ खास तो अपना अस्तित्व ही खो बैठी थी।^४

मुघलों के पतन के बाल में, जब शासक किसी भी विपत्ति में केन्द्रीय शक्ति पर अवलम्बित नहीं रह पाया तथा माग्याध के आक्रमणों ने उसकी सैनिक दुर्बलताओं को प्रकट कर दिया, तब उमड़े अपने सामन्तों विशेषकर 'आसामादार चाकर पट्टायतो' की सहायता पर अधिक निर्भर रहना पड़ा। वशानुगत अधिकारों से सम्पन्न ठाकुरों ने इसका लाभ उठाते हुए अपनी खायी हुई शक्ति व प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये। उन्होंने चाकरी व पट्टा प्रथा तथा उससे होने वाले हस्तक्षेपों का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। वे राज्य-प्रशासन को राठीड-कुली-सिद्धान्त पर पुनर्गठित करना चाहते थे तथा काबलीत व बीदावत ठाकुर इसका अग्रगण्य थे।^५ बीकानेर शासकों द्वारा अधिकृत

१ बीदावती की खगरीन छाया के ठिकान सही के बहुत में गांव छीनकर बणीरोत, कांध-सोत छाप के पट्टेदारा को प्रदान किए गये थे।—बीदावत पट्टे, पट्टा वही वि० सं० १०५३/१९८६ ई० नं० ७, परवाना बही वि० सं० १७४६/१९८२ ई०

२ सामान्यतः ठिकानों को 'बतों' करके खासमा में मिला लिया जाता था। कुछ उदाहरण दूसरे ठाकुरों को देने के भी हैं। बीका राठीड की बाघावन छाया के पास कमल भटनेर, मोहर व मेवाणा के कल व गांव ठिकान के रूप में रहे थे। अन्य राजपूत जातियों में सोनगरो के पास बाघ का ठिकाना था जो महाराजा जोरामर सिंह के काल में अथवा बीका राठीड को दे दिया गया। धनोत वही वि० सं० १८००/१७४३ ई०

३ दमानदास छाया (अग्र०) भाग २, पृ० ३१७-२२

४ बीका खोर व राजावत, रामावत छायावत व मदनदासोत का अस्तित्व ही मिट गया था।

५ बीकानेर के राठीडा की छाया महाराजा मुजानसिंह की सु० गवर्नरजी हार्डि, पृ० २, ७, २५, ३६; मोहता मदी, पृ० ६९ ६५, दयानदास छाया (अग्र०) ३, पृ० २५८-६६, २६५, ३२२

मुगल परगनो के क्षत्र तथा पूर्वी क्षेत्र के चिरो म पालसा भूमि के विस्तार की अभिलाषा ने प्रभावशाली ठाकुरो की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओ म बाधा उपस्थित की। धीरे धीरे हस्तक्षेपो तथा अनेक बाधाओ न उह विरोधी आचरण कतायना दिया।^१ दूसरी ओर मुगल कान म प्राप्त शक्ति व प्रतिष्ठा को शासन भी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे और विस्तृत करने की महत्वाकांक्षाएँ रखते थे। ऐसी परिस्थितियाँ में शासन और सामन्ता के सम्बन्धो म तनाव की स्थिति प्रकट हुई। शासन की सत्ता को चुनौती देत हुए हरासर, चूरू व भादरा के ठाकुरो न तो स्वतन्त्र इकाई के स्वामी के रूप म व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया।^२ षोडा रज्ज व हलवासी भाछ का प्रचलन हो जाने से ठाकुरो की परम्परागत सैनिक शक्ति की प्रतिष्ठा को और भी घबका पहुँचा। वे इन करा का भार महन नहीं कर पाये^३ जिसने उह विरोधी रज्ज अपनाते के

१ परगना भटनर व पुनिया के अधिकतर गांव खालसा में मिलाये गये थे। पट्टायतो को यह गांव अधिकतर चाकरी पट्ट के रूप में या मुनात में दिय गये थे जिन्हें शीघ्रता से वापस लिया जा सकता था। इन परगनो म भादरा व मीठमुख पट्ट के अलावा किसी भी पट्ट को स्थायी नहीं बनन दिया था। महाराजा सूरतसिंह ने अपने सभी विभिन्न क्षत्र खालसा में रख थे केवल फत्तोपी क गांव ही चाकरी पट्ट में अधिकतर भाटी ठाकुरो को प्रदान किये थे।

जब बीदावत बिहारीदास भगवदोन न अपनी शक्ति बढाकर फतेहपुर विजय की योजना बनाई थी तो महाराजा मुजाफसिंह न उसकी शक्ति वृद्धि की आज्ञा से उसे रोक दिया था। धनूपगढ़ व भटनर के क्षत्र खालसा में मिला देने में रतनमोत बीका नाराज हुए। क्योंकि वे इसी दिशा में अपना प्रभाव क्षत्र विस्तार कर सकते थे मीहूर रीणी व पुनिया म खालसा गांव बढान से कापिलोत दुखी हुए थे क्योंकि वे इसे अपना प्रभाव-क्षत्र मानते थे। भादरा ठाकुर लासमिह के साथ भयक का एक मुख्य कारण यही था।

—वही हासल भाछ परगना बनीवाल र गांव री वि० स० १७४५/१६८८ ई० न० २ राजगढ़ रे पुनीया रे परगन रे हासल लेख री बही वि० स० १७४६/१६६२ ई० न० ६ फत्तोपी रे जमा ग्राम री बही वि० स० १७४५/१६६८ ई० न० ३२ भटनर तामल री बही वि० स० १७४२/१६६५ ई० न० ११ बोकानर री ख्यात महाराजा मुजाफसिंह स महाराजा भजसिंह जी ताई प० ७१ दयालदास ख्यात (अग्र०) भाग २ प० २६५ २६७ २७२ ७४ ३०२ ३२२

२ दयालदास ख्यात (अग्र०) २ प० २१५ २२

३ दयालदास ख्यात (अग्र०) २ प० २६५ २१८ २२

श्री गोविंद अग्रवाल—चूरू का इतिहास प० २४२ लेखक न उन परवानों को उदघात किया है जिसमें फता चल्ता है चूरू के ठाकुर शिवसिंह महाराजा ने विरुद्ध स्वतन्त्र आचरण कर रखे थे।

४ भैया सप्तह भैया नयमल का पत्र माघ बनी १० वि० स० १८६१ २५ फरवरी १८०५ ई०

लिए सम्प्रेरित किया।^१ ठाकुरों के विरोध से राज्य में निरन्तर सघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि शासक के प्रति सदैव स्वामिभक्त रहने वाले, बीजावत ठाकुर भी इन परिस्थितियों में राज्य के विरोधी हो गये।^२ इन विरोधों के परिणामस्वरूप, शासक की स्थिति इतनी जेय हो गई कि फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सन्धि से ही उस सुरक्षित किया जा सका।

चाकरी पट्टायत

राज्य में 'आसामीदार चाकर पट्टायतों' के छुटभाईयों को तथा देशी पर-देशी राजपूतों को उनकी सैनिक या प्रशासनिक सेवाओं के बदले 'चाकरी पट्टे' प्रदान किये गये थे। ये पट्टे भी साधारणतः वशानुगत अधिकार प्राप्त करने पड़ते थे। इन पट्टों के मुख्य गाव या अन्य गावों में शासक मनोवांछित हेर-फेर कर सकता था, यहाँ तक कि उन्हें छीन भी सकता था।^३ चाकरी पट्टे एक गाव के भी तथा एक गाव के एक यास (भाग या मोहल्ले) के भी हो सकते थे। राज्य में बड़े गावों के कई भागों के अलग-अलग चाकरी पट्टायत होते थे।^४ ये लोग 'आसामीदार चाकर पट्टायता' सासण या पुनर्ष के गाव नहीं प्रदान कर सकते थे।^५ इन पट्टायतों के कोई क्षेत्रीय दावे नहीं थे। इनके द्वारा दी गई अनुदान-भूमि भी स्थायित्व नहीं रखती थी।^६ पट्टायत केवल 'भोग (माल)' व निर्धारित 'रोकड़ रकम' (महायक बमूली कर) बमूल करते थे तथा अपन क्षेत्र में शान्ति व व्यवस्था का दायित्व निभाते थे। 'आसामीदार चाकर पट्टायत' भी चाकरी पट्टे अलग से प्राप्त करते थे, जब उन्हें अपने क्षेत्र से अलग, कोई सैनिक व प्रशासनिक कार्य सौंपा जाता था। उस दायित्व की समाप्ति के साथ या पट्टायत की मृत्यु के साथ उनके गाव राज्य में मिला लिए जाते थे। ऐसे गावों को 'वपारे गाव' कहा जाता था। यह आवश्यक नहीं था कि ये गाव पट्टेदार के ठिकानों के

- १ कांगदा की बही वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृ० १२४, वि० सं० १८७२/१८९५ ई०, न० २१, पृ० २२-२६
- २ बपालदास ख्यात (अग्र०) पृ० ३१५-२२
- ३ परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृ० ४० ३५, पट्टा बही, वि० सं० १०५३/१६६६ ई०, पृ० ६० ६६
- ४ परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृ० ५३-५६
- ५ परवाना बही वि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृ० ५२
- ६ कांगदा की बही वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० ८६, वि० सं० १८७४/१८९७ ई०, न० २३, पृ० ३०, १३६
- ७ बही

पात ही स्थित हो।^१ चाकरी पट्टों का भविष्य पूर्णतया शासन की कृपा पर आश्रित था जोकि अधिराज्यत एक पट्टायत के जीवन काल में ही समाप्त हो जाता था। बहुत कम पट्टायत वंशानुगत अधिकारों का प्रयोग कर पाते थे।

आसामीदार व गैर आसामीदार चाकरी पट्टा के अध्ययन में दो बातें विशेषतः परिलक्षित होती हैं। प्रथम, राज्य के सीमा क्षेत्र पर ही शासन के द्वारा इन्हें अधिक पट्टे प्रदान किये थे।^२ सीमा की सुरक्षा के उद्देश्य में सम्भवतः ऐसा किया होगा। द्वितीय, शासकों को मुगलों से तनख्वाह जागीर के रूप में जो परगने उनकी वतन जागीर के समीप के क्षेत्र में प्राप्त हुये थे, उन परगनों में उन्हीं आसामीदार चाकरी पट्टे प्रदान किये थे।^३ कई नये ठिकाने वहाँ स्थापित किये थे।^४ कालान्तर में, शासकों ने उन परगनों पर अपना क्षेत्रीय दावा प्रस्तुत करके इन्हें स्थायी रूप से राज्य में मिला लिया था। राज्य के बाघसैनिकों व विशेषकर बीका सामन्त अधिकतर पट्टे इन्हीं परगनों में प्राप्त करना चाहते थे। यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ व समृद्धशाली था। समस्त शासक वर्ग में बीका राठीडा की दृढ़ स्थिति का एक कारण उनका इस उपजाऊ क्षेत्र पर अधिकार था था। पट्टायत इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पट्टे के भाव प्राप्त करने की प्रक्रिया में रहते थे। शासक वर्ग भी इसी क्षेत्र में खालसा भूमि का अधिकाधिक विस्तार करने का प्रयास करता था। महाराजा सूरतसिंह द्वारा भादरा की खालसा में मिलाने के पीछे यह भी एक उद्देश्य था। जैसा कि पहले निम्ना जा चुका है शासन व सामन्तों के बीच तनाव का यह एक मुख्य कारण बना।

कामदारो-हजूरियों के पट्टे

पट्टा प्रणाली केवल सैनिक सेवा तक ही सीमित नहीं थी बल्कि प्रत्येक प्रकार की चाकरी के वेतन के रूप में भी पट्टे प्रदान करने का प्रचलन था। ये 'रिजब पट्टे' कहलाते थे। राज्य के मुत्सदियों में प्रमुख मन्त्रियों व अधिकारियों को उनकी चाकरी व वतन के रूप में, कुछ नगद वेतन के साथ, पट्टे की आय

१ अनुगढ़ भटनर पूनीया हिसार व फलोधी के क्षेत्रों में पट्टायतों की पीढ़ेदार के रूप में नियुक्ति की गई थी व उसके बदले उन्हें चाकरी पट्टे दिये गये थे।

—पट्टा बही वि० सं० १७५३/१६६६ ई० पृ० ११ २६ ३८ ४४ ५०

२ देखिये पट्टेदारी क्षेत्र का मानचित्र

३. राज्य का प्रसिद्ध ठिकाना मांजू भीमा व भादरा पूनीया व रानीवाल परगनों में स्थित थे—परवाना बही वि० सं० १७४६/१६८२ ई० पृ० २५-२७ पट्टा बही वि० सं० १७५३/१६६६ ई० पृ० ८६ प्रायोज्यान पल्पद्रुम, पृ० ६० दयालदास क्वात (अग्र०) २ पृष्ठ २६३

४ उपयुक्त

भी वेतन में सम्मिलित की जाती थी।^१ राजा के निजी सेवक-हजूरियों तथा विभागों के कार्याध्यक्षों (फौजदार) को भी वेतन-भोगी पट्टे दिये जाते थे।^२ मुत्सद्दियों, कामदारों तथा हजूरियों के पट्टे 'भीतरलो' साथ के गाव कहलाते थे। ये पट्टे केवल चाकरी बाल तक के लिए दिए जाते थे। इन पट्टों का हस्तान्तरण भी होता रहता था।^३ केवल हजूरियों में कुछ गाव आसामीदार पट्टों के गाव थे।^४ कामदारों व हजूरियों के मुख्य गावों की ठिनाणा नहीं कटा जाता था, क्योंकि न तो वश की दृष्टि से तथा न किसी क्षेत्रीय दावे की दृष्टि से, ये पुराने तथा नये पट्टापतों के सम्बन्ध सम्झे जाते थे। ये राज्य के सफर हात थे। अपने पट्टे में से वे कोई 'मामण' या परिवार के व्यक्ति को, गाव दे नहीं सकते थे।^५ इनके पट्टे वेतन भोगी व व पट्टा के बान पर राज्य के सामन्त वर्ग में इनका कोई स्थान नहीं था। कामदार पट्टापतों की स्थिति कुल पट्टों में सन् १६२५ ई० में १७५ प्रतिशत ही थी, जो कि सन् १६५७ ई० में बढ़कर २५६ प्रतिशत हो गयी। सन् १६८५ ई० में २४३ प्रतिशत थी जो सन् १८१८ में ३४५ प्रतिशत हो गयी। मद्रास/जा मजमिह व सूरतमिह ने कामदारों को अधिक पट्टे दिये थे।^६ कुल 'भीतरलो' साथ पट्टों की स्थिति कुल पट्टों में सन् १६२५ में ३८१ प्रतिशत थी जो सन् १६५७ ई० में घटकर २५६ प्रतिशत रह गयी और सन् १६६८ ई० में तो यह १०४ प्रतिशत ही थी। सन् १८१८ ई० में इनकी स्थिति ५३६ प्रतिशत होने के कारण सन्तोषनाक हो गयी थी। प्रति पट्टापत इनके पास एक से कम गाव आता था।

बेतलब पट्टे

राज्य के कुछ चाकरी पट्टे जीविका निर्वाह हेतु प्रदान किए थे, जहाँ से राज्य-प्रशासन किसी प्रकार का कोई कर बमूल नहीं करता था। उस पट्टे की सारी आम पट्टापतों की हो जाती थी। बेतलब पट्टे विभिन्न व्यक्तियों को प्रदान किये गये थे जो उन्हीं के नाम पर विख्यात हुए थे। वे पट्टे निम्नांकित थे।

- १ कामदारों के पट्टे-पट्टा बही, वि० सं० १६६२/१६३५ ई०, न० २, वि० सं० १७२५/१६६८ ई०, न० ५, वि० सं० १७५३/१६६६ ई०, न० ७
- २ हजूरियों के पट्टे—उपयुक्त
- ३ उपयुक्त
- ४ गाव बेरामर, बयानु, उदरामसर हजूरियों के स्थाई प्रकृति के गांव थे, जहाँ वे यथानुगत अधिकारों का प्रयोग करते थे
- ५ कागदा की बही जेठबद व, वि० सं० १८५६/२४ मई १८०२ ई० न० १२
- ६ कामदारों के पट्टे, हजूरियों के पट्टे—वरवाना बही वि० सं० १८००/१०४३ ई०, देशदर्पण पृष्ठ १४७ ५२

राजलोकों के गाव

जब दरबार की ओर से, शासक के निजी सम्बन्धियों को, उनकी जीविका व सम्मान को बनाए रखने हेतु पट्टे प्रदान किये जाते थे, तो वे 'राजलोकों के गाव' कहलाते थे। इनमें कुवरो के पट्टे जो कि राजा के पुत्रों को दिये जाते, 'जनाना पट्टे' जो कि मुख्यतः महारानियों व रानियों को दिये जाते थे तथा भाईयो के पट्टे जो राजा के भाई व उनके पुत्रों को दिये जाते थे, मुख्य थे।^१ कुल पट्टों में इनकी स्थिति १५६ प्रतिशत से ज्यादा कभी नहीं बढ़ पाई। 'वेतलब पट्टों' में इनकी स्थिति १०५ प्रतिशत से अधिक नहीं थी। केवल सन् १८१८ ई० के लगभग ये राज्य के कुल पट्टों में ४७२ प्रतिशत थे, तथा वेतलब पट्टों में इनकी स्थिति १३८७ प्रतिशत थी।

सासण व पुनर्ध के गाव

राज्य दरबार, विभिन्न धर्मावलम्बियों, शिखा-शास्त्रियों तथा धार्मिक कृत्यों से सम्बन्धित लोगों को धर्म व पुनर्ध के अनुदान के रूप में, पट्टे के गाव देता था। साधारणतया ये पट्टे ब्राह्मणों चारणों व सन्यासियों को दिये जाते थे।

इसी भाँति, राज्य के कुछ प्रसिद्ध मन्दिरों का खर्चा चलाने हेतु कुछ पट्टे दिये जाते थे, जो 'मन्दिरात के पट्टे' कहलाते थे।^२ ऐसे पट्टों की स्थिति, कुल पट्टों में सन् १६२५ ई० में ०.८३ प्रतिशत थी। सन् १६६८ ई० में बढ़कर १.१३ प्रतिशत थी और सन् १८१८ ई० में बढ़कर यह ५.४७ प्रतिशत हो गयी। महाराजा सूरतसिंह द्वारा, ब्राह्मणों को काफी सख्या में पट्टे प्रदान करना ही इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण था।

व्यावसायिक पट्टे

राजमहल अथवा दरबार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो व्यावसायिक जातियाँ विभिन्न कार्य करती थी, उनको भी 'वेतलब' पट्टे दिये जाते थे। इन पट्टेदारों में सुधार, सुनार व उस्ते चित्रकार मुख्य थे।^३

१ प्रत्येक पट्टा बही राजलोक पट्टा से ही प्रारम्भ होती है। विस्तृत अध्ययन के लिए—परवाना बही वि० सं० १७४६/१६८२ ई०, पृष्ठ २२६

२ सासण पुनर्ध व मन्दिरात के पट्टे, पट्टा बही, वि० सं० १६८२/१६२५ ई०, न० १, वि० सं० १७२५/१६६८ ई०, न० २, वि० सं० १७५३ ई०, न० ७—विस्तृत अध्ययन के लिए—परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृष्ठ ७२ ८६

३ परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृष्ठ ७२ ८४

४ उपर्युक्त—पृष्ठ ६० ६४

अधिकार एवं कर्तव्य

राठोड-कुल-परम्पराओं के प्रभावशाली होने के समय सामन्तगण अपने क्षेत्र में विस्तृत अधिकारों का उपयोग करते थे। अपने क्षेत्रों में प्रत्येक सामन्त वस्तुतः शासक का प्रतिरूप होता था। वह अपने छाव-परिवार का 'पाटवी' होने के कारण, सारी 'जमीयत' को आने शण्डे के नीचे एकत्रित करता था। वह अपने क्षेत्र में फौजदारी व दीवानी का मुख्य न्यायाधिकारी होता था तथा क्षेत्र के सम्पूर्ण कर, उससे धजाने में जमा होते थे। वह अपनी भूमि पर वशानुगत अधिकारों का प्रयोग करता था। तथा उसे अपनी निजी सम्पत्ति समझता था। स्वयं को राज्य का सरावर भागीदार मानता था।^१ वे गढ़ व राज्य, अपने बुजुर्गों का मानते थे।^२ इस प्रकार उनके अपने पट्टे के क्षेत्र व राज्य में निश्चित वशानुगत क्षेत्रीय दावे थे। पट्टा प्रथा के आगमन ने उनके इन सामन्त अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया। राज्य के वे 'चाकर' बन गए थे तथा अपने पट्टे के क्षेत्र में भी अधिकारों का उपयोग, निर्धारित सेवाओं तथा शर्तों को मानने के बाद ही कर पाये। 'आगामोदार चाकर' पट्टायत भी, विशेष परिस्थितियों में जमीनी के सिद्धान्त से मुक्त नहीं थे। सामान्य परिस्थितियों में शासक, ठिकाने में उनके अधिकारों को सम्मान देता था। पट्टायत अपने क्षेत्र के फौजदारी मामलों का मुख्य न्यायाधीश होता था पर वह मृत्यु दण्ड तथा गुनेहगारी की सजा नहीं दे सकता था।^३ दीवानी मामलों में महाराजा के नाम पर राज्य के दीवान का, उससे क्षेत्र पर हस्तक्षेप होता था।^४ पट्टायत गांव के आमामियों के भूमि अधिकारों में दखल नहीं दे सकता था।^५ वह साथ ही एक बार दी गयी अनुदान की भूमि को छीन नहीं सकता था।^६ वह 'जगात वसूली के अधिकार' रखता था पर राज्य उससे यह अधिकार छीन भी सकता था।^७ चाकर पट्टेदारों को तो ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। पट्टायत को 'वैवाहिक सम्बन्धों'

१ बीकानेर रैं घणीया री याद—पृष्ठ १०-१४, राठोडा री वशाकली तथा बीकिया, पृ० ४०-४३, बीकानेर रैं राठोडा री ब्यात सीहंजी सूँ, पृ० १०१-४

२ भूकरका के ठाकुर कुलसिंह ने यह मन्त्र महाराजा जोगवरसिंह को जोधपुर आक्रमण के समय कहे थे।—बीकानेर री ब्यात महाराजा सुजाणसिखजी सु महाराज गजमिधजी तार्द, पृ० ७, रमालदास ब्यात (अप्रकाशित) २, पृष्ठ २६६

३ कागदी की मही, वि० सं० १८६७/१८१० ई०, न० १७ पृष्ठ २४४

४ उपर्युक्त, पृष्ठ ६७, ८४

५ उपर्युक्त वि० सं० १८३७/१८०० ई० न० ११, पृष्ठ २०८

६ उपर्युक्त, वि० सं० १८३७/१८०० ई०, न० ११ पृष्ठ ८६, वि० सं० १८७४, १८१७ ई०, न० २३, पृ० १५६

७ पट्टा वही, वि० सं० १७३३/१६६६ ई०, न० ७ पृष्ठ ६-६

के लिए भी शासक की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी ।^१

‘ठिकानेदारों’ को अपने मिवकों के प्रचलन का कोई अधिकार नहीं था ।^२ आमामीदार चाकर पट्टेदार अपने क्षेत्र में सासण की भूमि तथा अपने छुट-भाईयो को गाव प्रदान कर सकते थे ।^३ कुछ ठाकुरों को ‘शरणा’ के अधिकार भी प्राप्त थे ।^४ पट्टेदार अपने पट्टे को रेहण पर रखने का अधिकार भी रखते थे ।^५ अपने द्वारा किये गये अपराधों के लिए वे किसी भी अदालत में उपस्थित नहीं होते थे । अपराधों के लिए उन्हें सामान्यतः चेतावनी दी जाती थी दण्ड नहीं दिया जाता था ।^६ इस प्रकार केवल उनकी नैतिकता को ही जमाने का प्रयत्न किया जाता था । भयंकर अपराधों के लिए अवश्य शासक उन्हें कठोर दण्ड में दण्डित करता था ।^७ सामन्तों को गोद लेने का अधिकार था, हालांकि इसके लिए उन्हें शासक की पूर्ण अनुमति लेनी पड़ती थी व अधिम पेशकमी की रकम देनी पड़ती थी ।^८ पट्टेदार को अपने क्षेत्र में भू राजस्व वसूल करने व उसकी दर-निर्धारण की पूरी स्वतंत्रता होती थी । इस बात का उसे ध्यान रखना होता था कि वह प्रणाली जनता पर अत्याचारिता का प्रभाव नहीं छोड़े ।^९ ऐसा होने पर फिर शासक हस्तक्षेप करता था ।^{१०} चाकरी पट्टों में, पट्टायत के अधिकार, इस दिशा में बहुत सीमित थे ।^{११} वह दीवान द्वारा भेजे गये नियमों का ही पालन

१ सोहनलाल-तवारिख राज श्री बीकानेर, पृष्ठ ३०३-६

२, उपर्युक्त

३ राठौड़ा की मयावली में बीडिया में कुटकर बाता, पृष्ठ ६०, वैद्यवर्ण, पृष्ठ ६४-१०१, गोविन्द अग्रवाल, बुरू मण्डल का कोषपूर्ण इतिहास, पृष्ठ १६८-२३२

४ मण्डलावत ठाकुरों की यह अधिकार प्राप्त था । सगतसिंह मंडलावन राठौड़ और साकडा, राजस्थान भारती, पृ० ६६, अंक ३४, १६७६ ई०, बीकानेर इस अधिकार के अस्तित्व के किसी भी अपराधी को अपने यहां शरण दे सकते थे

५ कागदा की बही, बि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १७ पृष्ठ ८४, सोहनलाल (पूर्व), पृष्ठ ३०५

६ कागदों की बही, बि० सं० १८६७/१८१० ई०, न० १६, पृष्ठ ३३

७ उन्हें केवल चेतावनी दी जाती थी तथा अबले जम के बुरे परिणामों से अवगत कराया जाता था । उपर्युक्त, बि० सं० १८५७, १८०० ई०, न० ११ पृष्ठ २२७

८ सोहनलाल (पूर्व), पृष्ठ ३०५

९ प्रत्येक पट्टेदार का यह निर्देश दिया जाता था कि वह करो का निर्धारण न्यायसंगत ढंग से करेगा । परवाना बही, बि० सं० १७४६/१६६२ ई०, पृष्ठ १४ १८

१० कागदों की बही बि० सं० १८५७/१८००, न० ११, पृष्ठ ६१, १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृष्ठ ४-५

११ चाकरी पट्टेदार के पास भू राजस्व निर्धारण व न्याय के अधिकार नहीं थे । वह गुनेहगारों को किसी पर नहीं लगा सकते थे तथा निर्धारित दरों व करा को ही वसूल करता था कागदों की बही, बि० सं० १८६७, १८१० ई०, न० १७, पृष्ठ २४४, बि० सं० १८७४/१८१७ ई०, न० २३, पृष्ठ १५६

करता था। पट्टायत अपने पट्टे के क्षेत्र का सैनिक बल पर शत्रु के क्षेत्र में विस्तृत कर सकता था, पर इससे पूर्व उसे महाराजा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी।^१

पट्टायत के मुख्य कर्तव्य उसने पट्टे में ही निभे होते थे। उसका प्रमुख कर्तव्य राज्य की सैनिक सेवा करना होता था, जिसके विवरण की सूचना पट्टे में कर दी जाती थी। इसके अलावा उसने महत्वपूर्ण कर्तव्य, अपने पट्टे में करो को वसूल करना तथा आबादी को बनाये रखना होता था। निम्नी विशेष प्रशासनिक दायित्व को पूरा करने के लिए जब पट्टायत की नियुक्ति की जाती थी उससे यह आशा की जाती थी कि वह उन्हें निष्ठा से निभायगा।^२ राज्य की समस्त सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सामन्तो पर था।^३ महाराजा की अनुपस्थिति में राजधानी गढ़ की दयभाल व सुरक्षा का उत्तरदायित्व का कार्य भी इन्हीं में किसी को सौंपा जाता था।^४ प्रत्येक ठाकुर को अपने कार्यों की सूचना शासक को दनी होती थी।^५ दरबार के सभी महोत्सवों पर उन्हें सम्मिलित होना पड़ता था। दशहरा तथा शासक के जन्म दिवस के उत्सव पर इनमें से कोई भी अनुपस्थित नहीं रह सकता था।^६

सामन्तो की राज्य प्रशासन के विभिन्न प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपे गये थे। मथिमण्डल में भुसाहिब के पद पर अगोत बीका ठाकुर पृथ्वीराज व कुशल-मिह की नियुक्ति हुई थी। ठाकुर पृथ्वीराज ने महाराजा स्वरूपसिंह की बाल्या-वस्था व दक्षिण में नियुक्ति के कारण राज्य-प्रशासन को संभाला था।^७ ठाकुर कुशलसिंह ने दीवान मोहना बक्षानवरसिंह के साथ मिलकर, महाराजा जोरा-वरसिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात् शामक के अभाव में, राज्य-प्रशासन का संचालन किया था।^८ मुख्य मेनापति के रूप में भी सामन्तो की नियुक्ति होती रहती थी।^९ जोधपुर नरेश अभयसिंह बीकानेर आक्रमण के समय ठाकुर कुशल-

१ यह स्थिति भी पुराने जामाईदार पट्टायतों की थी। रतनकीन बीका राठीशा ने सर्व्व, अपने पट्टे के उत्तर की ओर विस्तार किया था। कायनालों की दक्षत हिमालय जिले में रहते थे। परवाना बही वि० न० १७८६/१९८२ ई०, न० ७-१०

२ वही

३ सीमा क्षत्रा पर स्थापित इनके ठिकानों से यह स्थिति स्पष्ट होती है। देखिये—गृहदारी क्षेत्र का मानचित्र ६

४ दयालदास दयाल (अग्र०) २, पृ० २३२, ३१४ ३२२

५ सोहनलाल (पूर्व) पृ० ३०६-१०

६ उपयुक्त, ३०४-१०

७ बीकानेर की रणाल, महाराजा सुजायसिंह सुजननिधजी तारी, पृ० ३-६

८ उपर्युक्त पृ० ३८-३९

९ उपर्युक्त

मिहू धीकानेर सना का सेनाध्यक्ष था ।^१ इसमें अलावा मुगल जागीरी परगना में फौजदार के पद पर,^२ राज्य के गाणों व मुख्य किलों पर सिनेदार फौजदार व हवलदार के पद पर भी ये लोग नियुक्त किये जाते थे ।^३

प्रशासनिक व्यवस्था

अपने क्षेत्र में, प्रमुख होने के कारण ठाकुर अनगिना प्रशासनिक व सैनिक शक्तियों का प्रयोग करता था । अपने पट्टे के क्षेत्र में प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये वह कई अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता था ।^४ उससे यह आशा की जाती थी कि वह अपने क्षेत्र में आय की वृद्धि करेगा तथा आबादी को बढ़ायेगा । पट्टेदार ने दो मुख्य प्रशासनिक दायित्व होते थे—करो को वसूल करना तथा शानि व भुव्यवस्था बनाए रखना । इन दोनों दायित्वों की पूर्ति के लिये जो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे 'प्रधान' कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति शासक की पूर्ण स्वीकृति पर निर्भर करती थी । यद्यपि प्रत्येक ठिठाणे में प्रधान का पद नहीं होता था, फिर भी कतिपय प्रमुख ठिठाणा में इसकी नियुक्ति पाई जाती है ।^५ कई प्रमुख ठिठाणों में तो महाराजा स्वयं प्रधान की नियुक्ति करता था । प्रधान से यह आशा की जाती थी कि वह अपने ठाकुर के प्रति स्वामिभक्त रहगा ।^६ प्रधान ही शासक व पट्टायत के बीच तथा पट्टायत व अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच की कड़ी होता था । शासक के मतियों व अधिकारियों के साथ मिलकर वह पेशकशी व अन्य कर निर्धारित करता था । ठाकुर की तरफ से महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक व राजनैतिक निर्णय लेता था । अपने पट्टायत के लिए अन्य पट्टायतों के पास बातचीत करने के लिए जाता था । कन्द्रीय प्रशासन द्वारा पट्टे के क्षेत्र की आय का विवरण मागन पर प्रस्तुत करता था । पट्टायत के लिए उसके छुट-भाईयो से पेशकशी की रकम वसूल करता तथा अन्य करो

१ उपयुक्त, पृ० ७

२, परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, पृ० ८१०

३ परगना रे जमा करव री बही वि० सं० १०२०/१६६२ ई० न० ३२ औरगाबाद करणपुर रे जमा करव री बही, वि० सं० १०६८/१६११ ई० न० १३१ साबा बही अनूपगढ़, वि० सं० १७२५/१३६८ ई०, न० १, साबा बही रोणी वि० सं० १८१४/१७२७ ई० न० १ रामपुरिया रिकाइस, बीकानेर

४ भिया सप्रह—भाटिया रे गावा री विगत वि० सं० १८४६/१७८२ ई०

५ परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, पृ० २१२४, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० ११११३

६, महाराज के प्रधान की नियुक्ति स्वयम् शासक करता था—परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, पृ० २४-२६

को निर्धारित करता था।^१ ठिकानों ■ कभी-कभी प्रधान के साथ या कभी अकेले मंत्री पद की भी नियुक्ति की जाती थी, जिसका कार्य प्रधान को सहयोग देना अथवा ठिकाने में प्रधान पद के न होने पर उससे दायित्वों को निभाना होता था।^२ ये प्रधान व मंत्री ठाकुर के साथ-साथ महाराजा से भी सम्मानित होते थे।^३

ठिकाने में विभिन्न करों की वसूली के लिए कामदार, साहणी, छत्रान्धी, दरोगा तथा उनके साथीनदारों की नियुक्ति की जाती थी। कामदार का कार्य, दफ्तर के हवलदार तथा गावों के हवलदारों के समान था। वह भूमि का मापन, कर निर्धारण व कर वसूली का कार्य करता था। साहणी, दरोगा उम इस कार्य में सहयोग देते थे। गाव का चौधरी व पट्टवारी स्थानीय अधिकारी होते थे, जो कामदार को छालसा गाव के हवलदार की भांति सहयोग प्रदान करते थे। कामदार और चौधरी दोनों मिलकर चोरो के हवलदार को कर वसूली में सहायता देते थे।^४

पट्टा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था स्थापित करने के लिए फौजदार की नियुक्ति की जाती थी, जिसका प्रमुख सहयोगी दरोगा होता था। ये फौजदार अपनी जमीन की सेना नियुक्त करता था।^५ इसके अलावा गाव के डेढ़, थोरी^६ आदि गाव के नौकर होते थे, जो पट्टापत की छोटी-मोटी आवश्यकताओं को निभाने का तथा सदेशवाहक का कार्य करते थे।^७ चोरो में स्थित, घाणों, के फौजदार का इन पर नियन्त्रण रहता था तथा विपत्तिकास में चोरो का फौजदार, पट्टे के क्षेत्र में, आकर व्यवस्था स्थापित करता था।^८

१ दणपत बिलास, पृ० ४०, ५१, ५४, ६८, परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६६३ ई०, पृ० १० २३, कागदों की बही, वि० सं० १८३८/१७८१ ई०, न० ५, पृ० ४६, मय्या सयह नयसलपत्र माघ बहि १०, वि० सं० १८६१/२५ फरवरी, १८०५ ई०

२ बीकानेर की इयाज, महाराजा नुसामनिष सू गजनिषजी साई, पृ० ३१, ४७ ८४

३ परवाना बही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, पृ० २१, २८, ५३

४ कागदा की बही, वि० सं० १८३७/१८०० ई०, न० ११, पृ० १८७, २४८, वि० सं० १८६३/१८०४ ई०, न० १६, पृ० ११४, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृ० २६१

५ साबा बही पीणो वि० सं० १८१४/१७२७ ई०, न० १, साबा बही धनूपगड़ वि० सं० १८१८/१७६१ ई०, न० ३

६ समाज के निम्नवर्ग (कमीनाय) के लोग

७ बही

८ कागदा की बही, वि० सं० १८३७/१८०० ई०, न० ११, पृ० ६१, १०७, १२४

चतुर्थ अध्याय

केन्द्रीय प्रशासन व मुत्सद्दी-वर्ग

मध्यकाल में, राठौड़ जाति को ही इन बात का श्रेय है कि उन्होंने इस रीतीसे क्षेत्र की, अपनी सम्बोधित करने वाली प्रशासनिक-एकता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक दृढ़ केन्द्रीय सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि आरम्भिक वर्षों में, अपनी लचीली सघीय बनावट के कारण केन्द्रीय सगठन प्रभावशाली नहीं हो पाया, लेकिन जर्न जर्न राज्य में शासन की स्थिति दृढ़ होने के साथ-साथ यह सुसंगठित हुआ और प्रभावी ढंग से कार्य करने लग गया।

राज्य के प्रथम पांच शासकों के समय प्रशासन का स्वरूप व प्रभाव कुल परम्परा के अनुसार कुलपति व उसके सम्बन्धियों के पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित थी। राजा व मामन्तो के बीच एक विरल राजनैतिक जोड़ ही केन्द्रीय सत्ता की बमजोरी का उद्गम था। केन्द्रीय सत्ता केवल कुलपति के क्षेत्र में ही प्रभावशाली थी। अन्य क्षेत्र की इवाइया विभिन्न राठौड़ कुल मुखियों के पास थी, जहाँ वे अपना प्रशासन स्वतन्त्रतापूर्वक तथा सुविधानुसार चलाते थे। इस प्रकार राज्य एक ढीली सघीय व्यवस्था पर टिका हुआ था।

छठे शासन, राजा रायसिंह के समय, सर्वप्रथम इस क्षेत्र की केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को सुदृढ़ करने के प्रयत्न प्रारम्भ हुए थे। वह और उसके उत्तराधिकारी बीका राजवंश के नेतृत्व में प्रशासनिक एकता व दृढ़ता लाने के लिए कटिबद्ध थे। मुगल सम्प्रभुता की मान्यता ने उन्हें विदेशी आक्रमण से सुरक्षा व आन्तरिक विद्रोहों के विरुद्ध सहायता व समर्थन प्रदान किया, जिससे उन्हें यह अवसर मिला कि वे अपनी शक्तियों को राज्य की राजनीतिक समस्याओं के विकास में जुटा सकें। राज सत्ता के विद्रोहियों के दमन से राज्य में शान्त वातावरण नैयार हुआ। मुगल साम्राज्य में, विभिन्न उत्तरदायी प्रशासनिक पदा पर बीकानेर के शासकों की नियुक्ति ने, उनका मुगल प्रशासन से सीधा सम्पर्क स्थापित कर दिया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने राज्य में भी प्रभावी मुगल नियमों को लागू किया।^१ मनसबदार के रूप में,

मुगल जागीरो से प्राप्त आय तथा शाही अभियानों में भाग लेने से उन्हें जो लूट की सामग्री प्राप्त हुई,^१ इससे उत्पन्न समृद्धि ने विदेशियों को आकर्षित किया कि वे यहाँ आकर बसें, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को कुशल एवं योध्य प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त हुए।^२ राज्य की समृद्धि ने धर्म, साहित्य व विभिन्न कलाओं को विस्तृत होने का अवसर प्रदान किया, जिससे राज्य के प्रशासन का स्वरूप बदलने लगा।^३ अन्ततः राजा के पद की गरिमा व उसकी शक्ति, इस काल में दृढ़ता से स्थापित हो गयी। अतः राज्य एकात्मकीय सरकार की विशेषताओं की ओर तेजी से, प्रभावशाली ढंग से बढ़ने लगा था।

मुत्सद्दी

राज्य में एकात्मकीय सरकार स्थापित होने का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि स्थानीय चेष्टाओं को कुचलती हुई दृढ़ केन्द्रीय सत्ता का विकास हुआ तथा प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक नये प्रभावशाली वशानुगत अधिकारी तन्त्र का जन्म हुआ। नये वर्ग के सदस्य 'मुत्सद्दी' नाम से विख्यात हुए। इस वर्ग से ही राज्य के मंत्री, अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गये।^४ हमने पूर्व 'मुत्सद्दी' के अवश्य पर वे राज्य के कुलीय ढाँचे के फलस्वरूप कमजोर व बटे हुए थे।^५ १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विभिन्न संस्थाओं के विकास तथा केन्द्रीय सेवाओं का रूप निर्धारित होने से इस वर्ग को परिस्थितियोंवश मिलने वाली प्रभावशाली एकरूपता का आभास हुआ। राजा रय्यासिंह ने केन्द्र व स्थानीय स्तर पर अनेक नये विभाग खोले तथा मंत्री

१. डैस्टोरी—ज० ए० सो० व० एन० एस० XVI, एपिडिम, मूरजपोल प्रशस्ति, जूनागढ़, बीकानेर

२. दयानदास ध्यात (प्र०) भाग २, पृ० ११६, १२२, १२९-२७, राजा रय्यासिंह ने जागीर से घाये कोठारी तिलोकासिंह की कारखानों का अध्यक्ष नियुक्त किया था

३. कर्णावतस, पृ० १७-१६

४. मुत्सद्दी का शाब्दिक अर्थ प्रवचक, अधिकारी, गुमास्ता, लिपिक व हिसाब-किताब रखने वाले से है, लेकिन बीकानेर राज्य में इस शब्द का प्रयोग प्रशासनिक वर्ग के लिये प्रयुक्त किया गया है। उर्दू-हिन्दी शब्दकोष, पृ० ३१०, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, १७७७

५. राज्य प्रशासन में प्रशासकीय वर्ग के लिये मुत्सद्दी शब्द का प्रयोग १७वीं शताब्दी के अन्त में अधिक प्रचलित हुआ है, अन्यथा कामदार शब्द का ही अधिक प्रचलन था। ध्यातों में सर्वत्र इस सर्वत्र में मुत्सद्दी शब्द का ही प्रयोग आया है।—बीकानेर की ध्यात महाराजा सुजानसिंहजी रूँ गजसिंहजी तर्क, पृ० ३८; मोहता ध्यात, पृ० ५७

नियुक्ति के लिये इन स्रोतों के साथ देखिये कामदारी पट्टे, परवाना वही न० १ तथा हुवासा कागद, कागदों की वही न० ३, ४, १०, ११

६. दयानदास ध्यात (प्र०) २, पृ० ३४-३६

व अधिकारी पदों के दायित्वों को बाटकर नई नियुक्तियाँ कीं।^१ ठकुराई क्षेत्र केन्द्रीय सत्ता की देख-रेख में आया तथा वहाँ की आप के स्रोत दीवान के विभाग के निरीक्षण में आये। ठकुराई क्षेत्र में विभिन्न चरों को बमूल करने तथा राजा के हितों की देख रेख के लिए केन्द्र की तरफ से वहाँ अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गये। राज्य की भूमि खालसा व पट्टा क्षेत्रों में न बाँटा कर नई प्रशासनिक इकाइयों—‘बीरा’ में बाँट दी गई, जिससे फलस्वरूप खालसा व पट्टा दोनों के साथ एक साथ केन्द्र द्वारा गठित सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत आ गये।^२ इन सब परिवर्तनों ने जहाँ ‘मुत्सद्दी’ वर्ग के सदस्यों की सङ्ख्या बढ़ाई वहाँ साथ-ही साथ उन्हें शक्ति व वर्ग एवम्ता भी प्रदान की। शासकों ने भी प्रशासन की कार्यकारिणी के सदस्यों के बढ़ते हुए महत्व को मान्यता दी तथा साथ ही उनका राजनीतिक लाभ भी उठाना चाहा। उन्होंने सामन्तों की शक्ति को नियन्त्रित करने के लिए सन्तुलन की नीति पर चलते हुए उनके विरुद्ध ‘मुत्सद्दी’ वर्ग को प्रोत्साहन दिया,^३ फलस्वरूप राज्य में राजा व सामन्तों के पश्चात् एक तीसरी शक्ति के रूप में ‘मुत्सद्दी’ उभरे। इस प्रकार मध्ययुगीन निरंकुश राजतन्त्र से अधिकारी तन्त्र की उत्पत्ति सम्भव हुई।

समकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों ने भी मुत्सद्दियों के प्रभाव की वृद्धि में सहायता दी। बीकानेर शासकों की दूरस्थ मुगल श्रेष्ठ में नियुक्ति के समय उनकी अनुपस्थिति में मुत्सद्दियों पर ही ‘वतन जागीर’ के प्रशासन का उत्तरदायित्व आ पड़ा।^४ मुगल दरबार में शासकों की अनुपस्थिति में ‘वकील’ के रूप में उनके हितों की देखभाल भी यही करने लगे।^५ इनकी सुपुर्द मैनिंग दायित्वों ने भी इनकी शक्ति व सभ्यता बढ़ाई।^६ पर सबसे बढ़कर जैसा कि लिखा जा चुका है, राजा व सामन्तों के बीच उनके कुलीय अधिकारों को लेकर व्याप्त असन्तोष व तनाव ने राजा को विवश किया कि वह इन मन

१ वही, पृ० ११६-२२

२ बीरा क्षेत्र के क्षेत्रों की वही वि० सं० १७४७/१६६० ई०, न० ६१ बीरा नोहर क्षेत्रों की वही वि० सं० १७५०/१६६१ ई०, न० २८—बीकानेर वहीमात, रा० रा० अ० बी०

३ इस दिशा में राजा रामसिंह व महाराजा अनूपसिंह व गजसिंह की नीति विशेष उल्लेखनीय है—दयालदास ख्याल (प्र०), पृ० ११७-२२, २११-१३, जी० एस० एल० देवडा, ध्युरोक्तेषी दून राजस्थान, पृ० XIV, ८

४ महाराजा अनूपसिंहजी से आनंदराम नाजर से नाम परवानों वि० सं० १७४६/१६६१ ई०, न० १६७/१६ अ० सं० पु० बी०

५ नामदारों व वकीलों से रोजगार से वही, वि० सं० १७५३/१६६६ ई०, न० २०६ बीकानेर वहीमात, रा० रा० अ० बी०

६ दयालदास ख्याल (प्र०) २ पृ० २११-१३

अधिक विश्वास करे ।^१

मूलभूत रूप से मुत्सद्दी वतनभोगी सबब से तथा साधारणतः इस काल के समाज के मध्यम वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे । यद्यपि इन्हें अपनी सेवाओं के बदले शासकों द्वारा 'पट्टे' भी प्रदान किये गये थे^२ पर इन जागीरों के बल पर इन्हें मध्ययुग के प्रसिद्ध भू अभिजाततन्त्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । वे पट्टे न तो वशानुगत होते थे और न ही मुत्सद्दियों का राजपूत सामन्तो की तरह पट्टे के श्रेणी पर कोई विशेष भू-स्वत्व अधिकारों का दावा होता था ।^३ इन्हें 'आमा मोदार चाकर पट्टायतो' की भाँति अपने पट्टे के आन्तरिक प्रशासन में भी किसी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती थी ।^४ ये पट्टे उनके धेतन के भाग होते थे तथा सेवाकाल से जुड़े रहते थे ।^५

राज्य सेवाओं में मुगल मनसब की भाँति किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं था ।^६ यह तो सेवादायित्वों के बीच अन्तर था जो एक पद को दूसरे पद से अलग करता था ।^७ इसमें सम्यक् नहीं कि राज्य सेवा में मंत्री, उच्च व कनिष्ठ पदाधिकारी तथा उनकी सहायता के लिये सेवकों की एक पक्ति खड़ी रहती थी, 'लेकिन इनके पास किसी प्रकार की दरबारी श्रेणी नहीं होती थी, जैसा कि मुगलों में प्रचलन था । वैसे भी बीकानेर दरबार अन्य राजपूत राजाओं के दरबार की भाँति सेवा श्रेणियों में नहीं बंटा हुआ था बल्कि इसका गठन तो राजा व सामन्तों के बीच रक्त के सम्बन्ध, विभिन्न खाँसों की पारस्परिक सामाजिक स्थिति तथा राजा के साथ कुलीय सम्बन्धों पर हुआ था ।^८ मुत्सद्दी भी दरबार में बैठते थे तथा कुछ को 'ताजीम' जैसा विशेषाधिकार भी प्राप्त थे,

१ मुहता भीमसिंह का वर्णन, पृ० ११, मोहता रिवाज, भाइको फ़िल्म रोल न० ८, रा० रा० अ० बी०

२ देखिये कामदारी पट्टे—परवाना वही न० १

३ वही, पट्टे का स्वरूप जानने के लिये आदेशपत्र देखिये

४ वही

५ वही

६ मोरनेण्ड—इण्डिया एट दी डेय ऑफ़ अकबर, पृ० ६६ देखी १६७४

७ देखिये—हवलदारों के पद के अलग-अलग दायित्व किस प्रकार थे । एक विभाग में हवालदार विभाग का अध्यक्ष है या उसी स्तर के दूसरे विभाग में वह सहायक अधिकारी है—ट्टवाला सीमा कागद, कागदा की वही न० ३, ५, १०, ११

८ पट्टा वही वि० सं० १८१२ मिनो भ दुवा यदि १२/३ मितम्बर १७५५ ई०, न० ७, पृ० १४२—कामदारी पट्टे परवाना वही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, न० १, व्यूरो-शेरी इन राजस्थान, पृ० २० २४

९ वही दरबार की व्यवस्था की रें समी री, भीम्या रिवाज रा० रा० अ० बी०

पर उनकी स्थिति राजा के नामदार की भांति ही थी।^१ वे दरबार के अग्रिम अंग के रूप में स्वीकार नहीं किये गये थे।^२ मध्ययुगीन सामन्ती ढाँचे में वे जातिगत 'पट्टायतों' के विशेषाधिकारों के साथ समता नहीं कर सकते थे।

इन मुल्कदियो की शक्ति, राज्य के लिए स्याई सतरे का कारण बनी नहीं बनी, क्योंकि इनकी शक्तियों पर कई नियन्त्रण थे। इनकी नियुक्ति पद्मोन्नति व सेवा-भुक्ति सभी शासन की इच्छाओं पर निर्भर थी।^३ ये केवल राजा के प्रति उत्तरदायी थे। जन-साधारण में इनका कोई आधार नहीं था। परन्तु अपने किसी घुरे वार्य में वे जनमत की निम्ना के पात्र अवश्य बन सकते थे।^४ राजा इनको स्वामी पट्टे प्रदान नहीं करता था, जिसके आधार पर वे अपनी शक्ति का संचय करके शासन का खुनीती देने की स्थिति में आ सकते। इनके पास कोई निश्चित निर्धारित सेना भी नहीं होती थी।^५ इनके पैतन का अग्रि-भाग भाग नवद दिया जाता था।^६ अतः ये बिना सामन्तों की सैनिक सहायता के कुछ नहीं कर सकते थे और सम्भवतः सामन्त बन्नी यह सहन नहीं कर सकते थे कि कोई मुल्कदी, उनसे कुल-शक्ति की गरी की खुनीती दे। इस प्रकार सैनिक व नागरिक दायित्वों के विभाजन ने मन्त्रियों व अधिकारियों को, राजा की स्थिति को खुनीती देने की स्थिति में बन्नी नहीं पहुँचने दिया। मुल्कदियों की आपसी कूट भी उनके हाथ में असंमित शक्तियों केन्द्रित करने में बाधक थी।

कार्यकारिणी की रचना एवं विनास

राज बीका जब जोधपुर की छोड़कर जामन प्रदेश की ओर खाना हुए तो उनके साथ सैनिक अधिकारियों के अलावा कुछ नागरिक अधिकारी—लाखणसी, चौधमल कोठारी, यत्तराज बच्छावत व पुरोहित विजयमसी भी

१. भैय्या पत्र, भादुना बदि २, १८०२/३ अगस्त, १८५५ ई०, भैय्या रिवास्, रा० रा० अ० बी०

२. जी० एस० एस० देवदा, गुजराती इन राजस्थान, पृ० XVII

३. परवाना बही वि० सं० १८००/१७५३ ई०, पृ० ६१-६२, १०२, १०४, १०६, १२०, १३०

४. मोहना द्यात, पृ० ३३, ६५-६६, मोहना भीमसिंह वर्णन, पृ० १९, दयालदास द्यात (अप्र०) २, पृ० ३२२-२६

५. उनके पद समाप्ति के साथ जागीर समाप्त हो जाती थी—परवाना बही वि० सं० १८००/१७५३ ई०, पृ० ६१-६२, १२०

६. भैय्या पत्र ज्येष्ठ सुदि ४ १८६५/२६ मई, १८०८ ई०, फात्तुन बदि ७ १८७३/४ फरवरी, १८१७ ई०, दयालदास द्यात (अप्र०) २, पृ० २११-१४

७. नामदारी पट्टे—परवाना बही, न० १

आये।^१ इन्हीं से राज्य का वशानुगत नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का वर्ग बना था। बाद में, विशेषकर राजा रायसिंह, महाराजा अनूपसिंह व महाराजा गजसिंह के समय विदेशियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया।^२ लेकिन इन नये आगन्तुकों के प्रति, पुराने मुत्सद्दियों की सदैव एक सीखी प्रतिक्रिया बनी रही, फलस्वरूप मुत्सद्दी वर्ग में दो गुट बन गये—पुराने व विदेशी या परदेशी।^३ शासकों ने जब हज़ूरियों की नियुक्ति भी विभिन्न प्रशासनिक पदों पर की तो मुत्सद्दियों व हज़ूरियों के बीच भी ईर्ष्या व प्रतिस्पर्धा व्याप्त हो गई।^४

मन्त्री-परिपद्

शासक मुत्सद्दियों व हज़ूरियों में से ही मन्त्री व उच्च अधिकारी नियुक्त करता था, जो राज्य में विशाल शक्तियों का उपभोग करते थे।

सदैव गैर-राजपूत जातियों, विशेषकर वैश्य तथा क्षत्रिय जाति में से ही मन्त्रियों व अधिकारियों का चयन होता था। वैश्यों में—मोहता, नाहटा, बच्छावत, मूँघडा, कोबर, कोठारी, सुराणा, बरदिया आदि मुख्य थे।^५ इनमें कुछ जैन धर्म के अनुयायी थे तो कुछ हिन्दू धर्म के उपासक थे।^६ मन्त्रियों व अधिकारियों के कार्य-क्षेत्र में प्रशासन का पूर्ण क्षेत्र आ जाता था। उनका मुख्य कार्य था—नई नीति का निर्धारण करना, शासक की स्वीकृति के पश्चात् उसे सफलतापूर्वक न्यायित करना, इसमें उठने वाली कठिनाइयों को दूर करना, राज्य के आध-व्यय के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण और उनका निरीक्षण करना, परराष्ट्र नीति का संचालन व सामन्तों के साथ सम्बन्धों पर विचार करना था।^७

प्रत्येक मन्त्री व अधिकारी अपने विभाग की देख-रेख स्वयं करता था और वही उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता था। शासक किसी मन्त्री से

१ कर्मचन्द्र, पृ० २५, बीकानेर रै राठोडा व बीजा लोकां री पीछीया, पृ० २७, दयाल-दास ध्यात (प्र०) पृ० २

२ दयालदास ध्यात (प्र०), पृ० १२२, १२८, २१५, जो एत एत देवडा—ध्युरीकेशी इन राजस्थान, पृ० XIX, २, बीकानेर, १९८०

३ वही

४ बीकानेर री ध्यात महाराजा मुजानमिथ सू महाराजा गजसिंघजी तार्द, पृ० ५-७

५ बीकानेर नै कामदारां वनैरा री पीछीया, न० २२६/२, अ० स० पु० बी०, परवाना बही, वि० स० १८००/१७४३ ई०, पृ० ७७-१२६

६ वही

७ बैरियम परवानाज ऑफ दी बीकानेर हलसं एंड्रेसेड टू दी मोहता फेमिली ऑफ बीकानेर, माइनी फिल्म रील न० ८, मोहता रिकार्ड्स, रा० रा० अ० बी०

स्वतन्त्र रूप से व मन्त्रियों एवं अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से भी मन्त्रणा कर सकता था। पर मन्त्री व अधिकारी का विभागीय उत्तरदायित्व व्यक्तिगत था, न कि सामूहिक।^१

राज्य में मन्त्रियों की संख्या तीन या चार तक ही सीमित थी, उनमें 'दीवान', 'मुसाहिब', 'बख्शी', 'शिवदार' मुख्य थे।^२ रायसिंह के समय में दीवान पद को निश्चित करके, उसके बाल, वेतन व वर्तव्यों की भी निर्धारित किया गया था।^३ अपने शासन के अन्तिम वर्षों में, राजा रायसिंह ने दीवान पद की असौमिल शक्तियों को नियन्त्रित करने के लिए, उसके दो सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी, जिनमें एक 'कोठारी' था, जो विभिन्न कारखानों का अध्यक्ष था। दूसरा, चालसा भूमि के प्रबन्धक (देश प्रबन्ध) का उत्तरदायित्व सम्भालता था।^४ सैनिक प्रशासन का दायित्व 'मुसाहिब' को सौंपा गया था।^५ 'पंजाग्वी व पुरोहित, अन्य दो मुख्य अधिकारी थे।^६ राजा दलपतसिंह ने अपने काल में दीवान के ऊपर मुसाहिब को 'मुख्य सलाहकार' के रूप में विभूषित किया था।^७ महाराजा अनूपसिंह ने कई अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनमें 'शिवदारी-पद' मुख्य था, जिसके दायित्व बदलते रहते थे।^८ महाराजा गजसिंह ने मैन्य विभाग का दायित्व एक नये पदाधिकारी 'तनवगसी' (तनवखशी) को सौंपा था।^९ इसके अलावा 'दपतर का हुक्मदार' शहर किल का किलेदार 'फौजदार', मढी या हुक्मदार व 'खुबामदार' आदि अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी थे।^{१०}

दीवान

राज्य में हर मन्त्री व अधिकारी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को निभाते थे, लेकिन राज्य का प्रधान 'दीवान या मन्त्री ही होता था, जो मुख्य रूप से देश के कुशल प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। यह पद राज्य में कई नामों

१ वही

२ राज्य में जोधपुर राज्य की भांति प्रधान का पद नहीं था—जो भी शर्मा एडमिन स्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दी राजपूत पृ० १५-१६ दिल्ली १९७६

३ कमबख्त पृ० ६१, ७२ दयालदास ख्यात (प्र०) २, पृ० ६२ १९७

४ दयालदास ख्यात (प्रकाशित) भाग २, पृ० १२२, १२८

५ वही पृ० १४२

६ वही पृ० १४२ १२८ ४२

७ वही पृ० १४२

८ वही पृ० २१४

९ परवाना वही वि० सं० १८००/१७४३ ई० पृ० १४४

१० वही पृ० १४२ ४७

से जाना जाता था। राज्य के प्रथम पाँच शासकों के समय यह पद 'मन्त्री' 'मुख्य-अमात्य' व 'मन्त्रीश्वर' के नाम से विख्यात था^१, लेकिन राजा रायसिंह के समय यह पद 'दीवान' के नाम से सम्बोधित होने लगा, जो मुगल प्रशासन के प्रभाव का द्योतक था।^२ दीवानेर राज्य की ख्याती में कई जगह 'मुख्यत्यार' शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जो डम बात का सूचक था कि राज्य का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता यही था।^३ कभी-कभी यह पद राजा के कामदार या प्रधान के नाम से भी जाना गया।^४

राज्य की स्थापना के बाद, प्रारम्भिक वर्षों में इस पद का कोई विशेष गौरव न था। ज्यों-ज्यों शासक की स्थिति राज्य में दृढ़ होती चली गई, ज्यों-ज्यों शासक के कामदार की स्थिति भी प्रभावशाली बनती चली गई। राज्य का प्रथम शक्तिशाली दीवान कर्मचन्द्र बच्छावत था, जिसने राजा रायसिंह के समय में असीमित शक्तियों का उपभोग किया। वह न केवल प्रशासन के मामलों में, बल्कि राज्य की हर गतिविधि में सक्रिय था। युद्ध व शान्ति दोनों काल में वह नीति-निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाया करता था।^५ कर्मचन्द्र बहुत महत्वाकांक्षी दीवान था। कर्मचन्द्र ने राजा रायसिंह को गद्दी से हटाकर उसके पुत्र, दलपत को गद्दी पर बिठाने की योजना बनाई थी; लेकिन वह असफल रहा।^६ फिर कर्मचन्द्र के राज्य से भाग जाने के पश्चात् दीवान पद के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये। दीवान पद पर से, बच्छावती का वशानुगत अधिकार समाप्त हो गया व मुहता बंद ठाकुरसी, जो बीवाजी के साथ आये बंद लाखणसी का वंशज था, को दीवान पद पर नियुक्त किया गया।^७

शक्ति रायसिंह ने दीवान पद की असीमित शक्तियों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य में, उसके कार्यों का विभाजन कर दिया। दीवान के साथ दो और अधिकारी नियुक्त कर दिये गये, जो खानसा भूमि व विभिन्न कारखानों का

१ कर्मचन्द्र, पृ० २५, ३५, ४४

२ दलपत बिरास, पृ० २५, २८, इब्न हमन—दी गेट्रल स्ट्रक्चर ऑफ दी मुगल एम्पायर-पृ० १४८, १६७०

३ दयालदास ख्यात (३०) भाग २, पृ० १२२, मोहता ख्यात पृ० ३३

४ परवाना वही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० ६० ६२

५ दलपत बिरास, पृ० २७, ३१-३२ ६६, कर्मचन्द्र, पृ० ७०-७२, उमरावसिंह—राइज एण्ड फाल ऑफ दी बच्छावत हिस्टोरिकल स्टडीज, १६१४

६ मोहता ख्यात, पृ० ३३, दयालदास ख्यात (३०) २, पृ० १२८, देवदरं पृ० १४

७ दयालदास ख्यात (प्रकाशित) भाग २, पृ० १२२, मोहता ख्यात वशारिख राजपूरी बीवानेर, पृ० १३५

प्रबन्ध अलग से करते थे।^१ दीवान पद का महत्त्व, उनके उत्तराधिकारी दलपत-सिंह के शासन काल में और भी कम हो गया था, क्योंकि राजा ने पुरोहित भानमहेश, जिसको 'मुसाहिब' बना रखा था, को अपना मुख्य मलाहवार नियुक्त कर लिया।^२ राजा सूरसिंह के काल में, पुनः दीवान का पद प्रभावशाली बनने लगा। उसके समय में मोहता (वैश्य) को पहली बार दीवानी प्राप्त हुई थी।^३ अब दीवान एक जाति या श्रेष्ठ विशेष का नेता न होकर एक दल (गुट) विशेष का नेता हो गया, जिसमें केवल उसी की जाति या वंश के लोग ही नहीं बल्कि अन्य जाति के व्यक्ति भी समान स्वार्थ के आधार पर सम्मिलित होते थे। दीवान अपनी नियुक्ति के पश्चात्, अपने सहयोगियों को भी राज्य के अन्य उच्च पदों पर नियुक्त कराता था।^४

महाराजा अनूपसिंह के समय एक और परिवर्तन आया, जबकि प्रथम बार हजूरियों में से दीवान पद के लिए नियुक्ति हुई। नाजर आनन्दराम को अनूपसिंहजी ने नियुक्ति का परवाना दक्षिण से भेजा था।^५ अनूपसिंहजी के समय हजूरियों का प्रभाव बहुत बढ गया था। खवास उदेराम, उनका दूसरा विश्वसनीय व्यक्ति था।^६ हजूरियों के बढ़ते प्रभाव से पुराने मुत्सद्दी ईर्ष्यालु होने लगे।^७ महाराजा अनूपसिंह के समय ही मूधड़े (वैश्य) प्रथम बार, राज्य के दीवान नियुक्त हुए।^८ महाराजा स्वरूपसिंह के काल में वे राजमाता व नाजर ललित के प्रभाव के कारण प्रभावशाली नहीं थे।^९ इस प्रकार दीवान का पद कई सतहों से गुजर रहा था।

१ ब्यालदास ब्याल (प्र०) भाग २ पृ० ११६-२२ मोहनलाल (पूर्व) पृ० १३५ मुगल प्रशासन में दीवान के विभाग में बायों का वितरण इस प्रकार था—सरकार—मुगल प्रशासन पृ० ३५ ४६

२ वही पृ० १४२ ४३

३ मोहता भीमसिंह द्वारा जोधपुर महाराजा अभयसिंह के बीकानेर घरे का वणन पृ० ४४ मोहता ब्याल, पृ० ३३

४ दलालदास ब्याल (प्र०) २ पृ० १५६ मोहता कल्याण भल दीवान के साथ अन्य अधिकारी नियुक्त हुए थे—कोचर उरजो जी तोषणीवाल कोठारी, बोयरा शाह दूगरसी दफतरी भीमवाल कोठारी कूबर, चोपड़ा भीमराज मोहता लक्ष्मीदास आदि

५ महाराजा अनूपसिंह जी से भानन्दराम नाजर रं नाम परवानों (पूर्व) महाराजा अनूप सिंह उस समय श्रीरंगदेव के दक्षिणी युद्धों में व्यस्त थे तथा उनकी नियुक्ति श्रीरंगदेव जिले में बाणूणी गढ़ से हुई थी

६ देशदपण, पृ० १४६

७ वही

८ कामदारा व ककीला रं रोजवार से वही वि० सं० १७५३/१६६६ ई० न० २०६

९ बीकानेर से ब्याल महाराजा मुजानसिंह जी भू महाराजा गजसिंहजी तारी पृ० ५६

महाराजा गुजराणसिंह व जोरावरसिंह ने अपने पूर्वजों की प्रतिभा की बर्मी में दीवान का पद महत्त्वपूर्ण बन गया। उन्हीं पाने के लिए मुत्सद्दियों^१ के बीच होड़ लग गई। जिनमें मूँघणो व मोहता की प्रतिस्पर्धा मुख्य थी। इस प्रतिस्पर्धा ने धीरे-धीरे इतना विषट रूप धारण कर लिया कि राज परिवार के सदस्य भी दीवान पद पर नियुक्ति के विषय में गुस्ता हस्तसेव करने लगे।^२ यही हाल राठौड़ ठाकुरों का भी था।^३ महाराज नुवर जोरावरसिंह ने मोहता बन्तावरसिंह को दीवान नियुक्त करवाने के लिए अपने पिता गुजराणसिंह पर दबाव डाला और जब वे उसमें असफल रहे तो शिवदार आनन्दराम नाज़र, जो मूँघणो का पक्ष पाती था की हत्या करवादी व मोहता की नियुक्ति करवाई।^४

महाराजा जोरावरसिंह की नि सन्तान मृत्यु ने इस पद की शक्तियों को नयी ऊँचाइयों पर चढ़ा दिया। दीवान मोहता बन्तावरसिंह ने मुमाहिब, ठाकुर पृथ्वीसिंह से मिलकर अपनी इच्छा के राजकुमार गजसिंह को, राज्य का नया महाराजा बनाया।^५ राज्य में बमंचन्द बरुठाबत के बाद मोहता बन्तावरसिंह ही शक्तिशाली व प्रभावशाली दीवान बना था। महाराजा गजसिंह सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे। वे शासक के पद की गरिमा को दीवान की शक्तियों से गिरने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने माहना दीवान को चार बार निलम्बित किया था व उसके स्थान पर कभी मूँघणो की, कभी बरखीयो की नियुक्ति दीवान पद पर की।^६ यह स्पष्ट व निश्चित कर दिया कि दीवान का पद पूर्णतया शासक की कृपा पर आश्रित है।

महाराजा सूरतसिंह के समय दीवान पद की प्रतिष्ठा गिर गयी। महाराजा स्वयं सारी शक्तियों को अपने हाथों में केन्द्रित करने के इच्छुक थे। सूरतसिंह का दीवान के साथ विरोध, गददी पर बैठने के साथ ही प्रारम्भ हो गया था। दीवान मनमुख नाहटा ने, सूरतसिंह द्वारा अपने भतीजे की हत्या का विरोध किया फलस्वरूप न केवल उसे पद ही त्यागना पड़ा, बल्कि वह भी हत्या का शिकार हुआ।^७ आशंकित सूरतसिंहजी ने बाद में किसी अन्य व्यक्ति को शक्ति

१ वही पृ० ५७, ७०, ७१, ७८

२ दयालदास की ख्यात (धप्र०) २, पृ० २६३

३ वही

४ वही

५ मोहता ख्यात, पृ० १६५-६६ दयालदास ख्यात (धप्र०) २ पृ० २७६

६ परवाना वही वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० ७३, दयालदास ख्यात (धप्र०) २, पृ० २६३ २६४, २६५, २७३, २७६ २८६ २८६

७ दयालदास ख्यात (धप्र०) २, पृ० ३१२, टॉड ने मोहता बन्तावरसिंह को हटाकर भारता लिखा है जो कि गलत है। मोहता थी बन्तावरसिंह की मृत्यु महाराजा गजसिंह के समय में ही सन् १७७६ ई० में हो गयी थी। टॉड, २ पृ० १११८, परवाना वही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० ७७

प्रबन्ध अलग से करते थे।^१ दीवान पद का महत्त्व, उनके उत्तराधिकारी दलपत-सिंह के शासन काल में और भी कम हो गया था, क्योंकि राजा ने पुरोहित मानमहेश, जिसको 'मुसाहिब' बना रखा था, को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया।^२ राजा सूरसिंह के काल में, पुन दीवान का पद प्रभावशाली बनने लगा। उसके समय में मोहता (बैश्य) को पहली बार दीवानी प्राप्त हुई थी।^३ अब दीवान एक जाति या गौत्र विशेष का नेता न होकर एक दल (गुट) विशेष का नेता हो गया, जिसमें केवल उसी की जाति या वंश के लोग ही नहीं बल्कि अन्य जाति के व्यक्ति भी समान स्वार्थ के आधार पर सम्मिलित होने थे। दीवान अपनी नियुक्ति के पश्चात्, अपने गृहयोगियों को भी राज्य के अन्य उच्च पदों पर नियुक्त कराता था।^४

महाराजा अनूपसिंह के समय एक और परिवर्तन आया, जबकि प्रथम बार हजूरियों में से दीवान पद के लिए नियुक्ति हुई। नाजर आनन्दराम को अनूपसिंहजी ने नियुक्ति का परवाना दलान में भेजा था।^५ अनूपसिंहजी के समय हजूरियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। सवास उदैराम, उनका दूसरा विश्वसनीय व्यक्ति था।^६ हजूरियों के बढ़ते प्रभाव से, पुराने मुत्सद्दी ईर्ष्यालु होने लगे।^७ महाराजा अनूपसिंह के समय ही 'मूधडे' (बैश्य) प्रथम बार, राज्य के दीवान नियुक्त हुए।^८ महाराजा स्वरूपसिंह के काल में वे राजमाता व नाजर ललित के प्रभाव के कारण प्रभावशाली नहीं थे।^९ इस प्रकार दीवान का पद कई मतहों से गुजर रहा था।

१ दयालदास श्यात, (प्र०) भाग २ पृ० ११६-२२ सोहनवाल (पूर्व) पृ० १३५ मुगल प्रशासन में दीवान के विभाग में बायीं का वितरण इस प्रकार था—सरकार—मुगल प्रशासन, पृ० ३३-४६

२ वही पृ० १४२-४३

३ मोहता भीमसिंह द्वारा जोधपुर महाराजा अश्वमेध के बीकानेर शरे का वर्णन पृ० ४४, मोहता श्यात, पृ० ३३

४ दलादाम श्यात (प्र०) २ पृ० १५६, मोहता कल्याण मल दीवान के साथ अन्य अधिकारी नियुक्त हुए थे—कोबर उरजो जी, तोपणीवाल कोठारी, बोधरा माह दूगरनी, दासरी भीमवाल कोठारी कूनर, चोपडा भीमराज श्रेष्ठ लखमोदाम आदि

५ महाराजा अनूपसिंह जी से आनन्दराम नाजर हैं नाम परवानो (पूर्व) महाराजा अनूपसिंह उस समय श्रीरंजित के दलितो मुन्ही से व्यस्त थे तथा उनकी नियुक्ति श्रीरामाबाद, जिले में आदमी गड से हुई थी

६ देशदर्पण, पृ० १४६

७ वही

८ नामदारो व वकीला हैं रोजगार री वही, वि० न० १७५३/१६६६ ई०, न० २०६

९ बीकानेर री द्याल महाराजा गुजाणसिंह जी मूं महाराजा गजसिंहजी तारी पृ० ५-६

महाराजा मुजानसिंह व जोरावरसिंह ने अपने पूर्वजों की प्रतिभा की कमी से दीवान का पद महत्वपूर्ण बन गया। उसे पाने के लिए मुत्सद्दियों के बीच होड़ मग गई। जिनमें मूँघडों व मोहतों की प्रतिस्पर्धा मुख्य थी। इस प्रतिस्पर्धा ने धीरे-धीरे इतना विकट रूप धारण कर लिया कि राज-परिवार के सदस्य भी दीवान पद पर नियुक्ति के विषय में झुत्ता हस्तक्षेप करने लगे।^१ यही हाल राठौड़ ठाकुरों का भी था।^२ महाराज कुंवर जोरावरसिंह ने मोहता बख्तावरसिंह को दीवान नियुक्त करवाने के लिए अपने पिता मुजानसिंह पर दबाव डाला और जब वे उसमें असफल रहे तो शिवदर आनन्दराम नाहर, जो मूँघडों का पक्ष-पाती था की हत्या करवादी व मोहतों की नियुक्ति करवाई।^३

महाराजा जोरावरसिंह की नि सन्तान मृत्यु ने इस पद की शक्तियों की नयी ऊँचाइयों पर चढ़ा दिया। दीवान मोहता बख्तावरसिंह ने मुमादिव, ठाकुर पृथ्वीसिंह से मिलकर अपनी इच्छा के राजकुमार गजसिंह को, राज्य का नया महाराजा बनाया।^४ राज्य में कर्मबन्द बख्तावरसिंह के बाद मोहता बख्तावरसिंह ही शक्तिशाली व प्रभावशाली दीवान बना था। महाराजा गजसिंह मुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे। वे शासक के पद की गरिमा को दीवान की शक्तियों से गिरने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने मोहना दीवान को चार बार निलम्बित किया था व उसके स्थान पर कभी मूँघडों की, कभी बरडों की नियुक्ति दीवान पद पर की।^५ यह स्पष्ट व निश्चित कर दिया कि दीवान का पद पूर्णतया जनक की हृपा पर आश्रित है।

महाराजा सूरतसिंह के समय दीवान पद की प्रतिष्ठा फिर बढ़ी। महाराज स्वयं सारी शक्तियों को अपने हाथों में केन्द्रित करने के इच्छुक थे। महाराज का दीवान के साथ विरोध, गद्दी पर बैठने के साथ ही प्रारम्भ हो गया।^६ दीवान मनमूँघ नाहटा ने, सूरतसिंह द्वारा अपने अंगरेजों की हत्या के निन्दित किया फलस्वरूप न केवल उसे पद ही त्यागना पड़ा, बल्कि वह कैद में भेजा गया।^७ आशंकित सूरतसिंहजी ने बाद में किसी अन्य व्यक्ति को दीवान

१ वही, पृ० ५, ७, ७०, ७१, ७८

२ दयालदास की व्याप्त (अप्र०) २, पृ० २६३

३ वही

४ वही

५ मोहता व्याप्त, पृ० १६५-६६, दयालदास व्याप्त (अप्र०) २, पृ० २६३

६ परवाना वही, वि० सं० १८००/१७५३ ई०, पृ० ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००

७ दयालदास व्याप्त (अप्र०) २, पृ० ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००

माला लिया है जो कि कल है। दयालदास व्याप्त (अप्र०) २, पृ० ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००

के समय म ही सं० १७५३ ई० में हुआ। दयालदास व्याप्त (अप्र०) २, पृ० ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००

नहीं सौंपी । सम्भवतः भय था कि दीवान पद की विदाल शक्तियों के प्रयोग से कोई भी आगे चलकर उनकी स्थिति को चुनौती दे सकता है ।^१ फलतः दीवान राजा के कामदार वाली स्थिति में पहुँच गया ।^२ प्रतापमल बंद को बहुत समय तक अन्य पदा पर कार्य करवाने के बाद दीवान बनाया गया ।^३ लेकिन अमरचन्द सुराणा के समय दीवान का पद फिर प्रतिष्ठित व भय उत्पन्न करने वाला बन गया था ।^४ महाराजा सूरतसिंह ने अमरचन्द की सैनिक योग्यताओं से प्रसन्न होकर ही उस दीवान पद पर नियुक्त किया था । उसने शासक व राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध ऐसी कठोर सैनिक कार्यवाहियाँ की कि राज्य में उसका भातक छा गया ।^५ सुराणा के प्रथम बार दीवान बनने से, पुराने मुत्सद्दी, इनकी पदोन्नति व अपने अधिकारों के बर्चित हो जाने से विरोधी हो गये थे ।^६ हजूरिये भी बेन्दगीकरण से नाराज थे ।^७ सामन्त इसे अपनी राह का रोड़ा समझत थे ।^८ इस कारण अमरचन्द सुराणा पड़्यन्त्र का शिकार बना । पहले उस पर अमीर खाँ पिण्डारी के साथ गुप्त पड़्यन्त्र का आरोप लगाकर राज्य-विरोधी अपराध में बन्दी किया गया, फिर विरोधियों के जोर देने पर उस मार डाला गया ।^९

वास्तव में महाराजा सूरतसिंह चारों तरफ अपन हो रहे विरोध से घबरा उठा था । अमरचन्द सुराणा को हटाकर महाराजा विरोधियों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था । इस दुष्कृत्य के परिणाम भी बुरे निकले । विरोधियों के सामने से विरोध हट जाने के परिणामस्वरूप महाराजा के विरुद्ध विद्रोही का ताता बढ गया, जिस नया मोहता दीवान नियन्त्रित नहीं कर पा रहा था ।^{१०} अमरचन्द ने मरकर राज्य में दीवान पद के महत्त्व को स्पष्ट कर दिया और अपनी आवश्यकता को समझा दिया था ।

दीवान का चुनाव या दीवान की योग्यताएँ

जयसोम ने मन्त्री की योग्यता का विवरण देते हुए स्पष्ट किया है कि

- १ कागदा की बत्ती, वि० सं० १८७२/१७१५ ई०, न० २१ पृ० १६० दयालदास व्यास (अप्र०) २ पृ० ३१२
- २ प्रतापमल बंद पहले कामदार ही नियुक्त किया गया था । परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० ८१
- ३ परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई० पृ० ८१
- ४ उपर्युक्त पृ० १०२
- ५ दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृ० १८ २२
- ६ वही
- ७ वही
- ८ वही
- ९ वही पृ० ३२४-३२५
- १० वही पृ० ३२५-२६

वह साम, दाम, दण्ड भेद नामक चारों उपायों को विधिपूर्वक काम में लाकर, शुद्ध हृदय से पण्डितों के विचारानुबल हो, राज्य शासन करें। राज्य के प्रथम पांच शासकों ने मन्त्रियों में, जो वच्छावत परिवार के थे, जयसोम यही योग्यता देखता है।^१ हालांकि प्राचीन स्मृति और नीतिशास्त्र मन्त्री में सैनिक योग्यता होना आवश्यक नहीं मानते, पर राज्य के दीवान सैनिक योग्यता भी रखते थे।^२ यहाँ तक कि मन्त्रियों के सैनिक दायित्व इतने बढ़ गये थे कि अराजकता के खेत्तों में बानून व व्यवस्था स्थापित करने के लिए सैनिक कार्यवाही करने जाते थे। मोहता बख्तावरसिंह व सुराणा अमरचन्द की सैनिक योग्यताएँ प्रसिद्ध थीं। १६वीं शताब्दी में, राज्य में एक आम प्रथा बन गयी थी कि मन्त्री ही सैनिक अभियानों का सञ्चालन करेंगे। यहाँ तक कि सैनिक विजय ही, उनकी पदोन्नति का एक प्रमुख कारण बन गयी।^३

साधारणतया राजा दीवान का चुनाव करते समय, पुराने मुत्सद्दियों के परिवारों को ही प्रधानता देता था। राजा रायसिंह के समय तक दीवान पद को, वच्छावत परिवार के सदस्यों ने ही, सुशोभित किया। फिर जमश बँद, मोहता, मूधडा आदि परिवारों के सदस्य मुख्य रूप से दीवान नियुक्त हुए। प्रशासकीय-व्यावहारिक ज्ञान को देखते हुए अन्य परिवारों से भी दीवान नियुक्त हुए थे, पर प्रधानता पुराने मुत्सद्दियों की ही बनी रही। हजूरियों को भी उनकी सेवाओं को पुरस्कृत करने व व्यक्तिगत-सम्बन्धों के कारण, यह पद कभी-कभी दे दिया जाता था।^४ लेकिन राजपरिवार या सामन्तों में से किसी को भी दीवान नहीं बनाया गया था।

सम्मान व उपाधियाँ

दीवान अपनी, नियुक्ति के समय, राजा को 'नजर' भेंट करता था व मोछावर करता था। राजा उसे सम्मानित करने के लिए 'मोतियों का चाँकड़ा, सिरपाव, कड़ा व कटार' प्रदान करता था। राज्य में यह परम्परा प्रचलित थी कि नए दीवान की नियुक्ति के बाद, राजा उसके घर पर दावत का निमन्त्रण

१ कर्मचन्द्र, पृ० ३१

२ दणपत विलास, पृ० ३०-३२, कर्मचन्द्र, पृ० ३५, ३६, ६१, दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृ० २०५, २११-१४, (अप्र०) २, पृ० २५६, २६४, २७३, ३१३, ३२२

३ बीजानेर की छ्वाज, महाराजा मुजानसिंहजी सू महाराजा बजसिंह जी तः पृ० ७१, दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृ० ३१३

मोहता बख्तावरसिंह को महाराजा बजसिंह ने अनेक सैनिक अभियानों में भेजा था। अमरचन्द सुराणा की दीवान पद पर नियुक्ति ही उसकी मदनर विजय के पश्चात् हुई थी।

४ दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृष्ठ २६४, २७६, २८६

नहीं सौंपी। सम्भवतः भय था कि दीवान पद की विशाल शक्तियों के प्रयोग से कोई भी आगे चलकर उनकी स्थिति को चुनौती दे सकता है।^१ फलतः दीवान राजा के कामदार वाली स्थिति में पहुँच गया।^२ प्रतापमल बँद को बहुत समय तक अन्य पदों पर बाँधे रखवाने के बाद दीवान बनाया गया।^३ लेकिन अमरचन्द सुराणा के समय दीवान का पद फिर प्रतिष्ठित व भय उत्पन्न करने वाला बन गया था।^४ महाराजा सूरतसिंह ने अमरचन्द की सैनिक योग्यताओं से प्रसन्न होकर ही उसे दीवान पद पर नियुक्त किया था। उसने शासक व राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध ऐसी कठोर सैनिक कार्यवाहियाँ की कि राज्य में उसका आतंक छा गया।^५ सुराणा के प्रथम बार दीवान बनने से, पुराने मुसद्दी, इनकी पदोन्नति व अपने अधिकारों के बर्चित हो जाने से विरोधी हो गये थे।^६ हजूरिये भी बेन्दगीकरण से नाराज थे।^७ मामूला इमे अपनी राह का रोड़ा समझते थे।^८ इस कारण अमरचन्द सुराणा पड़्यन्त्र का शिकार बना। पहले उस पर अभीर छा पिण्डारी के साथ गुप्त पड़्यन्त्र का आरोप लगाकर राज्य-विरोधी अपराध में बन्दी किया गया, फिर विरोधियों के जोर देने पर उस मार डाला गया।^९

वास्तव में महाराजा सूरतसिंह चारों तरफ, अपने हो रहे विरोध से घबरा उठा था। अमरचन्द सुराणा को हटाकर महाराजा विरोधियों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। इस दुष्कृत्य के परिणाम भी बुरे निकले। विरोधियों के सामने से विरोध हट जाने के परिणामस्वरूप, महाराजा के विरुद्ध विद्रोहों का ताता बढ गया, जिसे नया मोहता दीवान नियन्त्रित नहीं कर पा रहा था।^{१०} अमरचन्द ने मरकर राज्य में दीवान पद के महत्व को स्पष्ट कर दिया और अपनी आवश्यकता को समझा दिया था।

दीवान का चुनाव या दीवान की योग्यताएँ

जयसोम ने मन्त्री की योग्यता का विवरण देते हुए स्पष्ट किया है कि

१. कागदी की बही, वि० सं० १८७२/१७१५ ई०, न० २१, पृ० १६०, दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृ० ३१२
२. प्रतापमल बँद पहले कामदार ही नियुक्त किया गया था। परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० ६१
३. परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई० पृ० ६१
४. उपर्युक्त पृ० १०२
५. दयालदास व्यास (अप्र०) २, पृ० १८२२
६. यही
७. वही
८. वही
९. वही, पृ० ३२४-३२५
१०. वही, पृ० ३२५-२६

स्वीकार कर उसे सम्मानित करने जाता था। इसके अतिरिक्त राजा दीवान नियुक्ति के समय कभी कभी विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए अपने हाथ से उसके माथे पर टीका लगाता था। दयालदास ने मोहता परिवार को मिले सम्मान हेतु ऐसे तीन अवसरों का वर्णन किया है। राजा दीवान के काय से प्रसन होकर उसे पालकी भी प्रदान करता था।^१

मोहता बख्तावरसिंह को मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वितीय की ओर से राय का खिताब भी प्राप्त हुआ था।^२ महाराजा मूरतसिंह ने यह सम्मान दीवान सुराणा अमरचन्द को प्रदान किया था।^३

वेतन

दीवान का वेतन ६००० से १०००० रु० के बीच वार्षिक था।^४ मोहता बख्तावरसिंह के समय यह राशि घटकर १४००० रुपये तक पहुँच गई थी।^५ यह राशि कई भागों में बँटकर प्राप्त होती थी। कुछ नकद राशि के रूप में कुछ राज्य के करों की आमदनी से व कुछ पट्टे में प्राप्त राशियों की आमदनी से मिल कर पूरी होती थी। दीवान के कमचारियों को व निजी सेवकों को भी राज्य से वेतन प्राप्त होता था।^६

दीवान के काय

राज्य में हर मंत्री व अधिकारी का अपना दायित्व होता था परन्तु अच्छे प्रशासन को चराने का मुख्य दायित्व दीवान पर ही था। वैसे सही अर्थों में वह

१ कामदारों के पट्टे—पट्टा बही वि० सं० १७४२/१६८५ ई० न० ६ वि० सं० १७५३/१६८६ न० ७ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई० प० ६१ १११ दयाल दास ब्यात (अप्र०) २ प० ११ २७६ २६६

राजा मूरतसिंह ने प्रथम मोहता दीवान कल्याणमन को विक्रम सं० १६८०/१६२३ ई० में ब्यात भाग २ प० १५६ महाराजा स्वरूपसिंह ने मोहता मुकदराय को वि० सं० १७५६/१६८६ ई० में ब्यात (अप्र०) पृष्ठ २५७ और महाराजा यजसिंह ने मोहता बख्तावरसिंह को वि० सं० १८१७/१७६० ई० में अपने हाथ में टीका लगाया था

२ दयालदास ब्यात (अप्र०) २ पृष्ठ २८७ महाराजा यजसिंह ने मोहता बख्तावरसिंह को उठण का कुरब प्रदान किया था मोहता ब्यात पृष्ठ ६८

३ दयालदास ब्यात (अप्र०) २ प० ३२४ यह उपाधि महाराजा मूरतसिंह ने दीवान को चूरु विजय के पश्चात् प्रदान की थी।

४ कामदारों के पट्टे—पट्टा बही वि० सं० १७५३/१६८६ न० ७ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई० न० ६१

५ पट्टा बही वि० सं० १७५३/१६८६ ई० न० ७ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई० पृष्ठ १११ देखिये शरशिष्ट सख्या ४

६ बही

राज्य का वित्त मंत्री था। दीवान की नियुक्ति के पीछे यही आशय रहता था कि राज्य की आमदनी बढ़ाकर विभिन्न खर्चों की पूर्ति करेगा।^१

दीवान के क्या उत्तरदायित्व थे, इसका स्पष्ट उल्लेख हम उस परवान से प्राप्त होता है जो महाराजा अनूपसिंह ने नाज़र आनन्दराम को दीवान नियुक्त करत समय, आदूणी (आध्रप्रदेश दक्षिण) से सवत १७४६ में लिखकर भेजा था। उस परवान में महाराजा द्वारा दीवान के कार्यों से सम्बन्धित निर्देश दिये गये हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है^२ -

दीवान उन समस्त आदेश-पत्रों पर, जिस पर शासक की मुहर लगी होगी, अपनी मुहर लगायेगा। साथ ही वह खजान्ची द्वारा राज्य में व अन्य परगनों में जो पत्र भेजे जायेंगे, उनका निरीक्षण करेगा व अपनी मुहर लगायेगा। दरबार की कार्यवाही के बाद शासक की अनुपस्थिति में वह अपनी सूझ बूझ से पत्रों पर मुहर लगा कर आदेश देगा।^३

राज्य के आदेशों का पालन करवायेगा। दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड देगा।^४

किसे में जो राज्य का खजाना है उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करेगा। रुपये पैसा का हिसाब करके शासक को मूचित करता रहेगा।^५

प्रशासन के सभी विभागों का निरीक्षण करेगा उनकी दृष्ट-रेख करेगा। बड़ा कारखाना (राज परिवार की आवश्यकताओं से सम्बन्धित विभाग) का प्रबन्ध विशेषतौर पर करेगा। विभागीय अधिकारी, जो पहिले से नियुक्त हैं, और उपयुक्त हैं को बनाये रखेगा, अन्यथा उनके स्थान पर अन्य योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करेगा (हुवलदार)।^६

वह राज्य के मन्दिरों की व्यवस्था करेगा व मूल्यवान धातुओं, जैसे तांबा,

१ परवाना वही वि० सं० १८००/१७४३ ई० पृष्ठ ७७, मुगल प्रशासन में भी दीवान या बजीर मुख्य रूप से वित्त विभाग की सम्भालता था—भाइन जकबरी अनूबाद १ पृ० ६

२ महाराजा अनूपसिंहजी से मान दशम नाज़र ई नाम परवानो सवत १७४६ मिति मय-सर बदी १३ (२६ नवम्बर १६९३) धातूनी लिखित खास रुक्का मान-दराम को दीवानगी दते समय भेजा था। न० १६७/१६ राजस्थान अ० सं० पु० बी०, देखिय परिशिष्ट सख्या ५

३ और अध्ययन के लिये परवाना पीह सुद २ ५ वि० सं० १८१२/३ १० जनवरी १७५५ ई० बरियस परवानान भाफ दी व कानेर रुसस एड्डिब टू दी मोहता कमिती भाफ बीवानर (पूव)

४ और अध्ययन के लिये—वही

५ और अध्ययन के लिये देखिय—दलपत विलास पृष्ठ २७ कमचन्द्र पृ० ३६, वही थी रावते लेख वि० सं० १७७५/१७१८ ई० न० २१२, बीकानेर बहियात

६ और अध्ययन के लिये देखिय—हुजदारों से भय री वही वि० सं० १७०४/१६४३ ई० न० १२०, बीकानेर बहियात हुवाना सौपा भागद-कागदों की वही, न० ३ ५ १०, ११

पीतल इत्यादि के भण्डार-गृहों की देख रेख करेगा।^१

वह शस्त्रागार विभाग की सही व्यवस्था करेगा। तोपों में बिगाड़ न आने देगा। बंदूकों व बख्तरो का प्रबन्ध करता रहेगा। सभी मुख्य मुख्य हथियारों की अलग-अलग व्यवस्था करेगा।^२

वह किले में स्थित जितने भण्डार गृह हैं उनका कुशलता से प्रबन्ध करेगा। गावों से जो हासल प्राप्त होता है उस सही ढंग से भण्डारों में पहुँचायेगा। राज्य भण्डारा से जितने व्यक्तियों की सामग्री प्राप्त होती है उसका उचित वितरण करेगा व सही अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।^३

वह राज्य के जितने बोट हैं, उनकी व्यवस्था करेगा व वहाँ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

ठाकुरों के गावों से व जनाना पट्टों के गावों से जो आय होती है उसकी बार-बार माग करके, वसूली करेगा।^४

राज्य में जो सार्वजनिक निर्माण का काम होता है उसकी देख-रेख करेगा व मजदूरों के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करेगा।

राज्य में हासल उगाहने के लिए जो कामदार नियुक्त किये जाते हैं, उन्हें परगनों में नियुक्त हाकिमों को यह आदेश देगा कि वे निर्धारित रकम से ज्यादा वसूल न करें व फिजूल खगड़ों में न पड़ें। अगर कोई आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाए तो गुनेहगारी लगाकर दण्डित करेगा। पिछली बकाया रकम (तलबाना) वसूल करने में तत्परता दिखायेगा।^५

हजरिया के कार्यों का वितरण करेगा व उनकी जीविका का प्रबन्ध करेगा। अगर कोई खगड़ा फसाद करे तो गुनेहगारी लगायेगा। राज्य में जो सैनिक, तोपची बन्दूकची भरती किये गये हैं, उनके वेतन का उचित प्रबन्ध करेगा।^६

१ और अध्ययन के लिये—बैरिस परमानन्द मोहता रिकाड (पूब)

२ और अध्ययन के लिये—अनूपत बितास, पृष्ठ ३४ बही फौज रे पाछ री, बि० सं० १८६५/१८०८ ई० न० १६२, बीकानेर बहिषात

३ और अध्ययन के लिये—बही कोठार भोग री बि० सं० १७२३/१६६६ ई० न० ५८, बीकानेर बहिषात।

४ और अध्ययन के लिये—परगना रे बसा जोड री बही बि० सं० १७२६ १७५०/१६६३ ई० १६६३ ई० न० ६८, बीकानेर बहिषात, दस रे खालसा री बही, बि० सं० १७४०/१६८३ ई० न० ६७ बप्पानेर बहिषात

५ और अध्ययन के लिये—चीरा जमरामर रे लख री बही बि० सं० १७४८/१६६१ ई० न० २७ चीरा जमरामर, बीदाहट मुसाईमर रे लेख री बही बि० सं० १७६६/१७४२ ई० न० ३१, बीकानेर बहिषात

६ और अध्ययन के लिये—नेछा-बही बि० सं० १७१३/१६५६ ई०, न० १०५, बीकानेर बहिषात

रूपत से अगर लेनदार गैर-हिसाबी ऋण वसूली करने का प्रयत्न करे तो उसे रोकेगा। लेनदारों को राजपूतों से चार वर्ष तक ऋण अदायगी वसूल करने की मनाही करेगा। राजपूतों के पास से पहले राज्य का बकाया पैसा वसूल किया जायेगा, फिर राज्य के साहुकारों, ग्राहणों व जोहरो की लेनदारी हो, फिर अन्य लोग उनसे अपने ऋण की वसूली करें।^१

पट्टायतों पर कामदारों का कर्ज है। अगर उनके पास से पट्टा निकल गया व कर्जदार का दवाव पड़ रहा हो तो उन्हें ऋण भुन लेने देना। राज्य की भूमि की खरीद में अगर कोई बाधा डालेगा तो मना करना।^२

कोई राज्य में कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करे व उसको कोई समर्थन या सहायता दे तो बिना किसी हिचक उन्हें दण्ड देगा।

इनके अलावा दीवान के पास न्यायिक अधिकार भी थे। वह गावों की सीमाओं में उत्पन्न झगड़ों, कृषि क्षेत्रों में चोरी से सम्बन्धित घटनाओं, लेन देनदारों का वाद-विवाद सामाजिक वाद-विवादों का निपटारा भी करता था।^३

पटौसी राज्यों के साथ कटनीतिक सम्बन्धों के निर्धारण में दीवान मुख्य भूमिका निभाता था। राव कल्याणमल ने कर्मचन्द की राय पर मुगलों से सन्धि की थी।^४ मोहता बख्तावरसिंह ने मारवाड़ के गृह-युद्ध में व मारवाड़-मराठा संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहता बख्तावरसिंह बीकानेर-जोधपुर मैत्री सम्बन्धों को स्थापित करने का प्रबल पक्षधारी था। उसने महाराजा गजसिंह जी के समय राजपूतान में मराठा-विरोधी संध बनाने की गतिविधियों में सक्रिय योगदान दिया था।^५ उसकी कूटनीतिक चतुराई व कार्य कुशलता से मुगल सम्राट भी प्रमत्त थे। होल्कर मल्हारराव ने भी मोहता दीवान से भेंट करते समय पूर्ण सम्मान वरता था।^६

दीवान को पद से हटाये जाने के कारण

दीवान पद का कार्यकाल नियुक्त व्यक्ति पर राजा की आस्था व विश्वास

१. श्रीर अध्वयन के विवे—कापदो की बही, वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ २००-२२
२. श्रीर अध्वयन व विवे—बही जमीं रे नामदांरी, वि० सं० १८१४/१७५३ ई०, न० ५, रामपुरिया रिवाज, बीकानेर
३. बरियस डिप्रीन-स, रिवाज बख्तर दी बाबर बाफ दी दीवान ऑफ बीकानेर, माहता रिवाज, माहता डिप्रीन, गेस न० ८, गेस रा० प्र० बी०
४. दानत विरास, पृष्ठ १५
५. मोहता दान, पृष्ठ ६१, दानतदाम दान (मद्र०) २, पृष्ठ २०३, २८६, ८८
६. माहता दान, पृष्ठ ६१, राजपूत राज्यों में दीवान पद के कार्यों के विवरण—बी० सी० मर्मा—एशियनिस्टिक सिस्टम ऑफ दी राजपूत, पृ० १६-१८, दिस्को ११७६

से प्रभावित होता था। सामान्यतः दीवान पद से विमुक्ति का मुख्य कारण दीवान का राजा के विरुद्ध पङ्क्यन्त्रों में सहयोगी होना था।^१ १८वीं शताब्दी में जब दीवान के सैनिक उत्तरदायित्व बढ़ गये तब इस क्षेत्र में सैनिक अयोग्यता भी उनके पतन का कारण बन गई थी।^२

मोहता बख्तावरसिंह बीकानेर राज्य का अकेला व्यक्ति था, जो यहाँ के तीन शासक महाराजा सुजानसिंह जोरावरसिंह व गजसिंह द्वारा नियुक्त किया गया था और छह बार अपने पद से हटाया गया था। ऐसा कोई अन्य उदाहरण राज्य के इतिहास में नहीं मिलता है। वह दरबारी पङ्क्यन्त्रों, शासक के विश्वास को कमी व प्रशासन में भ्रष्ट तरीकों को अपनाने के आरोपों से पद विमुक्त हुआ था, लेकिन दण्ड के रुपये भर कर, 'पेशकसी' के रूप में भारी रकम मजूर करके व मित्रों के प्रभाव से बार-बार नियुक्त हो जाता था। मोहता बख्तावरसिंह अपने पद से अपनी पत्नी व पुत्रों की शिकायत से भी हटाया गया था। पारिवारिक झगड़ों के परिणामस्वरूप होन वाली पद विमुक्ति का यही अकेला

१ राज्य में राजा रामसिंह के विरुद्ध दीवान कर्मचन्द्र का पङ्क्यन्त्र प्रसिद्ध है। दयालदास, पाइलेट व बीप्सा का कथन है कि १५६५ ई० में इस पङ्क्यन्त्र के द्वारा राजा को घोंघ में मारकर दलपतसिंह को राजा वमचन्द्र व राजा के भाई रामसिंह को मुखिया बनाया निश्चित हुआ था। हालाँकि इनके कथन में रामसिंह आदि को लेकर असन्नतियाँ हैं क्योंकि रामसिंह हम घटना में पूर्व मारा जा चुका था पर इसमें शक्य सत्यापन है कि दीवान ने राजा की गद्दी से हटाने का प्रयत्न किया था, क्योंकि राजा रामसिंह अपनी युष्पुत्रक वञ्छावर्गों के विरुद्ध बदला लेने के विचार को त्याग नहीं पाया था। कमचन्द्र का मुगल दरबार में रामसिंह विरोधी गतिविधियों को जन्म देने में प्रमुख हथकड़ी था। इसी प्रभाव में सन्नाहू भकवर न राजा में जागीर छीन ली थी व दलपत के विरोध का भी मौन समर्थन किया था। समकालीन ग्रन्थ कमचन्द्र इस सम्बन्ध में मौन है व इसे दैवयोग घटना ही मानता है। लेकिन मोहता बख्त से कुछ रावक नई जानकारी मिलती है कि राजा की विसीय स्थिति व दुर्गति निर्माण खच्चों के कारणों को लेकर दोनों में मनमुटाव बढ़ा था। भाष ही एक-दूसरे की प्रतिष्ठा भी ईर्ष्या का कारण बन गयी थी। राजा रामसिंह इस बात से भी रुष्ट था कि कर्मचन्द्र ने उसकी पुत्री जो राजा उदयसिंह की दोहीती थी, का विवाह महजादे मलीम के साथ कराने में बहुत पहल की थी। दलपत विलास पृष्ठ ८४, ८६ ८७, वमचन्द्र पृष्ठ ७३ मोहता बख्त पृष्ठ ३३, दयालदास बख्त (अनामिका) २ पृष्ठ १२८; दशदपण, पृ० १४, पाउनेट गजटियर, पृष्ठ २६, अमरावतसिंह 'राज्य एवम् पात प्राक दी वञ्छावर्ग हिस्टोरिकल स्टडीज—अभय जैन श्यालय, बीकानेर राज्य का इतिहास I, पृ० १६४ १६५

दीवान मुराणा अमरचन्द्र पर यह आरोप लगाया गया था कि वह राज्य के नाश में पिण्डारियों के साथ गुप्त रूप से मिल गया था—दयालदास बख्त (अग्र०) २, पृष्ठ ३२५ परवाना बही, सं० १८००/१७४३ ई०, पृष्ठ ७७

उदाहरण हैं ।^१

इसके अलावा राज्य के वित्तीय प्रबन्ध में अकुशलता से भी किसी को दीवान पद से हटाया जा सकता था, बल्कि कई बार दीवान इसी उद्देश्य से राज्य में नियुक्त किया जाता था, जिसे पूरा न करने की स्थिति में उस विमुक्त कर दिया जाता था ।^१

मुसाहिब

यह पद 'मुसाहिब' व मुसाईब के नाम से भी जाना जाता था । 'मुक्त्यार' शब्द का प्रयोग भी कई बार इसी पद के सदस्य में किया गया है । यह राज्य में बहुत सम्मानित पद था बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में यह श्रेष्ठ पद आका जाता था । इस पद के पीछे इतने उत्तरदायित्व नहीं थे, जितनी कि इसकी प्रतिष्ठा । इस पद को सुशोभित करने वाला राजा का मुख्य सलाहकार माना जाता था । कई बार यह पद, मान व मर्यादा में, दीवान पद से भी अधिक ऊँचा उठ गया था ।^१ यह पद राजा अपने विश्वसनीय व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए ही देता था । अपने समस्त गौरव के बाद भी, मुसाहिब केन्द्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष नहीं बनता था । अतः यह पद प्रशासन-मण्डल में स्थायी भी नहीं था । विशेष परिस्थितियों में ही इस पर नियुक्ति की जाती थी । शक्तिशाली दीवान के समय इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं होती थी । वास्तव में

- १ मोहता बख्तावरसिंह का दीवानो काल महाराजा गुजानसिंह के समय, वि० स० १७६०/१७३३ ई०, प्रथम बार दीवानगी दी गयी जो वि० स० १६६१/१७३४ ई० तक चलती रही, दूसरा काल वि० स० १७६२/१७३६ ई०, से प्रारम्भ होता है, जो वि० स० १७६७/१७४० ई० तक चलती रही । उसी वर्ष दुबारा उस दीवान बनाया गया, जिसका कार्यकाल महाराजा जोरावरसिंह की मृत्यु तक चलता रहा । महाराजा गरमिह के राज्याभिषेक के समय मोहता की दीवानावली मिला । वि० स० १८०२/१७६५ ई० से वह वि० स० १८०८/१७८१ ई० तक रहा । इसके पश्चात् प्रथम वर्ष ही, वि० स० १८०६/१७५२ ई० में फिर नियुक्ति हो गयी, जिसका काल वि० स० १८१३/१७५६ ई० तक रहा था । वि० स० १८१३/१७५६ ई० में कुछ समय के लिये फिर पद से विमुक्त कर दिया गया । अगला कार्यकाल, वि० स० १८१३/१७५६ ई० से वि० स० १८१४/१७५८ ई० तक रहा ।

—परवाना वही, वि० स० १८००/१७४३ ई०, पृष्ठ ७७

- २ परवाना वही, वि० स० १८००/१८४३ ई०, पृष्ठ ७७, ८१
- ३ मुगल साम्राज्य में बकाल पद के साथ इसकी समता की जा सकता है । आदिल प्रनवरी (मनुवाव) भाग I, पृ० ५, १६३६ ई०, इम्नदगन—सं तुल स्टैनवर आक दी मुगल एम्पायर, पृ० १३५ ४०, जयपुर राज्य में मुसाहिब का पद प्रधानमन्त्री व सैन्यमन्त्री का पद था—जी० सी० शर्मा—एडमिनस्ट्रटिव सिस्टम, पृष्ठ १५

इसका महत्त्व तो उसी समय बढ़ता था, जब राजा व उसके दीवान के बीच मतभेद गहरे हो जाते थे, और 'मुसाहिव' का अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो जाता था।^१

सबप्रथम, इस पद का यणन राजा दलपतसिंह के शासन काल में आता है, जब राज्य का पुरोहित मानमहेण मुसाहिव बनकर राजा का मुख्य सलाहकार हो गया था।^२ इस पद की असीम शक्ति व उसका गौरव दलपतसिंह जी के शासन काल के अन्त के साथ ही समाप्त हो गया था। राजा बलसिंह ने दो मुसाहिव कोठारी जीवनदास व कुबड़ चौपड़ा नियुक्त किये।^३ राज्य के इतिहास में यही एक ही उदाहरण है, जब दो मुसाहिव एक साथ नियुक्त किये गये। महाराजा स्वरूपसिंह के बाल्यकाल में भूबरका क ठाकुर पृथ्वीराज मुसाहिव थे, और पहली बार राठौड़ सामन्तो में से किसी को इस पद पर नियुक्त किया गया था।^४ मोहता बख्तावरसिंह राज्य का जब तक दीवान रहा, मुसाहिव पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई। महाराजा सूरतसिंह के काल में फिर यह पद अपने गौरव की स्थिति में आ गया, जब मोहता प्रतापमल बंद को मुसाहिव नियुक्त किया गया।^५ उस समय दीवान पद की स्थिति गिरकर राजा के निजी कामदार जैसी रह गयी थी। महाराजा सूरतसिंह के काल में दीवान अमरचन्द मुराणा, विद्रोही सरदारों के विरुद्ध दमनकारी नीति से पुरस्कृत होकर मुसाहिव पद पर नियुक्त किया गया। अमरचन्द मुराणा पहला व्यक्ति था, जिसने दोनों पदों—दीवान व मुसाहिव पर एक साथ कार्य किया था।^६ मुराणा की हत्या के पश्चात् फिर यह पद अलग-अलग व्यक्तियों की सौंप दिये गये थे।

'मुसाहिव' के क्या कर्तव्य थे, इसका स्पष्ट विवरण राज्य की बहियो व रियासतों में नहीं प्राप्त होना है। इस सन्दर्भ में प्राप्त विवरण से ज्ञात होता है कि जिसको मुसाहिवी की धिजमत^७ सौंपी जाती थी, वह राज्य के प्रमुख विषयों पर अपनी सलाह देता था। कई बार सैनिक विभाग का संचालन भी 'मुसाहिव' किया करता था। प्रशासनिक क्षेत्र में राजा व सरदारों के बीच सम्बन्धों को जोड़ने वाली कड़ी मुसाहिव ही था। सामन्तों को पट्टे देते समय 'मुसाहिव'

१ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई० पृष्ठ ७० २१ १०२ दयालदास ख्यात (प्र०) २ पृष्ठ १४२ २१५

२ दयालदास ख्यात (प्र०) २ पृष्ठ १४२—राजा क भाई सूरसिंह को भी अपनी जागीर बनाने के लिये मानमहेण की प्रतिष्ठा व याचना करनी पड़ी

३ मोहता ख्यात पृष्ठ ४६ दयालदास ख्यात (प्र०) २ पृष्ठ १६७

४ बीकानेर से ख्यात महाराजा सुजाणसिंहजी व महाराजा यजसिंहजी साईं पृ० ५

५ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृष्ठ २१

६ वही पृष्ठ १०२

७ दायित्व या सेवा

की सलाह ली जाती थी। महाराजा स्वरूपसिंह के समय में, मुसाहिव राज्य के प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करता हुआ उल्लिखित हुआ है।^१

इस पद का वेतन भी, इसकी बदलती हुई स्थिति व दायित्वों पर निर्भर करता था। सामान्यतः रु० ३०००) से १०,०००) तक वार्षिक वेतन मिलता था।^१

बखशी

बखशी पद राज्य में बगसी व तनबगसी के नाम से जाना जाता था। महाराजा गजसिंह के काल में प्रथम बार इस पद की रचना हुई थी।^१ यह न केवल सैनिकों की भर्ती, उसकी सज्जा, अनुशासन व फौज खर्च के हिसाब के लिए ही उत्तरदायी था; बल्कि उसे बराबर विभागीय कार्य भी देखने पड़ते थे। वह सेना को वेतन देता था व अधिकारियों की नियुक्ति, पद-वृद्धि और पदावनति का विवरण भी रखता था। सेनाओं का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण भी वही करता था व उपस्थिति-पत्रिका भी रखता था। राजधानी के दुर्ग की पोली (दरवाजा) पर किलेदारों को वेतन व सिपाहियों की नियुक्ति करता था। साथ ही राज्य के सभी किलों का प्रबन्ध तथा नियुक्ति करता था।^१

लेकिन वह सैन्य संचालन का कार्य नहीं करता था और न ही यह पद राज्य के प्रधान सेनापति के रूप में माना जाता था।^१

तनबखशी का एक विशेष कार्य राज्य के सामन्तों के साथ सम्बन्धों को निर्धारित करना था। यह उत्तरदायित्व मुसाहिव पद से लेकर तनबखशी के पद को, उसके निर्माण के बाद दिया जाता था। सैन्य विभाग का अक्षय होने के नाते राज्य के पट्टाधर अपने सैनिक दायित्वों को लेकर इस पद से सम्बन्धित हो जाते थे। प्रत्येक पट्टे के प्रदान किये जाने से पहले, राजा के बाद तनबखशी के

१. बीकानेर री क्वाट महाराजा मुजार्णतिग जी सू महाराजा गजसिंह जी वार्ड, पृष्ठ ५, ७, १५; दयालदास क्वाट (अप्रकाशित) भाग २, पृष्ठ १८२, २२२.
२. परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृष्ठ ६१
३. वही, पृष्ठ १२०; मुगलों के बखशी पद में यह बहुत प्रचलित था—इन्सुलुशन (पूर्व) पृ० २१५ राजपूत राज्यों में इस पद के अध्ययन के लिए—जी० सी० बर्मा (पूर्व) १८-२०
४. परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० १२०, पट्टा बही, वि० सं० १७५३/१६६९ ई०, न० ७, पृ० १४४, भैरवा सग्रह—फौज री जमा खरब बही; वि० सं० १८०२/१८१५ ई० चौपनीमा तनबगसी का, वि० सं० १८०३-७४/१८१६-१७ ई०, सौर बपोरी हाजरी बही, वि० सं० १८७३/१८१६ ई०, दयालदास क्वाट (अप्र०) २, पृ० ३२२
५. भैरवा सग्रह—पत्र, आताक मुदी ४ वि० सं० १८४६/२३ जून, १७६२ ई०, पत्र, सावन मुद ७ वि० सं० १८७८/२२ जून; १८१७ ई०, बही कोटदी री खानम री वि० सं० १८७४/१८१७ ई०, मोहता क्वाट, पृ० ६५

हस्ताक्षर होते थे व इस काय व लिए वह पट्टायतो स पट्टे का 'लाजमा' नामक कर भी वसूल करता था। तनवल्ली पट्टायतो को उनके राज्य क प्रति सैनिक दायित्वो को पूरा करने के लिए विवश करता था और राजा को सूचना भेजता था।^१ अगर किसी पट्ट के क्षेत्र में कानून व व्यवस्था की समस्या किसी कारण को लेकर उत्पन्न हो जाती थी तो उसका प्रवक्ता भी तनवल्ली को ही करना पड़ता था।^२ सेना के विभिन्न भागों से सम्बंधित विभागों के अध्यक्ष जो हुबलदार व दरोगा होते थे के कार्यों का निरीक्षण भी वही करता था।^३

यह पद राज्य में वशानुगत नहीं था। मुत्सद्दिया के विभिन्न परिवारों के सदस्यों ने इस पद को सुशोभित किया था। प्राप्त विवरणों के अनुसार इस पद पर सबसे प्रथम नियुक्ति बायस्थ भैया आनमचन्द की सन् १७५२ ई० में हुई जो महाराजा गर्जसिंह के समर्थक और विद्वामपात थे। इसके पश्चात् मूधडा व मोहता परिवार के सदस्य इस पद पर चुने गये थे। भैया परिवार में नथमल जी ने फिर इस पद को महाराजा सूरतसिंह के काल में सभाना था। इस पद का वार्षिक वेतन ४०००) ६० वार्षिक था जो महाराजा मूरतसिंह जी के काल में बढ़कर ५०००) ६० कर दिया गया था।^४

शिकदार

वीकानेर राज्य का शिकदार मुगल के शिकदार से भिन्न था। मुगल व्यवस्था में शिकदार सिर्फ एक परगने का मुख्याधिपति था^५ जबकि वीकानेर प्रशासन में वह मल्लि भण्डन का एक सदस्य माना जाता था। राजा रायसिंह व उसके उत्तराधिकारियों के समय यह पद दीवान पद के बाद सबसे अधिक प्रभावशाली पद था। तनवल्ली से पूर्व सैन्य विभाग इसी पद के अन्तर्गत था। मुसाहिब के अभाव में पट्टा क्षत्र स सम्बन्धी कार्य भी इन्हीं सभालने पड़ते थे। दीवान की शक्तियों को नियंत्रित करने वाला यह अंग मंत्री होता था।^६

वैद ठाकुरसी राजा रायसिंह का विश्वसनीय शिकदार था। राजा ने उसे जागीर में भटनेर का परगना प्रदान किया था।^७ राज्य का प्रसिद्ध दूसरा

१ मोहता ख्यात पृ० ६५

२ वही पृष्ठ ६५

३ भैया मगह—फौज की जमा बही दि० सं० १८७२/१८१५ ई०

४ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० १२० ३२

५ रा० ए० एन० थोवाल्लव—जकबर महान् भाष—२ पृ० १४६ पी० सरन—दी प्रोविशियल गवर्नमेंट आफ दी मुगल्स पृ० १६६ ६७ एशिया १६७३

६ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई० पृ० ६१ १०२ मोहता ख्यात पृ० १७ २०, दयालदास ख्यात (वप्र०) २ पृ० २६२ ६३ ३२५ २७

७ दयालदास ख्यात (प्र०) २ पृ० १२२

शिकदार महाराजा मुजाफसिंह जी के समय खवास आनन्दराम हुआ था ।
इसका महाराजा पर अधिक प्रभाव होने की वजह से शीघ्र ही संघर्ष में आना
था जिसका परिणाम यह हुआ कि शिकदार की हत्या करवा दी गई ।^१ इस
घटना के बाद शिकदार पद का महत्त्व यौग होता गया । उसके अधिकार में
अंश राज्य की भूमि के क्रय-विक्रय, बुगी-कर और राज्य-टुकसाल का विभाग
रह गये थे ।^२ महाराजा सूरतसिंह जी के काल में एक बार फिर यह पद
हस्तपूर्ण बन गया । मोहता प्रतापमल बंद की इस पद पर नियुक्ति की गई
थी, जिसका वेतन ८०००) रुपया वार्षिक था; लेकिन दीवान पद व मुमाहिब
द के उरथान के साथ फिर इसका महत्त्व उसी काल में गिर भी गया था ।^३

कील

पड़ोसी शक्तियों के साथ कूटनीतिक पत्र-व्यवहार से सम्बन्धित विभाग
का अध्यक्ष वकील कहलाता था । साधारणतया कायस्थ परिवार के व्यक्ति ही
इस पद के लिए चुने गये थे । इस पद के पीछे वार्षिक वेतन २०००) ६० प्रदान
किया जाता था, जो आगे चलकर सन् १६८७ में ३०००) ६० हो गया था ।^४
मुगल काल में वह शाही दरबार में राजा के प्रतिनिधि के रूप में रहता था ।
अन्य राज्यों में भी वह राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता था ।
इसका मुख्य कार्य, मुगल दरबार की गतिविधियों की जानकारी अपने राजा
को भेजना होता था । उस समय वह शाही दरबार में सम्राट व अन्य प्रशास-
निक अधिकारियों का समर्थन पाकर अपने शासक के लिए मनसब व जागीर
में वृद्धि के प्रयत्न करता रहता था । सम्राट, वजीर व अन्य मुगल पदाधि-
कारियों को जो नज़र व भेंट दी जाती थी, उसका भी पूरा विवरण वकील
रखता था ।^५ मुगलों के पतन के बाद इसकी स्थिति व कार्य बदले गये । अब
वह पड़ोसी व अन्य राज्यों के साथ अपने राज्य के हों रहे पत्र-व्यवहार व कूट-
नीतिक बातों का संचालन करता था । एक तरह से विदेश-विभाग के कार्य
उसके द्वारा निर्देशित होते थे ।^६

१. बीकानेर की ख्यात महाराजा मुजाफसिंह जी सँ महाराजा जयसिंह जी वार्द, पृ० ७
२. मीरजा पत्र— पोप वार्द ११, १८७३/१२ दिसम्बर, १८१६ ई०; परवाना वही वि० सं० १८००/१७४३, पृ० ६१, १०२
३. परवाना वही वि० सं० १८००/१७४३ ई० पृ० १०२
४. कामदारो व वकीलो रे रोजगारो रे वही, वि० सं० १७४३/१६६६ ई०, नं० २०६; पर-
वाना वही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० १४२-४७
५. कामदारो व वकीलो रे रोजगारो रे वही, वि० सं० १७४३/१६६६ ई०, नं० २०६
६. कामदारो व वकीलो रे रोजगारो वही वि० सं० १७४३/१६६६ ई०, मीरजा पत्र पोप वार्द
२, वि० सं० १८४१/११ दिसम्बर, १७६४; नैसाख सुदी ७, १८६४/१४ मई १८०७,

पुरोहित

यह राजा व राज्य के धार्मिक, पुनीत कार्यों व समारोहों को सम्पन्न कराता था।^१ कई बार महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक कार्य के लिए पड़ोसी राज्यों में भी भेजा जाता था।^२ यह पद वंशानुगत था, जो तौलिमासर के पुरोहितों के पास रहता था।^३ पुरोहित मानमहेश ने राज्य की राजनीति में सक्रिय भाग लिया था तथा राजा दलपतसिंह के साथ अच्छे सम्बन्धों के परिणामस्वरूप वह राज्य का मुताहिब नियुक्त किया गया था। राजा सूरसिंह द्वारा अपने विरोधियों से बदला लेने की नीति के फलस्वरूप इनकी जागीरें जन्त कर लीं व पुरोहिती इस परिवार से छोन ली, जो बाद में वापिस कर दी गई थी।^४

अधिकारी व कर्मचारी वर्ग

मन्त्रियों व मुख्य पदाधिकारियों के अलावा प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई थी। ज्यों-ज्यों प्रशासनिक व्यवस्था दृढ़ व संगठित होती जा रही थी, उसी के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई व उनका कार्य-क्षेत्र भी निश्चित होता चला गया। इनमें से बहुत तो मन्त्रियों के अधीन कार्य करते थे और कुछ स्वतन्त्रतापूर्वक अपने-अपने विभाग का संचालन करते थे। कर्मचारी मन्त्री व अधिकारी के साथ जुड़े रहते थे। इस प्रकार पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार हो गया था।

खजाची

इस पद पर चरित्रवान और विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। यह खजाना-विभाग का अध्यक्ष होता था। खजाने में आने वाली आय व जाने वाले खर्च का ग्योरा रखता था। १८वीं शताब्दी में एक खजाची को सैनिक दायित्व भी सौंपे गये थे, और वह सैनिक अभियानों पर गया था। इसके विभाग में एक नायब भी होता था जो 'हुसदार' व कभी 'दरोमा' के नाम से जाना जाता था। खजाची को ५०) रु० मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाता था।^५

माघ सुदी १० वि० सं० १८७५/४ फरवरी १८१६ ई०, मोहता छ्वाट, पृ० १५, देवडा-
म्युरोकेषी इन राजस्थान, पृ० १००-१०६

१. कर्णाभित्त, पृ० १५

२. मोहता छ्वाट, पृ० ३१-२८

३. दयालदास छ्वाट (प्र०) २, पृ० १२८

४. वही, पृ० १४२-४३

५. खजाने की जमा धरव की बही, वि० सं० १७१५/१६६८ ई०, न० ३३; धोरावले लेखे बही, वि० सं० १७७५/१७१८ ई०, न० ३१२

दफ्तर का हुवलदार

दीवान कार्यालय में, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हुवलदार कहलाता था। इसका मुख्य दायित्व राज्य में वसूल होने वाले करों का निर्धारण करना था। दीवान से स्वीकृति आन पर वह निर्धारित करों की सूचना उन अधिकारियों को भेजता था जो कर-वसूली के लिए गांवों में जाते थे। उन अधिकारियों का वेतन व भत्ता भी निर्धारित करके उन्हें देता था। विपत्ति के समय में वह उन करों में छूट की भी घोषणा करता था। इन कार्यों से सम्बन्धित पत्र व आदेश उसका कार्यालय तैयार करता था। पट्टों के खेव से केन्द्र की होने वाली आय का हिसाब भी यही रखता था।^१

खुवासगिरी

खुवासगिरी की विजय प्राप्त करने वाला खुवास किसी विभागीय पद के अधिकारी के नाम से नहीं जाना जाता था। खुवास एक पदवी थी, जो राजा के हुजूरियों में से किसी एक को विशेष (खास) कृपा होने पर दी जाती थी। इसके अलावा राज्य की विशेष सेवा करने पर भी इन्हें खुवास की पदवी प्रदान की जाती थी। राजा के ये विशेष कृपा-पात्र न केवल राजा के साथ उसके पीछे हाथी पर बैठते थे, दरबार में उसके पीछे खड़े होते थे व राजा की मुहर रखते थे। कभी-कभी विभिन्न विभागों का दायित्व भी इन्हें सौंपा गया था। सेना के विभिन्न विभागों की फौजदारी इन्हें सुपुर्व की जाती थी व विभिन्न किलों के किलेदार भी नियुक्त किये जाते थे। खुवासगिरी भी वशानुगत होती थी।^१

इयोदीदार

राजमहलों की देख-रेख, निरीक्षण व सुरक्षा दायित्वों को निभाने तथा महलों के दरवाजों की चाबिया रखने वाला इयोदीदार कहलाते थे। राजपूतों की कुछ जातियाँ विशेषतः परिहार, भाटी तथा इनकी विभिन्न शाखाओं के व्यक्तियों को ही यह पद वशानुगत स्तर पर प्रदान किया गया था। अविश्वास की दशा में ही हटाया गया था। इस पद से जुड़े हुए मुख्य कर्तव्य इस प्रकार थे—शासक की

१. कागदों की बही, वि० सं० १८२०/१७३६ ई०, न० २, पृ० २४-२८, वि० सं० १८५७/१६०० ई०, न० ११, पृ० १०१-३, वि० सं० १८६७/१८१० ई०, न० १६, पृ० ५१-५३, कामदारी पट्टे—परवाना बही न० १

२. परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० १२८, देख-रेख, पृ० १४७ ५०, मोहता स्याउ, पृ० १२८

उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति, जो इनसे मिलने आता, उस पर पूरी दृष्टि रखना, शासक की अनुपस्थिति में जब कोई व्यक्ति शासक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आता तो उसका विवरण रखना, राजमहलों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना आदि थे।^१

साहणी—राजकीय अस्तबल (तबेला) का मुख्याधिकारी साहणी कहलाता था। चूँकि राठोड़ों की सेना में मुख्य अंग के रूप में घुड़मवार दस्तों का सदैव महत्त्व रहा था, इस कारण केन्द्रीय स्तर पर तबेले व उसके अधिकारी के रूप में साहणी का भी वैसा ही महत्त्व व सम्मान रहा। यह पद भी वंशानुगत रूप से हजूरियों में राजपूत परिवारों के पास रहा, जिनकी स्थायी जागीर बेलासर गाँव की थी।^२ साहणी घोड़ों की खरीद, उनके निरीक्षण व विभाग से सम्बन्धित सभी समस्याओं का दायित्व सभालता था। वह थारमीर^३ घुड़सवारों को घोड़े प्रदान करता था। दीवान, मुत्ताहिब, शिकदार व फौजदारों के सैनिक अधिकतर थारमीर ही होते थे। इसके सहायक अधिकारी हुवलदार व मुसरफ (मुशरफ) कहलाते थे जो कि रसद आदि की व्यवस्था रखते थे।^४

फौजदार

शुतरखाना (ऊठों का विभाग) तोपखाना, पीलखाना (हाथी-विभाग) व सिलेहपोसखाना (शस्त्रागार) का मुख्य विभागीय प्रशासनिक अधिकारी फौजदार कहलाता था। जो अपने विभाग से सम्बन्धित खरीद, निरीक्षण व वस्तुओं के प्रबन्ध की व्यवस्था रखते थे।^५ बीकानेर राज्य में ऊठसवारों के दस्तों सेना के एक महत्त्वपूर्ण अंग थे, जो रेगिस्तानी वातावरण में बहुत प्रभावशाली सिद्ध होते थे। अतः शुतरखाने के फौजदार का अपना महत्त्व होता था। इनकी सहायता के लिये हुवलदार व दरोगा होते थे, जो मुख्यतः हाथियों व ऊठों की

१. मोहता ब्यात, पृ० १२८, देसदरपण, पृ० १५७
२. मोहता ब्यात, पृ० १२८, देसदरपण, पृ० १५०
३. थारमीर वे सैनिक होते थे, जिन्हें लड़ने के लिये घोड़ा व शस्त्र राज्य की तरफ से मिलते थे। मुगलों में भी इस प्रकार के सवार थे—श्विन—दो आर्मी ब्राफ दो इण्डियन मगुम्स, पृ० ३६, ३८, दिल्ली १९६८
४. वही तबेला खरब वि० सं० १७१६/१६९९ ई०, न० २३४—बीकानेर बहीयात, कागदों की वही वि० सं० १८६३/१८०६ ई०, पृ० २६, सं० १८७०/१८९३ ई०, न० १९/२, पृ० ६०
५. हाथियों व तुलादान की वही वि० सं० १७४८/१६९१ ई०, न० २००; बीकानेर बहीयात, कागदों की वही सं० १८५७/१८०० ई०, पृ० ७३, २०६, सं० १८६३/१८०६ ई०, पृ० ४०, सं० १८७३/१८९६ ई०, पृ० ५२

व्यवस्था का दायित्व सभालते थे।^१ तोपखान का फौजदार नई तोपों के निर्माण तथा बारूद का प्रबंध करता था।^२ शस्त्रागार का फौजदार विभिन्न शस्त्रों का संग्रह तथा उनकी आपूर्ति की व्यवस्था करता था। शस्त्रागार बड़ा कारखाना के नाम से भी जाना जाता था।^३ इसके अलावा रथखाना का भी फौजदार होता था।^४

मंडी रा हुवलदार

इसे भी मंडी का हुवलदार भी कहा जाता था। राजधानी के क्षेत्र में होने वाली राहुदारी, जुगीकर, आयात-निर्यात कर, ख्य-विक्रय आदि की आय भी यहीं में जमा होती थी, जिसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हुवलदार होता था। यह हुवलदार बसबों व गांवों की मंडियों का निरीक्षण करता था तथा केन्द्रीय प्रशासन का एक सम्मानजनक अधिकारी होता था तथा शासक मुत्सद्दी की निष्ठा परखने के बाद ही किमी को इस पद पर नियुक्त करता था।^५

मोदीखाना रा हुवलदार

राजपरिवार, राजा पर आश्रित अनेक व्यक्ति, सबक, चाकर, सैनिकों की रसद, भद्रिया, अधिकारियों, व कर्मचारियों की यात्रा के समय रसद का प्रबंध मोदीखाना से होता था, जिसका मुख्य अधिकारी मोदीखाना का हुवलदार कहलाता था। जितनी भी रानियाँ पासुरे,^६ पासवान,^७ व सुशासवान^८ थी, उनका भी पेटीया^९ मोदीखाने से ही व्यवस्थित होता था।^{१०} मोदीखाने के अन्तर्गत ग्राहसामग्री व रसद के जो विशाल भंडार होते थे, उनकी व्यवस्था

- १ वि० सं० १८७३/१८९९, पृ० २२
- २ बहो फौज रं पीछ रो सं० १८६५/१८०८ ई० न० १६२, बीकानेर बहियात, कागदों की बही सं० १८२७/१७७० ई० पृ० ४१ ५० सं० १८६३/१८०८ ई० पृ० ७० ७२
- ३ कागदों की बही सं० १८५७/१८०० ई० पृ० ७३ १८५६/१८०२ ई०, पृ० ५१, सं० १८६३/१८०६ ई०, पृ० १४ २७, ३५ ४५, २८५
- ४ हाथिया व मुसाधान की बही सं० १७४८/१६६९ ई० न० २००
- ५ मंडी बहिया—सं० १७८३/१७२६ ई०, न० ७८ सं० १७६६/१७४२ ई० न० ७८ सं० १८०७/१७५० ई०, न० ८०, बीकानेर बहियात—रा० रा० अ० बी०
- ६ बहो कौछर रं पान रो, वि० सं० १७४२/१६८३ ई० न० ५६—बीकानेर बहियात—रा० रा० अ० बी०
- ७ दामियाँ, धामिकाप व नवक्रियाँ
- ८ राजा की विषय स्त्री
- ९ राजा की दुतायाज स्त्री
- १० भत्ता
- ११ परपना की जमा जोड़ बही वि० सं० १७२६ ५०/१६६६ ६३ ई०, न० ६६, बीकानेर बहियात रा० रा० अ० बी०

तथा उनकी पूर्ति व निरीक्षण का कार्य हुबलदार करता था। उसके सहायक दरोगा आदि होते थे।^१

लेखनीया—यह कर्मचारी वर्ग का सामूहिक नाम था। प्रत्येक विभाग में कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिक तथा कहीं-कहीं निरीक्षक का कार्य करने वाले लेखनीया के रूप में नियुक्त किये जाते थे। मन्त्री व अधिकारियों के आदेश को ठीक ठीक लेख्य बनाना ही इनका प्रमुख कर्तव्य था। सख्त तैयार हो जाने पर वे उम्र सम्बन्धित अधिकारी व मन्त्री को दिखाकर फिर शासक द्वारा स्वीकृति लेकर आगे के लिए प्रेषित करते थे। लेखनीयों भी मुत्सद्दी वर्ग से चुने जाते थे तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शिक्षित, कार्यपटु तथा निष्ठावान होंगे।^२ अधिकांश मन्त्रियों व अधिकारियों ने लेखनीयों के स्तर से ही अपना सवाकान प्रारम्भ किया था।^३ विभाग के निरीक्षक के रूप में लेखनीया की नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण होती थी व उन्हें दायित्व लेखनीया की शिक्षण के नाम से सौंपा जाता था।^४

उपर्युक्त विभिन्न पदों के विवरण से जहाँ यह बात स्पष्ट होनी है कि कबीला प्रधान रेगिस्तानी क्षेत्र में जहाँ एक केन्द्रीय प्रशासन की स्थापना हो गई थी, वहाँ इन पदों के वर्गीकरण में स्पष्टता व निश्चितता का अभाव खटकता है। अधिकारी-मन्त्र अपने शौचकाल से ऊपर उठता हुआ दृष्टिगत नहीं होता है, जबकि मुगल प्रशासन का गठन अपने समस्त पारस्परिक विरोधों के पश्चात् राज्य सामन्तवादी ढाँचे में विकसित अवस्था में था। बीकानेर राज्य में कहीं हुबलदार पद विभागाध्यक्ष के रूप में आया है तो वही साधारण कर वसूली के कर्मचारी के रूप में तो दूसरे स्थल पर एक सहायक अधिकारी के रूप में। लेखनीया भी प्रशासन के सभी स्तर के पदों के प्रयोग में आया है। केवल वेतन ही पद के स्तर का विभाजन करता है। संभवतः निर्जन रेतीली भूमि के कम आबादी वाले क्षेत्र में कुलीम व कबीलावादी परम्पराओं से जूझते हुए मुगल सेवा में रत बीकानेर शासकों को इससे अधिक करने का कुछ अवसर भी नहीं मिला होगा।

विभिन्न पदों व उनसे सम्बन्धित दायित्वों को देखते हुए हम मुत्सद्दी-वर्ग को तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी में वे मुत्सद्दी आते हैं जो राज्य के उच्च पदों पर मन्त्री या अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनका

१ बही कोठार रं घान री वि० सं० १७४२/१६८३ ई० (प्रव)

२ कामदारी पट्टे—परवाना बही न० १

३ जी० एस० एन० देवडा—ब्यूरोक्रेसी इन राजस्थान, पृ० ६-१८

४ लेखनीया की शिक्षण—कामदारी पट्टे—परवाना बही, सं० १८००/१७४३, न० १

वेतन कुछ नकद तथा कुछ पट्टे के धन की आय द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। जागीरी क्षेत्र के सम्मान तथा उच्चपद के कारण ये मुत्सद्दी वर्ग में उच्च श्रेणी के कहे जा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी में कर-वसूली के अधिकारी तथा मन्त्रियों व उच्च अधिकारियों के सहायक अधिकारी आते हैं। इनमें कर-वसूली के अधिकारी जो हुक्मदार के नाम में विख्यात थे, एक अनुबन्ध के रूप में वेतन की राशि प्राप्त करते थे अथवा कर की राशि में शासक द्वारा स्वीकृत प्रतिशत के रूप में वसूल करते थे। इस श्रेणी में खजाची, दरोगा मुशरफ आदि मासिक या वार्षिक वेतन के रूप में आय प्राप्त करते थे। यह मुत्सद्दी-वर्ग की मध्यम श्रेणी थी। अन्तिम व तृतीय अथवा वग की निम्न श्रेणी में लेखनीया, गुमास्ता आदि आते थे जो मासिक स्तर पर अपना वेतन राजकोष, पट्टायत अथवा मन्त्री या अधिकारी से प्राप्त करते थे। इस श्रेणी के मुत्सद्दियों की संख्या अन्य दो की तुलना में अधिक थी।^१ परन्तु ये तीनों श्रेणियाँ अलग अलग जाति से सम्बन्धित होने के बाद भी अपने समान हितों के फलस्वरूप जुड़कर एक ऐसे वर्ग का निर्माण करती हैं जो निश्चित रूप में अपने स्वार्थों में सामन्त विरोधी है तथा अपनी आय के साधनों को लेकर बनावट व स्वरूप में भी वैर-सामन्ती है। उस काल के समाज का मध्यम वर्ग इसी वर्ग में ढूँढा जा सकता है।

वैसे इस काल तक मुत्सद्दी-वर्ग अपनी समस्त नियुक्तियों व प्रभाव के पश्चात् भी सतोपजनक आधार ढूँढ नहीं पाया, और उसकी यह मूलभूत कमजोरी ही उसके विकास में बाधक थी। राजपूत प्रशासन में चाकर की सेवा पूर्णरूप से व्यक्तिगत थी। उसकी नियुक्ति, पदोन्नति तथा पदच्युति सभी राजा की इच्छा के परिणाम में होती थी। सार्वजनिक सेवा निश्चित व लिखित नियमों से बधी हुई नहीं थी बल्कि अपने मूल स्वरूप में अनुबन्धात्मक थी, जो बीच में ही समाप्त की जा सकती थी। इस स्थिति के फलस्वरूप मुत्सद्दी राजा की दया पर आश्रित रह गये थे। राजा उन्हें राज्य के सर्वोच्च पद से गौरवान्वित कर सकता था तथा उन्हें जीविका देने हेतु निम्न पद पर भी नियुक्त कर सकता था। एक मुत्सद्दी के जीवन में ऐसे ही क्षण आते थे जब वह एक अवसर पर सुख व समृद्धि से आश्वस्त रहता था तो वही दूसरे अवसर पर दो वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी तरसता था।^२ मुत्सद्दियों के राजपूत धामन्तों की तरह राज्य में किसी प्रकार के दावे नहीं थे। इस प्रकार अधिकारीतन्त्र, अपने आरम्भ से ही आर्थिक अस्थिरता तथा मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त था।

१ देखिये कामदारी पट्टे—परवाना बही न० १, हुजाना मोपा बागद—कागदों की बही न० ५, पृ १०, ११

२ जी एच एस देवडा—पूरोरणी इन राजस्थान पृ० ६, १०

दरबारी प्रतिस्पर्धा एवम् उसके परिणाम

सन १५७० ई० के पश्चात् जहाँ राज्य में एक ओर केन्द्रीय सत्ता दृढ़ता में स्थापित हुई, वहाँ दूसरी ओर इसके विभिन्न पदों का प्राप्त करने के लिए दरबारियों में एक समूहित गुटबन्दी का जन्म भी हुआ। इसका परिणाम राज्य के लिये अच्छे नहीं निकले थे। सत्ता लोलुप, व्यक्तियों ने झगडा, घृणा, प्रतिशोध व हत्या का शातावरण बनाकर नव स्थापित केन्द्रीय संस्थाओं के अस्तित्व तक को झकझोर डाला था।

राज्य की राजनीति व दरबारी प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ से ही सत्ता के आर्कषण से प्रेरित थी। परन्तु यह अपने उद्भव व स्वरूप को लेकर अलग अलग समय में भिन्न रही थी। प्रारम्भ में यह एक जातीय संघर्ष था। प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर बच्छावत वंश का एकाधिकार था तथा उन्हें शासक का पूर्ण विश्वास प्राप्त था। राव बीका के साथ आये अन्य कर्मचारी वर्ग ने इसे ईर्ष्या व संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन उन्होंने खुलकर विरोध कभी नहीं किया।^१ बच्छावतों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रथम संघर्ष स्वयं शासक के साथ ही हुआ जो कि उनकी शक्ति का मूल स्रोत था। दीवान कमल दत्त राजा रायसिंह को नहीं सह्य कर सका उसका पुत्र दलपत को गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई। पर उस सफलता नहीं मिली। वह अपनी पड़ोसीवारी गतिविधियों का भेद खुलन पर राज्य छोड़कर भाग गया और उसी के साथ ही प्रशासनिक पदों पर बच्छावतों का एकाधिकार भी समाप्त हो गया। राजा रायसिंह व उसके उत्तराधिकारी भी इस तथ्य को भाव गये कि एक जाति के एकाधिकार से राजवत में कभी भी भय उत्पन्न हो सकता है। इस कारण उन्होंने प्रशासनिक पदों पर एक जाति के व्यक्तियों के स्थान पर एक से अधिक जातियों के मुसद्दियों की नियुक्ति की। बीकानेर शासकों की इस कार्यवाही से दरबारी राजनीति में जातीय पक्ष कमजोर पड़ गया।

इसके बाद बीकानेर के मुसद्दियों ने नये मिरेस गुटों का निर्माण किया, जो कि पूणतया दलगत भावना से प्रेरित थे। नये गुट एक जाति के स्थान पर समान स्वार्थों के विभिन्न जातियों के व्यक्तियों से मिलकर तैयार हुए, जिसमें गुट का नेता दीवान बनने पर प्रशासन के विभिन्न पदों पर अन्य सदस्यों को नियुक्त करता था। इन नये गुटों में जातीय चरित्र पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था बल्कि कुछ जातियों ने मिलाकर एक गुट बना लिया था। इनमें मोहता व मूधडा अग्रणी थे।

महाराजा अनूपसिंह के काल में, इस प्रतिस्पर्धा में दो नये तत्व उभरने लगे। प्रथम, महाराजा ने बाहर से आये मुत्सद्दियों का राज्य में स्वागत किया था तथा उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त करके सम्मानित किया था। ये नये आगुन्तक, पुराने मुत्सद्दियों की ईर्ष्या के शिकार हो गए। पुराने मुत्सद्दी इन्हें परदेशी कहते थे^१ जिसके फलस्वरूप मुत्सद्दी-वर्ग देशी व परदेशी मुत्सद्दियों में बंट गया था। दोनों में, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, सभी पुराने मुत्सद्दी अपनी गुट-भावना को छोड़कर परदेशियों के विरुद्ध एक हो जाते थे। द्वितीय, अनूपसिंह ने प्रथम बार दीवान के पद पर 'हजूरियों' को नियुक्त किया था। मुत्सद्दी वर्ग का सघर्ष, मुख्यतः राज्य के महत्त्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने तथा अपने पक्ष के राजकुमार को, शासक बनाने से ही अधिक सम्बन्धित था। वह व्यक्ति जो दीवान पद पर नियुक्त होता था, वही विभिन्न 'चौरी' में 'हुवलदार' नियुक्त करता था^२, जो कि मुत्सद्दियों के 'मुख्य रोजगार' थे।^३ अतः वे इस आशा में एक गुट बना लेते थे कि उनके गुट के—व्यक्ति के नेता बनाने पर उन्हें रोजगार का अधिक लाभ मिलेगा।

राजपरिवार के सदस्य भी दरबारी गुटबन्दी में सक्रिय हस्तक्षेप करने लगे थे। उनमें से, अधिकतर युवक राजकुमार किसी एक पक्ष के साथ, अपने सम्बन्ध जोड़कर भविष्य में राजगद्दी पर बैठने के अपने दावे को दृढ़ करना चाहते थे। मुत्सद्दी अपना स्वार्थ इसमें यह दूढ़ते थे कि उनके पक्ष के व्यक्ति के गद्दी पर बैठने से उनका रोजगार निश्चित व लम्बे समय तक के लिए तय हो जायेगा। इन स्वार्थों ने राज्य के राजनीतिज्ञों को इतना उलझाया कि वे राज्य के हितों की परवाह न करके अपने हितों की पुति में जुट गए। इससे उत्पन्न होठ ने प्रत्येक प्रकार के नृशंस तरीकों को भी अपनााने के लिए उन्हें नहीं रोका।

१८वीं शताब्दी में दुर्भाग्य से राज्य को अयोग्य शासक मिले, जिनके काल में स्थिति नियन्त्रण में आने के स्थान पर और विकराल रूप धारण करने लगी। आपसी फूट व भासव की अयोग्यता व प्रशासन के प्रति उदासीनता ने राज्य के नव-स्थापित प्रशासन के शीशर काल में ही उसे एक घातक धक्का दिया।^४ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने लगी। राज्य की अव्यवस्था का लाभ सामन्ती बंदीजों व पड़ोसी जत्रुओं ने उठाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप

१ दयालदास ख्यात (प्र०) २, पृ० २१६

२ हुवाला सौगात काणद—काणदों की वही न० १०, ११

३ व्यवसाय से प्राप्त धन

४ बीकानेर राज्य की ख्यात महाराजा गुजराणसिंह जी ने महाराजा बजरंगसिंह ठाई, पृ० ५, ७, १३, ३५, ४२

राज्य की समस्या और जटिल हो गयी ।^१ मुत्सद्दी भी आपसी कलह व सघर्ष के कारण एक दूढ़ समूह नहीं बना सके । उनकी फूट ने राज्य में गैर सामन्तवादी शक्तियों को कभी एक नहीं होने दिया बल्कि पारस्परिक द्वेष के कारण वे स्वयं को ही अधिक नुकसान पहुँचा पाये ।^१

पंचम अध्याय

स्थानीय प्रशासन

सामान्य व विस्तीय प्रशासन सम्बन्धी सुविधाओं के लिए राज्य कई क्षेत्रीय इकाइयों में विभक्त था। इन इकाइयों का निर्माण किसी घोषणा या कानून द्वारा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक क्रम में हुआ था। प्रारम्भ में राज्य राजनैतिक व प्रशासनिक स्तर पर तीन क्षेत्रीय इकाइयों में विभक्त था, यथा—राजा या राव का क्षेत्र, कुल-मुखियों या ठाकुरों का क्षेत्र तथा कबीलों व जातियों का क्षेत्र। १६वीं शताब्दी के अन्त तक, यह श्रेणियाँ परिवर्तित होकर, खालसा, पट्टा व सासन के नाम में प्रसिद्ध हुईं। यह वर्गीकरण प्रारम्भ में राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुकूल था। कालान्तर में, प्रशासन के केन्द्रीकरण की बलवती इच्छाओं, सभी श्रेणियों में समान प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावनाओं, सामन्ती के क्षेत्र में हस्तक्षेप तथा कृषि व व्यापारिक वृद्धि व सुरक्षा की मांग के फलस्वरूप राज्य में, प्रशासनिक स्तर पर रद्दोद्घन की आवश्यकता अनुभव हुई। परिणामस्वरूप राज्य को, राजस्व व सामान्य प्रशासनिक इकाइयों के रूप में पृथक् तथा विभक्त किया गया। राजस्व इकाइयाँ, खीरा व परगना कहलाई तथा प्रशासनिक इकाइयाँ, थाणे के नाम से विख्यात हुईं। एक ओर राजस्व इकाई मण्डी पृथक् रूप से, थाणों के साथ प्रस्थापित की गयी। यद्यपि खालसा, पट्टा व सासन के गांव बन रहे, परन्तु (अब) वे एक चीरे के अंग बन चुके थे।

खीरा-व्यवस्था

खीरा-व्यवस्था वास्तव में, केन्द्रीय प्रशासन द्वारा निर्धारित करा की वसूली की एक सुविधाजनक, क्षेत्रीय राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजा रायसिंह के काल से राज्य में शासक की दुर्ग सत्ता स्थापित होने के साथ, सामन्ती श्रेणियों से भी, नियमित रूप से निर्धारित करों की वसूल करने की प्रथा प्रारम्भ हुई, यथा—'खेड़ खरज, हनुब, धुआँ भाछ, नोता, रुखवाली भाछ, घोडा रेख' इत्यादि।

१ खेड़ खरज, घाड़ा रेख, रुखवाली भाछ सैन्य कर थे, धुआँ भाछ गृहकार का नाम था, हनुब सामान्य व विविध कर था तथा नोता राज-परिवार के सदस्यों के विवाह के प्रसंग पर लगाया गया कर था।

से प्रभावित थी। प्राकृतिक विपदाओं के समय तो 'चीरे' के कई गांव सूने हो जाते थे तथा कभी-कभी पूरा 'चीरा' ही गायब हो जाता था ।^१

राज्य में विभिन्न 'चीरो' के नाम इस प्रकार थे—चीरा नौहर, रीणी, सीहागोटी, गधीली, बुधगाऊ, सीहवागो (राज्य के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में) गुसोईसर, शेखसर, खेदो, महाजन (मध्य क्षेत्र में) जसरासर, बीदाहद, राजाहद, (पूर्वी क्षेत्र में) अनूपगढ, पूगल (पश्चिमी क्षेत्र में) तथा मगरा घारी पट्टी (दक्षिणी क्षेत्र में), 'चीरे' के ये नाम उनकी भौगोलिक स्थिति व बसने वाली मुख्य जाति के नाम पर तथा क्षेत्र के सांस्कृतिक एवम् व्यापारिक महत्त्व के आधार पर रखे गये थे ।^१ विभिन्न 'चीरो' के नामकरण से राज्य के इतिहास में एक विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इससे पूर्व सभी क्षेत्रीय इकाइयाँ जाति-विशेष के नाम से विख्यात थीं। लेकिन अब राठौड़ों की सत्ता स्थापित होने के बाद अन्य कारण प्रभाव में आने लगे थे। इन 'चीरो' का वर्गीकरण क्षेत्रीय समानता के आधार पर नहीं किया गया था। यहाँ तक कि इसकी कुल भाषा भी समान न थी ।^१ 'चीरो' का मुख्य केन्द्र खालसा भूमि में ही स्थापित होता

१. सन् १७२६ ई० में चीरा खेदरा में ३८ गांव खासता के थे, जो सन् १७१६ ई० में, उनका जाने के कारण केवल एक गांव रह गया तथा उसी गांव के नाम पर चीरे का नाम बबल कर पुनर्सीसर हो गया था। सन् १७२६ ई० में गधीली व सीहागोटी के चीरे सूने हो गये थे। बचे हुए साबाद गांव चीरा नौहर में मिला दिये गये थे। चीरा बुधगाऊ भी पटकर चीरा राजाहद नाम से विख्यात हुआ था

—वही खासता दे गांव री, वि० सं० १८३०/१७७३ ई०, कागदों की बही, वि० सं० १८११/१७७४ ई०, न० १, पृष्ठ ४-८; वि० सं० १८३८/१७८१ ई०, न० ५, पृ० ५६-५८; वि० सं० १८३६/१७८२ ई०, न० ६, पृष्ठ ४४-४६

२. घुमा रोकठ बही, वि० सं० १७५०/१६६३ ई०, न० ८८; कागदों की बही, वि० सं० १८६३। १८०४, न० १४, पृष्ठ ११४—राजधानी के दक्षिण भाग की भूमि ककरीली व सलत है तथा मगरों के नाम से विख्यात है, इस कारण इस क्षेत्र का चीरा मगरा कहलाया। राजधानी के दक्षिण-पश्चिम भाग की भूमि लवण की विशेषता रखने के कारण वहाँ का चीरा घारी-पट्टी नाम से विख्यात हुआ। कुछ चीरे अपने क्षेत्र के प्रमुख गांव या कस्बे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उदाहरणार्थ—जसरासर, नौहर, शेखसर के चीरे। पुराने नगरों व कस्बों के सांस्कृतिक व व्यापारिक महत्त्व को देखते हुए उनके नाम पर चीरो का नामकरण किया गया, जैसे—रीणी, नौहर के चीरे—सेन्स रिपोर्ट, बीकानेर, पृष्ठ १८(बी), सन् १६४४ ई०

३. घुमा रोकठ बही, वि० सं० १७५०/१६६३ ई०, न० ८८; घुमा माछ गृहकर या जिते प्रत्येक गुनाड़ी से बगुल दिया जाता था। जहाँ चीरा रीणी की कुल भाषा २०८६६८॥) वार्षिक यो बड़ा चीरा गधीली की भाषा ४० १६४२॥) वार्षिक यो

था ।^१ चीरा महाजन व पूगल पूणतया पट्टा क्षत्र स निर्मित थ। अत व अपवाद थे। पट्टा क्षत्र को तभी चीरा स्तर प्रदान किया जाता था जब उसमें लगभग १०० गांव बसे होते थे ।^२

चीर का प्रशासन चानान के लिए दो तरह के अधिकारी नियुक्त होते थ जो अपने अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए भी एक दूसरे के सहयोगी कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करते थ । प्रथम वर्ग में एक तो वे अधिकारी आते थ जो अनुबन्ध वेतन पर चीरे में करो को वसूल करने के लिए समय समय पर भेजे जाते थे तथा दूसरे वे अधिकारी थ जो स्थायी रूप से वार्षिक वेतन पर नियुक्त किये जाते थे । द्वितीय वर्ग में वे स्थायी स्थानीय अधिकारी आते थे जिनकी स्थिति व वायकाल उनसे वशानुगत अधिकारों के आधार पर निर्धारित होता था ।^३ ये स्थानीय तत्त्व राज्य प्रशासन में घुन मिलकर उसके अविभाज्य अंग बन गये थे ।

राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों का मुखिया चीरायत था हाकिम कहलाता था । अनुबन्ध वेतन वाले अधिकारी हुक्मदार के नाम से विख्यात थे । अधिकारशत से तीनों पद एक ही व्यक्ति को दे दिये जाते थे । तब ये अपना वेतन अलग अलग दायित्व के अनुसार पाते थे । इन पदों का मुख्य महायक दरोगा होता था जो अपनी पुनिस शक्तियों के प्रयोग से हुक्मदार को कर वसूली में सहयोग देता था तथा हाकिम व चीरायत के लिए धन में व्यवस्था रखता था । कमचारियों में लेखणियों मुख्य होते थ जो निर्धारित करा की आय व्यव का हिसाब वित्तार रखते थ । खजांची का मुमास्ता एकत्रित धन को खजाने में जमा करवाता था ।^४ चीरे के स्थानीय स्थायी अधिकारियों में गांव का चौधरी जमींदार व पटवारी मुख्य होते थे जो हुक्मदार को उसके दायित्वों की पूर्ति में पूण सहयोग देते थे । चौधरी गांव का मुखिया होता था । जमींदार नव स्थापित गांव का मुख्य स्थानीय

१ यह सम्भवतः इस कारण हुआ हो क्योंकि केन्द्रीय प्रशासन घालसा भूमि पर ही बिना किसी बाधा के सीधे नियन्त्रण की प्रशासनिक नीतियां लागू कर सकती थी ।

राज्य चीरे का मुख्य स्थान था चुनाव करते समय अपनी व्यापारिक मण्डियों व मार्गों का भी ध्यान रखता था । अनुबन्ध चीरी नोहर महाजन बीदासर जसरासर के कसब व गांव व्यापारिक मार्गों पर स्थित थ तथा यहां मण्डियां स्थापित थी ।—साबा बहीर्वा—रामपुरिया रिवाज स बीकानेर ।

२ परबाना बही वि० स० १७४६/१६६२ ई० ।

३ चीरे की बहिया न० २७ ३१ बीकानेर बहियात बीकानेर

४ चीरा नोहर से लेखे की बही वि० स० १७४६/१६६२ ई० न० २८ धान की चौपाई की बही वि० स० १८३६/१७८२ ई० रा० अ० बी०

अधिकारी होता था व 'पटवारी' का मुख्य दायित्व गांव की आय का ब्योरा रखना व सामान्य प्रशासन में सहयोग देना था।

परगना

चीरो के समान ही 'परगना' भी एक स्वतन्त्र प्रशासनिक इकाई था। परगनो का प्रशासनिक इकाई के रूप में पृथक् रूप से गठित होने के मुख्य कारण, ऐतिहासिक शक्तिशाली थी। परगना मुख्यतः वे क्षेत्र थे, जो बीकानेर शासकों को मुगल सम्राट द्वारा 'तनख्वाह जागीर' के रूप में प्राप्त हुए थे। ये बीकानेर 'बतन जागीर' की सीमाओं पर स्थित थे। मुख्य रूप से, ये 'परगने' भटनेर वेणीवाल, पूनया, सिवराण के क्षेत्र तथा फलीदी व हिसार के कुछ भाग भी थे। मुगलों के पतन के काल में, बीकानेर राज्य में इन्हें स्थायी रूप से सम्मिलित कर लिया गया था, लेकिन इनके नामों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। इन्हें किसी क्षेत्र में शामिल न किये जाने के कारण पृथक् प्रशासनिक इकाई के रूप में, इनका अस्तित्व बना रहा। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में, चीरो के कुछ क्षेत्रों को विभाजित करके 'परगनो' का नाम दिया गया था, फिर भी ये चीरो की अधीनस्थ इकाई नहीं बने। इस काल से ही परगने तहसील के नाम से जाने जाने लगे।

'परगनो' के प्रशासन का स्वरूप लगभग वैसा ही बना रहा, जैसा कि मुगल नियन्त्रण के समय था। केवल उनके कुछ अधिकारियों के नामों में परिवर्तन किया गया। राजस्व वसूली के लिए 'आमिल' के स्थान पर 'हुवलदार' कार्य करता था। 'अमीन' भूमि-मापन व कर-निर्धारण के दायित्वों को निभाता था और 'पोतदार' करों को जमा करता था। इन परगनो में कानून व व्यवस्था के स्थापित करने के लिए 'फौजदार' की नियुक्ति की जाती थी। इनकी सहायता के लिए गांवों के स्थानीय अधिकारी 'बीघरी', 'पटवारी' व 'कानूनगो' सदैव तत्पर

१. खालसा गांव के क्षेत्रों की बही, वि० सं० १७२६/१९६६ ई०, न० ६५; देव रे खालसा बही, वि० सं० १७४०/१९८३ ई०, न० ६७—बीकानेर बहिषात
२. राज्य के इतिहास ग्रन्थों में परगनो को चीरो की छोटी इकाई माना गया है। इन परगनो का नाम बदलकर नाम तहसील रखा गया था, और ये निजामत के अन्तर्गत बने थे। उसी प्रभाव में इन्हें चीरो की इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया था।—पाउलेट पृष्ठ १०२, सोहनवाल—तवारिख, पृष्ठ २५-२७
३. राजा सूरजसिंह रे जागीर की विवरण, पृष्ठ ६०-६१, महाराजा अनूपसिंहजी रे मुस्तबक रे तख्त की विवरण, पृष्ठ ८८-९० फुटकर बात
४. देशदर्पण, पृष्ठ १२०-२२, न० १८६/८—अ० सं० प० बी०
५. पाउलेट, पृष्ठ १०२; सोहनवाल—तवारिख, पृष्ठ २५-२७

रहते थे।^१ इस प्रकार इन इकाइयों में मुगल प्रभाव पूर्णतया छाया रहा।

अन्य प्रशासनिक केन्द्र

चौरा क्षेत्र में मण्डी व बाबा स्वतंत्र राजस्व तथा प्रशासनिक केन्द्र के रूप में स्थापित किये गये जिन पर चौरा अधिकारियों का कोई नियन्त्रण नहीं होता था।

मण्डी

राज्य में सीमा कर व व्यापारिक कर की वसूली के लिए सीमा पर स्थित गावों में तथा व्यापारिक मार्गों के केन्द्रों पर मण्डिया स्थापित की थी। राजधानी की सदर मण्डी राज्य की मुख्य मण्डी थी और उसकी आय भी राज्य की तुलना में अधिक थी। अन्य मण्डियों में रीणी मोहर अनुपगढ़ राजगढ़ जूनाकरणसर बीदासर महाजन गंधीली व भूमल की मण्डिया प्रसिद्ध थी। भटनेर का राज्य का हमायी भाग बन जाने पर उत्तरी पश्चिमी भारत की यह प्रसिद्ध मण्डी भी राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गयी। इन मण्डियों की सहायक मण्डिया भी थी जो कसबों के आसपास के गावों में स्थित होती थी। उन्हें बाहरली चौकी^२ कहा जाता था।^३

इन मण्डियों का प्रशासनिक समूह इनके अलग अलग व्यापारिक महत्व को देखते हुए किया गया था। साधारणतया प्रत्येक मण्डी का मुख्य प्रशासनिक

१ परगनों की जमाबोड वही वि० सं० १७२६ ५०/१६६६ १६६३ ई० न० ६६ बही समन र चिठीया र खतावती वि० सं० १८६६ ७०/१८१२ १३ ई० न० ३६/२ रामपुरिया रिवाज स बीकानेर पी० सरन—बी प्रोविन्सियल गवर्नमेण्ट आफ दी मयल्स पृष्ठ १६७ ६२ एशिया १६७३

२ मुख्य-मध्य नगर व कस्ब के बाहर व्यापारिक मार्गों पर ये चौकिया स्थापित होती थी जब व्यापारी नगर या कस्ब में आकर बाहर से ही सीधे मार्ग पर भाग बंद जाते थे तो इन चौकियों पर कर जमा करते थे—बही समन र चिठीया र खतावती सं० १८६६ ७०/१८१२ १३ (पूर्व)

३ मण्डी र जमा घरण री बही वि० सं० १७८३/१७२६ ई० न० ७८ वि० सं० १७६६/१७४२ ई० न० ७६ वि० सं० १८०७/१७५० ई० न० ८०

मण्डी रीणी राजगढ़ मोहर व चुरू प० भारत के विरुषात व्यापारिक मार्ग दिल्ली भिबाना नागौर फलीदी या पाली-जहमदाबाद मार्ग पर स्थित थी। मण्डी रीणी मोहर भटनेर अनुपगढ़ प्रसिद्ध दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित थी। इसी प्रकार सिंध के साथ पूर्ण मण्डी व जूनाकरणसर मण्डी का महत्व था बीकानेर-जूनाकरणसर महाजन भटनेर व भटिण्डा एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग था—बी एस एल देवडा—सोशियो इकोनोमिक्स हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पृष्ठ ३६ ४५ जोधपुर १९८०

अधिकारी 'हुवलदार' होता था। उसका मुख्य सहायक 'दरोगा' था। दरोगा 'छोटी मण्डियो' व 'बाहरली चौकियो' पर, स्वतन्त्र रूप से भी नियुक्त किया जाता था।

'थीमण्डो' में जमाची 'गुमास्ता' भी नियुक्त होता था जो खजाने का कार्य समालता था। अधीनस्थ कर्मचारियों में लेश्चणिये मुख्य थे, जो आय आदि का ब्योरा रखते थे।^१

कस्बों की मण्डियों को 'मुकाते' (ठेके) पर चढ़ा देने की प्रथा पर्याप्त प्रचलित थी। ऐसी अवस्था में 'मुकाती' (ठेकेदार) कस्बों की बसूली करता था। तब वह राज्य द्वारा पूर्वनियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन देता था।^२ सभी अधिकारी व कर्मचारी 'महीनदार' होते थे।^३ इसके अलावा 'जमात' (बुगीकर) की बसूली के लिए, प्रत्येक गांव में एक कर्मचारी नियुक्त होता था, जो 'भोला-वणिमा' कहलाता था।^४

थाणा

राज्य की बाह्य सुरक्षा व आन्तरिक व्यवस्था के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों व मुख्य नगरों, कस्बों व गांवों और उपद्रवी स्थानों पर सैनिक, अर्द्धसैनिक व पुलिस स्तर के सुरक्षा केन्द्र स्थापित किये गये थे, जो 'थाणे' कहलाते थे। प्रत्येक घेरे में एक मुख्य थाणा अवश्य होता था। 'चीरे' की स्थिति व उसकी समस्याओं को देखकर, थाणों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती थी। इन 'थाणों' की सहायक चौकिया भी होती थी। १८वीं शताब्दी में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि प्रत्येक 'मण्डो' के साथ 'थाणा' अवश्य स्थापित हो।^५ इन 'थाणों' के अधिकारी सीधे केन्द्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे।^६

इन थाणों का दोहरा दायित्व था। वे सामरिक व नागरिक दोनों दायित्वों का निर्वहन करने थे। बाह्य आक्रमणों, आन्तरिक विद्रोहों को रोकने व दमन

१. मण्डो रे जमा खरची बही (उपर्युक्त), सोहनसाल—अ. रा. बी.—पृष्ठ २४२-४३

२. कामरा की बही, वि० सं० १८४०/१७८३ ई० न० ७, पृष्ठ ४४-४७, १६-१८

३. मण्डो रे जमा खर्च की बही, वि० सं० १७०१/१६४४ ई०, न० ७४—बोरोनर बहिषात महीनदार का वात्सर्व मासिक वेतन पाने वालों से है।

४. बागदों की बही, वि० सं० १८३८/१७८१, न० १, पृष्ठ ३३, वि० सं० १८६८/१८११ ई०, न० १८, पृष्ठ ३६

५. साया बही दोहर, वि० सं० १८२२/१७६३ ई० न० १, साबा बही रोणी, वि० सं० १८४५/१७६८ ई०, न० ८, सं० रा० घ० बी०

६. बागदों की बही, सं० १८२७, न० ३, पृष्ठ ४२; सं० १८७४, न० २३, पृष्ठ ४१

करने के साथ-साथ साधारण अपराधों की रोकथाम भी करते थे। मण्डियों में वसूल की गयी 'जभात' को थाणों में सुरक्षित रखा जाता था। थाणों के अधिकारी फरोही के अन्तर्गत 'गुनेहगारी' व 'चामचोरी' जैसे दण्ड कर भी वसूल करते थे।^१

साधारणतया, प्रत्येक थाणे में एक मुख्य अधिकारी के रूप में 'हुवलदार' व उसके सहयोगी के रूप में 'दरोगा', 'पोतदार' की नियुक्ति की जाती थी। इन अधिकारियों के अपने अधीनस्थ 'गुमास्ते' व चाकर ताबीनदार' होते थे। अधीनस्थ कर्मचारियों में 'कोतवाल', 'तोपची', 'सिपाही' मुख्य थे। मुख्य सैनिक केन्द्रों में 'हुवलदार' के स्थान पर 'फौजदार' की नियुक्ति की जाती थी।^२ महाराजा सूरतसिंह के काल में ठाकुरों के विद्रोहों को देखकर, प्रत्येक थाणे में कम से कम १५ बन्दूकचियों की टुकड़ी रखी गयी थी। इसके अलावा 'सीरबन्धियों' की नियुक्ति भी हुई थी।^३

स्थानीय प्रशासनिक सेवाएँ

राज्य की प्रशासनिक सेवाएँ चीरो, परगनों और उनमें स्थित विभिन्न मण्डियों व थाणों के स्तर पर बढी हुई थी। ये सब प्रशासनिक सेवाएँ, अपने-अपने कार्य क्षेत्र में, एक-दूसरे से स्वतन्त्र थी। इनके सम्बन्धित अधिकारी एक-दूसरे के अधिकार-निरीक्षण में नहीं आते थे। वे स्वतन्त्र रूप से शासक द्वारा सौंपे गए दायित्वों को निभाते थे।^४

अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों की सेवाओं में कोई श्रेणीबद्ध संगठन नहीं था। एक इकाई की प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत, विभिन्न स्थलों पर

१ सावा बही धनूपगढ़, वि० सं० १७१३/१९६९ ई०, न० १, सावा बही मौहूर, वि० सं० १८२२/१७६५ ई०, न० १ सावा बही रोणी वि० सं० १८५५/१९६८ ई०, न० ८, कागदों की बही, वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ १३९, (राज्य के कानूनों व आदेशों का पालन करने पर आर्थिक दण्ड गुनेहगारी ने नाम से लगाया जाता था। चामचोरी व्याभिचारिता को दण्डित करने वाला कर था। ये कर तथा साधारण अपराधों पर लगाये गये दण्ड फरोही के नाम से थाण में जमा होते थे।)

२ बही

३ सीरबन्धी बही, वि० सं० १८१०/१७५३ ई०, न० १६४, बीरानेर बहिषात, कागदों की बही, वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ १३६। सीरबन्धी वे सैनिक-सरदार थे जो राजा द्वारा मासिक वेतन पर राज्य के बाहर से निवृत्त किये गये थे। ये एक तरह से व्यवसायिक सैनिक थे। राजा जब इन्हें सम्मानित करने के लिये पगड़ी बाघता या प्रदान करता था, तब ये सीरबन्धी कहलाने लगते थे।

४ कागदों की बही—डूबाला कागद, वि० सं० १८११/१७५४ ई०, न० १, पृष्ठ १४, वि० सं० १८३८/१७८१ ई०, न० ४ पृष्ठ १८, वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११ पृष्ठ १४

नियुक्त अधिकारी भी, एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त थे। कोई किसी के अधीनस्थ नहीं था। उनके पद का सम्मान व्यक्ति की योग्यता व नियुक्ति के स्थान व महत्त्व पर आधारित था। चूंकि इन पदों के सेवाकाल में कोई निश्चितता व स्थायित्व नहीं था; अतः उनमें श्रेणीबद्ध संगठन का विकास नहीं हुआ।^१ सभी अधिकारी अपने पद पर बने रहने के लिए शासक व दीवान की कृपा पर निर्भर थे।^१

वैसे प्रत्येक मुख्य अधिकारी के साथ उसके सहयोगी व अधीनस्थ कर्मचारी होते थे पर उनकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा होती थी। वे अपने सेवाकाल में निर्देश अवश्य अपने मुख्य अधिकारी से प्राप्त करते थे पर उत्तरदायी वे केन्द्रीय सरकार के प्रति ही होते थे। लेकिन एक सेवा में पारस्परिक सहयोग से कार्य करना, राज्य सरकार की पहली शर्त होती थी।^१

स्थानीय प्रशासनिक सेवाएँ, भूस्वरूप से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं का ही एक विस्तृत भाग थी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य का क्षेत्रीय विभाजन करके सेवाओं के वितरण के स्थान पर, सेवाओं को विभक्त करके विभिन्न इकाइयों में बांट दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था तत्कालीन आवश्यकताओं से प्रभावित थी। यह एक सरल योजना थी, जो किसी मुनियोजित विचारधारा का परिणाम नहीं मालूम होती। समय-समय पर इसकी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया; किन्तु ऐसा करते समय यह ध्यान अधिक रखा गया कि उन परिवर्तनों से केन्द्र शक्ति में निरन्तर वृद्धि हो।^१

स्थानीय प्रशासनिक सेवाओं को पूरा करने के लिए दो विभिन्न लेकिन समानान्तर प्रणालियाँ अपनायी, जिन्हें 'हुवाला सीपा'^२ तथा 'मुकाता व्यवस्था'^३ की संज्ञा दी गयी।

१ कागदा की बही—हुवाला कागद, वि० सं० १८११/१७३४ ई०, न० १, पृष्ठ १-४; वि० सं० १८३८/१७८१ ई०, न० ४, पृष्ठ १-८; वि० सं० १८५७-१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ १-४

२ महाराना भनूपतिप्रसादी रो आनंदराम नायर दै नाम परवानो—वि० सं० १७४६/१६८२ ई० (पूर्व)

३. कागदों की बही, वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ६, पृष्ठ ४१, ५२, ८३, ८६

४. आर्याध्यान कल्पद्रुम, पृष्ठ २२६-२८, १८०/२

५ 'हुवाला' शब्द: 'हवाल' शब्द से बना हुआ है। हुवालाना सीपा का अर्थ यहाँ किसी को सुपुर्द या हस्तान्तरण कर देने से था।

६ मुकाता का तात्पर्य यहाँ उस अल्पकालीन अनुबन्ध से है; जिसमें एक दल अपने सम्पत्ति लाभों का प्रयोग किसी अन्य को निर्धारित राशि लेकर प्राप्त करता है। सम्भवतः यह शब्द दिल्ली सल्तनत की इक्ता के मुख्य अधिकारी मुक्ता से निकला हुआ है और अपने अर्थ में राज्य के क्षेत्र में प्रयोग किया गया।

हुवाला—सौंपा प्रणाली

प्रशासनिक सेवा में यह सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली थी। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ इसी प्रणाली के अन्तर्गत की गयी थी। इसके अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को सौंपी गई सेवा को, सनद में उल्लिखित क्षेत्र की इकाई में, निर्धारित समय में पूरा करना होता था।^१ 'हुवाला—सौंपा प्रणाली' अपने सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन माप दण्ड को लेकर दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है। प्रथम श्रेणी के अधिकारी, निश्चित समय में निर्धारित कार्य को पूरा करने के बदले, वेतन के रूप में एक निश्चित कुल भाग 'रोजगार रकम' पाते थे।^२ द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, अपनी सेवा के बदले प्रत्येक महीने में, निर्धारित वेतन प्राप्त करते थे।^३

प्रथम श्रेणी की 'हुवाला—सौंपा' प्रणाली चौराब परगना में प्रचलित थी। इस व्यवस्था का मुख्य अधिकारी 'हुवलदार' होना था, जो सौंपे गये क्षेत्र में निर्धारित विभिन्न करों की वसूली करता था।^४ लेकिन सभी निर्धारित कर एक 'हुवलदार' ही वसूल नहीं करता था। प्रत्येक चौरा में विभिन्न करों की वसूली के लिये अलग-अलग 'हुवलदार' थे।^५ एक 'हुवलदार' को एक चौरा में, दो करों

१. हुवारो रे सेवे रो बहो, बि० सं० १७०४/१९४७ ई०, न० १३०, कागदों की बही, बि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृष्ठ ८-१०, हुवाला सौंपा प्रणाली को समझने के लिए प्रत्येक कागदों की बही का हुवाला कागद बहुत सहायक है।

अधिकारी की नियुक्ति की मूचना सम्बन्धित गांव के निवाशियों के पास भी भज दी जाती थी।

हुवाला नु हुवाला सौंपा तरी विवर—

मुत्ताद्वार रे जीरे रे सोबा रो भोगता सोघरीया रेत समसुता जोम्य तथा बुबो देख प्रठ मुदघटे ने सीयो छे मु पुकाय देवा काम दोनदारी मु करखो छूट दरदार ने कागद मु भर ही जहा नाबो दरदार मन्नाय देवी म जोधमल कोठारी कोठारी मोहण नु सोपावो छे मु इतरा भर सोजवी,

१३१) रोजगार—सरफ सदामद भरदीने छे मु भर सोजवी,

—कागदों की बही, भादुवा मुद १०, बि० सं० १८२०/१६ सितम्बर, १७६३ ई०, न० २

२. कागदों की बही, बि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृष्ठ २-६
३. मन्ना रे जमा सरफ रो बहो, बि० सं० १७८३/१७२६ ई०, न० ७८, कागदों की बही सं० १८२०, न० ३, कागिद बही ६, १४ अक्टूबर, १७३० ई०
४. चौरा जमठगर सेवे रो बहो बि० सं० १७४८/१६६१ ई०, न० २७, बही हुनुव, बि० सं० १८०४/१७६७ ई०, हुनुव बहा न० १, सोकानेर, रा० रा० ब० बी०.
५. कागदों की बही, बि० सं० १८२०/१७३० ई०, न० ३, पृ० ३-४, भाद्र मुदि १२/ १ सितम्बर १७३० ई०

की वसूली के अधिकार भी दिये जाते थे व कभी-कभी एक कर को वसूल करने के लिए दो चीरे भी प्रदान किये जाते थे।^१ दो हुवलदार साथ मिलकर भी कार्य करते थे।^२ हुवलदारों को यह कार्य एक निश्चित समय में करना होता था व उनके आदेश-पत्र में 'रोजगार रकम' भी लिख दी जाती थी।^३ हुवलदार का प्रमुख सहायक 'दरोगा' था। वह भी निश्चित 'रोजगार रकम' पर हुवलदार के साथ कार्य करता था। इसके अलावा हुवलदार के अपने 'ताबीनदार' व 'गुमास्ते' होते थे।^४

द्वितीय श्रेणी को 'हुवाला—सीपा प्रणाली' मण्डी व थाणों में प्रचलित थी। मण्डियों की 'जगात' को वसूल करने के लिए हुवालदारों की नियुक्ति की जाती थी व थाणों के सामान्य प्रशासन-कार्य को पूरा करने का भार भी हुवलदारों पर छोड़ा जाता था।^५ राज्य की टकसाल को चासू रखने के लिए भी यही प्रणाली थी।^६ इस व्यवस्था के अन्तर्गत हुवलदार व उसका सहायक दरोगा व अधीनस्थ कर्मचारी सभी महीनदार होते थे। इनका सेवाकाल पूर्व निर्धारित नहीं होता था।^७ राजस्व छाते की आय के सभी मदों को पूरा करने के लिए हुवाला—सीपा प्रशासन में लोकप्रिय थी। यहाँ तक कि घास कटाई का दायित्व व निरीक्षण भी इसी व्यवस्था के अन्तर्गत था।^८

इन प्रणाली के अन्तर्गत हुवलदार केवल निर्धारित करों को वसूल करता था। कर निर्धारण में उसका कोई हाथ नहीं होता था। केन्द्र में स्थित 'दफ्तर का हुवलदार' चीरो में नियुक्त हुवलदारों को निर्धारित करों की रकम की सूची भेजता था।^९ राज्य के जिन गावों में 'जमाबदो' पहले से की हुई होती थी, उसी के आधार पर वे वसूली करते थे।^{१०} जिन क्षेत्रों में 'जमाबदो' नहीं थी, वहाँ हुवलदार 'गुवाडियों' (परिवारों) की गणना करके रकम वसूल करता था। ऐसी

१ कागदों की बही, वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृ० १-७

२ वही

३ बागदों की बही वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृष्ठ १-३.

४ हुजरा रो रे मेखे रो बहे, वि० सं० १७०४/१६४७ ई०, न० १३०

५ मण्डो रे जमा धरब की बही, वि० सं० १७०१/१६४४ ई० न० ७१, साथी वही अनुपमङ्ग वि० सं० १७१३/१६२६-२७ ई०, न० २०/१—रामपुरिया टिकाई, बीकानेर

६ कागदों की बही, बंसाय मुदि ३, वि० सं० १८२०/१८ अगस्त, १७६३ ई०, न० २

७ साथी वही अनुपमङ्ग, वि० सं० १७१३-१४/१६२६-२७ ई०, न० १, वही साथी मण्डी सदर, वि० सं० १७२२/१७२३ ई० न० १, रामपुरिया टिकाई, बीकानेर

८ वही

९ कागदों की बही, वि० सं० १८११/१७८४ ई०, न० ८, पृष्ठ ४१, वि० सं० १८६६/१८०८ ई०, न० १३, पृष्ठ ३७८

१० कागदों की बही, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, नम्बर ४, पृष्ठ ३२-४४

अवस्था में 'दफतन के हुवलदार' द्वारा प्रत्येक गुवाडी पर कर की दर पहले से से निर्धारित कर दी जाती थी।^१ बहुत कम ऐसा स्थान थे, जहाँ हुवलदार कर निर्धारण करके वसूली करता था। आपात्कालीन स्थिति में अवश्य ही उसके इस तरह के दायित्व बढ़ जाते थे।^२

'हुवाला—सौपा' की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह कर दाताओं की समृद्धि के प्रति उदासीन थी। इसके अन्तर्गत पूरी वसूली पर जोर दिया जाता था। हुवलदार को इस बात की जानकारी ही नहीं रहती थी कि कर दाता की स्थिति कैसी है? और नहीं उसके कर्तव्य में यह माना जाता था। प्राकृतिक विपदाओं के इस क्षेत्र में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि कर दाता किसी भी कर को देने की स्थिति में नहीं होता था और हुवलदार वहीं पटुब जाता था। हुवलदार को छूट देने का अधिकार भी नहीं था। कर दाता को छूट तभी प्राप्त होती थी, जब वह स्वयं या उसके कहने पर गांव का 'बीधरी' दरबार में जाकर प्रार्थना करता था। परन्तु यह सब होने से पूर्व हुवलदार अपना कर्तव्य निभा चुका होता था या तनाव की स्थिति में मर जाता था।^३ इससे करदाता व राज्य दोनों की आर्थिक क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता था। हुवलदार अपनी नौकरी के भविष्य के लिए अधिक सचेत रहने के कारण भी कर वसूली पर अधिक बल देता था क्योंकि ऐसा करने पर ही उसे अगले वर्ष नियुक्ति की आशा हो सकती थी।^४

इस प्रणाली की अन्य कमी यह थी, कि यह सुनियोजित व सुसंगठित नहीं थी। किसी भी आरात्कालीन स्थिति में यह टूट सकती थी। १८वीं शताब्दी में, जब राज्य बाहरी आक्रमणों व आन्तरिक विद्रोहों का शिकार बन गया तो, यह व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल पायी। अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति में गुराडिया इधर-उधर भागने लगी। परिणामस्वरूप गांव की जमाबन्दी भग हो

१ कागदों की बही, वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृष्ठ ६१-६७, माप बंदी १०, वि० सं० १८६१, २६ जनवरी, १८०१ ई०

२ भैया सग्रह—भैया नथमल का पत्र, पोप बंदी १०, वि० सं० १८६६, १ जनवरी, १८०६ ई०, चैत सुदी १३, वि० सं० १८६६, २६ मार्च, १८०६ ई०, चैत बंदी २, वि० सं० १८६६ १८ मार्च, १८१३ ई०

३ कागदों की बही, वि० सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ २७

४ कागदों की बही न० २१, २२ व २३ में हम सम्बन्ध में बहुत से लिखित व सनद कागद हैं

५ कागदों की बही, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १८, पृष्ठ १६, वि० सं० १८७२/१८१५ ई०, न० २१, पृष्ठ ४४-४८, भैया सग्रह—भैया नथमल के पत्र—पोप बंदी १०, वि० सं० १८६६, १ जनवरी, १८१० ई०, भादुवा बंदी ३, वि० सं० १८७३, २३ अगस्त, १८१५ ई० टाठ—पृष्ठ ११४३, ४५, ४७

स्थानीय-प्रशासन

गयी। हुबलदारो को कर-निर्धारण का दायित्व प्राप्त हो गया तथा उन्हें वसूली में मनमानी करने का अवसर भी मिल गया। इससे बिगड़ी हुई अवस्था में किसानों के कष्ट और बढ़ गये।

अव्यवस्था व अराजकता की स्थिति से निबटने के लिए राज्य की सैनिक भाग बढ़ गई थी, जिन्हें पूरा करने के लिए नये कर लगाये गये व पुराने करों की दरें बढ़ा दी गयी। हुबलदारो ने इन करों को बड़ी सख्ती से वसूल किया तो करों के दबाव के कारण, गुवाडियो में पलायन की प्रवृत्ति बढ़ गयी। राज्य के पट्टागत उन पर बढ़ाये गये करों को किसी भी दशा में देने के लिए तैयार न थे। गांव की गुवाडिया भी झूठी गणना करवाने लगी। कुछ गुवाडियो ने तो करों को देने से ही मना कर दिया। ऐसी अवस्था में, हुबलदार एक गांव से दूसरे गांव में, अपने खेमे गाँठते हुए निराशा व हताश घूमने लगे। इन परिस्थितियों में हुबलदारो ने अपना 'हुवाला' गांव के प्रभावशाली व समृद्ध व्यक्तियों को मुकाते पर सोप दिया। राज्य ने भी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं

१. कागदा की बही, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृष्ठ १, ७२, ६१, वि० सं० १८७३/१८१३ ई०, न० २१, पृष्ठ १०६, ११०, ११३; टॉड—पृष्ठ ११५६-६०, फेगन सेटलमेण्ट रिपोर्ट आफ बीकानेर, पृष्ठ १७, १८, पाउलेट पृष्ठ १०३
२. राज्य में प्रत्येक हल पर पढ़ने दो रुपये वसूल किए जाते थे, जो बढ़ाकर पाँच रुपये कर दिये गये। कछवाली माछ (रसाकर) की दर दो रुपया से बढ़ाकर दस रुपये कर दी गयी—कागदों की बही, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृष्ठ २६, ३५, ५६, वि० सं० १८२७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ ८१, ८६
३. भैंया सपह, पत्र चंत्त मुदी १३, वि० सं० १८६६, २६ मार्च, १८०६ ई०, कागदों की बही, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १८, पृष्ठ १६, वि० सं० १८७१/१८१४ ई०, न० २०, पृष्ठ २०, वि० सं० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृष्ठ १५, कागदों की बही न० १८, २० व २२ में इससे सम्बन्धित अनेक पत्र हैं
४. कागदों की बही, वि० सं० १८७१/१८१४ ई०, न० २०, पृष्ठ २१-२३, वि० सं० १८७२/१८१३ ई०, न० २१, पृष्ठ ६६-७१, १०३-१०८, १७३
५. भैंया सपह—पत्र—फाल्गुन बंदो ७, १८६१, २० फरवरी, १८०५ ई०, कागदों की बही वि० सं० १८७२/१८१५ ई०, न० २१, पृष्ठ ६६-७१
६. कागदा की बही, वि० सं० १८६७/१८१० ई०, न० १७, पृष्ठ ६, भैंया पत्र—फाल्गुन बंदो ७, १८७३/८ फरवरी, १८१७ ई०
७. भैंया सपह—पत्र—मार्च बंदो १०, वि० सं० १८६१, २५ जनवरी, १८०५ ई०; चंत्त मुदी १३; वि० सं० १८६६, २६ मार्च, १८०६, पोप बंदी ११, वि० सं० १८७३, १५ दिसम्बर, १८१६ ई०
८. हनुव बही, सं० १८५१/१७६४ ई०, अस्ता न० १ (बीकानेर), फेगन—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, बीकानेर, १८६४ ई०, पृ० १६

की पूर्ति हेतु हुवाला के स्थान पर मुकाता प्रणाली को प्रोत्साहित किया।^१ हुवाला प्रणाली को मुकाता के साथ-साथ राज्य की खतो पर उधार व सीरबधियों के वेतन की व्यवस्था से भी घनका लगा।^२ उन्हे गावों के विभिन्न बरा की आय सुपुर्द की जाने लगी। सैन्य अधिकारियों द्वारा 'हाकम' का कार्य करने पर दोहरे उत्तरदायित्व के कारण, सैनिक क्षमता व सामान्य प्रशासन की अवस्था दोषयुक्त हो गयी।

अधिकतर हुवलदार मुत्सद्दी-वर्ग में से चुने जाते थे।^३ हुवाला व्यवस्था के चौपट हो जाने से इनकी स्थिति की बहुत हानि पहुँची। पुराने मुत्सद्दी जीविका की तलाश में निराश होकर राज्य को छोड़कर भागने लगे।^४ वे ही मुत्सद्दी टिके रहे जिनकी आर्थिक स्थिति अन्य व्यवसायों के कारण उत्तम थी व अपनी समृद्धि के बल पर राज्य के घन की भाग को पूरा कर सकते थे।^५ इस प्रकार 'हुवाला सौपा' प्रणाली अपनी अन्तर्निहित कमजोरियों, हुवलदारों की लालची प्रवृत्तियों और राज्य की सैनिक व आर्थिक बढ़ती हुई माँगों के दबाव के सम्मुख प्रभावहीन होती गई।

मुकाता प्रणाली

राज्य में हुवाला प्रणाली की भांति राजस्व वसूली के लिए मुकाता-प्रणाली भी प्रचलित थी। प्रशासनिक क्षेत्र में यह प्रणाली १८वीं शताब्दी में बहुत

- १ इस बान में अर्थात् १८वीं शताब्दी के अन्तिम तीन दशकों में हम मुकाता प्रणाली के प्रचलन की अधिक सामग्री मिलती है—देखिये कागदों की बही नं० ३, ४, ९, ७१०, १२ के हुवाला व मुकाता कागद, जो बहियों के प्रारम्भ में ही है।
- २ खतो पर उधार का तात्पर्य यह था कि राज्य बज्र लेकर नरद रकम देने के स्थान पर लेनदारों को गावों का हासन भयवा कोई आय का मद वसूल करके पूर्ति करने को कह देता था। सीरबधियों अर्थात् खाद के सैनिकों को भी वेतन नकद न देने की स्थिति पर आद के विभिन्न मद वसूली द्वारा प्राप्त करने हेतु सुपुर्द कर देता था—कागदों की बही सं० १८५६/१८०२ ई०, कागद आश्विन बंदी १३, २५ सितम्बर, सं० १८६६/१८०६ ई०, पृष्ठ ३०२ ३०८, भैय्या सग्रह—फात्पुन सुदी २, सं० १८७३, २१ फरवरी १८१७ ई०, आश्विन बंदी ८ सं० १८८४, १३ सितम्बर, १८२७ ई०
- ३ उदाहरणार्थ १७६३ ई० में जो हुवाला सौपा गया, उसमें सभी वस्य जाति के वशानुगत मुत्सद्दी थे—कागदों की बही सं० १८२०/१७६३ ई०, नं० २, पृष्ठ १६
- ४ भैय्या सग्रह—भैय्या जठमल का पत्र, पोष बंदी १०, सं० १८६६, १ जनवरी, १८१० ई०
- ५ श्री एस एल देवदा—म्यूरोकेजी हन राजस्थान—पृष्ठ ३७-४१, कुछ मुत्सद्दियों ने आय के लिए वसूली के लिए ठके (मुकाता) लेना प्रारम्भ कर दिया—कागदों की बही सं० १८३१/१७७४ ई०, नं० ४ पृष्ठ ४, सं० १८६३/१८०८ ई०, नं० १६, पृष्ठ ६६

लोकप्रिय हुई। यह आधुनिक युग की ठेका-प्रणाली की भांति थी।^१ सबसे पहले इसे मण्डियों के प्रबन्ध में लागू किया गया।^२ बाद में, शनैः-शनैः, यह भू-राजस्व के क्षेत्र में भी लागू कर दी गई।^३

मुकाता-प्रणाली के द्वारा राज्य एक निश्चित अवधि के अनुबन्ध के अन्तर्गत अपनी आय के साधनों को किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी को अधिम अनुमानित राशि लेकर उपयोग के लिए प्रदान कर देता था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी किसी अन्य की तुलना में ऊँची रकम की बोली बोलकर राज्य की आय के साधनों की बमूली का एक निर्धारित अवधि के लिए, अधिकार प्राप्त कर लेता था। ऐसे व्यक्ति को 'मुकाती' तथा सम्पूर्ण पद्धति को 'मुकाता' प्रणाली कहते थे। 'मुकाती' व राज्य के बीच अधिकारों के हस्तांतरण का समझौता सामान्यतः एक से तीन वर्षों के काल के लिए होता था।^४ समझौते की शर्तें राज्य द्वारा 'मुकाती' को दिये जाने वाले पट्टे या सनद में लिखी होती थी। इस प्रपत्र में मुकाती का कार्य-काम, राज्य को चुकायी जाने वाली निर्धारित रकम व उसकी किराती की दरों का स्पष्ट उल्लेख होता था। 'मुकाती' को, 'मुकाता' लेने पर, जिन दायित्वों को निभाना पड़ता था, उनका विवरण भी उसमें अंकित किया जाता था। मुकातियों के लिए प्रमुख दायित्व थे—राज्य के नियुक्त अधिकारियों को वेतन देना, निर्धारित करों को बमूल करना तथा 'हाकमों की लाग' व 'लेखनीयों का लाजमा' आदि 'कर प्रदान करना'।^५ पट्टे की शर्तों के अनुसार राज्य व मुकाती

१. मुकाता प्रणाली भू-राजस्व-व्यवस्था में मुगलों की द्वारा-व्यवस्था की भांति थी, पूर्वी राजपूताना क्षेत्र में भी द्वारा-व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन पश्चिमी राजपूताना व हावेली में इसका नाम मुकाता प्रणाली था।

—एन० ए० मिह्रीकी—लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मण्डर बी मुगल्ल, पृ० ६२-६५, डॉ० एम० पी० गुप्ता—इलाहाबाद सिस्टम इन ईस्टर्न राजपूताना—मेडिकल इण्डिया मिसलेनी भाग-२, अलीगढ़ - डा० दिलशाह-लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्टर्न राजपूताना (अप्र० पब्लिश), पृ० १४०-४२; जे० एस० एल० देवड़ा—बीकानेर राज्य की मुकाता प्रणाली—राज० हिस्ट्री रावेल्, ज्वावर, १९७३

२. कागदा की बही, वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृ० ४-६

३. वही, वि० सं० १८२६/१८०२ ई०, न० १२, पृ० २-८

४. वही

५. कागदों की बहियों में हज़ा अधिकतर मुकाता प्रणाली से सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक बही हवाला व मुकाता कागदों से ही प्रारम्भ होती है।

राज्य द्वारा मुकाती को जो पट्टा प्रदान किया जाता था उसमें समझौते का विवरण इस प्रकार होता था—कागदा की बही, मार्गशीर्ष बदि १५; वि० सं० १८२७, १७ नवम्बर, १७७०, न० ३; हाकमों की लाग का तात्पर्य यहाँ चौरा, मण्डों व बाणा के हुबलदारों को उनके दायित्वों के बदले दी जाने वाली राशि से है। लेखनीयों का लाजमा वा तात्पर्य राज्य के लिपिका के इस कार्य में हुए परिश्रम के बदले राशि से है।

के बीच निर्धारित समय के पहले ही अगर कोई अन्य व्यक्ति ज्यादा रकम देकर मुकाता लेन को तैयार हो जाता था, तो पुराने मुकाती का मुकाता रद्द हो जाता था। नया मुकाती, पुराने मुकाती की उसकी सेवा के बदले एक निर्धारित 'रकम रोजगार' के रूप में चुकाता था तथा साथ में उसके द्वारा उठाये गये प्रशासनिक खर्चों को चुकाने के लिए लागत खर्च भी देता था। नये मुकाती के पट्टे में भी इसी प्रकार की शर्तें जुड़ी होती थी।^१ मुकाती इस प्रकार, अपने कार्यकाल के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाता था। परिणामस्वरूप, उसकी मुकाता क्षेत्र में आय के साधनों के विकास में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती थी।

साधारणतया एक ही व्यक्ति को मुकाती के अधिकार दिए गये थे। लेकिन दो व्यक्ति भी मिलकर मुकाता-अधिकार प्राप्त कर सकते थे।^२ अगर मुकाती, पट्टायत या हजुरी होता था तो उसके साथ निर्धारित समय का समझौता बीच में रद्द नहीं किया जाता था।^३

मुकाती को राज्य की तरफ से स्पष्ट निर्देश मिलते थे कि वह राज्य द्वारा निर्धारित दरो पर करो की वसूली करेगा। उतम वृद्धि करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगा।^४ गाँवों में मुकाती के अधिकार केवल कर वसूली तक ही सीमित थे,^५ क्योंकि प्रशासन यह नहीं चाहता था कि मुकाती, पट्टायतो जैसे स्वार्थ प्रदत्त क्षेत्र में पनप ले। मुकाती से यह आशा की जाती थी कि वह प्रदत्त क्षेत्र की आबादी बढ़ायेगा एवं विपत्ति काल में प्रशासन द्वारा 'रैत'^६ को दी गयी छूट का पालन करेगा।^७

मुकाता प्रणाली द्वारा अपनी आय के साधनों को ठेके पर चढ़ाकर राज्य एक पूर्व-नियोजित व अनुमानित आय की आशा करता था। मुकाती की अग्रिम राशि उस इस दिशा में आश्वस्त किया रखती थी। राज्य में उत्पादन के क्षेत्र इतने अधिक नहीं थे कि जिनके बल पर व्यावसायिक जगत में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती और सरकार उसका लाभ उठाती। अतः सरकार ने मुकाता-प्रणाली द्वारा आय

१ कागदो की बही, पीप सुदि ८, स० १८२७, २५ दिसम्बर, १७७० ई०, न० ३

२ वही

३ हामन वही श्री राजपट्ट फूनीयो रे परवर्न रो, वि० स० १७४६/१६६२ ई०, न० ६, कागदो की बही, वि० स० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ ३१

४ वही

५ कागदो की बही वि० स० १८२७/१७७० ई०, न० ३ पृष्ठ ३१, वि० स० १८२४/१७६७ ई०, न० १० पृष्ठ ७१, ७४, ७६

६ रैयत

७ कागदो की बही वि० स० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृष्ठ २२, वि० स० १८४०/१७८२ ई०, न० ७ पृष्ठ २१, वि० स० १८२७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ ८४

के स्रोतों में व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता को बढ़ाकर राज्य में व्यापारिक गतिविधियाँ में वृद्धि की चेष्टा की थी। इस कारण सरकार ने सर्वप्रथम उन्हीं शक्ती में इस लागू किया, जहाँ आय के साधन निश्चित नहीं थे तथा आय में घट-बढ़ होती रहती थी। मण्डिया की 'जगात' (सीमा शुल्क व चुगी कर) की आय सबसे अधिक थी। अतः राज्य ने श्री मण्डी को छोड़कर अन्य सभी मण्डियों में इस प्रचलित कर दिया।^१ व्यापारियों ने भी इस शक्ती में रुचि दिखाई और धीरे धीरे यह प्रथा इतनी लोकप्रिय हुई कि सभी छोटी मोटी मण्डियाँ इस प्रणाली के अन्तर्गत आ गयीं। कालान्तर में स्थिति यह हो गई कि मण्डियों के मुकाती शीघ्र बदलने लग। ऐसे भी अवसर आय कि एक मुकाती अपने मुकात अधिकारों को एक महीने से अधिक नहीं रख पाया और उस हटना पड़ा।^२ प्रतिद्वन्द्विता के फलस्वरूप मुकात की राशि बढ़ने लगी। सन् १७७० ई० में रीणी चौकी की जगात का मुकाता ८,००० रु० वार्षिक था। सन् १७८२ ई० तक बढ़कर वह १२,६३३ रु० तक पहुँच गया। अन्य मण्डियों की भी यही दशा थी।^३ इस वृद्धि के पीछे धीकानर में व्यापारिक मार्गों की सुविधा थी, क्योंकि राज्य के पड़ोसी क्षेत्रों में मराठा आक्रमणों का आतंक छाया हुआ था।

१८वीं शताब्दी में यह प्रथा मण्डियों के अलावा अन्य राजस्व क्षेत्रों में प्रचलित होने लगी। हुवाला व्यवस्था में उत्पन्न अव्यवस्था ने मुकाता प्रणाली को भी राजस्व प्रशासन में लोकप्रिय बना दिया। बीरों के अनवरत बरों की वसूली-मुकाते पर जान लगी।^४ राज्य की समस्त खानों इसी प्रथा के अन्तर्गत उठाई जान लगी।^५ यहाँ तक कि लक्षण कार्य भी मुकात पर होने लगा।^६

वास्तव में, १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विकट राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न प्रशासनिक अव्यवस्था में वातावरण में आर्थिक सुरक्षा तथा बढ़ती हुई सैनिक मांगों की पूर्ति हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध होने के लालच ने ही मुकाता-प्रणाली को भू-राजस्व वसूली के क्षेत्र में भी अधिक प्रचलित कर दिया। प्रशासन

१ श्री मण्डी में राज्य की तरफ से हुक्मद्वारा नियुक्त होता था। मण्डी के साहूकारों की वही, वि० सं० १७२६/१६६६ ई० न० २३२

२ बागदों की वही मासशीय मुद्रि १२ वि० सं० १८२७ २६ नवम्बर १७७०, वार्षिक बदि १० वि० सं० १८३६ ३१ अक्टूबर १७८२ पीप बदि १०, वि० सं० १८३६, २६ दिसम्बर १७८२ ई०

३ वही

४ शासन वही राजबंद के पुनीया परगने के लेखों की वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, न० ६, —बागदों की वही वार्षिक बदि १२ वि० सं० १८३४, १७ अक्टूबर १७६७ ई०, न० १०

५ कागदा की वही—ज्येष्ठ मुद्रि ३ १८४०, ३ जून १७८३ ई०

६ वही—सं० १८६३/१८०६ ई०, न० १४, पृ० ४-६

‘मुकाती’ से प्राप्त राशि के बल पर एक बार खर्चों की व्यवस्था जुटाकर निश्चित हो जाता था और सम्भवतः ‘लहणायतो’ या ‘बोहरो’ से कुछ समय के लिये ऋण मागने व उसके ब्याज के दबाव से बच जाता था।^१ भू-राजस्व वसूली प्रयोजन हेतु ‘मुकाता’ प्रणाली १७वीं शताब्दी में भी अपने अस्तित्व में थी, जब शासक अपने सैनिक अधिकारियों को मुगलों से प्राप्त जागीरों में उनकी सेवा के बदले मुकाते के रूप में गांव प्रदान करता था।^२ लेकिन यह मुकाता सैनिक-सेवा व दायित्व के बदले गांव की आय से प्रदान किया जाता था तथा मुकाती मुगल जागीरदारी व्यवस्था (बूहनर रूप में) की भांति अपने गांव या क्षेत्र का प्रशासन भी सभालता था।^३ १८वीं शताब्दी में मुकाती सैनिक अधिकारियों के स्थान पर अन्य अधिक होने लगे। ये नये मुकाती दायित्व व सेवा के स्थान पर ठेका प्रणाली की भांति ऊंची बोली बोलकर कर वसूली से मुकाता प्राप्त करने लगे। अब भी सैनिक अधिकारी मुकाती के रूप में रहे परन्तु उनकी सख्या कम थी और वे पुरानी प्रथा के अनुसार ही अपनी सैनिक या प्रशासनिक सेवा के बल पर ही मुकाता प्राप्त करते रहे।^४ भू-राजस्व वसूली में मुकाता गांव या क्षेत्र में पूर्व ‘जमाबंदी’ के आधार पर मुकाती के साथ को जोड़कर दिया जाता था।^५ किसी एक कर का मुकाता देने पर ‘दपतर का हुबलदार’ कर की दर पहले ही निर्धारित कर देता था।^६ यह मुकाता भी एक से तीन वर्ष के बीच अस्तित्व में रहता था।^७

मुकाता प्रणाली राजस्व-प्रशासन में व्यवस्था लाने के लिये एक सही समाधान नहीं थी। यह हुवाला प्रणाली की असंगतियों को दूर करने के स्थान पर उसे बंध रूप देने वाली व्यवस्था थी। हुबलदार राज-प्रतिनिधि होने के नियक्षण

१ राज्य में घाय के साधनों की कमी व खर्चों में वृद्धि के फलस्वरूप बजट में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ, उसकी पूर्ति को सदैव ऋण की सहायता से ही दूर किया गया। मुकाती की अग्रिम राशि ने उन्हें इस दिशा में कुछ राहत दी। राबले खरब की बही स० १८०५/१७४८ ई०, न० २१३—बीकानेर बहिषात, रा० रा० अ० बी०, कागदों की बही न० १, सनदी वाकद कार्तिक बदि ३, १८५७, ८ अक्टूबर, १८०० ई०, जमा खरब की बही न० १८६६/१८०६ ई०, मेय्या सग्रह, बीकानेर

२ परगना रँ जमा जोड दी बही—न० ६६, स० १७२६-५०/१६६६/१६६३ ई०, बीकानेरी बहिषात—इसमें परगनों के गावा का विवरण देखिए

३. बही

४ कागदों की बही—स १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृ० २५

५ कागदों की बही—न० ७, कार्तिक बदि ७, १८४०, १७ अक्टूबर, १७८३ ई०

६ मेय्या सग्रह—पत्र आश्विन सुदि १०, १८७२ ई०, १२ अक्टूबर १८१५ ई०

७ कागदों की बही, स० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृ० २५, न० ७, कार्तिक बदि ७, १८४०, १७ अक्टूबर, १७८३ ई०

से मुक्त होकर मुकाती के रूप में अपने काय क्षेत्र में स्वेच्छापूर्वक आचरण के द्वारा प्रशासन व प्रजा के हितों को सुविधा से चोट पहुँचा सकता था। जिस पूर्व-नियोजित आय की आशा से यह प्रणाली प्रशासन में प्रचलित हुई थी, वह अव्यवस्था के बातावरण में 'राज' व 'रैत' के स्थान पर मुकाती की ही अधिक लाभ दे सकती थी। इस प्रणाली को मुचारू रूप से चलाने के लिए सदैव निरीक्षण की आवश्यकता थी, जो जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत यह प्रणाली मूल राज्य क्षेत्र में लागू की गई थी, के अन्तर्गत सम्भव नहीं थी। कुछ समय तक राज्य व मुकाती दोनों को निर्धारित आय प्राप्त होनी रही, परंतु मुकाती क्षेत्र में, राज्य में हुआ 'राजनैतिक' अवस्था तथा मुकाती के सालाना के परिणाम-स्वरूप गुवाडियो के पलायन से निर्धारित आय गिरने लगी।^१ मुकाती प्रशासन पर समझौते की रकम कम करने पर दबाव डालने लगे।^२ इस प्रकार राज्य की इससे बाधित लाभ न मिल सके, बल्कि मुकाता प्रणाली से मुगलबाल में गठित राजस्व व्यवस्था को धक्का लगा।

मुकाती द्वारा दरो में वृद्धि करने पर चौधरी शिकायत कर सकता था, परन्तु ऐसे अवसरों पर जब मुकाती और चौधरी के बीच मिलीभगत हो जाती थी तो स्थिति दुष्परिणामों से वंचित नहीं हो पाती थी।^३ फिर मुकाती अधिकतर स्वयं मुरसदा वगैरे के अथवा उनके सम्बन्धी होते थे, जिनके कारण प्रशासनिक क्षेत्र में, उनका पूरा प्रभाव रहता था।^४ मुकाती पर बबन एक ही नियन्त्रण होता था कि वह गुवाडिया व भाग जान से अपने मुकात पर लगी रकम वसूल नहीं कर पाता था। राज्य द्वारा उम निर्देश प्राप्त होते थे कि वह अपने क्षेत्र में आबादी बढ़ाने का प्रयत्न करे।^५ गुवाडिया की संख्या में वृद्धि से, उसकी आय में भी वृद्धि की पूरी संभावना रहती थी। परन्तु १८वीं शताब्दी के अन्त में बिद्रोहों व लूटमार के कारण गुवाडियो का पलायन से, मुकाती की यह आशा भी

१ जी० एम० एन० देवड़ा—बाकानर राज्य की मुकाता प्रणाली, राज० हिस्ट्री कायस भ्यावर, १९७३

२ भया सप्रह-पत्र चंड मुदि १३ वि० सं० १८९९, २६ मार्च, १८०२ ई०, बागदा की बही, वि० सं० १८७२/१८९५ ई० न० २१, पृ० १२२-२४

३ भया सप्रह—पत्र, माछीब बदि १३, वि० सं० १८७४, अक्टूबर, १८१७ ई०, पृ०—सेटलमेण्ट रिपोर्ट बाकानर पृ० १४

४ फगन—सेटलमेण्ट रिपोर्ट पृ० १४

५ बागदा की बहियों में हुबाना व मुकाता कायद में जो नाम आये हैं, उनकी पट्टा बहियों में मुरसदियों के नामों के साथ तुलना करने पर यह बात विदित होती है। उदाहरणार्थ परवाना बही न० २ व बागदा की बही न० १०

६ कायदा की बही, वि० सं० १८२०/१७६३ ई० न० २, पृ० ३८

संभव नहीं थी। वेचन करा म वही हुई दर स लाभ ही उसही भूगत्तणा थी।

१८वीं शताब्दी के अन्त में मुकाना व्यवस्था को राजस्व प्रशासन में वित्तीय समस्याओं के हल के लिए 'राय' की गई कामचलाऊ व्यवस्थाओं से भी धक्का पहुँचा, जब 'सीरवन्धियों' का बतन तथा कज के खेतों की रकक खजाने से न चुकाकर सीधे करो की आय की वसूली के साथ जोड़ दी गयी तथा सीरवन्धी व कजदार अपना बतन स्वयं धमूली करवा प्राप्त करने लग्य थे।^१ बंस भी मुकाना प्रणाली ने बीकानेर राज्य की भू राजस्व व्यवस्था पर वही दुष्परिणाम छोड़ा, जैसी कि शिकायत भुगन इतिहासकार ग्राफीखा ने सम्राट फर्ग्युसियर के काल में इजारा व्यवस्था को लेकर मुगल प्रशासन पर पड़े परिणामों को लेकर की है।^२

नगर प्रशासन

१७वीं व १८वीं शताब्दी में राज्य में राजधानी बीकानेर के अलावा नोहर, महाजन चूरू, रीणी, हनुमानगढ़ आदि मुख्य नगर या कस्बे थे। १६वीं सदी के प्रारम्भ में रतनगढ़ राजलक्ष्मी राजगढ़ मुजानगढ़ आदि का विकास हुआ। प्रत्येक नगर या कस्बा मोहल्लों में विभाजित था। हर मोहल्ले में प्रायः एक ही जाति या पेशे के लोग रहते थे। राजा रायसिंह व प्रसिद्ध दीवान कमचन्द को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने राजधानी को अनेक मोहल्लों में विभक्त किया जहाँ अलग अलग जाति व व्यवसाय के लोग रह सके।^३

नगर का मुख्य प्रशासक कोतवाल होता था। प्रत्येक मोहल्ले में वह अपने आदमियों द्वारा नियन्त्रण रखता था। कोतवाल मुख्य रूप से नगर पुलिस का अध्यक्ष होता था पर साथ ही साथ वह नगरपालिका के प्रशासक का कार्य भी करता था। वह छोटे फौजदारी मुकदमों भी निपटाता था। शहर कोतवाली में जो 'नगर चौकड़े' के नाम से जानी जाती थी उसका मुख्य कार्यालय था। उसके मुख्य कार्यों में नगर में शांति व्यवस्था बनाय रखना गश्ती दलदलों पर नियन्त्रण रखना, बाजार में मूल्यों काटा व मापों का निरीक्षण करना आदि आते थे। वह लावारिस सम्पत्ति के निपटारे की व्यवस्था करता था और सामाजिक बुराईयाँ व अपराधों का रोकता था। धार्मिक स्थानों का प्रबन्ध करना भी उसका

१ देखिये इसी पुस्तक के पृष्ठ १४० पाद टिप्पणी नं० २

२ मुन्शावत उल मुजाब II पृ० ७७३ दिवलीविश्व इण्डिका कलकत्ता, १८७४

३ कमचन्द (पृ०) पृ० ३१८, साथ ही हनुमानगढ़, वि० सं० १८६२/१८०५ इ० नं० १५/१ चूरू के घरे व बाजार के लिए देखिये—'मरुथी' दिसम्बर १९७३ पृ० ४३ ४७ जनवरी-जून १९७६ पृ० २० ३० चूरू (राज०)

कार्य था ।^१

'कोतवाल' की नियुक्ति दीवान की सलाह पर महाराजाधिराज द्वारा होती थी। वह एक महीनदार के रूप में कार्य करता था। कोतवाल-ताम' के नाम पर एक पैसा वह शहर के माहूनारों के घर से वसूल करता था। उत्तमवा के अवसर पर कोतवाल के यहाँ 'कासा' भोजन की व्यवस्था थी।^२ राजधानी के मुख्य दरवाजों पर चौकसी के लिए जो अधिकारी नियुक्त किये जाते थे, उन्हें भी 'हुवलदार' कहा जाता था। उन्हें इस कार्य के लिए १ रुपया रोज मिलता था। वे मोदीखान में पट्टीया प्राप्त करते थे। इन्हें पट्टा गांव भी प्रदान किया जाता था। वह दरवाजा के पहरेदारों की हाजरी सत्ता व दरवाजों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करता था। दरवाजों से गुजरने वाला सब वह 'गहदारी' कर वसूल करता था।^३

अन्य नगरों के कोतवाल भी दीवान द्वारा नियुक्त होते थे। परन्तु वे थानों के हुवलदार व फौजदार के अधीनस्थ कार्य करते थे। ये भी महीनदार होते थे। इनका मासिक बतन पांच रुपये मात्र होता था। शहरों में आने-जाने वाले माल की बिक्री पर वसूल करने के लिए भी मण्डियों के वही अधिकारी होते थे।^४

ग्राम-प्रशासन

गांव (राज्य) के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक गांव कम-से-कम १००० बीघा क्षेत्र में बसा बतलाया गया है।^५ ग्राम-प्रशासन को चलाने के लिए मुख्य रूप से दो तरह के अधिकारी होते थे। प्रथम, राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी—जो कर-निर्धारण, वसूली तथा कानून व व्यवस्था को स्थापना करते थे। द्वितीय, स्थानीय अधिकारी जो अपन बशानुगत अधिकारों पर नियुक्त किये जाते थे तथा जिनका प्रमुख कर्तव्य गांव में भेजे गये प्रशासनिक अधिकारियों

१. कर्णविमल (पृष्ठ), पृ० ११, बागदो की बही, वि० सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ५१, वि० सं० १८२४/१७६७ ई० न० १०, पृ० १०१, 'जाता व ख्याता का सप्रह', पृ० १७, मोहता रिफाउ, रीम न० ८, रा० रा० अ० बी०
२. परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, बागदो की बही, वि० सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ ५१, वि० सं० १८२४/१७६७ ई०, न० १० पृष्ठ १०१, न० ४, रा० १८३१/१७७४ ई०, पृष्ठ ४
३. भैय्या सप्रह—राहदारी के हावल मन्ते व जाधपुर से बही, वि० सं० १८६०/१८०३ ई०
४. सावा बही भनूपगढ़, वि० सं० १७३३ २४/१६६६ ई०, न० २०/१, सावा बही हनुमानगढ़, वि० सं० १८६२/१८०२ ई०, न० १२/१
५. फेगन—सेटलमेन्ट रिपोर्ट, थोकानर, पृष्ठ १, बागदो की बहियों में जहाँ भी गांव के हावल फल का विवरण पाया है, सर्वत्र ही वह १००० बीघा से अधिक का बताया गया है।

की गिनती करके वसूली करता था। वह गांव के पटायरी व लपणीये की सहायता से भूमि मापन करवाता था तथा साहण^१ की सहायता से उपज का कुता^२ करवाता था। उसे गांव की आबादी बनाय रखने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते थे।^३ हुवाला साँपा के अ तगत हुवलदार और चौधरी राज्य प्रशासन में एक दूसरे की शक्तियाँ को सन्तुलित करते थे। चौधरी हुवलदार की शक्तियों पर नियंत्रण लगाता था। चौधरी का असहयोग उस चिन्तित कर देता था। जबकि जब हुवलदार राज्य को अग्रिम राशि देकर गांव का मुकाता लन लगे तो उनकी शक्ति असोमित हो गयी तथा जगह जगह से उनकी शिकायतें आने लगी। इससे राज्य के सम्मुख एक नयी समस्या खड़ी हो गयी। करो में आधिक्य और शक्ति से उनकी वसूली के कारण गुवाडिया इधर उधर भागने लगी।^४ राज्य के आर्थिक साधना पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। अतः समस्या से निपटने के लिए राज्य ने शिमायत प्राप्त होने पर हुवलदारों को उनके पद से हटा देने की नीति प्रारम्भ कर दी।^५ परन्तु १८१८ ई० तक कोई स्थायी हल नहीं ढूँढा जा सका।

१८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब हुवलदारों ने लहणायतो^६ से कज लेकर हुवाला साँपा के अधिकार उह देन शुरू किये तो उनकी उत्तरदायित्वहीन वसूली ने गुवाडियों को बड़े संकट में डाल दिया।^७ इस युग में मुकाता प्रणाली का प्रचलन भी बढने लगा था। गांव का मुकाता राज्य को अग्रिम राशि देकर

- १ साहणा गांव का बहु स्थानीय अधिकारी था जो उपज का मूल्यांकन करके राज्य का भाग निर्धारित करता था।
- २ भू राजस्व वसूली की एक प्रणाली जिसमें उपज का मूल्यांकन करके हासिल को वसूल किया जाता था।
- ३ यादगार गांव की बही वि० सं० १७२६/१६६६ ई० न० ६६ देमरे खालसा वि० सं० १७४०/१६८३ ई० न० ६७ छातमा देहानम वि० सं० १७४२/१६८६ ई० न० ६८—बीकानेर बहीयात
- ४ यादगार की बही वि० सं० १८६६/१८०६ ई० न० १६ पृष्ठ ४४४६ वि० सं० १८७२/१८१५ ई० न० २१ पृष्ठ १४० ४३ भय्या सप्तह—भय्या नथमन के पत्र यावज मुद्रि ७ ११ वि० सं० १८७२ ११ व १२ अथवा १८१५ ई०
- ५ कागदों की बही वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १२ पृष्ठ १ ६१ १२०
- ६ ऋणदान
- ७ बहीयात बिठी दे खातो रो वि० सं० १८२०/१७९३ ई० न० २६/१ रामपुरिया रिकार्डस बीकानेर भय्या सप्तह—भय्या नथमन के पत्र यावज मुद्रि ७ ११ वि० सं० १८७२ ११ व १२ अथवा १८१५ ई०

या वस्तु के रूप में देना पड़ा।^१ चौधरी की बदलती हुई परिस्थितियों में भी विशेषाधिकारों की बात यूँ समझ आती है, जब हम देखते हैं कि वह पुनर्भूतियों के लिए ग्राहकों को 'डोहली' (अनुदान भूमि) प्रदान करता था, जिसे भग करने का अधिकार पट्टायत को भी नहीं होता था।^२ नये बसे गावों में राज्य अवश्य चौधरी नियुक्त करता था, यद्यपि उनका भी पद पुराने चौधरियों की तरह वंशानुगत होता था; लेकिन वे उनके किसी प्रकार के भूमि दावे नहीं माने गये थे तथा वे किसी प्रकार का अनुदान नहीं दे सकते थे। वे मुख्य रूप से एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी की स्थिति में थे तथा अपनी ग्रामीण समाज में सर्वोच्च स्थिति बनाये रखने के लिए अन्य गुवाडियों से 'मलवा' अवश्य वसूल करते थे।^३ इसके अलावा 'नीता', 'डोल गुवाड' अन्य कर थे, जिन्हें वे सभी चौधरी वसूल करते थे।^४

चौधरी के मुख्य कर्तव्य अपने क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने तथा कर वसूली में राजकीय अधिकारियों को सहयोग देना था। इसके अलावा ग्रामीण जीवन में उठने वाली समस्याओं से प्रशासन को परिचित कराना था।^५ चौधरी गाव के भूमि सम्बन्धी झगड़ों को निपटाता था तथा सामाजिक व क्षेत्रीय आर्थिक विवादों में पक्ष का कार्य करता था।^६ गाव में चोरी होने पर चोर व माल की छोज का दायित्व भी उसी का था।^७ गाव के ऋणदाताओं को उनकी रकम दिलाने में सहायता करता था तथा गाव के मजदूरों के पारिश्रमिक तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व भी इसी पर था।^८ अपनी इन समस्त सेवाओं

१ वही, सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ २७, ४६, सं० १८७३/१८१६ ई०, न० २२; पृष्ठ १६

२ वही, सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ २२७, सं० १८७४/१८१७ ई०, न० २२, पृष्ठ १६, न० २३, पृष्ठ ३०

३ जी० एस० एल० देवरा—साक्षियों द्वोनोमिक हिस्ट्री थाफ़ राजस्थान, पृष्ठ ६४-६५ (पूर्व)

४ नागदो की वही सं० १८२८/१७८१ ई०, न० ५, पृष्ठ ४८, फेब्र—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, पृष्ठ १५, १६ (पूर्व)

५ दीवानो पत्र—मोहता सबह (बस्तावरमिह के समय के पूर्व)

६ नागदो की वही सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ ४४, सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृष्ठ २४

७ वही, सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ २०८

८ वही, सं० १८३८/१७८१ ई०, न० ५, पृष्ठ ४६; फेब्र—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, पृ० VIII-१४

के बदले राज्य की तरफ से 'नानकर' भूमि प्राप्त होती थी तथा लगान में 'पचोतरा' प्राप्त होता था।

जमींदार

सातवाँ गावों में 'जमींदारी' गांव अपनी एक विशिष्ट स्थिति रखते थे। ये अधिकतर राज्य के घने रेतीले पश्चिमी भाग में स्थित थे और सरकार की औपनिवेशिक नीति के परिणाम थे। यह जमींदारी गांव इसलिए कहलाते थे; क्योंकि प्रशासन गांव बसाने वाले को अथवा मुखिया को पट्टे द्वारा 'जमींदारी' अधिकार प्रदान करता था। जमींदारी अधिकार चौधरी के दायित्व में मिलते-जुलते थे, किंतु जमींदार का चौधरियों की तुलना में स्थिति उ सम्मान अधिक था। तत्पश्चात् में 'राज' ने वस्तुतः बसाने हेतु उत्साही व्यक्तियों को राठौड़ आग्रमण से पूर्व के गावों के चौधरी की स्थिति प्रदान कर दी थी, चूंकि ये बहुत ही निर्जन क्षेत्रों में अबादी बढ़ा रहे थे और जहां आय के साधन बहुत ही सीमित थे, इस कारण इन्हें कुछ विस्तृत अधिकार दे दिये गये थे। जमींदार को 'नानकर' भूमि व 'पचोतरा' के अलावा कुछ अन्य निजी कर वसूल करने तथा कहीं-कहीं तो 'जगात' वसूली के अधिकार भी प्रदान किये गये थे। चौरा अनुपगढ़ के जमींदारी गावों में राज्य कई वर्षों तक कोई वसूली नहीं करता था। ऐसी दशा में गांव की समस्त आय जमींदार के अधिकार में आ जाती थी। जमींदार गांव के चौधरी, 'पटावरी' व कानूनगो—सभी का कार्य सभालता था। इस प्रकार 'जमींदारी' राज्य की निर्जन क्षेत्र में विशेष औपनिवेशिक नीति का परिणाम थी।

पटावरी

'पटावरी' राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त वशानुगत अधिकारों में मुख्य गांव का दूसरा मुख्य अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य गांव की भूमि, उसका मापन

१ बिना कर की भूमि

२ लगान का पाषा प्रतिशत—पञ्च—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, बीकानेर, पृष्ठ सूरत देही VIII-१४

३ गांवों की बही—सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृष्ठ ३३, सं० १८६७/१८१० ई०, न० १०, पृष्ठ २४८

४ बही, न० १२, मार्गशीर्ष सुदि ६, १५, सं० १८५६, ३० नवम्बर, ६ दिसम्बर, १८०२ ई०

५ भैंया सग्रह—भैंया देईदान पत्र—माघ सुदि ६, १८७७, १० फरवरी, १८२१; माघ सुदि १, १८७८, २८ अक्टूबर, १८२१ ई०

६ कागदों की बही सं० १८४७/१८०० ई०, न० ११, सं० १८७४/१८१७ ई०, न० २८, पृ० ६६

७. पटावरी

और हासल वसूली के आलेखों को तैयार करना होता था।^१ गांव की सुरक्षा का दायित्व भी पटावरी पर था।^२ यह पद राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गांवों में अधिकतर उत्तिष्ठित हुआ है, इतना अन्य भागों में नहीं। पटावरी भी अपनी प्रशासनिक व सैनिक सवालों के बदले 'नानकर भूमि व पचोतरा' प्राप्त करता था, पर ऐसा कहीं उत्त्तिष्ठ नहीं आया है कि वह भी 'चौधरी' की भांति अलग से कोई कर वसूल करता था अथवा गांव की भूमि पर उसका कोई ऐतिहासिक दावा होता था।^३

'चौधरी', जमींदार व 'पटावरी' तीनों के पद वंशानुगत थे। तीन कारणों से इनके पद रिक्त हो सकते थे—(१) इनकी मृत्यु पर, (२) दायित्वहीन कार्यवाही पर 'राज' द्वारा इन्हें हटाये जाने पर (३) इनके द्वारा 'राज' की स्वीकृति के पश्चात् अपने अधिकार हस्तान्तरण करने पर। साधारणतया इन अधिकारियों की मृत्यु के पश्चात् इनका बड़ा पुत्र ही पद का अधिकारी बनता था, पर चाहे तो 'राज' किसी अन्य पुत्र को भी अधिकार सौंप सकता था। यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि शासक चाहे तो गांव में चौधरियों की संख्या घटा व बढ़ा भी सकता था।^४

पचायत व्यवस्था

राज्य के सामान्य प्रशासन व न्यायिक संगठन में विद्यमान विभिन्न तरह की पचायतें एक अभिन्न अंग थीं। न्याय के क्षेत्र में जहाँ केन्द्रीय स्तर पर राजा व दीवान सभी प्रकार के मामलों में निणय देते थे, वहाँ खीरा व गांव स्तर पर फौजदारी मामले चौरों व धाणों के फौजदार व हुवलदार तथा शहर व कस्बे में कोतवाल निपटाते थे, पर अधिकांश नागरिक प्रकृति के विवाद विभिन्न पचायतों के सम्मुख ही आते थे। सामान्य व नागरिक प्रशासन में पचायतों की विद्यमानता इस बात की धातक है कि राज्य ने प्रशासन में सत्ता की विकेंद्रीकरण की शक्तियों को भी स्वीकारा था तथा उन्हें अपने संरक्षण में राजा की निरकुशता पर ध्यान आते हुए फलने-फूलन दिया था। पचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली के बारे में बीकानेर रामपुरिया संग्रह की कागदों की सभी बहियां विस्तृत

१. भैंया संग्रह पत्र बैशाख सुदि २ १० व ११ स० १८७३, २, ७ मई, १८१६ ई०

२. वही, भैंया पत्रा में पटावरी के व्ययगत्र के लिए विवरण और घर देखिये—रामगढ़ गांव की झूट का मामला।

३. कागदा की बही स० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृष्ठ १२६, स० १८७४/१८१७ ई० न० २३, पृ० ८२

४. फगन—सटसमण्ट रिपोर्ट बीकानेर, पृ० VIII १४, जी० एच० एन० देवदा—सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, पृ० ६६ ६७

रूप से प्रकाश डालती हैं।^१ इन बहियों में, जिस ढंग से पचायतो का वर्णन आया है, उससे प्रमाणित होता है कि वे प्राचीन मान्यता प्राप्त संस्थायें थीं। अधिकांश पचायतें ग्रामीण क्षेत्र में ही प्रभावशाली थीं। शहर व कस्बों में जाति व व्यावसायिक पचायतों^२ की प्रधानता थी।

उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री से प्रमाणित होता है कि राज्य में तीन प्रकार की पचायतें प्रचलित थीं—(१) गाव-पचायत, (२) जाति-पचायत, (३) व्यवसायो से सम्बन्धित पचायत। राज्य के अधिकांश गाव एक ही जाति की प्रधानता से बसे होने थे, इस कारण उन गावों की जाति व गाव-पचायतें एक ही होती थीं। अनेक जातियों से बसे गावों की जाति व गाव-पचायतें अलग-अलग होती थीं। इन गाव-पचायतों में विभिन्न जातियों का कितना प्रतिनिधित्व होता था, इस पर स्रोत मौन हैं। शहर व कस्बों में जाति-पचायतों की प्रधानता थी जैसे सोनारों, मालियों व सुधारों की पचायतें। यहाँ तक कि वहाँ मुसलमान भी विभिन्न जातियों में बँटकर अपनी-अपनी पचायतों का निर्माण करते थे। गावों में अनेक व्यवसायों से सम्बन्धित बसने वाले विभिन्न जाति के लोग संख्या में बहुत कम थे। जाटों की किसी एक शाखा के गाव में बनिया या सुधार की गुंदाड़ी एक या दो ही होती थी।^३ इस कारण उनकी जाति-पचायतें कई गावों के उनके जाति बन्धुओं से मिलकर बनती थीं। शहर व कस्बों में विद्यमान व्यावसायिक पचायतों में तात्पर्य किमी जाति विशेष की पचायतों से न होकर व्यापार व वाणिज्य की विभिन्न शाखाओं में लगे व्यक्तियों के संगठन की पचायत से है। जैसे आठतियों की पचायत, मिश्री व व्यापारियों की पचायत, साहूकारों की पचायत इत्यादि। साधारणतया इन पचायतों के पक्षों की नियुक्ति व मान्यता दरबार द्वारा पुष्ट की जाती थी।

इन विभिन्न पचायतों में पक्षों की संख्या कितनी होती थी, इस पर फिर स्रोत मौन है। स्वयं राज्य द्वारा नियुक्त पक्षों के आदेश-पक्षों से ज्ञान होता है कि यह संख्या लगभग पाँच थी, बँस मात-आठ व कभी-कभी इससे अधिक

१ पचायती व्यवस्था का सम्पूर्ण विवरण राजबंदी की बहियाँ के मन्दब, 'पलिधत' व 'रीठ' नामों में उपलब्ध होता है। इस विषय में प्रस्तुत विवरण के लिए राजबंदी की बहियों नं० १ में २१ तक पृष्ठी हैं जो स० १८११/१७५४ ई० से स० १८७३/१८१६ ई० की हैं—रामपुरिया रिकार्ड, बीकानेर—स० २० अ० बी०

२ एक व्यवसाय से सम्बन्धित पचायत के कारण ही सुविधा के लिए इन पचायतों का नाम व्यावसायिक पचायत दिया गया है।

३ उदाहरणार्थ धोरा खेवडा का गाव जेतसीनर ओभीयो ना जहाँ कुछ व्यावसायिक जातियाँ थी, फिर भी वहाँ जाटों की मुख्य जाति के कारण जाटों का गाव कहलता था—बही हासल रे लेखे गी—स० १८४६/१८६२ ई०, न० २८, पृष्ठ २२-२५—स० २० अ० बी०

पंचों की नियुक्ति के विवरण प्राप्त होते हैं। राज्य द्वारा पंचों की नियुक्ति के अलावा पंचायतों के पंच किस प्रकार निर्वाचित या नियुक्त होते थे, इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राज्य तो पहले से चले आ रहे पंचों को ही नियुक्ति में चुनता था। हा, गांव का जो चौधरी होता था या उसके परिवार के सदस्य होते थे, वे अवश्य अपने पद की स्थिति व क्षेत्रीय ऐतिहासिक दावों के कारण पंच-समूह में अवश्य स्थिति पा जाते होंगे।

जाति-पंचायत के विषय में तो स्पष्ट ही है कि इसके सदस्य उसी जाति विशेष से चुने जाते थे, तथा मुख्य रूप से एक जाति से बसे गांव के पंच भी वही होते थे। परन्तु बड़े गांवों की गांव-पंचायत के पंच किस जाति से चुने जाते थे, इसका विवरण नहीं मिलता। सम्भवतः भू-स्वत्व अधिकारों से युक्त काश्तकारों में से ही पंच चुने जाते थे। क्योंकि गांव में इन्हीं की संख्या सबसे अधिक होती थी। ऐसा अनुमान है कि 'कमीनान' को निम्न जाति का हाने के कारण, महत्व नहीं दिया जाता होगा। व्यावसायिक जाति के लोगों की संख्या कम होती थी, पर उनके कुछ सदस्य गांव-पंचायत में लिये जाते होंगे। राज्य में यह भी आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक गांव में पंचायत हो, छोटे-छोटे गांव पंचायती प्रशासन के लिये पास के बड़े गांव से जुड़े रहते थे। जाति-पंचायतों का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत होता था। किसी जाति की विशेष समस्या को सुलझाने के लिए पूरे एक चोरे व यहा तक कि आस-पास के चोरो में से भी उम जाति के पंच आते थे।

पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण समाज में नित्यप्रति उठने वाले सामाजिक व आर्थिक विवादों को निपटाना था। पंचायत के सम्मुख आने वाले विवाद निम्न प्रकार के होते थे तथा उनसे सम्बन्धित पंचायत बैठ कर उन पर अपना निर्णय देती थी।

ग्राम-पंचायत के सम्मुख मुख्य रूप से आर्थिक विवाद ही आते थे, जैसे भू-स्वत्व अधिकार, भूमि के रेहन, भूमि के मुकाते, खेत की सीमा के प्रश्न, गांव की सीमा के प्रश्न आदि। इनके अलावा, गांव-पंचायतें साधारण अपराधों जैसे चोरी, मिलावट, अपहरण, बलात्कार आदि के मामलों को भी निपटाती थीं।

जाति-पंचायतों के सम्मुख मुख्य रूप से सामाजिक रीति-रिवाजों व परंपराओं से सम्बन्धित वाद-विवाद प्रस्तुत किए जाते थे। जैसे विवाह, नाता, पले लगाना, मगाई, गोद लेना, वंशानुगत सम्पत्ति के बंटवारे तथा जाति में दुराचार आदि के विवाद।

व्यावसायिक पंचायतें, जो कस्बों व नगरों में स्थित होती थी, व्यापारियों के लेन-देन, लेखा-जोखा, साक्षेदारी, मुकाते के विवादों को निपटाती थी।

उपर्युक्त विवाद था तो सीधे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पंचायत के सम्मुख लाये जाते थे अथवा प्रशासन द्वारा उन्हें सुलझाने के लिए सौंपा जाता था।

पचायत स्वयं भी स्थिति की गम्भीरता का अध्ययन करके मामले को अपने हाथों ले सकती थी तथा शासक व प्रशासन को सूचित किये बिना निर्णय देती थी।

प्रशासन की यह निश्चित नीति थी कि अधिकतर स्थानीय सामाजिक व आर्थिक विवाद पचायतो के ही सुपुर्दे गये जायें। शासन स्थानीय सामाजिक व आर्थिक विवाद इससे सम्मुख आने पर पचायतो का सुपुर्दे कर देता था। उस समय वह जो आदेश पचो के लिये भेजता था, उसमें स्पष्ट रूप में उल्लिखित होता था कि वे ईमानदारी से अपना काय मर्यादा करें तथा निष्पक्ष होकर ही फैसला करें। इसके लिए उन्हें 'दूध-पूत-खेती' की सौमंछ दी जाती थी। बादी-प्रतिवादी को यह चेतावनी दी जाती थी कि अगर उन्होंने पचो व निर्णय को स्वीकार नहीं किया तो उन पर 'गुनहगारी' लगगी, जिसकी राशि भी लिखित आदेश में माय लिखी जाती थी।^१

पचायत का निर्णय अन्तिम नहीं होता था। उनके फैसले के विरुद्ध दरबार में अपील की जा सकती थी। शासक स्वयं भी सुनवाई कर सकता था अथवा पचो को पुनः मामले की नये सिरे से खोज-बीन करने के लिए आदेश दे सकता था।

शासक कई बार किसी गांव की सामाजिक व आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए दूसरे गांव के पचो को भी नियुक्त करता था। व पच एक गांव के भी हो सकते थे तथा विभिन्न गांवों के पचो में से भी नियुक्त किये जा सकते थे। विवाद पर, मगाई के मामले को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में एम उदाहरण मिलते हैं।

एक बार तो नागौर के पचो को भी मगाई के विवाद को सुलझाने के लिये आमन्त्रित किया गया था।^२ दो गांवों की 'सीब' का विवाद तो तीसरे गांव के पच सुलझाते ही थे।

इन पचायतो के दण्ड, जो राज्य प्रशासन द्वारा अनुमोदित होते थे, अपनी सीमा में साधारण व कठोर दोनों प्रकार के होते थे। प्रायश्चित्त, क्षमायाचना व जुर्माना साधारण प्रकार के दण्ड थे। जाति से बहिष्कृत करना, सम्पूर्ण जाति को सामूहिक भोज देना आदि कठोर दण्ड थे। शासक अपनी इच्छा से इन दण्डों में

१ गो० लुणकरणसर में ईतरो पचो जोय वीया बुवे बंधते वोजे रे घर रो जमरयो छ सु ये पच छो बडा परमेसरी नोवेड दे जो हर कुरक हीरी राखी तो चोरे दूध पूत रो सीब छे।

तेरी सख समझ नोवेड दे जो चोहीरो नहो उबपयो तो मुनेगारी लागतो। रामपुरिया चतरू होली बुचो—बुमानो, मुबो, नुमो जीपडो।

—कायदों की वही वि० सं० १८१७/१८०० ई० न० ११, पृष्ठ २०६

२ कायदों की वही—चल बदि ६, १८३६, २४ मार्च, १७८३ ई०, न० ६

३ सीमा

परिवर्तन कर सकता था। वह जाति से बहिष्कृत व्यक्ति से पुनः जाति में प्रवेश दिना सकता था। ऐसी स्थिति में शासन को नजर भेंट करने का नियम था। इस प्रकार, शासन पचायती व्यवस्था को पूरा सम्मान दत्त हुए भी अन्तिम नियम अपने हाथों में ही रखता था।

पचायत संस्थाओं की स्थानीय प्रजापति सरकार दोनों के लिये लाभदायक थी। सरकारी अधिकारियों का इन संस्थाओं के साथ रहना भी इस अर्थ में लाभप्रद था कि वे ग्रामीण समस्याओं से तथा स्थानीय नियमों से परिचित रहते थे। साथ ही स्थानीय सदस्यों के लिए सरकारी अधिकारियों से साथ रहना एक गौरव का विषय था क्योंकि इससे साधारण और सरकारी अधिकारियों के बीच समानता बनी रहती थी। यह स्थिति सामान्य से गुच्छाक रूप में चलाने में बड़ी उपयोगी थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहाँ तक जाति पचायतों का सम्बन्ध है, वे किसी सीमा तक निस्वार्थ न्याय देने में महयोगी सिद्ध हुईं। स्थानीय रीति-रिवाजों का इस व्यवस्था द्वारा एक स्तर बन सका और सामाजिक नियमों के परिपालन में समाज में परम्परागत अनुशासन की भावना को दृढ़ करने का अवसर मिला।^१ इस प्रकार राठौड़ नामका वे भूमि से सम्बन्धी अवधि से बसी आ रही सम्मानजनक परम्पराओं को प्रशासन में महयोगी बनाकर स्थानीय लोगों की प्रशान्तता के प्रति निष्ठा प्राप्त की कि उन्हें स्वयं का मानकर नष्ट कर दिया।^२

१ जी० जी० एन० शर्मा—राजस्थान का इतिहास पृष्ठ ६४४

२ जी० एस० एल० देवडा—पचायत मिस्टम एण्ड आर्कडवस सोर्भोज—सोधपत्र प्रस्तुत सेमिनार, सेक्टर आफ राजस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, मार्च १९७७

षष्ठम अध्याय वित्तीय प्रशासन आय

मुगल साम्राज्य में बीकानेर 'वतन जागीर' का मुख्य ३४८, ७५० ह० आका गया था, जिसमें परगना बीकानेर की आय २ ५०,००० ह० थी।^१ बीकानेर के शासकों को मुगल साम्राज्य में मनसब के वेतन के बदले जो 'तनख्वाह जागीर' प्राप्त होती थी, उनकी आय भी फिर इसमें सम्मिलित कर दी जाती थी। राजा रायसिंह को 'वतन जागीर' के साथ मुगलों से ८ ६२ ०६८ ह० की जागीर आय प्राप्त हुई थी।^२ राजा सूरसिंह व अनूपसिंह को क्रमशः ह० ३,४४,८३४ व रुपये १,१०,५१५ की जागीरी-आय मिली थी।^३ लेकिन इस कुल आय के विभिन्न व्योतों का स्वतन्त्र उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। महाराजा अनूपसिंह राज्य के प्रथम शासक थे, जिनके काल की वहीदों में, 'वतन जागीर' की कुल आय, उसमें होने वाली छालसा व पट्टा भूमि की आय तथा मुगल जागीर से प्राप्त होने वाली आय का अलग-अलग विवरण मिलता है। इनमें 'वतन जागीर' की आय के विभिन्न व्योतों का वर्णन भी उपलब्ध है।^४ सन् १६७० ई० से सन् १६८२ ई० तक राज्य के खालसा गांवों की, कुल आय ह० १६,६८,७७६ थी। इन २३ वर्षों

१ राजा सूरसिंहजी के जागीर की विवरण, (२०), महाराजा अनूपसिंहजी के मनसब में तख्त की विवरण, २०६/२ (पूर्व), परगना सरकार विवरण, सिरदार बीकानेर मुबो अदमर—२२७/३ अ० सं० पु० बी० अकबर के काल से यह राशि बढ़ गई थी। इसका उल्लेख पूर्व राजपद अध्याय में हो चुका है।

२ सम्राट अकबर का राज रायसिंह को फरमान वि० सं० १६२६/१५६६ ई० (पूर्व)

३ राजा सूरसिंहजी के जागीर की विवरण, महाराजा अनूपसिंहजी के मनसब में तख्त की विवरण (पूर्व)

४ महाराजा अनूपसिंहजी के समय की समस्त गांवों की वहीदें, वि० सं० १७२७-४५/१६७०-६२ ई०, न० ७१ परगना के जमा जोद की वहीदें, वि० सं० १७२६ ई०/१६६६-१६६३ ई०, न० ६६, परगना के जमा खर्च की वहीदें, वि० सं० १७५०-५१/१६६८-६९ ई० न० ३२, बीकानेर बहिषाव, रा० रा० अ० बी०

मे पट्टे के गाँवों से होने वाली आय रु० १८,८६,२३१ थी।^१ इसी बाल के एक अन्य विवरण से ज्ञात होता है कि सन् १६६६ ई० से सन् १६६३ ई० तक, २६ वर्षों में राज्य की कुल आय रु० ३८,५०,६०५ थी, अर्थात् राज्य की प्रति वर्ष रु० १,५४,०२४ की आमदनी होती थी। इन वर्षों की मुगल जागीरी आय को मिला देन से प्राप्त होने वाली कुल आय रु० ६७,२४,०२४ हो जाती थी।^२ १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में, अलग-अलग वर्षों में आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन अवश्य कही-कही मिलता है, परन्तु उनमें सम्पूर्ण आय का अनुमान लगाना कठिन है। तदुपरान्त, महाराजा ग़ज़सिंह के काल की 'खाता खजाना बही' में राज्य की कुल आय रु० १,२०,०४० का वर्णन उपलब्ध है।^३ महाराजा सूरतसिंह के काल में आय-वृद्धि सन् १७६५ ई० में रु० १,८६,५५८ या,^४ जो सन् १८०६ ई० में बढ़कर रुपये ६,५१,६५३ हो गयी। यह वृद्धि अपने-आपमें अत्यन्त महत्वपूर्ण थी।^५

सन् १५७४ ई० में १८१८ ई० के काल के बीच राज्य की कुल आय में काफी उतार चढ़ाव आये थे। मुगल-प्रशासन ने, बीकानेर 'वतन जागीर' की आय रु० ३,४८,७५० निर्धारित की थी। परन्तु महाराजा अनूपसिंह के समय, स्थानीय स्रोतों के अनुसार, राज्य की वास्तविक औमत आय प्रतिवर्ष रु० १,५४,०२४ थी। इस प्रकार 'जमा' व 'हासल' के आकड़ों की सूची में बहुत अन्तर

१. बही समस्त गावां री, वि० सं० १७२७-४५/१६७०-६२ ई०, न० ७१, परगना रे जमा-जोड़ री बही वि० सं० १७२६-५०/१६६६-६३ ई०, न० ६६—बीकानेर बहियात

२. परगना रे जमा जोड़ री बही वि० सं० १७२६-५०/१६६६-६३ ई० (पूर्व)

३. लेखा बही वि० सं० १८१४/१७५७ ई०—बीकानेर बहियात, ग० रा० भ० बी०

४. बही खाता खजाना सदर, वि० सं० १८५२/१७६५ ई०, बीकानेर रोख बहियात—रा० रा० अ० बी०

५. जमा खरच री बही, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, शैय्या सग्रह, बीकानेर

नोट—इस अध्याय की मूल सामग्री सम्मत गावां री बही, परगना रे जमा जोड़ री बही, लेखा बही, बही खाता खजाना सदर व जमा खरच री बही पर आधारित है। आगे के पृष्ठों पर इनकी सूचना के सदृश में पाद-टिप्पणियों के रूप में बार-बार प्रयोग नहीं किया गया है। इन बहियों से सम्बन्धित वर्ष इनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इन वर्षों का विवरण इस प्रकार है—

समस्त गावां री बही—१६७० ई० से १६६२ ई० तक

परगना रे जमा जोड़ री बही—१६६६ से १६६३ ई० तक

लेखा बही—१७५७ ई०

बही खाता खजाना सदर—१७६५ ई०

जमा खरच री बही—१८०६ ई०

सावधानी के लिए इन वर्षों में किसी अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है।

था। यद्यपि इस काल के आय आकड़ा की सूची से विदित होता है कि राज्य की आय में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। सन् १६६६ ई० की तुलना में १६६३ ई० तक यह वृद्धि ३१ ६६ प्रतिशत थी। इन बीच के पच्चीस वर्षों में अधिकतम आय वृद्धि ६६ ८७ प्रतिशत सन् १६८६ ई० में हुई थी। केवल तीन वर्षों, सन् १६७०, १६७२ व १६७४ ई० में ही आय में गिरावट आई थी। ये वर्ष अकाल व सूखे के वर्ष थे। राज्य की आय में वृद्धि के अनेक कारण थे जिनमें प्रमुख करा की दर में वृद्धि खालसा गांवों की सख्या व आय में वृद्धि तथा 'पट्टायत' क्षेत्र में नये करों की लगाना आदि थे। १६८६ ई० तक खालसा गांवों से होने वाली आय निरन्तर बढ़ती गई। १६७० ई० में जहा खालसा गांवों से ३७ ५४७ रुपये प्राप्त होते थे, वहा १६८२ ई० में १,६३ ८६६ रु० तथा १६८७ ई० में २,१५,६०५ रुपये प्राप्त हुए।^१ राज्य के रेगिस्तानी वातावरण में, आय के उतार-चढ़ाव की देखते हुए यह उल्लेखनीय प्रगति थी। जबकि उन वर्षों में सम्पूर्ण भारतवर्ष में अकाल व महामारी का प्रकोप चल रहा था और मारवाड़ व दक्षिण भारत युद्ध ग्रस्त था।^२ १६६० ई० के बाद राज्य में अव्यवस्था आ जाने के कारण दूसरे दक्षिण प्रकट होन लगे।

१८वीं शताब्दी में राज्य की आय में कमी आने लगी थी। मुगल साम्राज्य के पराभव के परिणामस्वरूप ज़मीनी आय समाप्त हो गई। इस काल में खालसा गांवों की सख्या भी घटने लगी थी।^३ पड़ोसी राज्य के आक्रमण, ठाकुरों के विद्रोही आचरण व प्रशासनिक शिथिलता ने आय में गिरावट को प्रेरित किया था।^४ यद्यपि शताब्दी के मध्य तक राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मुगल परगनों के स्थाई रूप में राज्य में मिल जाने के कारण आय में वृद्धि होनी चाहिये थी, परन्तु अव्यवस्था के वातावरण में वृद्धि की वे सम्भावनाएँ प्रभावहीन हो गईं। सन् १७५७ ई० में आय सन् १६६६ ई० की तुलना में ५६ ६६ प्रतिशत रह गई थी। सन् १७५७ ई० का वर्ष अकाल व युद्ध का वर्ष भी था।^५ महाराजा सूरतसिंह के कठोर प्रशासन तथा नये करा के प्रचलन से, सन् १७६५ में आय १७५७ ई० की तुलना में बढ़ गई थी, लेकिन सन् १६६६ ई० की तुलना में अब भी यह ७१ ४४ प्रतिशत ही थी। महाराजा सूरतसिंह के काल में राज्य की

१ सपछत गावा री बहो १६७० ६२ ई० (पूर्व) देखिये सारणी प्र भी

२ सरकार—मीरगञ्ज पृष्ठ २३२ ३३, डा० हरफान हबीब—दी ऐगरेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया पृष्ठ १०१-१०३ डा० जी० एन० शर्मा राजस्थान, पृष्ठ ४६१ ६२

३ सन् १६६८ ई० में खालसा गावा की सख्या २५५ थी जो १७५६ ई० तक घट कर १५२ रह गई—हासल बहिया—वि० सं० १७२५/१६६८ ई० वि० सं० १८१३/१७५६ ई० रा० रा० प्र० भी०

४ दयालदास ख्यात (अग्र०) २ पृष्ठ २७०-७४, ३१८ २०

५ बीकानेर री ख्यात महाराजा गुजराणसिंहजी सूरतसिंहजी तारी १८६/११ (पूर्व)

उत्तरी, पश्चिमी व दक्षिणी सीमाओं में विस्तार हुआ था। भटनेर सदैव के लिए खालसा में मिला लिया गया था। मीरगढ़ और फलोधी राज्य नियन्त्रण में आ गये। महाराजा ने पुराने व नये करों की दरों में वृद्धि कर दी थी। विद्रोही ठाकुरों से 'पेशकसी' की अधिक रकम वसूल की गई थी। इन सब के परिणाम-स्वरूप सन् १८०६ ई० में राज्य की आय बढ़कर ६,५१,६५३ रुपये हो गई। सन् १६६८ ई० की तुलना में यह वृद्धि ४०७ १० प्रतिशत अधिक थी। यह राज्य की आय में अधिकतम वृद्धि थी।^१ राज्य की इतनी अधिक आय तो राजा रायसिंह के काल में, मुगल जागीरी आय को सम्मिलित करने से भी नहीं हुई थी। इसके लिये महाराजा सूरतसिंह की प्रशासनिक व सैनिक आवश्यकतायें मुख्य रूप से उत्तरदायी थीं।

राज्य की कुल आय की सूची^२

(स० १६६६ से १८१८ ई० तक, १०० प्रतिशत के आधार पर)

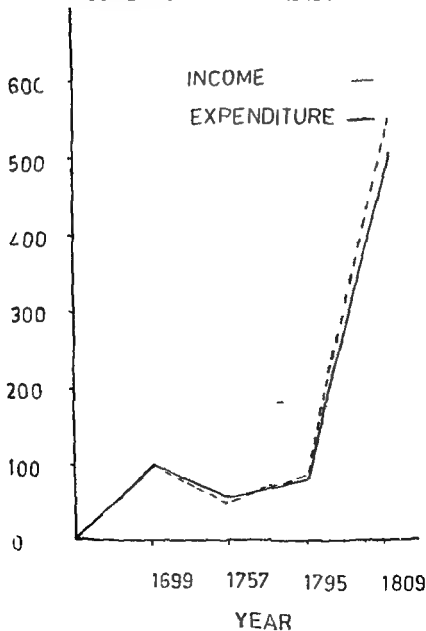
वर्ष	आय (रुपयों में)	प्रतिशत (१०० के आधार पर)
१६६६	१,८७,७७५	१००
१७५७	१,१२,०२०	५९.६६
१७६५	१,३४,०७८	७१.४४
१८०८	६,५१,७६५	५०७.१०२

१. देखिये कुल आय की सारणी

२ राज्य की कुल आय के विवरण से संबंधित जानकारी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। करीब सौ साल से अधिक समय में हुई आय को प्रकट करने वाली सिर्फ चार बहिया प्राप्त हुई हैं। उनके बीच के वर्षों का अंतर अधिक होने के कारण, सही तथ्यों को खोज निकालना कठिन हो जाता है। लेकिन प्राप्त सामग्री के आधार पर आय की दिशा का पता लगाया जा सकता है। हमने इस अध्ययन के लिए १६६६ ई० को आधार वर्ष चुना है, क्योंकि सबसे पुरानी प्रामाणिक सामग्री जो उपलब्ध हुई है, वह इसी वर्ष की है। यह वर्ष हर दृष्टि से सामान्य हान के कारण, अध्ययन की दृष्टि से एक आदर्श वर्ष के रूप में लिया जा सकता है। इस वर्ष न तो अकाल पड़ा था और न बाढ़ों से अधिक उत्पादन हो हुआ था। इससे पूर्व १६६६ ई० की सामग्री भी है, लेकिन आय के पूरे विवरण उपलब्ध न होने के कारण इसे 'आधार वर्ष' चुना नहीं जा सका। फिर, आय की व्यय की साथ तुलना करने के लिए भी १६६६ ई० का वर्ष चुनना आवश्यक है, क्योंकि व्यय के विवरण इसी वर्ष से प्राप्त होते हैं। प्राप्त सामग्री में आगे के वर्ष असाधारण हैं। १७५७ ई० का वर्ष सामान्य है, परन्तु १८०६ ई० का वर्ष व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये करों की आय-वृद्धि से भरा हुआ है। देखिये रेखाचित्र पृष्ठ १६२ पर।

Total Income And Expenditure And Its Difference

SCALE 2 CM = 100 PERCENTAGE



आय के साधन

आय के स्योकृति-पत्र

राज्य की आय के विभिन्न स्रोत य जिह निम्नलिखित शीर्षकों में विभा-
जित किया जा सकता है—

- १ भोग या हासल (माल)
- २ धुआ भाछ या गृह कर
- ३ हलगत या हला पर निर्धारित कर
- ४ जगात या आयात निर्यात पर कर तथा खुशी कर
- ५ छड खरच या फौज खरज (सैन्य कर)
- ६ पेशकसी फरोही, नहराना नहर व जुर्माना कर, गुनेहगारी आदि
- ७ श्रीमण्डी या राजधानी की मण्डी की आय—श्रीमण्डी की आमदनी के जगात के अलावा ये कर थे—
(अ) गोला (गोद लेन पर कर)
(ब) चौध जमीन (जमीन की बिक्री का कर)
(स) गईवान (लावारिम सम्पत्ति)
- ८ मण्डियों की जमा—श्रीमण्डी के अलावा राज्य की मण्डियों की आय
- ९ कोयला दलाला री भाछ (मीठा दलाली भाछ)
- १० साहूकारा री भाछ
- ११ कीरामत लोको री भाछ—(शहर में रहने वाली विभिन्न जातियों पर लगाया गया कर)
- १२ टकसाल
- १३ राजकीय नहरखान
- १४ कमूर (जुर्माना)
- १५ साल झीलडी की भ छ (कारीगरो पर लगाया कर ब्राह्मणा से भी इस वसूल किया जाता था)
- १६ नीता (शादी ब्याह पर लिया जाने वाला कर)
- १७ हाकमो का रोजगार (अधिकारियों का पारिश्रमिक कर)
- १८ मेला (त्योहार)
- १९ मुकाला (ठेका)
- २० रीठ (पुनर्विवाह कर)
- २१ जोड रे साहे (शहर का चराई कर)
- २२ बहेलिमा री खेल (चरवाहो पर कर)
- २३ कोरड, मुरज, घास-चारा (घास कर)

- २४ सींगोटी (भट्ट चराई कर)
- २५ पान-चराई कर (चराई कर)
- २६ अंग भाछ (जानवरो पर लगाया गया कर)
- २७ सेण्णीयो का लाजमा (लिपिओ क लिए लगाया गया कर)
- २८ ठाकुरजी गुमोइ का लाजमा (देवी देवताओ का कर)
- २९ हवक (विविध कर)
 - (अ) कीयाबी भाछ (प्रत्येक घर के दरवाजे वा कर)
 - (ब) देसप्रठ (गाव म बसने का कर)
 - (स) ऊठो की भाछ (ऊठो का कर)
३०. मुगा कर (बाहर के जानवरो पर लगाया गया चराई कर)
- ३१ मापा (झिन्कीकर)
- ३२ दणवाली भाछ (रक्षा वा कर)
- ३३ घोडा रेख (पट्टदारो स लिया गया सैनिक कर)
- ३४ धान की चौयाई या आधीया (धान बिक्री कर)
- ३५ कामदारो की भाछ (धर्मचारियो स लिया गया कर)
- ३६ हजूरियो की भाछ (निजी संवको स लिया गया कर)
- ३७ बीरामणो की भाछ (ब्राह्मणो स लिया गया कर)
- ३८ पोत्राण—(खानो पर कर)
- ३९ लूण—(नमक कर)
- ४० चौघर वाब पगवरी वाब (चौधरी व पटवारियो स लिया गया कर)
- ४१ बीदाह्वो का वधा (बीदावत राठीओ पर लगाया गया कर)
- ४२ थाणो का कर
- ४३ अवालत रे साहे (न्याय कार्यों क लिए लिया गया कर)

इनमे से बहुत स कर एक साथ वसूल नहीं किए जाते थे। कुछ कर अन्य करो के भाग थे। महाराजा अनूपसिंह, गर्वासिंह व सूरतसिंह ने कई नये करा को लागू किया। अकेले मूरतसिंह ने १० नये कर लगाये थे।

विवरण

राज्य की आय का मुख्य भाग 'हासल' स ही प्राप्त होता था, परन्तु इसने जनावा अन्य महत्वपूर्ण कर भी थे जो राज्य की आय के पूरक थे।

१ भूमि कर या हासल—राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर या 'हासल' ही था। जो भू राजस्व या हासल वसूल किया जाता था, वह मुख्य तौर पर तीन भागो स गठित होता था— भोग' (भाल), रोकड रकम (सहायक

कर) व 'बीजा रकमे' (अन्य कर) । 'भोग' या 'भाल' वास्तव में कृषि कर होता था तथा साधारणतया हामल का प्रमुख अंग होता था ।^१ 'भोग' कृषक की कुल उपज में राज्य के निर्धारित भाग के रूप में वसूल किया जाता था । 'रोकड-रकम' या सहायक कर बीकानेर राज्य में हासल के गठन में 'भोग' के समकक्ष व बिल्कि उससे भी महत्वपूर्ण अंग के रूप में होते थे जबकि राजस्थान के अन्यत्र क्षेत्रों में भुगत परगनों में हासल में सहायक कर की ऐसी स्थिति नहीं थी ।^२ यहाँ गाँवों की जमाबन्दी भी रोकड रकमों की होती थी । 'भोग' को बसूली के समय निर्धारण करके ले लिया जाता था । 'भोग' व 'रोकड रकमों' की बसूली में जो प्रशासनिक खर्च आता था, उनका तथा मन्दिरों व अन्य धार्मिक कृत्यों के नाम से जो अन्य वर वसूल किये जाते थे, उन्हें 'बीजा रकम' कहा जाता था ।^३

बीजा रकमों हासल के पाँच प्रतिशत भाग का निर्माण करती थी ।^४ लेकिन 'भाग' व 'रोकड रकम' हासल के बितने प्रतिशत भाग होय यह भू राजस्व की विभिन्न प्रणालियों पर निर्भर करता था, क्योंकि राज्य में कुछ प्रणालियाँ ऐसी थी, जिसमें 'भोग' वसूल ही नहीं किया जाता था जैसे पसरौती,^५ मुक्ताती व बोली-यार पद्धति । केवल हाली पद्धति में भोग व रोकड रकम साथ साथ वसूल की जाती थी । एक अन्य पद्धति बीघड़ी में प्रति बीघा लगान नकदी में ले लिया जाता था, जबकि भोग जिनस में वसूल होता था । भीत की भाछ पद्धति में घरों या गुवाडियों की गिनती करके निर्धारित पर स हासल वसूल कर लिया जाता था ।^६ इस प्रकार इस रेगिस्तानी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र व पद्धतियाँ प्रचलित थी जिनमें हासल का सम्बन्ध कृषि से बिल्कुल नहीं होता था । भू राजस्व पद्धति व हामल का निर्धारण भूमि की उपजाऊ शक्ति, प्रशासनिक ढाँचे तथा कार्रवार की जाति के आधार पर मुख्य तौर पर होता था । ऊँचे वण की जातियाँ रियासती दरों पर लगान चुकाती थी, वैसी ही स्थिति कमोनान् की

१. लेखा बही वि० सं० १८१४/१७५७ ई० बही खाता खजाना मंदर वि० सं० १८५२/१७६५ ई०

२. परगना दे जमा जोड री बही सन् १६३६/१६६३ ई० (पृष्ठ)

३. हासल भाछ री बही वि० सं० १७४०/१६८३ ई० न० १, परगना बणीबाण व बरुड ग बही वि० सं० १७४३/१६८८ ई०, न० २, बीदाबता री—गावा री हासन री बरुड ग बही, वि० सं० १७४५/१६८८ ई० न० ७, हामल बहिया बीकानेर रा० रा० ४० ८०

४. बही

५. बही खालसे दे गावा री व परगने दे जमा जोड री सं० १७५०/१८१३ ई०, न० १२ रा० रा० ४० ४०

६. हामल बही रीणो री सं० १७५२/१६६५ ई० न० १२, बरुड ग बही व बरुड ग बही, वि० सं० १८२७/१७७० ई०, बस्ता न० १ रा० रा० ४० ४०

धी। करो का पूरा बोझ कृषक जातियों पर पड़ता था। शासकीय जाति व चारण तो करमुक्त होती बोलते थे।^१

हासल में 'रोकड़ रकम' से होने वाली आय माघारणतया भोग की आय से अधिक रही है। सम्भव है कि किसी पद्धति या क्षेत्र में भोग की आय अधिक आ गई हो, पर हासल की कुल आय में भोग की तुलना में रोकड़ रकम ही अधिक भारी पड़ी है। स० १७२६/१६६६ ई० से स० १७५०/१६६३ ई० के बीच हासल की कुल आय के उपलब्ध आकड़ों में जहाँ भोग से होने वाली आय ४५ ४४ प्रतिशत रही है, वहाँ 'रोकड़ रकम' की आय ४८ प्रतिशत हुई है। बीजा रकमों की आय ६ ५६ प्रतिशत आई है।^२ ऐसे भी कुछ वर्ष हैं जब भोग की आय 'रोकड़ रकम' की आय से अधिक बढ़ गई। उदाहरणार्थ स० १७४५/१६८८ ई० में जब हासल में 'रोकड़ रकम' का प्रतिशत ३८ ४१ प्रतिशत था जबकि 'भोग' की आय का प्रतिशत ५४ ४० प्रतिशत था। पर अधिकतर भोग की आय 'रोकड़ रकम' की तुलना में कम ही रहती थी। स० १७३१/१६७४ ई० में तो यह उससे आधी रह गई थी।^३

'रोकड़ रकम' का प्रचलन महाराजा अनूपसिंह के काल से प्रारम्भ हुआ था क्योंकि उससे पूर्व राजस्व खातों में इसका विवरण नहीं आया है। सम्भवतः महा राजा अनूपसिंह ने भुगत जागीरों से गिरती हुई आय (१७वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में) तथा राज्य में विद्रोहों के फलस्वरूप बढ़ती हुई सैनिक मागों के कारण वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु इनका प्रचलन किया हो। रोकड़-रकम लागू होने से ही राज्य की भू-राजस्व में पूर्णता भी आई, उससे पूर्व पट्टायत जाति व कबीलों के मुखिया भू-राजस्व का अधिक भाग रखते थे। रोकड़ रकमों के लागू होने के बाद उनके हिस्से में कमी आई। इससे जहाँ राज्य के खजाने की आय बढ़ी वहाँ 'मध्यस्थों' की स्थिति कमजोर हुई।^४

१ बही खालसा र गावा री स० १८२७/१७७० ई०, बस्ता न० १ रा० रा० अ० बी०

२ बही खालसा र गावा री व परगने र जमा जोड़ री (पूर्व) देखिये हासल की सारणी, पृ० १६७

३ बही

४ वित्तीय समस्याओं व समाधान के अध्ययन के लिए देखिए—बही खालसा र गावा री व परगने र जमा जोड़ री (पूर्व) बही समस्त र गावा री (पूर्व) परगनों र जमा खरच री बही न० ३२ स० १७२० ५१/१३६३ ६४ ई०—बीकानेर बहियान्न—रा० रा० अ० बी० जी० एस० एस० देवडा—नेपर एण्ड इसीड स आफ रोकड़ रकम इन दी लेण्ड रेवेन्यू सिस्टम आफ द बीकानेर स्टेट (१६५०/१६०० ई०)—इण्डियन हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव कान्ट्री १९७६

सारणी—अ

भू-राजस्व के प्रमुख स्रोतों की व कुल आय की सूची

(१९६६ ई० से १९६३ ई० तक)

कुल आय (रुपयों में)	वर्ष ई०	रोकड़ रकम (रुपयों में)	भोग (रुपयों में)	बीजा रकमे (रुपयों में)	कुता (जिन्स में)
११४४८५	१९६६	६८४२८	४३७८७	६०६०	मन २४४८१३
६६०१२	१९७०	५६२२१॥	३०१२६।	६६६४	" १३७६३०
१९२०७८	१९७१	३०१७८॥	८३६६६	८२०४।	" ३६८०१०
१०८०६३	१९७२	७५५८४	२००५१	६४५८	" ७१३६५
१५६४८८	१९७३	७२४८६	६८६६०	१८३४२	" ३७६५७०
६०६८३	१९७४	६१०६८	२७५५५	२०३०	" २०७१११
१३७५०३	१९७५	६०४१८॥	५६१३०।	१७६५४।	" ४२८२०३
११८४४४	१९७६	६ ८. ३॥	४४३५४।	१७२५६।	" २२१८६५
१७४५३७	१९७७	६७६४४	१०५३३८॥	१५५४॥	" ४३७७६५
१७४०५७	१९७८	६६६३६	१०२२३१	१८६०	" ३७२८६७
१३४०७१	१९७९	६७२५६	६३७१४	३१०१	" २५१०६२
२१४२८६	१९८०	८३१७४॥	१२४७७०॥	६३६१	" ५८६२६६
११६७५८	१९८१	७८११६	३६५१७	२११८	" १२२६
११६५६१	१९८२	७७३१६॥	४३६७६।	५६५।	" १६८४०
१५४४०२	१९८३	८३६००॥	६०६६६।	११००२	" ६३५००६
१२६८०१	१९८४	७१३७३॥	५४४६८	६५६॥	" ५५४२५०
११८५३८	१९८५	६६४७३	३७६५१	११८१०	" १६६६२६
२०६६२४	१९८६	७५७१७	११२०८७	२१८२०	" ७४२६८०
२१६५७४	१९८७	८६८२७।	११८३०१०	१३४४४	" ६३४४०१
२२२६२४	१९८८	८६६०२	१२१२८६	१२२३४	" ६८२६५६
२२८८२२	१९८९	८५६२६	६८३३१	४६८६६	" ७४६४२१
१७२३१२	१९९०	७६१०६	८६७६३	६४६३	" ७५३६८५
१६७६१०	१९९१	८२१५८	७७५०६	८२६३	" ६६५६५५
१६१४८७	१९९२	८१०४५	७७७३२	२७१०	" ५६७१८८
१५१११३	१९९३	८४७८४	६३६२७	२४०२	" ३७२८२६

३८५०६०५ १८५१८१२ १७६५६७२ २३३१२११ मन १०३२६६०१
प्रतिशत १००% ४८% ४५.४४% ६.५६%

सारणी—ब
हासल आय की सूची
(१६६६ ई० १८०६ ई०)

वर्ष	हासल रकम (रुपये मे)	प्रतिशत १०० के आधार पर	राज्य की कुल आय प्रतिशत मे
१६६६	३४ ३८६	१००.००	१८.३२
१७५७	१४,४३५	४१.६७	१३.१५
१७६५	५६ ६३६	१६४.७०	४२.२६
१८०६	४३,६४७	१२६.६२	४५.६

धुआ भाछ

‘रोकड रकम’, जो अनेक सहायक करो का सामूहिक नाम था, के गठन में ‘धुआ भाछ’ मुख्य थी। ‘धुआ भाछ’ गांव के प्रत्येक घर में जलने वाले चूल्हे की सख्या पर लगाई जाती थी। यह एक किस्म का गृह कर था। धुआ भाछ प्रति चूल्हा अथवा प्रति गुवाडी १ रु० की दर से वसूल होती थी जो १८वीं शताब्दी के अन्त तक बढ़कर १ रु० २५ टका हो गयी थी। चूंकि इसकी रकम ‘रोकड’ में मिल जाती थी व रोकड की रकम हासल में, इस कारण इसकी रकम को अलग से आकना कठिन है। महाराजा अनूपसिंह के काल में ‘रोकड’ की रास पट्टा क्षेत्र से भी वसूल की गई, तब इसका ‘चीरा’ स्तर पर अलग से खाता बनाया गया। तब ‘धुआ भाछ’ को अलग से आका गया। सन् १६६३ ई० में राज्य को इस भाछ में ४०,३६७ रुपये की आय हुई थी। ‘रोकड’ की अन्य रकमों की तुलना में धुआ भाछ की रकम, कुल रोकड की आय में ४० से ५० प्रतिशत के बीच निर्धारित होती थी।^१ इस प्रकार ‘रोकड रकम’ का यह सर्वप्रमुख भाग था।

रोकड की अन्य रकमों में ‘देसप्रठ’, ‘ठाकुरजी’, ‘गुमोईजी’, ‘मेला पाडखती’^२ आदि मुख्य थे। इनके अलावा ‘घास-चारे’ पर भी कर लगाया जाता था, जो

१ धुआ बही—स० १७४६/१६८६ ई०, न० ४५, वही धुआ देस पर—स० १७८६/१७२६ ई०, न० ६०, रोकड बही स० १७६६/१७३६ ई०, न० २२३—बीकानेर बहियात। वही परगना रंजना जोटरी, १६६६/१६६३ ई०, (पूर्व) टाट-२, पृ० ११५७
२ देसप्रठ—वसने का कर; ‘ठाकुरजी’—क्षेत्रीय देवी देवताओं के नाम का कर, गुमोईजी—माधु-मन्त्रों का कर, मेला पाडखती—त्वौहारी का कर।

कि अलग-अलग घास के नाम पर ही वसूल की जाती थी, जैसे—'कोरड', 'भुरज' 'घास-चारा', 'सहत' आदि।^१ इन करो को अधिकतर महाराजा अनूपसिंह, गरुसिंह व सूरतसिंह ने लागू किया था तथा घास-चारे के करो को छोड़कर, रोप को चीरा स्तर पर वसूल किया जाता था। घास-चारा केवल खालसा में ही वसूल किया गया था। पट्टे के क्षेत्र में वसूली के अधिकार पट्टेदार के ही हाथ में रहे गए।^२ राज्य इन करो को प्रति-गुवाडी वसूल नहीं करता था, वस्ति गांव की आर्थिक दशा के आधार पर जमानगी करके रकम को निर्धारित किया जाता था, जिसे हुबलदार व चौधरी गुवाडियों में बराबर बांट कर वसूल करते थे।^३ साधारणतया इन सभी करो की आय 'रोकड रकम' में 'धुआ भाछ' के समकक्ष या उससे कुछ अधिक होती थी। 'देसप्रठ', 'ठाकुरजी', 'गुसोईजी', 'मेला पाद-खती' की कुल आय धुआ भाछ से लगभग आधी होती थी। १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'घास, चारा, भुरज, व कोरड' की आय अवश्य 'धुआ भाछ' के समकक्ष या उससे कुछ अधिक हो गई थी। 'रोकड-रकम' में 'धुआ भाछ' निकल जाने पर बाकी कर 'रोकड रकम' के नाम से जाने जाते थे। १६६३ ई० में कुल 'रोकड रकम' की आय जो ८,३६,१८१ रु० थी, धुआ भाछ की आय का भाग ४०,२६७ रुपये था व बाकी सब करो की आय ४३,८४७ रु० थी।^४

- १ राज्य में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की घास व चारे का नाम है। कोरड—सूखे मोठ व तिन की घास, भुरज भुरट की घास (कटीली), सहत—सेवज नाम की घास—धुवे री गिणती री जमा, वि० सं० १७४८/१६७१ ई०, न० ८७, बही हासल री, वि० सं० १८१०/१७५३ ई०, वस्ता न० १—रा० रा० अ० बी०, टाड—पृष्ठ ११५७
- २ वही
- ३ गो० रोणी रे 'बीरे में गो० नवलसरी री जमा इन भात बास दोबी छ' धुवो५), देसप्रठ ३), धीठाकुरजी ११), गुसोईजी ११), मेसो पादखती ५), देसप्रठ रोयगार १), कोरड ५११), भुरज जखीरी ३) चारो ११) —२२१११), बागद, मगसर मुसी १, ७ अक्टूबर, बागदो की बही, वि० सं० १८२०/१७७३ ई०, न० २—रा० रा० अ० बी०
आर्थिक दशा से यहा छालस्य भाव की भूमि की उपज लवित, रुपि-क्षेत्र, चरागाह भूमि तथा रुपको की दशा से है—हुवाला सोपा कागदो में इस प्रकार निर्देश दिया गया है—
हुवाला सोपा कागद—बागदो की बही, सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३
- ४ धुआ रोकड वही, वि० सं० १७५०/१६६३ ई०, न० ८८ (पूर्व), रोणी रे बीरे रे धुवे देसप्रठ रो लेखो, वि० सं० १८११/१७५४ ई०
आसामी—धुवो ८२१) ५१, देसप्रठ २४८१) २४८/१२६, ठाकुरजी ४६१) ३१, २१५६११) गुसोईजी ४५१११) में पादखती २३२११) आसामी ४८१, देसप्रठ—२१५६११) २५६/३७ २५१/१२, दुलो चौपलाणी २५११) हयसेवो ६६११) कनुवो ४३१) २४१११) २३१) १२७) २८ खरख बघा रे
—वही हासल री, वि० सं० १८११/१७५४ ई०, वस्ता न० १, रा० रा० अ० बी०

हासल की आय में 'रोकड़ रकम' की प्रधानता के उपरान्त भी 'भोग' की आय में वृद्धि के कारण उसका प्रभाव बना रहा। सन् १६६६ ई० से १६६३ ई० के बीच के काल में राज्य की हासल की आय में वृद्धि के पीछे एक कारण भोग की आय में वृद्धि होना था। 'भोग' की आय में इन वर्षों में बीच ४५ ७७ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भोग की अधिकतम आय के वर्ष सन् १६८०, १६८६, १६८७ व १६८८ ई० थे, इनमें क्रमशः १८४ ६५ प्रतिशत, १५५ ६८ प्रतिशत, १७० ७० प्रतिशत व १७६० ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भोग आय की वृद्धि के पीछे मुख्य कारण फसल के उत्पादन तथा भोग के प्रतिशत में वृद्धि होना था। उत्पादन इन वर्षों में ५२ २६ प्रतिशत बढ़ गया था। अच्छी वर्षा के वर्षों में उत्पादन १०० से २०० प्रतिशत के बीच भी बढ़ा था। सन् १६६० ई० में उत्पादन ३०७ ८६ प्रतिशत होकर २०६ ८६ की वृद्धि का अधिकतम बिन्दु पर पहुँच गया था।^१ फसल उत्पादन में यह वृद्धि राज्य के लिए इसलिए उत्पादक थी, जबकि इन वर्षों में भारत बुरी तरह से अभ्यवस्था का शिकार था।^२ 'भोग' के प्रतिशत में भी वृद्धि उपर्युक्त १/५, १/६, १/७, १/८, के स्थान पर १/३, १/४ व १/५ पर बल देने से हुई गई थी।^३ भोग वृद्धि के साथ साथ महाराजा अनूपसिंह द्वारा रोकड़ रकमों में लगे बरा के निर्धारण में भी हासल की आय को वृद्धि-लाभ प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त इन वर्षों में खालसा गांवों की सख्या भी २०० से बढ़कर २५० में लगभग पहुँच गई थी।^४

१८वीं शताब्दी में भी हामल की आय में निरन्तर वृद्धि होती रही थी। सन् १६६६ ई० की आय के आधार पर हासल आय सन् १७६५ ई० तक ६४ ७० प्रतिशत बढ़ गई थी। सन् १८०८ ई० में भी इसकी वृद्धि २६ ६२ प्रतिशत थी। प्राप्त आंकड़ा में केवल सन् १७५७ ई० का वर्ष ही ४६ ३ प्रतिशत की बढ़ी जतजाता है।^५ यह वर्ष अकाल व सैनिक गतिविधियों का वर्ष था। हामल आय में वृद्धि का मुख्य कारण भूमि का विस्तार, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, बरा की दर में वृद्धि इत्यादि थे।^६ इसका साथ राज्य प्रशासन द्वारा छूट आदि देकर कृषि को प्रोत्साहन देना भी था। यह छूट कृषकों का अत्यधिक कर दबाव से

१ समस्त गाँवों से बहो (पूर्व) टॉल २, पृष्ठ ११३७ दण्डित सारणी ८

२ गजपत बंद—उत्तर मुघलशाहीन भारत—प्रथम अध्याय, इरफान हुसीन—दो एंग्लो-सिन्धु घाट मुघल शाहिया—नवम् अध्याय

३ हासल बहो रोषा से स० १०१२/१६६३ ई० (पूर्व)

४ हासल बहो स० १०२५/१६९८ ई० (पूर्व)

५ दण्डित सारणी—८

६ राज्य की मुख्य परपनों के मिल जाने से भोज विस्तार, विस्तृत व बहुत घनी का विस्तार, तथा रोड़ रकमों के बंधन को रोक, भूख व भूमि घाट में वृद्धि आदि कारण थे।

मुक्त कर फिर कृषि व्यवसाय में जुटा देती थी ।^१

१७वीं शताब्दी में हासन आय राज्य की आय का सर्वप्रमुख साधन थी, लेकिन १८वीं सदी में 'पेशकसी' की आय हासल से अधिक बढ़ गयी थी । १७वीं शताब्दी में कुल आय में हासल की स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव आये थे । सन् १६६६ ई० में जहाँ इसकी स्थिति कुल आय में १८.३२ प्रतिशत थी वहाँ १७५७ ई० में १३.१५ प्रतिशत रह गयी । सन् १७६५ ई० में कुल आय की ४२.२६ प्रतिशत होने पर हासल की आय सर्वप्रमुख आय के रूप में सम्मानित हो गयी । इसी प्रकार १९वीं सदी के प्रारम्भ में १८०६ ई० में हासल की आय घट कर केवल ४.५६ प्रतिशत रह गई थी जो कि इसका निम्न बिन्दु कहा जा सकता है । इस वक़्त राज्य की आय में पाँच गुना में भी अधिक वृद्धि हुई थी । इस कमी का मुख्य कारण यह नहीं था, कि हासल की आय में गिरावट आयी हो, बल्कि प्रशासन ने कृषि का छोड़कर अन्य उपायों से आय में वृद्धि की थी । नये करो तथा बढ़ती हुई पुराने करो की दरों का दबाव इस पर नहीं डाला जाता था, ताकि कास्तकार अधिक से अधिक भूमि जोतने का साधन न छोड़ सकें ।

(१) पेशकसी-करोही—शासक के अधीन जितने भी ठाकुर, बबीलौ के मुखिया, गांव के चौधरी, पटावरी, 'जमींदार', तथा मुत्सद्दी व हजुरी थे, वे शासक को विभिन्न अवसरों पर 'नजराना' देते थे, जिस 'पेशकसी' कहा जाता था । 'नजर' इससे भिन्न होती थी । प्रत्येक नया पट्टेदार पट्टा प्राप्त करने पर, चौधरी, पटावरी व जमींदार अपने पद की सनद प्राप्त करने पर तथा मुत्सद्दी व हजुरी अपने पद की नियुक्ति का परवाना प्राप्त करने पर शासक को पेशकसी देते थे । इसके अलावा शासक के विहासनारोहण पर, जन्म-दिन, विवाह, पुत्र-जन्म, राज परिवार में विवाह, उनसे मिलन के समय आदि अवसरों पर भी भेंट की जाती थी 'नजर' कहलाती थी । इसकी आय भी पेशकसी में गिनी जाती थी । इन सब रकमा का निर्धारण क्रिम आधार पर होता था, इसका विवरण उपलब्ध नहीं है । साधारणतया यह स्थिति व सम्मान के अलग अलग मापदण्डों पर १००० से १०,००० रुपये के बीच तय होती थी ।^१ वास्तव में यह कर एक

१ करो में छूट का तात्पर्य यहाँ करो में कटौती तथा घटपटान के अर्थ उनकी समाप्ति से है । वापसी की प्रत्येक बही में अलग से छूट के पत्र मिलते हैं । उदाहरणार्थ न० ३, ७, ६, १०, १७ देखिये । छूट के महत्त्व के लिए इसी अध्याय में 'छूट' शीर्षक के अन्तर्गत विवरण दी देखिये ।

२ पट्टा बही वि० सं० १६८२/१६२५ ई० न० १ वि० सं० १६६२/१६३५ ई० न० २, वि० सं० १७०४/१६४७ ई०, न० ३, बही खासना रे गावा री, वि० सं० १७६१/१७०४ ई० न० १०१ बही पेशकसी वि० सं० १८१४/१७३७ ई०, वि० सं० १८१७/१७६० ई०, वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, वि० सं० १८६०/१८०३ ई०—महकमा पेशकसी, ग० रा० अ० बा०

शासक की सर्वमान्य निर्णायक शक्ति का प्रतीक था। महाराजा अनूपसिंह ने महाजन के ठाकुर को पट्टा देते समय ८०,००० रुपये की पेशकशी वसूल की थी।^१ १८वीं शताब्दी में पेशकशी एक नियमित कर की भाँति हो गई थी, जो प्रत्येक राज्य-निवासी से वसूल की जाने लगी थी। साहूकारों व व्यापारियों से विभिन्न उत्सवों पर, झगड़ों में दण्ड के रूप में व अन्य किसी अपराध में 'गुनेहगारी' के रूप में पेशकशी वसूल की जाने लगी। 'फरोही कर', जो दण्ड व 'गुनेहगारी' का मिश्रित रूप था, को भी पेशकशी में सम्मिलित कर दिया गया।^२

१६वीं व १७वीं सदी में पेशकशी की आय राज्य की कुल आय का एक मुख्य अंग थी, परन्तु १८वीं शताब्दी में यह आय का सर्वाधिक स्रोत बन गई। इस काल में, इस आय में, निरन्तर वृद्धि हुई थी। सन् १६६६ ई० की तुलना में यह, शताब्दी के अन्त तक, ६५.६७ प्रतिशत बढ़ गई। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में १८०६ ई० में यह अपनी वृद्धि के अधिकतम बिन्दु ६७५.५७ प्रतिशत पर पहुँच गई। इस काल में महाराजा सूरतसिंह ने, विद्रोही ठाकुरों से पेशकशी की रकम बढ़ा-चढ़ाकर सक्ती से वसूल की थी। फिर भी नियमित कर के रूप में प्रत्येक जाति से वसूल की गई।^३ गाँवों में भी पेशकशी एक कर के रूप में प्रत्येक गुवाड़ी से वसूल की गई।^४ महा तक कि 'नजराना' भी एक 'भाछ' (कर) के रूप में वसूल किया गया।^५ सरकारी व अर्द्ध-सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को तो यह कर सदा में ही नियमित रूप से देना पड़ता था।^६ इन सब कारणों से १५७ ई० के वर्ष को छोड़कर जो आर्थिक आपत्ति का वर्ष था, इस शीर्षक के अन्तर्गत राज्य की आय सदैव बढ़ती रही। १८०६ ई० में यह बढ़कर २,०३.७१७ रुपये हो गई थी, लेकिन १७६५ ई० की कुल आय की तुलना में २३ प्रतिशत गिर गई थी क्योंकि इन वर्षों में, राज्य को अन्य करों से भी बहुत

१ परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई० (पूर्व)

२ वही पेशकशी, वि० सं० १८१४/१७५७ ई०, वि० सं० १८१७/१७६० ई०; वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, वि० सं० १८२३/१७६६ ई०, वि० सं० १८३४/१७७४ ई०, वि० सं० १८४३/१७८४ ई०, वि० सं० १८६०/१८०३ ई०—महकमा पेशकमी (पूर्व) गुनेहगारी के लिए—वही पेशकशी रै लेखें रो वि० सं० १८३३/१७६६ ई० बीकानेर—रा० रा० अ० बी

फरोही के अन्तर्गत आने वाले सभी वर आर्थिक दण्ड के स्वरूप होते थे।

३ कीरायत लोगो की भाछ—कागदों की बही—सं० १८५१/१७६४ ई०, न० ८, छूट के कागद, सं० १८५६/१८०२ ई०, न० १२, पृष्ठ ४०२, सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृष्ठ ३३, सं० १८६७/१८१० ई०, न० १६, पृष्ठ १५, ३२

४ कागदों की बही—न० १०, भाद्र सुब १३, १८५४/४ सितम्बर, १७७७ ई०

५ वही—सं० १८७०/१८१३ ई०, पृष्ठ ८५, १७६, सं० १८७२/१८१५ ई०, पृष्ठ १२, १४

६ वही—सं० १८३३/१७७८ ई०, न० ५, पृष्ठ ३१, सं० १८७३/१८१६, पृष्ठ ४६

आय हुई थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि करो के रूप में पेशकशी से होने वाली आय राज्य के खजाने में जमा होती थी, शासक को व्ययितगत दी गई भेंट का कोई उल्लेख नहीं होता था।^१

पेशकशी की कुल आय की सूची

वर्ष	रकम (रूपयों में)	कुल आय में प्रतिशत	आय का प्रतिशत (१०० के आधार पर)
१६६६	३०,१५८	१६.०६	१००.००
१७५७	३३,५५८	०७.६४	२८.६१
१७६५	५६,०६३	४४.०६	१६५.६७
१८०६	२,०३,७१७	२१.४०	६७५.५७

(३) जमात—वस्तुतः, यह सीमा शुल्क, आयात-निर्यात कर तथा घुगी कर का मामूहिक नाम था जो कि मुख्य रूप से इन वस्तुओं पर लिया जाता था, जो बाहर से आती थी, बाहर जाती थी, राज्य क्षेत्र से गुजरती थी या यहाँ बिकती थी।^२ मुगल कानून में 'घतन जागीर' के क्षेत्र से इस तरह की होने वाली आय को 'राहदारी' कहते थे।^३ सम्राट अकबर ने राजा रायसिंह को बीकानेर क्षेत्र में होने वाली सीमा-शुल्क की आय को लेने से मना कर दिया था। केवल 'मागों' की चौकसी व सुरक्षा हेतु 'गने वाले' आवश्यक खर्चों के लिए 'राहदारी' शुल्क, लेने की स्वीकृति दी थी।^४ श्रीमण्डी में इसे वसूल किया जाता था। सन् १६६८ ई० में इसकी कुल आय केवल १२२५ रु० थी। मुगलों के वैभव के लुप्त होने के पश्चात् इस शुल्क की आय बढ़ने लगी। राज्य के क्षेत्र में दिल्ली-मुल्तान,

- १ महाराजा अनूपसिंह ने महारज क ठाकुर से जो ८०,००० रुपये लिये थे, उसका खजाने की रसीदों में कोई उल्लेख नहीं है—परवाना वही सं० १८००/१७४३ ई०
- २ जमात खरच वही, वि० सं० १७५४/१६६७ ई०, न० ७३, वही मण्डी जमात, वि० सं० १८०६/१७५२ ई०, न० ८३, वही जमात आमदनी, वि० सं० १८२२/१७६५ ई०, न० ८४—जमात बहिया, बीकानेर, रा० रा० सं० बी०
- ३ सम्राट अकबर का रायसिंह को फरमान दि० १२, रजब-उल-मुराज्जब ६६०, हि० सं०, २५ अप्रैल, १५६२ ई० (पूब), डा० ए० एल० धावास्तव—अकबर, भाग २ (पूब), पृष्ठ २३४, डा० जी० एल० शर्मा—राजस्थान स्टडीज (पूब), पृष्ठ १८२-१६
- ४ सम्राट अकबर का राजा रायसिंह का फरमान—१२ रजब उल मुराज्जब ६६० हि० सं०, २५ अप्रैल, १५६२ ई०

मुल्तान-पाली, जयपुर-मिन्ध के ग्रहर, दिल्ली-रीणी पाली के मार्ग गुजरते थे ।^१ राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में मराठों के आगम से, व्यापारियों ने लिए इन मार्गों का महत्त्व बढ़ गया था । 'श्रीमण्डी' के अलावा राज्य में नोहर, रीणी, चूड़, पूगल, महाजन अनूपगढ़ हनुमानगढ़, लूणकरणसर की मण्डिया मुख्य थी, जो 'जगात' बसूली करती थी । इनके अलावा इन मण्डियों की चौकिया भी होती थी । राज्य में जसगामर, पुनरामर राजलदेमर, गधीली, रावतमर, छारदारा, झम्बू व बालू की प्रमुख चौकिया थी । वड़े गावों में 'जगात' बसूली के लिए 'भोसावणीयो' की नियुक्ति की जाती थी ।^२ मण्डियों की 'जगात' मुकाते पर भी चढ़ा दी जाती थी ।^३ 'आमापीदार चाकर पट्टेदार' भी अपने क्षेत्र में, शासक की स्वीकृति के पदचात्, 'जगात' की बसूली करते थे ।^४ नाधारणतया राज्य में 'जगात' का मुख्य, वस्तु के मूल्य का ३ प्रतिशत होता था ।^५ पट्टायतो को कुल मुल्क का एक तिहाई प्रदान किया जाता था ।^६ मुगल साम्राज्य के सशक्त प्रशासन-बाल में राज्य को, इसके अन्तर्गत बहुत कम आय प्राप्त होती थी ।^७ सन् १६६६ ई० में जगात से राज्य को केवल १२२६।) ४० की आय हुई थी । १८वीं सदी में राजपूताने के अन्य क्षेत्रों में परस्पर सघर्ष व मराठों के निरन्तर आक्रमणों

१ वही समझता है जमा खरब री, वि० स० १७५८/१७०१ ई०, न० ७७—बीबानेर बहियात, साबा वही रीणी वि० स० १८१४/१७५७ ई०, न० १, साबा मूरतगढ़, वि० स० १८४४/१७८७ ई०, न० १, साबा अनूपगढ़, वि० स० १७५३/१६६९ ई०, न० ६, साबा नोहर, वि० स० १८५३/१७६८ ई०, न० ८—रामपुरिया रिकार्ड्स, बीबानेर—रा० रा० अ० बी०, पाउलट—गवेटियर (पूर्व), पृष्ठ ६९-६७, डा० जी० एन० हर्मा—राजस्थान रटडीज, पृष्ठ १६२ ६६ (पूर्व), जी० एस० एस० देवडा—सोशियो-इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान (पूर्व), पृष्ठ ३६-४५

२ वही जगात आमदनी न० १८२२, न० ८३, साबा नोहर, रीणी, भादरा, गधीली, चूड़, जसरासर, पूगल, अनूपगढ़ हनुमानगढ़ की बहिया, न० १-५, रामपुरिया रिकार्ड्स, बीबानेर—रा० रा० अ० बी०, भोसावणीया का धर्म यहाँ निबरानी रखने वाले अधिकारी से है ।

३ बागदों की वही—मुकाता जगात—आश्विन बदि ११, वि० स० १८२७, १५ सितम्बर, १७७० ई०, न० ३, लिखत के बागद—वि० स० १८६६/१७८२ ई०, न० ६

४ महाजन का पट्टा—परवाना वही, वि० स० १७४६/१६६२ ई०, भैया सग्रह—महाजन रे पट्टे री विगत, वि० स० १८२१/१७६४ ई०

५ वही जगात आमदनी, वि० स० १८२२/१७६५ ई०, न० ८३; बागदों की वही, वि० स० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृष्ठ २२; वि० स० १८३१/१७६४ ई०, न० ८, प्रचुण

६ महाजन का पट्टा—परवाना वही, वि० स० १७४६/१६६२ ई०, बागदों की वही, वि० स० १८५४/१७६७ ई०, न० १०, पृष्ठ ४६

७ इसकी अधिकतर आय मुगल खजाने में जाती थी—डा० ए० एस० श्रीवास्तव—अवर, २, पृष्ठ १६८

के कारण, बीकानेर क्षेत्र के आगारिक मार्ग अधिक प्रयोग में लाने लगे थे। १७५७ ई० में यद्यपि 'जगात' की आय कुल आय की, १.८२ प्रतिशत थी; परन्तु सन् १६६६ ई० की तुलना में इसमें ८८ ८५ प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। सन् १७६५ ई० में 'जगात' की आय २४४५.६३ प्रतिशत की आश्चर्य-जनक प्रगति के रूप में रही तथा उस वर्ष की कुल आय में भी इसकी स्थिति २२.३० प्रतिशत की रही। सन् १८०६ ई० में चिद्रोह व संधर्ष की स्थिति के बावजूद, सन् १६६६ ई० की तुलना में यह वृद्धि २०५० ०४ प्रतिशत की हुई। परन्तु कुल आय में इसका प्रतिशत केवल २.६६ प्रतिशत रह गया। १८वीं शताब्दी में राज्य की आय को बढ़ाने में 'जगात' का प्रमुख योगदान था, क्योंकि उससे पूर्व, राज्य की आय में इसका नाममात्र का ही भाग रहता था।

जगात वसूली के लिए 'श्रीमण्डी' मुख्य केन्द्र था। लेकिन 'श्रीमण्डी' से होने वाली आय में, 'जगात' के अलावा अन्य कर भी वसूल किये जाते थे; जैसे—

१. जमीं चौध या धरती की चौपाई—जो कि जमीन की बिक्री के मूल्य का चौथा भाग होती थी।

२. छोला—गोद लाने पर कर, यह व्यक्ति की समृद्धता के आधार पर आका जाता था।

३. बलाली कर—विभिन्न वस्तुओं से सम्बन्धित दलाती कर, जो साधारणतया 'मुकाते' पर चढ़ा दिया जाता था।

४. गईवाल—नावारिस सम्पत्ति, जिस पर राज्य का अधिकार माना जाता था।

५. सोना-चांदी की छदामी—जोकि स्वर्ण तथा रजत की बिक्री पर लगता था।

६. स्पोटा—यह दुकानदारों पर लगाया गया कर था तथा ऊटों की बिक्री आदि पर लगाया जाता था।

७. जुए का मुकाता—यह जुआ खेलने वालों पर लगाया जाने वाला कर था, जो मुकाने पर बढ़ाकर मुकाती में रकम लेकर वसूल किया जाता था।

८. रूतरी, छड़ोमी तथा अफीम का सौदा—यह अफीम तथा वर्षा की सभावना के सट्टे पर लगाया जाने वाला शुल्क था।

९. कीरायत लोगों की भाछ—इसे 'सूरसागर की भाछ' कहा जाता था तथा शहर की प्रत्येक जाति से इसे वसूल किया जाता था।

१०. हुवलदार-दरोगा का लाजना—'श्रीमण्डी' के प्रमुख अधिकारी तथा दरोगा के नाम से यह कर वसूल होता था।

११. तालाब घड़सीसर की भाछ रा—घड़सीसर तालाब में पानी पीने पर यह कर लगाया जाता था।

१२ मेर की खाण, रा—यह मुस्तानी मिट्टी के उत्पादन का शुल्क था ।

१ चुगो बिछाइती माल रो—धूल में वस्तुओं को बेचने वाला पर यह वर था ।

१४ सेहर कोट की जगात—किने की मरम्मत आदि क लिए यह कर रिया जाता था ।^१

श्रीमण्डी क अलावा अ य मण्डियों की आय का और भी इसी प्रकार था, उनमें जगान के माथ माथ कसूर फरोही व गुनेहगारी की रकम भी जमा कर ली जाती थी ।^१

(४) ■ य कर—राज्य में सना के खर्च के नाम पर जो कर वसूल किया जाता था वह खड खरच या फौज खरच के नाम से विख्यात था । शासक की अपनी कोई निजी विशाल सना नहीं थी जिससे कि उसे सेना के एक बड खर्च का भार वहन करना पड । राज्य की सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ठाकुरों की जमीयत से पूरी होती थी । लडाई के समय खानमा व पट्टा क्षत्र से खेड खरच भाछ वसूल कर ले जाती थी । महाराजा रायसिंह ने इसे एक स्थायी कर का स्वरूप प्रदान कर दिया था ।^१ इससे होने वाली आय अधिक नहीं थी । १७५७ ई० में यह कुल आय की ० १३ प्रतिशत थी तथा सन १७६५ ई० में इसकी स्थिति ० २६ प्रतिशत की थी । सन १८०६ ई० में यह फौज खरच के नाम से वसूल की गयी थी जो कि कुल आय की १ १६ प्रतिशत थी । वसूल होने वाली आय १७६५ ई० में ३६६ रुपये की तुलना में ११ ३ ८७ रु० थी । १८वीं शतब्दी में विभिन्न सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खड खरच की भाछ दश में जाती

१ मण्डी बहिया वि० स० १७८३/१७८६ ई० वि० स० १७८६/१७८८ ई० वि० स० १८०७/१७१० ई० स० ७८ ७६ ८० जगात रो साहबा बही वि० स० १८१७/१८०० स० २४६—बीकानेर बहियात नागदो की बही—न० २ चन्न बदि १४ १८२० ३१ मार्च १७६४ ई० न० १२ बन्नाख बदि १२ भाद्र बदि ४ चन्न बदि ११ १८५६ २६ अग्रत १६ अगस्त १८०२ ई० १६ भाष १८०३ ई० सोहनलात—तबारिख राजपूरी बीकानेर पृष्ठ २४१ ४३

२ साबा बही अनपगड वि० स० १७१३/१६६६ ई० न० १ साबा बही नोहर वि० स० १८२२/१७६६ ई० न० १ साबा बही भरू देवाय रो वि० स० १८२६/१७७२ ई० न० १ साबा बही रोणी वि० स० १८१३/१७६८ ई० न० ८—रामपरिया रिक ड स भूम्या संग्रह—बही गी नोहर र थाण रो जमा खरच वि० स० १८७३/१८१६ ई० बही अनपगड र जमा खरच रो वि० स० १८७७/१८२० ई०—बस्ता न० ४ बीकानेर

३ कामगारो व बकाला के रोजगार की बही वि० स० १७१३/१६६६ ई० न० २०६ बही हजर रे खड रो वि० स० १८०३/१७४६ ई० न० २०८—बीकानेर बहियात कामदो की बही—न० २ अगिबन बदी ७ १८२० २६ सितम्बर १७६३ ई० न० १४ स० १८६३/१८०६ ई० पृष्ठ १३३

नाम का, कर अलग से भी वसूल किया गया था। सन् १७७४ ई० में राज्य को इससे २६,८४४ रु० की आय हुई थी।^१ सन् १७८१ ई० में यह राजपूतों की अलग-अलग धारों से वसूल की गई थी।^२ सन् १८०६ ई० में मारवाड़ आक्रमण के कारण फौज खर्च प्रति-गुवाडी २० रु० की दर से वसूल किया गया था।^३ सन् १८१८ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा, महाराजा सूरतसिंह को सैन्य सहायता देने के परिणामस्वरूप, उस सेना का खर्च वहन करने हेतु प्रति-गुवाडी १५ रु० की दर से, एक लाख रुपये प्रजा से वसूल किये गए।^४

घोड़ा व हथवाली भाछ — महाराजा सूरतसिंह के समय कई नये सैन्य करो की शुरुआत हुई थी। उनके शासनकाल में जब राज्य में राठो, सिक्खो, जोड़ियो तथा ठाकुरों के विद्रोह व सूट से उत्पात मच गया था, तब उन्होंने देश में उन्हें रोकने के लिए बड़े मये सैनिक दायित्वों की पूर्ति हेतु 'हथवाली भाछ' (रक्षात्मक कर) लागू किया।^५ सन् १७६५ ई० में आस-पास इस कर को सर्वप्रथम वसूल किया गया। यह कर न केवल व्यक्तिगत पर बल्कि पशुओं पर भी लगाया गया था।^६ पहले इसकी दर प्रति-गुवाडी २ रु० थी, जो सन् १८०० ई० के बाद प्रति-गुवाडी १ = रु० हो गई।^७ इस खाससा व पट्टे के गावों में समान रूप से वसूल किया गया था। पट्टायतों को इस कर व इनकी दर के प्रति भारी असंतोष था, जत इस कर का वसूली में कठिनाईया आती रहती थी।^८ सन् १७६५ ई० में इसकी कुल रकम १६,२३५ रु० की थी, जो कुल आय का १४ ३५ प्रतिशत थी। सन् १८०६ ई० में यह घटकर १७ ७०३ रु० हो गयी, जोकि कुल आय की १ ८६ प्रतिशत रह गयी।

महाराजा सूरतसिंह ने ठाकुरों के विद्रोही हथकों देखते हुए, उनकी सैन्य शक्ति पर निर्भर रहना छोड़कर, उनकी 'जमीयत' की जाकरी बन्द कर दी थी, तथा उसके स्थान पर शासक की निजी सना तैयार की थी। उसके खर्च को

१ हनुव बही, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, बस्ता न० १, बीकानेर

२ हनुव बही, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, बस्ता न० १, बीकानेर

३ भैंया सग्रह जेठ सुदी २, वि० सं० १८६६, १६ मई, १८०६ ई०, बस्ता न० २

४ भैंया सग्रह—बही फौज के भाछ रो, वि० सं० १८७३/१८१८ ई०, छायरा कागद पोप बदी १२, १८७३, २४ दिसम्बर, १८१८ ई०

५ टाह-२ पृष्ठ ११५६; सोहनवाल—तवारीख (पू०), पृष्ठ ३०२

६ गुवाडी १ रु० १, ऊठ १ रु० २, बनद १ रु० ११, २५, भैंस १ रु० १, गाय १ रु० ११, २५, कंण २० रु० ११, २५—हनुव बही, वि० सं० १८५४/१७६० ई०, बागदो की बही, वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ २६

७ बागदो की बही, वि० सं० १८६३/१८०६ ई०, न० १६, पृष्ठ १६६, वि० सं० १८७१/१८१४ ई०, न० २०, पृष्ठ ३२२

८ भैंया सग्रह—आश्विन सुदी ८, १८६४, ६ अक्टूबर, १८०७ ई०

वहन करने के लिए ठाकुरों से सवारों के स्थान पर नगदी रकम, 'घोडा-रेख' के नाम से, वसूल करने प्रारम्भ की।^१ इस 'रेख' का प्रारम्भ भी सन् १७६४ ई० के लगभग हुआ था।^२ प्रारम्भ में प्रति घोड़ा ५० रुपये के लगभग लिये गये,^३ जो १८०० ई० के बाद बढ़कर प्रति घोड़ा रुपये १००) निर्धारित किए गये।^४ यह कर केवल पट्टायतो से वसूल किया जाता था।^५ बाद में यह कर हटावाली की भाछ के साथ मिल जाने पर केवल 'रेख' कहलाया। बाद में १९वीं शताब्दी के मध्य में 'दरबार की रकम' कहलाया, जो पट्टे की कुल आय का तिहाई हिस्सा होती थी।^६ इस कर व कर की दर को लेकर शासक व ठाकुरों के बीच सम्बन्धों में सदैव तनाव बना रहता था।^७ सन् १८०६ ई० में इससे होने वाली आय ४६,१४३ रु० थी, जोकि कुल आय का ४८% प्रतिशत थी।

प्रशासन ने उपरोक्त करा के अलावा कभी-कभी 'घाणो की भाछ' तथा 'सिपाही-भाछ', जोकि शासक के निजी सैनिकों से ली जाती थी, को भी वसूल किया था।^८

(५) कसूर या जुर्माना—राज्य अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करने पर, चोरी के माल पर, जाली सिक्के बनाने पर, कर न देने पर, पट्टायतो द्वारा उत्तरदायित्वों को भली भाँति न निभाने पर, राजाज्ञा की अवहेलना करने पर तथा विभिन्न सामाजिक व जाति-व्यवस्था के दण्ड व 'गुनहगारी' के रूप में, जो जुर्माना लगाया जाता था, उसे 'कसूर' कहा जाता था।^९ यह 'कसूर' दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार का होता था। इस कर की प्रवृत्ति को देखते हुए इसकी आय घटती-बढ़ती रहती थी। सन् १६६८ ई० में जहाँ यह १६५१ रु० थी, वहाँ सन् १७५७ ई० में ४१६ रु० ही थी। सन् १७६५ ई० में यह कुल आय की १/६६ प्रतिशत थी, और सन् १८०६ ई० में ५,३६५ रु० की आय होने पर भी ०.५६ प्रतिशत मात्र ही थी। सामाजिक क्षेत्र में व्यभिचार, रीति-रिवाज

१ टाड (पूर्व), पृष्ठ ११५६, सोहनताल, (पूर्व) पृष्ठ ३०२

२ कागदों की बही, वि० सं० १८५१/१७६४ ई०, न० ८, प्रमुख कागद

३ कागदों की बही वि० सं० १८५४/१७६७ ई०, न० १०, छूट कागद

४ कागदों की बही, वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११ छूट कागद, भेंया सग्रह—पत्र पोप बही ११, १८६४, २५ दिसम्बर १८०७ ई०, कागदों की बही, सं० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृष्ठ १०१-१०८

५ राठम की तरफ से स्पष्ट निर्देश के लिए देखिये—कागदों की बही, सं० १८७३/१८१६ ई० न० २२, पृष्ठ १०१

६ देशदण, पृष्ठ ६४ (पूर्व)

७ दयालदास श्याम, (घट्ट ०) २, पृष्ठ ३१४-१८

भेंया सग्रह—छजाना बही, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०

बही पेशकशी के लेखों से, वि० सं० १८१३/१७७६ ई०

मताब्दी के अन्तिम वर्षों में यह भाछ राज्य की समस्त जातियों (राजपूत, ब्राह्मण व साहूकारों को छोड़कर) से वसूल की गयी। बीकानेर नगर के लिए इसे 'सूर-सागर की भाछ' भी कहा जाता था। मात्ती व सिक्कें अलग से 'कोहूर की भाछ' भी देते थे।^१ सन् १७६५ ई० में कुल आय में इस कर की आय १४० प्रतिशत थी। सन् १८०६ ई० में यह १४,१२८ रु० थी, जोकि कुल आय का १.४६ प्रतिशत थी। इसके अलावा 'ब्राह्मणों की भाछ' को ब्राह्मणों से वसूल किया गया, जिसे महाराजा सूरतसिंह ने प्रथमवार लागू किया था। राजपूतों से 'खेड खरब की भाछ' वसूल की जाती थी।^२

व्यावसायिक जातियों में अलग से 'साहूकारों की भाछ' भी थी, जो व्यापारियों, विप्रेताओं तथा सूदखोरों से वसूल की जाती थी। साहूकारों की भाछ भी 'मात-हजारी', 'साठ हजारी', 'दो लाख की' के नाम से जानी जाती थी। साहूकारों की गुल्लक पर भी यह भाछ लगायी जाती थी। सम्भवत यह प्रत्येक साहूकार की आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर निर्धारित की जाती थी।^३ महाराजा गजसिंह व सूरतसिंह के समय में, साहूकार इस भाछ के दबाव से देशनोक खले जाते थे या राज्य छोड़कर बाहर भी निकल जाते थे, तब उन्हें पुनः राज्य में आने को प्रोत्साहित करने के लिए करो में छूट प्रदान की जाती थी।^४ सन् १७५७ में इसकी आय १२,५७७ रु० थी, जोकि कुल आय की १२.३८ प्रतिशत

१. वही घडसीसर तालाब की, स० १७४५/१६८८ ई०, न० ५५, वही अनोपसागर—स० १८११/१७५४ ई०, न० २३३, नागदो की वही—माघ बदि १, स० १८५१, ६ जनवरी, १७५४ ई०, न० ८, इस वही के छूट के कागद भी देखिए, न० १२, ज्येष्ठ बदि ८, १८५६, २४ मई १८०२ ई०, स० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृ० ४०२, १४, ३२, ३३, ४२, पाणी पीछरी जमा खरब वही, स० १८७७/१८२० ई०, न० २५०—बीकानेर बहिषात। यहाँ तक कि ब्राह्मणों, वैरागियों व स्वामियों से भी इस कर को वसूल किया गया जबकि ये लोग इस कर से मुक्त रहते थे—नागदो की वही, स० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृ० ४१, ४२
२. वही हनुवरी, स० १८३१, १८५४/१७७४, १७६७ ई०, हनुव बरता—बीकानेर
३. मण्डी के साहूकारों की वही, स० १७२६/१६६६ ई०, न० २३२, साहूकारों के गुल्लक की वही, स० १८६१/१८०४ ई०, न० १६०; साहूकारों के भाछ की वही, स० १८६५/१८०८ ई०, न० १५६—बीकानेर बहिषात; कागदों की वही, स० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृ० १६
४. देशनोक बीकानेर नहर से ३० किलोमीटर दक्षिण में बीकानेर-जोधपुर मार्ग पर स्थित है, यहाँ राज्य की मुचदेवी करनीजी का मन्दिर है। सत्ता के प्रयोग से बचने के लिये यहाँ करण पाते थे।
५. कागदों की वही, न० ७, पोष बदि ७, १८४०, १६ दिसम्बर, १७८३ ई०, स० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० १२०, जो० ए० ए० देवडा—व्यूरोकेसरी इन राजस्थान, पृ० ७८

धी व सन् १८०६ ई० मे २१,४७८ रु० थी, जो कुल आय की २.२६ प्रतिशत थी।

(११) अधिकारियों व कर्मचारियों की भाछ—राज्य का प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी अपनी नियुक्ति के अवसर पर, शासक को पेशकशी व नज़र भेंट करता था। महाराजा सूरतसिंह ने इसे एक नियमित कर के रूप में परिवर्तित कर दिया। मुत्सद्दियों से 'कामदारी भाछ', 'हज़ूरियों' से हज़ूरियों की भाछ' चौधरियों से 'चौधरवाब' तथा पटवारियों से 'पटावरवाब' वसूल की। साधारणतया यह प्रति व्यक्ति १५ रु० की दर से वसूल की गयी। कामदारों की भाछ व हज़ूरियों की भाछ, राज्य की कुल आय का ३ प्रतिशत तथा चौधरी व पटावरी-वाब मिलकर कुल आय का ०.५८ प्रतिशत भाग पूरा करती थी। महाराजा सूरतसिंह ने हुबलदारों से 'हुबलदार भाछ', नियमित सेना के 'सिरबन्धीयों' से 'सौरबन्धीयों की भाछ' तथा 'परदेसी' सिपाहियों से 'परदेसियों की भाछ' भी वसूल की थी, परन्तु ये कर नियमित नहीं थे।^१

(१२) चराई—'पठत' की जमीन व 'जोड़' में पशुओं के चरने पर 'पान चराई' कर वसूल किया जाता था। यह प्रति ऊट ५ रु०, बैल १ रु०, गाय १ रु०, बकरी १) आना की दर से वसूल की जाती थी। पट्टा क्षेत्र में चराई कर को 'भूगा' कहा जाता था। कर प्रति जानवर १ रु० की दर से उन पशुओं पर लिया जाता था, जो अन्य क्षेत्र से पट्टा के क्षेत्र में चरने के लिए जाते थे। 'सीमोटी' एक अन्य चराई कर था जो भेड़ों पर लागू होता था, जिसकी दर १४ भेड़ों पर १ रु० थी।^२ इस होने वाली आय सन् १७२५ ई० में कुल आय की ०.४३ प्रतिशत थी तथा सन् १८०६ ई० में १.०० प्रतिशत थी।

(१३) मोता—यह शादी-व्याह के आमन्त्रण पर कर था। राज-परिवार के कुवर और कुवराणियों की शादी पर पट्टे व खालसा के गांवों से यह वसूल किया जाता था। प्रति-गुवाडी इसकी दर २ रु० थी। इस कर को पट्टायत व चौधरी भी अपने-अपने गांव में वसूल करते थे। यह कोई नियमित कर नहीं था।^३

१ कामदारों व बनीसों के रोज़गार से बही (पूर्व), बही पेशकशी वि० स० १८१४/१७५७ ई०, वि० स० १८६०/१८०३ ई०, महकमा पेशकशी, कागदों की बही, वि० स० १८६६/१८०६, न० १५, पृ० २३०, २३५, २४३, भैंया सग्रह-पत्र, आश्विन वदि १४, १८७१, १२ अक्टूबर, १८१४ ई०, न्यूरोकेसी इन राजस्थान, पृ० ३६

२. सन् १८०६ ई० की कुल आय के आधार पर

३ बही पेशकशी से, स० १८६०/१८०३ ई० (पूर्व)

४ कागदा की बही, वार्षिक वदि ३, वि० स० १८५४, ८ अक्टूबर, १७६७ ई०, न० १०, वि० स० १८६३/१८०६ ई०, न० १४, पृ० ७, २७४, २६४

५. बही सरदार कवर से व्याह से, वि० स० १७७६/१७१६ ई०, न० १४४—बीकानेर बहि-मात, कागदा की बही, वि० स० १८२७/१७७७ ई०, न० ३, पृ० ३६ ४०, भैंया सग्रह—नोतापत्र—वि० स० १८६३/१८०६, वस्ता न० २

(१४) बीदावतों की भाछ—महाराजा गजसिंह ने बीदावत ठाकुरों के विद्रोही आचरण को दखते हुए सन् १७६६ ई० में, बीदावतों पर प्रतिवर्ष ६,००० रु० की बीदावतों की भाछ^१ लगा दी।^२ हालांकि इस रकम में घटोतरी-बढोतरी होती रहती थी, परन्तु हर शासक ने इसे सख्ती से वसूल किया था। महाराजा सूरतसिंह के समय इस रकम की राशि ५०,६६३ रु० थी, जोकि कुल आय का ५३२ प्रतिशत थी। बीदावतों की इस भाछ के कारण 'घोडा-रेख' व 'रुखवाली की भाछ' में मुविघाण दी गयी थी रुखवाली भाछ प्रति-मुवाडी = ६० की दर से और घोडा रेख प्रति घोडा ८० रु० की दर से वसूल की गई थी।^३

इसके अलावा अन्य कई छोटे-बड़े कर थे, जिन्हें वसूल करने में राज्य उतनी ही तत्परता दिखाता था। चरवाहों^४ पर लगाया गया कर, 'बहैनियों की भाछ' 'धनो का कर', 'जोड़ की भाछ', 'देवस्थान व पुनर्ध' के लिए 'ठाकुरजी व गुसाईजी की भाछ', घोड़ों के लिए 'धी की भाछ', 'घास पटाई की भाछ, अधिकारियों का परिश्रम—'हाकमो का रोजगार', विभिन्न मेलों पर लगी 'जगात' इत्यादि अन्य प्रमुख कर थे। शासक को नजर व उद्धार भेंट की जाती थी, जो देसवसी में शामिल हो गई थी।^५

छूट—जब तक उल्लिखित सभी करों के विवरण के साथ राज्य की वित्तीय व्यवस्था में एक स्थायी अंग 'छूट' का उल्लेख करना भी आवश्यक है अथवा करों के दबाव को समझना कठिन होगा। इन वषित करों में करदाताओं को सहायता व निस्तार देना ही यहाँ छूट का अर्थ था। राजकीय बहियों में इससे सम्बन्धित पत्र—'छूट के कागद' कहलाते थे। ये पत्र प्रशासन की ओर स सम्बन्धित व्यक्तियों को व सरकारी अधिकारियों को भेजे जाते थे। उन पर सरकारी मुहर अंकित होती थी, जिन्हें वे वसूली के अवसर पर

- १ बागदो की बही, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृ० ३७६, बीदावतों का बधा—भाछ बगता; दयाल दास ब्यात (भप्र०) २, पृष्ठ ३१०; बीदावतों की ब्यत, भाग १, पृष्ठ ६२७
- २ बही खाता खजाना सदर, १७६५ ई०, बागदो की बही, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १५, पृ० ३७६
- ३ पत्र चराने वालों पर
- ४ गादीवालों पर कर
- ५ धनी पान के जंगल का पटाई कर
- ६ हबू व बहिया, वि० सं० १८०१/१७४४ ई० से वि० सं० १८२०/१७६३ ई० तक, बस्ता न० १

दिखाते थे ।^१

राज्य का प्रशासन निम्न परिस्थितियों में विभिन्न करो में छूट की सुविधाएं प्रदान करता था—(१) 'अकास', (२) 'सूखा', (३) महामारी, (४) गांव का लूटमार वा शिकार होने पर, (५) लड़ाई का क्षेत्र होने पर, (६) गांव के 'नीवला' होने पर, (७) गांव 'सूना' होने पर, (८) 'बेतलब' गांव होने पर, (९) नये गांव बसाने पर, (१०) गांव में नये व्यक्तियों को बसाने पर, (११) पुरानी गुवाड़ियों को वापस बसाने पर, (१२) व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिये, (१३) व्यावसायिक जातियों को गांव में बसाने के लिये, (१४) 'पेशकसी' वसूली के समय, (१५) गुवाड़ी की 'नीवली' स्थिति होने पर आदि ।

प्रशासन इन परिस्थितियों से जूझने के लिए जो उपाय जुटाता था, उन्हें अध्ययन की दृष्टि से तीन स्तरों में विभक्त कर सकते हैं—

- (१) गांव में सामूहिक स्तर पर ।
- (२) व्यक्ति व उसके परिवार के स्तर पर ।
- (३) चौरा स्तर पर ।

प्रथम प्रकार की छूट का लाभ, एक गांव के सभी निवासियों को, समान रूप से प्राप्त होता था । इस प्रकार की छूट में 'जमाबन्धी' का बड़ा महत्व था, जिसके अनुसार गांव में लगाये गये विभिन्न करो में निश्चिन्त समय के लिये कमी करके राहत दी जाती थी ।^२ सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये जाते थे कि वे अधिक वसूली न करें । इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने हेतु, उनका रोजगार व उनके जानवरों का खर्च आदि नियत कर दिया जाता था । 'जमाबन्धी' के अलावा चौरा स्तर पर वसूल किये गये करो में भी, इसी प्रकार कमी कर दी जाती थी । करो में छूट की मात्रा तीन प्रकार की थी—(१) चौथाई, (२) आधी, (३) पूर्ण समाप्ति । साधारणतया पिछली 'वकाया'

१. नोट—इस अध्याय में छूट से सम्बन्धित सम्पूर्ण वर्णन नागवो की बहियों में छूट के पन्नों पर आधारित है । ये पन्ने प्रत्येक बही में अलग से छूट के नाम से लिये गये हैं । उपर्युक्त वर्णन के लिये वि० सं० १८११/१७५४ ई० से वि० सं० १८७२/१८१५ ई० तक की बहियों का जो सञ्चा सं २१ है, का प्रयोग किया गया है ।

रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर, रा० सं० बी० ३ ; देखिये—जी० एस० एल० देवडा, बीकानेर की मध्यकालीन ऋणव्यवस्था में गहायता व निस्तार का प्रतिरूप—राज० हिस्ट्री कांफ्रेंस, पाली अधिवेशन, १९७५

२. आर्थिक दृष्टि से कमजोर

३ खाली होना, उजाड़ होना

४ कर-रहित क्षेत्र

५ उदाहरणार्थ—वागदा की बही, न० २, मार्गशीर्ष मुदि० १०, १८२०, १४ दिगम्बर, १७६३ ई०

को समाप्त करने के साथ-साथ आने वाले एक से तीन वर्षों के बीच कटौती का प्रावधान रखा जाता था। गांव से पेशकशी की वसूली के समय सभी कर स्थगित कर दिये जाते थे। प्राकृतिक विपदाओं व 'पेशकशी' के समय ऋण-दाताओं का भी यह आदेश भेज दिया जाता था कि वे अपने ऋणों की वसूली निर्धारित वर्ष में स्थगित कर दें। आवश्यकता पड़ने पर राज्य गांव में सैनिकों की नियुक्ति भी करता था, ताकि गांव सूने न हो जायें।

नये गांव के बसने पर कुछ वर्षों तक करो में पूरी छूट दी जाती थी, तदुपरांत करो में प्रमश बढ़ोत्तरी करके कर वसूल किया जाता था। गांव के चौधरी को बस्तिया बसाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उसे हमेशा के लिए 'नौनकर' भूमि प्रदान की जाती थी, तथा उपज का पांच प्रतिशत दिया जाता था।

दूसरे प्रकार की छूट व्यक्ति व उसके परिवार अर्थात् 'गुवाही' से सम्बन्धित होती थी। राज्य में निरन्तर अकाल व सूखे का भय बना रहने के कारण, गुवाडिया 'मऊ' चली जाती थी। इनमें से कुछ सौटकर भी नहीं आते थे। राज्य, उन्हें बसाने के लिए, उदार नीतिया अपनाता था। तीस से चालीस वर्ष बाद भी अपने गांव में वापस आकर बसने वाला व्यक्ति, विभिन्न करो में, आने वाले दो-तीन वर्षों तक कटौती का लाभ उठाता था।^१ राज्य ने कहीं-कहीं तो ऐसे किसी व्यक्ति को पूरे जीवन-भर की कटौतिया भी प्रदान की। समकालीन स्रोतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, राज्य की ओर से तीसरी पीढ़ी तक कटौतियों का लाभ भी दिया गया। 'बेगार' को भी समाप्त कर दिया जाता था। व्यावसायिक जातियाँ— सुधार, तेली आदि को, जिनकी आवश्यकता ग्रामीण जीवन में अनुभव की जाती थी, उन्हें गांवों में बसाने के लिये राज्य अनेक करो में छूट प्रदान करता था।

इसी प्रकार विपत्तिकाल में साहूकारों के माल पर 'जगात' में भी छूट दी जाती थी। जब साहूकार, 'साहूकार भाछ' को देने में असमर्थ पाकर 'देशनोक' चले जाते थे, तो राज्य उनके करो में कमी करके उन्हें वापिस बुलाता था। व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिये शासक हुण्डियों के भुगतान की सुविधा व्यापारियों को देता था।

तीसरे प्रकार की छूट चीरा स्तर की थी। 'धुआ भाछ', 'छखवाली भाछ', 'चौधर-पटावरी बाब' 'नोता' आदि करो में एक सत्तीन वर्ष के बीच ४ प्रतिशत से ४२ प्रतिशत तक छूट दी जाती थी। यह छूट अपने-आप में महत्वपूर्ण थी,

१ परदेश

२ गुवाडियों के ६५ व १०० वर्ष बाद वापिस आकर बसने में उदाहरण प्राप्त होते हैं। कागदा की वही, सं० १८१७/१८००, न० ११, ५० ११, २०१

और निश्चित रूप से निवासियों को प्रोत्साहित करती होगी।

इस क्षेत्र की प्राकृतिक विभीषिका तथा करो के प्रकोप से बचने के लिये प्रशासन द्वारा समय-समय दी गई वषित छूट इस तथ्य की ओर निश्चित रूप से इंगित करती है कि थार मरुस्थल के उजाड़ क्षेत्रों में निवासियों को बसाने के लिये राज्य सदैव सज्जित रहा था। प्रशासन इस ढर से सदैव शक्ति रहता था कि गुवाडिया नहीं अग्न्यत जाकर न बस जायें। यही कारण है कि राज्य की कोई भी वही बिना छूट के पत्तों के पूर्ण नहीं है और कोई गांव इस सुविधा से वंचित नहीं है। इन पत्तों के माध्यम से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि सभी करो की पूर्ण वसूली शायद ही कभी होती थी। यहाँ जिस स्तर तक करो में सुविधायें प्रदान की गई हैं, उसका विवरण भी अग्न्यत नहीं मिलता है। यहाँ यह 'छूट' अपने-आप में एक आकर्षण है। यह केवल विकास की अवस्थाओं के लिये निर्धारित नहीं थी, बल्कि सामान्य जीवन तथा बसने की हर अवस्था में प्राप्त थी। संभवतः उत्तर-मुगल काल में यही कारण, जमींदारी क्षेत्र के कृषकों को जागीरी क्षेत्रों के कृषकों से कुछ उत्तम स्थिति में ला देता होगा। इस 'छूट' का पूर्ण व व्यापक प्रभाव दो कारणों से सम्भव नहीं हो पाता था। प्रथम, विपत्ति का प्रभाव पड़ने के पश्चात् प्रशासन द्वारा छूट की घोषणा तथा द्वितीय, सैन्य व प्रशासनिक मामलों के फलस्वरूप नये कर लगाकर पुराने करो की छूट के महत्त्व को समाप्त कर देना, जैसा कि १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों में हुआ था। पर, इसके पश्चात् भी राज्य द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयत्नों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।

भाग २

व्यय

राज्य में व्यय से सम्बन्धित सर्वप्रथम वर्णन महाराजा अनूपसिंह के काल की, सन् १६७० से १६९२ ई० की 'समस्त गावा री वही' से प्राप्त होता है; परन्तु उससे राज्य के कुल व्यय का अनुमान लगाना कठिन है। सन् १६९८-१६९९ ई० की 'परगना की जमा-खरच वही', प्रथम वही है जो कुल व्यय के साथ साथ व्यय के विभिन्न सूत्रों की जानकारी भी देती है। सन् १६९९ ई० में राज्य के कुल व्यय की राशि २,१५,०८५ रु० थी। इसके उपरान्त १८वीं शताब्दी में खर्च की राशि में भारी कमी हुई। सन् १७५७ ई० में राज्य की व्यय राशि घटकर १,२०,०८० रु० रह गयी। कमी का एक मुख्य कारण मुगल जागीरी आरु की समाप्ति से प्रशासन द्वारा अपने खर्चों में कटौतियां करना था। इस काल में

राज्य के बाह्य सैनिक दायित्व भी कम हो गये थे तथा मुगल दरबार में पक्ष की जान वाली शक्ति भी सदैव के लिए समाप्त हो गई थी। सन् १७५७ ई० के पश्चात् व्यय में वृद्धि के लक्षण फिर प्रकट होने लगे। सन् १७६५ ई० में यह बढ़कर ८६ ७४ प्रतिशत पर पहुँच गया, यद्यपि सन् १६६६ ई० की तुलना में यह अब भी १३ २६ प्रतिशत कम था। १६वीं सताब्दी के प्रारम्भ में पक्ष राज्य-इतिहास में सबसे अधिक बढ़ा। सन् १८०६ ई० में पक्ष की होने वाली शक्ति ११,६६,६८० रु० थी, जो सन् १६६६ ई० की तुलना में ४५७ ६४ प्रतिशत बढ़ गई थी। सन् १७६५ ई० से लेकर सन् १८०६ ई० के बीच चौदह वर्षों में, यह वृद्धि ४७१ २० प्रतिशत थी। इस वृद्धि के पीछे प्रशासनिक व सैनिक पक्ष मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, फिर मूल्यों में भी वृद्धि हो रही थी।

राज्य के कुल व्यय की सूची*

वर्ष	व्यय की शक्ति (रुपयों में)	प्रतिशत (१०० के आधार पर)
१६६६ ई०	२१,५०,६५	१०० ००
१७५७ ई०	१२,००,८०	५५ ८३
१८६५ ई०	१ ८६ ५५८	८६ ७४
१८०६ ई०	११ ६६ ६४०	५५७ ६४

व्यय सूची

मुख्य रूप से राज्य के व्यय के मुख्य विवरण इस प्रकार थे—^१

- १ मन्दिरान्तर्गत पुनर्निर्माण कार्य (आधिकारियों पर तथा पक्ष)
- राजशाही शासन (राज परिवार का पक्ष)
- कारखाने में (विभिन्न कारखानों की लागत पक्ष)
- कर्मठान में (निर्माण कार्यों पर पक्ष)
- बाह्य लक्ष्य (कुओं का खुदशान व उसका मामला का पक्ष)

१ नोट—व्यय का कुल विवरण भी स० १६७०, १६६६, १७२०, १७६२ व १८०६ की तुलना पर जोड़ा गया है। इससे भी सन् १६६६ ई० की तुलना पर आधारित व्यय-विवरण दिया गया है। इसके साथ ही व्यय का रेखांकित भी।

२ नोट—इस विवरण की तुलना पक्षों का विवरण दिया गया है जो राज्य पक्ष में शामिल नहीं है। राज्य की विवेक शक्ति व उसके व्यय-विवरण पक्षों का बाई-दो-पक्ष नहीं दिया है।

६. महीनदारो व रोजीनदारो का खर्च	(वेतनभोगी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन खर्च)
७. सिलावटो लेखे	(राजमहल के कारीगरों का खर्च)
८. मोदीखाने लेखे	(शाही भण्डार का खर्च)
९. पेटीये लेखे	(यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तों का खर्च)
१०. टुकसाल लेखे	(सिक्के ढलवाने के विभाग का खर्च)
११. सिरपाव रा	(पारितोषिक, इनाम, भेंट इत्यादि)
१२. सीरबखी दाखल	(शासक की निजी-सेना का खर्च)
१३. सीलेपासी दाखल	(अस्त्र-शस्त्र व सैनिक खर्च)
१४. थाणो का खर्च	
१५. कासीदा दाखल	(सदेश-वाहक खर्च)
१६. घोडा खरीद बाबत खर्च	
१७. कोठार लेखे	(भण्डार गृह खर्च)
१८. पातसाह साहै रो खर्च	(मुगल दरबार का खर्च)
१९. परचूण खर्च	(विविध खर्च)
२०. खरीद दाखल खर्च	(बाहर से मंगाई गई वस्तुओं का खर्च)
२१. ब्याज-हुडावण खर्च	(प्रशासन द्वारा लिये गये ऋण का ब्याज तथा बाहर से ऋण ले आने की भाँति हुण्डी पर खर्च इत्यादि)
२२. कर्ज लेखे	(ऋण को चुकाने की रकम)

उपर्युक्त खर्चों को समान प्रकृति की कई इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। जिनका विवरण इस प्रकार है—

(१) राज-परिवार से सम्बन्धित खर्च—राज परिवार के खर्च में न केवल श्री जी का परिवार, बल्कि उनके सभी निजी सम्बन्धियों व 'जनानी इयोही' का खर्चा सम्मिलित होता था। यद्यपि 'राज-लोदी' की मुख्य आवश्यकताएँ 'मोदी-दाने' से पूरी हो जाती थी, पर इसके बाद भी, उनके 'सेवकों' व 'चाकरों' के खर्च तथा उनके सम्मान को बनाए रखने हेतु, खर्चों की प्रति राज-शेखर खर्च से की जाती थी। सन् १६७० ई० से सन् १६९३ ई० तक राजशेखर का खर्च, ३,७४,६५१ रु० था। राजशेखर खर्च में महाराजा के पितामह पिता के परिवार, उनकी 'दासों', 'पासवानों', श्री जी की 'महाराणियों', 'राणियों', 'दासों', 'रामदानों', 'बहारानों' तथा 'राणियों' व 'कुमारानियों' सहितियों, 'धाय बहन-भाईयों', 'महाराज कुमारों', उनके 'प्रधान' तथा 'माणस' व राज-परिवार के

१. जनानी इयोही की मुख्य अधिकारियों

२. व्यक्ति

समस्त चाकरों का वेतन आदि का सर्वे सम्मिलित होता था। 'कुवराणियों' को 'मोदीयाने' के छर्चों के साथ प्रतिमाह करीब ३० ६० मिलत थे। वरिष्ठ कुवराणियों को पट्टे भी प्राप्त होते थे। वरिष्ठ अणद कुवर व 'माणसो' को ३२, १३३ ६०, २३ वर्ष में वेतन के रूप में दिये थे। साधारणतया 'पातरो' व 'गवामो' को प्रतिमाह ५ ६० से ३० ६० के बीच मिलते थे। वरिष्ठ 'गवामो' महाराज की कृपापात्र होने पर, अधिक भी पा सकती थी। महाराजा अनूपसिंह की खयाल वसंतराय को तथा महाराजा गजसिंह की खुवासन को एक मास के १०० ६० तथा उनकी सहसियों को एक मास के ३ ६०, चाकरो को २ ६० से ६ ६० तक, 'नात्ररो' को प्रतिमास ६ ६० से २० तक वेतन प्रदान किया गया था। महाराणियों व रानियों को वेतन व पट्टे प्रदात किये जाते थे। महाराजा अनूपसिंह की रानियों को, मन् १६७० ई० से १६९२ ई० तक, ४, १३, २७१ ६० छर्चों के लिये दिये गये थे। सन् १७५७ ई० में 'गजसोको' का कुल छर्च राज्य के कुल छर्च का ३ १६ प्रतिशत था, जो सन् १६९५ ई० में बढ़कर १२ ७८ प्रतिशत हो गया। छर्च की कुल राशि २३, ८४३ ६० थी, जो मन् १८०९ ई० में बढ़कर ६२, ७५० ६० हो गयी, लेकिन यह राशि कुल छर्च की ५ २३ प्रतिशत थी। राजसोरो गरब' में यह बात विशेष दखने में आयी है कि छर्च में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई थी। सन् १६९३ ई० में लगे छर्च की तुलना में मन् १८०९ ई० तक केवल ० ५६ प्रतिशत की ही वृद्धि आयी थी।

(२) कारखाना छर्च— दरबार व राज्यमहल की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु, जो विभिन्न विभाग स्थापित किये गये थे—जहाँ 'बारगाना जात' कहा जाता था। राज्य में मुख्य बारगाना ये थे—'रसोडा' (रसोई), 'यगाजलगाना' (पेय विभाग), 'बारगाना बन्ना' (आभूषण व फैशन की अन्य वस्तुओं का निर्माण विभाग), 'दवाईगाना' (औषधि), 'मोदीगाना' (रसदव अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण विभाग), 'हीनगाना' (हाथीखाना) 'मूतरगाना' (ऊट विभाग), 'रसगाना' (रस विभाग), 'तोपगाना' (तोप विभाग), 'तबला' (घोषों का विभाग), 'कीरीगाना' (उद्यान विभाग), 'टक्काल' (मुद्रा विभाग), 'मरम्मतगाना' (लकड़ी विभाग) 'करामगाना' (डोरा या पड़ान विभाग), 'किरकिरगाना' (ताबू जानसरा का विभाग), 'मिनाहगाना', 'मिनाहपागाना' या बड़ा कारगाना (वे जस्त्र-जस्त्र विभाग थे), इनमें 'मोदीगाना' व बड़ा बार-

खाना' मुख्य थे।^१

'कारखानाजात'^२ के खर्च में केवल 'मोदीखाना', 'दवाईखाना', 'मरम्मत-खाना', 'फराशखाना', 'किरकिरखाना' तथा 'फीलीखाना' के खर्च ही सम्मिलित होते थे। बल्कि कहना यूँ चाहिये कि 'कारखाना जात' का खर्चा मुख्य रूप से मोदीखाना का खर्च ही था। अन्य कारखाने के खर्च 'मोदीखान' में सम्मिलित कर दिये जाते थे। 'मोदीखान' के मुख्य खर्च ये थे—सरकारी हाथियों, घोड़ों, चाकरो का रसद व खर्च, शासक की यात्रा पर आया खर्च, राजमहल के दिन-प्रतिदिन के धार्मिक व पुनर्चर्च कार्यों का खर्च, दूतों का खर्चा, राज-परिवार की स्त्रियों व लड़कियों के सामाजिक व धार्मिक उत्सवों पर खर्च, शिकार खर्च, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के घोड़ों की रसद का खर्च, विदेशी मेहमानों पर आया खर्च, 'गगाजल खर्च'^३ इत्यादि। बाकी कारखाना 'फीज खर्च', 'उच्चत खर्च',^४ 'टकसाल खर्च' कोहुरी का 'खर्च'^५ आदि अलग-अलग 'लेख' में दिखाये जाते थे।^६

'कारखानाजात' में काम करनेवाले कर्मचारियों को नकद वेतन व 'पेटीया'^७ मोदीखाने से प्राप्त होता था। इन कारखानों का मुख्य अधिकारी 'हुबलदार' व उसका सहायक 'दरोगा' कहलाते थे, जिन पर अधिकतर 'मुतसद्दियों व हजूरियों' की नियुक्ति की जाती थी। मोदीखान में सन् १६६८ ई० में ११,३६८ रु० का खर्चा हुआ था। यह राशि सन् १७५७ ई० के विपत्ति वर्ष में ३,७६१ रु० ही रह गयी, जोकि राज्य के कुल खर्च की ३.१६ प्रतिशत थी। तदुपरात यह राशि बढ़ती ही गयी। सन् १७६५ ई० में तथा सन् १८०६ ई० में, इस पर

१ परगना की जमा जोह वही, वि० सं० १७२६-८०/१६६६-६३, न० ६६, वही समसत दे जमा खर्च, वि० सं० १७५८/१७०१ ई०, न० ७७, सोहनताल-तवारीख, पृ० २६१-७२, राज्य में इस बात का बहुत प्रचलन रहा है कि बीवानेर राजा ३६ कारखाना के स्वामी रहे हैं, पर यह केवल उसकी समृद्धि को बतलाने के लिये मुगलक व मुगल शासकों की तरफ प्रसिद्ध कर दिया था, अथवा, इस सच्चा को किसी भी समयकालीन स्रोत से पुष्टि नहीं होती।

२ कारखाना जात का तात्पर्य राजा के निजी कारखाना के नाम से है

३ पीने के पानी पर आया खर्च

४ ऊपरी खर्च

५ कुर्मी का खर्च

६ कोठार बहिषो, वि० सं० १७४२/१६८५ ई० न० ३५, कोठार दे लेखे री बही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, न० ३५, बडे कोठार दे खरडे री बही, वि० सं० १७४३/१६६६ ई०, न० ३६, कोठार दे जमा खर्च री बही, वि० सं० १७५५/१६६८ ई०, न० ३८, लेखे का तात्पर्य यहाँ आय-व्यय के हिसाब से है।

७ भत्ता

प्रमश २३,८६३ रु० व ६२,७१० रु० पच निय गये। मोदीमान के अलावा अन्य कारखानों का पच भी बढ़ता जा रहा था। सन् १७७६० में जहाँ २७ पर १४,११४ रु० का पच हुआ, वहाँ यह सन् १८०६ ई० तक बढ़कर १,३०७३० रु० तक पहुँच गया। इस वर्ष ६४,८३६ रु० की तो बचत पक्षमीन ही खरीदी गई थी।

कारखाना जात का पच

वर्ष	पच रकम (रुपया में)	प्रतिशत (१०० के आधार पर)	कुल आय का प्रतिशत
१६६६	१५,५७०	१०० ००	७ २४
१७५७	२५,२३७	१६२ ०६	२१ ०२
१७६४	५१,११३	३२८ २८	२७ ४०
१८०६	७५,५७२	१ ६०६ ३२	२० ८८

पच सूची में जात होता है कि विभिन्न कारखानों पर सतत व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। सन् १६६६ ई० के आधार पर यह वृद्धि १८वीं शताब्दी के अन्त तक सन् १७६६ ई० में ३२८ २८ प्रतिशत तक बढ़ गयी थी, और १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सन् १८०६ ई० में १६० ३२ प्रतिशत तक पहुँच गई थी। कुल पच की रकम में भी इनका प्रतिशत सन् १६६६ ई० में ७ २४ प्रतिशत से सन् १८०६ ई० तक बढ़कर २० ८८ प्रतिशत हो गया था। मोदीखाने में यह वृद्धि ४१० ७१ प्रतिशत तक अन्य कारखानों में ६१ ६३ प्रतिशत थी। वृद्धि का मुख्य कारण सिरयधी तथा विदशिवा के पटीमा खख तथा विलासिता की गामभी की खरीद थी। महाराजा गर्बाह य सूरत सिंह के पत्र में उनके भाईयो पर जमा पच भी मोदीखाने के पच में सम्मिलित कर लिया गया था। अलग में बहुत हुए सैनिक खर्चों के साथ 'कारखानाजात' का बढ़ा हुआ खख वित्त की सम्भार रमत्वाओ के प्रति सारखाहो का चातख था तथा राज्य की समस्याओं में वृद्धि करने वाला था।

(३) प्रशासनिक खच राज्य प्रजान में प्रशासनिक पच के रूप में एक बड़ी रकम निकल जाती थी। इसमें राजकीय सेवाओं के सभी वर्गों तथा सभी तरह के अधिकारियों के मचारिया के वेतन सम्मिलित थे। उस समय 'आगरिक व सैनिक सेवाओं में कोई विशेष भेद नहीं था। विभिन्न कारखानों के 'धानी', 'मण्डियों के हुबलदार', उनके सहायक 'दरोगा', 'कीतवाल' अधीनस्थ कर्मचारियों में 'लेखणिये', 'गुमास्ते', 'तावीनदार' 'महीनदार' तथा 'रोजीनदार'

के रूप में वेतन पाते थे। मंत्रियों व उच्च-अधिकारियों को भी कुछ 'नकदी वेतन' मिलता था। मंत्रिया व उच्च अधिकारियों के 'ताबीनदारों' व उनके 'तवेले' वा खर्च भी राज्य वहन करता था।^१ चीरो तथा ग़ालसा गावा के हुवलदारों का वेतन अधिकांश रूप में, करा वी वसूली के साथ 'रकम-रोजगार' व नाम से निर्धारित होता था। राज्य में अधिकारियों का वेतन प्रतिमाह १५) ६० स ३०) ६० के बीच था। सहायकों का वेतन प्रतिमाह ५) ६० स १५) ६० के मध्य था। अधीनस्थ कर्मचारी प्रतिमाह १) ६० स ५) के बीच पाते थे। प्रत्येक अधिकारी व उसके कर्मचारी को अपना वस्तु-व्यपालन न करने पर जुर्माना देना पड़ता था, जो उसके वेतन का आठ सिया जाता था।^२ सन् १६७० ई० से १६६३ ई० के बीच बाईस वर्षों में, राज्य का लगभग एक लाख रुपया वेतन के रूप में खर्च हो गया था। सन् १६६६ ई० के एक वर्ष में खर्च की रकम ४२२१ ६० थी।

महीनदारों व रोजीनदारों का खर्च

वर्ष	खर्च रकम	प्रतिशत १०० के आधार पर	कुल खर्च रकम में प्रतिशत
१६६६	४,२२१	१०० ००	—
१७५७	२,३४८	५६ ६६	१.६६
१७६५	१५,५६८॥ =)	३५८ ४६	८.३६
१८०६	४७,८७२	१,१०० २५	३ ६६

सन् १७५७ ई० में अवश्य खर्च की रकम में वमी आई थी परन्तु उसके उपरान्त इसमें निरन्तर बढाव आ होती रही। सन् १७६५ ई० में ३५८ ६६ प्रतिशत तथा सन् १८०६ में १,१०० २५ प्रतिशत तक यह खर्च पहुच गया। इस काल में न केवल महीनदारों के हुवलदारों को 'रकम-रोजगार' चुकानी पड़ी, बल्कि दीवानों में लगे ताबीनदार तक के वेतन में वृद्धि हो चुकी थी।^३ महाराजा सूरजमल के शासक में नये प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना से भी खर्चा बढ गया था।^४

१ कामदारों व बकीलो के रोजगार की वही, वि० सं० १७५३/१६६६ ई०, न० २०६

२ वही

३ तुलनात्मक अध्ययन के लिय दखिये—पट्टा वही, वि० सं० १६८२/१६२५ ई०, न० १, परवाना वही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, दीवान का वतन १७वीं शताब्दी में १०,००० ६० था, जो १८वीं सदी के अंत तक १४,००० ६० हो गया था। हुवलदार का वेतन ५ ६० से बढकर प्रतिमाह १५ ६० हो गया था।

४ रतनगढ़, भूख, भादरा, भोरगढ़, फलोदी, फुलडा, हनुमानगढ़ में नये नदर स्थापित किये गये थे।

महीनदारा का खर्चा राज्य का कोई महत्वपूर्ण खर्चा नहीं था। कुल खर्च की रकम में इसकी स्थिति ८ प्रतिशत से अधिक कभी नहीं बढ़ पाई थी।

(४) श्रीमण्डी का खर्च—श्रीमण्डी के 'हुवलदार', दरोगा व तालीनदारों का खर्च राज्य में सदैव अलग से अंकित होता था।^१ श्रीमण्डी का अपना ही लेखा जोखा था। इसका अपना महत्व ही था, कि जहाँ सन् १७५७ ई० में अन्य खर्चों में कटौतियाँ की गईं वहाँ मण्डी के खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस वर्ष यह कुल खर्च की रकम की ६६० प्रतिशत थी, अर्थात् मण्डी का खर्च महीनदारा से अधिक होता था। श्रीमण्डी के अधिकाधिक व वक्ताचारियों की सख्या तो महीनदारा से कम थी, परन्तु इन्हें वेतन अधिक मिलता था। श्रीमण्डी का हुवलदार प्रति माह ६० रु० से १०० रु० के बीच वेतन पाता था।^२ परन्तु १८वीं शताब्दी के अन्त तक राज्य की सीमावर्ती भूमियों के विकसित होने के फलस्वरूप इसका महत्व घटने लगा, जिससे श्रीमण्डी के खर्च में भी कमी आने लगी।^३

श्रीमण्डी का खर्च

वर्ष	खर्च रकम रुपये में	प्रतिशत १०० के आधार पर	कुल खर्च में प्रतिशत
१६६६	७,२२६।।)	१०० ००	३ ३६
१७५७	११,८६२	१६४ ५४	६ ६०
१७६५	८३१।। =)	११ ५१	० ४५
१८०६	३३७७)	४६ ७२	० २८

इस प्रकार राज्य ने प्रशासनिक खर्चों को सदैव नियन्त्रण में ही रखा। यह खर्च कभी भी राज्य के कुल खर्च में ६ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पाया, बल्कि अधिकतर ५ प्रतिशत से कम ही रहा। इस कमी के पीछे मुख्य कारण यह था कि मुकाना प्रणाली के प्रचलन में हुजाला व्यवस्था की वेतन वाली रोजगार प्रथा समाप्त हो रही थी। फिर बहुत से प्रशासनिक खर्च मोदी-खाने से पूरे हो जाते थे। पर, शामकी ने जिस प्रकार अपने निजी खर्चों में वृद्धि की, उसके स्थान पर अगर इस खर्च में कुछ और वृद्धि करते तो राज्य में बाहर आने वाले योग्य व्यक्तियों का यहाँ बसने का आकर्षण बना रहता। इसके

१ श्रीमण्डी के जमा खर्च की वही वि० सं० १७०१/१६४४ ई०, न० ७४

२ वही

३ साबा बहिनो—रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर

अभाव में, राज्य का मुत्सद्दी वर्ग सम्पूर्ण ही पुराने प्रशासकों के वशजों से भरा रहा।

(५) **सैन्य-खर्च...** राज्य में मिलेगोस' (अस्त्र शस्त्र) शालावाग्द, सैनिक सज्जा व सैनिकों के वेतन के रूप में, सैन्य खर्च किया जाता था। प्रारम्भ में सैन्य खर्च बहुत कम था, क्योंकि सेना के अधिकांश भाग की पूर्ति सामन्तों की सेनाओं से होती थी; जिसका खर्च व स्वयं वहन करते थे।^१ महाराजा अनूप-सिंह के काल से शासक की निजी सेना पर खर्च दिया जान लगा था।^२ महाराज गजसिंह के समय तो शासक की स्थायी सेना के निर्माण हेतु निजी सेना का और गठन और विस्तार किया गया।^३ इससे तथा सेना के विभिन्न अंगों विशेष-कर तोपखाने' के विस्तार में सैन्य खर्चों में वृद्धि होने लगी।^४ १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में कई नई टुकड़ियों को भरती किया गया तथा राज्य में 'बाणों' की संख्या में भी वृद्धि हुई।^५ इन सबने राज्य के सैन्य खर्चों की नई ऊँचाइयों

राज्य का सैन्य खर्च

वर्ष	खर्च रकम (रुपयों में)	प्रतिशत खर्च का (१०० के आधार पर)	प्रति (कुल खर्च) में
१६६६	१,१५,३५४	१०० ००	५२.६४
१७५७	७४,४१६	६४ ५१	६१.६७
१७६५	१,१३,०८३	९८ ००	६०.५६
१८०६	६,७८,६२०	५२८ २२	५६.५५

- १ रिमाफा बड़ी, वि० सं० १६८७/१६३० ई०, दयालदास अग्रवाल (प्र०) २, पृष्ठ ८, १८, २५, ५४
- २ बही वकीलों व नामदारा व रोजगार की (पूर्व); खालसा के बाबा की बही, न० ६८, सं० १७४३/१६८६ ई०
- ३ वी नकल की—वि० १६४, सं० १८१०/१७५३ ई०, खाता खजाना सदर बही, सं० १८१४/१७५७ ई०
- ४ बही लमकर रो, वि० सं० १७२६/१६६६ ई०, न० २४१; तबेला खर्च बही, वि० सं० १७५६/१६६६ ई० न० २३४, बही बाबा खरोदरी, वि० सं० १७४६/१६८६ ई०, न० १३५—बीकानेर बहियात
- ५ बही कूबमुकाम के कागदा रो, वि० सं० १८१०/१७४३ ई०—रामपुरिया रिकार्ड्स, बीकानेर, नामको की बही, सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० ६६, सं० १८६१/१८०४ ई०, न० १३—रावत सर बाबा के बाबद। इस सदम में भीष्मा सग्रह के मोहर से भीष्मा नयमल के पत्र अध्ययन में बहुत सहायक है।

पर पहुँचा दिया, जिसके फलस्वरूप राज्य भयंकर वित्तीय कठिनाइयों में फँस गया।^१

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सैन्य खर्च राज्य का प्रमुख खर्च था और कुल खर्च में आधे से अधिक राशि इसी पर खर्च की जाती थी। कुल खर्च के ६० प्रतिशत के साथ साथ सामन्तों का भी सैन्य खर्च अगर ध्यान में रखा जाये तो राज्य की समस्त आय का ८० प्रतिशत में अधिक तो केवल सेना पर ही खर्च हो जाता था।

सैन्य खर्च की सारणी से दो मुख्य मुख्य रूप से उभरते हैं। प्रथम १७वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों की तुलना में १८वीं शताब्दी में सैन्य खर्च में कमी आ गई थी, जो १६६६ ई० के आधार पर १७२७ ई० में ६४५१ प्रतिशत थी। इन वर्षों में बीकानेर शासकों के मुगल सेना से हट जाना तथा खर्च में भारी कटौतियाँ लागू करने पर यह कमी आई थी। फिर इन वर्षों में राज्य की घटती हुई आय के साथ-साथ तुलना भी स्थापित करना था। द्वितीय, राज्य के कुल खर्च में सैन्य खर्च के प्रतिशत में कमी नहीं बूझी हुई थी। १६६६ ई० में, जहाँ कुल खर्च में सैन्य खर्च का प्रतिशत ५३.६४ प्रतिशत था, वहाँ १७५७ ई० में यह ६१.७७ प्रतिशत बढ़ गया और यही स्थिति १८वीं शताब्दी के अन्त तक बनी रही। इससे प्रतीत होता है कि राज्य की सैनिक माँगों में बूझी ही हुई थी, जो १८वीं शताब्दी के राजस्थान की राज्यों के अन्दर व बाहर पारस्परिक कलह के अविवकलपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए समझ में भी आती है। इन वर्षों में शासकों ने भी सैन्य खर्चों में बूझी की ही इच्छा की थी, न कि घटोतरी की। १८वीं शताब्दी के अन्त में १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राजा व ठाकुरों तथा पटोसी शक्तियों के साथ संघर्ष में राज्य के सैन्य खर्च जो १६६६ ई० की तुलना में पाँच गुना अधिक बढ़ा दिया। महाराजा सूरतसिंह ने केवल भाड़ के सैनिकों पर एक वर्ष में ३,५६,११६ रुपये खर्च किये। अस्त्र शस्त्रों का खर्च अवश्य कमी २ प्रतिशत में अधिक नहीं बढ़ा, क्योंकि भाड़े के सैनिकों अपना हथियार स्वयं लाते थे। बस यह खर्च महाराजा गजसिंह के काल से ही प्रारम्भ हो गया था, उन्होंने भी कुल सैन्य खर्च का ५६.३६ प्रतिशत सीरबन्धीयाँ पर खर्च कर दिया था।

महाराजा गजसिंह व सूरतसिंह ने सेना के सभी विभागों को दृढ़ करने के लिये नई खरीद की। १७५७ में 'तोपखाने', 'तवेले', 'फीलखाने' पर १३८६ रु० खर्च किये जो १७६५ ई० में उड़कर ११,६४२ रुपये की राशि तक पहुँच गये। १८०६ ई० में इस वावज़ २४,६०० रुपये की खरीद हुई। इस वर्ष 'फौज खर्च' भी बहुत बढ़ गया। अकेले मारवाड़ अभियान में १,४३,६८१ रुपये के

१ सैनिकों की वेतन में दे पाने की दुर्घट स्थिति के लिये देखिये—भैय्या सग्रह के भैय्या नथमन के पत्र, ब्यूरोक्रेसी इन राजस्थान—पृ० ७०-७७

खर्च का दबाव पड़ा था। राज्य के उत्तरी भागों में हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिये राजगढ़ में जो सेना रखी थी, उस पर १६,६८३ रुपये का खर्च आया था। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर नियुक्त टुकड़ियों के खर्च को मिलाकर यह राशि १,८६,११६ रुपये तक पहुँच गई थी।

१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों से राज्य हर प्रकार में एक सैनिक शिविर बन गया था। थाणों या खर्च भी स्थायी रूप से बढ़ रहा था। पहले जहाँ दस मुख्य भागों थे, वहाँ महाराजा मूरतसिंह के काल में सत्ताईस, उच्च-स्तर के भागों स्थापित किये गये।^१ १७६५ ई० में इन भागों पर ४६,३६० रुपये की राशि खर्च की गई, जोकि १८०६ ई० में बढ़कर १,०७,०१७ रुपये की हो गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन समस्त खर्चों के पश्चात् भी महाराजा मूरतसिंह ने आय के साधनों को बढ़ाकर राज्य के कुल खर्च में सैन्य खर्च को ६० प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ने दिया, बल्कि १८०६ ई० में जब वैसे सैन्य खर्च पाँच गुना बढ़ गया था, पर कुल खर्च में पहले से कम अर्थात् ५६.५५ प्रतिशत रहा। इस प्रकार बजट में खर्चों के बीच काफ़ी संतुलन स्थापित करने के यत्न किये। लेकिन यह संतुलन राज्य के लिये बहुत महंगा व कष्टदायक सिद्ध हुआ। सैन्य खर्चों में निरन्तर वृद्धि ने राज्य को विवश किया कि वह नये कर लगाकर आय के साधनों में वृद्धि करे अथवा नृण लेकर व्यवस्थित करे। इन दोनों ही प्रयत्नों ने राज्य के आर्थिक साधनों को निचोड़ दिया तथा प्राकृतिक विपत्ति के भारे लोग इस विपत्ति को न सहन कर पाने पर यहाँ से भाग खड़े हुए।^२

(६) मुगल सेवा में खर्च—बीकानेर शासकों द्वारा मुगल दरबार में जाने पर, साम्राज्य में किसी स्थान पर नियुक्ति होने पर, ज़मीन व पद की प्राप्ति पर तथा विभिन्न उत्सवों आदि पर निर्धारित खर्च करने पड़ते थे। महाराजा अनूपसिंह ने अपने दक्षिण-सेवाकाल में इस तरह के कई खर्च किये थे। उन्होंने सन् १६८१ ई० में सन् १६६२ ई० के बीच १,६६,०५६।। =) रुपये दुयब दाखल^३ करवाए थे। इसी प्रकार इन्हीं वर्षों में जो अन्य खर्च हुए थे, वे इस प्रकार

१. दयालदास ग्राम (प्र प्र) २, पृ० ३०२-२०

२. डॉर ने जो उस समय राजस्थान में ही था, इस स्थिति का सुन्दर चित्रण किया है डॉर, भाग २, पृ० ११४५-४०

३. खुराके-दबाव—सादशाह के अस्तवत्न खर्च व पञ्जबों के भोजन के लिए भनसबदारी के वेतन में कटौती। ऐसा प्रतीत होता है कि 'दुयब दाखल' में न केवल खुराके दबाव की कटौती बल्कि अन्य छोटी-बड़ी सभी कटौतियाँ भी शामिल थीं। वज़ा-ए दाम-ए-चौपाई की कटौती राशि भी घसग से नहीं मिलती, जबकि उसका नाम 'वहीयो' में दुयब दाखल के साथ मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि चौपाई भी 'दुयब दाखल' में सम्मिलित थी। इन कटौतियों के अध्ययन के लिये देखिये—घतहरजली, मुगल नॉनिलिटी अफ़र मोरगजेव (पृ०), पृ० ५०-५२, इन बाल में अनूपसिंह को मुगल जाबोरा से किवनी प्राप्त हुई, इसका निश्चित विवरण नहीं मिलता है।

पर पहुँचा दिया, जिसके फलस्वरूप राज्य भयानक वित्तीय कठिनाई का म फस गया।^१

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि सैन्य खर्च राज्य का प्रमुख खर्च था और कुल खर्च में बाघे से अधिक राशि इसी पर खर्च की जाती थी। कुल खर्च के ६० प्रतिशत के साथ-साथ सामन्तों का भी सैन्य खर्च अगर ध्यान में रखा जाये तो राज्य की समस्त आय का ८० प्रतिशत से अधिक ठा बचल मना पर ही खर्च हो जाता था।

सैन्य खर्च की कारणों से दो तथ्य मुख्य रूप से उभरते हैं। प्रथम, १८वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों की तुलना में १८वीं शताब्दी में सैन्य खर्च में अभी आ गई थी, जो १६६६ ई० के आधार पर १७५७ ई० में ६६५१ प्रतिशत थी। इन वर्षों में बीकानेर शासकों के मुगल सत्ता से हट जाने से तथा राज्य में भारी कठोरता लागू करने पर यह कमी आई थी। फिर, इन वर्षों में राज्य की पटती हुई आय के साथ शतुलन भी स्थापित करना था। द्वितीय, राज्य के कुल खर्च में सैन्य खर्च के प्रतिशत में कमी नहीं बृद्धि हुई थी। १६६६ ई० में, जहाँ कुल खर्च में सैन्य खर्च का प्रतिशत ५३.६६ प्रतिशत था, वहाँ १७५७ ई० में यह ६१.७७ प्रतिशत बढ़ गया और यही स्थिति १८वीं शताब्दी के अन्त तक बनी रही। इससे प्रतीत होता है कि राज्य की सैनिक मांगों में बृद्धि ही हुई थी, जो १८वीं शताब्दी के राजस्थान की राज्यों के अन्दर व बाहर पारस्परिक बल के अविश्वपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए समझ में भी आती है। इन वर्षों में शासकों ने भी सैन्य खर्चों में बृद्धि की ही इच्छा की थी, न कि पटोती की। १८वीं शताब्दी के अन्त में १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राजा व ठाकुरों तथा पटोती सैनिकों के साथ संधि ने राज्य के सैन्य खर्च को १६६६ ई० की तुलना में पाँच गुना अधिक बढ़ा दिया। महाराजा मूरतसिंह ने केवल भाड़े के सैनिकों पर एक वर्ष में ३,५६ ११६ रुपये खर्च किए। अस्त्र-शस्त्रों का खर्च अवश्य कभी २ प्रतिशत में अधिक नहीं गया, क्योंकि भाड़े के सैनिक अपने हथियार स्वयं लाते थे। वैसे यह खर्च महाराजा गजसिंह के बाल से ही प्रारम्भ हो गया था, उन्होंने भी कुल सैन्य खर्च का ५६.३६ प्रतिशत सौकर-धीरों पर खर्च कर दिया था।

महाराजा गजसिंह व मूरतसिंह ने सना के सभी विभागों को दृढ़ करने के लिये नई खरीद की। १७५७ में तोपखाने, 'तबेले', 'फौजखाने' पर १३८६ ४० खर्च किए, जो १७६५ ई० में उठकर ११ ६८२ रुपये की राशि तक पहुँच गये। १८०६ ई० में इस बार २८,६०० रुपये की खरीद हुई। इन वर्षों 'फौज खर्च' भी बहुत बढ़ गया। अबले मारवाड़ अभियान में १,४३,६८१ रुपये के

१. सैनिकों को वेतन न दे पाने की दुःखद स्थिति के लिये देखिये—भैय्या सप्रह के भैय्या मयमल के पत्र, अमरोकेशी इन राजस्थान—पृ० ७०-७७

खर्च का दबाव पड़ा था। राज्य के उत्तरी भागों में हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिये राजगढ़ में जो सेना रखी थी, उस पर १६,६८३ रुपये का खर्च आया था। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर नियुक्त टुकड़ियों के खर्च को मिलाकर यह राशि १,८६,११६ रुपये तक पहुँच गई थी।

१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों से राज्य हर प्रकार में एक सैनिक शिविर बन गया था। थाणों का खर्च भी स्थायी रूप से बढ़ रहा था। पहले जहाँ दस मुख्य थाणों थे, वहाँ महाराजा मूरतसिंह के काम में सत्ताईस, उच्च-स्तर के थाणों स्थापित किये गये।^१ १७६५ ई० में इन थाणों पर ४६,३६० रुपये की राशि खर्च की गई, जोकि १८०६ ई० में बढ़कर १,०७,०१७ रुपये की हो गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन समस्त खर्चों के पश्चात् भी महाराजा मूरतसिंह ने आय के साधनों को बढ़ाकर राज्य के कुल खर्च में सैन्य खर्च को ६० प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ने दिया, यद्यपि १८०६ ई० में जब वैसे सैन्य खर्च पाँच गुना बढ़ गया था, पर कुल खर्च में पहले से कम अर्थात् ५६.५५ प्रतिशत रहा। इस प्रकार बजट में खर्चों के बीच काफी सतुलन स्थापित करने के यत्न किये। लेकिन यह सतुलन राज्य के लिये बहुत महगाय कष्टदायक सिद्ध हुआ। सैन्य खर्चों में निरन्तर वृद्धि ने राज्य को विवश किया कि वह नये कर लगाकर आय के साधनों में वृद्धि करे अथवा ऋण लेकर व्यवस्थित करे। इन दोनों ही प्रयत्नों ने राज्य के आर्थिक साधनों को निचोड़ दिया तथा प्राकृतिक विपत्ति के मारे लोग इस विपत्ति को न सहन कर पाने पर यहाँ से भाग खड़े हुए।^२

(६) मुगल सेवा में खर्च—बीकानेर शासकों द्वारा मुगल दरबार में जाने पर, साम्राज्य में, किसी स्थान पर नियुक्ति होने पर, जागीर व पद की प्राप्ति पर तथा विभिन्न उत्सवों आदि पर निर्धारित खर्च करने पड़ते थे। महाराजा अनूपसिंह ने अपने दक्षिण-सेवाकाल में इस तरह के कई खर्च किये थे। उन्होंने सन् १६८१ ई० से सन् १६९२ ई० के बीच १,६६,०५६।। =) रुपये दुयब दाखल^३ करवाए थे। इसी प्रकार इन्हीं वर्षों में जो अन्य खर्च हुए थे, वे इस प्रकार

१. दयानिदास ध्याम (स प्र) २, पृ० ३०२-२०

२. टॉड ने जो उस समय राजस्थान में ही था, इस स्थिति का सुन्दर चित्रण किया है टॉड, भाग २, पृ० ११४३-४०

३. घुरावे-दबाव—बादशाह ने वस्तुतः खर्च व पण्डों के भोजन के लिए मनसबदारों के वेतन में कटौती। ऐसा प्रतीत होता है कि 'दुयब दाखल' में न केवल घुरावे दबाव की कटौती बल्कि अन्य छोटी-बड़ी सभी कटौतियाँ भी शामिल थीं। वज़ा-ए-दाम-ए-चोषाई की कटौती राशि भी घलन में नहीं मिलती, जबकि उसका नाम 'बहीषो' में दुयब दाखल के साथ मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि चोषाई भी 'दुयब दाखल' में सम्मिलित थी। इन कटौतियों के अध्ययन के लिये देखिये—मनहरबख्सी, मुगल नॉबिलिटी अण्डर प्रोरग्रेस (पूर्व), पृ० १०-१२, इस बाल में अनूपसिंह को मुगल जागीरों से कितनी आय हुई, इसका निश्चित विवरण नहीं मिलता है।

ये—मुगल दरबार में विभिन्न अवसरों पर बादशाह साहजादों, बज़ीर, मीर-बख़्शी एवं अन्य महत्त्वपूर्ण मुगल अधिकारियों को जो नज़र भेंट की थी, उसमें बादशाह को (१५,२७० रु०, साहजादा साहब आत्म को २,८७६ =) ६० आजम-शाह को (१२,५८६।) ६० विभिन्न अवसरों पर नज़र दिये गये थे। बज़ीर असद खाँ मीरबख़्शी, सातहजारी मनसरदार यात्रोउद्दीन खाँ आदि अन्य अधिकारियों तथा मानसरदारों को नज़र के रूप में २,२५,०८७।।) ६० भेंट किए गये थे। इसके अलावा सम्राट द्वारा बख़्शीय देने पर भी नज़र देनी पड़ती थी। यहाँ के शासकों को जब नई जागीर या नया पद दिया जाता था, तब भी नज़र भेंट करनी पड़ती थी। 'मतालये बाबत' यहाँ के शासक को ५,८७३।) ६० मुगल राजानों में जमा कराने पड़े थे। 'जागीरी ख़ैर' में 'बज़िया' को ख़म बग़ूल करके जमा करनी पड़ती थी। विभिन्न जागीरों के पदों के लिए जो 'फरमान' प्राप्त होते थे, उन पर भी नज़र भेंट होती थी। जिस परगने में नियुक्ति होती थी, वहाँ पर नियुक्त अधिकारियों को भी बख़्शीय देनी पड़ती थी।^१ इसके अतिरिक्त शासक के जो कर्मचारी जागीर में कार्य करते थे उनको 'महीनदार' के रूप में वेतन दिया जाता था। इन दृष्टि से १२ वर्षों में ३०,०८५।। ६० खर्च हुआ था। केवल बख़्शीय में ५,६१४।। ६० का खर्च आया था। शासक के मुगल दरबार के खर्च, उनके 'बकील' के माध्यम से होते थे। बकीलों को महीनदार के रूप में वेतन प्राप्त होता था।^२ राव कर्णसिंह व महाराजा अनूपसिंह की बहियों से ज्ञात होता है कि यहाँ के शासक, इन खर्चों की पूर्ति, पहले महाराजों से श्रृण लेकर करते थे। जागीरी आय प्राप्त होने पर श्रृण को चुरा दिया करते थे। राव कर्णसिंह ने तो अपनी ममस्त दक्षिणी 'जागीरी आय' को 'इज़ार' पर चढ़ा दिया था।^३ महाराजा अनूपसिंह के १२ वर्षों के, दक्षिण सबावाल में खर्च की कुल राशि ६,४०,५२० रु० थी। १८वीं शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य से यह खर्च बिलकुल समाप्त हो गया था। लेकिन जितनी मुगल दोना की आय न मिलन में हानि हुई, उतना प्रभाव इस खर्च की समाप्ति में नहीं पड़ा।

(७) सिरोपाय—शासक अपने सामन्ता, दरबारियों, बर्मधारियों को विभिन्न अवसरों पर दरबार में पुरस्ठुत करत समय, जो 'फैदा' या पगड़ी,

१. मुतालिब—मनसरदारा को दी जाने वाली अधिप राशि
२. इन सभी खर्चों की राशि जो इन वर्षों में ४०,०४५ थी, 'बाजगारदोनी बाबत' दीपक के अंतर्गत लिखी गई है।
३. लिप्यत बही, वि० सं० १७४०/१६८३ ई०, न० २०७, बामदास व बख़्शीओं के राजगार की बही, वि० सं० १७५३/१६९६ ई० न० २०६
४. औरंगाबाद करणपुरे के जमा खर्च की बही, वि० सं० १७६८/१७११ ई०, न० १३१
५. साफ़, पगड़ी

‘दुशाला’, ‘कडा’ व ‘पालकी’, घोडा इत्यादि वस्तुओं में देता था, उनका खर्च, ‘सिरोपाव खर्च’ कहलाता था। यह कुल खर्च राशि का १ प्रतिशत से अधिक कभी नहीं होता था।^१

(८) अन्य प्रशासनिक खर्च—कालीद खर्च राज्य में उन ‘सन्देशवाहकों’ का खर्च था, जो राज्य की उसकी सीमाओं के भीतर व बाहर दोनों तरफ, अपनी सेवाएँ अर्पित करते थे।^२ सन् १७५७ ई० में कुल खर्च में इसकी राशि ०.०६ प्रतिशत थी, १७६५ ई० में ०.२३ प्रतिशत तक १८०६ ई० में ०.१४ प्रतिशत थी।

(९) कमठाणा खर्च—राज्य में महारो, किलो व अन्य सार्वजनिक निर्माण में जो खर्च आता था, वह ‘कमठाणा’ लागत के नाम से दर्ज होता था।^३ इसकी खर्च होने वाली राशि कुल खर्च में सन् १७५७ ई०, सन् १७६५ ई० व सन् १८०६ ई० में, क्रमशः १०.२७ प्रतिशत, २०.०० प्रतिशत व १.४४ प्रतिशत थी। १८०० ई० के पश्चात् सैनिक खर्चें बढ़ जाने के कारण निर्माण कार्यों में रुकावट आई, इसी कारण इसका खर्च १.४४ रह गया। विभिन्न प्रशासनिक खर्चों में कागज-स्याही का जो खर्च आता था, वह ‘पाठा’ ‘साही लागत’ के नाम से जाना जाता था।^४ यह खर्च १७६५ ई० में, कुल खर्च राशि का ०.३३ प्रतिशत था और १८०६ ई० में ०.०६ प्रतिशत रहा; जबकि कागज-स्याही के खर्च की राशि इन दो विभिन्न वर्षों में ५६२ रुपये से बढ़कर १०६० रुपये हो गई।^५ प्रतिशत में गिरावट का कारण अन्य खर्चों में कटमय वृद्धि होना था।

(१०) परचुण या खरीद खर्च—दरबार व राजमहल की विभिन्न वस्तुओं को खरीदने का खर्च इसके अन्तर्गत आता था।^६ इस खर्च की राशि १६७० से १६६३ ई० के बीच ११,०१२ रुपये आई थी। राज्य के कुल खर्च में इसकी राशि का प्रतिशत १७६५ ई० में १.४२ प्रतिशत तथा १८०६ ई० में ३.५२ प्रतिशत था, अर्थात् यह खर्च भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालता जा रहा था।

(११) घास खर्च—राज्य के विभिन्न विभागों के तबेलों के पशुओं के लिए जो चारा-घास खरीदी जाती थी, इसका अलग में विवरण रखा जाता था। यह खर्च राज्य के कुल खर्च में, १७५७ ई० में २.६२ प्रतिशत; १७६५ ई० में २.८३

१. वही परवाना टीबाणा रो, वि० सं० १८८५/१८९८ ई०, नं० ४०/११, रामपुरिया रिवाइस, बीकानेर

२. वही उपरली पदें खर्च, वि० सं० १७८३/१७८६, नं० ३३

३. वही बड़ा कमठाणा रो, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, वि० सं० १८५७/१८०० ई० तक

४. वही छाप रे कागद रो, नं० ४०/१२, रामपुरिया रिवाइस, बीकानेर

५. कागद की बही, सं० १८४६/१७८६ ई०, नं० ८, पृ० ४६

६. वही परचुण खर्च, सं० १७९७/१६९० ई०, नं० १२०, बीकानेर बहियात

प्रतिगत तथा १८०६ ई० म० ६६ प्रतिगत का स्थान रखा था।^१ १८०६ ई० म० घटोतगी र कारण सब राजि का कम उद्दा होना था वल्कि अय ग्रहों की दोड़ म पीछ रह जाना था।

(१२) धार्मिक छव—यह छव राज्य म पुनथ, मदिरात व देवस्थान ग्रथ न नाम स जाना जाना था। यहाँ के सासव अपन राज्य को पुनदवी करणीजी य पुनदेरता सहमीनारायणजी का उपशर मानत थ। इस वारण इनके मदिरो का सम्पूर्ण ग्रर राज्य वफन करता था। हिन्दु धर्म के निष्ठावान अनुयायी तथा उनके रक्षक होने न वारण यहाँ के सासव अय मदिरो व धार्मिक कृत्या पर भी छव किया करते थ। यहाँ न राजा परम्परास १ र और बिगी भी धार्मिक क्रिया को सम्पन्न क ले म सदैव उत्साह ितात थे। राज्य म समय समय पर यज्ञ व अनुष्ठान फिय जात थे।^२ यहाँ न सामन्य अपने धर्म व प्रति उत्साही अवस्थ थ लेकिन पट्टर धर्मापसम्बी नहीं थ। उन्होंने अय धर्म व सम्प्रदायो को पूरा मरक्षण प्रदान किया तथा अनुदान प्रदान करने म पूरी रचि दियाई।^३ राज्य के बाहर भी वो मदिर व मस्जिदें थी उह भी अनुदान के रूप म वापिन भेंट प्रस्तुत की जाती थी।^४ १७वां सताब्दी म छ मिव कृत्या पर नये छव की कुल राजि राज्य के कुन छव मे अपना १ प्रतिगत स्था रखा थी लेकिन १८वीं सताब्दी म इनका अनुपात बढ़ गया महाराजा मूरतसिंह न का न म यह स्थान ६ प्रतिगत स भी अधिक बढ़ गया जोकि मय व प्रशामनिक यत्नों की पुक्ति की सेजी म अपना अलग स महस्य रखता है। महाराजा मूरतसिंह ने सगन अधिर पुनथ दान दिये थ तथा ये सग्रा ग्राहणो म पिरे रहने थे।^५

भाग—३

वित्तीय प्रबन्ध

राज्य मे दीवान के पद पर किसी की नियुक्ति करत समय सामन उसन यह आशा रखता था कि वह राज्य की वित्तीय व्यवस्था का समुचित प्रब ध

- १ जयपुरी रो बही स० १७५६/१७०२ ई० न० १३६ बीकानेर बहियात
- २ निमदान रे मेये रो बही स० १७७०/१७१३ ई० न० १८८ बीकानेर बहियात ग्राहण करामी पुरोहित सोमी (स्वामी सन्वासी) पकोर पुरोहित रेखे—परवाना बही स० १८००/१७४३ ई०
- ३ परवाना बही स० १८००/१७८३ ई० विशेषकर देखिये—पृ० २१६, २२० २२१
- ४ समस्त गाँवा रो बही स० १७२५/१६६८ ई० (पृ०)
- ५ टॉड—भाग २ पृष्ठ ११४२ (पृ०)

करेगा।^१ इस आशा के फलीभूत न होने पर दीवान को पद से विमुक्त कर दिया जाता था।^२ अतः दीवान का यह प्रमुख कर्तव्य होता था कि वह राज्य की आय व व्यय के बीच सही अनुपात में, सही सतुलन बिठाये। इसके लिये वह कैसे प्रयत्न करता था इसका उत्तरे १७वीं शताब्दी के मध्य काल तक कही नहीं मिलता है। महाराजा अनूपसिंह के काल की खातसा व परगना जमा खर्च की बहियों से प्रथम बार जानकारी मिलती है कि प्रशासन की ओर से आय व व्यय की राशि के बीच सही सतुलन स्थापित करने के लिये कई उपाय जुटाये गये थे।^३

१८वीं शताब्दी में दीवान के कार्यालय में आय व्यय के आकड़ों की सही जानकारी रखने के लिए खजाना व लग्ना बहिया तैयार की गयी थी। खजाने में जमा-खर्च होने वाली राशि का पूरा विवरण रखने के लिए भी खाताखजाना बहिया बनाई गई। दम प्रकार राज्य के वित्तीय प्रबंध को व्यवस्थित रूप दिया जाने लगा तथा आधुनिक अर्थों में बजट निर्माण की नींव पड़ी।^४

खजाना सर्व्व ही राज्य का एक आवश्यक अंग माना गया है। बीकानेर राज्य में 'श्री रावले' तथा 'श्री चौतड़े', ये दो मुख्य खजाने थे। 'श्रीरावना' राज परिवार से सम्बन्धित खर्चों की पूर्ति करता था व मुख्य रूप से भुगतल जागीरी आय इसमें एकत्रित की जाती थी। 'श्री चौतड़ा खजाना', यत्न जागीर की आय में, हासिल की मुख्य रूप से सप्रहीत करता था। राज परिवार के अलावा अन्य राज्य खर्चों की पूर्ति इससे की जाती थी। इसके 'अनावा 'कोट खजाना' भी था, जिसमें बहुभूतय रत्न, मोने व जडाऊ आभूषण जमा होते थे।^५ राज्य में 'श्री मंडी' व 'मोदीखाने' के सहायक खजाने भी थे, जो अपने क्षेत्र से व विभाग से सम्बन्धित आय व्यय का हिसाब रखते थे। १८वीं शताब्दी में 'श्री रावला' व 'चौतड़ा' का खजाना मिला दिये गये थे व इनका सम्मिलित नाम, 'श्री रावला खजाना' रखा गया। ये सभी खजाने अर्थ व्यय का हिमाव व तमकी रमीदें रखते थे।^६

१ महाराजा अनूपसिंहजी से नावर बाबूदराम से नाम परवानो वि० सं० १७४१/१६६२ ई०, १६७/१६

२ दयालदास व्यास (पृष्ठ०) २ पृ० २६३

३ परगना से जमा जोड से बड़ी वि० सं० १७२६ ५०/१६६६-६३ ई०, न० ६६ परगना से जमा खर्च से बड़ी, वि० सं० १७५० ५१/१६६३ ६४ ई०, न० ३२

४ वित्तीय प्रबंध का बयान भी सन् १६६६ १७५७ १७६५ व १८०६ ई० की बहिया पर आधारित है।

५ राजा क कोट खजाने का राज्य की बहियों में कोई विवरण नहीं प्राप्त होता है।

६ नोट से सार्च दायल से जमा खर्च बड़ी, सं० १७१६/१६५६ ई०, खजाने से जमा खर्च बड़ी, सं० १७५३ १६/१६६८ ६६ ई० न० ३३, मंडी से जमा खर्च बड़ी, सं० १७०१/१६४४ ई०, न० ७४—बीकानेर बहियाव

शामक स्वयम् खजाने में सम्पर्क बनाए रखता था तथा अपनी अनुपस्थिति में दीवान को इसकी देखभाल का दायित्व सौंपता था।^१ खजाने का मुख्याधिकारी 'खजान्ची' होता था, जो दीवान के निरीक्षण में कार्य करता था। खजान्ची का सहायक 'दरोगा खजाना' कहलाता था तथा खजान्ची के अनेक गुमास्ते व 'ताबोनदार' होते थे। 'सेप्रा व खजाना बहियां' तैयार करने के लिये 'सेप्रागिया' की नियुक्ति की जाती थी।^२

आय तथा व्यय की राशि में अन्तर^३

सन् १६६६ से १८१८ ई० तक १०० प्रतिशत के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन

वर्ष	आय	व्यय	अन्तर
१६६६	१००.००	१००.००	०.००
१७५७	५६.६६	५५.८३	+३.८६
१७६५	७१.४४	८६.७४	-१५.३३
१८०६	५०.७१	५५.७६	-५.०५

इस रगिस्तारी राज्य की वित्तीय स्थिति में सबसे बड़ी दुःखद घटना यह रही है कि यह अपने जाय और व्यय के बीच सतुलन स्थापित करने में असफल रहा है। सर्वत्र ही राज्य की आय उसका खर्चों की पूर्ति करने में पीछे रही है। १६ वीं शतब्दी के अन्त तक राज्य की प्रशासनिक योजनाएँ अपन पैर जमा चुकी थी पर आर्थिक अस्थिरता ने फिर भी उसका अविव्य सन्निध्य बना रखा था। प्राकृतिक अनुदारता यहाँ के विनाश की सबसे बड़ी रुकावट थी। एक सुसंगठित प्रशासन को चलाने के लिये त्रिश निश्चित आय व दृढ़ आर्थिक स्थिति की आवश्यकता होती थी, उस सूखे व अभाव ने कभी पनपन नहीं दिया। मुगल जागीरों से प्राप्त अतिरिक्त आय ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रोत्साहित किया, परन्तु उस बीच प्रशासकों ने वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु स्थायी उपाय ढूँढने का यत्न न करके अवसर को गवाँ दिया। यहाँ के शासकों को मुगल साम्राज्य के विस्तार, उसकी दृढ़ता व सम्पन्नता ने निश्चित बना दिया था। वे राज्य की आय वसाधनों को विनमित करने व स्थान पर अधिक मुगल जागीरों को प्राप्त करने की लपेट में आ गये। फिर शासकों ने बढ़त हुए निजी

१ महाराजा अनुपस्थित हो नाजर आनदराय रै नाम परबान्ने (पूब)

२ श्री रावल देवे, स० १७७२/१७८० ई०, न० २१२

३ देखिये देखाचित्र

खर्चों व गानग्रीकत ने भी वित्तीय स्थिति को पक्ष में नहीं होन दिया। १६६६ ई० में जहाँ राज्य की आय १,८७,२६५) रुपये थी, वहाँ खर्च की कुल राशि २,१५,०६५) रुपये थी। इस प्रकार २७,८००) रुपये की कमी बनी हुई थी। १८ वीं शताब्दी में मुगल जागीरी आय की समाप्ति से ठठिनाइयाँ और बढ़ी; क्योंकि मुगल सेवा के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी, थोड़े समय बाद, पारस्परिक झगड़ों व पड़ोसियों के साथ संघर्ष ने सैन्य खर्चों में बर्बादी नहीं आने दी। १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस बात के प्रयास किये गये कि खर्च में कटौती कर, उसका आय के साथ समुत्तुलन स्थापित किया जाये। लेकिन ठाकुरों के विद्रोह, मारवाड़ के साथ युद्ध व प्रशासनिक ढिलाई ने खर्चों में वाछित कमी को सम्भव नहीं होने दिया वल्कि बिगाड़ दिया।^१

१७५७ ई० का बजट अवश्य नटौतियों का बजट था, जिससे सैनिक व प्रशासनिक खर्च विशेषकर प्रभावित हुए थे। इस वर्ष जहाँ आय की राशि में ४० ३१ प्रतिशत की कमी आई थी, वहाँ व्यय में ४४ १७ प्रतिशत की मिरावट आई थी। तत्पश्चात् स्थिति नियन्त्रण से बाहर जाने लगी। महाराजा गजसिंह के काल में 'सीरबन्धीयों' के खर्च बढ़ गये थे व साथ ही महीनदारों व कारखानों के खर्च में भी वृद्धि होने लगी थी। इस बीच राज्य में मुगल परगनों के स्थायी रूप से मिन जाने से आय में वृद्धि हुई थी, लेकिन सैनिक व प्रशासनिक मागों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होने दिया। महाराजा गजसिंह १८ वीं शताब्दी का प्रथम व अन्तिम राजा था, जो किसी प्रकार वित्तीय स्थिति को नियन्त्रित कर सका। महाराजा मुरतसिंह के काल में विद्रोह बढ़े व उत्तरी सीमा पर जार्ज थॉमस व सिक्खों का आक्रमण होने लगे, जिससे सैनिक खर्चों में और वृद्धि हुई। १७५७ से १७६५ ई० के वर्ष तक सैन्य खर्च, महीनदारों का खर्च तथा कारखानों का खर्च क्रमशः ३३ ४६ प्रतिशत, ३० २ ५३ प्रतिशत व १६६ १६ प्रतिशत बढ़ गया था। इन वर्षों में, आय में भी हासल, पेशकशी, जमात में क्रमशः १२२ ६३ प्रतिशत, १६७ ०६ प्रतिशत व २३५६ ७८ प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके साथ ही 'घोडा रेख' व 'रुखवाली भाछ' नाम के नये कर भी लागू किये गये। परन्तु सन् १७५७ ई० की तुलना में, सन् १ ६५ ई० में आय ११ ३७ प्रतिशत बढ़ी, वहाँ व्यय में ३० ८१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय और व्यय का यह अन्तर अपने आप में काफी था व इस घाटन के भी पूरे प्रयास किये गये। राज्य की सभी सीमाओं में विस्तार हुआ व नये क्षेत्रों से राज्य की आय बढ़ी।^१ परन्तु महाराजा के ठाकुरों के साथ सम्बन्ध ठीक न होने के परिणाम-

१ श्रीकानेर रं रठौडा री व्याप्त महाराजा मुद्रापरिचय की मुं बन्धसिध्दी ताई पृ० ५ (५४), दयालदास व्याप्त (अप्र०) २, पृ० २१२ १५

२ दयालदास व्याप्त (अप्र०) २, पृ० ३०१ ८

स्वरूप विद्रोहों में तीव्रता और बड़ी तथा मारवाड़ पर आक्रमण ने भी सैनिक खर्चों को बढ़ा दिया।^१ इनका समाधान करने के लिये करो की दरों में वृद्धि कर दी गई तथा 'घान की बोथाई' कर को अधिक सख्ती से सभी निवासियों से वसूल किया गया। राज्य में निवास करने वाली प्रत्येक जाति पर कर लगा दिये गये, जिसमें सन् १८०६ ई० में राज्य की अधिकतम आय हुई, लेकिन खर्च भी उसी तेजी से बढ़ा। राज्य में १६६६ ई० की तुलना में जहाँ आय में ५०७.१०२ प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहाँ खर्च में भी ५५७.६४ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार आय-व्यय के बीच इस दृष्टि से ५०.८४ प्रतिशत का अन्तर बना रहा। यह अन्तर अपने आप में बहुत विशाल था। एक कम साधनों वाले रेगिस्तानी राज्य के लिये अनेक कठिनाइयों को आमन्त्रित करने वाला था।

राज्य ने आय व व्यय के बीच मही सतुलन स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से तीन उपाय जुटाये—प्रथम ऋण द्वारा, द्वितीय नये करो को लागू करके, तथा तृतीय खर्च में कटौतियाँ करके।

इन सबमें, सबसे अधिक, ऋण का ही सहारा लिया गया था। रेगिस्तानी क्षेत्र की अस्थिर आय को, व्यय के साथ, सतुलित करने का यह एक आशावादी उपाय था। राज्य मुख्य रूप से दो कारणों से ऋण लेता था, प्रथम आय की कमी को पूरा करने के लिए, द्वितीय, खर्च की आकस्मिकता को रोकने के लिए। आय की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया ऋण, आगामी वर्षों में नकद राशि के साथ चुका दिया जाता था, जबकि खर्च की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 'खतो पर कर्ज'^२ लिया जाता था, जिसमें ऋण लेकर राजकीय आदेश का पत्र ऋणदाता को दे दिया जाता था और वह निर्धारित क्षेत्र से हासल व अन्य करो की वसूली करके, अपने ऋणों का भुगतान कर लेता था।^३ १८वीं शताब्दी में जब सैनिक व प्रशासनिक व्यय के लिए खर्चों की निरन्तर आवश्यकता पड़ी, तो राज्य ने 'खतो पर' पर कर्ज अधिक लिया था।^४ राज्य ने सार्वजनिक ऋण की माँग भी की थी। उस ऋण का हिसाब, प्रत्येक निवासी को व्याज सहित राज्य को दिये जानेवाले करो की रकम में, व्यवस्थित कर दिया जाता था।^५ साधारणतया इन ऋणों पर २ से १० प्रतिशत के बीच व्याज लगता

१ दफातदारान ख्यात (अग्र०) २, पृ० ३०५ ८

२ ऋण के गिरवी पत्र—राजने घरख की बही, नं० १८०५/१७४८ ई०, नं० २१३, भूरी-कमी इन राजस्थान पृ० ६३ ६८ (पूर्व)

३ कागदा की बही, नं० ११, वारिक बदि ५, १८५७/८ अक्टूबर, १८०० ई०

४ बही, नं० १८५६/१८०२ ई०, नं० १२, पृ० ४४ ५१, नं० १८७४/१८१७ ई०, नं० २३, पृ० ५४-५८

५ बही, गवळ गुदि २, ख० १८११/२६ मई, १७५४ ई०, नं० १

था व साथ में ऋण की दृष्टि होने पर 'हुडावण' भी चुकाना पड़ता था, जिसकी दर स्थान की दूरी पर निर्धारित होती थी।^१

सन् १६७० ई० से सन् १६६२ ई० के बीच जब राज्य की कुल आय में वृद्धि हो रही थी, तब भी तेईस वर्ष में तीन लाख छत्तीस हजार का ऋण लिया था।

ऋण की रकम की सूची

वर्ष	रकम (रुपयों में)	प्रतिशत (१०० के आधार पर)	आय के साथ सम्बन्ध (प्रतिशत में)
१६६६	३५,६५१	१००.००	१६.१५
१७५७	८,०६०	२२.४१	७.३४
१७६५	५२,४८०	१४५.६७	३६.१६
१८०६	२,४८,२८६	६६०.६२	२६.०८

सन् १६६६ ई० में ऋण की रकम का कुल आय के साथ अनुपात १६.१५ प्रतिशत का था। १८वीं शताब्दी में ऋण की रकम व उसका आय के साथ अनुपात—दोनों में वृद्धि हुई। केवल सन् १७५७ ई० का आय-व्यय का लेखा इसका अपवाद था, जबकि ऋण की रकम केवल ८,०६०) ४० थी तथा आय के साथ अनुपात ७.३४% का था। सन् १७६५ ई० में ऋण का प्रतिशत बढ़कर ४५.६७ प्रतिशत हो गया तथा सन् १८०६ ई० में ऋण सन् १६६६ ई० के आधार पर लगभग सात गुना अधिक लिया गया। कुल आय के साथ सम्बन्ध में भी अन्तर बढ़ता जा रहा था। १७६५ ई० में ऋण का अनुपात राज्य की कुल आय में ३६.१६ प्रतिशत था; अर्थात् राज्य के खर्च को पूरा करने के लिये आय केवल ६०.८४ प्रतिशत भाग को ही पूरा करती थी। यह अपन आय में कोई स्वस्थ वित्तीय स्थिति नहीं थी। अगर किसी विपत्ति अथवा सघर्ष की स्थिति में वर्ष अचानक उठान वाली आवश्यकताओं के कारण ऐसा होता, तब भी बात थी, परन्तु ऋण की यह प्रभावशाली व दबाव की स्थिति तो राज्य के बजट का एक स्थायी अंग बन चुकी थी। महाराजा सूरतसिंह ने इससे छुटकारा पाने के लिये प्रचलित आय के साधनों को गहन किया तथा अतिरिक्त साधन भी जुटाये। तैमिन १८०६ ई० में राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरा निचोड़ने के बाद भी उस वर्ष कुल आय में ऋण का अनुपात २६.०८ प्रतिशत रहा। अतः

१ रोड वही, स० १७६६/१७३६ ई०, न० ३२३, कागदों की बही, न० १२, मासाद बहि १३, १८५६/२८ जून, १८०२ ई०

यह स्पष्ट हो गया कि खर्च की असीमित मांगों के सम्मुख ऋण से छुटकारा पाना कठिन है। खर्चिन ऋण भी अपने आप में कोई समाधान नहीं था, क्योंकि इसका ब्याज राज्य के आन वाले वर्षों के बजट से और ऋगाड देता था। १६६६, १७५७, १७६५ ई० में कुल खर्च का क्रमशः ६२८%, १५३६%, २८८५% ब्याज की रकम चुमाने में चला जाता था।

राज्य के बजट को संतुलित करने के लिये तथा ऋण के दबाव से मुक्ति पाने के लिये प्रशासकों की यह नीति रही थी कि प्रचलित करों की दर बढ़ा दी जाये तथा नये करों का लागू कर दिया जाये। वैसे भी, संन्य व प्रशासनिक कारणों के फलस्वरूप उठने वाली अचानक मांगों का पूरा करने के लिये अतिरिक्त कर, जिस ह्यूब^१ कहा जाता था, लागू कर दिया जाता था, जो उस मांग की समाप्ति के साथ रोक दिया जाता था। कई बार, राज्य का जो क्षत्र संपर्क से प्रभावित होता था, वहाँ के निवासियों से अतिरिक्त कर वसूल किया जाता था। साधारण परिस्थितियों में भी नये कर लगाने की प्रथा महाराजा रायसिंह के समय से ही चली आ रही थी। प्रारम्भिक अवस्था में तो नये करों का प्रभाव प्रजा में इसलिये नहीं पड़ा क्योंकि वे कन्द्रीय सत्ता को कर चुकाकर 'पट्टापतो' व चौधरियों की मांग से मुक्त हो जाते थे, अर्थात् सर्व प्रथम केवल करों का हस्तांतरण हुआ था और उससे केवल ठाकुरों व मध्यस्थों की स्थिति कमजोर पड़ी थी। शनैः शनैः कन्द्रीय सत्ता की मांग उनके नियन्त्रण के साथ बढ़ती गई व प्रजा पर करों का दबाव बढ़ने लगा। महाराजा अनूपसिंह ने न केवल 'हासल' की दर में वृद्धि की बल्कि रोकड़ रकम को कई नये व पुराने करों के साथ मिलाकर गठित किया। पट्टा क्षत्र में भी धुआभाछ जैसे कर लागू कर दिये गये। यह मुगल जागीरी आय में ह्रास का काल था तथा जमींदारों^२ को अपने ही साधनों से अपनी स्थिति बनाये रखने की कष्टदायक स्थिति हो रही थी। उनका मुगल सेवा में आकर्षण समाप्त हो रहा था। १८वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में प्रचलित अव्यवस्था के वातावरण में मुगल जागीरा से निर्धारित आय की वसूली की सदिग्ध अवस्था के कारण यहाँ के शासक मुगल सेवा के दायित्वों से मुक्त होकर खर्च के दबाव को कम करने का प्रयत्न करने लगे थे। महाराजा गजसिंह ने अपनी सभी आवश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं के पूर्ण की पूर्ति पूणतया राज्य के साधनों से ही की। उन्होंने 'पट्टापतो' पर 'पशकसा' व 'अन्ना' की राशि का और दबाव डाला। ह्यूब अधिकतर वर्षों में

१ विविध करों का नाम

२. राशि की जमा। उदाहरणार्थ बीदावली का वधा

‘गढ़ से नीचे उतरने लगी ।’ कोरड, भुरज, घास, चारा की राशि रोकड़ रकम में बड़ा दी गई । घुआभाछ’ भी प्रति गुवाडी २५ टका बढ़ गया । महाराजा मूरतसिंह जिनके काल में राज्य का खर्च स्थायी रूप से पान गुना अधिक बढ़ गया था, ने प्रचलित करो की दर में वृद्धि की, अस्थायी करो को स्थायी बना दिया तथा नय करो को लागू किया । हासल की दरों में प्रति हल व बीघा वृद्धि हुई । प्रति हल एक रुपये से तीन रुपये हो गया । ‘भोग’ की रकम १/८ से आकर १/३ व १/५ के बीच स्थिर हो गई । ‘खंड खरब की भाछ’, ‘कीरायतो की भाछ’, कामदारों की ‘भाछ’ व ‘हवूब’ जैसे अस्थायी कर स्थायी रूप धारण करने लगे । खंड खरब की भाछ’ स्थायी रूप से प्रति गुवाडी २) रुपये वसूल होने लगी । ‘घोडा रेख’, ‘खुवासी भाछ’, कीयाडी जैसे नय कर लागू किये गये व साथ ही शीघ्र उनकी दर भी बढ़ा दी गई । खुवासी भाछ’ प्रति गुवाडी २) की दर से लागू हुई, जो २० वर्षों के भीतर ही प्रति गुवाडी १० रुपये पहुँच गई । ‘धान की चौथाई’ को मराठों की भाँति चौथ की तरह वसूल किया गया । इस प्रकार अतिरिक्त कर व दर से राज्य की आय बढ़ाने के उपाय किये गये, पर इससे भी बाछनीय परिणाम नहीं निकला । करा की ‘अकरायत’ से गुवाडिया इधर-उधर बिछरने लगी व गांव सुने होने लगे, परिणामस्वरूप भयभीत होकर महाराजा को करो में छूट की घोषणा करनी पड़ी व कई कर समाप्त करने पड़े ।’

तृतीय उपाय खर्च की कटौतियों में दूढ़ा गया । १७५७ ई० का बजट इसका श्रेष्ठ उदाहरण है । इस बजट में खर्च का ‘लेखा’ केवल आठ महीने का बनाया गया । वेतन भागियों का एक वर्ष का वेतन केवल आठ महीने का वेतन चुकाकर पूरा किया गया । जो ‘रोजीनदार’ थे, उन्हें २० वर्ष से २५ दिन के बीच ११ ही वेतन एक माह के रूप में दिया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि वेतन में कटौतियाँ आम वाले वर्षों में भी प्रचलित रही; जैसा कि १७६५ ई० के बजट से ज्ञात होता है । पर इन कटौतियों का प्रभाव भी खर्चों की असामित

- १ राजकीय बर्हियों में हवूब कर को लागू करत समय ।।। के घोषणियों व पट्टावठा को यह निबन्ध भजा जाता था कि अब हवूब (उंच हवा का झंका) यह से नीचे उतरी है पर्याप्त यह कर लागू हो रहा है आर महंगय कर ।—हवूब बर्हियों—बस्ता न० १
२. हवूब बर्ही, स० १८३५/१७७८ ई०—हवूब बस्ता
- ३ पान की ओसाई की बर्ही (पुन)
- ४ बीघवा
५. कागदों की बर्ही, न० २०, २१, २२ में इससे सम्बन्धित बहुत से पत्र हैं ।
- ६ कागदा की बर्ही, स० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृ० १६१-६२
- ७ बर्ही पाठा खजाना सदर, स० १८१४/१७६७ ई०, भंग्या सग्रह—बर्ही मोशवान की डीकरी, स० १८३०/१७७३ ई०

मागो के आगे समाप्त हो गया।

ये सभी उपाय राज्य व वित्तीय सनट को सुलझाः में समर्थ नहीं हो पाये। ऋण सहारा लेना तथा नये करों को लाद देना प्रशासन की पराजित मनोवृत्ति में उठाये गये कदम थे। इसमें तो वित्तीय समस्याएँ और जलज गई। ऋण के ब्याज का खर्च 'कारखाना जात' व समकक्ष पहुँच गया, जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा खर्च कहलाता था। करों में वृद्धि तो सीमित स्रोतों को सुखाने वाली सिद्ध हुई तथा राज्य की जनसंख्या पर बड़े विपरीत प्रभाव पड़े। कटौतियों का उगम एक शकीय था। जहाँ अधिनारियाँ व कर्मचारियों में घतन में कटौती हुई यहाँ राजपरिवार के निजी खर्चों में कोई कमी नहीं आई। परिणामस्वरूप राज्य में बाहर से योग्य व्यक्तियों का आना बन्द-सा हो गया। बल्कि ऐसे विवरण मिलते हैं कि राज्य के 'मुत्सददी' रोजगार के लिए बाहर जान को विवश हो गये।^१

करो का दबाव

करो में अधिक वृद्धि भी, आय के साधनों को कम करने का कारण बन गई थी। साधारणतया कर वसूली के पीछे प्रशासन का यह आशय छिपा हुआ था कि उतना ही वसूल किया जाय, ताकि उत्पादनकर्त्ता पूरे वर्ष तक तथा आगामी आपत्ति वर्ष में बचे अन्न में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।^२ राज्य में एक फसल के उत्पादन तथा अकाल व सूख की समस्या निरन्तर बन रहने के कारण उत्पादन में बच अन्न को निर्धारित करना भी कठिन था। किसी तरह की कठोरता राज्य निवासी को घर छोड़ने को विवश कर सकती थी। यद्यपि करो के सही दबाव के बारे में जानना कठिन है, क्योंकि राज्य में विभिन्न व्यवसायों में लग लोगों की पूर्ण आय की जानकारी देने में राजकीय बहिया मोन हैं। केवल नू-राजस्व कर के बारे में जानकारी मिलती है जो कि कुल उत्पादन का ४५ प्रतिशत वसूल किया जाता था।^३ 'हामल' की दर में इसके पश्चात् कोई विशेष अंतर नहीं आया था। महाराजा राजसिंह व सूरतसिंह द्वारा कुछ दरों में वृद्धि से हासिल ४६% तक पहुँच गया।^४ संभवतः यह इस कारण हुआ हो कि प्रशासन कृषि पर कर बढ़ाकर राश्वतकार व कृषि भूमि विस्तृत करने के लालच को नहीं समाप्त करना चाहता था और न ही उस अन्य व्यवसाय की

१ मैथ्या सप्तह—मैथ्या जठमल का पत्र—गोप बदि १० १८८६/१ जनवरी १८१० ई०

२ कर्णाविलस पृ० ११ (पृ०)

३ परगना रे जमा जोड रे बही (पृ०)

४ बही हासिल रे १७१७ ई० से १७६६ ई० तक—हासिल बस्ता, स० १ २ ३—बीकानेर रिकार्ड्स

और झुकाना चाहता था। छूट के कागदों में भी अधिक मुविद्या 'हासल' में ही दी गई थी। हासल की माग को स्थिर रखते हुए महाराजा गजसिंह व सूरतसिंह ने नये करों को लागू किया था जिनका दबाव निःसन्देह राज्य के निवासियों पर पड़ा होगा। महाराजा सूरजसिंह ने करों की दरों में काफी वृद्धि कर दी थी। 'रूखवाली भाछ' जो प्रति गुवाड़ी २) ६० थी, वह १०) ६० की दर से वसूल की गई। राज्य के प्रत्येक निवासी को 'पेशकसी' की रकम शासक को चुकानी पड़ी। 'घान की चौथाई' को कठोरता से वसूल किया गया।^१ कर न देने वाली के गांव 'जबती' कर लिये गये।^२ इस बढ़ि से करों का दबाव निवासियों पर कितना बढ़

रहे थे।^३ इस काल में कर वसूली भी एक टेढ़ी खीर बन गई थी। परिणाम-स्वरूप आय में वृद्धि के स्थान पर आय वसूली ही कठिन हो गई।^४ इस समय टॉड लिखता है कि करों की मक्ती से राज्य की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी।^५ विवश होकर महाराजा ने १८१६ ई० में यह घोषणा करवाई कि करों को, बढ़ती हुई दरों से वसूल नहीं किया जायेगा और न गांव जबती होंगे। नये करों में 'घोडा रेख' व 'रूखवाली भाछ' को छोड़कर शेष सभी को समाप्त कर दिया गया।^६

प्रशासनिक अव्यवस्था—१८वीं शताब्दी में विशेषकर अन्तिम धरणों में फैल रही अव्यवस्था ने भी राज्य की वित्तीय स्थिति को बहुत गिराया। इन वर्षों में हुवाला के स्थान पर मुकाता प्रणाली को बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा। साथ ही बर्मचारी भ्रष्ट उपायों से अपनी आय बढ़ाने लगे।^७ इन स्थितियों में राज्य की आय वृद्धि से लाभ नहीं पहुँचता था। अन्त में, राज्य में यह कोई आवश्यक

१. रागदा की बही, वि० सं० १८६७/१८१० ई०, न० १७, पृ० ६-११, ४६-४८, ७०-७५, ८१-८६, वि० सं० १८७१/१८१४ ई०, न० २०, पृ० ३२-३६; कागदा की बही, वि० सं० १८६६, ६७ व ७२ की बहिया में इससे सम्बन्धित अनेक पत्र हैं।

२. वही

३. कागदों की बही, वि० सं० १८७१/१८१४ ई०, न० २०, पृ० २२२-२३०; वि० सं० १८७२/१८१५ ई०, न० २१, पृ० ६६-७१, १०३-१०८, (कागदों की बही, वि० सं० १८६१, ६६, ७१ व ७२ में बहुत से पत्र इससे सम्बन्धित हैं) भैय्या सगड़ में मोहर के हुबतदार भैय्या नचमल के वि० सं० १८७१-७२ के पत्र भी इस पर प्रकाश डालते हैं।

४. वही

५. टॉड—भाग २, पृ० ११-८२-८३

६. कागदा की बही, सं० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृ० १६१-६२

७. टॉड २, पृ० ११५७-५६; मुकाता के लिए देखिये—स्पानीय प्रशासन अध्याय में मुकाता प्रणाली

नियम नहीं रह गया था कि समस्त आय की राशि खजाने में जमा की जाये और फिर खच के नये वितरित की जाये। विभिन्न करो को वसूल करते समय जो लागत खच आता था वह उसी समय पूरा कर दिया जाता था। महीनदारों व रोजीनदारों को वेतन भी दे दिया जाता था। मण्डी व थाणों के सैनिक खर्चों की पूर्ति भी हो जाती थी। बाकी बची राशि को श्री रावने में जमा कराया जाता था।^१ खतो पर व वेतन के बढ़ने जब गांव की हासन प्रदान कर दी जाती थी तो वसूल की गई वास्तविक आय की जानकारी तब मिलती थी जब कोई उनके विरुद्ध शिकायत करता था।^२ १८वीं शताब्दी के अंत में सीरबधियों का वेतन आय के विभिन्न स्रोतों से जोड़ दिया गया।^३ जब राज्य की सहायता के लिये नोहर व भादरा में सिक्खों की सना पट्टी तो उनके खच का सम्प्रदाय घोड़ा रेख व लड़वाली भाछ की आय में जोड़ दिया जिसे ठाकुरों की विशेषज्ञता स्थिति से वसूल कर पाना कठिन हो रहा था। खाणगी की समस्या को लेकर अनेक उत्पात मच।^४ इस प्रकार राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग खजाने को छुए बिना ही खच हो गया। व्यय को बिना व्यवस्थित क्रिये आय के साथ जोड़ देने से समस्याएं और भी जटिल हो गई। आय में वृद्धि के विकास की सारी सम्भावनाएं मिट गई।

- १ बही हासन की वि० सं० १८०४/१७४७ ई० वि० न० १८१०/१७५३ वि० सं० १८१४/१७५७ ई० बस्ता न० १—बीकानेर
- २ कागदों की बही वि० सं० १८२७/१७७० ई० न० ३ पृ० ४६ ४७ वि० सं० १८६७/१८१० ई० न० १६ पृ० ३३ ३७ वि० सं० १८७०/१८१३ ई० न० १६/१ पृ० १४० ४१
- ३ सीरबधी की बही वि० सं० १८१०/१७५३ ई० न० १६४ बही सीरबधी की वि० सं० १८५७/१८०० ई० बीकानेर (पुनः) कागदों की बही वि० सं० १८६८/१८११ ई० न० १ में इससे सम्बंधित बहुत से पत्र हैं।
- ४ कागदों की बही वि० सं० १८६६/१८०६ ई० न० १५ पृ० २२२ २४ भग्ना सम्प्रदाय भग्ना नयमन के पत्र गावण सुद ७ ११ वि० सं० १८७२/२० व २४ जुलाई १८०५ ई० बसाख बंद १३/४ अगस्त १८०३ ई०

खाणगी का उत्पन्न महा सैनिकों के वेतन व पेटीया (भत्ता) से है।

अध्याय ७

भू-राजस्व प्रशासन

भू-वर्गीकरण : अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, बीकानेर राज्य की रेतीली भूमि कई वर्गों में बंटी हुई थी। इनमें 'घोरा', 'मगरा', 'खारी पट्टी', 'ताल' व 'सूई', की भूमि का नाम उल्लेखनीय है।^१ शासन की भूमि-राजस्व-प्रशासन नीति के अन्तर्गत भूमि की उत्पादन क्षमता के अनुरूप, राजकीय हितों के सर्वधन के लिए, उचित वर्गीकरण लागू किया गया था।^२ इसी आधार पर राज्य के चारे व परगने भी, अपनी भूमि की उर्वर-शक्ति के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट दिये गये थे। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के चारे—नीहर व रीणी तथा परगना राजगढ़ व भटनेर, अवश्य 'सूई' भूमि की प्रधानता होने के कारण, इस प्रकार के भू-वर्गीकरण से प्रभावित नहीं थे।^३ इसके विपरीत राज्य के मध्यवर्ती दक्षिण व पश्चिम, क्षेत्र के चारों—खेखसर, गुसोईसर, जसरसर, मगरा, खारी पट्टी, पूगल और सदर की भूमि, उत्पादन क्षमता के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित की गई। श्रेणियां पुनः आगे अपनी विभिन्न श्रेणियां अथवा किस्मों में बांटी गई थी। प्रथम वर्ग में जोत की भूमि आती थी, जो 'मजरआ' के नाम से जानी जाती थी व जिसकी उत्पादन क्षमता साधारण रेगिस्तानी भूमि के स्तर की थी। 'मजरआ' में 'ताल' की भूमि उत्तम होती थी। 'मजरआ' भूमि बरमात के गानी से सीधे जाने पर 'बारानी' के नाम से पुकारी जाती थी। द्वितीय, श्रेणी की भूमि, 'पडत' व 'बजर' कहलाती थी। पडत भूमि वह थी, जो

१. घोघ—वह भूमि जो छोटे-बड़े रेतीले टीलों की है।

मगरा—ककरीसी, सख्त भूमि जो बीकानेर के दक्षिण भाग में है।

खारी पट्टी—वह भूमि जिसमें खारीय तत्व हो।

ताल—समतल व कुछ सख्त भूमि जहां पानी एकत्रित हो जाता है।

सूई—समतल भूमि जो चिकनी भी होती थी।

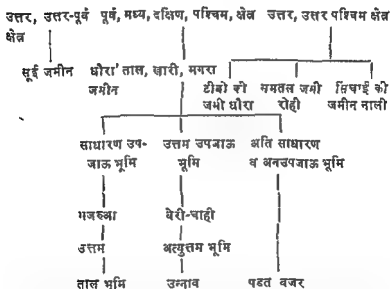
—धान रे भाग से बहो, स० १७३६/१६७९ ई०, न० ५७; फन—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, पृ० ३-४, सोबी हुकमसिंह—ज्योधाफरी माफ बीकानेर, पृ० ३-५

२. जी० एच० एल० देवड़ा—रेगिस्तानी क्षेत्र में कृषि भूमि व उसका वर्गीकरण—राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसिडिंग, १९७६

३. फेन—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, पृ० ४

साधारणतया तीन वर्षों के जोत के पश्चात् कुछ समय के लिये छोड़ दी जाती थी। वज्र भूमि अधिक वर्षा होने पर ही काम आ सकती थी। मध्यवर्ती व दक्षिणी क्षेत्र के चौरों के कुछ गांवों में एक उत्तम किस्म की भूमि भी विद्यमान थी जिसे 'बेरी', 'चाही' व 'बाडी' के नाम से पुकारा जाता था। इसे कुआँ, बावड़ियों व तालाबों के पानी से सींचा जाता था। यहाँ की भूमि में अत्युत्तम भूमि का लाभ 'उन्नाव' की भूमि में था। जहाँ वरसाती नाले का पानी आकर भर जाता था। 'बेरी' भूमि की एक और किस्म भी थी, जिसमें सामान्यतः बेर की छोटी-छोटी झाड़ियाँ उगी होती थी।^१

राज्य का क्षेत्रीय भू वर्गीकरण



कृषि भूमि के दृष्टिकोण से अनुपगढ़ चौरा, दो भागों में बंटा हुआ था। चौरा का दक्षिण भाग रेतीले टीबों से भरा था, जहाँ की भूमि एक समान थी, परन्तु, उत्तरी भाग की भूमि अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ थी। इसकी तीन किस्में थी—प्रथम, नाली की भूमि, जो उत्तम थी, जिसे पंजाब से बहकर आने वाला

१ भोग रो बड़ी, वि० सं० १७४६/१९६२ ई०, न० ६५, चौरा जसरसर बीराहद, गुप्तोई-सर रो लेख रो बड़ी, वि० सं० १७५०-५१/१९६३-६४ ई०, न० ३२, फेनन—सटलमेण्ट रिपोर्ट, बीकानेर, पृ० ३५, रजिस्टर देहात रियासत, बीकानेर, पृ० १-२०, जो० एम० एल० देवडा—रेगिस्तानी खत (बीकानेर राज्य) में कृषि योग्य-भूमि व उसका वर्गीकरण, राजस्थान हिस्ट्री कावेस, १९७६

बाढ़ का पानी सींचता था, द्वितीय, रोही' की भूमि, जो 'सूई' व जोत योग्य थी, तथा तृतीय, घोरो व टीबो की भूमि, जहाँ की उपज साधारण थी।^१

उत्पादन क्षमता के आधार पर प्रत्येक श्रेणी की भूमि पर अलग अलग दरो से लगान वसूल किया जाता था। उदाहरणतः, बजर' से मजदूरा' का लगान मामूली मा अधिक होता था, लेकिन 'नाली' 'उन्नाव व चाही' भूमि पर लगान की दर मजदूरा से दोगुनी थी।^२ भौगोलिक दृष्टि से, इस क्षेत्र की भूमि अधिकांश पठार' की भूमि थी। रेतीली अनुपजाऊ जमीन, सिंचाई के साधनों का अभाव, पीने के पानी की कमी, खाद्य फसलों का अधिक महत्त्व, प्राकृतिक विपदाओं की मात्र तथा जनसंख्या की कमी के कारण राज्य में कृषि के काम आने वाली भूमि अत्यन्त सीमित थी। बजर भूमि के साथ साथ जोत योग्य भूमि भी बिना जोत के रहती थी। यहाँ के निवासियों के सम्मुख, जोतने योग्य भूमि की उपरता को लेकर जोत के लिए प्राथमिकता का प्रश्न था।^३ भूमि की स्थिति को ध्यान में रख कर ही राज्य में बस्तियाँ बसी थी। जब कि अधिक उपजाऊ होने के कारण राज्य का उत्तर पूर्वी भाग अधिक घना बसा हुआ था। जबकि मध्य व दक्षिणी भाग छितरा हुआ बसा हुआ था तथा पश्चिमी भाग बहुत ही कम आबाद था।^४ अतएव चौरा व परगना में जोत योग्य भूमि में, जोती जाने वाली भूमि का अनुपात अलग-अलग था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ५० प्रतिशत से अधिक जोत योग्य कृषि भूमि होने के बाद भी, जोती जाने वाली भूमि राज्य में एवं तिहाई में भी कम थी।^५

१ अनुपपड़ या छत व गांव रो बहा, वि० सं० १७५०/१९६३ न० ६८, अनौपपुरे हासल रो बही, वि० सं० १८०४/१७४७ ई०, न० २५, फन—सेटलमेंट रिपोर्ट बीकानेर पृ० ४५

२ राज्य में प्रति हज़ार जा लगान वसूल किया जाता था, उससे यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। बजर भूमि में प्रति हज़ार २ ६०, मजदूरा में प्रति हज़ार ३ ६० तथा चाही व बरी भूमि में ४ ६० व ५ ६० तक वसूल होता था।

—बही घालसे रो वि० सं० १८१२/१७५५ ई०, बस्ता न० १

३ जी० एस० एन० दबडा—रेगिस्तानी खज (बीकानेर राज्य) में कृषि योग्य भूमि व उसका वर्गीकरण राजस्थान हिस्ट्री कांसस कोटा १९७९

४ राज्य में अधिकतर गांव उहीं चौरों में स्थित थे जहाँ कि भूमि घनत्व व कृषि योग्य थी। पने रेतीले चौरों में आबादी कम बसी हुई थी। उत्तर-पूर्व खज के चोरे व परगने मोहूर, रोनी व राजपड़ में जहाँ क्रमशः १२४ १२६ व १३७ गांव थे जहाँ महाजन, खन्डा व पुगल में क्रमशः ६६ २५ व ३० गांव थे।

—हवुव बही, वि० सं० १८१०/१७५३ ई० बस्ता न० १ भँव्या सपट्ट—भँव्या देईदान के पत्र उदाहरणार्थ माप मुदि ६, १८७७/१० फरवरी १८२१ ई०, पाउनेट पृ० ८६ (पूर्व)

५ सेटलमेंट रिपोर्ट में राज्य की औसत जाती जाने वाली भूमि १३ प्रतिशत बाँकी गयी है। फन से परगना भटनेर में यह ३२ प्रतिशत थी तथा चौरा अनुपपड़ में ३ प्रतिशत थी।—फन—सेटलमेंट रिपोर्ट, बीकानेर, पृ० ६३

कागदों की बहियों के 'लिप्यत' व 'सनद' के 'कागद' राज्य में काश्तकारों के भू-स्वत्व अधिकारों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राज्य-प्रशासन जिस काश्तकार को 'मोहरछाप लिखत कागद' या पट्टा प्रदान करता था, वह उसमें उल्लिखित भूमि पर जोतने के वशानुगत निजी अधिकारों का प्रयोग कर सकता था।^१ केवल राज्य की नीतियों का पालन न करने पर अथवा राज्य-अपराधी घोषित होने पर ही उसे इन अधिकारों से वंचित किया जाता था।^२ अन्यथा प्रशासन उसके अधिकारों पर होने वाले प्रत्येक हस्तक्षेप से उसे बचाता था।^३ काश्तकार या 'आसामी' के संतान न होने पर उसकी पत्नी और उसके पश्चात् निकटवर्ती सम्बन्धी उस भूमि को जोतने के अधिकार पाते थे।^४ मृतक 'आसामी' की पत्नी द्वारा पुनर्विवाह करने पर उसके पूर्व पति की भूमि पर समस्त अधिकार समाप्त हो जाते थे तथा वह भूमि मृतक व्यक्ति के निष्ठ के सम्बन्धियों के अधिकार में चली जाती थी।^५ इस सब कार्यवाही में गाव के चौधरी व पचायत की भूमिका निर्णायक होती थी तथा वे ही भूमि के नये दावेदारों को चुनकर मान्यता प्राप्त करवाते थे।^६ अगर कोई 'आसामी' किसी विपत्ति के मारे अपना छेत व घर छोड़कर बाहर चला जाता था, तब भी उसके भू-स्वत्व अधिकार समाप्त नहीं होते थे। पाँच-दस वर्ष पश्चात् उसके लौटने पर उसे अपने अधिकार वैसे ही प्राप्त हो जाते थे।^७ ऐसे भी विवरण आये हैं कि ४० वर्ष पश्चात् लौटने पर भी राज्य ने उसके पुराने अधिकारों को दिलाने में सहायता पहुँचाई थी।^८ साधारण-तया एक काश्तकार की लम्बी अवधि की अनुपस्थिति में गाव का या बाहर का कोई काश्तकार गाव के चौधरी की अनुमति से उस भूमि को जोतने लगता था तथा वास्तविक स्वामी के आने पर उसे छोड़ देता था।^९ अगर ३० ॥

एक अविश्वसनीय लम्बी अवधि के पश्चात् गाव लौटता था ।

१ कागदों की बहियाँ—सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३

१८०० ई०, न० ११, पृ० २१६

२ उपर्युक्त—सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ०

३ उपर्युक्त—पृ० ४५

४ उपर्युक्त—न० ३, कागद माघ बदि ७, १८२१

५ उपर्युक्त—न० ६, कागद सावन सुदि १२, १

६ उपर्युक्त

७ उपर्युक्त—सं० १८२७/१८०० ई०, न० ११, पृ० ८१

८ उपर्युक्त—१८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ०

९ उपर्युक्त—सं० १८७४/१८१७ ई०, न० १

उसकी भूमि पर किसी अन्य के भू-स्वत्व अधिकार विकसित हो गये हैं तो वह राज्य द्वारा उसी माप की दूसरी भूमि प्राप्त करता था।^१

काश्तकार (भासामी) अपना खेत किसी अन्य को जोतने के लिये किराये पर दे सकता था, ऋण के बदले रेहन पर चढ़ा सकता था तथा आवश्यकता पड़ने पर बेच भी सकता था।^२ भूमि बेचने के अधिक विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं; मभवतः इसका कारण बिना जोत के अधिक भूमि का पड़ा रहना है। यहाँ यह उल्लेखनीय बात यह है कि गांव के पट्टा या खालसा किसी में भी बदलने पर 'भासामी' के भू-स्वत्व अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता था।^३

जहाँ तक किसी 'भासामी' के अपनी जोत की भूमि पर अधिकारों का प्रश्न है, स्थिति काफी स्पष्ट थी, लेकिन उसके ये अधिकार और वहाँ तक विस्तृत थे, इनके लिये भू-अधिकारों के स्थानान्तरण के ऐतिहासिक घम को जानना आवश्यक है। साधारणतया राठौड़ राज्य के गांव स्वतन्त्र कृषक परिवारों के निजी खेतों व घरों से निर्मित थे तथा उनके अलग-अलग भूमि अधिकार स्पष्टतया विभाजित थे तथा किसी एक का दूसरे के अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। पर वे गांव जो राठौड़ आक्रमण से पूर्व के बसे हुए थे तथा जहाँ पर पूर्व 'भोमियो' व 'प्रासियो' के परिवार का अधिकार रहा था; स्थिति कुछ विभिन्न थी। राठौड़ शासकों ने इन गांवों में पुराने भोमियो व प्रासियों के परिवार या 'विरादरी' के उच्च भू-अधिकारों को स्वीकार करके प्राचीन समाज में उन्हें विनिश्चित स्थिति प्रदान कर दी थी। वास्तव में उनके ऐतिहासिक दावों को मान्यता प्रदान करके राजनैतिक समझौता किया गया था। इसी 'विरादरी' का भुगिया हो गांव का चौधरी बनता था।^४ राज्य पक्षों में स्पष्टतया उल्लिखित होता था कि "गांव खालसा का है व जमीन जाटों की है।"^५ इन गांवों में जो अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि होती थी उस जोतने का सर्वप्रथम अधिकार 'विरादरी' के सदस्यों को होता था। उनके न जोतने पर

१ उपर्युक्त १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० १४४, २०१

२ कागदों की बही—न० ३, कागद संग्रह बंदि २, १८२०/३१ मार्च, १७६३ ई०, कालिक मुदि १५, १८२०/२० नवम्बर, १७६३ ई०, आश्विन मुदि ७, १८२७/२९ सितम्बर, १७७० ई०, न० ३, ज्येष्ठ मुदि ४, स० १८५७/१ जून, १८०० ई० न० ११, ज्येष्ठ बंदि ११, १८५८/२६ मई, १८०२ ई०, न० १२

३ उपर्युक्त—स० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० २१६

४ जी० एम० एन० देवड़ा—सौविशो इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, पृ० ८४

५ कागदों की बही—न० १६, पृ० ३१, कागद संग्रह मुदि १२, स० १८६७/१२ अगस्त, १८१० ई०

उनकी स्वीकृति पाकर अन्य कोई जोत सकता था।^१ उनके परिवार के अतिरिक्त गाव के सभी काश्तकार इन्हे 'मलबा' नाम का कर चुकाते थे,^२ जिसमें गाव का ठाकुर भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।^३ गाव की 'पटत' की भूमि पर भी इनके विशेषाधिकार मुरक्षित रहते थे।^४ ये लोग गाव में पुनर्नय की जमीन भी प्रदान कर सकते थे, जिसे राजा या ठाकुर भी चुनौती नहीं दे सकता था।^५ राटोड आक्रमण के बाद वैसे गाव में इस प्रकार के उच्च भू-अधिकारों से सम्पन्न वर्ग का अभाव था। वैसे १८वीं शताब्दी में राज्य ने अवश्य बस्तिया बढ़ाने में प्रोत्साहन देने के लिये नये 'चौधरी' व 'जमींदार' को भी 'मलबा' वसूल करने का अधिकार प्रदान कर दिया था।^६

राज्य उन काश्तकारों के अधिकारों को भी मरक्षण प्रदान करता था जो किराये पर किसी अन्य का खेत जोतते थे। ये साधारणतया 'मुकाती' कहलाते थे।^७ गाव में बाहर से आये कृषकों को भी जो 'नवा' कहलाते थे, पहले 'मुकाते' पर खेत दिया जाता था।^८ भू-स्वामी व किरायेदार के बीच तीन साल का समझौता विद्यमान था। उसको बीच में भंग करने का अधिकार किसी भी पक्ष को प्राप्त नहीं था।^९ जो काश्तकार किसी अन्य के खेत को जोतने योग्य बना लेता था, उसे उस पर तीन वर्ष तक कृषि करने का अधिकार मिल जाता था।^{१०} बदले में वह भू-स्वामी को 'मुकाता' व 'मलबा' चुकाता था। 'मलबा' या 'मुकाता' न चुकाने पर किरायेदार को हटाया जा सकता था।^{११} राज्य में ऐसे विवरण भी प्राप्त हुए हैं जबकि ३० वर्ष तक भूमि को किराये पर जोता गया था।^{१२}

काश्तकार राज्य हित में ही अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकते

१ उपर्युक्त—सं० १८११/१७७४ ई०, न० ४, पृ० १९

२ उपर्युक्त

३ उपर्युक्त

४ कागदों की वही, सं० १८१७/१८०० ई०, न० ११, पृ० २१०

५ उपर्युक्त—सं० १८१७/१८०० ई०, न० ११, पृ० ४७, सं० १८७४/१८१७ ई०, न० २१, पृ० ३०

६ उपर्युक्त—सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ४०, सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृ० ४३

७ उपर्युक्त—सं० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृ० ७५

८ उपर्युक्त—सं० १८३१/१८७४ ई०, न० ४, पृ० २२

९ उपर्युक्त—सं० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृ० ७३

१० उपर्युक्त

११ उपर्युक्त

१२ उपर्युक्त—न० ३, कागद अश्विन सुदि ७, १८२७/२६ सितम्बर, १७७० ई०

ये। उन पर राज्य-प्रशासन ने अपने हितों की पूर्ति हेतु कुछ नियन्त्रण लगा दिये थे। एक 'आसामी' अपने भू-स्वत्व अधिकारों का प्रयोग तभी तक कर सकता था, जब तक वह खेत जोतता रहे तथा राज्य को निर्धारित कर चुकाता रहे। अन्यथा उसका खेत 'अव्यत' किया जा सकता था।^१ इस प्रकार प्रत्येक कृषक को, अपने अधिकार बनाये रखने के लिये राज्य-नीतियों का पालन करना आवश्यक था।

गांव की पड़त व चरागाह भूमि पर राजा का अधिकार होता था। उसका प्रयोग करने पर राज्य को निर्धारित कर चुकाने पड़ते थे।^२ राज्य व चौधरी की स्वीकृति के पश्चात् ही पड़त की भूमि को जोतने व योग्य किया जा सकता था।^३ गांव चौधरी इन सब स्थानों पर राजा के हितों की देखभाल करता था।

ग्रामीण समाज

राज्य के अधिकांश गांव किसी विशेष जाति या उपजाति से आबाद थे। यद्यपि उस गांव में अन्य जातियां भी निवास करती थी; तथापि गांव अपनी निवास करने वाली प्रमुख जाति या उपजाति से ही जाना जाता था, जैसे सारणों का गांव, पूनीयों का गांव, पलीवालियों का गांव, चारणों का गांव इत्यादि^४। अगर गांव बराबर की संख्या की कई जातियों या उपजातियों से सभ जाता था तो वह अनेक 'वास' (मोहस्तो) में विभक्त हो जाता था।^५ प्रत्येक गांव के निवासी अपने भू-स्वत्व अधिकारों, राज्य के प्रति दायित्वों व सम्बन्धों तथा जाति विशेष को लेकर कई भागों में विभक्त हो जाते थे। राज्य प्रशासन भी जब किसी गांव के निवासियों को सम्बोधित करता था इन्हीं श्रेणियों को मस्तिष्क में रखता था।^६ मुख्य रूप से गांव के समाज को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो न केवल इस क्षेत्र के ऐतिहासिक नाम को प्रदर्शित करते हैं बल्कि ग्रामीण समाज में उनकी स्थिति तथा राज्य के साथ सम्बन्धों को भी स्पष्ट करते हैं।

प्रथम वर्ग अपने उच्च भूमि-अधिकारों अथवा विशेष अधिकारों को लेकर

१. उपर्युक्त—सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ४४; सं० १८७२/१८१५ ई०, न० १५, पृ० १३०—३५

२. उपर्युक्त—सं० १८२७/१८०० ई०, न० ११, पृ० २१५, ज्येष्ठ बदि ११, सं० १८२६/२७ मई, १८०२

३. उपर्युक्त

४. फुटकर गांव रे हासन रो बही—सं० १७४८/१६६१ ई०, न०, ५१, बीकानेर बदिमात

५. उपर्युक्त

६. कागदों की बही—सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ३, पृ० ३१

निर्मित होता था। इसमें गांव के चौधरी, पुराने भोभीया व घासिया के परिवार तथा जमींदार व उनके बिरादरी के लोग सम्मिलित होते थे।^१ राज्य प्रशासन भी जब कोई आदेश-पत्र गांववासियों को भजता था तो सबसे पहले इसी वर्ग को सम्बोधित करता था।^२ गांव में प्रशासनिक दायित्वों के कारण भी इस वर्ग की विभिन्न स्थिति उभरी थी। साधारणतया ये चौधरिया व नाम \square बड़े जाते थे।^३ जंगल लिखा जा चुका है, राठोड आक्रमण से पूर्व बस गांव के चौधरियों व उनके परिवार वालों के गांव की भूमि पर विशेष अधिकार माने जाते थे। इनकी छूटकाश्ट भूमि पर या तो घर बसूल नहीं किया जाता था अथवा रियायती दरा पर प्राप्त किया जाता था। ऐसी ही करो म मुविद्या दूसरे चौधरियों व 'जमींदारों' को भी प्राप्त थी। इनका अपनी प्रशासनिक सहायों के बदले लगान में पचोतरा प्राप्त होता था। गांव की पड़त व चरागाह भूमि पर इनके परिवारों को विशेष मुविधायें प्राप्त होती थी। कई स्थानों पर तो चरागाह भूमि का प्रयोग करने पर कोई घर बसूल नहीं किया जाता था। मलबा नाम का कर दूसरे काश्टकारों से वसूल करने से भी ग्रामीण समाज में इनकी विशेष व उच्च स्थिति का भान होता है।^४

द्वितीय वर्ग 'आसामीयो' का था जो अपने भू स्वत्व अधिकारों तथा चाति विशेष को लेकर फिर अनेक श्रेणियों में विभक्त थे। केवल भू स्वत्व अधिकारों तथा आर्थिक स्थिति पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के वे 'आसामी' थे जो स्वयम् काश्ट करते थे और कुछ भूमि को मलबा व मुवाते के बदले दूसरों को काश्ट करने के लिये उठा देते थे। द्वितीय प्रकार के वे 'आसामी' थे, जो स्वयम् तो बहुत कम काश्ट करते थे, लेकिन अधिकांश भूमि को मलबा व मुकाता पर दूसरों को काश्ट के लिये दे देते थे। तृतीय 'आसामी' वे थे जिनके पास स्वयम् काश्ट करने के लिये भूमि बहुत कम होती थी, वे दूसरों की भूमि पर 'मलबा' व 'मुकाता' दकर काश्ट करते थे। इन सभी 'आसामीयान्' को राज्य प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी करो को चुकाना पड़ता था। इस वर्ग में आने वाले अधिकांश लोग काश्टकार जातियों—जाट विष्णोई व माली इत्यादि थे, जिन पर करो का पूरा बोझ था। इन 'आसामीयो' में एक वर्ग रियायती

१ गाँवाँ के भोग व कुठा री बहो, स० १७४०/१६८३ ई०, न० २०७, बीकानेर बहियाण, मेवाड़—तवारिख रियासत बीकानेर—पृ० ३४, सोहनवाल—तवारिख राजभी बीकानेर—पृ० २३३ ३६

२ बागदा की बहो—स० १८३१/१७७४ ई०, न० ३, पृ० ३१

उपयुक्त

विशेष अध्ययन के लिये स्थानीय प्रशासन का अध्याय देखिये।

भू-राजस्व प्रशासन

अवश्य था, जो 'पसाइती' कहलाता था तथा सदैव के लिये कम दरो पर निर्धारित लगान को चुकाता था।

इन 'आसामीयान्' के अतिरिक्त जातीय आधार पर विभक्त एक और वर्ग भी था, जिनके भू-स्वत्व अधिकार सुरक्षित थे तथा कम दरो पर राज्य को लगान चुकाते थे। इस 'आसामी' वर्ग में ब्राह्मण, साहवार, राजपूत जाति के लोग सम्मिलित थे। इन्हें कई बार मुकाती भी कहा जाता था, क्योंकि ये राज्य को समस्त करो के स्थान पर एक रियायती दर वा निश्चित लगान दे देते थे। इस प्रकार 'आसामीयो' के इस वर्ग पर करो वा कम बोझ था। वे जातिवा, जो काश्त के साथ-साथ अन्य व्यवसायों में भी जुटी होती थी, जैसे सुधार, सुतार, तैली, लुहार आदि, ये सभी अपने भू-स्वत्व अधिकारों के साथ कम दर का लगान चुकाती थी। ये 'चाकरी आसामीयान्' कहलाते थे। अपनी निर्धारित लगान-व्यवस्था के कारण ये मुकाती व बोलीयार भी कहलाते थे। 'चाकरी' 'आसामीयान्' में वे लोग भी सम्मिलित थे जो राज्य को सैनिक सेवा प्रदान करते थे। इन 'आसामीयान्' से थोड़ी कर वसूल नहीं किया जाता था। राजपूतों में बीका राजपूत, जिनका राजवज से खन वा सम्बन्ध था तथा चारण जाति के लोग विशेष सरक्षण के कारण अपने भू-स्वत्व अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए किसी प्रकार का लगान नहीं चुकाते थे। इन 'आसामीयान्' के अधिकारों को 'कब्जा अवतान' कहा जाता था। चारणों की छूट वा चारण उनका बीकानेर राज्य की कुलदेवी करणी माता की जाति से सम्बन्धित होना था।

तृतीय वर्ग, 'रैत' अर्थात् रैयत वा था, जो निम्न वर्ग के थे तथा अधिकांश दूसरों की भूमि पर वास्तव करते थे। कृषि व्यवसाय में श्रमियों की पूर्ति इसी वर्ग से होती थी। ये गौधरियों तथा 'आसामीयो' के खेतों पर काम करते थे। इनके पास जो भूमि होती थी उस पर यह अवश्य एक आसामी की भांति अधिकारों का प्रयोग करते थे। पर उस भूमि का क्षेत्रफल कम होता था। गांव

१. विशेष अध्ययन के लिए स्थानीय प्रशासन का अध्याय देखिये।

- २ फुटनर गावा रे हागल रो बही, सं० १७४८/१६६१ ई०, न० ५१
- ३ बही हागल रे लेखे रो, सं० १७४८/१६०१ ई०, न० ७, उदाहरणार्थ छेददा गांव का हागल देखिये, बायदो की बही, सं० १८७१, न० २०, पृ० ४६
- ४ बही हागल रे लेखे रो, सं० १७४८/१६६१ ई०, गांवों के हागल में मुकाती व बोलीयार की सूची देखिये।
- ५ बायदो की बही, न० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० ३, न १२ बायद वेशाय मुदि ६, १८४६/८ ई०, १८०२ ई०
- ६ मोहनसाल—उत्तारिख राजकी बीकानेर, पृ० २३३-६६
- ७ बही

ठाकुर व चौधरी इन्हें गांव की सेवा करने के बदले भी जीविका हेतु भूमि प्रदान करते थे, जिन पर उनका अधिकार 'कब्जा कमीनान' के नाम से जाना जाता था।^१ इनकी भूमि पर भी कम दर से लगान बसूल होता था तथा अपनी भू-राजस्व बसूली प्रणाली के नाम से ये 'मुकाती' व 'बोलीयार' भी कहलाते थे।^२ कई बार व्यावसायिक जातियो जैसे सुथार, लुहार व तेली के भू-अधिकारों को भी 'कब्जा कमीनान' में सम्मिलित कर लिया जाता था।^३

ग्रामीण समाज में अनुदान भूमि का काम उठाने वालों के वर्ग का भी विविष्ट सामाजिक महत्व था। राज-दरबार, पट्टायत व गांव के चौधरी द्वारा ब्राह्मणों, वैरागियों, विभिन्न सम्प्रदायों के साधुओं तथा गाने-बजाने वाले भाट व मिरासियों को जो अनुदान भूमि प्रदान की जाती थी, उसे 'डोहोली' कहा जाता था।^४ राज्य में 'डोहोली' प्राप्त करने वालों में ब्राह्मण मुख्य थे, जो गांव में धार्मिक व सामाजिक कार्यों को सम्पन्न कराने के बदले यह अनुदान प्राप्त करते थे।^५ इस पुनश्च की भूमि पर भी वशानुगत अधिकारों का प्रयोग किया जाता था। केवल पट्टायत द्वारा प्रदत्त 'डोहोली' को नया पट्टायत छीन सकता था।^६ 'डोहोली' की भूमि को किराये पर उठाया जा सकता था, रहन पर धवाया जा सकता था, पर उसे बेचा नहीं जा सकता था।^७

गांव में बाहर से आकर बसने वालों को नया कहा जाता था। गांव का 'पट्टायत' व चौधरी इन्हे बसने के लिये सुविधाएं प्रदान करता था। वे 'मलवा' व 'मुकाता' देने के बदले कृषि करते थे। धीरे-धीरे नई भूमि पर इनके अधिकार स्थापित हो जाते थे व राज्य द्वारा भाग्यता मिलने के बाद ये 'आसामी' कहलाने लगते थे।^८

मुख्य फसलें

राज्य के रेगिस्तानी वातावरण के कारण, अधिकांश भाग में एक ही

१. गाबा रे रकम वसूली की बही, स० १७१६/१९६६ ई०, न० ६४; बही जालसा रे गाबा की—स० १७६१/१७०४ ई०, न० १०१ बीकानेर बहियात
२. बही हावल री लेखे री, स० १७४८/१९६१ ई०, न० ७—देवियेसूखी मुकाती व बोलीयारकी
३. सोहनलाल—तयारिख राजधो बीकानेर, पृ० २३३-३५
४. नागदो की बही—न० १, फरगुल बदि ६, १८११/२ फरवरी १७१५ ई०; न० ११, वैशाख बदि ३, १८१७/१३ अप्रैल, १८०० ई०
५. परवाना बही—स० १८००/१७४३ ई०; पृ० २३२-३५, सैय्या सख्—नागद १८६७/१८२० ई० व
६. नागदो की बही—स० १८१७/१८०० ई०, न० ११ पृ० ४७
७. बही—स० १८११/१७१४ ई०, न० १, पृ० ६०-६२; स० १८२७/१७७० ई०, न० १३, पृ० ४१
८. बही—स० १८३१/१७७४ ई०, पृ० २२

फसल—खरीफ होती थी और यह भी पूर्णतया वर्षा पर आधारित थी। राज्य के मध्य व पश्चिमी क्षेत्र एवं ही फसल के भाग थे।^१ खरीफ फसल भी मुख्यतः धान फसल ही थी, जिस यहाँ 'धान' कहा जाता था। इसमें मुख्य फसल बाजरा की थी तत्पश्चात् मोठ का महत्त्व था।^२ अन्य फसलों में ग्वार, ज्वार व मूँग थे, जो राज्य के प्रत्येक भाग में बोये जाते थे। मूँग अवश्य रीणी, पूनीया व सुदहा चीरा में पम बोयी जाती थी जबकि ज्वार परगना भटनेर में सबसे अधिक बोयी जाती थी।^३

राज्य के उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र के चीरा व परगनों के सीमित क्षेत्र में अवश्य ही फसलों की लेनी होती थी। रबी की फसल के लिये समतल भूमि व अच्छी वर्षा का

थी।^४ राज्य में

से सिंचाई की व्यवस्था थी, रबी की फसल बोई जाती थी।^५ रबी की मुख्य फसलों में गेहूँ, जौ, चना व सरसो मुख्य थे। रबी की फसल का सबसे अधिक उत्पादन परगना भटनेर में होता था।^६ वैसे रबी की फसल बहुत कम मात्रा में बोई जाती थी। १७वीं शताब्दी के अन्तिम दशक के उपलब्ध विस्तृत आकड़ों से विदित होता है कि राज्य के उत्तरी-पूर्वी चीरो—रीणी, नोहर व गधोली में रबी की फसल का कुल उत्पादन उस समय की कुल खरीफ फसल के उत्पादन की तुलना में मात्र नमूना ०.०६%, ०.२६%, ०.२६% था। परगना भटनेर में यह अवश्य २६.५५ प्रतिशत था। इसका वाद चीरा मगरा ने ६ गांव में जहाँ रबी की फसल होती थी, वहाँ यह २६.०० प्रतिशत था।^७

व्यापारिक फसलें भी यहाँ अनउपजाऊ भूमि व सिंचाई के साधनों के अभाव में कम बोई जाती थी। केवल समतल व चिकनी भूमि में कपास व तिल बोया जाता था।^८ १६६० से १७०० ई० के बीच के उपलब्ध आकड़ों से ज्ञात होता है

१ क्रोप पैटर्न एण्ड फसल सेटलमेण्ट इन नोर्थ वेस्ट राजस्थान—श्रीधर, राजस्थान हेल्थर, सेमिगार, जयपुर, १९७८

२ फगन—पृ० ३-६

३ वही हासल दे लेखे री, सं० १७६८/१६४१ ई०, न० ७, वही परगनारी, सं० १७४६ ४७/१६६२-१७०० ई०, न० १—बोकानेर बहियात

४ फगन—पृ० ३-६

५ वही हासल दे लेखे री, सं० १७४८/१६६१, न० ७

६ वही हासल दे लेखे री सं० १७४८/१६६१ ई०, वही परगना री, सं० १७४६-४७/१६६२-१७०० ई०

७ वही

८ फगन—पृ० ३-६

कि खरीफ फसल में व्यापारिक फसलें ग्राह्य फसल की तुलना में २ प्रतिशत से भी कम उत्पादित होती थी।^१ चौरा मगरा के तालाबों से मिर्चाई क्षेत्र में गांवा में कपास की खेती अधिक होने से अवश्य इसकी स्थिति सम्मानजनक थी। इन दस वर्षों में हुए कुल उत्पादन में कपास का उत्पादन ८२ ७० प्रतिशत था।^२ जो बिरेगिस्तानी वातावरण तथा आज के समय में दस फसल की मात्रा में आश्चर्यजनकता लगता है। खैर, साधारणतया व्यापारिक फसल की महत्वहीन स्थिति के कारण इस क्षेत्र में एक बृहद् व्यापारिक आधार नहीं तैयार हो सका।

कृषि-पद्धति

मिर्चाई के साधनों में अभाव में रतीली भूमि की कृषि-पद्धति अत्यंत सरल थी। यहां की हल्की रतीली भूमि में खरीफ फसल के समय केवल एक ही हल की जोत काफी होती थी। उसी से जमीन पोली हो जाती थी और उसी समय बीज भी बो दिया जाता था। जोत पर लगाया गया भ्रम यहां इतना कम था कि एक ऊट पांच बीघा भूमि को १५ दिन में बाह^३ सकता था। दो 'हलो' का प्रयोग कुछ सघन भूमि के लिए किया जाता था, जिसमें एक दिशा में चलाया हुआ पहला हल जमीन को पोली करने के लिए चलाया जाता था व दूसरा हल बीज डालने के लिए। इसमें अधिक उत्पादन होता था व प्रशासन भी 'दोलहड़' हल के नाम पर अधिक लगान वसूल करता था।^४ काश्तकार तब तक खेत को जोतता रहता था, जब तक कि उसकी उर्वर शक्ति समाप्त नहीं हो जाती थी। ऐसा होने पर वह नयी भूमि को 'तोड़ता' था। इसी कारण राज्य में काश्तकार के पास बचर व पड़त की भूमि अधिक होती थी।^५ रबी के लिए उपयुक्त 'सूई' व चिकनी भूमि में, उत्पादन के लिए, तीन हलो की आवश्यकता होती थी। पहले हल से भूमि समतल की जाती थी, द्वितीय से भूमि पोनी की

१ यही हासल है लेख रो, सं० १७४८/१९६१ ई०, बही परपना रो सं० १७४६ ५७/१९६२-१७०० ई०

२ यही

३ बाहना, फगन—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, पृ० ७

४ परवाना यही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० २३२ कागदों की बही, वि० सं० १८३१/१७५४ ई० नं० ४ पृ० ३९, वि० सं० १८३८/१७८१ ई०, नं० ५, पृ० ५४ इकलिये (एक) हल पर तीन रुपये तथा दोलहड़े (दो) हलो पर चार रुपये लगते थे।—कागदों की बही वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, नं० २, पृ० ३६

५ फगन—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, बीकानेर, पृ० ६, एग्जीक्यूटिव एम्पाइसमेंट एम्प्लायड इन वेस्टन राजस्थान—जी० एस० एस० देवडा, शोधपत्र—हिस्ट्री ऑफ इण्डियन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी सेमिनार प्रसंगा, दिल्ली, फरवरी, १९८०

जाती व तृतीय में जाकर बीज बोया जाता था। रबी की फसल में 'भूमि को 'उमरा' कहा जाता था।^१ काश्तकार खरीफ व रबी दोनों फसलों के समय जोतते वक्त इस बात का अवश्य ध्यान रखता था कि प्रति वर्ष हल की दिशा बदल दी जाये।^२ परगना भटनेर तथा चीरा ममरा में नालो व तालाबों के पानी से सिंचाई की व्यवस्था जुटाई जाती थी।^३

हासल निर्धारण के नियम व विधि

भू-राजस्व, जिसे 'हासल' कहा जाता था। 'भोग' (कृषि कर) तथा 'रोकड' (अग्न्य कर) से मिलकर बनता था। खालसा भूमि में वसूल की जाने वाली हासल की पूरी रकम राज्य खजाने में जमा होती थी। पट्ट व 'सासन' के क्षेत्र का 'भोग' पट्टायत व 'आसामी' के पास चला जाता था। 'रोकड' की रकमों में कर, कुछ शासक को व कुछ पट्टायतो को प्राप्त होते थे। मुख्य रूप से भूमि के स्वरूप, फसल की विशेषता तथा काश्तकार की जाति को ध्यान में रखकर हासल का निर्धारण किया जाता था। हासल की दर के निर्धारण का कोई एक नियम नहीं था। राज्य हासल में निर्धारण की कई पद्धतियाँ विद्यमान थी; वल्कि एक गाँव में सभी प्रचलित प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं। ये प्रणालियाँ गाँव में सामूहिक रूप में भी लागू की जाती थी तथा इनके अनुसार प्रत्येक काश्तकार से लगान, अलग-अलग भी तय किया जाता था। राज्य जब गाँव में लगान हेतु आदेश पत्र भेजता था तो विभिन्न प्रणालियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रणाली के नाम से सम्बन्धित करता था। उदाहरणार्थ, 'पसाइती', 'मुकाती', 'बोलिया', 'हाली' आदि।^४

राज्य में विभिन्न भू-राजस्व निर्धारण पद्धतियों का विकास भी राज्य की शक्ति के उत्थान के साथ श्रमशः उसी प्रकार हुआ था। सर्वप्रथम राजा का नियन्त्रण केवल खालसा भूमि तक ही सीमित था। वहाँ भी वे पुराने ग्रामीणों व 'भोमियो' से एक बड़ी रकम ही लगान के रूप में ले पाते थे तथा वह बंझी रकम 'भोमोये' व 'ग्रासीये' अपने गाँव में जोत के आधार पर वितरित करके वसूल करते थे। शनैः-शनैः राजा के कामदारों ने खालसा गाँवों में जाकर भूमि का निरीक्षण करके लगान निर्धारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रशासन का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राजा रायसिंह के काल से प्रारम्भ होता है। उन्होंने हलो पर भी एक निर्धारित कर लागू कर दिया था। महाराजा अनूपसिंह ने हासल के साथ-

१. पेंगन—सेटलमेण्ट रिपोर्ट, बीकानेर, पृ० ६.

२. वही, पृ० ६

३. वही, पृ० ६

४. कागसों की बहो, पं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ३१

साथ 'भाछ' को भी लागू किया। व १८वीं सताब्दी के प्रारम्भ तक तो विभिन्न प्रणालियों विद्यमान हो गई थी; जिनका परिणाम यह निकला कि प्रशासन का भूमि संप्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया, मध्यस्था की स्थिति कमजोर पड़ी लेकिन दृष्टियों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ गया।

कृता—राज्य में 'कृता' प्रणाली का प्रचलन सबसे पूर्व हुआ। जब म प्रशासन का दृष्टि के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया तब म इस प्रणाली का प्रयोग किया गया। दूसरे अनुसार हासन या 'भोग' (मास) का निर्धारण राज्य का 'कामदार' या 'हुजदार' एक अन्य अधिकारी 'सहाया' की सहायता स गन्धी फगल के उत्पादन को आँकता था 'कृता' या तथा कुल उत्पादन को निर्धारित करता था। कृता में पिछले वर्ष के आँकड़ों से भी सहायता ली जाती थी। कृता में वास्तविक की बात को भी गुना जाता था तथा उसके विश्राम न जमन पर यह राज्य व दीवान व राजा को अपनी शिकायत भी पहुँचा सकता था। 'कृता' समय काश्तकार की आर्थिक अवस्था पर भी विचार किया जाता था। कुल उत्पादन निर्धारण होने के पश्चात् 'भोग' राज्य सगान के रूप में उसके ७, ८, ९वें हिस्स के रूप में बगुन कर लिया जाता था। १७वीं सताब्दी के अन्त तक यह भाग साधारणतया कुल उत्पादन के १/५ या १/६ के रूप में वसूल होने लगा। कुछ दृष्टियों में 'तिहानिया' व 'नौथाई' अर्थात् १/३ व १/४ रूप में वसूल किया जाता था, यह उत्तरी भूमि की उत्पादन क्षमता पर निर्भर होता था। १८वीं सताब्दी के अन्त में यह भाग 'आधीया' अर्थात् १/२ के रूप में पहुँच गया लेकिन इसका दबाव प्रत्येक काश्तकार पर नहीं पड़ा तथा विरोध होने पर दसवें समाप्त भी कर दिया गया। 'भोग' के साथ-साथ 'बीजाकर' भी वसूल दिये जाते थे। जिनमें 'माली', 'सिराण', 'तूटा', 'हुजदार', 'ठाकुरजी', 'डेरा खर्च' आदि मुख्य थे। ये कर नववी व जिन्स दोनों में वसूल किये जाते थे। टीलों की भूमि में ये अन्य कर १ मन जिन्स से अधिक वसूल नहीं होते थे जबकि समतल व उपजाऊ भूमि में इनका अतिरिक्त दबाव मन तक पहुँच जाता था। 'सिराण' कुल उपज का ०.५६ प्रतिशत 'तूटा'

१. कागदों की बही, स० १८६६/१८०६ ई०, न० १६, पृ० १८

२. अन्य कर

३. विल पर लगा कर

४. भू-राजस्व वसूली के अधिकारियों के खान पान के खर्च को सगान का कर

५. भू-राजस्व के अधिकारियों के पशुओं का चरवाई कर

६. अधिकारियों के तालीनदारों के खान-पान खर्च की लागत का कर

७. दलान्तों की पूजा आदि के खर्च की लागत का कर

८. पहाव खर्च

१ १४ प्रतिशत, हुजदार ० ७८ प्रतिशत जिस के रूप में प्राप्त किया जाता था। ठाकुरजी का 'भोग' १ मन के पीछे १ या २ सर के रूप में होता था। भाग' को से जान व लिय जाताथात धर्च के रूप में १० मन के पीछे २) रुपया 'सूखडा' के नाम से वसूल किये जाते थे। इसके अतिरिक्त जब 'भोग' का नगदी में बदला जाता था तब गांव का चौधरी व पटवारी भी अपने हिस्से 'काबल' व 'धूधरी' के नाम से पाते थे।'

१७वीं शताब्दी के अन्त तक इस भोग में 'हासल' व 'भाछ' नाम के दो कर और जोड़ दिये गये व इस प्रणाली के अन्तगत वसूल किया जान वाला वास्तु-कार 'हाली' कहलाने लगा। इस कारण यह 'हाली हासल' प्रथा भी कहलानी थी। हासल के रूप में प्रति काश्तकरसे प्रति हल १ रुपया लिया गया जो बाद में 'पचव' में एक हल में दठरर रुमश तीन व चार रुपया वसूल किया गया। पचव हल का तात्पर्य यहा भूमि को एक चार जातन से है (इकलीया) व एक हल का ता पयं यहा भूमि को दो चार जातने से है (दोलडा) हासल की यह दर बढ़ती घटती भी रहती थी। यह कर देजहाली के नाम से भी लिया जाता था। जब इसमें 'रवम'— 'धुआ', 'देशप्रठ', 'कोरड' आदि जुड़ जाता था तो यह हासल में 'भाछ' के नाम से वसूल होती थी। धुआ प्रति गुवाडी एक रुपया पचवीस टका तथा 'देशप्रठ' प्रति गुवाडी चार आना की दर से वसूल होता था।' कई बार इसमें 'अग भाछ' भी जुड़ जाती थी, जब प्रति बैल १।।), प्रति गाय १), प्रति ऊट ३।।।) तथा प्रति बैलगाडी १।।।) रुपया वसूल होता था। ये सभी कर सदैव लागू नहीं हुए व कदा कदा खाय लागू नहीं होते थे। दरा में परिवर्तन घोडा-बहुत अवश्य हुआ ग्हाटा था।'

इन करों की सरचना के अन्तगत काश्तकार अपने व अपने अनु-अनु कर प्राप्ति पर जितनी भूमि चाहे जोत सकता था। अधिक भूमि जातन ७, ८, ९ नाम की रवम में ही वृद्धि होती थी, बाकी रोकड के कर 'गर्मिन्द' ग्हाटा था। रेगिस्तान में बिना जोत की भूमि को जोतने के लिए यह एक बड़ा बाधा था।

हलगत

राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग को छोड़ कर, ग्हाटा ग्हाटा ग्हाटा ग्हाटा जाता था, शेष समस्त क्षेत्र के गांवों में हलगत प्रथा ग्हाटा ग्हाटा था। इसका काश्तकार 'पसाईती' कहलाता था और हासल-काश्तकार ग्हाटा ग्हाटा था।

१ खालसा गंव की बही वि० सं० १७२६/१६९६ ई०, पृ० १, पृष्ठ १२४ व १२५
वि० सं० १७३६/१६७६ ई०, पृ० २३, पृष्ठ १२४, २०५ व १२६-२७
२ वही

३ हनुव बही, वि० सं० १८२१/१८६४ ई०, पृष्ठ २०, २१

रियायती करदाता था। यह रियायत राज्य आदेश द्वारा काश्तवार को प्राप्त होती थी। इसके अनुसार, प्रत्येक 'पसाईती' जोत व' लिए प्रयोग में लाय हलो पर एकमुश्त चुकाता था। प्रत्येक बैल से जोते गये 'इकलीय' हल पर ३) ६० तथा ऊट से जोते गये इकलीय हल पर ५) ६० वसूल किये जाते थे। 'दोलढे' हल का प्रयोग करने पर ६० १) अधिक देना पड़ता था। ब्राह्मण तथा वैश्य जाति से इकलीय बैल से जोते गये इकलीय हल की दर ६० २) तथा ऊट से ६० ४) थी। यह 'हलगत' की एकमुश्त कहलाती थी। कई बार 'हलगत' की एकमुश्त सामूहिक रूप से 'जमा' के नाम पर गांव पर सामू कर दी जाती थी। पसाईती को हासी की तरह ही, प्रति गुवाडों व गुवाडों के प्रति व्यक्ति पर धुआं भाछ तथा 'देसप्रठ' वसूल किया जाता था। इनसे भी कभी-कभी अंग भाछ हासियों की तरह ही ली जाती थी। 'भोग' इन्हें नहीं चुकाना पड़ता था। पसाईती भी निर्धारित एकमुश्त चुका कर, अपनी शक्ति के बल पर, जितनी चाहे जमीन जोत सकता था, और उससे कोई अन्य कर नहीं लिया जाता था। कृषि क्षेत्र को विस्तृत करने का यह एक कारगर उपाय था। राज्य गांव व 'पटवारियों' 'साहणों' तथा सैनिकों को भी पसाईती घनाकर भूमि प्रदान करता था। 'हलगत' को भी कई बार 'मुकाते' या ठेके पर चड़ाकर वसूल किया जाता था।^१

मुकाता तथा बोलीया

यह एक तरह की अनुबन्ध व्यवस्था थी। इस पद्धति के अन्तर्गत अधिकतर चौधरी के परिवार के सदस्य, ब्राह्मणों, साहूबारा, कारीगरों, शिल्पकारों तथा 'कमीनान' की जोत की भूमि आती थी। इसमें काश्तकार हल पर और भोग पर हासिल नहीं चुकाता था, बल्कि चौधरी व साहणा के द्वारा खेत का मूल्यांकन करने के पश्चात्, निर्धारित की गई एकमुश्त चुकाता था, जो साधारणतया ३) से ५) के बीच में होती थी और 'जमा' कहलाती थी। इसके साथ धुआं, 'देसप्रठ' वसूल किया जाता था और यह सब 'रकमे' मिला कर 'रोकड' कहलाती थी। कभी-कभी इनसे भी 'अंग भाछ' वसूल होता था। वास्तव में इस प्रथा का नाम 'बोलीयार' था, जो दोनों पक्षों द्वारा बातचीत के माध्यम से लगान निर्धारण का

१ गुजराईसर दे हासल रो बही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, न० १० बही हलगत रो वि० सं० १८१७/१७६० ई०, बस्ता न० १, बही खातवा रो गांवा रो, वि० सं० १८२७/१७७० ई० बस्ता न० १, हबूब बही, वि० सं० १८२१/१७६४ ई०

२ परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० २३२, नागदो की बही, वि० सं० १८३१/१७७६ ई०, न० ४ पृ० ३१, वि० सं० १८३८/१७८१ ई०, न० ५, पृ० ५४

३ बही हासल रो लेख रो, सं० १७४८/१६६१ ई०, परवाना बही वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० २३२, नागदो की बही, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृ० २४

कार्य करती थी। लेकिन जब निर्धारित रकम आने वाले वर्षों में भी अनुबन्ध के रूप में वसूल की जाने लगी तो यह मुकाती प्रथा कहलाने लगी। जिनका लगान प्रतिवर्ष आका गया वह 'बोलीयार' तथा जिनका पिछले अनुबन्ध की रकम से वसूल किया गया वह 'मुकाती' कहलाने लगा।

मुकाते की निर्धारित रकम, जो किसानधारणतया १) से ३) होती थी, लेकर अपनी

द्वितीय उपाय में काश्तकार मुकाता व हासल की सम्पूर्ण रकम लेकर अपनी भूमि अन्य काश्तकार को देता था। इस अवस्था में 'आसामी' की प्रशासन को हासल व अन्य रकम चुकानी पड़ती थी। अगर गाव का चौधरी तथा पुराने आसामी अपनी भूमि 'मुकाते' पर चढ़ाते थे, तो मुकाते के साथ-साथ 'मनवा' भी वसूल करते थे। राज्य द्वारा गाव को मुकाते पर देने पर, हासल की रकम 'मुकाते' के रूप में वसूल की जाती थी। ऐसी अवस्था में मुकाती, जोकि सम्पूर्ण गाव के हासल को वसूल करने का अनुबन्ध लेता था, चौधरी के साथ मिलकर विभिन्न पद्धतियों के अनुसार 'रोकड़ रकम' व 'भोग' को वसूल करता था। गाव में नये बसने वालों में भी कम दर के 'मुकाते' पर हासल वसूल किया जाता था; ताकि 'नवो' को बसने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरे गाव के 'आसामियों' से भी छेत-बाहने पर 'मुकाता' दरों पर रकम वसूल की जाती थी।

१. बामु रे हामल री बही, वि० सं० १७५४/१६६७ ई० न० ६३, बाबा रे रकम वसूली वि० सं० १७५६/१६६६ ई०, न० १२३; बही खालसा रे गाबा री, वि० सं० १८२७/१७७० ई०; हबूब बही, वि० सं० १८५१/१७६४ ई०
२. कागदा की बही, वि० सं० १८३१/१७७८ ई०, न० ४, पृष्ठ ३८; भैया सग्रह-पत्र, आसाढ़े सुद १० वि० सं० १८७२/१६ जुलाई, १८१५ ई०.
३. कागदो की बही, वि० सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ३१; वि० सं० १८३१/१७७४ ई० न० ४, पृ० ३८
४. उपर्युक्त—वि० सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ २६, ३४, वि० सं० १८६७/१८१० ई०, न० १६, पृ० २६
५. कागदो की बही, कालिक बदि ६, वि० सं० १८४६/१० अक्टूबर, १७८६ ई०, न० ८, कालिक बदि १२, वि० सं० १८५४/१७ अक्टूबर, १७६७ ई०, न० १०, भैया सग्रह-पत्र आसाढ़ सुदि १०, वि० सं० १८७२/१६ जुलाई, १८१५ ई०, देखिये परिशिष्ट, न० ७
६. हबूब बही, वि० सं० १८५१/१७६४ ई०
७. कागदो की बही, वि० सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ३१; वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृष्ठ २६, ३८

बीघेडी

यह राज्य की एक अन्य मुख्य प्रणाली थी, जो उत्तर व उत्तर-पूर्वी बीरो व परगनों में अधिक प्रचलित थी। इसके अनुसार, प्रत्येक काश्तकार की जोती गई भूमि को माप लिया जाता था और फिर प्रत्येक बीघे पर नकद कर वसूल कर लिया जाता था, जो 'बीघेडी' कहलाता था। मापन के लिए बीस अंगुल की डोरी का पैमाना प्रयोग में लिया जाता था जिसकी सम्बाई लगभग ६६ हाथ की होती थी तथा यह बीकानेरी बीघा कहलाता था। यह मापन प्रत्येक तीन साल पश्चात् होता था।^१ प्रति सौ बीघा हासल की दर ६) ६० थी।^१ मापन की अवधि के बीच के काल में अगर कोई काश्तकार अपनी निर्धारित भूमि से कम भूमि पर खेती करता था, तब भी उसको पूर्व निर्धारित 'बीघेडी' ही चुकानी पड़ती थी। और अगर वह अधिक भूमि पर खेती करता था, तो भी बीघेडी की दर पूर्ववत् ही रहती थी। इस प्रकार कम भूमि जोतने पर काश्तकार को तथा अधिक भूमि जोतने पर राज्य को नुकसान होता था। चिरा रीणो, नोहर व सीहागोटी में इस प्रणाली के अन्तर्गत होने वाले लाभ व हानि को गाव का चौधरी वहन करता था, क्योंकि वह मापन के बाद सम्पूर्ण गांव की जमाबन्दी करवा लेता था, जिससे कर देने का उत्तरदायित्व उसके कंधों पर आ जाता था। अतः जोत भूमि की कमी का नुकसान व जोत वृद्धि का लाभ उस ही प्रभावित करता था।^२ रबी की फसलों व व्यापारिक फसलों पर यही प्रणाली लागू की जाती थी।^३ काश्तकार को इसके बाद कई बार भोग व सहायक कर भी चुकान पड़ते थे। उस रोकड़ रकमों में अन्य पद्धतियों की भांति, 'धुआ भाछ', 'देसप्रठ', 'अम भाछ' चुकाने पड़ते थे।^४ इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक काश्तकार को अपनी सामर्थ्य से कृषि भूमि बढ़ाने पर हासल भी अधिक देना पड़ता था, क्योंकि 'सूई क्षेत्र' में पड़त की भूमि कम थी।

१. राज्य में बीकानेर बीघा की सम्बाई एक समान नहीं रहती थी। प्रति बीरा इसमें एक से हाथ का अंतर आ जाता था। पर डोरी बीस अंगुल की ही रहती थी। बीकानेरी बीघा एक एकड़ का लगभग ३६ भाग होता था।—परवाना बही, वि० सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० २३२, कागदों की बही, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृ० १६
२. कागदों की बही, वि० सं० १८३८/१७८१ ई०, न० ३, पृ० ४७, वि० सं० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृ० १७
३. फेगन—सेटलमेण्ट-रिपोर्ट, बीकानेर, पृ० १४-१५
४. कागदों की बही, वि० सं० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृष्ठ ६१, वि० सं० १८६६/१८०६ ई०, न० १३, पृष्ठ ३८७
५. रीणो री हासल भाछ बही, वि० सं० १७५२/१६६५ ई०, न० १२, बीकानेर बहियात, कागदों की बही, सं० १८३८/१७८१ ई०, न० ३, पृ० ४३; भोग की दर कृता प्रणाली की भांति ही १/३ से १/८ तक वसूल की जाती थी।

अन्य प्रणालियाँ

‘भीत की भाछ’ आवासीय मकानों पर लगाया जाने वाला भू-राजस्व कर था। इसका कृषि भूमि तथा इसका जोते गये हज़ से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह प्राणाली राज्य के पश्चिमी ‘चीरो’ में प्रचलित थी, जहाँ वर्षा की कमी के कारण खेती की बहुत कम संभावनाएँ रहती थी और बहुत ही सीमित मात्रा में खेती होती थी। इन चीरो में रहने वाले निवासी कृषि कार्य से अधिक पशु-पालन व्यवसाय पर निर्भर रहते थे। प्रशासन इस तरह के गावों में प्रत्येक घर से हालियो के समान एक निश्चित रकम ‘धुआ,’ ‘देसप्रठ’ तथा ‘अगभाछ’ के रूप में वसूल करता था। गाव के ‘बोधरी’ व ‘जमीदार’ पर इसको उगाहने का दायित्व होता था। इसके अलावा ‘दतोई’ प्रणाली का भी वर्णन आता है पर उसका स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं होता है।^१

अन्य कर व जमावंधी

हासल को वसूल करते समय आसामियों व रैयत द्वारा हुवलदार व चौधरी को अन्य कर या ‘बीजा रकमे’ भी चुकानी पड़ती थी। ये ‘बीजा रकमे’ कर-निर्धारण की सभी पद्धतियों के साथ लागू होती रहती थी, जब तक कि राज्य इन करों की ‘छूट’ न दे देता था। जो पसाईती इन करों से मुक्त होते थे, वे ‘पसाईती बेलब’ कहलाते थे। इनमें मुख्य रकमे ‘ठाकुर जी’, ‘गुसाई जी’, ‘मेला, पाडबती’, ‘हाकमों या लाजमा’, ‘कोरठ’, ‘भूरज’, ‘धास’, ‘चारा’, ‘सेहत’, ‘झाल’, ‘जखीरा’, ‘हयमलो’, ‘तलब’, ‘डेरो’, ‘आसामी’, ‘घरच’, ‘हुलो’ और ‘चोपलणी’, इत्यादि होती थी। ये रकमे गाव के ‘स्तर’ पर निर्धारित की जाती थी। इसमें ‘ठाकुरजी’, ‘गुसाईजी’, ‘आसामी झाल’, ‘तलब’, प्रति गाव १) ६० लिपा जाता था। गाव की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने पर १) की दर से वसूल होता था। ‘डेरो घरच’ व अन्य खर्च अधिकारियों व कर्मचारियों की

१. भीत की भाछ—छामसा री गोवारी बही, सं० १८१२/१७५६ ई०; हदूब बही—सं० १८५१/१७६४ ई०; भैय्या पत्र—माघ सुदी ६, सं० १८७७/१० फरवरी, १८२१ ई०; फौज—पृ० १६; दतोई के लिये—कायदों की बही, सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृ० ३६, ४१, ४७
२. लकड़ी काटने का कर तथा पेड़ों की उपयोगिता का लाभ उठाने का कर
३. सूखी लकड़ी काटने का कर
४. कर्मचारियों का खर्च कर
५. डेरा खर्च कर
६. कार्य में लगे व्यक्तियों का खर्च कर
७. बागवन्-स्थाही खर्च कर—बानी करों का खर्च पहले स्थान-स्थान पर दिया जा चुका है।

लागत के आधार पर वसूल होते थे। 'हथमेला' प्रति गांव १॥) ६० तथा 'दुल्लो चोपलणी' कागज स्याही के खर्च के आधार पर वसूल होता था। इसके अलावा 'रोजगार'-रकम निर्धारित होने पर वसूल की जाती थी। इसमें 'हुवलदार', 'कामदार', 'साहणा' 'लेखणिया' आदि का पारिथमिक लाजमा^१ के रूप में वसूल होता था। माघ में साहणों के दीवाली जीमण^२ तथा 'मले' के कर भी प्रत्येक गांव से १) रुपये के हिसाब से वसूल किये जाते थे।

ये सभी रकम हासल में रोकड़ के साथ मिलाकर वसूल की जाती थी। सभी रोकड़ रकमों की 'जमाबंदी' पहले ही हो जाती थी। केवल भोग को हुवलदार व चौधरी फमल कटने के समय निर्धारण करके वसूल करता था। 'रोकड़ रकम' व बीजा रकमों में या तो प्रत्येक कर की दर पहले निर्धारित हो जाती थी, जिस गुवाडियों की गिनती करके वसूल कर लिया जाता था अथवा प्रत्येक गांव पर सामूहिक रूप में लागू कर दिया जाता था, जिसे गांव वालों में बराबर वितरण करके वसूल कर लिया जाता था।^३

हासल उगाही-व्यवस्था

राज्य के दीवान का प्रमुख कर्त्तव्य हासल निर्धारण से वसूली तक व उससे होने वाली आय पर पूरी दृष्टि रखना होता था। उसकी नियुक्ति के समय शासक यह आशा करता था कि वह हासल की आय में वृद्धि करेगा। भू-राजस्व की वसूली के लिए नियुक्त सभी हुवलदारों की नियुक्ति उसी के द्वारा होती थी अथवा वह उनकी नियुक्ति के लिए शासक को मसाला देता था। 'भोगता व सातण' के क्षेत्र में कास्तकारों के स्वार्थों का दायित्व भी वही सभासत्ता था। 'भोगता से 'पेशवसी' की रकम तथा उनके क्षेत्र में चौरा स्तर की रोकड़ रकमों को वसूल करता था। हासल से सम्बन्धित सभी विवादों का फैसला देने के लिए वह अन्तिम अधिकारी था।^४

दीवान के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए उसका एक दफ्तर गठित किया गया था जिसमें खालसा गांवों के प्रबन्ध के लिए 'दीवान ए तन, अधिकारी

१ प्रबन्ध खर्च

२ दीपावली के अवसर पर की गई रसोई

३ उत्सव त्यौहार

४ कागदों की बंदी, स० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ३२, स० १८५७/१८०० ई०, न० ११ पृ० १६, स० १८७४/१८१७ ई०, न० २३ पृ० ८

५ कर्मचन्द (पूव) पृ० ६५, मशरूफा अमृतसिंहजी रो आनंदराम नाबर रे नाथ परखानी, बैरियस डिप्टी जज रिजर्वेड मज्दर दी आदित्य भाई दी दीवान भाई दीकानेर, मोहता रिवाज स—(पूव)

उसका मुख्य सहायक होता था। 'दफ्तर का हुवलदार' इसके विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। चोरे व खालसा के हुवलदार, दरोगा समय-समय पर नियुक्त होने वाले अस्थायी अधिकारी होते थे, जबकि गांव के 'चौधरी', 'पटावारी' आदि स्थाई अधिकारी थे। हासल तय करने व वसूल करने में इन सभी की समान भूमिका होती थी। 'दफ्तर का हुवलदार' हासल से सम्बन्धित सभी पत्रों को 'लेखणियों' की सहायता से तैयार कराता था व खालसा के हुवलदारों व चोरो के हुवलदारों को दीवान के आदेश से भेजता था। आदेश-पत्रों में करो का विवरण, उनकी दरें, हुवलदार व उसके सहायकों व अधीनस्थों का 'रोजगार' व उनका सेवाकाल आदि के विषय में स्पष्टतः लिखा होता था। हामल में छूट या मुआफ़ी के पत्र समयानुसार तैयार करके सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ भिजवा दिये जाते थे। गांव के 'चौधरी', 'पटावरी' व 'जमींदार' को भी इस सम्बन्ध में दफ्तर से सूचना भेजी जाती थी तथा आमांमियों व 'रैत' को भी करो को देने के लिए आदेश भेजा जाता था। हासल से होने वाली आय का समस्त विवरण तैयार करने का दायित्व 'लेखणीयों' का होता था। हासल की जमा-राशि को खजान्ची के पास भेजकर 'श्री रावले' में जमा करवा दिया जाता था।

राज्य में हासल व रोकड़ रकमों को वसूली के लिए खालसा व पट्टे के गांवों में 'हुवाना' व 'मुकाता' प्रणालिया प्रचलित थी।

हुवाला-व्यवस्था

खालसा गांवों की यह हुवाला-व्यवस्था चोरो में प्रचलित हुवाला-व्यवस्था के गमान ही थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत, हासल व उससे सम्बन्धित करो को वसूली के लिए, निश्चित समय हेतु, निर्धारित रोजगार पर हुवलदार की नियुक्ति की जाती थी। कर-भुगतान या तरीका व हासल की दर, दफ्तर के हुवलदार द्वारा पहले ही निर्धारित कर दी जाती थी। हुवलदार गांव के चौधरी, 'पटावरी' व 'साहणे' के साथ मिलकर हलों को गिनकर, कुल 'धीधो को' देख कर, तैयार फमल को 'कूनकर' या बांट कर, भोग को निर्धारित करता था, और निश्चित निर्धारित हासल व अन्य सामों को वसूल करता था। छूट व मुआफ़ी के 'सनदी' पत्रों को देखकर वह उनके अनुसार कार्य करता था।

हुवाला सौंपते समय राज्य की ओर से 'सनद' द्वारा हुवलदार को यह आदेश दिया जाता था कि वह हासल 'हसाबों' लेगा, 'कृषि भूमि' में वृद्धि करेगा, गांव

१ दयालदास श्याम, (प्रकाशित) भाग २, पृ० १२८

२ हासल बढ़ी, पृ० १८१२/१७५५ ई०, नस्खा न० १

३. बागदो की बही, वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृ० २-३

यथाये रखेगा तथा आबादी को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा।^१ उसी समय सम्बन्धित गाववासियों को जो सूचना भेजी जाती थी उसमें उनका लिए यह आदेश होता था कि उनके गाव में अमुक नाम के व्यक्ति की हुवलदार के रूप में नियुक्ति की गयी है। अतः वे समस्त कर अथवा उस ही अदा करें। कर देने में वे न तो कोई चोरी करें और न ही किसी प्रकार की बाधा ही उपस्थित करें। हुवलदार व गाव के 'आसामी' व 'रेंट' दोनों में यह आशा की जाती थी कि वे ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभायेंगे।^२

साधारणतया हुवाला सोपा^३ अवधि एक वर्ष के लिए निश्चित की जाती थी। पहले के हुवलदार को ही अगले वर्ष फिर नियुक्त किया जा सकता था। एक गाव का एक हुवलदार होता था, लेकिन एक हुवलदार को एक से अधिक गाव भी सौंपे जा सकते थे। कभी कभी दो व्यक्ति मिल कर भी एक गाव का हुवाला लेते थे। हुवलदार के साथ कार्य करने के लिए उससे सहयोगी के रूप में 'दरोगा' को भी भेजा जाता था, पर उसकी नियुक्ति तभी होती थी, जबकि हुवलदार का कार्य-क्षेत्र अधिक विस्तृत होता था।^४ परगनों के खालसा गावों में हुवलदार के साथ 'अमीन' व 'पोतदार' की नियुक्ति भी की जाती थी, जो भूमि का मापन, कर-निर्धारण व कर-संग्रह का काम करते थे।^५

मुकाता-व्यवस्था

इसमें राज्य-प्रशासन खालसा गावों का एक निश्चित रकम के बदले अनुवन्ध के रूप में 'मुकाती' को कर उगाहने के अधिकार दे देता था। 'मुकाती' को भी यह आदेश दिया जाता था कि वह जमावघी से अधिक कर वसूल नहीं करेगा। पूर्वी सीरो में बीघेड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत गाव का चौधरी जमावघी के आधार पर गाव को 'इजारे' या 'मुकात' पर ले लिया करता था। मुकाते की रकम के निर्धारण के समय, गाव की जमावघी व मुकाती के लाभ को सामने रखा जाता था। कोई भी व्यक्ति राज्य को उससे अधिक रकम दकर पहले वाले

१ कागदो की बही, वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २ पृ० २-३

२ कागदो की बही, वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृ० १६, बही खालसे रें गावा की वि० सं० १८३०/१७७३ ई०, न० १, बीकानेर, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृ० २, ३१

३ कागदो की बही, वि० सं० १८२०/१७६३ ई०, न० २, पृ० १-६, बही खालसे रें गावा की वि० सं० १८३०/१७७३, न० १

४ हासन भाछ परगना वेणीवास रें गावा रो, वि० सं० १७४५/१६८८ ई०, न० २, राजगढ़ रें पूनीया रें परगने रें हासन लेखे रो बही, वि० सं० १७४६/१६६२ ई०, हासन भाछ भटनेर रो बही, वि० सं० १७२२/१६९१ ई०, न० ११—बीकानेर बहियात

मुकाती से मुकाती अधिकार छीन सकता था। उस केवल पूर्व मुकाती को रोज-गार रकम के नाम पर एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी, जिस राज्य प्रशासन समझौता करते समय पहले से ही पूर्व मुकाती से निश्चित कर लेता था।^१ १८वीं सताब्दी में बहुत से हुबलदार मुकाती बन गये। वे प्रशासन को निश्चित रकम देकर गांव का हासल उगाहन का दायित्व प्राप्त करने लगे।^२ आन्तरिक विद्रोहों, विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न प्रशासनिक अव्यवस्था के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि राज्य सकट काल में आय को पहले ही प्राप्त करके निश्चिन्त होना चाहता था। उसी यह आवश्यकता 'मुकाती' ही पूरा कर सकते थे।

अधिकारी वर्ग

हासल वसूली के नियम राज्य दो प्रकार के अधिकारी नियुक्त करता था। प्रथम, वे अधिकारी जो राज्य प्रशासन द्वारा समय समय पर नियुक्त करके भेजे जाते थे। इनमें हुबलदार व दरोगा मुख्य थे। द्वितीय बशानुगत अधिकारों से युक्त स्थानीय अधिकारी होते थे, जिनका नियुक्ति से पूर्व शासक की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक थी। इनमें 'चीघरी, पटावरी व साहणा' मुख्य थे। इन समस्त अधिकारियों के कार्य, विशेषाधिकार तथा आय के साधन बड़ी थे, जो चीरे व स्थानीय प्रशासन व अधिकारियों व नर्मचारियों के थे। यत्कि यही चीरे व स्थानीय प्रशासन व अधिकारी हात थे, जिनका उल्लेख पहले विस्तृत ढंग से हो चुका है।^३

भोगता

पट्टायत धपन पट्ट क क्षत्र में काश्तबारा से हासल व रूप में 'भोग' वसूल करने व कारण 'भोगता' कहलाता था। 'भोगता' के गांव में हासल-वसूली का कार्य हुबलदारी के स्थान पर उसके 'गुमास्ते' करते थे। वे गांव के चीघरी के साथ मिलकर हामान निधारण, उसकी वसूली क तरीके तथा उसकी दरें निधारित करके वसूली किया करते थे।^४

१ बागदो की बही, वि० सं० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ३१ ३८, वि० सं० १८३३/१७७४ ई० न० ४, पृष्ठ २६, ३८, भोग्या सबह-यज याबाब बंद १०, वि० सं० १८७२/१९ जुलाई, १८९२ ई०

२ पगन—पृ० १४ १७

३ देखिये स्थानीय प्रशासन का अध्याय

४ बागदो की बही, वि० सं० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृष्ठ २८

पट्टा क्षेत्र में हासल-निर्धारण की सभी पद्धतियाँ विद्यमान थीं। उनकी दरें भी खालसा गावों से अधिक नहीं होती थी। भोगता हाली ॥ 'देज' व 'भोग', पसाईती से हलगत, मुकाती से मुकाता व बीघेडी में प्रति बीघा दर वसूल करता था।^१ लेकिन हासल की अन्य रोकड़ रकमें जैसे धुआ, देसप्रठ 'अग भाछ, मेला' पाडघत्ती, 'गुमोईजी' ठाकुरजी आदि चोरे के हुबलदार आकर वसूल करते थे।^२ 'कोरड', 'भुरज', 'घास' व 'चारे' की रकम पट्टायत को मिलती थी।^३ पट्टायत अपनी गुमोईजी, ठाकुरजी, मेला 'पाडघत्ती', डेरा सरख आदि की रकमें अलग से वसूल करता था। कामदारों का पचं हाकमों के रोजगार के स्थान पर लिया जाता था।^४

भोगतों के क्षेत्र में 'भोग' व निर्धारित रकमों की वसूली पूर्णतया 'भोगता' के हाथों में थी, लेकिन राज्य प्रशासन के उस पर कई नियन्त्रण थे। भोगता निर्धारित हासल में अधिक वसूली नहीं कर सकता था और न ही मनचाही दरें बढ़ा सकता था।^५ खालसा के काश्तकारों को वह अपने यहाँ नहीं बसा सकता था।^६ बिना किसी उचित कारण के काश्तकार की ज़ोत में वह 'खेचल' नहीं कर सकता था और न ही उसके भूमि अधिकारों को समाप्त कर सकता था।^७ उस गाव के चौधरियों को मलबा दिसवाना पड़ता था।^८ वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए काश्तकार के खेतों को 'रेहन' पर नहीं रख सकता था।^९ ऐसा सब करने के लिए उसे प्रशासन की ओर से कड़े आदेश दिए जाते थे।

१ उपर्युक्त—वि० स० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ ३४, वि० स० १८३१/१७७४ ई०, न० ४, पृष्ठ २५, वि० स० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० २४८

२ बीरा जसरामर बीदाहद, गुमोईसर सेवे से बही, वि० स० १७९६/१७४२ ई०, न० ३१, भाछ से बही, वि० स० १७४६/१६८६ ई०, न० ४६—बीकानेर बहिषाव, पागदों की बही, वि० स० १८५१/१८९४ ई०, न० ८, पृष्ठ ४४-४६

३ गावा रे लेन देन की बही, न० १२२, गावा रे रकम वसूली, वि० स० १७३६/१६९९ ई०, न० १२३

४ कागदों की बही, वि० स० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृ० ४६; वि० स० १८७३/१८१६ ई०, न० २२, पृष्ठ ७४

५ कागदों की बही, वि० स० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ ३४, वि० स० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० २११, २४८

६ उपर्युक्त—वि० स० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ ४१

७ विघ्न

८ कागदों की बही वि० स० १८५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० ८६, २०८, वि० स० १८७४/१८१७ ई०, न० २३, पृ० १३६

९ उपर्युक्त—वि० स० १८२७/१७७० ई०, न० ३, पृष्ठ ३४

१० उपर्युक्त—वि० स० १७५७/१८०० ई०, न० ११, पृ० २०८

भोम

‘भोम’ की भूमि भी इसके प्राप्तकर्ता ‘भोमिया’ के लिए वशानुगत अधिकारों में युक्त तथा हासल व लाग से मुक्त होती थी। ‘भोम’ भूमि के अधिकार साधारणतया, उन लोगों को मिले हुए थे, जो राठोड़ों के आक्रमण से पूर्व इस क्षेत्र के प्रशासकीय अधिकारी थे। भूमि पर उनके पूर्व अधिकारों की मान्यता देते हुए तथा उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए ‘भोम’ भूमि की सुविधा प्रदान की गयी थी। बीका, बीदावत व काधलोत राठोड़ों को भी ‘भोम’ भूमि प्रदान की गई थी; क्योंकि ये राज्य के संस्थापक बीका, बीदा व काधल के वंशज थे। माटियो, भट्टियो व जोहियों के कबोलेदारों को भी पूर्व प्राप्त अधिकारों व उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए यह सुविधा दी गयी थी। ‘भोम’ भूमि-दार खुद-काशत भी होते थे व अपनी भूमि मुकाते पर भी चढ़ा दिया करते थे। ये प्रशासन को केवल ‘भोमवाव’ नामक कर ही चुकाया करते थे, जो भूमि की उत्पादन शक्ति के अनुमान से आका जाता था। इन्हे भूमि माप करके दी जाती थी, ताकि ये अधिक भूमि पर अधिकार करके प्रशासन को करों से वंचित न करे।^१

१. बही लेखे रो, न० ४६; भाछ रो बही, वि० सं० १७३६/१९५६ ई०, न० ५६; गावा रे लेखे रो बही, न० १७६६/१७६३ ई०, न० ६४; परवाना बही, सं० १८००/१७४३ ई०, पृ० २३२-२४

उपसंहार

सन् १५७० ई० के अन्तिम चरण में, मुगल सम्राट अकबर की नागौर यात्रा, राजपूताने में हस्तक्षेप करने की उसकी नीति का साहसिक नदम थी। मुगल शक्ति इस क्षेत्र के प्रमुख शक्ति-स्तम्भों—चित्तौड़, अजमेर, नागौर व रणथम्भीर को जीत कर अपनी श्रेष्ठता का सिक्का जमा चुकी थी। सम्राट अकबर इसके परिणामों का लाभ उठाने में देर करना उचित नहीं समझता था। अतः उसने बीकानेर के शासक राव कल्याणमल को मुगल अधीनता स्वीकार करने का निमन्त्रण भेजा जिसे अस्वीकार करने का साहस राव में नहीं था। राज्य की उत्तरी, उत्तर-पूर्वी व उत्तर-पश्चिमी सीमाएँ मुगलों के घेराव में आ चुकी थी। राव जैतसी की मृत्यु के पश्चात् राज्य आन्तरिक अव्यवस्था का शिकार बन गया था। मारवाड़ के आक्रमण व सामन्तों के विद्रोहों की आशंका उसे निरन्तर सताती रहती थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी, दिल्ली के समीप स्थित होने के कारण, मुगल शक्ति के प्रति उदासीन रहना उसके धर्म की बात नहीं थी। उसने सम्मुख दो ही विकल्प थे—या तो अपने सैन्य बल द्वारा मुगल शक्ति का विरोध करें, जो लगभग असंभव था अन्यथा उसकी अधीनता स्वीकार करके राज्य के अस्तित्व को बनाये रखें। अधीनता स्वीकार करने के दो प्रत्यक्ष लाभ थे—प्रथम, बाह्य आक्रमणों की आशंका से एक लम्बी अवधि के लिए मुक्ति और दूसरा, मुगल संरक्षण के बल पर आन्तरिक शत्रुओं से निपटने में सुविधा तथा राज्य की स्थायित्व प्रदान करने का सुव्यवहार। अधीनता स्वीकार करने में प्राप्त होने वाले तात्कालिक लाभों को ध्यान में रखकर राव कल्याणमल ने नागौर जाकर सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।

इसके उपरान्त, सम्राट अकबर ने नागौर में ही राव कल्याणमल से निकट के सम्बन्ध स्थापित किए। दो राजवंशों के बीच, इस प्रकार मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के नये युग का सूत्रपात हुआ। सम्राट ने कुंवर रार्यासिंह को अपनी सेवा में रखने व राव कल्याणमल को बीकानेर वापस जाने की अनुमति प्रदान की। कुंवर रार्यासिंह ने मुगलों की सेवा में रहने का पूरा लाभ उठाया। समय के साथ-साथ सम्राट का विश्वास उसमें बढ़ता गया। चार वर्ष बाद, सन् १५७४ ई०

उसके गद्दी पर बैठने के उपरान्त वे पारस्परिक सम्बन्ध जोर भी मुदृङ्ग हुए। राय दलपत व राजा कर्ण के अन्तिम बाल को छोड़कर रायमिह व उमर सभी उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध मुगल के साथ सदैव सौहार्दपूर्ण ही रहे। मुगल सम्राटों ने अपने विभिन्न सैनिक अभियानों में उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया तथा समय समय पर अनेक प्रशान्ति पदा का गोषा जि ह लगन व निष्ठा के साथ बीकानेर के शासकों में निभाया। मुगल सत्ता के बदले में उन्हें राज्य से बाहर स्थित कई समृद्ध जागीरें प्राप्त हुई जिनसे प्राप्त होने वाली आय कई बार बतन जागीर की आय से अधिक होती थी। उनसे आयी समृद्धि व शाही अभियानों में सूट की आय ने, राज्य के आन्तरिक प्रशासन की शक्ति व प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया। ऐसी ही टीबो व समृद्धि की ऐसी बात इससे पूर्व कभी नहीं देखी गयी थी। राज्य में आयी समृद्धि ने साहित्य व कला के विकास को प्रेरित किया। शासकों ने विद्वान साहित्यकारों व कलाकारों को संरक्षण दिया जिससे राज्य का, भौतिक के साथ-साथ सांस्कृतिक स्वरूप भी निखरने लगा।

मुगल ने बीकानेर शासकों को मनसब व जागीर प्रदान करने में सदैव उदारता व उत्साह दिखाया। कभी भी बीकानेर शासकों का मनसब १,०० जात व १००० सवार से कम नहीं रहा, ताकि इनकी बतन जागीर की सीमाएँ अक्षुण्ण रहे। मुगल द्वारा इनकी बतन जागीर की सीमाओं को कभी खण्डित नहीं किया गया और न ही अपनी सावभौम सत्ता के प्रदर्शन के दरादे में अन्य पड़ोसी राजपूत राज्यों की भाँति, मनसब निर्धारण के अनुसार, इनकी सीमाओं में कूटनीति या पटौती की गयी। अकबर के बान में निर्धारित सीमाएँ अक्षुण्ण बनी रही। जो क्षेत्र बीकानेर राज्य में नहीं माने गये, उन्हें अलग में जागीर के रूप में प्रदान करके उस क्षेत्र पर उनसे आनुवंशिक दावों का सम्मान किया गया, परन्तु वे जागीरी क्षेत्र उन्हें मनसब वृद्धि के साथ ही प्राप्त होते थे। सम्राट इन पर पूरा ध्यान रखता था कि मनसब वृद्धि के समय वे क्षेत्र ही उन्हें प्राथमिकता के तौर पर जागीर में दिये जायें। ये क्षेत्र बीकानेर शासकों की मृत्यु तक ही उनके पास रहते थे। सम्राट ने राजा का कम मनसब होने पर इन क्षेत्रों को उसके परिवार के अन्य सदस्यों को प्रदान करके उनके दावों के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त किया था। महाराजा स्वरूपसिंह की जागीर में केवल बीकानेर राज्य ही रहा। अन्य क्षेत्र उसके छोटे भाई आनन्द सिंह को दे दिये गये। इस प्रकार सीमित अभिभाज्य क्षत्र में ही बीकानेर राज्य की सीमाएँ सद्यप्रथम निर्धारित हुईं तथा बढ़ प्रशासन वहाँ लागू हुआ। अन्य क्षेत्रों को भी बीकानेर के प्रभाव में रखा गया जिसका पूरा लाभ बीकानेर के राजाओं ने मुगल शक्ति के पतन के काल में, उन्हें अपने राज्य का अंग बना कर उठाया।

जीरा राजवंश की प्रमुखता लाभ प्राप्त करता है वही उसका अधिकारक मान्य म मृग । मगघाट की विजातीय विजातीय ने स्वीकार करता पड़ा । मुगल मगघाट । भी राजवंश विजातीय म ही विजातीय ने प्रभाव करके न बाल अनी दूना न राजकुमारा को गद्दी पर बिठाया, अतः मही उन्ही दूना उन्ही म व्यवस्था करता रहा कि उसी स्थिति, जतिन न सम्मान मगघाट की दूना पर आधारित है ।

सन् १६८० ई० म मगघाट अन्तर विभिन्न प्रजागणिक गुणार करके अन्त मगघाट म एव मुगलविजय प्रजागणिक व्यवस्था की नींव डालन म मगघाट हुआ था, विजातीय बीरानेर राजा की आन्तरिक व्यवस्था पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ा । यहाँ न सागर राज्य मगघाट म, प्रभाव न ही नियमित म साथ रहा । य । उनका म उन्ही अधिकारिया न । मुगल-प्रशासन के प्रति आकर्षण व उसका तीव्र तराकी न । राजा म साथ करता की दूना, इसमें एव प्रभावशाली तराकी थी । मुगल मगघाट राज्य भी मगघाट म प्रशासित मगघाट पर एव दूना था व इसमें सम्मान प्राप्त आदेश अधीन सागर न मगघाट म । बीरानेर राजा जमीर, मुगल मगघाट अन्तर की मगघाट जहाँ की मगी विजातीय आन्तरिक स्थिति म मुगल मगघाट की प्रभावशाली वदम उन्ही की मगघाट प्रदान की मगी । इतना ही नही, मुगल दरबार म दूना मगघाट मगघाट पर विजातीय । न यहाँ न व्यवस्था न प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था । अतः, मगघाट न आन्त मुगल मगघाट के प्रजागणिक व्यवस्था, मगघाट न अधिकारिया की दूना तथा परिस्थितियों के फलस्वरूप मुगल प्रजागणिक प्रभाव राजा म पर करता पड़ा गया ।

राज्य न प्रजागणिक शीघ्र पर मुगल प्रभाव मगघाट तीन प्रकार म पड़ा । प्रथम, राज्य की स्थिति पर, द्वितीय, प्रजागणिक दूनादूना न मगघाट पर तथा तृतीय, प्रजागणिक प्रजागणिक पर ।

मुगल सरकार म मगघाट अधिक लाभ राजपद की ही पदवी । उसकी सत्ता अन्तरी सीमाओं के अन्त न बल दूना दुई, अतः प्रजा म भी उसका सम्मान बढ़ गया । अन्त यह कुलीन भाई-भारे की व्यवस्था म सातदशरी न मगघाट नही रहा था, बल्कि राज्य की निरकुलवादी शासकीय सत्ता म डलकर उसकी एकता न प्रतीक बन गया था । उसने विजातीय सामन्तों की शक्ति का दमन करके तथा विभिन्न नवीनो को नियमित करके, बीरा राजवंश के उत्तर म राठीड़ा की अग्रज अविभाज्य सत्ता स्थापित कर दी थी ।

राजा की शक्तियों म वृद्धि । सामन्तों व विद्रोही नवीनो पर उसके नियन्त्रण न, प्रशासन को राज्य म एक प्रजागणिक प्रजागणिक लागू करने का अवसर दिया । सर्वप्रथम, केन्द्रीय प्रशासन मुगल शैली पर मगघाट किया गया । पुराना मन्त्री 'दीवान' कहलाया व उसका मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन के साथ-साथ

मुगल वजीर की तरह राज्य के वित्तीय मामलों का प्रबन्ध करना निर्धारित किया गया। उम कार्य-सम्पादन में सहायता के लिए दो नये सहयोगी, 'दीवान-ए-तन, व दीवान-ए-खाससा', दिये गये। इससे दीवान की शक्तियों पर नियन्त्रण रखना भी संभव हो गया, ताकि अधिक शक्तिशाली बन कर वह राजपद को चुनौती न दे सके। सैन्य विभाग के मामलों की देख रेख 'मुसाहिब' पद की सीपी गई, जो मुगलों के 'बखशी' के दायित्वों को पूरा करने के साथ-साथ वकील पद का सम्मान भी राजा के विश्वामोय व्यक्ति के रूप में प्राप्त करता था। सैन्य विभाग की बाद में अलग संगठित करके, इसके मुख्य प्रशासकीय अधिकारी के रूप में 'बगसी' पद की रचना की गई। राजाओं ने शाही बरखानों की तरह राजधानी में विभिन्न कारखानों की स्थापना करने में भी पूरी रूचि दिखाई।

मुगलों के प्रभाव से केन्द्रीय प्रशासन की भांति प्रान्तीय व स्थानीय प्रशासन भी अछूता नहीं रहा। प्रशासनिक एकरूपता के मिथ्यान्त में व्यावहारिकता तभी आ सकती थी, जब कि उम प्रान्तीय व स्थानीय रूप में भी लागू किया जा सके। राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र चारों भू विभक्त कर दिया गया, जो अकबर की करोड़ी-व्यवस्था के समान राजस्व इकाई के रूप में गठित हुए थे। इसमें खानमा क साथ-साथ सामन्तों का क्षेत्र भी सम्मिलित था। इन चारों के अधिकारी 'चीरायत' या 'हकूम' कहलाते थे। 'हुबलदार' का नाम भी प्रभाव का द्योतक है। राज्य में शांति व व्यवस्था रखने के लिए जो 'थाणे' स्थापित किये गये थे, उनके मुख्य अधिकारी फौजदार के वर्तन्य भी वे ही थे, जो मुगल सरकार के फौजदार कहोते थे। स्थानीय स्तर के अधिकारियों में, चौधरी व पटवारी, पञ्चोसी मुगल क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों के समान ही दायित्व सम्भालते थे। 'शहर कोतवाल' बीकानेर व अजमेर नगर में एक से ही अधिकार रखता था।

राज्य में प्रशासकीय विकास व समर्पण के फलस्वरूप एक प्रभावशाली प्रशिक्षित अधिकारी वर्ग 'मुत्सद्दी' का तैयार हुआ, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लालच में राज्य में सन्निध हस्तक्षेप की ओर प्रेरित हुआ। दरबारी गुटबंदी राजनीति का प्रभाव भी राज्य में छाने लगा। राज्य को, जहाँ एक ओर 'मुत्सद्दी' की प्रतिस्पर्धा से सुयोग्य व कर्तव्यनिष्ठावान प्रशासक मिले, वहाँ उनके निजी स्वार्थों की होड़ से पड़्यन्तों की बढ़ावा भी मिला, चूंकि यह सम्पूर्ण वर्ग राजा की ओर कृपा की आशा से देखता था, अतः इसकी योग्यता व अयोग्यता पद की स्थिति व शक्ति को बढ़ाती-घटाती रहती थी। राजा के कमजोर होना पर प्रशासन व्यवस्था स्वयं सूचारु रूप से नहीं चल सकती थी, क्योंकि 'मुत्सद्दी' अपने लाभ व भावी हितों का पूरा करने में जुट जाते थे। लेकिन, मुगल अधिकारी-वर्ग की तरह ये राज्य अथवा राजवश को अधिक हानि

नहीं पहुँचा सके क्योंकि साम्राज्य या प्रत्यक्ष उच्च अधिकारी व कमचारी मनसबदार होता था, जिसके माध्यम निश्चित सैनिक दायित्व वध होता था। यहाँ वे मुत्सद्दियाँ के पास शक्ति मंचित करने के लिए सम्पूज्य जागीरें नहीं थी। इस तरह वे दरारों में राज्य के सामन्ती वर्ग का सहयोग भी उस प्राप्त नहीं हो सक्ता था क्योंकि वे किसी भी दशा में 'मुत्सद्दी' के हाथों में अपने कुनपति का अपमान नहीं कर सकते थे। अतः मुत्सद्दियों के पक्ष में सामन्तों के साथ मिलकर अपने पक्ष के राजकुमारों को गद्दी दिलाने तथा राजा का अत्यधिक विश्वास प्राप्त करने तक ही सीमित रहे।

राज्य के साम तो ढाँच में, जो मूल रूप से परिवर्तन आया वह मुगलों के प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम था। पट्टा व्यवस्था मनसब प्रणाली से प्रेरित थी। शासक मनसब प्रणाली की भाँति राज्य के सामन्तों को निश्चित दायित्वों से बाधना चाहता था। उसने सम्पूर्ण पट्टा प्रणाली या मुख्य स्रोत स्वयं को बना दिया, जिसमें प्रत्येक पट्टायत्त अपनी स्थिति व अधिकारों को लेकर उसकी छाप पर आश्रित हो गया। उस जागीर के 'भोग' का भोग करने के लिए राज्य को निर्धारित गावरी अर्पित करनी पड़ी, जिसमें किसी प्रकार की कमी होने पर उसे दण्डित भी किया जा सकता था। मुगल जागीरों के स्थानान्तरण की भाँति, पट्टों के गावों में भी स्थानान्तरण का गुण आ गया। चाकरी की समाप्ति के साथ पट्टे भी छीन लिए जाते थे। राज्य का कुल मुत्सद्दियाँ पट्टायत्त के रूप में मुगल जागीरदारों की तरह राज्य के नियमों में बंधकर अपने क्षेत्र का प्रशासन चलाते थे बाध्य हुआ। उनके क्षेत्र में करा की दरें निर्धारित हो गयीं, जिनके विरुद्ध शिकायत आने पर राज्य की ओर से उचित कार्रवाही की जा सकती थी।

सामन्ती व्यवस्था का ढाँचा भी मुगल दरबार के नियमों से प्रभावित होकर अपनी खाप की विशेषता को बनाय हुए गठित किया गया। साम तो वे खाप स्तर पर अनेक श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया व दरबार में उनका स्थान व स्थिति निश्चित कर दी गयी। सामन्तों की गुटबंदी खाप वर्गीकरण से प्रभावित होने लगी।

राज्य में मुख्य आय के रूप में भू राजस्व व्यवस्था का गठन भी इस काल में किया गया। भू राजस्व, जो पहले कुल उत्पादन का २० प्रतिशत था, अब हामल के रूप में उपज के आध भाग को अपने 'कब्जे' में करने लगा। हामल का निर्माण 'भोग' (मात) रोकड़ रकमा' व बीजा रकमों ('जिहात') से किया गया। उसकी वसूली में निश्चितता लाने के लिए मुगलों की तरह भूमि मापन को प्रोत्साहित किया गया व उसे बीघों में विभक्त करके उसके आधार पर हासल का निर्धारण किया गया। इस प्रकार भू राजस्व वसूली व्यवस्था में 'बीघरी' प्रथा

जन्म हुआ। मापनकी डोरी 'बीघा-ए-दलाही' की तरह थी। 'इजारा प्रणाली' प्रभाव राज्य में 'मुबताता प्रणाली' के रूप में था, जो अनुबन्ध पर वसूली का कार्य करती थी।

राज्य में प्रशासकीय कार्यों के संचालन की जो पद्धतियाँ थी, उन सभी को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मुगल प्रशासन ने प्रभावित किया। केन्द्र में 'हुवलदार का दफ्तर' बनाया गया। इसके जिम्मे कर्ग की दरें निर्धारित करने का कार्य था। हुवलदार गाँवों में हासल व 'रोकड़ रकमों की जमाबन्धी' करता था, जिससे प्रशासकों का केवल यही दायित्व रह जाता था कि वे समय पर वसूली करके उसे राज्य के खजाने में जमा करावें। आय व व्यय का पूरा विवरण लेखा बहियों में तैयार किया जाने लगा तथा राज्य की आय का पूर्ण अनुमान लगाने की व्यवस्था शुरू हुई। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मुगल मनसब का वेतन, बतन जागीर की जमा पर निर्धारित होता था। राज्य के सभी राजकीय आदेशों को लिखित रूप में भेजा जाने लगा तथा उनकी नकल 'दफ्तर' में रखी जाने लगी।

प्रशासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त पदों व कर्गों के नाम भी राज्य पर मुगल प्रभाव के द्योतक थे। राज्य में 'दीवान', 'मुमाहिब', 'शिकदार', 'हुवलदार', 'फौजदार', 'बगसी', 'ताबीनदार', 'रोजनदार', 'महीनदार', 'तोपची', 'नीगोणची', 'बन्दूकची', 'मुमरफ' तथा बरों में 'जगात', 'दासन', 'अदालती', 'नजगना' आदि राज्य के प्रचलित नाम इसका समर्थन करते हैं।

मुगल शक्ति के संरक्षण व उसके प्रभाव के वास्तविक महत्व की जानकारी उस समय हुई, जब मुगलों के पतन काल में राज्य पुनः बाह्य आक्रमणों व आन्तरिक विद्रोहों का शिकार हुआ। राजपद के सिद्धांत को खुली चुनौती दी गई तथा शासक को राजपद की प्रतिष्ठा व राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए निरन्तर संघर्षों में जूझना पड़ा। अव्यवस्था व अशांति के वातावरण में प्रशासनिक ढाँचा छिन्न-भिन्न होने लगा। १८वीं शताब्दी के समाप्त होते-होते एक राजनैतिक व प्रशासनिक संकट का जन्म हुआ, जिससे उबरने के लिए पुनः प्रतिष्ठापनी केन्द्रीय सत्ता की शरण लेने की आवश्यकता पड़ी।

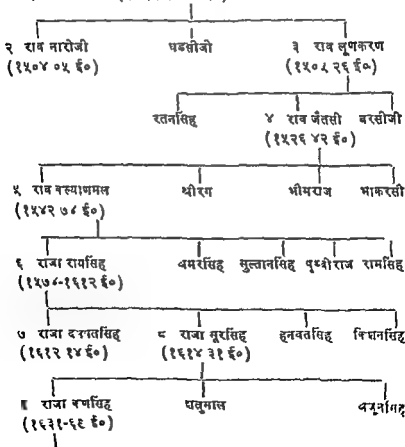
अतः स्पष्ट है कि बीकानेर राज्य में मुगल शक्ति का विशेष प्रभाव था। राज्य की मर्यादाएँ मूल रूप में अपनी परम्पराओं, क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा प्राचीन हिन्दू परम्पराओं से प्रेरित थी, लेकिन प्रशासकीय व्यवस्था मुगलों की शैली में ढल गयी थी। प्रशासकीय व्यवस्था को छोड़कर बीकानेर राज्य राज-पूताना के उन राज्यों में था, जहाँ मुगल प्रभाव तुलनात्मक दृष्टि से कम पड़ा था। राज्य की भौगोलिक स्थिति, शासक वर्ग की जातीय परम्पराएँ तथा

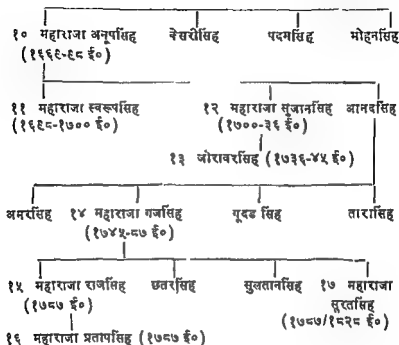
निवासी जातियों व बचीलों के नियम, किसी बाहरी हस्तक्षेप व सलाह के प्रति उदार नहीं थे। रगिस्तानी राज्य में, जहाँ आवागमन के साधनों का अभाव एक प्रमुख समस्या थी, मुगल शांति की प्रभावशाली प्रशासनिक-व्यवस्था को अपनाना एक भागीरथ कार्य था। निरकुश नृपतन्त्र की सफलता भी यहाँ सन्देहास्पद थी, क्योंकि इस शासन की समस्याएँ ऐसी थी, जिनका सही हल समन्वय में ही ढूँढ़ा जा सकता था। अतः राज्य के शासकों ने वे कदम ही उठाये थे, जिनमें राज्य का स्थायित्व व समृद्धि सम्भव थी। उन्होंने मुगल व्यवस्था के उन तरीकों को ही ग्रहण किया, जो उनके क्षेत्र में लागू हो सकते थे और जिनके लागू किये जाने से राज्य की हितसाधना अधिक भली प्रकार सम्भव थी। भू-राजस्व प्रशासन में प्रचलित विभिन्न प्रणालियाँ तथा स्थानीय अधिकारियों की शक्तियों के स्वरूप का समर्थन करते हैं। भू-भाषन व्यवस्था भी रैतीले क्षेत्र में वही अपनाई गई, जहाँ सूई (समतल) भूमि थी।

राजपूतों की कुलीन परम्परा दृढ़ता से स्थापित हो चुकी थी, उन्हें उखाड़ फेंकना आसान काम नहीं था। स्थानीय जातियों के सामाजिक व आर्थिक नियम इसलिए प्रचलित किये गये, क्योंकि वे परिस्थितियों के अनुकूल थे तथा उनमें हस्तक्षेप करके एक सामूहिक विरोध का सामना करना कोई विवेकसम्मत कार्य नहीं था। स्थानीय प्रशासन, भू-राजस्व व न्याय-व्यवस्था में शासक ने क्षेत्रीय व राठौर परम्पराओं को ही अधिक मान्यता दी थी। सेना व सामन्तों के ढाँचे में परिवर्तन अवश्य हुए थे, लेकिन उनसे उनके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ था। उन्हें मूलतः वैसा ही रहने दिया गया था। आवश्यकतानुसार अवश्य कुछ संशोधन किये गये थे। राजा स्वयं प्राचीन हिन्दू नरेशों के आदर्श पर चलना चाहता था तथा प्राचीन भारतीय परम्पराओं को लागू करके यश प्राप्त करना चाहता था। अतः मुगल शक्ति का यही लाभ उसने उठाया कि उसके बल पर राज्य की सुरक्षा व स्थिरता प्रदान करना उसके लिए सम्भव हो सका।

परिशिष्ट १
घोकानेर शासको का वंशवृक्ष
[राव बीका से महाराजा सूरतसिंह तक]

१ राव बीकाजी (१४६५-१५०८ ई०) बीकानेर राज्य का स्थापक





परिशिष्ट २

महाराजा अनूपसिंह का आइणी (दक्षिण) से आनन्दराम
नाजर को राज्य-दीवान पर नियुक्त करते समय उसके
कार्यों व दायित्वों के प्रति निर्देश

महाराजा अनूपसिंहजी से आनन्दराम नाजर के नाम परवानो १७४६

सही

स्वस्ति महाराजाधिराज महाराजा श्री अनूपसिंहजी वचनात नाजर जोणद
राम जोणय सु प्रसाद बाचजो तथा हिमंतु देस पोहती छं मु दसतुर से प्रवोनो
तोनु कर बीयो छं आगे उपर सारी जायता भली भोत करे—

। छाप देस माहे दरवार बंठो दीवान बचनायत से बागद हुवं सारो नंजर
अर पजनच से थोडी देस प्रगने सारे उपर हुवं ते उपर कीयो करे अर दरवार
उठीया पछे जरूर काम से हुवं त उपर करे अर मुनेणो छं कारण सायक थोडी
हुवं तै उपर छाप कीवी करे कारण सायक न हुवं ते उपर मने करे—

। बाण हुवाई न माने तेन सत्ता देई

। कोट भीतर खजनों छं तेरी जायता भली भात कर सभले अर टका
पिण सारा सभाल ठीक कर सामे तणे से अरज लिखे ।

। कारखानों बढो थो बीकानेर छे अर हजूर मु मेलीयो छं तेरी जायता
भली भात करे आगला कारखाना सारा मेहली सभाल पछे हजूर से सभाल
भली भेत अर मेला कर राखे आदमी हुवालदार आगला छे मु भला हुवं तो
राखे नही तो बीजा भला देण राख अर सारो विले से विलेकरे ।

। मदुर हुवाले से कारखानो पुसतण तबो पीतल और चाव हुवं मु सारो
सभाल भली भात विले कर राखे ।

। सिलेकरवीने से कारखानो माछे रे हुवाले से हजूर से सारो सभाल
आगे छं मु सरख सरख सभाल धासा हथीमारो जुदो कर ज्या अर तसरफी से

जुदो कारखानो कर ज्यो तोष खानो सतुर ताल रमचगी हवे तेरी धनी जाबता करै बगतर खास बढुको हुवै सु पिणवल कर राखे ।

। कोठार श्री कोटमाहे सारा छै सु सभाल भली भत जाबता कर विले कर राखै अर घन रो अवेरा जिनस रो सारो जाबता कर प्राणी री नवी करे अर गावो रो हासल रो भोग आवै सु कौठार माहे जाबता कऱ घतावै नेजे रो काठार छै स पिण सुभाल विलै करै हुवालदार आगला भता हुवै तो राखजै नही तो पीज करणा हुवै ते ये बीजा भला देख करे अर कण ये रे कोठार माहे लोक पावै छै सु खबर करे हुवै तेन देई अर घसीयो हुवै तेरो को लेखे न लेण मत देई ।

। श्री ठाकुरो रे गावो रो अर श्री बाईजी रे पटे रो गावो रो पईसी भासी सु तागीदी कर भरीये अर गाव जासणो कोट ३ तान के छै सु तु जाबता कर भले आदमी रे हवाले नरे जमा सरवरी मुहसो रे बँठा छै ते भात बेसे त ईलाज करे मुजरो कर दिवालै ।

। कमठोणे रे कोम री जाबता करै केही हिषायती रो चाकर मजुर दुखो दीडे तेरी जाबता कर बुर करे ।

। देस माहे कोमदार हासल उधावण जावै ताहरो डेर रो खरच दरबार रे लिखीयै सु बधीक लेवै अर हाकम रो बेटावे भाई और कामदार जावै सु देस माहँ मैलो लेवे अर चोचो कर इराय लेवे तेनु मने करे अर कीई लेवे ते कने इगारी सुघो सझा दे भर लेई अर उमराय भवता जाबता देस माहँ खेचल करण मते देश डेरे रो अरसरा दसतर माफक छै सु चालीया जावै ।

। हजुरी देस माहँ खिजमत पावै छै सु लिखीयै सु बाघ लेवे चोचो करे तेनु सझा देई पकड अर इगारी सुघो भर लेई अर भीतर बाहीया ६० तोपची २०० मीरघो रे तालके कर चोतडे दाखल दोडणा ठेहरामा छै सु लिखीयै सु बाघ मेगे जाजती कर देम माहे रईयत सु पकड सझा देई अर तलव रो पईसे कोस रो दसतुर छै सु हुसी सके जरूर काम उपर करे तो सिरस माफक जवण वाले नु दिरायै बघै नु सिरकार दाणल जमा करायै ।

। साहुकार ब्राह्मण लेहणे वालो सु गैर हसावी बसी हवो मये तँनु मने करे अर बरम ४ तेई रजपूतो कने आगलो लेहणो मने बीयो छै सु लेण मता दो ।

। रजपूतो कने लेहणो लोको रो छै सु थिता सिरकार रो छै अरबीजी साहु-करो री छै ब्राह्मणी वोहरो री छै सु थित रो रणियो चको पछै रजपूतो रे पटे रे गाव माहँ बघै नु दमसही लेण देई पेहली खेचल कर आदमी मेल तिके आदमी नु पकड कोट माहे देई ।

। कोमदार रो लेहणो पटायतो कनै छँ अर पकै पटो बीजै नु हुवै ताहरो जोर
घात लेहणो उपै कनै लेछै सु लेण मत देई ।

। श्री मोहसो रो लोक बुरो घालै अ जाजती करे सेहर देस माहँ अर बीजो
ही बमण हिमायती इये पेढे घालै तिको सिगला न सझा देई भुलाजो मते करे ।

घरती सरकार रो बिकता कोई बीच अडबी करै अर चौकी वँ दसतुर कीधी
हवै सुमने करै । सवत् १७४६, मिती भिंगसर (मार्गशीर्ष) बदि १३, मुकाम
आधूणी ।

परिशिष्ट ३

महाराजा सूरतसिंह जी द्वारा करों की अकरायत की शिकायत आने पर उन्हें नये ढंग से निर्धारित करने व लागू करने का आदेश-पत्र

देस रो गोवो रो चोघरीयो रेत सममुतो जोग्य तीया थी.. जी साहबो देस सरवाल री मरजाद बाधी छै सु आगै सदामद पीड़ी सु रकम तीज छै सु तीजसी आगे साल १ मे रकमो ४ ती ५ पड़तो सो दुर कीयो छै ते सबाम बधती साल १ मे दण्डवाली री भाछ रा गुवाडी १ रु० १०) १०। ईक दर सोठी नीबली माडी हुसी सु सरवाल गीणती वर सीजसी गुवाडी री गोहो चोघरी हुवलदार राखण पावे नही राखसी तो चोघरी गुनेगारी रा रु० ११) हुवलदार उधावण जासी तीको रु० २५) देसी आगे तो सदामद हरी खेजडी बड़ी वा बल तणी बहाता नही हुनेह्यो वरसो मे हरी खेजडी बड़ी वा बलदतणी बहाता से स० १८५३ साल हरी खेजडी बाठण री वा बलद तणी बवण री मनाई कीवी कै तेरा कामद देस सरवाले रे गावो मे हुय गया छै तेमे जाव छै ईतरो कोमो ने तो हरी खेजडी बढसी तेरी तो माफी छै हाल हालबउ वा गोडे रे पईयो रो पुठ वा पाटलो कोहर रो भुवण तेली री धोणी जवाडी पजाली वा बडे फलसे री फलसो बटवा चुलीयो सु खेजडी रा हुवे नही आली खेजडी सदामद हुवै छै अर अंघड उठो नु लोक हाथस सुतर नाय सोउ चोलपण हुवी तो ओकोडें सु ऐसी कुहाडो लगावण पावे नही ईतरो कोमो ने मोहरी खेजडी बढसी तेसदाम हरी खेजडी बढसी वा बलद तणी माहसी तो गुनेगारी रा रु० २५) लागसी अर तपावस रो जाव आप ममेले होणे देण री घर जमी रो कोई असरचो हुसी तो वरा परदेसरी पचो उप्रा-घात नोव रुराय दीजसी हरकुर कई री नरहसी जीण कर श्री दरबार वा काई दुजी हरकुर राखमी तो सीना रा ईण ईसरो सु वे मुख हसी अर द्यो वरसो मे गोव जबती हुवा वा कोई गुवाडी दुजी पकड तमें आई सु हमें गोव जबते ने हुसी कोई गुवाडी पकड न मे न आसी जमा यातर राख गुवाडी बाहर छै तीका नु पुठो वमाण लेजो अर दुजै देगरा गुवाडी सुवाई वससी तीका कता साल ३ रकम सरव अघखरनीजसी नै आगै सु जमीदारा रे गुवाडी नै रकम हासल भाछ लागसी

तंसू हँसो १ चोचाई या रँ पुत पातै नु छुटा जासी सुवाई गुवाडी आहीढो री जमी
 झालसी सु जमोदारा बरोबर रकमी देसी अर हाकम देस मै नागारा ले चढसी
 जो कै गो वजासी तीके गोव रा मेले रा ६० १) ले सी अर सार्ग श्री दरबार
 रा रसँ लो हुसी ता नीरण रा जावतो कारासो नै कही गोव मै मुकाम हुसी लो
 पाछतो रो गोवो सु नीरण रसीले नै मगाय लेसी ईया वरसो मे बेरा छरच वा
 बीचड़ी रा रसीमा उघावै छै सु ह्ये न उघासी हमै ये जमा खातर राछ गोय
 बसावजो थारी भोत भोत पीठ रहमी नै सेहेर रँ साहुकारी री भाछ लेवण री
 मरजाद श्री...जी साहयो देसणोक मे बीराज भौण फुरमाय कागद रा मोर छाप
 रा उप्र राम सहीबा स दमकतो कर दीया छै तँ मरजाद माफ कईया कागदा री
 मरजाद रहसी हमै बोई वा रा बीसवास मतो रखजो श्री दरबार रो वचन छै
 सं० १८७३ जेठ वद २ अदासत सु कागद गोव गोव रा ह्ये उप्रली छरच माफक
 नारा नारा हुवे छै ईका नकल रा मीती नारी नारी छै ।

कागदो की वही, वि० सं० १८७३, नंबर २२, पृष्ठ १६१-६२ ।

परिशिष्ट ४

बीवान पद पर नियुक्ति व उसका वेतन

मुहत्तो बघतावर संप मीनारूप फतेसपतोत रुपनाय भीवसिध अणदरूपोत
नु महाराजा गजसिंहजी मेहरवानगी कर दीवोनगी खीजमत दीनायत कीबी तेरी
बिगत

८००६) इतरा गोवपटे छै

२७०१) गो. कीलोनसर महीयोरो

२००१) गोव सखमीसर

१००१) गोय तेजसासर

२०१) हासी रीणी चलकोडी पाचुनाथु सरस

१०१) मुजोणदेसर रा उमोव अर खेत भोमीयो रो

२००१) जागीर देनी

८००६)

२८३७) इतरा रोकडो पासी

८४६) मास १ खजोनची सुतेरा मास १२ पासी २४) देसमै मा. १

१५ आपरा ६ आसोमी

४६॥) श्री हजुर मे मा. १ पासी

१५) आपरा ४॥) आसोमी १

२७) चाकरारा ४) चौपदार ४) फरास १६) चाकर ४

७०॥) मा. १ तेरा मा. १२ रा ६० ८४६) पासी

१६६१) इतरा रोकड सलीणै पासी

१६०१) मंसे रा घुवेर गोबो रा तथा ह्यमेलो रो

३६०) दुजापासी तेरी बिगत

१००) हजदारो कनै १५०) रसोदीये रापटे री ठोड मोहं

१००) नीरण रा गोवो सु ४०) मोगडी रा

३६०)

१६६१)

२८३७)

१११६) झितरो कीठार मोदीखाने पेटेनु माबार मै पासी

४८६) श्री हजूर मे मढे स भा. १२ उनमोन

उनमोन भा. १ ६० ४०॥) तेरा भा. १२ ६० ४८६)

६३३) देस माहे छे सु पासी

.....बोहा वारमी

१११६)

२०३६) दरी बैताबैरो खाना सु दीरावण

५००) पालसी खरच रा पामी

१४५०१) अखरे चवदे हजार पाच सोइक झीण भोत रोजक पासी खोजमत दानतदारी सु करसी स० १८०६ भी. वै. मु. मु० गोव चगोडी प्रवामो तीमो खोजमत स० १८०६ मी. पोहसुद १४ ईन्यात कीबी तागीर मं० १८१३ सो. व १५ भा. १ महर्त मूवाडीसध नु खोजमत रो हुवम भा. व १० खोरपोव हुत्रो दी २५वद चलो मे मूघको राजरूप अमर-सिध चीठी नीची

गुमामतो २ झण भोत पामी—१७) हरताल दुवारकोणी दफतर मोडमी १३) दमतर दुवारकोणी गजोनची सु पासी

३०) अमर तीम माह १ रा पासी, चाकरो दातदारी सु करमी ॥ १८०६

वै० मुद २—गट्टावही, वि स. ११२ मिती भादुवा वद १२ (३ सितम्बर, १७५५ ई०) न० ७, पृ० १४२

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

प्राथमिक स्रोत

(१) अभिलेख सम्बन्धी सामग्री

(अ) बीकानेर बहियात—रा० रा० अ० बी०

बीरा बहिया .

- १ बीरा छेदडे री बही, न० ७०, वि० स० १७३६
- २ बीरा सेखसर रे लेखे री बही, न० ६१, वि० स० १७४७
- ३ बीरा जमरासर रे लेखे बही, न० २७ वि० स० १७४८
- ४ बीरा मोहर रे लेखे री बही, न० २८ वि० स० १७४६
- ५ अनूपगढ़ रा खत य गावा री बही, न० ६६, वि स० १७५०
- ६ राणीये रे बीरे री बही, न० ४८ वि० स० १७८३
- ७ बीरा गुसोईसर रे लेखे री बही, न० २६ वि० स० १७६५
- ८ बीरा जसरासर रे लेखे री बही, न० ३०, वि० स० १७६७
- ९ बीरा जसरासर, बीदाहद गुसोईसर रे लेखे री बही, न० ३१, वि० स० १७६६

जगात बहियां .

- १ मण्डी रे साहूकारा री बही, न० २३२, वि० स० १७२६
- २ जगात खर्च बही, न० ७५, वि० स० १७५४
- ३ बहो फिरोती री, न० ७०।२, वि० स० १७५६
- ४ मण्डी री बही, न० ७८, वि० स० १७८३
- ५ मण्डी री बही, न० ७९, वि० स० १७९६
- ६ मण्डी री बही, न० ८०, वि० स० १८०१
- ७ जगात आमदनी बही, न० ८४, वि० स० १८२२
- ८ मण्डी जगात बही, न० ८३, वि० स० १८२२

- ६ जगात री सावा बही, न० २४६, वि० स० १८५६-५७
१० बही जगात रे खर्च री बही, न० २८६, वि० स० १८६६

जमा-खर्च की बहियाँ :

१. मण्डो रे जमा खर्च री बही, न० ७४, वि० स० १७०१
- २ परगना री जमा-जोड़ बही, न० ६६, वि० स० १७२६-५०
३. जमा खर्च बही, न० १११, वि० स० १७८०-८३
- ४ परगना रे जमा खर्च री बही, न० ३२, वि० स० १७५०-५१
- ५ कस्बा रीणी रे जमा खर्च री बही, न० ५४, वि० स० १७५३
- ६ खजाने री जमा खर्च बही, न० ३३, वि० स० १७५५-५६
- ७ समसत रे जमा खर्च री बही, न० ७७, वि० स० १७५८
८. जमा खर्च बही, न० २२१, वि० स० १७६४
९. भोरगावाड करणपुर रे जमा खर्च बही, न० १२१, वि० स० १७६८
- १० रोकड़ बही, जमा खर्च, न० २२३, वि० स० १७६६
- ११ छेड़ खरब री जमा बही, न० १२६, वि० स० १८०३
- १२ रावले खर्च री बही, न० २१३, वि० स० १८०५
१३. जंसलमेर कानी फौज रे जमा खर्च री सावा, न० १६३, वि० स० १८५५
१४. पाणी भीछ रे जमा खर्च बही, न० २५०, वि० स० १८७७

घान के कोठार की बहियाँ :

१. कोठारी भीवराज रे लेखे री बही, न० ८४, वि० स० १६८६
२. कोट रे घाने दाखन रे जमा मर्च बही, न० ८५, वि० स० १७१६
३. कोठार घान री बही, न० ६७, वि० स० १७१८
४. मोदी जयाराम रे लेखे बही, न० ५०, वि० स० १७२८
- ५ कोठार रे घान री बही, न० ५६, वि० स० १७६३
६. मोदी अमरदत्त हरमकत री लेखो, न० ५२, वि० स० १७४८
७. कोठार रे लेखे री बही, न० ३५, वि० स० १७४६
८. बडे कोठार रे खरब री बही, न० ३६, वि० स० १७५३
९. बडे कोठार रे जमा खर्च री बही, न० ३७, वि० स० १७५४
१०. कोठार रे जमा खरब री बही, न० ६७, वि० स० १७५५.
११. कोठार रे जमा खरब री बही, न० ३८, वि० स० १७५५
१२. कोठार रे घान री बही, न० ८०, वि० स० १७५६

घुआं बहिया ।

- १ घुआ भाछ री बही, न० ८५, वि० स० १७४६
२. घुआ भाछ री बही, न० ८६, वि० स० १७४६
- ३ घुए री गिणती री जमा बही, न० ८७, वि० स० १७४८
- ४ घुआ रोकड बही, न० ८८, वि० स० १७५०
- ५ घुआ देसप्रठ री बही, न० ८९, वि० स० १७८६

लेखा बही

- १ हुजदारो रे लेखे री बही, न० १३०, वि० स० १७०४
- २ लेखा री बही, न० १०५, वि० स० १७७३
- ३ लेखा री बही, न० १०७, वि० स० १७४१
- ४ साहे री बही, न० ६३, वि० स० १७४७-५०
- ५ गाव रे लेखे री बही खालमा, न० ६४, वि० स० १७५०-६०
- ६ श्री रावले लेखे बही, न० २१२, वि० स० १७७५
- ७ लेखा बही, न० २२२, वि० स० १७८६

हासल बहिया :

- १ गावा रे हलगत री बही, न० १३३, वि० स० १७३६
- २ गावा रे हासल भाछ री बही, न० १ वि० स० १७४०
- ३ खालमा रे हासल भाछ री बही न० ६८, वि० स० १७४३
- ४ गाव गुसोईसर रे हासल भाछ री बही, न० १०, वि० स० १७४६
- ५ राजगढ रे पूनीया रे परगने रे हासल लेखे री बही, न० ६, वि० स० १७४६
- ६ जसरासर हासल भाछ री बही, न० २६, वि० स० १७१०
- ७ भटनेर हासल भाछ री बही, न० १२, वि० स० १७५२
- ८ रीणी हासल भाछ री बही, न० ११, वि० स० १७५२
- ९ कालू रे हासल भाछ री बही, न० ६३, वि० स० १७५४
- १० अनूपपुरे रे हासल भाछ री बही, न० २५, वि० स० १८०४

भोग बहिया ।

१. कोठार रे भोग री बही, न० ५८, वि० स० १७१६
२. गाव पुनसीसर रे भोग रे लेखे री बही, न० ६४, वि० स० १७१६
३. धान रे भोग री बही, न० ५७, वि० स० १७३६

- ४ गावा रे भोग री व कुन्ता बही, न० २०७, वि० स० १७४०
- ५ भोग व कुन्ता बही, न० २०७।१, वि० स० १७४०
- ६ भोग व कोठार री बही, न० ३४, वि० स० १७४२
- ७ भोग री बही, न० ६५, वि० स० १७८६

खालसा बहिया

- १ खालसा गावा री बही, न० ६५, वि० स० १७२६
- २ देश रे खालसा बही, न० ६७, वि० स० १७४०
- ३ खालसा रा गाव हुआदारा सू किया तेरी विगत न० १००, वि० स० १७५५
- ४ गावा रे लेखे री बही खालसा, न० ६४, वि० स० १७६०
- ५ बही खालसा गावा री, न० १०१, वि० स० १७६१

घोडा बहिया

- १ घोडा खरीद बही, न० २३५, वि० स० १७४६
- २ तबेला खर्च बही, न० २३४, वि० स० १७५६
- ३ घोडा रे जमा खर्च री बही, न० १४०, वि० स० १७८८

बिबाह बहिया

- १ बाईयो रे ब्याव री बही, न० १४३, वि० स० १८१६
- २ बाईजी सरदार कुवरजी रे ब्याव री बही, न० १५४, वि० स० १८२७

अन्य बहिया

- १ खाता पट्टे गाव लिख दीणा तेरी विगत, न० २१६, वि० स० १७०८
- २ परचूण खर्च, न० १२०, वि० स० १७१७
- ३ खरडा बही, न० २३८, वि० स० १७१७
- ४ समसत गावा री बही, न० ७१, वि० स० १७२७ ४५
- ५ अनूपगढ रे गावा री बही, न० ६६, वि० स० १७५०
- ६ घूत खरीदने री बही, न० २३६, वि० स० १७५२
- ७ गावा रे बित री बही, न० २२७, वि० स० १७५२
- ८ कामदारो व वकीला रे रोजगार री बही, न० २०६, वि० स० १७५३
- ९ उगरी बही, न० २२६, वि० स० १७५४
- १० अनूपसागर बही, न० २३३, वि० स० १७५४
- ११ जखीरे री बही, न० १३६, वि० स० १७५६

- १२ बीदावतो की नजर बही, न० २०२, वि० स० १८०३
- १३ बही हजूर रे खट री, न० २०८, वि० स० १८०३
- १४ लस्कर बही न० २४१, वि० स० १८२६
- १५ हावियो व तुलादान री बही, न० २००, वि० स० १८४८
- १६ सीरबन्धो री बही, न० १६४, वि० स० १८४८
- १७ साहुकारा री गुलकरी बही न० १६०, वि० स० १८६१
- १८ साहुकारा रे भाछ री बही, न० १५६, वि० स० १८६५

(आ) बीकानेर रिकोर्ड्स, रा० रा० अ० बी०

- १ बस्ता हवूब (हवूब बहिया वि० स० १८०२ स १८६८ तक), बस्ता न० १
- २ बस्ता खालसा गावो का (खालसा गावो की बहिया, वि० स० १८२० से १८७५ तक), बस्ता न० १-२
- ३ बस्ता खाता खजाना सदर (खाता खजाना सदर बहिया, वि० स० १८१० स १८७५ तक)
- ४ बस्ता लेखापाढा (लेखा बहिया, वि० स० १८४० से १८७५ तक)
- ५ बस्ता सम्भाल व भाजम रा (बही सम्भाले लाजमे री, बही तनवगसी पणे री लाजमो सरदारो कन लियो तेरो नेखो, वि० स० १८६२)
- ६ सावा खजाना सदर, वि० स० १८११, नम ६, न० ८५
- ७ बही खजाने री, नवत् १८१५, न० १६
- ८ बस्ता परगना हामल भाछ (परगना हासल भाछ री बहिया, वि० स० १८०२ से १८६६ तक)
- ९ बस्ता महबूबा पेशवसी (बही पेशवसी री, वि० स० १८१८, १८१७, १८२०, १८२३, १८३४, १८५८, १८६०—सात नम)
- १० बस्ता महकमा धान री चौथाई का (बही धान री चौथाई री, वि० स० १७६३, १८११, १८२०, १८३८, १८४६, १८४७, १८६०, और १८६३-आठ नम)
- ११ धान री चौथ, वि० स० १८११, चीरे री बही
- १२ बही १८२० साल री खत किया तथा उधारा लिया, वि० स० १८२०
- १३ बही खजाना री, वि० स० १८५२
- १४ बही भाछ री, वि० स० १८५४

(३) रामपुरिया रिकोडेंस, बीकानेर, रा० रा० अ० बी०

कागदों की बही

- १ कागदा की बही, वि० स० १८११
- २ कागदों की बही, वि० स० १८२०
- ३ कागदा की बही, वि० स० १८२७
- ४ कागदा की बही, वि० म० १८३१
- ५ कागदा की बही, वि० स० १८३८
- ६ कागदों की बही, वि० स० १८३६
- ७ कागदों की बही, वि० म० १८४०
- ८ कागदों की बही, वि० स० १८४६
- ९ कागदों की बही, वि० स० १८५१
- १० कागदों की बही, वि० स० १८५८
- ११ कागदों की बही, वि० स० १८५७
- १२ कागदों की बही, वि० स० १८५९
- १३ कागदों की बही, वि० स० १८६१
- १४ कागदा की बही, वि० म० १८६३
- १५ कागदा की बही, वि० स० १८६६
- १६ कागदों की बही, वि० स० १८६७
- १७ कागदों की बही, वि० स० १८६७
- १८ कागदों की बही, वि० स० १८६८
- १९/१ कागदों की बही, वि० स० १८७०
- १९/२ कागदों की बही, वि० स० १८७०
- २० कागदा की बही, वि० स० १८७१
- २१ कागदों की बही, वि० स० १८७२

सावा बहिया

क—सावा बही राजगढ़

- १ सावा बही राजगढ़, वि० स० १८२८, २ वि० स० १८३१,
- ३ वि० स० १८३५, ४ वि० स० १८४२-४४

ख—सावा बही रतनगढ़, वि० स० १८५८ म १८६१

ग—सावा बही मण्डी सदर

- १ सावा बही मण्डी सदर, वि० स० १७९२, २ वि० स० १८०२-४,

३ वि० स० १८१०-१२, ४ वि० स० १८२१-२२

घ—सावा बही रोणी

१ सावा बही रोणी, वि० स० १८१४-२३, २ वि० स० १८२४-२८,

३ वि० स० १८२८, ४ सावा बही रोणी, वि० स० १८३४-३८,

५ वि० स० १८३९-४३, ६ वि० स० १८५४-५५

च सावा बही हनुमानगढ़, वि० स० १८६२-६७

छ सावा बही मूरतगढ़, वि० स० १८४४-५४

ज सावा बही अनूपगढ़,—

१ सावा बही अनूपगढ़, वि० स० १७५३-५४, २ वि० स० १८१८-

२१, ३ वि० स० १८२१ स२८, ४ वि० स० १८२८ से ३४, ५

वि० स० १८३८ से ४३, ६ वि० स० १८५४-५५

झ सावा बही नोहर—

१ सावा बही नोहर, वि० स० १८२२-२५, २ वि० स० १८२५ से

२७, ३ वि० स० १८३१ स ३२, ४ वि० स० १८३४-४०, ५

वि० स० १८४०-४३, ६ वि० स० १८४३-४६, ७ वि० स० १८४९

ट सावा बही भादरा, वि० स० १८७६-८५

ठ सावा बही चूरू, वि० स० १८२९

ड सावा बही सरदारगढ़, वि० स० १८८८

बही जमीं रे कागवा री, नंबर ५

१ बही जमीं रे कागवा री, वि० स० १८१४-२१ २ वि० स० १८४३-४५

३ वि० स० १८४६-५६ ४ वि० स० १८६२-६३

बही बिट्ठी रे खतों री, नंबर २६

१ बही बिट्ठी रे खतों री, वि० स० १८२०, २. वि० स० १८३७, ३

वि० स० १८४९, ४ वि० स० १८५१, ५ वि० स० १८५७, ६

वि० स० १८६४-६५

१ बही खरब री, वि० स० १८८५, न० ३०

१ बही तलवे तपारी, वि० स० १८६६, न० ३१

खालसा बहिया, न० ३२

१ बही खालसा रे गाव री, वि० स० १८२७, २ वि० स० १८३०

३ वि० स० १८६५

पट्टा बही, न० ३३

१. पट्टा बही, वि० सं० १६८२, २. वि० सं० १६६२, ३. वि० सं० १७०४-५, ४. पट्टा बही, वि० सं० १७२५, ५. वि० सं० १७२५-२६, ६. वि० सं० १७४२, ७. वि० सं० १७५३

बही बडा कमठाणा री

१. बही बडा कमठाणा री, वि० सं० १७४६, २. वि० सं० १८०८-१२, ३. वि० सं० १८१२ से १३, ४. वि० सं० १८१६, ५. वि० सं० १८२१, ६. वि० सं० १८२३-२४, ७. वि० सं० १८२५

आप बहिर्पा

१. बही कूच मुकाम रे कागदा री, वि० सं० १८१०-१४ न० ३४
१. बही अमल रे चीठोया रे खता री, वि० सं० १८१६-१८ न० ३६
१. बही पेशकसी रे लेखे री, वि० सं० १८५३, न० ३८
१. बही सासन री, वि० सं० १६७१, न० ३९
१. बही महाजना पहिया री, न० ४०११
१. बही महाराज गजसिपजी धाम पधारिया लेरी, वि० सं० १८४३, न० ४०१२
१. बही परगना फनोदी रे गाव री, वि० सं० १७०१, न० ४०१३
१. बही पानावली ठिकाणा री, वि० सं० १८००, न० ४०१५
१. बही विगत ताजीम री, नवर ४०१६
१. बही पट्टे रे गावा री, न० ४०१८
१. बही घोडा रेख री, वि० सं० १८३५, नवर ४०१९
१. बही कछवाली भाछ री, वि० सं० १८७६, न० ४०११०
१. बही परबून ठिकाणा री, वि० सं० १८८५, न० ४०१११
१. बही छाप रे कागद री, नवर ४०११२
१. बही रसाते री, वि० सं० १९८७, न० ४०११३
१. बही वाईजी श्री सरदार कुमरजी रे ब्याव री, वि० सं० १८२७, न० ४०१२२

परवाना बही

१. परवाना बही, वि० सं० १७४०, न० २२१३
२. परवाना बही, वि० सं० १८००, न० २२१२
३. बही खाल रे मता री, न० २२१३

(ई) जोधपुर रिकार्ड—रा० रा० अ० बी०

- १ खरीता रजिस्टर और खरीता बहिया
- २ ख्यात री बही, बस्ता न० ४३
- ३ तवारिख जोधपुर, बस्ता न० ४०
- ४ विजय विलास, बस्ता न० १४
- ५ हकीकत बहिया, वि० सं० १८२१ से १८७५

(उ) अन्य रिकार्ड—रा० रा० अ० बी०

- १ जयपुर बही बीकानेर विभाग
- २ तवारिख जैसलमेर बस्ता न० ७५
- ३ खरीता, बीकानेर महाराजा गजसिंह का, मगसिर (मार्गशीर्ष) बंद २, वि० सं० १८१२

(ऊ) मोहता रिकार्ड—रा० रा० अ० बी०

- १ बेरियस परवानाज ऑफ दी बीकानेर क्लर्क्स एड्रेस बु की मोहता फेमिली ऑफ बीकानेर पतेष न० २, माइक्रो फिल्म रील न० ८, (२१ परवाने)
- २ कोन्टेम्परेरी नेरेटिव प्रिपेयरड बाई दी मोहता भीमसिंहजी रिगाडिंग दी सीज ऑफ बीकानेर बाई महाराजा अभयसिंह आफ जोधपुर एलोगविद अदर नेरेटिव ऑफ अलियर रेन्स, (मोहता भीमसिंह द्वारा जोधपुर—महाराजा अभयसिंह के घेरे का वर्णन), पतेष न० २, माइक्रो फिल्म रील न० ८

(ए) भैंय्या संग्रह— निजी संग्रह, बीकानेर

- १ भैंय्या आलमचन्दजी व पत्न, वि० सं० १८०२-१८३० तक, सं० ४८
- २ भैंय्या नथमल व जेठमल व पत्न वि० सं० १८६६-१८७३ तक, सं० १२६

बहियात

- १ बही मोदीखाने रे ठीक री, वि० सं० १८२६
- २ बही घर खरच री, वि० सं० १८४३
- ३ भाटियो र गाव री विगत, वि० सं० १८४६
- ४ जमा खरच की बही, वि० सं० १८५४
- ५ गारी पट्टी मगरे री रुखवानो री बही, वि० सं० १८५६

- ६ लेखे री बही, वि० सं० १८६०
- ७ बीदाहृद री खखवाली भाछ री बही, वि० सं० १८६१
- ८ मोरगढ़ रे थोणे री जमा खर्च री बही, वि० सं० १८६२
९. बीरे खारी पट्टे रे जमा खर्च री बही, वि० सं० १८६५
१०. पैदा री सरख ठोक री बही, वि० सं० १८६६
- ११ गांव बुधणाव रे लेखे री बही, वि० सं० १८७०
१२. जमा खर्च री बही, नयमल, वि० सं० १८७२
१३. विगत रुक्को री, वि० सं० १८७२
१४. गुवाडियो रे मै भाछ उगाई री बही, वि० सं० १८७२
१५. फौज री जमा खर्च री बही, वि० सं० १८७२
१६. बही फौज रे भाछ री, वि० सं० १८७२
- १७ लेखे री बही, वि० सं० १८७२
१८. नोहर रे धाणे री जमा खर्च री बही, वि० सं० १८७२
१९. चोपनिया तनवगसी रा, वि० सं० १८७३
२०. बही घता री, वि० सं० १८७३
- २१ सीरबन्धी री हाजरी री बही, वि० सं० १८७३
२२. सीरबन्धी री चिठिया री नवल, वि० सं० १८७३
२३. बही साहूकारो री जमात रे लेखे री, वि० सं० १८७४
२४. बही कोटही रे साग्रम री, वि० सं० १८७४
- २५ बही नोहर धाणे रे जमा खर्च री, वि० सं० १८७४
२६. बन्कूकचीया री विगत, वि० सं० १८७५
२७. विगत कागद मू उतारी, वि० सं० १८७८

(२) शिलालेख (संस्कृत) बीकानेर

१. चिन्तामणि मन्दिर शिलालेख, म० १६६२
२. मूरज पोख प्रशस्ति, जूनागढ़, बीकानेर, वि० सं० १६५०
३. बीकानेर जय शिलालेख, वि० सं० १८८७
४. छत्री शिलालेख (अनूपसिंह) वि० सं० १७५७
५. छत्री शिलालेख (सुजानसिंह), वि० सं० १७६२
- ६ छत्री शिलालेख (जोरावरसिंह) वि० सं० १८००

(३) ऐतिहासिक साहित्य

(अ) राजस्थानी साहित्य

- १ राव जैतसी रो छन्द बीठु सुजे रो कयो, अ० स० पु० बी०
- २ दलपत विलाम—सम्पादक रावत सारस्वत, सार्दुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर, १९६०
- ३ राजा मूरजसिंघ जी रे जागीर री विगत, फुटकर बाता, न० २०६।२-२०, अ० स० पु० बी०
- ४ सूबा री सरकारा ने परगना री विगत, न० २ ६।३, अ० स० पु० बी०
- ५ नागोर रे मामले री बात कवित, न० ६, अ० स० पु० बी०
- ६ राठौडो री वशावली तथा पीढिया, न० २३२।५, अ० स० पु० बी०
- ७ बीकानेर रे पट्टे रे गावा री विगत कर्णसिंघजी रे समै री, न० २२६।२, अ० स० पु० बी०
- ८ बीकानेर रे घणीया री याद ने बीबी फुटकर बाता, न० २२५।१, अ० स० पु० बी०
- ९ महाराजा अनूपसिंघजी रो आनन्दराम नाजर रे नाम परवानो वि० स० १७४९, आदुणी लिखत खास रुक्का न० १९७।१९, अ० स० पु० बी०
- १० मुहणोत नैणसी री छगत, न० २०२।२४, अ० स० पु० बी०
- ११ बरमलपुर विजय—मधेरण जोगदास, अ० स० पु० बी०
- १२ महाराजा अनूपसिंघजी रे मुनसब न तसब री विगत, न० २०६।२-१९ अ० स० पु० बी०
- १३ बीकानेर रे राठौड राजाभा री ने बीजा लोका री पीढिया—बीकानेर रे कामदारा बगैरा री पीढिया अ० स० पु० बी०
- १४ राठौडा री वशावली व पीढिया व फुटकर बाता, न० २३३।६ अ० स० पु० बी०
- १५ ओसवाला री पीढिया, न० २२८।१ अ० स० पु० बी०
- १६ फुटकर बाता, न० २०६।२, अ० स० पु० बी०
- १७ क्यामखा रासो, राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला, जयपुर

(आ) संस्कृत साहित्य

- १ अमस्त-राजधर्म कौत्तुभ, न० २५२।५४, अ० स० पु० बी०
- २ गीत गोविन्द टीका, न० २६-२६, अ० स० पु० बी०

३. जयसोम—रुमचन्द्र वंशोत्कर्तनकम् काव्य, अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, न० १२०६ इति
४. दिनकर भट्ट—साहित्य कल्पद्रुम, अ० स० पु० बी०
५. पेरशास्त्रिन—अनूप यशोवर्णन, न० ४६, अ० स० पु० बी०
६. महादेव—रायसिंह सुधासिन्धु, न० ४२८३, अ० स० पु० बी०
७. रायसिंह प्रशस्ति, न० २६-२६, अ० स० पु० बी०
८. रायसिंहजी रो बँत, न० २६-२६, अ० स० पु० बी०
९. विद्वत् कृष्ण विद्यावागीश—अनूपसिंह गुणावतार, न० ४५, अ० स० पु० बी०
१०. होशिंग कृष्ण—कर्णावतार, न० २६८१, अ० स० पु० बी०

(इ) फारसी-साहित्य

१. अब्दुल कादिर बदायूनी—मुन्तखब-उत-तवारिख, अनु० रॉकिंग एण्ड लॉ
२. अब्दुल हमीद लाहोरी—बादशाहनामा, भाग २, विबलियोपिका इण्डिका, कलकत्ता, १८६७-६८
३. अब्दुल फजल—अकबरनामा, अनु० एच० वेवरिज, भाग ३, ऐशियाटिक सोसायटी, बंगाल, कलकत्ता, १८६७-१८९०
४. अब्दुल फजल—आईन-अकबरी, अनु० ब्लौकमैन, भाग १, १८७३ ई०; जैरेट, भाग २-३, १८८४ ई० विबलियोपिका इण्डिका, कलकत्ता
५. इनायतखान—शाहजहाननामा, अनु० इलियट एण्ड डायसन, भाग ७
६. ग़ुलाम हुसैन—सिमार-उत-मुताक़्किरिन, भाग १-४ कलकत्ता, १८०२
७. तुजुके जहांगीरी, अनु० रोजर्स एण्ड वेवरिज, भाग २
८. निजामुद्दीन अहमद—तज़क़ात-ए-अकबरी, अनु० बी० डे०, भाग ३, विबलियोपिका इण्डिका, कलकत्ता, १८२७
९. मुहम्मद काज़िम—आलमगीर नामा, विबलियोपिका इण्डिका, कलकत्ता, १८६५-७३
१०. मुहम्मद काज़िम हिन्दुशाह—तारीख-ए-फरिश्ता, अनु० जे० ब्लौकमैन—हिस्ट्री ऑफ़ दी राज्ज ऑफ़ मोहम्मदन पावर इन इण्डिया, भाग ४
११. मुहम्मद मकी मुस्तैद खान—मासिरे आलमगीरी, अनु० सर ज़ुलताफ़ सरकार, कलकत्ता, १८४७
१२. मुहम्मद हाशिम खाफ़ीखान—मुन्तखब-उल-नुबाव
१३. शाहनवाज़ खान—मासिर-उल-उमरा, भाग ३, ऐशियाटिक सोसायटी, बंगाल, कलकत्ता

फरमान, रा० रा० अ० बी०

- १ सम्राट अकबर का राजा रायसिंह के नाम फरमान, दिनांक ■ उदिविहिस्त ३७, २५ अप्रैल, १५६२, न० १
- २ सम्राट अकबर का राजा रायसिंह के नाम फरमान, दिनांक ५ उदिविहिस्त, ४२१ अप्रैल, १५६६, न० ४
- ३ सम्राट अकबर का राजा रायसिंह के नाम फरमान, दिनांक ६ दाइ ४२, फरवरी, १५६७, न० ६
- ४ शहजादा सलीम का रायसिंह के नाम निशान, दिनांक २६, अज़र ४२, नवम्बर, १५६७ न० ८
- ५ सम्राट अकबर का राजा रायसिंह के नाम फरमान, दि० १६ उदिविहिस्त ४६, अप्रैल, १६०४, न० १२
- ६ सम्राट जहागीर का राय सूरजसिंह के नाम फरमान, दि०—दाई इलाही १।१२, दिसंबर १६०६, न० १८
- ७ शहजादा खुर्रम का राजा सूरजसिंह को निशान, दि० १५ फरवरदीन १।२६, मार्च, १६१४ ई०, न० २४
- ८ सम्राट जहागीर का राय सूरजसिंह को फरमान, दि० १ खर्वादाद, ६ मई, १६१४, न० २६
- ९ सम्राट जहागीर का राय सूरजसिंह को फरमान, दि० ५, अमरदाद ६, जुलाई १६१४, न० २७
- १० शहजादे खुर्रम का राजा सूरजसिंह को निशान, दि० ५, अस्फन्दारमुख, इलाही, ११ फरवरी, १६१६, न० ३३
- ११ सम्राट जहागीर का राजा सूरजसिंह को फरमान, दि० १३, दाइ इलाही १२, नवम्बर, १६१७, नंबर ३७
- १२ सम्राट जहागीर का राय सूरजसिंह को फरमान, दि० १४, अस्फन्दारमुख १५ फरवरी १६२०
- १३ साम्राज्ञी नूरजहा का रानी गंगाबाई को निशान, २ महरार, १४, अगस्त, १६१९, न० ३७
- १४ सम्राट जहागीर का सूरजसिंह को फरमान, दि० १६, मेहर—२२/२६ सितम्बर, १६२७ न० ६१
- १५ दावर बख्त का राय सूरजसिंह को निशान, दि० २० अबान—२२, अक्टूबर, १६२७, न० ६२
- १६ सम्राट जहागीर का राय सूरजसिंह को फरमान, दि० ८, मोहर , सितम्बर, न० ६६

- १७ सम्राट औरंगजेब का अनूपसिंह को फरमान, दिनांक १६, रबी-उल अब्बल १०, ११ न० ६१
- १८ सम्राट शाह आलम का महाराजा गजसिंह को फरमान, दि० १४ जमा-दिउसशानी ४, जुलाई, १७६२, न० ८०

माध्यमिक स्रोत

(१) राजस्थानी-साहित्य

- १ आर्षाख्याम कल्पद्रुम—सिदायच दयालदास, न० १८०१८ अ० स० पु० बी०
- २ देशदर्पण—दयालदाम, न० १८६१८, अ० स० पु० बी०
- ३ दयालदाम की कथात, भाग १, भाग २, न० १८८१० (क—घ), अ० स० पु० बी०, भाग २, प्रकाशित—अनु० दशरथ शर्मा, सादुल प्राच्य ग्रन्थमाला, अ० स० पु० बी०, स० २००५
- ४ बाबीदास की कथात—सम्पादक जिन विजय मित्र, जयपुर १९५५
- ५ बीदायतो की कथात—ठाकुर बहादुरसिंह
- ६ उदयपुर की कथात व फुटकर कविता, न० १२२१४, अ० स० पु० बी०
- ७ बीकानेर व राठोड़ी की कथात, सीहू जी सू, न० १९२-१४, अ० स० पु० बी०
- ८ मारवाड़ की कथात, भाग-२, अ० स० पु० बी०

(२) हिन्दी-साहित्य

- १ यश भास्कर—सूर्यमल्लमिश्रण, भाग २, जोधपुर, वि० स० १९५६
- २ बीर विनोद—रियामत दास, मवाड गवर्नमण्ट पब्लिकेशन, १८८६ ई०
- ३ लक्ष्मीधर तवारिख राज श्री जैसलमेर, गवर्नमण्ट पब्लिकेशन, जैसलमेर, १९०४ ई०
- ४ मूषी सोहनलाल—तवारिख राजश्री बीकानेर, स० १९४७
- ५ ठाकुर मेरसिंह—तवारिख रियामत बीकानेर, गवर्नमण्ट पब्लिकेशन, बीकानेर १८५८

आधुनिक स्रोत

(१) प्रकाशित

१. अनूपदायी—राजा चयसिंह, १९३४
- २ अनन्त सदासिब अनवर—शाहीन भारतीय मामल पदवि, द्वितीय

संस्करण, प्रयाग, १९५९

३. अतहरअली—दी मुगल नॉबिलिटी अण्डर औरंगजेब, एशिया, १९६६
४. आर० बी० सिंह—हिस्ट्री ऑफ चाहमन्ग, १९६४
५. आर० पी० त्रिपाठी—सम आस्पेक्ट्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इलाहाबाद, १९६४
६. आर० पी० त्रिपाठी—मुगल साम्राज्य का उत्थान व पतन, अनु० कालीशम कपूर, द्वितीय संस्करण, इलाहाबाद, १९६९
७. आर० पी० व्यास—नाबिलिटी इन भारवाड, दिल्ली, १९६९
८. ओसा निबन्ध संग्रह—भाग १ से ५, विद्यापीठ, उदयपुर, १९५९
९. इब्ने हसन—दी सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ दी मुगल एम्पायर, बम्बई, १९३६
१०. इरफान ह्यूब—दी एंग्लोरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया, बम्बई, १९६३
११. ईलियट एण्ड डाउसन—दी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया एज टोटल बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स, भाग १-८, लन्दन, १८६६
१२. ए डेस्क्रेप्टिव लिस्ट आफ फरमान्स, मन्सूर एण्ड निशान्स, डायरेक्ट्रेट ऑफ आरकाईव्स, बीकानेर, १९६२
१३. ए० एल० श्रीवास्तव—अकबर महान, भाग १-३, अनु० डा० भगवानदास गुप्त, आगरा, १९६७, १९७२
१४. ए० पी० एडम्स—दी वैस्टर्न राजपूताना ऐस्टेट्स एण्ड दी बीकानेर एजेन्सीज् लन्दन, १९००
१५. एन० एल० डे०—दी जियोग्राफीकल डिक्शनरी ऑफ एनशियन्ट मैडिवल इण्डिया, १८१९
१६. ए० सी० बनर्जी—राजपूत स्टडीज्, कलकत्ता, १९४४
१७. ए० सी० बनर्जी—दी राजपूत स्टेट्स एण्ड दी ईस्ट इण्डिया क०, कलकत्ता १९५१
१८. एम० एम० मेहता—लार्ड हैस्टिंग्स एण्ड दी इण्डियन स्टेट्स, लन्दन, १९२५
१९. करणीसिंह—दी रिलेशन्स ऑफ दी हाउस ऑफ बीकानेर विद दी सेंट्रल पावर्स, दिल्ली, १९७४
२०. कर्नल जेम्स टॉड—एनल्स एण्ड एन्टिक्वीटीज् ऑफ राजस्थान, ऑक्स-फोर्ड, १९२०
२१. वनॅल मैन्सन—ए हिस्टोरिकल स्केच ऑफ दी नैटिव स्टेट्स ऑफ इण्डिया, लन्दन, १८७५

- २२ कालिका रजन कानूनगो—शेरशाह एण्ड हिज टाइम्स, अनु० मधुरालाल शर्मा खानियर, १९६६
- २३ के० एम० पनिकर—हिज हार्डिनेस दी महाराजा ऑफ बीकानेर, ऑक्सफोर्ड, १९३७
- २४ गोविन्द अग्रवाल—चुरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास चुरू, १९७४
- २५ जी० एन० शर्मा—ए बिबलियोग्राफी ऑफ मेडिवल राजस्थान, आगरा, १९६५
- २६ जी० एन० शर्मा—सोशियल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान (१५००-१८०० ई०) आगरा, १९६८
- २७ जी० एन० शर्मा—ऐतिहासिक निबन्ध राजस्थान, जोधपुर, १९७०
- २८ जी० एन० शर्मा—राजस्थान का इतिहास, द्वितीय संस्करण, आगरा, १९७३
- २९ जी० एस० एस० देवडा—भ्यूरोक्रेण्टी इन राजस्थान, (१७४५-१८२९) बीकानेर, १९८०
- ३० जी० एस० एस० देवडा—सोशियो इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जोधपुर, १९८०
- ३१ जी० डी० शर्मा—राजपूत, पोलिटी दिस्ली, १९७७
- ३२ जी० सी० शर्मा—एडमिनिरट्रटिव सिस्टम ऑफ राजपूतस, दिस्ली, १९७९
- ३३ जी० आर० परिहार—मारवाड एण्ड दी मराठाज, जोधपुर, १९६८
- ३४ जी० एस० सर देसाई—न्यू हिस्ट्री ऑफ दी मराठाज, भाग ३, १९४८
- ३५ जे० एन० सरकार—औरंगजेब, भाग १-४, १९१२, १९२४, १९२८, १९३०, १९३४
- ३६ जे० एन० सरकार—फात ऑफ दी मुगल एम्पायर, भाग ३, कलकत्ता, १९५२
- ३७ जे० एन० सरकार—फात ऑफ दी मुगल एम्पायर, भाग २, कलकत्ता, १९५३
- ३८ जी० एच० ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग १-२, अजमेर, वि० स० १९६६, वि० स० १९६७
- ३९ जी० एच० ओझा—जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग १-२, अजमेर, १९३८, १९४१
४०. जार्ज योमस—बिलट्री मेमोयर्स, सम्पादक विलियम फ्रेंकलिन, कलकत्ता, १८०३
- ४१ टेसीटोरी—ए डेस्क्रिप्टिव केटलोग ऑफ बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मेन्स-

स्विफ्ट सवशन, प्रोजेक्शनिकल्स, पार्ट सेकिण्ड, बीकानेर स्टेट—विबलियो-थिका इण्डिया—कलेक्शन ऑफ ओरियन्टल चर्च, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, न्यू सीरीज, नम्बर १४१३, १९१८

४२ डब्ल्यू इरविन—सेटर मुगल्स, भाग १-२, १९२२

४३ डब्ल्यू इरविन—मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी मुगल्स, अनु० रमेश तिवारी, इलाहाबाद

४४ थोमस एडवर्ड—दी मेनिंग ऑफ दी इण्डियन प्रिन्स, १९४३

४५ दी हाऊस ऑफ बीकानेर—ए नेरेटिव, बीकानेर १९३३

४६ दशरथ शर्मा—अर्ली चौहान डायनेस्टी, दिल्ली, १९५०

४७ दशरथ शर्मा—राजस्थान थू दी एजेंड, बीकानेर, १९६६

४८ वमरथ शर्मा—लेक्चर्स ऑफ राजपूत हिस्ट्री, दिल्ली, १९७०

४९ पी० सरन—स्टडीज इन मेडिवल इण्डियन हिस्ट्री, द्वितीय संस्करण, बम्बई, १९७३

५० पद्मजा शर्मा—महाराजा मानसिंह ऑफ जोधपुर, आगरा, १९७२

५१ फोर डीकेडम आफ प्रोग्रेस इन बीकानेर, बीकानेर, १९४४

५२ बीकानेर गोल्डन जुवली, गवर्नमन्ट पब्लिकेशन, बम्बई, १९३७

५३ बी० पी० मक्सेना—शाहजहाँ ऑफ दिल्ली, इलाहाबाद, १९३२

५४ मीर मुन्सी श्रीराम—ताजीमी, राजबीज, ठाकुरस एण्ड खुवासवाल्स ऑफ बीकानेर, बीकानेर

५५ मधुरालाल शर्मा—हिस्ट्री ऑफ जयपुर स्टेट जयपुर, १९६६

५६ मोतीचन्द खन्ना-ची—मीनियेचर पेन्टिंग्स, ससित कला ऐकेडमी, नई दिल्ली, १९६०

५७ मोर लेण्ड—दी ऐगरेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया, इलाहाबाद, १९२६

५८ रजिस्टर देहात छालसा, बीकानेर

५९ रघुवीर सिंह—पूर्व आधुनिक राजस्थान, उदयपुर, १९५१

६० रफाकत अली खान—दी कच्छावाहा अण्डर अकबर एण्ड जहाँगीर, दिल्ली, १९७६

६१ रायबहादुर हुवमसिंह सोढी—जियोग्राफी ऑफ बीकानेर, बीकानेर

६२ बी० ए० स्मिथ—अकबर, दी ग्रेट मुगल, आक्सफोर्ड, १९१६

६३ बी० एन० रेऊ—मारवाड का इतिहास, भाग १-२, जोधपुर, १९४०

६४ बी० एस० भटनागर—लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ सवाई जयसिंह (१६८८-१७४३) दिल्ली, १९७४

६५ बी० एस० भागवत—मारवाड एण्ड दी मुगल्स एम्परर्स, दिल्ली, १९६६

- ६६ सर जोन पॉल्कम—मैमोयर्स ऑफ सैन्ट्रल इण्डिया भाग १ लन्दन १८८०
 ६७ सर एच० एम० ईलियट—नार्थ वेस्ट प्रोविन्सस ऑफ इण्डिया, लन्दन
 ६८ सर्जन मेजर डब्ल्यू एच नेलसन—ए-मैडिको टोपोग्राफिकल एकाउण्ट
 आफ बीकानेर विद मैक्स एण्ड प्ला-स, इलाहाबाद, १८६६
 ६९ सी० यू ऐतबीसन—ए कलैब्रेशन ऑफ ट्रीटीज, ए इन्वेन्टर्मन्ट्स एण्ड
 सनदस, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, कलकत्ता, १९३२
 ७० सैय्यद मुसल हसन—घोटस ऑन एगरेरियन रिलेशन्स इन मुगल इंडिया,
 नई दिल्ली, १९७३
 ७१ सैय्यद अतहर अब्बास रिजवी—हुमायूनाभा भाग १ मुगलकालीन
 भारत, अलीगढ़ १९६१
 ७२ हरमन गौयट्ज—आर्ट एण्ड आरकिटेक्चर ऑफ बीकानेर, आक्सफोर्ड
 १९५०

(२) अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध

- १ एस० पी० गुप्ता—दी लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन ईस्टर्न
 राजस्थान, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, १९७५
 २ सोलाराम अग्रवाल—रिलेशन्स बिटवीन दी क्लसर्स एण्ड दी नॉबल्स प्राँफ
 बीकानेर १८१८—१९१९
 ३ दिलबागसिंह—लोकल एण्ड लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी स्टेट
 ऑफ जयपुर, १७५०—१८००, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
 १९७५
 ४ शशी अरोड़ा—पोजिशन आफ वूमन इन राजस्थान (१६००-१८००)
 राजस्थान विश्वविद्यालय, १९७८

(३) गजेटियर, पत्रिका, शब्दकोष, तिथि-पत्रक

- १ हम्पीरिवर गजेटियर ऑफ इण्डिया, प्रोविन्सियल सीरीज, राजपूताना,
 १९०८
 २ गजेटियर, दी बीकानेर स्टेट, कंप्टन पी० डब्ल्यू, पाउलेट गवर्नमेन्ट प्रेस,
 बीकानेर १९३५
 ३ के० डी० अर्मेकिन—राजपूताना गजेटियर, गवर्नमेन्ट पब्लिकेशन,
 कलकत्ता, १९०६
 ४ जनरल ब्राफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, न्यू सीरीज, बलकत्ता
 ५ दी इण्डियन इकोनॉमिक एण्ड सोशियल हिस्ट्री, रिब्यू, बोल्डूम, न० १
 जुलाई-सितम्बर, १९६३

- ६ प्रोसिडिङ्स आफ राजस्थान हिस्ट्री कांफ्रेंस जयपुर सेशन, १९६७, जयपुर, सेशन १९६८ व्यावर मसन, १९७३ पानी मसन, १९७४ अजमेर सेशन १९७५, डिपार्टमेंट आफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी आफ जोधपुर, जोधपुर
- ७ प्रोसीडिंग्स आफ इण्डियन हिस्ट्री कांफ्रेंस, १९५८-६२
- ८ परम्परा, सम्पादक नाराणसिंह भाटी, राजस्थान शोध-संस्थान, चोपासनी, जोधपुर, भाग २८-२९, १९६९
- ९ राजस्थान भारती, सादूल राजस्थान रिसर्च इस्टीमेट, बीकानेर, दिसम्बर १९७२ जनवरी-मार्च, १९७४ जुलाई-दिसम्बर, १९७४
- १० वैचारिकी, भारतीय विद्यामंदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर, दिसम्बर १९७५
- ११ शोध-पत्रिका, उदयपुर, १९५०-६३
- १२ ऐतिहासिक तिथि पत्रक, जगदीश सिंह गहलोत, जोधपुर, १९६२
१३. मानविकी-शब्दावली ह्यूमैनिटीज ग्लोसरी— मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन, गवर्नमेंट आफ इण्डिया, १९६६
- १४ सक्षिप्त हिन्दी शब्द मागरी, नागरी प्रचारिणी मण्डल, काशी, सप्तम् संस्करण, १९७१

अनुक्रमणी

अकबर (मुगल सम्राट) १७, २४,
३२-३३, ३५, २३६-३७
अनुपगढ १०, १२, २१२
अनुपसिंह १०, १६-२०, २५, ३०,
३३, ३५, ६६, ८३, ८४, १०५,
१५८-५९, १६६, १८७, १९०,
१९८, २२३
अमरचंद सुराणा १०६, ११४
आसामीदार चाकर ५३, ५८, ५९-
६६ (पट्टायत), ८३-८७, १७४
औरंगजेब २०, ३१, ३३, ३५
बमचन्द बच्छावत १०३-१६, १११-
११२
कल्याणमल ६-१०, १५, २८, २३६
कामदार ५५, ८८-८९, १००, १८३
काधलीत ५१, ५३, ६१-६६ (पट्टा)
कुसा २२८-२५
कुमानसिंह २५-२६, ६३
कोतवाल १४६-४७, १९२, २३६
खाना-ची ६५, ११८, १३३, १९३
खाण ३०, ५१, ५६
खालसा २८, ५५, १२७-३१, १५६-
६०
खुवाम १७, ११६, १८६
गंगारानी (महारानी) ६६
गजसिंह ११, १६-२१, २६-२७, ४२-
६३, ६३-६४, ७३-७५, ८४, ८६,
१११, १७६, १९० २०३
घासीया ३, ५, २२३
घोडारेख ५६, १७७-७८, २०३,

२०७
चीरा ३०, ६५, ६८, १२७, २११,
२११, २२६-२६, २३८
चौधरी १५०-५३, १७१, २१४-१६,
२२०, २२३-३०
जजिया ३१, १९८
जगत ५६, १७३-७६
जनानी हथोडी ४५-४६, ६०, १८६,
जमीदार २१, ३६, १५२, १७१,
२२३-२६, २३०
जहांगीर २२, ३३
जागल देश १
जावता असवार ७८-८०
जैतसी १५, ४६
जोरावरसिंह २५, ४६, ५६, ६३-६५
जोहिया ५-८, ११-१२, ३०
टिकावल ८
ठकुराई ५६
ठीकाणा ५१, ५३, ५७, ५८-६५
ढोहोली १५१, २२०
तनवगसी ११५-१६, २४१
भाणा १२०, १३३-३४, १६६-६७,
२३१
दन्पतसिंह २८, ३३, १०४
दरोया ६५, १९२
दाऊद भुल १२
दीवान २५, २६, १०२-११३, २३०,
२३८-३९, २४१
धुआं भाछ १६८-७१, १८६, २०७,
२२३-२६

पटावरी १५३ १७१, १८३,
२२३-२६, २३०
परगना १० १३१-३२, २१३, २२१,
२३७-३८
परसंगी ७१
पचायत १५३-५७
पाटवी ५०, ५७
पासवान १७, १८६
पूनीया ३, १०
पेशकसी ५६, १६१, १७१-७३, २०
फलोधी ११ १२
बलनावरसिंह २५, ६३, १०५, १११-
१२
बडारण १७, १८६
बीका (राव) ७-१०, १४-१५, ३६,
१००
बीकावास ५७-६१ (पट्टा), ८७
बीजा रकम १६५-७१, २२३, २२५-
३०
बीदा ५२, ६६-६६
बीदावत ५२, ६६-७१ (पट्टा), १८४
भटनेर ४, १०-१३, २२१
भाटी ३, ६, ७, ३०, ७५, ८३
भोमीचारा ३
भोमीया १४, २१८, २२३, २३४-३५
मण्डलाजी ६६
मनसब १०, ३२, ३३, ३४-३६,
(सूची), २३७
मडी १२१, १३२-३३, १७४-७६,
१६४
मुकाता १४०-४६, १७४-७६, २१६,
२१८, २२३, २२६-२२७- २३२-
२३३
मुल्गही २५, ६६, ६६, १०६, १२५,
११७ १६५. २०८. २३६-४०

मुसाहिव २६, ६३, १०३, १०४,
१०८, ११३-११५. २४१
मोदीखाना १२१, १६०-६२,
रायसिंह १०, १६, २०, २४, २६-
३०, ३२, ३३, ५२, ५७, ६४,
७६, १०३, १५८-५६, १८०,
२२३, २३६-३७
कलवाली भाछ ५७, १७७-७८, १८६,
२०३, २०६,
रोऊड रकम १६४-७१, २२३, २२५-
२६, २४१
लूणकरण राव १५, ४६
लैखणीया १२२, १६२
लेहणायत १४६
वकील ११७, १६८
वतन जागीर १६, ३१, ३५-४१,
सूची-३८-३९, १५८, २३७-३८
शिकदार ११६-१७, २४१
साबता ५-७, ७२
सासन ६०, १२३
साहणा ६५, २२४-२५
सिरायत ५७, ६४
सूरसिंह १६, २४, ३३, ४६, ५७,
६३, ७४
सुरतसिंह ११-१२, २७, ४२-४३,
५७, ६५, ८१, ८६, १०५-१०८,
१५८-५६, १७७, १८३, १६५,
१६७, २०३
सोनगरा ७३
हजुरी १७, ५५, ८८-८६, १०६,
१२५, १८३
हवुव ५६, १८१, २०६
हासल १६४-७१, २०८, २२३,
२२०-२६, २४०, २४१
हुवाला १३६, ४०, २३१-३२

डॉ० जी एस एल देवड़ा

जन्म बोकानेर (राजस्थान) म १८८२ ई० म , राजस्थान विश्वविद्यालय म १९६७ ई० म इतिहास (मध्यकालीन भारत) म प्रथम श्रेणी म एम० ए० (स्वर्ण पदक प्राप्त) , १९७६ म इसी विश्वविद्यालय स पी एच० डी० डिग्री प्राप्त ; लगभग १३ वर्ष का स्नातक एवं स्नातकोत्तर बधाओं क अध्यापन का अनुभव , इस समय दूगर महा-विद्यालय, बोकानेर के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग स सम्बन्धित ।

डॉ० देवड़ा के २८ शोध लेख , राजस्थान की राज-नीतिक, आर्थिक व विज्ञान की समस्याओं स सम्बन्धित , विभिन्न शोध पत्रिकाओं म प्रकाशित हो चुके हैं । अब तक प्रकाशित पुस्तकें य—भूगोलीय इतिहास राजस्थान, इण्डियन कैलण्डर , वास्तव्यता व पंचांग , सम आस्वदत्त ऑफ सोशियो-इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान (सम्पादन) व महाराजा गंगासिंह शताब्दी ग्रन्थ (सम्पादन) उल्लेखनीय हैं ।